



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1976/फाल्गुन 2, 1897
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 1976/PHALGUNA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आवेदन

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1975

का० प्रा० 717.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 321-हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तुलैया, ग्राम ब पञ्चालय छानी बुजुर्ग, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपन निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री तुलैया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/321 74 (476)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 26th December, 1975

S.O. 717.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tulaiya, Village and P.O. Chhani Buzurg, District Hamirpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 321-Hamirpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tulaiya to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/321/74(476)]

आदेश

का० प्रा० 718.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए

321-हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरीश चन्द, ग्राम व पत्तालय पाथिया बुजुर्ग, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्बन्ध सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरीश चन्द को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/321/74(477)]

ORDER

S.O. 718.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Harish Chand, Village and P.O. Pauthia Buzurg, District Hamirpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 321-Hamirpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Harish Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/321/74(477)]

आदेश

क्र० प्रा० 719.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 321-हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू राम, ग्राम पुलन्दर, पत्तालय देहली, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्बन्ध सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बाबू राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/321/74(478)]

ORDER

S.O. 719.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Ram, Village Pulandar, P.O. Deheli, District Kanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 321-Hamirpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/321/74(478)]

आदेश

क्र० प्रा० 720.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये 322-मौदाहा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भीरमा, ग्राम व पोस्ट बसहरी, जिला बाँदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्बन्ध सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री भीरमा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/322/74(479)]

ORDER

S.O. 720.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhairma, Village and Post Basahari, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 322-Maudaha assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhairma to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/322/74(479)]

आदेश

का० प्रा० 721.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 322-मौदहा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव प्रसाद सिंह, मौदहा मुहल बाजार, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री शिव प्रसाद सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/322/74(480)]

ORDER

S.O. 721.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Prasad Singh, Maudaha Mubal Bazar, District Hamirpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 322-Maudaha assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Prasad Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/322/74(480)]

आदेश

का० प्रा० 722.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 329-बबीना (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रेम चन्द, 201-तालपुरा झांसी, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री प्रेम चन्द को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने

और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/329/74(481)]

ORDER

S.O. 722.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prem Chand, R/o 201, Talpura, Jhansi, District Jhansi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 329-Babina (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prem Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/329/74(481)]

आदेश

का० प्रा० 723.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 329-बबीना (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुन्ना लाल, 957-चमरयाना, बबीना-कैंट, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मुन्ना लाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/329/74(482)]

ORDER

S.O. 723.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Munna Lal, R/o 957, Chamaryana, Babina Cantt. District Jhansi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 329-Babina (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Munna Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of

a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/329/74(482)]

आदेश

का० प्रा० 724.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 336-भोगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेंद्र सिंह, ग्राम व पोस्ट सिमरई, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री महेंद्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/336/74(483)]

ORDER

S.O. 724.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendra Singh, Village and P.O. Simarai, District Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 336-Bhongaon assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/336/74(483)]

आदेश

का० प्रा० 725.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 339-शिकोहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेन्द्र राजपूत, नगला सैदलाल, डाकघर उरमारा किरार, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नरेन्द्र राजपूत को संसद के किसी भी सदन के

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/339/74(484)]

ORDER

S.O. 725.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narendra Rajput, Nagla Saidal, P.O. Urmaura Kirar, Shikohabad, Dist. Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 339-Shikohabad assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narendra Rajput to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/339/74(484)]

आदेश

का० प्रा० 726.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 339-शिकोहाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ज्ञान सिंह, ग्राम मलखानपुर बिदरख, पो० प्रा० दखनारा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री ज्ञान सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/339/74(485)]

ORDER

S.O. 726.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gyan Singh, Village Malkhanpur, Bidarkha, P.O. Dakhinara, District Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 339-Shikohabad assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gyan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/339/74(485)]

आदेश

का० प्रा० 727.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 422-हरिद्वार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रमणि, भीम गोडा, हरिद्वार, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री चन्द्र मणि को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/422/74(491)]

ORDER

S.O. 727.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Mani, Bheem Goda, Hardwar, District Saharanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 422-Hardwar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Mani to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/422/74(491)]

आदेश

का० प्रा० 728.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 422-हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल्ला, मोहल्ला चकलान, ज्वालपुर, हरिद्वार, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अब्दुल्ला को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/422/74(492)]

ORDER

S.O. 728.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdulla, Mohalla Chaklan, Jwalapur, Hardwar, District Saharanpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 422-Hardwar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdulla to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/422/74(492)]

आदेश

का० प्रा० 729.—अतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 422-हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोला दास, ग्राम शाहपुर शीतल खेडा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये पर्याप्त कोई कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री भोला दास को संसद् के किसी भी सदन के या किसी भी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/422/74(493)]

ORDER

S.O. 729.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bholadas, Village Shahpur Sheetla Kheda, District Saharanpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 422-Hardwar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhola Das to be disqualified for being chosen

as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/422/74(493)]

आदेश

क्रा० प्रा० 730.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 422-हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मेघ सिंह, ग्राम रुहालकी, किशनपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मेघ सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/422/74(494)]

ORDER

S.O. 730.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Megh Singh, Village Ruhalki Kishanpur, District Saharanpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 422-Hardwar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Megh Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/422/74(494)]

आदेश

क्रा० प्रा० 731.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 422-हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रतन सिंह, ग्राम अजीतपुर, डा० मिश्रपुर, कनखल, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रतन सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/422/74(495)]

ORDER

S.O. 731.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ratan Singh, Village Ajitpur, P.O. Misarpur, Kankhal, District Shaharanpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 422-Hardwar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ratan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/422/74(495)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1975

क्रा० प्रा० 732.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 346-सोरों निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोम प्रकाश, ग्राम इतवारपुर, डाकघर अहंगीरपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री भोम प्रकाश को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/346/74(497)]

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1975

S.O. 732.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Om Prakash, Village Itwarpur, P.O. Jahangirpur, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 346-Soron assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure

and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Om Prakash to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/346/74(497)]

प्रादेश

का० प्रा० 733.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 346-सोरों निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती एम० डी० मोहल्ला, गन्दानाला साउथ, पोस्ट कासगंज, जिला एटा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाञ्छित करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्रीमती एम० डी० को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०-प्र०-वि० सं०/346/74(498)]

ORDER

S.O. 733.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati M. D., Mohalla Gandanala South, Post Kasganj, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 346-Soron assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati M. D. to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/346/74(498)]

प्रादेश

का० प्रा० 734.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 346-सोरों निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बुध-अज, 76 मोहल्ला दुबे, पोस्ट सोरन, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाञ्छित करने में असफल रहे हैं-

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बुध सेन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०-प्र०-वि० सं०/346/74(499)]

ORDER

S.O. 734.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Budhsen, 76-Mohalla Dubey, Post Soron, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 346-Soron assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Budhsen to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/346/74(499)]

प्रादेश

का० प्रा० 735.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 350-जलेश्वर (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जपाल सिंह, ग्राम पसियापुर बेगमपुर, तहसील व आ० जलेश्वर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाञ्छित करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०-प्र०-वि० सं०/350/74(500)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

S.O. 735.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Trapal Singh, Village Pasiapur-Begumpur, Post and Tahsil Jalesar, Dist. Etah Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 350-Jalesar (SC) assembly constituency, has failed to lodge an

account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Trapal Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/350/74(500)]

A. N. SEN, Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1976

का० आ० 736.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स जी श्री टेक्सटाइल्स एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 271/70 दिनांक 26-10-1970) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 2/13/74-एम० 2]

एम० सी० वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Company Affairs)

New Delhi, the 5th February, 1976

S.O. 736.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. Jaya Shree Textiles & Industries Limited under the said Act (Certificate of registration No. 271/70 dated the 26th October, 1970).

[No. 2/13/74-M. II]

M. C. VARMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1975

आय-कर

का० आ० 737.—आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उप-धारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, दिल्ली स्थित पारसी जोरास्ट्रियन अग्नि मन्दिर को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में सर्वत्र विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 1159 / का० सं० 176/38/75-आई० टी० ए० I]

एम० शास्त्री, भवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 28th November, 1975

Income-Tax

S.O. 737.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Parsi Zoroastrian Fire Temple at Bahadur Shah Zafar Marg, Delhi Gate, Delhi to be a place of public worship of renown throughout the Union Territory of Delhi for the purposes of the said section.

[No. 1159/F. No. 176/38/75-IT. AI]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

का० आ० 738.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 3 के खंड (44) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार श्री बी० अनन्तकृष्णन को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर बसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 50 (का० सं० 404/46/71-आई० टी० सी० सी०) तारीख 10 नवम्बर, 1971 के अधीन श्री टी० गिरिराजन की नियुक्ति रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना श्री बी० अनन्तकृष्णन के कर बसूली अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1165/का० सं० 404/94/75-आई० टी० सी० सी०]

बी० पी० मिश्र, उप सचिव

New Delhi, the 19th December, 1975

S.O. 738.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri B. Ananthakrishnan, who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri T. Girirajan, made under Notification No. 50(F. No. 404/46/71-ITCC) dated 10th November, 1971 is hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. Ananthakrishnan takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 1165/F. No. 404/94/75-ITCC]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1975

का० आ० 739.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को, विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ केवल अनुसन्धान के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है। यह संस्था अपने अनुसन्धान प्रियाकलापों की बाबत परिषद को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगी।

संस्था

आल इंडिया इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली।
यह अधिसूचना इस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 1174/का० सं० 203/183/75-आ० क० अ० II]

एम० के० पांडे, उप-सचिव

New Delhi, the 24th December, 1975

S.O. 739.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for research purposes only. The institution will submit annual report and accounts regarding its research activities to the prescribed authority.

INSTITUTION

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

This notification will be effective for a period of two years from this date.

[No. 1174/F. No. 203/183/75-ITA. II]

M. K. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली. 27 दिसम्बर, 1975

का० आ० 740 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संस्था को, विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ केवल अनुसन्धान प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है। यह संस्थापन अपने अनुसन्धान क्रियाकलापों की बाबत विहित प्राधिकारी को, वार्षिक रिपोर्ट और लेख प्रस्तुत करेगी।

संस्था

सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थापन, मुम्बई।

यह अधिसूचना इस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 1176/का० सं० 203/177/75-आ० क० अ० II]

New Delhi, the 27th December, 1975

S.O. 740.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for research purposes only. The Foundation will submit annual reports and accounts regarding its research activities to the prescribed authority.

INSTITUTION

The Foundation for Research in Community Health, Bombay.

This notification will be effective for a period of two years from this date.

[No. 1176/F. No. 203/177/75-ITA. II]

का० आ० 741.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संस्था को, विहित प्राधिकारी,
145 GI/75—2

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, केवल अनुसन्धान के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है। यह प्रस्पताल अपने अनुसन्धान क्रियाकलापों की बाबत विहित प्राधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रस्तुत करेगा।

संस्था

बाल चिकित्सा प्रस्पताल, मुम्बई।

यह अधिसूचना इस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 1177/का० सं० 203/176/75-आ० क० अ० II]

S.O. 741.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, for research purposes only. The hospital will submit annual reports and accounts on the research activities of hospital to the prescribed authority.

INSTITUTION

Children Orthopedic Hospital, Bombay.

This notification will be effective for a period of two years from this date.

[No. 1177/F. No. 203/176/75-ITA. II]

का० आ० 742 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संस्था को, विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ केवल अनुसन्धान के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है। यह सोसाइटी अपने अनुसन्धान क्रियाकलापों की बाबत विहित प्राधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट और लेख प्रस्तुत करेगी।

संस्था

मंगलूर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, मंगलूर।

यह अधिसूचना इस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 1178/का० सं० 203/75-आ० क० अ० II]

S.O. 742.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, for research purposes only. The Society will submit annual reports and accounts regarding its research activities to the prescribed authority.

INSTITUTION

Mangalore Medical Relief Society, Mangalore.

This notification will be effective for a period of two years from this date.

[No. 1178/F. No. 203/175/75-ITA. II]

का० प्रा० 743 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, निम्नलिखित प्राधिकारी, चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, केवल अनुसन्धान के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है। यह अस्पताल अपने अनुसन्धान क्रियाकलापों की आवन परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट और लेख प्रस्तुत करेगा।

संस्था

जी० कुण्डस्वामी नाइडू मेमोरियल अस्पताल, कोयम्बटूर।

यह अधिसूचना इस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 1179/का० सं० 203/100/75-प्रा० क० प्र० II]
टी० पी० जनुजनुवाला, उप-सचिव

S.O. 743.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for research purposes only. The Hospital will submit annual reports and accounts regarding its research activities to the Council.

INSTITUTION

G. Kuppaswamy Naidu Memorial Hospital, Coimbatore.

The notification will be effective for a period of two years from this date.

[No. 1179/F. No. 203/100/75-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

स्टाम्प

का. आ. 744.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से, जो पंजाब विस्तीय निगम, चण्डीगढ़ द्वारा जारी किए गए पचापन लाख रुपये मूल्य के डिबेंचर्स के रूप में बन्धपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[सं० 9/76-स्टाम्प-का. सं० 471/7/76-सीमा शुल्क 7]
डी. के. आचार्य, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1976

STAMP

S.O. 744.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act,

1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures to the value of fifty-five lakhs of rupees, floated by the Punjab Financial Corporation, Chandigarh, are chargeable under the said Act.

[No. 9/76 Stamps-F. No. 471/7/76-Cus. VII]

D. K. ACHARYA, Under Secy.

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th January, 1974

S.O. 745.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. S. O. 4062 dated the 10th September, 1975, published on pages 3419—3421 of the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 20th September, 1975, the following shall be omitted/inserted in the heading "Metal Composition" appearing on page 2 and in the heading "Remedy allowed in Composition" in Hindi version appearing on page 3:—

(i) The word "Quarternary" shall be read as "Quaternary".

(ii) The figure '71' shall be substituted by 74.

[No. 1/28/74-Coin]

S. L. DUTT, Under Secy.

पूँजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० प्रा० 746.—केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र में बित्त मंत्रालय (प्राथमिक कार्य विभाग) की अधिसूचना, संख्या का० प्रा० 558 दिनांक पहली फरवरी, 1969, में प्रकाशित पूँजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के पैरा 5 के परस्पर के खंड (ix) के अनुसरण में इस अधिसूचना द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त पैरा के प्रयोजन के लिये 1976 के कैलेंडर वर्ष में पहली जून, 1976 से लेकर 30 जून, 1976 तक (दोनों दिन सहित) और पहली अगस्त, 1976 से 31 अगस्त, 1976 तक (दोनों दिन सहित) कोई भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी समय के धारे में केन्द्रीय सरकार की पहले अनुमति लिये बिना 249 लाख रुपये (अंकित मूल्य) से अधिक मूल्य की (जिसमें सरकार और गैर-आवासियों द्वारा खरीदा जाने वाली रकम शामिल नहीं है) सिक्यूरिटियों का कोई भी प्रस्ताव न तो जारी कर सकेगी और न ऐसी सिक्यूरिटियों में रकम लेना जारी रख सकेगी।

[संख्या एक० 2(2)-सी० सी० आई०/76]

जे० पी० मुखर्जी, निदेशक

(Office of the Controller of Capital Issues)

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 746.—In pursuance of Clause (ix) of the proviso to paragraph 5 of the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, published with the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S. O. 558, dated the 1-2-1969, the Central Government hereby directs for the purpose of the said paragraph, that during the calendar year 1976 no offer of securities in excess of Rs. 249 lakhs (nominal value) (exclusive of the amount to be subscribed by the Government and non-residents) by a public limited company shall be made or kept open during the periods from the 1st June, 1976 to 30th June, 1976 (both days inclusive) and from the 1st August, 1976 to 31st August, 1976 (both days inclusive) without obtaining the prior permission of the Central Government as to the timing of the offer.

[No. F. 2(2)-CCI/76]

J. P. MUKHERJEE, Director (Investment).

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1976

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1976

का० आ० 747.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये न्यू० बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली पर, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध इस बैंक द्वारा मैसर्स माज्दा थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड की शेयर-धारिता से है।

[सं० 15(2)बी० ओ० III/76]

(Department of Banking)

New Delhi, the 29th January, 1976

S.O. 747.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to the New Bank of India Ltd., New Delhi, for a period of one year from the date of this notification in so far as they relate to its holdings in the shares of M/s. Mazda Theatres Pvt. Ltd.

[No. 15(2)-B.O. III/76]

का० आ० 748.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) और (ii) के उपबन्ध, फेडरल बैंक लिमिटेड, अवधाय पर, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबन्धों का सम्बन्ध इसके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के० पी० हार्मिस के, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कम्पनी 'केरल इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, का निदेशक होने पर रोक लगाते हैं।

[सं० 15(1)बी० ओ० III/76]

मे० भा० उसगांवकर, भ्रवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1976

S.O. 748.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to the Federal Bank Ltd., Alwaye, for a period of two years from the date of this notification, in so far as the said provisions prohibit Shri K. P. Hormis, its Chairman and Managing Director, from being a Director of the Kerala Industrial Development Corporation Ltd., Trivandrum, being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(1)-B.O. III/76]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1976

का० आ० 749.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसूचन में जनवरी 1976 के दिनांक 23 को समाप्त हुये सप्ताह के लिये लेखा दृशू विभाग

देयतायें	रुपये	रुपये	प्राप्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुये नोट	43,34,09,000		सोने का सिक्का और धुलियन:-		
संचलन में नोट	6317,40,91,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,51,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
जारी किये गये कुल नोट		6380,75,00,000	विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,48,000
			रुपये का सिक्का		16,07,40,000
			भारत सरकार की रुपया प्रति-		
			भूतियां		6040,41,48,000
			देशी धिनियम बिल और दूसरे		
			वाणिज्य-पत्र		
कुल देयतायें		6380,75,00,000	कुल प्राप्तियां		6380,75,00,000

दिनांक, 29 जनवरी, 1976

भार० के० गोवात्रि, उप गवर्नर

23 जनवरी, 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयतायें	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	बोट	43,34,09,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,88,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	छोटा सिक्का	6,55,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	खरीदे गये और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	(क) देशी	175,32,58,000
जमा राशियां:—		(ख) विदेशी	..
(क) सरकारी:		(ग) सरकारी खजाना बिल	303,12,10,000
(i) केन्द्रीय सरकार	64,10,90,000	विदेशों में रखा हुआ ऋण*	773,87,75,000
(ii) राज्य सरकारें	10,24,99,000	निवेश**	582,44,59,000
(ख) बैंक:		ऋण और अधिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	550,62,40,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,57,34,000	(ii) राज्य सरकारों को@	118,76,53,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,64,93,000	ऋण और अधिम:—	
(iv) अन्य बैंक	54,18,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	611,43,50,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	394,17,47,000
		(iii) दूसरों को	15,17,75,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अधिम और निवेश	
		(क) ऋण और अधिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,43,10,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,84,49,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वास और विकास निगम को	86,20,00,000
(ग) अन्य	1444,95,67,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,16,66,000
देय बिल	156,74,65,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अधिम	
अन्य देयतायें	886,73,00,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अधिम	93,09,76,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अधिम और निवेश:	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अधिम	351,61,38,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	508,06,88,000
	रुपये 4152,18,06,000		रुपये 4152,18,06,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ऋणरक्षापत्र शामिल हैं।

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दीयानी बिलों पर अधिम दिये गये 120,52,50,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

[सं० फा० 10(1)/76-बी प्रो० I]

आर० के० शेषाद्रि, उप गवर्नर

दिनांक, 29 जनवरी 1976

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 3rd February, 1976

S.O. 749.—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 for the week ended the 23rd day of January, 1976

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	43,34,09,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	6317,40,91,000		(a) Held in India	182,52,51,000	
Total notes issued		6360,75,00,000	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,48,000
			Rupees Coin		16,07,04,000
			Government of India		
			Rupee Securities		6040,41,48,000
			Internal Bills of		
			Exchange and other		
			Commercial paper		
Total Liabilities		6360,75,00,000	Total Assets		6360,75,00,000

Dated the 29th day of January, 1976.

R. K. SESHADRI, Deputy Governor

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 23rd January, 1976

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	43,34,09,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,88,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	6,55,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	175,32,58,000
Deposits:—		(b) External	
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	303,12,10,000
(i) Central Government	64,10,90,000	Balances Held Abroad*	773,87,75,000
(ii) State Governments	10,24,99,000	Investments**	582,44,59,000
(b) Banks		Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	550,62,40,000	(i) Central Government	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,57,34,000	(ii) State Governments††	118,76,53,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,64,93,000	Loans and Advances to:—	
(iv) Other Banks	54,18,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	611,43,50,000
(c) Others	1444,95,67,000	(ii) State Co-operative Banks@	394,17,47,000
Bills Payable	156,74,65,000	(iii) Others	15,17,75,000
		Loans, Advances and Investments from	
		National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to:—	
		(i) State Governments	69,43,10,000
		(ii) State Co-operative Banks	15,84,49,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	86,20,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,16,66,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	93,09,76,000
		Loans, Advances and Investments from	
		National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	351,61,38,000
		(b) Investment in bond/debentures issued by the Development Bank	
Other Liabilities	886,73,00,000	Other Assets	508,06,88,000
Rupees	4152,18,06,000	Rupees	4152,18,06,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 120,52,50,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

R. K. SESHADRI, Dy. Governor.

[No.F.10(1)/76—BO. I]

Dated the 29th day of January, 1976.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1976

क्रा० प्रा० 750.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी, 1976 के दिनांक 30 को समाप्त हुये सप्ताह के लिये लेखा दृष्टि विभाग

देयतायें	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुये नोट	41,58,17,000		सोने का सिक्का और मुलियत:-		
संचलन में नोट	6270,12,10,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,51,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6311,70,27,000	जोड़		304,26,48,000
			रुपये का सिक्का		17,02,61,000
			भारत सरकार की रुपया प्रति-		
			भूतियां		5990,41,18,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे		
			वाणिज्य पत्र		
कुल देयतायें		6311,70,27,000	कुल आस्तियां		6311,70,27,000

दिनांक : 4 फरवरी, 1976

क्र० प्रा० पुरी, गवर्नर

30 जनवरी, 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयतायें	रुपये	आस्तियां	रुपये
मुक्तता पूंजी	5,00,00,000	नोट	41,58,17,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,65,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	छोटा सिक्का	5,62,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	(क) देशी	170,43,98,000
जमा राशियां:-		(ख) विदेशी	..
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	294,28,90,000
(i) केन्द्रीय सरकार	55,66,89,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	829,50,01,000
(ii) राज्य सरकारों	11,48,89,000	निवेश**	523,29,48,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:-	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	566,43,65,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18,71,27,000	(ii) राज्य सरकारों को	126,58,90,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,62,26,000	ऋण और अग्रिम:-	
(iv) अन्य बैंक	82,38,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को X	670,54,50,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को X X	401,04,29,000
		(iii) दूसरों को	15,26,75,000
		राष्ट्रीय, कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण,	
		अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:-	
		(i) राज्य सरकारों को	69,43,11,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,73,97,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्बिल और विकास निगम को	86,20,00,000

देयतायें	रुपये	प्राप्तियाँ	रुपये
(ग) अन्य	1452,95,52,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको के डिबेचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	10,12,78,000 92,46,68,000
देय विल	144,53,27,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयतायें	944,05,97,000	ऋण, अग्रिम और निवेश (क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम (ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बॉण्डों/डिबें- चरों में निवेश	356,89,03,000
		अन्य प्राप्तियाँ	511,80,26,000
रुपये	4215,29,08,000	रुपये	4215,29,08,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थाई ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

× भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी धिलों पर अग्रिम दिये गये 106,75,00,000 रुपये शामिल हैं।

× × राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

के० आर० पुरी, गवर्नर

[सं० फ० 10 (1)/76 बी० प्रो० I]

अ० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव।

New Dehi, the 7th February, 1976

S.O. 750.—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 30th day of January, 1976

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	41,58,17,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	6270,12,10,000		(a) Held in India	182,52,51,000	
Total notes issued		6311,70,27,000	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	121,73,97,000	
			TOTAL		304,26,48,000
			Rupee Coin		17,02,61,000
			Government of India		
			Rupees Securities		5990,41,18,000
			Internal Bills of		
			Exchange and other		
			Commercial paper		..
Total Liabilities		6311,70,27,000	Total Assets		6311,70,27,000

Dated the 4th day of February, 1976.

K. R. PURI, Governor

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 30th January, 1976

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	41,58,17,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,65,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	5,62,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	170,43,98,000
Deposits:—		(b) External	..
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	294,29,90,000
(i) Central Government	55,66,89,000	Balances Held Abroad*	829,50,01,000
(ii) State Governments	11,48,89,000	Investments**	523,29,48,000
(b) Banks		Loans and Advances to:	
(i) Scheduled Commercial Banks	566,43,65,000	(i) Central Government	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	18,71,27,000	(ii) State Governments@	126,58,90,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,62,26,000	Loans and Advances to:—	
(iv) Other Banks	82,36,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	670,54,50,000
(c) Others	1452,95,52,000	(ii) State Co-operative Banks‡	401,04,29,000
Bills Payable	144,52,27,000	(iii) Others	15,26,75,000
Other Liabilities	944,05,97,000	(a) Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
Rupees	4215,29,08,000	(a) Loans and Advances to	
		(i) State Governments	69,43,11,000
		(ii) State Co-operative Banks	15,73,97,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance & Development Corporation	86,20,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,12,78,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	92,46,68,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	356,89,03,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	511,80,26,000
		Rupees	4215,29,08,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations), Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 106,75,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bill under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

K. R. PURI, GOVERNOR

[No- 10 (1)/76-BO 1]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

Dated the 4th day of Feb. 1976

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का०अ० 751.—जुलाई, 1974 से 30 जून, 1975 तक के वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कामकाज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट।

भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत सरकार को 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कामकाज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :—

1. 1974-75 में अर्थव्यवस्था का स्वरूप

प्रस्तावना : एक समग्र मूल्यांकन

1973-74 में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्या अभूतपूर्व मुद्रास्फीति थी। यह समस्या अन्य सारी समस्याओं पर हावी हो गयी थी। किन्तु 1974-75 में अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप विद्यमान था उसके मूल्यांकन से यह महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन लाया गया। जो राजकोषीय, मुद्रागत और प्रशासनिक उपाय किये गये उनसे पहले उच्च स्तरों पर पहुँचे हुए मूल्यों को कम किया जा सका और उनके साथ-साथ कच्चे माल की पूर्ति और परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने से पुनः औद्योगिक वृद्धि हो सकी। इससे देशी बचत में गिरावट आने के बावजूद निवेश के स्तर को बनाये रखा जा सका। विदेश व्यापार के क्षेत्र में भारत के व्यापार में गिरावट आने से भुगतान संबंधी भारी समस्या उत्पन्न हो गयी थी, किन्तु अंशतः नियत प्रामाणिकताओं के बढ़ने और अंशतः अधिक मात्रा में विदेशी वित्तीय सहायता के उपलब्ध होने से इस समस्या का समाधान भी हो सका।

2. अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में इन प्रयासों का जो महत्वपूर्ण योगदान था उसे पूर्ण रूप से समझने के लिए 1974-75 में अर्थव्यवस्था में पाये गये कार्य व्यापार की अलग से नहीं, किन्तु हाल ही के वर्षों की गतिविधियों के संदर्भ में समीक्षा करना आवश्यक है। यह स्मरण होगा कि 1971-72 से प्राकृतिक विपत्तियों से प्रमुखतः कमशर्तों वर्षों में कृषि उत्पादन में हुई भारी गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था सामान्य वृद्धि के मार्ग से हट गयी थी। अर्थव्यवस्था पर पाया गया यह तनाव शरणार्थियों की सहायता के लिए और सूखे की स्थितियों का सामना करने के लिए भारी मात्रा में किये गये राहत संबंधी परिषदों के बीच के कारण और बढ़ गया था। इसके बाद सारे विश्व में गंभीर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के साथ-साथ हमारे देश में भी मुद्रास्फीति के तत्व काफी बढ़ गये थे जिनसे 1972-72 और 1973-74 दोनों वर्षों में मूल्यों में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।⁽¹⁾ अतः 1974-75 में मुद्रास्फीति के इन बढ़ते हुए दबावों को नियंत्रित करने और भुगतान की भारी समस्या से उत्पन्न अत्यावधिक अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य विकास की दीर्घवर्षिक समस्या के समाधान की अपेक्षा बहुत ही प्राथमिकता देने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी थी।

3. वर्ष 1974-75 पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष था; अतः योजना प्रारूप में बचत, निवेश और विकास के लिए परिकल्पित विभिन्न लक्ष्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था का परीक्षण करने की इच्छा अवश्य होती है। किन्तु इस प्रकार परीक्षण करने पर उपलब्धियां

असंतोषजनक ही प्रतीत होंगी। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई जबकि 5.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित था। किन्तु योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य का मूल्यांकन करना अनुचित होगा; क्योंकि अर्थव्यवस्था को उपर्युक्त समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं के कारण दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया में बिलकुल बाधा पड़ी थी। बाधाओं और उर्वरकों के आयातों की मात्रा को काफी अधिक बढ़ाना पड़ा। अतः उनके विषयमूल्यों में हुई वृद्धि के कारण सूखे और बाढ़ों से 1974-75 में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कठिनाइयां और बढ़ गयीं। जब इस परिदृश्य में अर्थव्यवस्था का परीक्षण करते हैं तब उसमें सामान्य स्थिति लाने की दिशा में जो प्रगति हुई है वही महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है।

4. 1974-75 की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि मूल्य वृद्धि का स्तर कम हो गया था। 1973-74 में 25 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि (घोक मूल्य सूचकांक) हुई थी, किन्तु वर्तमान वर्ष में औसत मूल्यों में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।⁽²⁾ वास्तव में यदि वस्तुवार मूल्य वृद्धि की तुलना की जाए तो उक्त कमी और अधिक होगी। जून 1974 के अंत और जून 1975 के अंत के बीच घोक मूल्यों में केवल 0.6 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 27.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मार्च 1972 से मूल्यों में निरंतर जो वृद्धि होती रही वह वस्तुतः 1974-75 में गिरावट में परिणत हो गयी। वास्तविक गिरावट सितंबर 1974 के तीसरे सप्ताह और अप्रैल 1975 के पहले सप्ताह के बीच पायी गयी। कठोर मुद्रागत और राजकोषीय नीतियों के संचित प्रभाव के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट आयी। कुल मांग को सीमित करने के उद्देश्य से उक्त दोनों नीतियां अमल में लायी गयीं। इन नीतियों में जमाखोरी और तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से अपनाये गये कई प्रशासनिक उपायों से और तीव्रता लायी गयी।

5. राजकोषीय नीति के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं : व्यापक कर प्रयासों से बहुत अधिक वित्तीय साधन जुटाये गये, व्यय को कम करने में राजकोषीय अनुशासन अमल में लाया गया और उसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटे के परिमाण को कम किया गया। 1974-75 में केन्द्रीय सरकार ने 890 करोड़ रुपये की प्रतिरिक्त राशि जुटाई जो अभूतपूर्व थी। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये प्रयास राज्यों के प्रयासों द्वारा सशक्त किये गये। राज्यों के कुल मिलाकर 358 करोड़ रुपये जुटाये। वित्तीय साधन जुटाने के इन प्रयासों की प्रतिरिक्त शक्ति को कम करने के उद्देश्य से लागू किये गये दूसरे प्रयासों से और बल मिला। उक्त प्रयास इस प्रकार थे : प्रतिरिक्त महंगाई भत्ते के आधे भाग और मजदूरी तथा वेतन में होने वाली प्रायः सारी वृद्धि को जमा कर दिया गया, वितरणीय लाभ-राशि के लिए उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी और उच्चतर आय वर्गों में घाने वाले कर-शतांशों के लिए प्रतिबाध्य बचत की व्यवस्था की गयी। किन्तु विकासेतर व्यय के संबंध में सरकार द्वारा प्रतिरोधक कार्रवाई किये जाने के बावजूद खाद्यान्नों और उर्वरकों के लिए दी गयी सहायता, सरकारी कर्मचारियों को भत्ता किये गये महंगाई भत्ते, सूखा-राहत पर किये गये व्यय जैसे कई कारणों से 1974-75 में बजट घाटा बढ़कर 897 करोड़ रुपये हो गया।³ यद्यपि यह घाटा पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक था, फिर भी उसमें एक अंतर पाया गया। 1974-75 के घाटे में काफी अधिक मुद्रास्फीति रोधक तत्व पाये गये। उक्त घाटे के एक अंश का कारण यह था कि

(2) मासिक औसत : जुलाई-जून का आधार।

(3) वास्तव में बैंकों द्वारा सरकार को दिए गये ऋण में 1974-75 में 831 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो 1973-74 में हुई 957 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में कम थी (31 मार्च का आधार)।

(1) मासिक औसत : जुलाई-जून का आधार।

केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक से आयातों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गयी राशि से संचित विदेशी मुद्रा खरीदी थी। यदि इस तत्व को हटा दिया जाए तो घाटे का मुद्रास्फीतिकारक अंश और कम हो जाता है।

6. इन राजकोषीय प्रयासों को उत्पादन में बाधा डालने बिना व्यय को कम करने के उद्देश्य से किये गये मुद्रागत प्रयासों के और बल मिला। ऋणनीति को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया गया। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है कि जुलाई 1974—जून 1975 के वर्ष में बैंक ऋण में 1105 करोड़ रुपयों या 14 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह 1973-74 में हुई 1446 करोड़ रुपयों या 23 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। सकल ऋण (पुनः भुनाई गयी ढुंडियों सहित) की दृष्टि से उक्त वृद्धि और कम अर्थात् केवल 12 प्रतिशत थी जबकि वह पिछले वर्ष 27 प्रतिशत थी। वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के 91 प्रतिशत के स्तर से कम होकर केवल 69 प्रतिशत हो गया।

7. 1974-75 की ऋणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि व्याज-दर मुद्रा प्रबंध के उल्लेखनीय साधन के रूप में उभर आयी। ऋण की मांग को न केवल रिजर्व बैंक से ली जाने वाली सहायता को सीमित कर, बल्कि ऋण की व्याज दर को बढ़ाकर भी नियंत्रित करने की व्यवस्था की गयी। जुलाई 1974 में बैंक दर को बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर देने के परिणामस्वरूप ऋण के प्रयोग में अनुशासन लाने और जमा-राशि जुटाने के कार्य में सहायता पहुँचाने के दुहरे लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ समग्र व्याज दरों में भी वृद्धि की गयी। ऊपर बैंक ऋण के विस्तार की धीमी गति का जो उल्लेख किया गया वह इस संदर्भ में लागू किये गये अनुशासन का द्योतक है और 1974-75 में मीयादी जमा-राशियों में जो उच्चतर वृद्धि हुई वह जमा-राशि जुटाने के प्रयास का परिचायक है।

8. इन प्रतिबन्धक राजकोषीय और मुद्रागत नीतियों के प्रभावस्वरूप मुद्रा विस्तार की दर में उल्लेखनीय मंदी पायी गयी। जुलाई 1974 से जून 1975 तक की अवधि के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 1973-74 की तुलना में 725 करोड़ रुपयों या 6.3 प्रतिशत की न्यून वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1973-74 में पायी गयी 1488 करोड़ रुपयों या 14.9 प्रतिशत की वृद्धि के आधे से कम थी। वास्तव में इस वर्ष मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि की दर पिछले चौदह वर्षों में हुई वृद्धि के संदर्भ में न्यूनतम थी।

9. मुद्रा उपलब्धि के एक घटक अर्थात् चल मुद्रा की प्रवृत्ति अधिक उल्लेखनीय थी। 1974-75 में उसमें 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। देशी नीतियों के प्रभाव के अलावा विदेशी मुद्रा भास्तिथियों के निकाले जाने से भी मुद्रा विस्तार में मंदी आयी। यह तत्व वास्तव में मुद्रा उपलब्धि में कमी लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अकेला तत्व था। यह तत्व न केवल सामान्य रूप से मुद्रा विस्तार की न्यूनतर दर का कारण है, बल्कि विशेष रूप से चल मुद्रा के विस्तार की दर में पायी गयी तीव्र गिरावट का भी कारण है।

10. विदेश व्यापार के क्षेत्र में यद्यपि 1974-75 के वित्तीय वर्ष के दौरान 29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई फिर भी आयातों में धीरे-धीरे से 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे व्यापार क्षेत्र की खार्ह व्यापक हो गयी। 1096 करोड़ रुपयों का अनुमानित व्यापार घाटा 1973-74 के 402 करोड़ रुपयों के घाटे के तुलने से अधिक था। आयातों के मूल्य में हुई वृद्धि का अधिकांश भाग प्रमुख रूप से ईंधन, खाद्यान्नों और उर्वरकों के आयातों में पाया गया। मुख्यतः व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप वर्ष 1974-75 भुगतान संतुलन के भारी घाटे के साथ समाप्त हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गयी राशियों और विदेशी सहायता

के रूप में अधिक मात्रा में प्राप्त वित्तीय साधनों ने उक्त घाटे का वित्तपोषण किया गया। प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों जहाँ मार्च 1974 में 947 करोड़ रुपये थी वहाँ मार्च 1975 में थोड़ी सी बढ़ाकर 969 करोड़ रुपए हो गयी जो भारी मात्रा में प्राप्त विदेशी वित्त के समक्ष महत्वहीन थी।

11. 1974-75 में विदेशी मुद्राओं में जो राशि प्राप्त हुई वह 1973-74 की अपेक्षा लगभग 649 करोड़ रुपए अधिक थी। इसमें से 423 करोड़ रुपए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाले गये और 226 करोड़ रुपए विदेशी सहायता के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए। इस प्रकार अधिक मात्रा में प्राप्त अतिरिक्त वित्तीय साधनों से देशी अर्थव्यवस्था में काफी अधिक स्थायिता लायी जा सकी। 1974-75 में खाद्यान्नों के अपेक्षाकृत अधिक आयात किये जाने से खाद्यान्नों की कुल पूर्ति के स्तर को बनाये रखा जा सका। इस प्रकार यदि भारी आयात नहीं किये गये होते तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखना कठिन हो गया होता। चूंकि वसूली के न्यूनतर स्तर के बावजूद खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण को सन्तोषजनक स्तर पर रखा गया, अतः मूल्य वृद्धि पर सन्तोषजनक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा 1974-75 में खाद्यान्नों के कुल सार्वजनिक वितरण में आयातित खाद्यान्नों का अंश अधिक था; अतः खाद्यान्नों की बिक्री से प्रारम्भिक मुद्रा में अतः कमी आयी। समग्र रूप से अधिक मात्रा में विदेशी वित्त प्राप्त नहीं हुआ तो यह संभव था कि 1974-75 में अमल में लायी गयी राजकोषीय और मुद्रागत नीतियाँ कम प्रभावकारी सिद्ध होतीं।

12. आगे शैक्षीय विकास, राजकोषीय और मुद्रागत नीतियों, मूल्यों की प्रवृत्तियों, वस्तु और निवेश तथा विदेशी क्षेत्र की भूमिका का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम खण्ड में उपलब्ध निर्वेशकों के आधार पर 1975-76 के विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय आय, कृषि और औद्योगिक विकास

राष्ट्रीय आय

13. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्रकाशन अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्यों के अनुसार) में 1973-74 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1972-73 में उसमें 0.9 प्रतिशत की वास्तविक गिरावट आयी थी। यद्यपि 1974-75 के लिए राष्ट्रीय आय के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आय में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि-दर का जो लक्ष्य निर्धारित है उससे तुलना करने पर वास्तविक वृद्धि निश्चित रूप से असन्तोषजनक है। यह वृद्धि पिछले वर्ष हुई 3 प्रतिशत वृद्धि के अनु रूप में नहीं है। किन्तु इसका महत्व इस बात में है कि क्रमशः दूसरे वर्ष निश्चित रूप से थोड़ी-सी वृद्धि-दर जारी रही है और इससे अर्थव्यवस्था में स्थायिता आ सकी है जबकि इसके पूर्व के दो वर्षों में प्रमुखतः प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न समस्याओं के कारण राष्ट्रीय आय की सामान्य वृद्धि के मार्गों में बाधा पड़ी थी।

कृषि उत्पादन

14. 1974-75 में राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर में जो गिरावट आयी उसका कारण कृषि क्षेत्र में पायी गयी गिरावट की है। 1972-73 में प्रति धोर मांग के बीच भारी असन्तुलन पाया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर खाद्यान्नों का उत्पादन थोड़ा-सा सन्तोषजनक था। फिर भी ऐसा

जतीत होता है कि 1974-75 के दौरान कुल कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सीमान्त गिरावट आयी। इसका प्रमुख कारण यह था कि पटसन के उत्पादन में भारी गिरावट और तिलहनों के उत्पादन में कुछ हद तक कमी आयी।

15. वर्ष 1974-75 में सूखे और बाढ़ की स्थिति पायी गयी। इन प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बावजूद खाद्यान्नों के कुल उत्पादन की मात्रा 1040 लाख से 1050 लाख मी० टन तक होने का अनुमान है जो 1973-74 में हुए 1036 लाख मी० टन के उत्पादन की तुलना में सन्तोषजनक है। यह उत्पादन इस वर्ष के लिए निर्धारित 1180 लाख मी० टन के लक्ष्य से काफी कम है। कुल खरीफ अनाजों का उत्पादन 620 लाख मी० टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 47 लाख मी० टन कम था। जहाँ 400 लाख से 410 लाख मी० टन तक का खरीफ ज्वारल उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर पर ही था वहाँ बाजरे के उत्पादन की मात्रा 70 लाख मी० टन से कम होकर

40 लाख मी० टन हो गयी। इस प्रकार कुल उत्पादन में हुई कमी का अधिकांश भाग बाजरे के उत्पादन में पाया गया। खरीफ फसल में हुई यह कमी खरी अनाजों के अग्रिक उत्पादन से अधिक समायोजित हो गयी। खरी अनाजों का कुल उत्पादन 420 लाख से 430 लाख मी० टन तक के स्तर तक पहुँचने का अनुमान है जो पिछले मौसम के उत्पादन की अपेक्षा 50 लाख से 60 लाख मी० टन तक अधिक है। प्रायः सभी क्षेत्रों में बुवाई के प्रारम्भ से ही अनुकूल वर्षा और मौसम होने से और गेहूँ के उत्पादक प्रमुख दो राज्यों, अर्थात् पंजाब और हरियाणा में कृषि के लिए समय पर बिजली प्रदान किये जाने से उच्चतम मात्रा में उत्पादन हुआ। कुल खरी उत्पादन में से गेहूँ का उत्पादन 270 लाख मी० टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 220 लाख मी० टन था। हाल ही के वर्षों में चुने गये पण्यों का जो उत्पादन हुआ था उसके आंकड़े सारणी 1 में दिये गये हैं।

सारणी 1 : कृषि उत्पादन : चुने गए पण्य

	यूनिट	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
					(अनुमानित)
कुल खाद्यान्न	दस लाख मी० टन	105.2	97.0	103.6	104.0—105.0
खरीफ खाद्यान्न	"	63.0	58.6	66.7	62.0
खरी खाद्यान्न	"	42.2	38.4	36.9	42.0—43.0
दालों से भिन्न अनाज	"	94.1	87.1	93.9	अनु०
चावल	"	43.1	39.2	43.7	अनु०
गेहूँ	"	26.4	24.7	22.1	27.0
दालें	"	11.1	9.9	9.7	अनु०
खाद्यान्नेतर पण्य				5.8	—
रई	दस लाख गांठें	6.6	5.4	(6.8@)	(7.0@)
	प्रति गांठ 180 कि० ग्राम				
जूट और मेस्ता	"	6.8	6.0	7.3@@	5.5*
तिलहन	दस लाख मी० टन	8.7	6.9	8.7	—
मूंगफली	"	6.2	4.1	(8.9@)	(8.3@)
				5.8	—
				(6.0@)	(5.0@)
गन्ना (गुड़ के रूप में)	"	11.6	12.8	14.0	अनु०

*अन्य अनुमान।

@आयात क्षेत्र के अनुमान।

@@आंशिक रूप से परिशोधित अनुमान।

अनु० = अनुपलब्ध

16. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1974-75 में कृषि उत्पादन में जो गिरावट आयी वह बाणिज्यिक फसलों में पायी गयी, किन्तु इस सन्दर्भ में भी गिरावट पण्यवार अलग-अलग प्रकार की थी। अस्थायी अनुमानों के अनुसार रुई के उत्पादन की मात्रा 67.5 लाख गांठों से सीमान्त रूप से बढ़कर 69.5 लाख गांठों हो जाने की आशा है और चीनी के उत्पादन की मात्रा 1973-74 के 39 लाख मी० टन के मुकाबले में 48 लाख मी० टन तक पहुंचने की संभावना है। चाय के उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है। इसके विपरीत पांच प्रमुख तिलहनों के उत्पादन की मात्रा पिछले वर्ष के 89 लाख मी० टन के मुकाबले में कम होकर 83 लाख मी० टन होगी। उत्पादन में पायी गयी गिरावट पटसन और मेस्ता के मामले में अपेक्षाकृत अधिक थी। उनके उत्पादन की मात्रा जहाँ 1973-74 में 73 लाख गांठें थीं वहाँ इस वर्ष 55 लाख गांठें हो जाने की संभावना है।

वसूली और सार्वजनिक वितरण

17. खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर 1974-75 के दौरान काफी अधिक दबाव पड़ा। इसका कारण यह था कि देशी उत्पादन में लगभग स्थिरता आ गयी थी और विशेष रूप से वसूली की मात्रा भी अपर्याप्त थी। इस सन्दर्भ में वसूली नीति में पायी गयी प्रमुख गतिविधियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 1974-75 (नवम्बर-अक्तूबर) के वसूली मौसम में खरीफ खाद्यान्नों के सन्दर्भ में वसूली नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने धान की मानक किस्म की वसूली के मूल्य को प्रति क्विंटल 70 रु० से बढ़ाकर 74 रु० कर दिया। ज्वार, मकई, रागी और बाजरे का वसूली मूल्य प्रति क्विंटल 74 रु० निर्धारित किया गया जबकि पिछले वर्ष ज्वार, मकई और रागी का मूल्य 70 रु० और बाजरे का मूल्य 72 रु० था। 1973-74 में 43 लाख मी० टन के खरीफ अनाजों की वसूली की गयी थी। 1974-75 के मौसम में 15 जुलाई, 1975 तक 35 लाख मी० टन के खाद्यान्नों की वसूली की गयी।

18. गेहूँ की वसूली के सन्दर्भ में वसूली नीति में प्रमुख परिवर्तन हुआ। 1974-75 के रबी मौसम (अप्रैल-मार्च) के लिए थोक व्यापार के सरकारी एकाधिकार की नीति को छोड़ दिया गया और निजी थोक व्यापारियों तथा सहकारी संस्थाओं को लाइसेंस और नियंत्रण प्रणाली के अधीन व्यापार कार्य करने की अनुमति दी गयी। इस प्रणाली के अधीन थोक व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे अपने द्वारा खरीदे गये गेहूँ के 50 प्रतिशत को प्रति क्विंटल 105 रु० के निश्चित मूल्य पर सरकार को दे दें। शेष 50 प्रतिशत को थोक व्यापारी खुले बाजार के मूल्यों पर बेच सकते हैं जिनपर कतिपय अधिकतम सीमाएं प्रवण्य लागू होंगी। यह आशा की गयी कि निजी व्यापारी/थोक व्यापारी सार्वजनिक वितरण के लिए लगभग 50 लाख मी० टन गेहूँ प्रदान करेंगे। न केवल व्यापारी इस वायिख की पूर्ति करने में जुक गये, बल्कि ऐसे भी संकेत प्राप्त हुए कि किसानों और व्यापारियों ने लेवी से बचने के लिए बाजार में गेहूँ के आगमन की मात्रा को झूठमूठ दिखाया था। वसूली के प्रति किसानों और व्यापारियों की इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप गेहूँ की कुल वसूली की मात्रा पिछले मौसम के 43 लाख मी० टन से घटकर 19 लाख मी० टन हो गयी। वसूली में इस प्रकार काफी अधिक मात्रा में कमी आ जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिकतर आयातों के द्वारा व्यवस्थित करना पड़ा। 1974 के दौरान खाद्यान्नों के आयातों की मात्रा को बढ़ाकर 49 लाख⁽⁴⁾ मी० टन कर दिया गया जबकि 1973 में उक्त मात्रा 36 लाख मी० टन थी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1974 में वितरित कुल मात्रा को 1973 के 110 लाख मी० टन के स्तर पर बनाये रखा गया। इसके अलावा जनवरी-जून,

1975 के दौरान भी अधिक आयात किये गये; अर्थात् जहाँ जनवरी-जून 1974 में 25 लाख मी० टन के आयात किये गये थे वहाँ जनवरी-जून 1975 में 35 लाख मी० टन के आयात किये गये। जनवरी-जून 1975 के दौरान सार्वजनिक वितरण की मात्रा 57 लाख मी० टन थी जो 1974 की उसी अवधि में वितरित 52 लाख मी० टन की तुलना में अधिक थी।

वसूली नीति : 1975-1976

19. 1975-76 के रबी मौसम (अप्रैल-मार्च) की वसूली नीति की प्रमुख रूपरेखा का विवरण भागे प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि गेहूँ का वसूली मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति क्विंटल 105 रु० बना रहेगा फिर भी केन्द्रीय सरकार ने एक बोनस योजना बनायी है। जिन राज्यों में गेहूँ की वसूली की जाएगी वहाँ की सरकारों को प्रति क्विंटल 4.75 रु० का औसत बोनस भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकारें इस प्रकार प्राप्त बोनस का उपयोग किसानों को वस्तुओं के रूप में अर्थात् कम दाम के उर्वरकों, बीजों, डीजल तेल आदि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए करेंगी। इस मौसम की वसूली का लक्ष्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 55 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है। जुलाई 1975 के मध्य तक की गयी वास्तविक वसूली की मात्रा 36 लाख मी० टन⁽⁵⁾ थी। यह मात्रा 1974-75 की पूरी अवधि में की गयी 19 लाख मी० टन की वसूली की तुलना में काफी अधिक थी।

20. इसके अलावा राज्यों के बीच गेहूँ की आवाजाही पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये उन्हें प्रत्येक राज्य को एक अनलग क्षेत्र के रूप में मानकर जारी रखा जाएगा। अतः केन्द्रीय सरकार के लिए होने वाली आवाजाही के सिवाय गेहूँ की कोई आवाजाही राज्य के बाहर नहीं होने दी जाएगी। इस बात पर निर्णय करने का भार अलग-अलग राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वसूली की प्रणाली क्या हो अर्थात् गेहूँ विनियमित बाजारों में खरीदा जाए और/या लेवी प्रणाली द्वारा।

औद्योगिक उत्पादन

21. औद्योगिक क्षेत्र का कार्य कृषि क्षेत्र की तुलना में थोड़ा बहुत बेहतर था। 1974 में 3 प्रतिशत के आसपास जो वास्तविक वृद्धि हुई वह यद्यपि प्रवण्य महत्वपूर्ण थी फिर भी वह इस कारण उल्लेखनीय है कि 1973 में औद्योगिक क्षेत्र में अर्धस्थायिता की जो स्थिति विद्यमान थी उसके मुकाबले में इस वर्ष सुधार परिलक्षित हुआ।

22. औद्योगिक उत्पादन से संबंधित आंकड़े केवल सितम्बर 1974 तक उपलब्ध हैं; जनवरी-सितम्बर 1974 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आधार 1970) के मासिक औसत स्तर⁽⁶⁾ में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1973 की तदनुसृत अवधि में उसमें केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपलब्ध अधिम निर्येशकों से यह संकेत मिलता है कि 1974 में औद्योगिक उत्पादन में 3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई

(5) 1975-76 विपणन मौसम में से।

(6) हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, वाशिंगटन ने औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को 1970 को आधार बनाकर परिणोदित किया है। परिणोदित आंकड़े केवल सामान्य सूचकांक से संबंधित हैं। 1970 के आधार पर अलग-अलग उद्योगों और उद्योग-समूहों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। अतः समूहवार और उद्योगवार उत्पादन-प्रवृत्तियों का विश्लेषण 1980 के पुराने आधार पर किया गया है। ये आंकड़े जुलाई 1974 तक उपलब्ध हैं।

(4) ये आंकड़े कैंलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।

जबकि 1973 में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक विकास में पायी गयी मन्दी के अनेक कारण थे। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार थे: देश के विभिन्न भागों में बिजली और ईंधन की कमी की स्थिति बराबर विद्यमान थी; परिवहन संबंधी बाधाएं पायी गयीं, अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेषकर कृषि-जन्य कच्चे माल का अभाव था और श्रमिक अशांति विद्यमान थी। इन कारणों से अनेक उद्योगों में स्थापित क्षमताओं का न्यून उपयोग किया गया। मूल वस्तुओं के प्रतिरोधों के अभाव में 1974 में औद्योगिक विकास और अधिक उल्लेखनीय हो

सका। 1974 में औद्योगिक विकास में केवल पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक था, बल्कि अपेक्षाकृत अधिक व्यापक भी था। जिन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि पायी गयी उनका कुल वजन 1973 के 34 प्रतिशत से बढ़कर 1974 में 60 प्रतिशत हो गया। किन्तु जिन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट पायी गयी उनका वजन 1973 के 63 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गया (सारणी 2)।

सारणी: 2 वृद्धिदरों के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण

वृद्धि दरों का स्वरूप@		सामान्य सूचकांक के वजन के अनुसार (आधार : 1960 = 100)				
		पूरा वर्ष			जनवरी-जुलाई	
		1971	1972	1973	1973	1974 ×
1		2	3	4	5	6
अ. वृद्धि						
1.	सामान्य : 5 प्रतिशत से कम	27.99	31.98	20.57	25.11	16.78
2.	उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और अधिक	31.96	55.16	12.74	8.97	42.74
उसमें से :						
10	प्रतिशत और अधिक	15.72	15.89	7.18	7.57	13.21
3.	वजन (1+2)	59.95	87.14	33.31	34.08	59.52
आ. कमी :						
4.	सामान्य : 5 प्रतिशत से कम	19.98	5.53	42.93	39.29	20.97
5.	उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और अधिक	17.59	4.85	20.65	23.52	16.40
उसमें से :						
10	प्रतिशत और अधिक	5.30	1.99	6.01	7.60	9.10
6.	वजन (4+5)	37.57	10.38	63.58	62.81	37.37
इ. स्थायी		0.63	0.63	0.63
कुल वजन (अ+आ)		97.52*	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*

@वृद्धि की दरें संबंधित पूर्व वर्षों की तुलना में उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि की द्योतक हैं।

× अंतिम।

*केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन वजन के योग 2.48 प्रतिशत के साथ उद्योगों के सूचकांक को नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करता।

23. विभिन्न वर्षों के उद्योगों की प्रवृत्तियां सारणी 3 के आंकड़ों से विवृत हो सकती हैं। मूल उद्योगों, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन में क्रमशः 1.8 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल उद्योगों के मामले में जो वृद्धि हुई वह अधिकांशतः कोयले और बिजली के उत्पादन में हुई। किन्तु सीमेंट के उत्पादन में क्रमशः दूसरे वर्ष भी तेजी से गिरावट आयी। भारी प्रकाशिक रसायनों, एल्यूमिनियम तथा पीतल की चीजों के उत्पादन में भी कमी आयी। मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योगों में से सूत की कटाई, किटिंग, फिक्सचर और जुड़नारों, टायर और ट्यूब, पेट्रोलियम परिष्करण-शालाओं में बननेवाली वस्तुओं, संरचना, संबंधी मिट्टी की वस्तुओं तथा बेटरियों के उत्पादन में 5.6 प्रतिशत और 59.6 प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के मामले में परिष्कृत चीनी और चाय के उत्पादन में क्रमशः 11.1 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिन अन्य उद्योगों में उत्पादन संबंधी वृद्धि हुई उनमें कागज और कागज से बनी चीजों, परिष्कृत रसायनों और औषधीय

वस्तुओं, साबुन और धुलाई तथा सफाई की दूसरी मिश्र वस्तुओं, धातु की बनी चीजों और संचार उपकरणों के उद्योग भी सम्मिलित थे। किन्तु वनस्पति, सूती वस्त्रों की बुनाई और जूते (रबड़) जैसी कतिपय जनसामान्य के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा कम थी।

24. इसके विपरीत पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में जनवरी-जुलाई 1974 के दौरान 2.3 प्रतिशत की गिरावट पायी गयी जबकि 1973 की तुलना में उसमें 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यद्यपि उक्त गिरावट अधिकांश उद्योगों में पायी गयी फिर भी उनमें से अधिक स्पष्ट उद्योग रेल-सड़क उपकरणों, मोटर-गाड़ियों और मशीनी उपकरणों और पुर्जों के उत्पादन से संबंधित थे जिनका अंश पूंजीगत वस्तुओं के सभी उद्योगों के कुल वजन के भांश से अधिक था। रेल-सड़क उपकरणों के उत्पादन में प्रमुख रूप से रेलवे के माल डिब्बों के उत्पादन में कमी के कारण गिरावट आयी।

सारणी : 3 समूहवार औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियाँ (आधार 1960=100)

(औद्योगिक उत्पादन संबंधी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सूचकांक पर आधारित)

(वर्ष के दौरान घट-बढ़ : प्रतिशत)

समूह	वर्ष	1970	1971	1972	1973	जनवरी-जुलाई*	
						1973	1974
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सूचकांक (असंशोधित)	100.00	+4.8	+2.9	+7.1	+0.7	-0.2	+2.3
उपयोग पर आधारित वर्गीकरण							
1. मूल उद्योग	25.11	+4.6	+5.5	+8.8	-1.5	-1.3	+1.8
2. पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग	11.76	+5.0	-0.1	+8.6	+12.4	+13.9	-2.3
3. मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग	25.88	+2.8	+1.0	+6.7	+2.2	-0.8	+6.0
4. उपभोग्यता वस्तुओं के उद्योग	37.25	+6.5	+3.2	+5.3	-3.7	-5.0	+3.8
मूल वस्तुओं पर आधारित वर्गीकरण							
1. कृषि आधारित उद्योग	44.08	+4.5	-0.3	+5.1	-1.8	-2.8	+2.2
2. धातु आधारित उद्योग	16.55	+5.7	+2.5	+7.0	+6.6	+7.9	+0.4
3. रसायन आधारित उद्योग	8.94	+8.0	+6.9	+12.9	+2.7	-1.0	+3.2
क्षेत्रीय निर्देशक							
1. परिवहन उपकरण और संबद्ध उद्योग	10.90	--	+0.5	+6.4	+6.5	+4.0	+5.3
2. बिजली और संबद्ध उद्योग	8.42	+11.5	+9.0	+8.4	-1.0	-3.0	+5.8

*अप्रतिम।

25. औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि के आकार और व्यापकता को देखने पर कुछ क्षेत्रों में पायी गयी यह धारणा सही सिद्ध नहीं होती कि औद्योगिक क्षेत्र में सामान्यतः मंदी की प्रवृत्ति विद्यमान थी। जिन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट पायी गयी उनमें भी विकास के बाधक तत्व अक्सर बिजली और परिवहन की कठिनाइयाँ और कृषि-जन्य कच्चे माल की कमी रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इंजीनियरी उद्योगों और जूट के वस्त्रों के उद्योग में मांग की कमी के कारण मंदी की प्रवृत्ति आयी। किन्तु यह भी सही है कि जूट की वस्तुओं के उद्योग क्षेत्र की समस्या का प्रांशिक कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य प्रतियोगियों की तुलना में हमारे मूल्य का अधिक होना है। कपड़ों की देशी मांग में जो मंदी पायी गयी वह उच्चतर मूल्यों के प्रति परिलक्षित उपभोक्ताओं के विरोध का परिणाम भी हो सकती है। इस प्रकार इन कतिपय उद्योगों में भी व्यापार की कमी का कारण न केवल मांग की कमी थी, बल्कि इसके अन्य कारण भी थे।

26. वस्तुतः 1974 के अन्त में औद्योगिक विकास की गति में तेजी के संकेत पाये गये हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बिजली उत्पादन, इस्पात और कोयले के उद्योगों जैसे कुछ क्रोड़ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई और नूँक यह क्षेत्र दूसरे उद्योगों के विकास का प्रमुख आधार है अतः यह स्पष्ट है कि 1975-76 के दौरान तेजी से औद्योगिक विकास होगा।

राजकोषीय नीति और मांग प्रबंधन

27. पिछले खंड में खाद्यान्नों के उत्पादन के स्तर को अधिक आयातों द्वारा सीमान्त रूप से उच्चतर बनाये रखने और औद्योगिक उत्पादन में सुधार किये जाने के संबंध में विमर्श किया गया है। किन्तु इनसे अर्थव्यवस्था में पूर्ति और मांग के बीच विद्यमान असंतुलन पूर्णरूप से

दूर नहीं हुआ। वास्तव में पिछले वर्ष मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व दरों में थोड़ी-सी गिरावट आने के बावजूद 1974 में मांग के दबाव चिन्ता के विषय बने रहे। अतः यह अत्यावश्यक हो गया कि इन दबावों को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय और मुद्रागत नीतियों को और सशक्त किया जाए।

बजट घाटा :

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें

28. 1974-75 की राजकोषीय नीति में बजट घाटे को कम करने पर अधिक बल दिया गया। किन्तु सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने, अधिक मात्रा में खाद्य सहायता प्रदान करने, अधिक मात्रा में उर्बरक खरीदने और पूंजी निर्माण पर अतिरिक्त परिव्यय करने के कारण कुल व्यय बजट में प्रत्याशित व्यय से काफी अधिक बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप 1974-75 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 1048 करोड़ रुपयों के अत्याधिक वित्तीय साधनों के जुटाये जाने के बावजूद उनके संयुक्त घाटे की राशि 1974-75 में 727 करोड़ रुपए⁽⁷⁾ हो गयी जो 1973-74 की अपेक्षा 234 करोड़ रुपए अधिक थी। नूँक

(7) भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के आधार पर अनुमानित उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1974-75 के समय संयुक्त घाटे की राशि 727 करोड़ रुपए होती है। इसमें केन्द्रीय सरकार के 697 करोड़ रुपए (बकाया राजकोषीय बिलों में हुई शुद्ध वृद्धि और नकदी जमा में हुई घट-बढ़ के कारण उत्पन्न) और राज्य सरकारों के 30 करोड़ रुपए (रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार नकदी जमा, रिजर्व बैंक से किये गये अर्थ-पाय अधिमों और राजकोषीय बिलों के रूप में धारित निधियों में हुई घट-बढ़ के कारण उत्पन्न) शामिल हैं।

727 करोड़ रुपयों के इस घाटे के प्रमुख प्राप्तिधों और वितरणों के विवरण उपलब्ध नहीं है अतः भाग का विश्लेषण 1971-75 के परिशोधित अनुमानों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 567 करोड़ रुपयों का संयुक्त बजट घाटा⁽⁸⁾ (परिशोधित अनुमान) 1973-74 की अपेक्षा (547 करोड़ रुपयों) केवल सीमान्त रूप से अधिक था। किन्तु घाटे की राशि वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजटों में परिकल्पित 110 करोड़ रुपयों की अपेक्षा काफी अधिक थी। (सारणी 4)।

29. यद्यपि 1974-75 में केन्द्रीय सरकार के घाटे की राशि प्रत्यक्ष मात्रा से अधिक थी फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गयी राशि से संचित जिस विदेशी मुद्रा वित्त को केन्द्रीय सरकार ने आयातों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से खरीदा था उसमें उक्त वृद्धि का अधिकांश भाग पाया गया। यह एक ऐसा घटक है जिससे मुद्रास्फीति नहीं होती।

30. 1974-75 में किये गये संयुक्त कुल वितरण 1973-74 की अपेक्षा 19.2 प्रतिशत अधिक थे। वितरणों में अधिकांश वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई: खाद्य सहायता के लिए अधिक राशि वितरित की गयी; उर्वरकों के लिए अधिक राशि बाहर गयी; सरकारी कर्मचारियों की अतिरिक्त महंगाई भत्ता अदा किया गया; श्रद्धा क्षेत्र की परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि हुई राज्यों की सूखा-राहत के लिए अग्रिम योजना सहायता प्रदान की गयी; और असाधारण रूप से भारी रेलवे घाटे की विस्तृति भी गयी। विकासेतर व्यय में 17.7 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह विकास व्यय में हुई 16.6 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी। कुल प्राप्तिधों में 1973-74 की अपेक्षा 2573 करोड़ रुपयों अथवा 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल प्राप्तिधों में हुई वृद्धि का 31.1 प्रतिशत ग्रंथ विकासेतर व्यय के बढ़ जाने से उसमें खप गया।

वित्तीय साधनों का संचयन :

केन्द्रीय सरकार⁽⁹⁾

31. फरवरी 1974 में जब 1974-75 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया उसके थोड़े समय के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि खाद्यान्न संबंधी सहायता, महंगाई भत्ते की अदायगी और सूखा-राहत की अपेक्षाओं के कारण बजट घाटा तक तब प्रत्याशित मात्रा से अधिक ही होगा जब तब अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के कदम नहीं उठाये जाते। अतः केन्द्रीय सरकार ने जुलाई 1974 के अन्त में एक पूरक बजट पेश किया जिससे इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान अतिरिक्त करों द्वारा और 136 करोड़ रुपयों तथा पूरे वर्ष में फरवरी 1974 के बजट में प्रस्तावित 211 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त कराधान से अधिक 232 करोड़ रुपयों जुटाये जाएंगे। इसके बावजूद पूरक रेलवे बजट भी पेश किया गया जिसमें रेलवे के बढ़ते हुए व्यय का वित्तपोषण करने के लिए माल-भाड़े और सवारी किराये की दरों में वृद्धि की गयी। कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा 1974-75 में जुटाये गये अतिरिक्त वित्तीय साधनों से 1974-75 में 690

करोड़ रुपयों⁽¹⁰⁾ और पूरे वर्ष में 935 करोड़ रुपयों प्राप्त होने की आशा है (रेलवे सवारी किराये, माल भाड़े की दरों और डाक दरों में किये गये परिवर्तनों से प्राप्त होनेवाली राशि इनमें शामिल है)। इस प्रकार पांच वर्षों की अवधि में केवल इन प्रयासों से पांचवीं योजना में परिकल्पित राशि से अधिक राशि प्राप्त होगी।

32. 1974-75 में कुल प्राप्तिधों में बालू प्राप्तिधों, पूंजीगत अन्तरण, ऋणों की चुकोतियां और विभागीय प्रतिष्ठानों के आन्तरिक साधन सम्मिलित हैं और उनकी राशि 7365 करोड़ रुपयों है। इन प्राप्तिधों से 1974-75 के कुल व्यय के 75.5 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया। कुल व्यय और कुल प्राप्तिधों के बीच 2388 करोड़ रुपयों की जो खाई थी उसमें से 847 करोड़ रुपयों का वित्तपोषण देशी ऋणों से और 916 करोड़ रुपयों का वित्तपोषण विदेशी ऋणों से किया गया। शेष 625 करोड़ रुपयों का वित्तपोषण घाटे⁽¹¹⁾ की वित्तव्यवस्था से किया गया। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, घाटे की वित्तव्यवस्था की मात्रा 1974-75 के बजट अनुमानों में प्रत्याशित मात्रा से 125 करोड़ रुपयों अधिक थी और 1973-74 के 328 करोड़ रुपयों की तुलना में लगभग तुलनी थी।

33. पूर्वोक्त प्रकार से इस घाटे का देशी प्रभाव खाद्यान्नों और उर्वरकों के लिए की गयी अदायगियों के कारण कम मुद्रास्फीतिकारक होगा। सरकार ने भी सांग-प्रबन्धन की अपनी विभिन्न समय नीतियों के ग्रंथों के रूप में अतिरिक्त महंगाई भत्तों के अग्रशोध तथा मजदूरी और वेतन में परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न पूरी वृद्धि को अपने पास जमा रखकर और उच्चतर आय वर्गों के करदाताओं के लिए अनिवार्य जमाराशियों तथा कंपनियों द्वारा लाभांशों के संवंध में की जानेवाली घोषणा पर प्रतिबन्धों की व्यवस्था कर उपभोक्ताओं की व्यय योग्य आय पर नियंत्रण रखने के प्रयास किये। इस प्रकार व्यय किये जाने से रोकी गयी जमाराशियां 27 जून 1975 को महंगाई भत्तों, अतिरिक्त वेतन (वेतन का लेखा) और अनिवार्य जमा योजना (आय कर दस्ता) के अन्तर्गत क्रमशः 209.6 करोड़ रुपयों, 33.1 करोड़ रुपयों और 56.9 करोड़ रुपयों थीं।

केन्द्रीय सरकार का व्यय

34. 1974-75 (परिशोधित अनुमान) के लिए केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय की राशि 9753 करोड़ रुपयों थी। उसमें पूंजी निर्माण से इतर उद्देश्यों के लिए किये गये व्यय का अनुपात 63.3 प्रतिशत था जबकि 1973-74 में उक्त अनुपात 67.2 प्रतिशत था। कुल व्यय में 1973-74 की अपेक्षा 1622 करोड़ रुपयों या 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेल वित्त में जो कमी आयी उसके कारण भी केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में वृद्धि पायी गयी। रेलवे का घाटा 1974-75 में 144 करोड़ रुपयों (परिशोधित अनुमान) होने का अनुमान है जबकि बजट में 53 करोड़ रुपयों का घाटा परिकल्पित था और 1973-74 में 100 करोड़ रुपयों का घाटा पाया गया था। 1974-75 में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोग और पूंजी निर्माण पर किये जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय में पिछले

(8) केन्द्रीय सरकार के मामले में बकाया राजकोषीय शिलों की शुद्ध वृद्धि और नकदी जमा में से निकाली गयी राशियों से तथा राज्य सरकारों के मामले में जैसा कि राज्य बजटों में दर्शाया गया है, नकदी जमा में कमी, राज्यों द्वारा अपने नकदी जमा निवेश लेखों में धारित प्रतिभूतियों की शुद्ध बिक्री, प्रारक्षित राजस्व निधियों में धारित प्रतिभूतियों की धुलाई और रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अभियानों और (1 मई 1972 से लागू की गयी व्यवस्था के अधीन 7 कार्य दिनों के भीतर चुकाने योग्य) शेयर-ड्राफ्टों के रूप में दिये गये ऋणों की शुद्ध वृद्धि से घाटे का निर्धारण किया जाता है।

(9) आंकड़ों का आधार केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण है।

(10) आर्थिक सर्वेक्षण 1974-75।

(11) रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार 1974-75 के वास्तविक बजट घाटे की राशि 697 करोड़ रुपयों थी।

सारणी : 4 केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और वितरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1973-74 (लेखे)	1974-75 (बजट अनुमान) @	1974-75 (परिशोधित अनुमान)	1975-76 (बजट अनुमान) @
	राशि	राशि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	राशि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	राशि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)
I. कुल प्राप्तियाँ (अ+ब)	12945*	14329 + 10.8	15518 + 19.9	16982 + 9.4
(अ) राजस्व प्राप्तियाँ उनमें से	9286	10227 + 10.1	11366 + 22.4	12548 + 10.4
कर प्राप्तियाँ	7363	8020 + 8.9	8872 + 20.5	9917 + 11.8
(ब) पूँजीगत प्राप्तियाँ	3659*	4102 + 12.1	4152 + 13.5	4434 + 6.8
II. कुल वितरण	13492*	14439 + 7.0	16085 + 19.2	17236 + 7.2
उनमें से	6560	6933 + 5.7	7648 + 16.6	8248 + 7.8
(अ) विकास परिषद (क+ख)				
(क) राजस्व	4778	4971 + 4.0	5266 + 10.2	5847 + 11.0
(ख) पूँजीगत	1782	1962 + 10.1	2382 + 33.7	2401 + 0.8
(आ) विकासेतर परिषद (क+ख)	4526	5045 + 11.5	5329 + 17.7	5921 + 11.1
(क) राजस्व	4315	4764 + 10.4	5092 + 18.0	5650 + 11.0
(ख) पूँजीगत	211	281 + 33.2	237 + 12.3	271 + 14.3
III. समग्र अधिशेष (+)/या घाटा (—) (I—II)	—547	—110	—567	—254**

टिप्पणी : 1. अन्तर-सरकारी अन्तरणों के लिये राज्य सरकारों के बजटों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों की समायोजित किया गया है, परन्तु संयुक्त समग्र स्थिति अपरिचित है।

2. यहाँ दिये गये आंकड़े 1973-74 के पहले के वर्षों की रिपोर्टों में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते; क्योंकि 1974-75 में बजट संबंधी वर्गीकरण में परिवर्तन किये गये हैं। 1973-74 के आंकड़ों को भी इस सारणी में संशोधित वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। एक रूपता बनाये रखने के लिये हरियाणा और तमिलनाडु के संबंध में 1973-74 (लेखे) के पुराने वर्गीकरण के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को स्थूल रूप से संशोधित रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. केन्द्रीय सरकार ने जुलाई 1975 में आय-कर की छूट सीमा में वृद्धि और अनुदानों की पूरक मांगों की जो घोषणा की उसका प्रभाव इन आंकड़ों में शामिल नहीं है।

@ इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं, किन्तु 1974-75 (बजट अनुमान) की कुल प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों और कर-प्राप्तियों के आंकड़ों में 31 जुलाई 1974 को संसद में पेश किये गये केन्द्रीय सरकार के वित्त विधेयक सं० 2 में समाविष्ट अतिरिक्त कर संबंधी प्रस्तावों से प्राप्त होने वाले 136 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

* इसमें भारत-अमेरिकी करार, 1974 के अधीन किये गये पी० एल० 480 लेनदेन शामिल नहीं है।

** बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बजट में सम्मिलित न किये गये 11 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते के कारण होने वाले केरल के 17 करोड़ रुपये के व्यय-भार को यदि हिसाब में लिया जाये तो घाटे की राशि में 28 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। उक्त राज्य सरकारों के बजटों में उपर्युक्त के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

वर्ष की अपेक्षा 951 करोड़ रुपये और अव्यवस्था के शेष क्षेत्रों को किये गये वित्तीय वितरण में 671 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उपर्युक्त प्रत्यक्ष व्यय में जो वृद्धि हुई वह उपभोग व्यय के अन्तर्गत अधिक थी और उसकी राशि 2897 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 584 करोड़ रुपए अधिक थी। इसमें कुल प्रत्यक्ष व्यय में हुई वृद्धि का 61.4 प्रतिशत पाया गया। उपभोग व्यय में हुई वृद्धि अधिकांशतः मजदूरी और वेतन में पायी गयी और उनका अंग कुल वृद्धि का 78.4 प्रतिशत था। शेष 21.6 प्रतिशत पण्यो और सेवाओं के व्यय के अन्तर्भ

में पाया गया। विकास व्यय⁽¹²⁾ में 1974-75 में 30.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 5)।

(12) आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण के अनुसार खाद्य सहायता और प्राकृतिक विपत्तियों के लिये राशियों की प्रवृत्ति सहायता विकासेतर है। किन्तु 1974-75 में बजट का जो तया लेखा वर्गीकरण अपनाया गया उसके अनुसार इस प्रकार के व्यय को विकास व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है।

सारणी 5: केन्द्रीय सरकार का विकास और विकासांतर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

	1973-74 (लेखे)		चौथी योजना (1969-70 से 1973-74 तक) कुल राशि	चौथी योजना की वार्षिक औसत राशि	1974-75		1974-75		1975-76**	
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत			बजट (अनुमान)		(परिणोधित अनुमान)		(बजट अनुमान)	
					राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत
कुल व्यय(प्र+प्रा)	8131 (100.0)	+3.6	32993@	6599 (100.0)	8654 (100.0)	+6.4	9753 (100.0)	+19.9	10577 (100.0)	+8.4
प्र. विकास व्यय (i+ii)	3754 (46.2)	+4.9	15756	3151 (47.7)	4244 (49.0)	+13.1	4912 (50.4)	+30.8	5353 (50.6)	+9.0
(i) सामाजिक सेवाएं	601 (7.4)	—9.5	2385	477 (7.2)	625 (7.2)	+4.0	610 (6.3)	+1.5	705 (6.7)	+15.6
(ii) आर्थिक सेवाएं*	3153 (38.8)	—4.0	13371	2674 (40.5)	3619 (41.8)	+14.8	4302 (44.1)	+36.4	4648 (43.9)	+8.0
प्रा. विकासेतर व्यय (i+ii)	4377 (53.8)	+12.2	17237	3448 (52.3)	4410 (51.0)	+0.8	4841 (49.6)	+10.6	5224 (49.4)	+7.9
(i) सामान्य सेवाएं	2452 (30.1)	+5.3	9954	1991 (30.2)	2509 (29.0)	+2.3	2623 (26.9)	+7.0	2810 (26.6)	+7.1
(ii) अनिवारिणीय व्यय	1925 (23.7)	+22.5	7283	1457 (22.1)	1901 (22.0)	—1.2	2218 (22.7)	+15.2	2414 (22.8)	+8.8

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल व्यय में प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

@ इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गयी 84 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि और 1970-71 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की प्रतिनिधित्व, व्याज-रहित रुपया प्रतिभूतियों के रूप में अदा किये गये 114 करोड़ रुपये के अनुमानित अतिरिक्त अभिदान की राशि शामिल नहीं है ।

* इनमें एकमुश्त अनुदान तथा ऋण शामिल हैं ।

** केन्द्रीय सरकार ने जुलाई 1975 में अनुदानों की पूरक मांगों की जो घोषणा की उसका प्रभाव इन आंकड़ों में शामिल नहीं है ।

बजट साधन और पूंजी निर्माण

35. 1974-75 में बजट साधनों से पूंजी निर्माण पर 3578 करोड़ रुपये का जो कुल व्यय किया गया उसमें 34.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी और उक्त व्यय कुल व्यय का 36.7 प्रतिशत था जबकि 1973-74 में 32.8 प्रतिशत था । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण व्यय में 46.9 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई । इसमें से अधिकांश वृद्धि स्टाकों में विशेषकर खाद्यान्नों और उर्वरकों के स्टाकों में की गयी वृद्धि के कारण हुई । इसी प्रकार शुद्ध प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण या शुद्ध निवेश (नवीकरणों और प्रतिस्थापनों के व्यय को घटाने और स्टाकों में हुई वृद्धि को मिलाने पर विद्यमान संचल प्रत्यक्ष संचल पूंजी निर्माण) की राशि 1010 करोड़ रुपये थी जो 1973-74 के 629 करोड़ रुपये की अपेक्षा 60.6 प्रतिशत अधिक थी । स्टाकों को छोड़ देने पर सकल संचल पूंजी निर्माण में 1974-75 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पूंजी निर्माण के लिए 1974-75 में 2429 करोड़ रुपये की जो वित्तीय सहायता प्रदान की गयी वह 1973-74 में प्रदत्त 1883 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की अपेक्षा 29.0 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 6) ।

36. केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत की राशि 1974-75 में बढ़कर 669 करोड़ रुपये हो गयी जबकि उक्त राशि 1973-74 में 431 करोड़ रुपये थी । यह वृद्धि विभागीय प्रतिष्ठानों की मूल्यह्रास व्यवस्था और अधिधारित लाभों में 48 करोड़ रुपये की गिरावट के बावजूब हुई । इसका कारण यह था कि सरकारी प्रशासन की बचत में करों से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण 270 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । उक्त बचत की राशि बढ़कर 726 करोड़ रुपये हो गयी । किन्तु शुद्ध पूंजी निर्माण का पूर्ण रूप से वित्तपोषण करने के लिए शुद्ध बचत पर्याप्त नहीं थी ।

अतः इन दोनों के बीच विद्यमान खाई 1973-74 के 198 करोड़ रुपये से बढ़कर 341 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 7) ।

केन्द्रीय सरकार का बजट—¹³1975-76.

37. केन्द्रीय सरकार के 1975-76 के बजट में केन्द्रीय सरकार के कुल 10577 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी है जो 1974-75 में व्यय में हुई 10.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1975-76 में 8.4 प्रतिशत वृद्धि की सीमा तक है । 5353 करोड़ रुपये का जो विकास व्यय निर्धारित है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा 441 करोड़ रुपये अधिक है । पिछले वर्ष उसमें जहां 30.8 प्रतिशत वृद्धि हुई वहां इस वर्ष 9.0 प्रतिशत वृद्धि होगी । विकासांतर व्यय में भी पिछले वर्ष हुई 10.6 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा 7.9 प्रतिशत की न्यून वृद्धि होने की प्रत्याशा है । यह इस कारण संभव हो सका है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिक्त महंगाई भत्ता अदा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में विकास व्यय का अनुपात 1974-75 के 50.4 प्रतिशत से सीमांत रूप से बढ़कर 1975-76 में 50.6 प्रतिशत हुआ है ।

(13) जुलाई 1975 में केन्द्रीय सरकार ने आयकर की छूट सीमा को ६०६००० से बढ़ाकर ८०८००० कर दिया और क्षतिपूर्ति अन्य बनों के लिए आय कर-चर में उचित समायोजन किये गये । इसके अलावा 285.76 करोड़ रुपये के व्यय के लिए अनुदानों की जो पूरक मांगें पेश की गयीं उनको भी संसद ने अनुमोदित किया । केन्द्रीय सरकार के 1975-76 के बजट अनुमानों के विश्लेषण में इन गतिविधियों के प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

सारणी 6: पूंजी निर्माण पर भारत सरकार का व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

	1973-74 (लेखे)	चौथी पंचवर्षीय योजना-जोड़ (1969-70 से 1973-74 तक)	चौथी योजना का वार्षिक औसत	1974-75 (बजट अनुमान)	1974-75 (परिमोक्षित अनुमान)	1975-76** बजट अनुमान)
I. सकल प्रत्यक्ष अचल पूंजी निर्माण	711	2857	581	865	856	887
II. स्टाकों में वृद्धि	71	111	23	3	293	131
III. शुद्ध प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण (सकल प्रत्यक्ष अचल पूंजी निर्माण, तथीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किये गये व्यय को घटाने किन्तु स्टाकों में हुई वृद्धि को जोड़ने के बाद)	629	2419	484	721	1010	862
IV पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (क+ख+ग)	1883	7901*	1580	2226	2429	2913
(क) राज्य और संघशासित क्षेत्र	1191	4570	914	1091	1204	1223
(ख) विभागेतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (1+2)	593	2761*	552	996	1103	1555
1. वित्तीय संस्थाएं	111	425*	85	190	133	135
2. अन्य	482	2336	467	806	970	1420
(ग) अन्य पार्टियां@	77	570	114	139	122	135
जोड़ (I+II+IV)	2665	10869*	2174	3094	3578	3931

टिप्पणी :- इस सारणी में पूंजी निर्माण पर हुआ व्यय सकल आधार पर दर्शाया गया है।

* 1970-71 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रदा की गयी 84 करोड़ रुपये की अनुमानित क्षतिपूर्ति को छोड़कर।

@स्थानीय प्राधिकारियों और अन्यो को दी गई सहायता को मिलाकर।

**केन्द्रीय सरकार ने जुलाई 1975 में अनुदानों की पूरक मांगों की जो घोषणा की उसका प्रभाव इन भांकड़ों में शामिल नहीं है।

सारणी 7 : केन्द्रीय सरकार की बचत

(राशि करोड़ रुपये में)

	1973-74 (लेखे)	चौथी योजना- जोड़ (1969-70 से 1973-74 तक)	चौथी योजना का वार्षिक औसत	1974-75 (बजट अनुमान)	1974-75 (परिमोक्षित अनुमान)	1975-76* (बजट अनुमान)	घट बढ़ का प्रतिशत स्तम्भ (1) की तुलना में स्तम्भ (5) में	स्तम्भ 5 की तुलना में स्तम्भ (6) में
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. सरकारी प्रशासन की राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	4828	18995	3799	5290	6057	6709 (6687)	25.5	(10.8) (10.4)
(1) कर राजस्व	3876	14820	2964	4278	4882	5436 (5414)	26.0	11.3 (10.9)
(2) करेतर राजस्व	952	4175	835	1012	1175	1273	23.4	8.3
2. बालू व्यय	4372	17812	3563	4938	5331	5887	21.9	10.4
3. सरकारी प्रशासन की बचत (1-2)	456	1183	236	352	726	822 (800)	59.2	13.2 (10.2)
4. विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मूल्य- ह्रास व्यवस्था और अभिधारित लाभ (i+ii)	129	923	185	220	81	244	-37.2	201.2
(1) मूल्य-ह्रास व्यवस्था	650	658	132	157	156	162	4.0	3.8
(2) अभिधारित लाभ	-21	265	53	63	-75	82		

	1	2	3	4	5	6	7	8
5. केन्द्रीय सरकार की सकल बचत (3+4)	585	2106	421	572	807	1066	37.9	32.1
						(1044)		(29.4)
6. नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर व्यय	154	550	110	148	138	156	-10.4	13.0
7. शुद्ध बचत (5-6)	431	1556	311	424	669	910	55.2	36.0
						(888)		(32.7)
8. शुद्ध निवेश	629	2419	484	731	1010	862	60.6	-14.7
9. शुद्ध निवेश की तुलना में शुद्ध बचत में अधिकता (+) या कमी (-) (7-8)	-198	-863	-173	-297	-341	48		
						(26)		
10. मद (1) के प्रतिशत के रूप में मद (3)	9.4	6.2	6.2	6.7	12.0	12.3		
						(12.0)		

कोष्ठों में दिये गये आंकड़े 30 अप्रैल 1975 को करों में घोषित रियायतों के प्रभावस्वरूप विद्यमान आंकड़े हैं।

*केन्द्रीय सरकार ने जुलाई 1975 में अनुदानों की पूरक मांगों की जो घोषणा की उसका प्रभाव इन आंकड़ों में शामिल नहीं है।

38. इस बजट में योजना के लिए निर्धारित वित्तीय साधनों में काफी अधिक वृद्धि की परिकल्पना की गयी है। उक्त साधन 1974-75 के 2966 करोड़ रुपये से बढ़कर 3612 करोड़ रुपये होने की आशा है जो लगभग 22 प्रतिशत वृद्धि की ओर है। योजना में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार पर विशेषकर कृषि और संबंधित सेवाओं, जल और बिजली के विकास उद्योग तथा खनिज पदार्थों के संबंध में अधिकतर वित्तीय वितरण किया गया है। योजना परिव्यय में 23 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है।

39. सरकार के कुल व्यय में हुई कम वृद्धि के अनुरूप उपभोग और पूंजी निर्माण में होनेवाले प्रत्यक्ष व्यय की वृद्धि दर 1974-75 के 30.7 प्रतिशत के विपरीत काफी कम अर्थात् 2.4 प्रतिशत होगी और अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों को प्रदान की जानेवाली वित्तीय सहायता की वृद्धि-दर पिछले वर्ष के 13.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष केवल भिन्नात्मक रूप से कम अर्थात् 12.8 प्रतिशत होगी। उपभोग और पूंजी निर्माण में होने वाले प्रत्यक्ष व्यय की वृद्धि-दर इस कारण काफी कम हो जाने का अनुमान है कि आयातों और उर्वरकों के स्टाकों के लिए कम व्यवस्था किये जाने के कारण प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण के व्यय में काफी अधिक गिरावट आ गयी थी।

40. पूंजी निर्माण के लिए 1975-76 में कुल 3931 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है वह 1974-75 के स्तर की अपेक्षा 353 करोड़ रुपये अधिक होने की आशा है। विकास प्रयोजनों के लिए 3896 करोड़ रुपये के पूंजी निर्माण व्यय की व्यवस्था की गयी है जो कुल विकास व्यय का 72.8 प्रतिशत होगा जबकि 1974-75 में उक्त प्रतिशत 72.2 प्रतिशत था।

41. सरकारी प्रशासन में 1975-76 में 800 करोड़ रुपये की बचत की व्यवस्था की गयी है जो 1974-75 की तुलना में 74 करोड़ रुपये अधिक होने की आशा है। इसका कारण यह है कि चालू प्राप्ति या चालू व्यय से अधिक होंगी। नवीकरणों और प्रतिस्थापनों से संबंधित व्यय में वृद्धि होने के बावजूद केन्द्रीय सरकार की 888 करोड़ रुपये की जो बचत होगी वह 1974-75 की अपेक्षा 219 करोड़ रुपये अधिक होगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि 1975-76 में विभागीय प्रतिष्ठानों के प्रतिरक्षित लाभों के रूप में 82 करोड़ रुपये की बचत होगी जबकि 1974-75 में 75 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि का व्यय हुआ था। जहाँ इस प्रकार 1975-76 में शुद्ध बचत की राशि अधिक होगी वहाँ शुद्ध निवेशों की व्यवस्था में 14.7 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित होती है; इससे निवेशों की तुलना में बचत अधिक होगी।

42. 862 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश और वित्तीय प्राप्तियों तथा पूंजीगत अंतरणों (2324 करोड़ रुपये) को मिलाने पर 3186 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध पूंजीगत व्यय 1975-76 में 129 रुपये अधिक हो जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि इस व्यय की पूर्ति 1489 करोड़ रुपये की वेशी देयताओं और 801 करोड़ रुपये की विदेशी देयताओं द्वारा की जाएगी। इस वर्ष के 325 करोड़ रुपये के बाजार ऋण 1974-75 के 495 करोड़ रुपये की तुलना में कम है। व्यय में पायी गयी इस खाई को पाटने के लिए 1975-76 के बजट में 247 करोड़ रुपये⁽¹⁴⁾ के बजट घाटे का अनुमान लगाया गया है।

राज्य सरकारों के बजट संबंधी कार्यकलाप—1974-75

43. राज्य सरकारों के वित्त का भ्रम हम संक्षेप में विमर्शण प्रस्तुत करें। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से विदित होता है कि 1974-75 के घाटे की राशि 30 करोड़ रुपये होगी। किन्तु राज्य सरकारों के 1974-75 के बजटों के परिणोक्षित अनुमानों से यह विदित होता है कि बजट अनुमानों में प्रत्याशित 16 करोड़ रुपये के अधिशेष और 1973-74 में विद्यमान 219 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में इस वर्ष 58 करोड़ रुपये का अधिशेष पाया गया (सारणी 8)। राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए किये गये प्रयासों, योजना और योजनेतर व्यय में की गयी थोड़ी-सी किरफायत और छोटे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी ऋण-राहत तथा अतिरिक्त सहायता अनुदानों के अभाव में 1974-75 का घाटा और अधिक हो गया होता।

44. अंतिम प्राप्तियों और वितरणों के विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः निम्नलिखित विश्लेषण परिणोक्षित अनुमानों के आधार पर किया गया है राज्य सरकारों द्वारा 1974-75 के बजटों में और बजट के बाव की अवधि में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किये गये प्रयासों से 1974-75 में 358 करोड़ रुपये⁽¹⁵⁾ और पूरे वर्ष में 540 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। राज्य सरकारों ने पूरी चौथी योजना अवधि में 1058 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाये थे। इसके विपरीत 1974-75 में उनके द्वारा किये गये प्रयास काफी अधिक संतोषजनक थे और पांच वर्षों की अवधि में इनसे राज्य सरकारों के लिए पांचवीं योजना में निर्धारित 2550 करोड़ रुपये के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। काफी अधिक वित्तीय साधन जुटाये जाने और अंशतः

¹⁴ 30 अप्रैल 1975 को घोषित कर संबंधी रियायतों को ध्यान में रखते हुए यह राशि निर्धारित की गयी है।

¹⁵ इस राशि में राज्य बिजली बोर्डों और सबक परिवहन निगमों द्वारा जुटाये गये 110 करोड़ रुपये शामिल हैं किन्तु राज्यों की राज्य प्राप्तियों में इस राशि का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता।

मूल्य वृद्धि से कर-प्राप्तियों में तेजी आने के कारण अपने करों से राज्यों को प्राप्त होनेवाली राशि में 19.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि बजटों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गयी थी। राज्यों के अपने करों पर राजस्व में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों में परिकल्पित वृद्धि के लगभग समान थी। राज्यों की अपनी पूंजीगत प्राप्तियों में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई यद्यपि बजटों में केवल लगभग 7.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित थी।

45. राजस्व और पूंजीगत लेखों में राज्यों के अपने वित्तीय साधनों में जो काफी अधिक वृद्धि हुई उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारें अपने विकासेतर व्यय की पूर्ति करने के बाद 1974-75 में अपने वित्तीय साधनों से विकास व्यय और विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य पाठियों को प्रदान किये जाने वाले ऋणों के 51.1 प्रतिशत का वित्तपोषण कर सकीं जबकि 1973-74 में 44.1 प्रतिशत का वित्तपोषण कर सकी थीं।

सारणी 8 : राज्यों की समग्र बजट स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

	1973-74 (लेखे)	1974-75 (बजट अनुमान)	1974-75 (परिशोधित अनुमान)	1975-76 (बजट अनुमान)
राशि	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घटबढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घटबढ़ का प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल प्राप्तियां (अ+आ)	8052	7946 (8136)	8611	9068
		—1.2 (+1.1)	+7.0	+5.3 (+7.2)
(अ) राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	5552	5897 (6087)	6271	6800 (6962)
		+6.2 (+9.6)	+13.0	+8.4 (+11.0)
(1) राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियां	3452	3622 (3786)	4029	4397 (4518)
उन में से		+4.9 (+9.7)	+16.7	+9.1 (+12.1)
कर प्राप्तियां	2305	2364 (2497)	2742	3001 (3116)
		+2.6 (+8.3)	+19.0	+9.4 (+13.6)
(2) केन्द्रीय सरकार से अंतरित वित्तीय साधन (क+ख)	2100	2275 (2301)	2242	2403 (2444)
		+8.3 (+9.6)	+6.8	+7.2 (+9.0)
(क) करों में से प्राप्त हिस्सा	1163	1197 (1223)	1226	1324 (1365)
		+2.9 (+5.2)	+5.4	+8.0 (+11.3)
(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान	937	1078	1016	1079
		+15.0	+8.4	+6.2

टिप्पणियां:—(1) यहाँ दिये गये आंकड़े बजट वर्गीकरण में किये गये परिवर्तनों के कारण 1973-74 की रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों को छोड़कर अन्य पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

(2) हरियाणा और तमिलनाडु के मामले में पुराने वर्गीकरण के आधार पर 1973-74 (लेखे) के लिये दिये गये आंकड़ों की स्थूल रूप से संशोधित वर्गीकरण में परिवर्तित किया गया है।

(3) 1974-75 (बजट अनुमान) के लिये कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों राज्यों के बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि (164 करोड़ रुपये) और केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को (26 करोड़ रुपये) जोड़ने के बाद निकाले गये हैं।

(4) 1975-76 (बजट अनुमान) के लिए कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े राज्यों के बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि (83 करोड़ रुपये), 30 अप्रैल, 1975 को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर संबंधी रियायतों के प्रभावसहित केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान से राज्यों को मिलने वाले हिस्से (41 करोड़ रुपये) और केन्द्रीय बिक्री कर में किये गये परिवर्तन (38 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं।

सारणी 8 : राज्यों की समग्र बजट स्थिति—(आरी)

(राशि करोड़ रुपये में)

	1973-74 (लेखे)	1974-75 (बजट अनुमान)	1974-75 (परिशोधित अनुमान)	1975-76 (बजट अनुमान)
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घटबढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घटबढ़ का प्रतिशत
	1	2	3	4
(आ) वृजोगत प्राप्तियाँ (i+ii)	2500	2049	—17.8	2340
(1) राज्यों की अपनी				
राजस्व प्राप्तियाँ	947	1015	+7.2	1166
उनमें से				
बाजार ऋण (सकल)	166\$	265	+59.6	309\$
(2) केन्द्रीय सरकार से ऋण (सकल)	1553	1034	—33.4	1174
II कुल वितरण	8271	8120	—1.8	8553
उनमें से				
(क) विकास परिषद (i+ii)	4696	4906	+4.5	5081
(1) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	2428	2443	+0.6	2521
उनमें से				
प्राकृतिक विपत्तियों पर व्यय	372	71	—80.9	119
(2) आर्थिक सेवाएं	2268	2463	+8.6	2560
(ख) विकास पर व्यय	1899	1908	+0.5	1936
(ग) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौती	934	511	—45.3	506
(घ) अन्य पार्टियों को ऋण और अधिम	603	574	—4.8	810
(ङ) बाजार ऋणों की चुकौती	3\$	100		102\$
III. समग्र अधिपेध (+) या घाटा (—) (I-II)	—219	—174		+58
		(+16)*		—169†
				(—7)

*अतिरिक्त केन्द्रीय कराधान में राज्यों के हिस्से की जो राशि (13 करोड़ रुपये) वित्त विधेयक सं० 2 में प्रस्तावित है वह इसमें सम्मिलित नहीं है।

‡नागालैण्ड के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार आंकड़े दिये गये हैं।

‡तमिलनाडु के मामले में भूमि क्षतिपूर्ति बांडों की प्राप्तियों को सम्मिलित किया गया है।

@नागालैण्ड के मामले में आंकड़े शामिल नहीं किये गये हैं कि विवरण उपलब्ध नहीं है।

†यदि बिहार, केरल, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के मामले में बजट में व्यवस्थित न किये गये 11 करोड़ रुपये के परिषद और उच्चतर मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त व्यय भार (17 करोड़ रुपये) को हिसाब में लिया जाये तो बाटे की राशि में 28 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

46. ऋणों सहायता अनुदानों और विभाजित करों के रूप में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को वित्तीय साधनों का जो शुद्ध अंतरण किया जाता है उसमें 7.0 प्रतिशत वृद्धि (191 करोड़ रुपये) परिलक्षित हुई जबकि 1973-74 में उसमें 3.8 प्रतिशत (108 करोड़ रुपये) की गिरावट पायी गयी थी। राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियों में इन अंतरणों का अंश 1974-75 में 35.9 प्रतिशत था जबकि 1973-74 में उक्त अंश 38.2 प्रतिशत था।

47. 8553 करोड़ रुपये के कुल वितरण 1973-74 की अपेक्षा केवल 3.4 प्रतिशत अधिक थे। 1936 करोड़ रुपये का विकासेतर व्यय 1973-74 में उसमें हुई 18.4 प्रतिशत की तुलना में 1.9 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि का द्योतक था। इसके विपरीत विकास व्यय में जहाँ 1973-74 में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1974-75 में केवल 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1974-75 में विकास व्यय में हुई कमी का कारण प्राकृतिक विपत्तियों पर होने वाला न्यूनतर परिव्यय था। उक्त परिव्यय को नये बजट वर्गीकरण में विकास व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राकृतिक विपत्तियों पर 1974-75 में 119 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जबकि 1973-74 में 372 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। प्राकृतिक विपत्तियों पर हुए व्यय को छोड़ देने पर 1974-75 में विकास व्यय में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि पायी जाती है जो 1973-74 में हुई वृद्धि के लगभग बराबर थी।

राज्य सरकारों के बजट संबंधी कार्यकलाप 1975-76

48. राज्य सरकारों की 1975-76 की बजट स्थिति में 1974-75 के परिशोधित अनुमानों की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। समग्र स्थिति 58 करोड़ रुपये के अधिशेष से 7 करोड़ रुपये के घाटे में परिणत हो जायी। यदि बजट में अनिर्धारित परिव्यय और कतिपय राज्यों द्वारा अपने बजटों में सरकारी कर्मचारियों को वेध अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के लिए न की गयी व्यवस्था को हिसाब में लिया जाए तो सामग्र स्थिति में और गिरावट पायी जायेगी। राज्य सरकारों के 1975-76 के बजटों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उनके योजना परिव्यय में 594 करोड़ रुपये की वृद्धि (28.1 प्रतिशत) की गयी और उक्त परिव्यय की राशि बढ़कर 2711 करोड़ रुपये ⁽¹⁰⁾ हो गयी। किन्तु यह राशि अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए प्रयासों के अनुरूप नहीं है। जहाँ 1974-75 में 248 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय साधन ⁽¹⁷⁾ जुटाये गये वहाँ 1975-76 में शोधित उपायों से केवल 83 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। योजना परिव्यय में की गयी वृद्धि के अलावा विकासेतर व्यय में हुई तीव्र वृद्धि के कारण भी राज्य सरकारों की 1975-76 की बजट स्थिति तनावयुक्त होगी। प्रमुखतः प्रशासन व्यय में वृद्धि ब्याज की अदायगियों में बढ़ोत्तरी और ऋण की कम करने या ऋण को छोड़ देने के लिए किए गए उच्चतर विधिधान के कारण बजट में विकासेतर व्यय में वृद्धि हुई है।

49. बजट में राज्य सरकारों की 9068 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों (कराधान की 1974-75 की दरों पर) की जो व्यवस्था की गयी है वह 1974-75 की अपेक्षा 457 करोड़ रुपये या 5.3 की प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है जबकि 1974-75 में उनमें 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नये प्रयासों से प्राप्त होने वाली राशि (83 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त करों से राज्यों को प्राप्त होने वाले अंश (41 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय बिजली कर दरों में वृद्धि किये जाने से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व (38 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेने पर कुल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 7.2 प्रतिशत वृद्धि पाई जायेगी। राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियों में जहाँ 1974-75 में 16.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष के बजटों के अनुसार 12.1 प्रतिशत वृद्धि होगी करों की 1974-75 की दरों के अनुसार राज्यों को अपने करों से प्राप्त होने वाली राशियों में 9.4 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है जबकि 1974-75 में उनमें 19.0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। नये प्रयासों से प्राप्त होने

वाली राशियों को सम्मिश्रित करने पर कर प्राप्तियों में 13.6 प्रतिशत वृद्धि होगी। राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि में राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट के कारण 41 करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार से राज्यों को वित्तीय साधनों का जो अंतरण किया जाता है उसके संबंध में यह ध्यान रखना है कि जहाँ केन्द्रीय करों से राज्यों को प्राप्त होने वाले अंश और अनुदानों में 202 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी वहाँ ऋणों (शुद्ध) में 167 करोड़ रुपये की कमी होगी। इससे अंतरित वित्तीय साधनों की शुद्ध राशि 35 करोड़ रुपये रह गयी।

50. 9237 करोड़ रुपये के कुल वितरणों की राशि में 684 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि (8.0 प्रतिशत) परिलक्षित होती है जबकि 1974-75 में 282 करोड़ रुपये की वृद्धि (3.4 प्रतिशत) हुई थी। विकास परिव्यय में 1974-75 में हुई 8.2 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले में 8.8 प्रतिशत वृद्धि होगी। प्राकृतिक विपत्तियों पर होने वाले व्यय के लिए जहाँ 1974-75 में 119 करोड़ रुपये निर्धारित थे वहाँ इस वर्ष 99 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। विकासेतर व्यय में जहाँ 1974-75 में 1.9 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष क बजट के अनुसार 13.9 प्रतिशत वृद्धि होगी। केन्द्रीय सरकार की ऋणों की जो चुकौती की जायेगी। उसे यदि छोड़ दिया जाए तो वितरणों में 548 करोड़ रुपये की वृद्धि पायी जायेगी। इस अतिरिक्त व्यय के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सरकार से केवल 35 करोड़ रुपये शुद्ध का अतिरिक्त वित्त प्राप्त होगा और शेष अंश की पूर्ति राज्यों के निजी वित्तीय साधनों से की जायेगी। विकासतेर व्यय में काफी अधिक वृद्धि की परिकल्पना के बावजूद राज्य सरकारें अपने विकास व्यय और विकास के प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के 52.4 प्रतिशत की पूर्ति अपने निजी वित्तीय साधनों से करेगी।

51. इस प्रकार राज्य सरकारें 1974-75 में काफी अधिक वित्तीय साधन जुटाकर अपनी बजट स्थिति में बेहतर संतुलन स्थापित कर सकेंगी। 1975-76 में यद्यपि राज्य सरकारें 83 करोड़ रुपये जुटाने के लिए कबम उठा चुकी हैं फिर भी उन्हें सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिए जाने और परियोजना लागतों आदि के बढ़ जाने के कारण अपनी बजट स्थिति पर उत्पन्न होने वाले दबाव को रोकने के लिए और अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने होंगे। राज समिति की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए अधिकांश राज्यों को विशेष रूप से ऋण क्षेत्र से प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों के संबंध में अभी तीव्रतापूर्वक कबम उठाने हैं।

मुद्रा और ऋण नीति

52. पिछले खंड में अर्चित राजकोषीय प्रयासों को मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए किए गए मुद्रागत प्रयासों द्वारा पुनः संशक्त रूप से लागू किया गया। इस खंड में प्रथमतः कुल ऋण विस्तार तथा बाद में निधियों के प्रयोग और रिजर्व बैंक से ली जाने वाली सहायता के संबंध में वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रणाली को विनियमित करने के लिए 1974-75 में किये गये विभिन्न प्रयासों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन किया गया है। अंतिम विश्लेषण के अनुसार राजकोषीय और मुद्रागत दोनों प्रकार की नीतियों का संश्लिष्ट प्रभाव मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों पर परिलक्षित होता है; इस पहलू पर इस खंड के अंत में खर्चा की गई है।

(10) इस राशि में सिकिम राज्य के लिए निर्धारित 6.31 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय शामिल है।

(17) इनमें वे साधन शामिल नहीं हैं जो राज्य बिजली बोर्डों और सड़क परिवहन निगमों द्वारा जुटाये गये।

ऋण नीति के लक्ष्य

53. ऋण नीति के प्रमुख लक्ष्य पहले की तरह इस प्रकार थे ; बैंक ऋण को मुख्य वित्तीय साधन के रूप में समझना चाहिए तथा ऋण वितरण के लिए जमाराशियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक से सहायता प्राप्त कर निमित्त किये जाने वाले धन के प्रयोग की मात्रा को राशि और उपभोग की अवधि दोनों के संदर्भ में न्यूनतम स्तर पर रखना होगा। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऋण वितरण में अनुपालनीय स्थूल प्राथमिकताओं का संकेत बैंकों को दिया गया। ब्याज दरों को बढ़ाया गया और पुनर्वित्त तथा ढुंढियों की पुनर्मुनाई के द्वारा रिजर्व बैंक से जो सहायता ली जाती है वह प्रायः संपूर्ण रूप से औचित्य के आधार पर प्रदान की गयी। इस संबंध में प्रत्येक बैंक की आवश्यकताओं का अलग-अलग मूल्यांकन किया जायेगा।

ऋण नीति : कम कामकाज का समय—1974

54. 1974 के कम कामकाज के समय के प्रारंभ में ही बैंकों से कहा गया कि रिजर्व बैंक के प्रति उनकी ऋणप्रस्तुता में पिछले अधिक कामकाज के समय में जो अधिक वृद्धि हो गयी थी, उसे वे समाप्त करने की ओर अधिक ध्यान दें। जहाँ एक ओर जून 1973 में सांविधिक प्रारंभित नकदी में की गयी 2 प्रतिशत की वृद्धि को जून 1974 के अंत में समाप्त कर दिया गया वहाँ दूसरी ओर न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात (बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अधीन) को 1 प्रतिशत बढ़ाकर कुल मांग और मीयादी देयताओं के 32 प्रतिशत से 33 प्रतिशत किया गया। उधारों के समापन और अतिरिक्त निवेशों की इन आवश्यकताओं के कारण ऋण विस्तार के लिए अधिक गुंजाइश नहीं रही तथा यह स्पष्ट रूप से निदिष्ट किया गया कि कम कामकाज की संपूर्ण अवधि के दौरान ऋण में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त जमाराशियों के अधिक से अधिक 33 से 35 प्रतिशत तक का उपयोग किया जा सकता है।

ब्याज दरों का विन्यास

55. कम कामकाज के समय में ऋण की प्रवृत्तियों की समीक्षा करने से पूर्व कम कामकाज के समय के मध्य में उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख करना आवश्यक है। मुद्रा और ऋण में होने वाली वृद्धि को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 1974 को ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की ; उनमें उधारों और जमाराशियों की ब्याज दरें दोनों शामिल हैं। बैंक दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गयी अर्थात् उसे 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया तथा बैंकों द्वारा दिये जानेवाले अधिमों पर न्यूनतम ब्याज दर को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के लिए दिये जानेवाले अधिमों की न्यूनतम ब्याज-दर में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। निर्यात ऋण तथा खाद्यान्नों की वसूली के लिए दिये जानेवाले अधिमों पर लागू होनेवाली अधिकतम ब्याज दरों को भी क्रमशः 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया। ब्याज पर जब कर लागू किया गया तब ब्याज दरों को बढ़ाकर अनाजों की वसूली के लिए दिये गये अधिमों के मामले में 12 प्रतिशत और निर्यात ऋण के मामले में 11.5 प्रतिशत किया गया। प्राप्तगित भ्रवायगी की शर्तों पर किये जानेवाले निर्यातों से संबंधित ऋण की ब्याज दर को भी 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया।

56. जमाराशियों की ब्याज दरों में जो परिवर्तन किया गया उसका प्रमुख लक्ष्य बचत को प्रोत्साहित करना था। अतः जहाँ एक ओर बचत जमाराशियों की ब्याज दर (इसमें अप्रैल 1974 में एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी) को 5 प्रतिशत ही रहने दिया गया वहाँ दूसरी ओर विभिन्न वर्गों की सवधि जमाराशियों की ब्याज दरों को बढ़ाया गया। यह

वृद्धि अल्पावधि जमाराशियों के संदर्भ में 0.5 प्रतिशत थी ; किन्तु 5 वर्षों से अधिक अवधि की जमाराशियों के लिए 2 प्रतिशत तथा 3 से 5 वर्षों तक की जमाराशियों के लिये 1.25 प्रतिशत थी।

1974 के कम कामकाज के समय में पायी गयी प्रवृत्तियाँ

57. कम कामकाज के समय के दौरान पायी गयीं ऋण सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर पुनः विचार करते हुये प्रत्येक बैंक के लिए उसके द्वारा लिये गये ऋणों की चुकौती का कार्यक्रम बनाया गया तथा उसके अनुपालन की पूरी व्यवस्था की गयी। अतः इस प्रकार रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों में 270 करोड़ रुपये की कमी की जा सकी इस प्रकार कम की गई राशी अधिक कामकाज के समय के दौरान ऋणों में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी। (सारणी 9)। रिजर्व बैंक से बैंकों द्वारा लिये गये उधारों की बकाया राशि पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ में कम थी (अर्थात् उक्त राशि जहाँ पिछले वर्ष 80 करोड़ रुपये थी वहाँ इस वर्ष 63 करोड़ रुपये थी)। बैंकों से कहा गया कि वे रिजर्व बैंक से पुनः भुनायी गयी ढुंढियों की सीमाओं को पिछले अधिक कामकाज के समय के अंत में विद्यमान बकाया स्तर के लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर दें। इस अवधि में बकाया राशियों को 279 करोड़ रुपये से कम कर 108 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप कम कामकाज के समय में सकल बैंक ऋण में 99 करोड़ रुपये की गिरावट आयी। किन्तु कुल बैंक ऋण (पुनः भुनायी गयी ढुंढियों को छोड़कर) में 72 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि उसमें 1973 में 346 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। खाद्यान्नों के लिए दिये गये अधिमों में 170 करोड़ रुपये की गिरावट आयी। इससे यह स्पष्ट होता है कि दूसरे अधिमों (खाद्यान्नों की वसूली को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए दिये गये) में 242 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1973 के कम कामकाज के समय और 1973-74 के अधिक कामकाज के समय में उनमें क्रमशः 403 करोड़ रुपये और 923 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस समय के दौरान जमाराशियों में 914 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह वृद्धि-दर 1973 की वृद्धि दर (10.3 प्रतिशत) की अपेक्षा कम (8.8 प्रतिशत) थी। इस अवधि के अंत में ऋण-जमा अनुपात 68.3 प्रतिशत था जबकि पिछले कम कामकाज के समय में यह अनुपात निश्चित रूप से उक्त अनुपात से एक प्रतिशत कम था। किन्तु कम कामकाज की संपूर्ण अवधि के दौरान वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात केवल 7.9 प्रतिशत था तथा यह अनुपात उक्त अवधि के प्रारंभ में निश्चित 33 से 35 प्रतिशत तक की सूत्रक सीमा से काफी कम था।

अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति 1974-75

58. 1974-75 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति के दो प्रमुख तत्व इस प्रकार थे; ऋण वितरण में जिन प्राथमिकताओं का पालन करना है उनकी ओर संकेत किया गया और रिजर्व बैंक द्वारा विवेकाधीन ऋण प्रदान किये जाने के सिद्धांत को और व्यापक बनाया गया। संवेदनशील पण्यों के मूल्यांकन पर सट्टेबाजी के कारण पड़नेवाले बचावों को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार के पण्यों पर चयनात्मक नियंत्रण को बनाये रखा गया।

59. किन्तु इस बात पर जोर दिया गया कि जहाँ एक ओर समग्र नियंत्रण की आवश्यकता बनी रही वहाँ दूसरी ओर बैंकों को उपलब्ध साधनों की सहायता से उत्पादन और निवेश के लिए सहयोग देना होगा। ऋण प्रदान किये जाने के लिए जिन प्राथमिकताओं को अपनाना था उनके संबंध में कुछ स्थूल मार्ग-दर्शी सिद्धांत निदिष्ट किये गये। उनमें से कुछ इस प्रकार थे : खाद्यान्नों की पर्याप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कृषि ऋण और निर्यातों की आवश्यकताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता

दी जाए। निजी औद्योगिक क्षेत्र में 'क्रोड' क्षेत्र के यूनिटों तथा 'निर्बाह वस्तुओं' के उत्पादन में लगे हुए यूनिटों को अधिमान दिया जाए। लघु-उद्योग क्षेत्र में भी व्यवसायिक नीति लागू की गयी और यह संकेत दिया गया कि दुर्लभ बैंक ऋण न केवल ऋणकर्ता यूनिट के प्रकार, बल्कि उस यूनिट द्वारा किये जाने वाले उत्पादन के स्वरूप के आधार पर भी उपलब्ध कराया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापारिक कार्यकलाप में संलग्न यूनिटों की अपेक्षा उत्पादन यूनिटों को अधिमान दिया जाएगा।

विवेकाधीन वित्तीय सहायता

60. ऋण विस्तार के लिए निमित्त धन के प्रयोग को सीमित करने के समग्र लक्ष्य के एक अंश के रूप में वृद्धिशील सांविधिक प्रारंभित नकदी में जो वृद्धि हुई थी उसका एक भाग लौटाया गया; इससे बैंकों के अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के पास अभिरक्षित न्यूनतम सांविधिक जमा राशियों को मांग और मीमादी वेयताओं के 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। उक्त जमा राशियों में इस प्रकार दो किस्तों में कमी की गयी। 14 दिसंबर 1974 से 0.5 प्रतिशत तथा 28 दिसंबर 1974 से और 0.5 प्रतिशत कम किया गया। इससे बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए 120 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

61. पुनः भुनायी गयी हुंडियों पर विवेकाधीन वित्तीय सहायता की नीति को लागू कर रिजर्व बैंक से स्वतः प्राप्त होने वाली राशि को और सीमित किया गया। पहले की तरह बैंक की मांग और मीमादी वेयताओं (सितंबर 1974 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान) कि एक प्रतिशत से अधिक ऋण शुद्ध चलनिधि अनुपात द्वारा निर्धारित दरों पर रिजर्व बैंक अपने विवेक के अनुसार प्रदान करेगा। जिस न्यूनतम शुद्ध चलनिधि अनुपात के आधार पर बैंक दर पर उधार लिए जा सकते हैं उसे 40 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया; किंतु उधारों पर सी जानेवाली अधिकतम ब्याज दर को 18 प्रतिशत ही रहने दिया गया। इसी प्रकार हुंडियों के लिए मूल कोटा खरीदी और भुनायी गयी कुल वेयो हुंडियों (सितंबर 1974 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान) का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया। इससे अधिक राशि की पुनर्भुनाई सीमाएं न केवल राशि के संबंध में बल्कि ब्याज दरों के संबंध में भी रिजर्व बैंक के विवेक के अनुसार 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक स्वीकृत होंगी।

62. छाछान्तों की सार्वजनिक बसूली के लिए प्रवृत्त ऋण के संबंध में विशेष पुनर्वित्त की सुविधा जारी रही। किंतु जब छाछात्र ऋण की बकाया राशि 300 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है तब वृद्धि के 50 प्रतिशत तक पुनर्वित्त को सीमित किया जाएगा तथा बकाया राशि के 450 करोड़ रुपये के स्तर से अधिक हो जाने पर पूरी राशि के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। पहले की तरह 10 प्रतिशत की निर्धारित ब्याज दर पर शुद्ध चल निधि अनुपात को प्रभावित किये बिना पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा।

63. यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अधिक कामकाज के समय के लिए ऋण विस्तार की कोई स्पष्ट उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी जबकि 1973-74 में इस प्रकार की सीमा निर्धारित की गयी थी। यह अनुभव किया गया कि सुनिश्चित प्राथमिकताओं के अनुसार, उत्पादन, वितरण और निवेश की उचित आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने और ऋण विस्तार को न्यूनतम बनाये रखने के लक्ष्य की पूर्ति अलग-अलग बैंकों से विचार-विमर्श करके अधिक अच्छे ढंग से की जा सकेगी। जहाँ एक ओर प्रत्येक बैंक के साथ रिजर्व बैंक ने अलग-अलग उसके ऋण के बजट पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किये वहाँ दूसरी ओर पूरे वर्ष में बड़े बैंकों के साथ भी निकट संपर्क बनाये रखा गया; इससे रिजर्व बैंक सही परिस्थिति से अवगत हो सका। रिजर्व बैंक से स्वतः प्राप्त होनेवाली सहायता पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया और

उसके द्वारा प्रवृत्त ऋण-सुविधाएं केवल औचित्य पर निर्भर करेंगी; इससे "नैतिक उदात्तता" को और बल मिला।

64. पूरे वर्ष में लागू की गयी प्रतिबंधक ऋण नीति के प्रभाव-स्वरूप ऋण विस्तार की गति धीमी हो गयी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 1974 के कम कामकाज के समय के दौरान कुल बैंक ऋण में हुई वृद्धि अपेक्षाकृत कम अर्थात् केवल 0.9 प्रतिशत थी जबकि पिछले कम कामकाज के समय के दौरान उसमें 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यदि सकल आधार पर देखा जाए (अर्थात् पुनः भुनायी गयी हुंडियों को मिलाकर) तो आलोच्य अवधि में बैंक ऋण में वास्तविक गिरावट पायी गयी।

65. 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान सकल ऋण (पुनः भुनायी गयी हुंडियों को मिलाकर) में 1009 करोड़ रुपये या 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान उसमें 1355 करोड़ रुपये या 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 9)। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि आलोच्य अवधि के दौरान खाद्य ऋणों में 317 करोड़ रुपये की वृद्धि पायी गयी थी जो 1973-74 के अधिक कामकाज के समय में हुई 188 करोड़ रुपये की वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक थी। छाछान्तों की बसूली के लिए दिये गये ऋण को यदि शामिल न किया जाये तो सकल ऋण में हुई वृद्धि काफी कम अर्थात् 9.2 प्रतिशत थी जबकि 1973-74 के दौरान उक्त वृद्धि 18.5 प्रतिशत थी। 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान जमा राशियों की वृद्धि की गति कुछ कम अर्थात् 6.3 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष उनमें 7.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई थी। किंतु इस प्रकार की वृद्धि के स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन पाया गया। 1973-74 में अतिरिक्त जमा राशियों का लगभग 60 प्रतिशत अंश मांग जमा राशि के रूप में पाया गया था। किंतु 1974-75 में लगभग उतना ही अनुपात मीमादी जमा राशियों में पाया गया। यह शायद इस बात का द्योतक है कि मीमादी जमा राशियों की ब्याज दरों को बढ़ाने के कारण ऐसी जमा राशियों के प्रति रुझान अधिक हो गया था। अधिक कामकाज के समय के अंत में ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 73.7 प्रतिशत की अपेक्षा कम अर्थात् 72.2 प्रतिशत था।

1974-75 के वर्ष का समग्र मूल्यांकन

66. जुलाई 1974 से जून 1975 तक की संपूर्ण अवधि के दौरान निधियों के प्रयोग का स्वरूप पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी भिन्न था। जमा राशियों में हुई वृद्धि राशि के रूप में केवल सीमांत रूप से अधिक (अर्थात् जहाँ पिछले वर्ष उक्त वृद्धि 1591 करोड़ रुपये थी वहाँ इस वर्ष 1606 करोड़ रुपये थी) तथा प्रतिशत के रूप में कम थी (अर्थात् पिछले वर्ष जहाँ 17.4 प्रतिशत थी वहाँ इस वर्ष 14.9 प्रतिशत थी)। इसके विपरीत बैंक ऋण में हुई वृद्धि काफी कम अर्थात् 1105 करोड़ रुपये या 14.1 प्रतिशत थी जबकि उक्त वृद्धि 1973-74 में 1446 करोड़ रुपये या 22.6 प्रतिशत थी। सकल ऋण की दृष्टि से यह वृद्धि और भी कम अर्थात् केवल 11.8 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष उक्त वृद्धि 26.5 प्रतिशत थी। इसके विपरीत 1974-75 के दौरान उधारों और पुनः भुनायी गयी हुंडियों में गिरावट परिलक्षित हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें वृद्धि पायी गयी थी। दूसरे शब्दों में जहाँ 1973-74 में रिजर्व बैंक से प्राप्त सुविधाएं शुद्ध निधि-स्रोत थीं वहाँ 1974-75 में इस प्रकार की सुविधाओं को समाप्त कर देने से उपलब्ध निधियों का उपयोग करना पड़ा। यह तथ्य वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात से भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है। उक्त अनुपात 1974-75 में 68.8 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष 90.9 प्रतिशत था।

सारणी 9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में मौसमी घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपये में)

	मौसमी घट-बढ़				कम कामकाज का समय			
	कम कामकाज का समय	अधिक कामकाज का समय	कम कामकाज का समय	अधिक कामकाज का समय	कम कामकाज का समय	अधिक कामकाज का समय	1 अगस्त 1975@	1 अगस्त 1974
	1972	1972-73	1973	1973-74	1974	1974-75		
1. कुल जमा राशियाँ	+ 705	+ 811	+ 899	+ 677	+ 914	+ 714	+ 800	+ 624
(क) मांग	+ 262	+ 335	+ 251	+ 407	+ 300	+ 292	+ 368	+ 294
(ख) सीयादी	+ 443	+ 476	+ 648	+ 270	+ 614	+ 422	+ 432	+ 330
2. बैंक ऋण	+ 67	+ 897	+ 346	+ 1111	+ 72	+ 950	+ 204	+ 199
उनमें से								
(क) खाद्यान्नों की बसूली के लिए दिये गये ऋण	—1	+ 5	—57	+ 188	—170	+ 317	+ 137	+ 45
(ख) दूसरे ऋण	+ 68	+ 892	+ 403	+ 923	+ 242	+ 633	+ 67	+ 154
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीदी और भुनाई गयी वैशी ठुडियाँ	—10	+ 10	+ 15	+ 244	+ 171	+ 59	—107	—48
4. सकल बैंक ऋण	+ 57	+ 916	+ 361	+ 1355	—99	+ 1009	+ 97	+ 151
5. सरकारी और अन्य अनुमोचित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश	+ 620	+ 4	+ 282	+ 157	+ 472	+ 269	+ 275	+ 269
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	+ 519	—89	+ 187	+ 73	+ 349	+ 223	+ 138	+ 190
(ख) अन्य अनुमोचित प्रतिभूतियों में	+ 110	+ 93	+ 95	+ 84	+ 123	+ 46	+ 137	+ 79
6. नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	+ 57	+ 60	+ 444	—214	+ 114	—98	+ 68	+ 60
(क) नकदी	+ 27	+ 20	+ 25	+ 4	+ 21	+ 12	—4	—11
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	+ 30	+ 40	+ 419	—218	+ 93	—110	+ 72	+ 71
7. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिक्रिया राशि	+ 13	+ 72	—41	—96	+ 61	+ 29	—13	+ 26
8. भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार	—16	+ 17	+ 56	+ 253	—270	+ 183	—191	—122
ऋण-जमा-अनुपात (मौसम के अंत में)	66.2	70.3	67.3	73.7	68.3	72.2	69.3	71.3
ऋण-जमा-अनुपात (खाद्यान्नों की बसूली के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)								
(मौसम के अंत में)	62.6	67.0	64.9	69.6	66.1	67.4	63.7	67.0
निवेश-जमा-अनुपात (मौसम के अंत में)	36.3	33.0	32.9	32.2	33.8	34.0	34.1	32.8

टिप्पणियाँ :—(1) ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के अधीन बैंकों द्वारा पेश की गयी साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित हैं। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक ऋण सूचनाओं पर आधारित हैं।

(2) घट-बढ़ अप्रैल और अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित है।

@अनंतिम।

अधिक कामकाज के समय में लिए गए उधार

67. अधिक कामकाज के समय के दौरान रिजर्व बैंक से ली गयी कुल वित्तीय सहायता (पुनर्भुनाई तथा पुनर्भुनाई दोनों रूपों में) 659 करोड़ रुपये के उच्चतम शिखर तक पहुँच गयी थी। यह स्तर न केवल पिछली अवधि के 698 करोड़ रुपये के शिखर स्तर से कम था, बल्कि आलोच्य अवधि के अंत में उसे और अधिक बढ़ाकर 413 करोड़ रुपये कर दिया गया था। किन्तु पिछले वर्ष इस प्रकार ली गयी वित्तीय सहायता में गयी गयी गिरावट कम थी और सहायता की मात्रा 612 करोड़ रुपये रही; इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय तत्त्व पुनर्भुनाई के स्वरूप से संबंधित हैं। 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों का शिखर-स्तर 473 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था; इनमें से 227 करोड़ रुपये खाद्यान्नों की वसूली के लिए ऋण के रूप में तथा 22 करोड़ रुपये तेल कंपनियों को प्रवृत्त ऋण के लिये विशेष पुनर्भुनाई के रूप में प्रदान किये गये। पिछले अधिक कामकाज के समय में लिये गये 422 करोड़ रुपये के उधारों में से 42 करोड़ रुपये खाद्यान्नों की वसूली के लिए तथा 16 करोड़ रुपये तेल के संबंध में लिये गये। अतः अनिवार्य उद्योगों के लिए दी गयी सहायता पिछले अधिक कामकाज के समय में प्रवृत्त सहायता से काफी कम थी।

रिजर्व बैंक में पुनः भुनायी गई ढुंडियाँ

68. एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पिछले अधिक कामकाज के समय के दौरान पुनर्भुनाई की सुविधा का बहुत कम प्रयोग किया गया। 1973-74 के अधिक कामकाज के समय में रिजर्व बैंक से उधारों और पुनर्भुनाई के रूप में प्राप्त अतिरिक्त सहायता लगभग समान थी (अंशः 253 करोड़ रुपये तथा 244 करोड़ रुपये); किंतु 1974-75 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रवृत्त सुविधाओं के वृद्धिशील प्रयोग का केवल एक-बीघाई भाग पुनर्भुनाई के रूप में प्रवृत्त सहायता का था (अर्थात् जहाँ उधारों के रूप में प्राप्त 183 करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया वहाँ पुनर्भुनाई के रूप में प्राप्त 59 करोड़ रुपये प्रयोग में लाये गये)। इसका कारण यह हो सकता है कि आलोच्य वर्ष के दौरान सुविधा की शर्तों को युक्ति-संगत बनाया गया था। जहाँ एक ओर वास्तविक व्यापार ढुंडी बाजार को विकसित करना तथा नकदी ऋण प्रणाली से अधिक ढुंडी वित्त का प्रयोग करना दीर्घकालीन नीति का लक्ष्य रहा है वहाँ दूसरी ओर यह भी आवश्यक समझा गया कि ढुंडी वित्त को जो अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया उसका उपयोग समग्र ऋण नियंत्रण से बचने के लिए करने की प्रवृत्ति को रोका जाए। अतः जून 1974 में आदेशिती तथा आदेशक की ढुंडियों में अंतर किया गया तथा आदेशिती की ढुंडियों के संबंध में आदेशक की ढुंडियों की अपेक्षा अधिक न्यूनतम व्याज दर लागू की गयी। यह भी निश्चित किया गया है कि आदेशिती की ढुंडियों पर लिये जानेवाले व्याज की दर उसी उधारकर्ता को प्रवृत्त नकदी ऋण सुविधा पर लिये जाने वाले व्याज की दर के ही समान होनी चाहिए। यह इसलिये किया गया कि वस्तुएं खरीदने के लिए प्रवृत्त ढुंडी वित्त नकदी ऋण प्रणाली की अपेक्षा कम व्ययशील न हो। जुलाई 1974 में जब उधारों की न्यूनतम व्याज दर को बढ़ाया गया था तब आदेशिती की ढुंडियों से संबंधित न्यूनतम व्याज दर को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत तथा आदेशक की ढुंडियों से संबंधित व्याज दर को बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया। इसके

अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया कि ढुंडियों को पुनर्भुनाई के द्वारा उपयोग में लायी गयी रिजर्व बैंक की निधियां वापस आ जाएँ। इसके लिए यह शर्त निर्धारित की गयी कि पुनः भुनायी गयी ढुंडियों की बकाया राशि में कम कामकाज के समय के दौरान 40 प्रतिशत कटौती की जाए। पुनर्भुनाई की सुविधा के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के लिए निर्धारित नीति में यह व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार की सुविधा संपूर्ण रूप से श्रेष्ठि के आधार पर ही प्राप्त होगी।

ऋण का क्षेत्रीय स्वरूप : अधिक काम काज का समय, 1974-75

69. 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान ऋण का जो क्षेत्रीय वितरण किया गया उससे स्पष्ट रूप से यह विवृत होता है कि उस संबंध में निश्चित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया गया था (सारणी 10 और 11)। अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि खाद्य ऋण का अंश पिछले अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा इस वर्ष अधिक था। 1974-75 के अधिक कामकाज के समय में प्रदान सकल ऋण में हुई वृद्धि में खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिए प्रवृत्त ऋण का अंश 31.2 प्रतिशत था जबकि 1973-74 के अधिक कामकाज के समय में यह केवल 13.3 प्रतिशत था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का अंश भी पिछले अधिक कामकाज के समय (15.4 प्रतिशत) की अपेक्षा 1974-75 के अधिक कामकाज के समय में अधिक (19.7 प्रतिशत) था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में से कृषि क्षेत्र को प्राप्त ऋण में हुई वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है; कुल ऋण में हुई वृद्धि में इस क्षेत्र का अंश पिछले वर्ष जहाँ 2.4 प्रतिशत था वहाँ इस वर्ष 8.4 प्रतिशत था। लघु-उद्योग क्षेत्र को प्राप्त अंश अपेक्षाकृत कम था। (जहाँ यह अंश पिछले अधिक कामकाज के समय में 11.2 प्रतिशत था वहाँ 1974-75 के अधिक कामकाज के समय में 7.9 प्रतिशत था)। इसका कारण अन्य बातों के साथ-साथ यह भी था कि इस क्षेत्र को उसकी उपलब्धि के आधार पर ऋण प्रदान किया गया। निर्यात ऋण के अंश में हुई गिरावट भी उल्लेखनीय है। किंतु यह इस बात का संकेत नहीं है कि निर्यात क्षेत्र के प्रति बैंकों द्वारा लापरवाही बरती गयी है। इस गिरावट के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। निर्यातों को जिस अवधि के लिए अधिमार्ग ऋण प्रदान किया जा सकता है उसमें पिछले वर्ष से कमी की गयी थी। इसके परिणाम-स्वरूप इस क्षेत्र को प्रवृत्त ऋण अधिकाधिक बार उपयोग किया जा सका। यह बात किसी अमूक तारीख को ऋण के बकाया स्तर में पायी गयी गिरावट से भी स्पष्ट हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि निर्यात ऋण का वर्तमान स्तर निर्यातों की बालू मात्रा को बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। निर्यातों के लगभग 3,200 करोड़ रुपये के वार्षिक मूल्य को देखते हुए लगभग 750 करोड़ रुपये के बकाया ऋण की राशि मोटे तौर पर इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि एक बार प्रवृत्त ऋण का हर तीन महीने में बार-बार प्रयोग होता है जो अधिमार्ग व्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित नीति में निश्चित सीमा के अनुरूप है। किंतु निर्यातों की विशेष महत्ता को देखते हुए अब 8 मई 1975 की घोषित कम कामकाज के समय की ऋण-नीति के अनुसार अधिमार्ग व्याज दरों पर प्रदान किये जाने वाले ऋण की अवधि में कुछ रियायतें की गयी हैं।

सारणी 10 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण
(भारतीय रिजर्व बैंक में पुनः भुनायी गयी ऋणों को मिलाकर)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	अधिक काम काज का समय 1973-74			अधिक काम काज का समय 1974-75		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
	1	2	3	4	5	6
1. खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिए ऋण	+187 (49.3)	—	+187 (13.3)	+306 (68.6)	—	+306 (31.2)
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (निर्यात ऋण सहित)	+13 (3.4)	+203 (19.8)	+216 (15.4)	+8 (1.8)	+186 (84.7)	+194 (19.7)
(क) लघु उद्योग	+4 (1.0)	+154 (15.0)	+158 (11.2)	+1 (0.2)	+77 (14.4)	+78 (7.9)
(ख) कृषि	+8 (2.1)	+25 (2.4)	+33 (2.4)	+7 (1.6)	+76 (14.2)	+83 (8.4)
(ग) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	+1 (0.3)	+24 (2.4)	+25 (1.8)	—	+33 (6.1)	+33 (3.4)
3. अन्य सभी क्षेत्र* (निर्यात ऋण सहित)	+179 (47.2)	+824 (80.2)	+1003 (71.3)	+132 (29.6)	+350 (65.3)	+482 (49.1)
4. बाह्योत्तर ऋण (2+3)	+192 (50.7)	+1027 (100.0)	+1219 (86.7)	+140 (31.4)	+536 (100.0)	+676 (68.8)
5. मद 4 में से—निर्यात ऋण	+42 (11.1)	+179 (17.4)	+221 (15.7)	+9 (2.0)	—22	—13
6. कुल सकल ऋण (1+4)	+379 (100.0)	+1027 (100.0)	+1406 (100.0)	+446 (100.0)	+536 (100.0)	+982 (100.0)

*इसमें बड़े तथा मझोले उद्योग और थोक व्यापार शामिल हैं।

टिप्पणियाँ : (1) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सकल बैंक ऋण में ऋणों के अनुपातों को दर्शाते हैं।

(2) यह सारणी 59 प्रमुख बैंकों से एकत्रित किये गये आंकड़ों पर आधारित है। अतः कुल ऋण के आंकड़े पिछली सारणी में दिये गये आंकड़ों से पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते।

कम कामकाज के समय की ऋण नीति—1975

70. 1975 के कम कामकाज के समय के लिए निर्धारित ऋण नीति से विवक्षित होता है कि 1974-75 के परंपरागत अधिक कामकाज के समय के अनुमानों में ऋण-नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं किया गया। पिछले वर्ष की तरह बैंकों से कहा गया कि वे रिजर्व बैंक से लिये गये अपने ऋण की मात्रा को क्रमिक रूप से कम करें। एक ओर जहाँ कम कामकाज के समय के लिये माँग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत के पुनर्वित्त का मूल कोटा जारी रहा वहाँ दूसरी ओर इस बात पर जोर दिया गया कि इसे ऋण विस्तार के स्त्रोत के रूप में नहीं, बल्कि केवल अपरिहार्य स्थिति में आवश्यक अस्थायी स्रोत के रूप में माना जाए। पुनर्भुनाई के संदर्भ में अधिक प्रोत्साहन का पालन किया गया; साथ ही मूल कोटा से अधिक न्यूनतम प्रतिशत प्रोत्साहनमूलक वित्तीय सहायता की भी गुंजाइश रखी गयी। खाद्यान्नों की वसूली के लिए अधिक कामकाज के समय के लिए निर्धारित रीति (अर्थात् ऋण में 300 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये के स्तरों के बीच हुई वृद्धि का 50 प्रतिशत पुनर्वित्त और उसके आगे की वृद्धि के लिए पूरी राशि का पुनर्वित्त) से विशेष पुनर्वित्त प्रदान किया गया किन्तु यह भी सूचित किया गया कि इससे अधिक कामकाज के समय में यह सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

71. ऋण नियंत्रणों का सामान्य स्वरूप अपरिवर्तित रहा। नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता पर बल देते हुए बैंकों से कहा गया कि वे अपने कार्यकलाप को इस प्रकार योजनाबद्ध करें कि 1975-76 (मई-अप्रैल) के पूरे वर्ष में ऋण विस्तार जमा-राशियों में होनेवाली वृद्धि के लगभग

63 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक सीमित रहे। निर्यात ऋण की सहायता को दोहराया गया तथा जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, निर्यात ऋण के संदर्भ में कुछ रियायतों की घोषणा की गयी। पहले बैंकों को 90 दिनों से आगे बढ़ाया रहने वाले पोतलवानपूर्व ऋण पर 'सामान्य' बरों पर ब्याज वसूल करने की अनुमति थी। अब यह निवेश दिया गया कि इन मामलों में और 45 दिनों की अवधि के लिए ब्याज दर में 2 प्रतिशत से अतिरिक्त वृद्धि की जा सकती है। साथ ही निविष्ट मजदूरी और भारी इंजीनियरी वस्तुओं के मामले में पोतलवानपूर्व ऋण पर जिस अवधि के लिए रियायती दर पर ब्याज लिया जा सकता है उसे 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया। जब निर्यात के वर्ष में न रहने वाले कारणों से पोतलवानपूर्व ऋण और अधिक अवधि के लिए अग्रणीत हो तब बैंकों को सूचित किया गया कि वे 90 दिनों की और अवधि के लिए उच्चतम सोमा से 2 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज लें। इन मुविष्टाओं के लिए पात्र वस्तुओं की सूची में 44 निर्यात वस्तुएं शामिल की गयी हैं।

72. ऋण वितरण के लिए जिन प्राथमिकताओं का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उनको दोहराया गया और उर्वरकों के वितरण के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। निवेशों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों से यह भी कहा गया कि वे उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दिये जाने वाले मीयादी ऋण में अपने योगदान को बढ़ावें। किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि उक्त ऋण बैंकों के अपने वित्तीय साधनों से ही मीयादी ऋण के लिए निर्धारित नीतियों का पालन करने हुए दिया जाए।

सारणी 11 : बकाया सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(भारतीय रिजर्व बैंक में पुनः धुनायी गयी ढुंडियों सहित)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	26 अप्रैल 1974 को			25 अप्रैल 1975 को		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़
	1	2	3	4	5	6
1. छाद्याओं की वसूली के लिये बिये गये ऋण	423.3	0.5	423.8	564.1	—	564.1
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (निर्यात ऋण सहित)	136.9	1665.1	1802.0	149.8	2000.3	2150.1
(क) लघु उद्योग	8.4	918.2	926.6	7.7	1035.2	1042.9
(क) कृषि	121.5	477.3	598.8	136.4	648.6	785.0
(ग) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	7.0	269.6	276.6	5.7	316.5	322.2
3. शेष सभी क्षेत्र* (निर्यात ऋण सहित)	722.6	4881.3	5603.9	970.5	5101.8	6072.3
4. बाह्यतर ऋण (2+3)	859.5	6546.4	7405.9	1120.3	7102.1	8222.4
5. मद 4 में से-निर्यात ऋण	94.8	740.0	834.8	90.1	659.3	749.4
6. सकल बैंक ऋण (1+4)	1282.8	6547.0	7829.8	1684.4	7102.1	8786.5

*इनमें बड़े और मझोले उद्योग तथा थोक व्यापार शामिल हैं।

टिप्पणी : यह सारणी 59 प्रमुख बैंकों से एकत्रित किये गए आंकड़ों पर आधारित है। अतः सकल बैंक ऋण के आंकड़े सारणी 9 में प्रकाशित से पूर्ण आंकड़ों के रूप से मेल नहीं खाते।

1975 के कम कामकाज के समय की प्रवृत्तियाँ

73. अब तक (1 अगस्त 1975 तक) बालू कम कामकाज के समय की प्रवृत्तियाँ संतोषजनक रही हैं। जमाराशियों में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत अधिक तीव्र रही है। अब तक जमाराशियों में 800 करोड़ रुपयों (6.7 प्रतिशत) की वृद्धि पायी गयी है जबकि पिछले वर्ष की तदनुसृत अवधि में 624 करोड़ रुपयों (6.0 प्रतिशत) की वृद्धि पायी गयी थी। मीयादी जमाराशियों की ओर विशेष रुझान बना रहा। जहाँ 1974 की तदनुसृत अवधि में जमाराशियों में हुई कुल वृद्धि में मीयादी जमाराशियों का अंश 53 प्रतिशत था वहाँ आलोच्य अवधि में कुल वृद्धि में उसका अंश लगभग 54 प्रतिशत रहा। आलोच्य अवधि में (1 अगस्त 1975 तक) बैंक ऋण में पायी गयी 204 करोड़ रुपयों की वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुसृत अवधि में हुई 199 करोड़ रुपयों की वृद्धि की अपेक्षा सीमांत रूप से अधिक थी। छाद्याओं की वसूली के लिए बिये गये अधिमों में 137 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जो पिछले वर्ष हुई 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी। रिजर्व बैंक में पुनः धुनायी गयी ढुंडियों में काफी अधिक गिरावट होने के कारण सकल बैंक ऋण में 97 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जो पिछले वर्ष हुई 151 करोड़ रुपयों की वृद्धि से बहुत कम थी। यदि छाद्याओं की वसूली के लिए बिये गये अधिमों के लिए सकल बैंक ऋण को समायोजित किया जाए तो उसमें 40 करोड़ रुपयों की कमी पायी जाएगी जब कि 1974 के कम कामकाज की तदनुसृत अवधि में 108 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। रिजर्व बैंक से बिये गये उधारों में 191 करोड़ रुपयों की गिरावट पायी गयी जबकि इसके विपरीत 1974 में 122 करोड़ रुपयों की गिरावट पायी गयी थी।

ऋण नीति और उसका कार्यान्वयन

ऋण-नीति के साधन के रूप में ब्याज दरें

74. संक्षेप में पिछले दो वर्षों में कार्यान्वित की गयी ऋण नीति की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहाँ सम्बन्धित तीन पहलुओं पर विचार किया जाता है। उक्त पहलू इस प्रकार हैं : ऋण नीति के साधन के रूप में ब्याज दर उभर आयी,

वस्तुओं का अधिक अच्छा नियंत्रण प्रमल में लाया गया तथा रिजर्व बैंक द्वारा बिये जाने वाले उधारों में औचित्य का तत्त्व लामू किया गया। इनमें से सर्वाधिक उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि मुद्रास्फीति के प्रतिरोध के सन्दर्भ में मुद्रा प्रबन्धन के प्रमुख साधन के रूप में ब्याज दरें उभर आयीं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 1974-75 में ब्याज दरों के समग्र स्वरूप में काफी अधिक वृद्धि की गयी है। इस प्रकार ऋण के प्रयोग में अनुशासन लाने और जमाराशियों के संग्रहण में सहायता पहुंचाने के दुहरे उद्देश्यों के साथ ब्याज दरों में वृद्धि की गयी है। मुद्रास्फीति के मनोविज्ञान के प्रमुख पहलुओं में से एक यह है कि मूल्य वृद्धि की सम्भावना के कारण स्टॉकों को जमा करने की इच्छा बढ़ जाती है। अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था में यह तत्त्व भी काफी महत्वपूर्ण है कि ऋणों के वितरण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लागू किये जाने के अतिरिक्त स्टॉकों को जमा करने की उपर्युक्त प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए जमा की गयी वस्तुओं की लागत को काफी अधिक उच्च-स्तर पर रखा जाये। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बैंकों की जमाराशियों पर प्राप्त होने वाला लाभ वास्तव में इतना कम नहीं होना चाहिए कि उससे जमाराशियों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इन सभी तत्त्वों को वर्तमान ऋण नीति के निर्धारण के समय ध्यान में रखा गया है। जमाराशियों की उच्चतर ब्याज दरों के प्रभावस्वरूप मांग जमाराशियों की अपेक्षा मीयादी जमाराशियों में उच्चतर वृद्धि पायी गयी है। सामान्यतः अधिकांश श्रेणियों के उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज-दर उधारों के लिए निर्धारित न्यूनतम ब्याज-दर से अपेक्षाकृत अधिक है। जून 1974 की मूल सांख्यिकीय विवरणियों से ब्याज दरों के अनुसार ऋण वितरण सम्बन्धी जो अद्यतन आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे यह विदित होता है कि उक्त महीने के अन्तिम शुक्रवार को जहाँ उधारों के लिए निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर 11 प्रतिशत थी, वहाँ सभी उच्चतर ऋणों और अधिमों (अर्थात् 10,000 रुपयों से अधिक ऋण) के 33.8 प्रतिशत पर 12 प्रतिशत से अधिक दरों पर ब्याज लिया गया। इसके विपरीत जून 1973 में उक्त अनुपात केवल 3 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। उधारों की ब्याज दर में अब और अधिक वृद्धि हुई तब अगस्त 1974 में बैंक ऋणों से प्राप्त ब्याज की आय पर 7 प्रतिशत का कर लागू किया गया जिससे ऋण की लागत लगभग एक प्रतिशत बढ़ गयी है। ऐसा प्रतीत होता कि

ऋण की लागत में वृद्धि होने से ऋण की मांग में कमी आ गयी है जो अपेक्षित थी।

स्टाकों का नियंत्रण

75. ऋण की लागत को बढ़ा देने मात्र से स्टार्कों में वांछनीय परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जा सकती। वास्तव में बैंक बेहतर स्टार्क नियंत्रण के लिये कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा स्टार्कों के मानक निर्धारित करने के लिए नियुक्त किये गये अध्ययन बल ने इस प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल, तैयार वस्तुओं तथा प्राप्य वस्तुओं पर विद्यमान अग्रिमों के सम्बन्ध में अनुपालनीय मानकों की अन्तरिम सिफारिशें की हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे इन मानकों को प्रयोग में लाएं और अपने व्यावहारिक अनुभव के सम्बन्ध में सूचना दें। जहाँ पहले ही दिया गया ऋण सिफारिश किये गये मानकों से अधिक है वहाँ यह सुझाव दिया गया है कि बैंक ऋणकर्ताओं के साथ मिलकर ऋण में कमी लाने के एक क्रमबद्ध कार्यक्रम का निर्णय करें। इसके प्रतिरिक्त ऋण के सम्बन्ध में की गयी सामान्य कड़ाई से यह निश्चित हुआ है कि ऋण भंजूर करने के पहले पूरी जांच-पड़ताल करना तथा उसके पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक है। बैंक और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के ऋणकर्ता दोनों अब इस बात की अधिकाधिक समझने लगे हैं तथा वित्तीय अनुशासन के सामान्य स्तर में अब काफी अधिक सुधार आया है।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रवृत्त उधारों के संवर्ध में औचित्य का सिद्धांत

76. ऋण नीति का एक दूसरा पहलू यह है कि वह प्रत्यक्षतः केन्द्रीय बैंक का प्रमुख साधन है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रवृत्त सुविधाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाओं तथा औचित्य के सिद्धान्त पर अधिकाधिक बल दिये जाने के कारण रिजर्व बैंक का यह स्वरूप अधिक स्पष्ट हुआ है कि वह एक ऐसा ऋणदाता है जिसकी सहायता किसी दूसरे स्रोत के अभाव की स्थिति में ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार औचित्य सिद्धान्त का प्रयोग किये जाने से समग्र ऋण नियंत्रण को बनाये रखते हुए अत्यावश्यक प्रयोजनों के निमित्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए अपेक्षित लचीलापन आ गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा अलग-अलग प्रमुख ऋणकर्ताओं को सामान्यतः औपचारिक या अनौपचारिक सहायता संघों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में भी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं खाद्यान्नों की वसूली, तेल कम्पनियों तथा कुछ सरकारी क्षेत्र के प्रमुख यूनिटों के लिए की गयी थीं। आलोच्य वर्ष के दौरान जूट उद्योग तथा व्यापार और उर्वरक वितरण की न्यूनतम आवश्यकताओं का भी मूल्यांकन किया गया तथा उनकी पूर्ति की भी व्यवस्था की गयी।

77. सामान्य नीति के वार्षिक कार्यान्वयन के सन्दर्भ में अपेक्षाकृत अधिक चयनात्मकता का अनुपालन करने की समग्र प्रवृत्ति रही है। इस कारण बैंक ऋण सम्बंधी अपने कार्यकलापों को योजनाबद्ध करने की

आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गये हैं। रिजर्व बैंक से अपनी ओर से पिछले दो वर्षों में बैंकिंग की समग्र प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में मुद्रा प्राधिकारियों की अपेक्षाओं की अग्रिम सूचना दे दी है। इस प्रकार बैंकों से कहा गया है कि 12 महीनों की अवधि में उनके वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात की सीमाएं क्या हों और उन्हें यह भी संकेत दे दिया गया है कि रिजर्व बैंक से वे किस सीमा तक सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें निःसन्देह स्थूल संकेत मात्र हैं और इनमें परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किये जा सकते हैं, फिर भी इनसे बैंकों को अपने कार्यकलापों को योजनाबद्ध करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त अवश्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मौसमी ऋण योजनाओं के स्थान पर वार्षिक ऋण योजनाओं की व्यवस्था कर इस दिशा में प्रारम्भिक कदम उठाया गया है। बैंक भी इस ओर अधिकाधिक जागरूक हो गये हैं कि ऋण प्रदान करने के मामले में समग्र योजनाओं के प्रयोजनों के लिए 'सीमित' या लेखावार दृष्टिकोण के स्थान पर 'व्यापक' या क्षेत्रवार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक बैंक में प्रभावकारी आन्तरिक प्रबंध सूचना प्रणाली को स्थापित करना भी अत्यधिक आवश्यक है। इस सम्बन्ध में बैंकों को सहायता प्रदान करने के निमित्त मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए रिजर्व बैंक आवश्यक कदम उठा रहा है।

मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियाँ

78. 1974-75 में मुद्रा उपलब्धि की जो प्रवृत्तियाँ पायी गयीं वे इस वर्ष के दौरान लागू किये गये प्रतिबन्धात्मक राजकोषीय तथा मुद्रागत नीतियों के प्रभावस्वरूप हुईं। जुलाई 1974 से जून 1975 तक की अवधि के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 1973-74 की अपेक्षा कम वृद्धि हुई अर्थात् उक्त अवधि में मुद्रा उपलब्धि में केवल 725 करोड़ रुपये या 6.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी; यह वृद्धि पिछले वर्ष के दौरान हुई 1488 करोड़ रुपये या 14.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आधे से भी कम थी (सारणियाँ 12 तथा 13 देखें)। पिछले वर्ष मुद्रा उपलब्धि में हुई 14.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1974-75 में 6.3 प्रतिशत की कम वृद्धि पायी गयी। विशेषकर जब हम इसे आलोच्य वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में पायी गयी 2 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धि है। वस्तुतः यह वृद्धि पिछले चौदह वर्षों के दौरान मुद्रा उपलब्धि में पायी गयी न्यूनतम वृद्धि है।

79. मुद्रा उपलब्धि के एक घटक अर्थात् चलमुद्रा की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण थी। जहाँ पिछले वर्ष के दौरान चलमुद्रा में 774 करोड़ रुपये या 13.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि पायी गयी थी वहाँ 1974-75 में केवल 159 करोड़ रुपये या 2.4 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। मांग जमाराशियों में 566 करोड़ रुपये या 11.7 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी जबकि पिछले वर्ष उनमें 714 करोड़ रुपये या 17.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी।

सारणी 12 : मुद्रा उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ (वार्षिक)

(राशि करोड़ रुपये में)

	निम्नलिखित वर्षों में जून के अन्त में बढ़ाया राशि				घट-बढ़
	1973	1974	1975	1973-74	
	1	2	3	4	5
(अ) जनता के पास मुद्रा उपलब्धि (1+2)	9962	11,450	12,175	+1488 (+14.9)	+725 (+6.3)
(1) जनता के पास चलमुद्रा	5829	6603	6762	+774 (13.3)	+159 (+2.4)
(2) मांग जमाराशियाँ	4133	4847	5413	+714 (+17.3)	+566 (+11.7)
(आ) मुद्रा उपलब्धि की घट-बढ़ को प्रभावित करने वाले तत्व (1+2+3+4+5)					
(1) बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (क+ख)	8416	9102	10,491	+686	+1389
(क) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	6149	6570	7515	+421	+945
(ख) अन्य बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण	2268	2532	2976	+264	+444
(2) बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण (क+ख)*	7580	10,014	11,242	+2134	+1228
(क) रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण	290	652	625	+362	—27
(ख) अन्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण	7590	9362	10,617	+1772	+1255
(3) बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	601	683	310	+71	—362
(4) जनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा देयताएँ	482	521	543	+39	+22
(5) बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा देयताएँ (क+ख+ग)	7409	8870	10,411	+1450	+1552
(क) बैंकों के पास सीमावर्ती जमाराशियाँ	5491	6459	7566	+968	+1107
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रा देयताएँ	1143	1474	1955	+331	+481
(ग) भवशिष्ट	873	926	890	+143	—36
(इ) कुल मुद्रागत साधन (अ+आ) (क)	15,455	17,909	19,741	+2454	+1832

* इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों की वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये ऋण शामिल हैं।

80. यदि हम व्यापक मुद्रा¹⁸ के सिद्धान्त का प्रयोग करें तो भी कमी की यही प्रवृत्ति पायी जाएगी। 1974-75 में कुल मुद्रागत साधनों में 1832 करोड़ रुपये या 10.2 प्रतिशत की जो वृद्धि पायी गयी वह निश्चित रूप से 1973-74 में उनमें हुई 2454 करोड़ रुपये या 15.9 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी हालाँकि सीमावर्ती जमाराशियों में हुई 1107 करोड़ रुपये की वृद्धि 1973-74 में पायी गयी 968 करोड़ रुपये की वृद्धि से सीमान्त रूप से अधिक थी।

मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्व

81. यद्यपि राजकोषीय और मुद्रागत नीतियों पर इसके पहले किये गये विचार-विमर्शों से मुद्रा उपलब्धि में पायी गयी गिरावट का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण हो जाता है फिर भी मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों के सन्दर्भ में और अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस सन्दर्भ में तीन प्रमुख तत्वों, अर्थात् बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले शुद्ध ऋण, बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण और बैंकिंग व्यवस्था की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। सारणी 12

के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये ऋणों में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थी; सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों में पिछले वर्ष हुई 421 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1974-75 में 945 करोड़ रुपये¹⁹ की वृद्धि हुई और वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में पिछले वर्ष हुई 264 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 444 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ऋणों में 1228 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष हुई 2134 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। परन्तु बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सरकार तथा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ऋणों में वृद्धि की जो प्रवृत्ति पायी गयी वह काफी हद तक बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 362 करोड़ रुपये की कमी से नियंत्रित हो गयी; 1973-74 के दौरान शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में 71 करोड़ रुपये की वास्तविक वृद्धि पायी गयी थी। इस प्रकार विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई कमी 1974-75 में मुद्रा उपलब्धि का सबसे बड़ा अकेला अवरोधक तत्व सिद्ध हुई।

¹⁸ व्यापक मुद्रा का आणय कुल मुद्रागत साधनों से है जिनमें जनता के पास मुद्रा उपलब्धि तथा बैंकों के पास रहने वाली सीमावर्ती जमाराशियाँ शामिल हैं।

¹⁹ जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, इस सन्दर्भ में भी 1974-75 में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये ऋण का काफी अधिक भाग मुद्रास्फीति उत्पन्न करने वाला नहीं था (खण्ड 'राजकोषीय नीति और मांग प्रवृत्ति' देखिए)।

82. बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रांतर देयताएँ ऐसे दूगरे तत्त्व हैं जिनके कारण मुद्रा उपलब्धि की मात्रा में कमी आयी। 1974-75 में इन देयताओं में शुद्ध रूप से 1552 करोड़ रुपयों में की भारी वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 1450 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इन देयताओं के घटकों में से मीयादी जमा राशियों और भारतीय रिज़र्व बैंक की शुद्ध मुद्रांतर देयताओं में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई।

83. इस संदर्भ में 1974-75 के दौरान चलमुद्रा की जो अत्यधिक न्यूनतर वृद्धि हुई उसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। 1974-75 में चलमुद्रा में 159 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष हुई 774 करोड़ रुपयों की वृद्धि का केवल 20 प्रतिशत थी। इस कमी के स्पष्टीकरण के लिए अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है और यह वास्तव में बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई उपर्युक्त कमी से सम्बद्ध है। विदेशी मुद्रा का अधिकांश भाग खाद्यान्नों, उर्वरकों और ईंधन के आयात का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया गया और केवल इस कारण देश के 1974-75 के आयात बिल में अधिकांश वृद्धि हुई (विवरणों के लिए खण्ड "विदेशी क्षेत्र की भूमिका" देखिए)। अन्ततः इन वस्तुओं/पण्यों की जनता को जो विक्री की गयी उससे संभलन में रहने वाली चलमुद्रा की काफी अधिक राशि कम होने में सहायता मिली। इस वर्ष के दौरान खाद्यान्नों, उर्वरकों, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के वैश्वी फुटकर मूल्यों में वृद्धि होने से चलमुद्रा को वापस लेने की प्रक्रिया में और सहायता मिली। दूसरे शब्दों में जो विदेशी मुद्रा निकाली गयी उससे न केवल सामान्य रूप से मुद्रागत विस्तार को कम करने में सहायता मिली, बल्कि विशेष रूप से अधिकांश विदेशी मुद्रा जिस उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी गयी थी उसके परिणामस्वरूप चलमुद्रा के विस्तार की दर में भी तीव्र गिरावट आयी।

कम कामकाज का समय—1974

84. मुद्रा उपलब्धि पर प्रतिबन्धक राजकोषीय और मुद्रागत नीतियों का जो प्रभाव पड़ा वह समग्र वर्ष में पायी गयी प्रवृत्तियों में थोड़ा बहुत अस्पष्ट-सा था। इसका आंशिक कारण यह था कि वित्तीय और लेखा वर्ष एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। यदि कम कामकाज और अधिक कामकाज के समय की प्रवृत्तियों का अलग-अलग विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। 1969 के बाद पहली बार 1974 के कम कामकाज के समय में जनता के पास रहने वाली मुद्रा उपलब्धि में वास्तविक कमी परिलक्षित हुई (सारणी 14 देखिए)। 1974 के कम कामकाज के समय के दौरान मुद्रा उपलब्धि में 159 करोड़ रुपयों की कमी हुई जो 1973 के कम कामकाज के समय के दौरान हुई 322 करोड़ रुपयों की वास्तविक वृद्धि के सर्वथा विपरीत थी। इस प्रकार 1974 में मुद्रा उपलब्धि में जो कमी आयी उसका एकमात्र कारण यह था कि जनता के पास रहने वाली चलमुद्रा में लगभग 444 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी। इसके विपरीत जमा रकम में हुई वृद्धि थोड़ी बहुत अधिक थी। मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मुद्रा उपलब्धि में हुई कमी के कारण भूत तत्त्व इस प्रकार हैं: बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में 150 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी और बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रांतर देयताओं में 699 करोड़ रुपयों में वृद्धि हुई। इन तत्त्वों से मुद्रा उपलब्धि में जो कमी आयी वह बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये ऋणों में 527 करोड़ रुपयों की वृद्धि होने और बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ऋणों में 171 करोड़ रुपयों की वृद्धि होने से आंशिक रूप से समायोजित हो गयी।

अधिक कामकाज का समय, 1974-75

85. 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 838 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी; उक्त वृद्धि 1973-74 के अधिक कामकाज के समय के दौरान पायी गयी 1219 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में लगभग दो-तिहाई थी। चलमुद्रा और जमा राशि, दोनों घटकों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि परिलक्षित हुई। मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की दृष्टि से सरकार को रिज़र्व बैंक तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में क्रमशः 578 करोड़ रुपयों और 221 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो 1973-74 के अधिक कामकाज के समय के दौरान उनमें हुई 193 करोड़ रुपयों और 74 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में काफी अधिक थी। इसके विपरीत बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये ऋण में 1180 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष हुई 1451 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में काफी कम थी। इनके अलावा शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 130 करोड़ रुपयों की भारी कमी तथा मुद्रांतर देयताओं में हुई 1043 करोड़ रुपयों की काफी अधिक वृद्धि से भी मुद्रा उपलब्धि में कमी आयी।

मूल्य स्थिति

86. मार्च 1972 से निरंतर मूल्य वृद्धि की जो प्रवृत्ति पायी जाती रही वह 1974-75 में बदल गयी। यह स्मरण होगा कि मूल्यों में विशेष रूप से कृषि पण्यों के मूल्यों में भी पिछले दो वर्षों में वह मौसमी गिरावट नहीं आयी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परंपरागत रूप से हुआ करती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो 1974-75 के दौरान मूल्यों का जो परंपरागत स्वरूप प्रत्यावर्तित हुआ वह इस बात का संकेत था कि अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है।

87. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1974-75 में मूल्यों की वृद्धि की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना संभव हुआ है मूल्यों के मासिक औसत स्तर (धोक मूल्य सूचकांक; 1961-62-100) में 1974-75 में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि 1973-74 में उसमें 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी यदि प्रत्येक वस्तु की दृष्टि से तुलना की जाए तो मूल्यों में हुई कम वृद्धि और भी स्पष्ट हो जाती है। जून 1974 के अंत और जून 1975 के अंत के बीच धोक मूल्यों में केवल 0.6 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि पायी गयी जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में लगभग 27.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 15)। इस प्रकार 1974-75 के दौरान जो मूल्य स्थिति निर्मित हुई उसे प्रतिबन्धक मुद्रागत एवं राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन का संचित परिणाम कहा जा सकता है। इसके अलावा ये नीतियाँ जमाखोरी एवं तस्करी को रोकने के लिए अमल में लाये गये कई प्रशासनिक उपायों द्वारा भी अधिक सशक्त हुईं। इस प्रकार अभूतपूर्व मात्रा में उत्पन्न मुद्रास्फीति के कारण 1973-74 में जहाँ अर्थव्यवस्था कमजोर हो गयी थी वहाँ इन प्रयासों से 1974-75 में उसे कुछ राहत मिली।

88. 1974-75 के दौरान पायी गयी मूल्य प्रवृत्ति का तीन स्पष्ट चरणों में अधिक सार्थक विश्लेषण किया जा सकता है। पहला चरण जून 1974 के अंत से सितंबर 1974 के तीसरे सप्ताह तक का है जब धोक मूल्यों में 7 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी; दूसरा चरण 21 सितंबर 1974 से 5 अप्रैल 1975 तक का है जब मूल्यों में 7.4 प्रतिशत की गिरावट आयी और तीसरा चरण अप्रैल 1975 के पहले सप्ताह के बाद का है जब मूल्यों में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति आयी और उनमें 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 13 : मुद्रागत साधन

वर्ष (जुलाई-जून)	प्रमुख निर्वेशक				प्रमुख अनुपात				
	चलमुद्रा	बैंक मुद्राई	मुद्रा उपलब्धि	मीयादी जमा राशियाँ	कुल मुद्रागत साधन	प्रारंभित मुद्रा	मुद्रा उपलब्धि में चलमुद्रा का अनुपात	मुद्रागत साधनों में चलमुद्रा का अनुपात	
अंतिम शुक्रवार को बकाया राशि (करोड़ रुपये)						श्रीसत अनुपात (प्रतिशत)			
1971-72	4979	3544	8523	4476	12999	5604	58.4	38.3	
1972-73	5829	4133	9962	5491	15454	6743	58.5	37.7	
1973-74	6603	4847	11450	6459	17909	7375	57.7	36.9	
1974-75*	6762	5413	12175	7566	19741	7656	55.5	34.3	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (करोड़ रुपये)						सीमांत अनुपात (प्रतिशत)			
1971-72	388	673	1061	816	1877	570	30.6	20.7	
1972-73	850	589	1439	1015	2454	1139	59.1	34.6	
1973-74	774	714	1488	968	2454	841	52.0	31.5	
1974-75*	159	566	725	1107	1832	72	21.9	8.7	
एक वर्ष में हुई प्रतिशत घट-बढ़									
1971-72	8.5	23.4	14.2	22.3	16.9	11.3			
1972-73	17.1	16.6	16.9	22.7	18.9	20.3			
1973-74	13.3	17.3	14.9	17.6	15.9	12.5			
1974-75*	2.4	11.7	6.3	17.7	10.2	0.9			

*अनंतिम भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रहने वाली अन्य जमा राशियों को मिला कर ।

सारणी 14 : मुद्रा उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ (सामयिक)

(राशि करोड़ रुपये में)

	निम्नलिखित समय के दौरान घट-बढ़			
	कम कामकाज का समय		अधिक कामकाज का समय	
	1973	1974	1973-74	1974-75
(अ) जनता के पास मुद्रा उपलब्धि (1+2)	+322	—159	+1219	+838
(1) जनता के पास चलमुद्रा	+96	—444	+783	+508
(2) मांग जमा राशियाँ	+227	+286	+435	+331
(आ) मुद्रा उपलब्धि की घट-बढ़ को प्रभावित करने वाले तत्व (1+2+3+4—5)				
(1) बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (क+ख)	+603	+537	+267	+799
(क) रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	+412	+168	+193	+578
(ख) अन्य बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण	+191	+359	+74	+221
(2) बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण (क+ख)*	+588	+171	+1451	+1180
(क) रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण	+54	—76	+290	+134
(ख) अन्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण	+534	+247	+1160	+1047
(3) बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आप्रतियाँ	+7	—150	+77	—130
(4) जनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा देयताएं	+26	—7	+19	+131
(5) बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा देयताएं (क+ख+ग)	+903	+699	+595	+1043
(क) बैंकों के पास मीयादी जमा राशियाँ	+681	+647	+295	+436
(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा मुद्रा देयताएं	+60	+64	+206	+433
(ग) अवशिष्ट	+162	—12	+94	+176
(इ) कुल मुद्रागत साधन [अ+आ5] (क)	+1003	488	+1514	+1272

*इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अग्रिम शामिल हैं ।

जून-सितम्बर 1974 में मूल्य की प्रवृत्तियाँ

89. इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान थोक मूल्यों के सूचकांक में 1973-74 के पूरे वर्ष में हुई 27.8 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 7 प्रतिशत की वृद्धि (21 सितम्बर तक) पायी गयी। उक्त वृद्धि की मात्रा 1973-74 की उसी अवधि के दौरान पायी गयी 3.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में भी अधिक थी। उक्त मूल्य वृद्धि सभी प्रमुख पण्य वर्गों में पायी गयी जिनमें से “खाद्य वस्तुओं” (8.6 प्रतिशत) तथा “मशीनों और परिवहन उपकरणों” (11.2 प्रतिशत) के मूल्यों में हुई वृद्धि अधिक स्पष्ट थी। “खाद्य वस्तुओं” के वर्ग के अन्तर्गत लगभग सभी खाद्यान्नों के मूल्यों में 11.0 प्रतिशत (ज्वार) और 27.4 प्रतिशत (बाजरा) के बीच वृद्धि पायी गयी। 1973-74 के दौरान बाजरे और गेहूँ के उत्पादन में जो गिरावट आयी वह खाद्यान्नों में मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि का प्राणिक कारण है। गेहूँ का उत्पादन कम होने के कारण गेहूँ की पूर्ति की मात्रा अपर्याप्त हो गयी थी। उक्त स्थिति 1974-75 के विपणन भीसम के लिए सरकार की बसूली नीति में किये गये परिवर्तनों के कारण और अधिक बिकट हो गयी। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण स्तर पर अनाजों की जमाखोरी होने लगी। अतः बाजार में बिक्री के लिए आनेवाली मात्रा में कमी आ गयी। इन गतिविधियों का समग्र परिणाम यह हुआ कि बसूली की मात्रा शोचनीय ढंग से अत्यधिक कम हो गयी और खुले बाजार

में गेहूँ के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। “मशीनों और परिवहन उपकरणों” के मूल्यों में हुई वृद्धि अंशतः सरकार द्वारा लागू किये गये मूल्यों के कारण और अंशतः कच्चे भात, ईंधन और बिजली के उच्चतर मूल्यों के कारण हुई। आलोच्य अवधि में जिन पण्यों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि पायी गयी उनमें रुई (14.5 प्रतिशत) और पटसन (43.7 प्रतिशत) भी थे। अच्छी फसल की संभावनाओं के बावजूद रुई के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका कारण यह हो सकता है कि नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के संबंध में बाधित की पूर्ति करने के निमित्त मशीनें रेशोवाली रुई के संदर्भ में मिलों की मांग बराबर बनी रही; पटसन के मामले में बाढ़ के कारण भारी मात्रा में फसल को भति पहुँचने की सूचनाएं प्राप्त होने के परिणाम-स्वरूप मूल्य वृद्धि हुई।

मौसमी गिरावट : सितम्बर 1974 से अप्रैल 1974 तक

90. 21 सितम्बर 1974 और 5 अप्रैल 1975 के बीच मूल्यों में जो गिरावट आयी वह काफी व्यापक थी। परंतु उक्त गिरावट औद्योगिक कच्ची सामग्री (20.8 प्रतिशत) के मामले में अधिक स्पष्ट थी उसके बाद “खाद्य वस्तुओं” (8.3) प्रतिशत और “निमित्त वस्तुओं” (3.8 प्रतिशत) का स्थान था। यद्यपि मूल्यों में आयी गिरावट को स्थूल रूप से सामयिक स्वरूप का माना जा सकता है, फिर भी कुछ अन्य दृष्टियों से वह विशिष्ट

सारणी 15 : थोक मूल्यों के आधार पर सूचक अंकों की प्रवृत्तियाँ—घट-बढ़ का प्रतिशत

(आधार : 1961-62—100)

समूह/उप समूह/पण्य	वजन*	घट-बढ़ का प्रतिशत							
		1973-74				1974-75			
		जून 1973 का अंत और 22 सितम्बर 1973	22 सितम्बर 1973 और 6 अप्रैल 1974	6 अप्रैल 1974 और जून 1974 का अंत	जून 1973 का अंत और जून 1974 का अंत	जून 1974 का अंत और 21 सितम्बर 1974	21 सितम्बर 1974 और 5 अप्रैल 1975	5 अप्रैल 1975 और जून 1974 का अंत	जून 1974 का अंत और जून 1975 का अंत
सभी पण्य	1,000	+3.7	+14.1	+8.0	+27.8	+7.0	-7.4	+1.5	+0.6
I. खाद्य वस्तुएं	413	+4.6	+7.9	+11.6	+26.0	+8.6	-8.3	+3.4	+2.9
खाद्यान्न	(35.5)	+4.4	+16.1	+12.6	+36.6	+15.6	-11.1	+1.1	+3.8
(क) दालों से भिन्न अनाज	(29.3)	+4.7	+16.7	+15.8	+41.4	+14.3	-8.3	+1.0	+5.9
(1) चावल	(16.2)	+9.1	+15.8	+8.1	+36.7	+12.6	-9.9	+8.9	+10.4
(2) गेहूँ	(7.8)	—	+18.1	+40.3	+65.7	+17.3	-7.1	-10.3	-2.3
(3) ज्वार	(2.2)	+0.5	+9.2	+18.2	+29.7	+11.0	-6.5	-1.8	+1.9
(4) बाजरा	(1.1)	-24.0	+12.2	+18.0	+0.7	+27.4	+13.4	-7.4	+33.6
(ख) दालें	(6.4)	+3.8	+34.3	+2.9	+22.0	+19.8	-20.3	+1.2	-3.4
II. शराब और तमाकू	25	+0.1	+9.9	+12.6	+23.9	+0.4	+1.3	+2.3	+4.1
III. ईंधन, पावर, बिजली और बिकानाई के पदार्थ	61	+2.3	+59.2	-0.2	+62.4	+3.3	+1.0	+0.5	+4.1
VI. औद्योगिक कच्ची सामग्री	121	-1.3	+9.3	+5.6	+13.8	+6.5	-20.8	-1.8	-17.8
(1) रुई	(18.5)	+7.2	+25.9	+6.9	+44.3	+14.5	-14.9	-3.5	-24.8
(2) पटसन	(9.6)	-17.3	-6.6	+7.6	+16.9	+43.7	-18.9	+8.7	+26.7
(3) तिसहन	(43.3)	-2.6	+6.0	+8.1	+11.6	+4.3	-21.7	-2.5	-20.3
(4) मंगफली	(20.8)	-13.8	-2.4	+11.8	-5.9	+4.2	-14.2	+2.0	-8.8
V. रसायन	7	+1.7	+28.4	+4.8	+36.9	+4.7	+9.2	+0.5	+14.9
VI. मशीनों और परिवहन उपकरण	79	+2.1	+21.6	+7.7	+33.7	+11.2	+2.3	+0.7	+14.5
VII. निमित्त वस्तुएं	294	+6.3	+18.8	+4.7	+32.2	+4.8	-3.8	-0.2	+0.6
(क) मध्यवर्ती वस्तुएं	(19.5)	+10.2	+19.5	+8.6	+43.0	-2.2	-11.2	+1.2	-12.1
(ख) सैयार वस्तुएं	(80.5)	+5.0	+18.5	+3.5	+28.9	+7.3	-1.4	-0.7	+5.1
वस्त्र	(38.6)	+5.2	+20.6	+1.3	+28.7	+6.5	-5.8	-1.5	-1.2
(1) सूती वस्त्र	(26.8)	+2.9	+14.1	+6.0	+24.4	+5.5	-3.3	+0.3	+2.2
(2) जूट के वस्त्र	(8.1)	+8.5	+42.9	-7.7	+43.1	+15.0	-14.2	-6.9	-8.2
धातु से बनी वस्तुएं	(13.0)	+6.2	+17.2	+0.2	+24.6	+9.3	+3.6	—	+13.2
रासायनिक वस्तुएं	(9.2)	+4.4	+19.8	+14.2	+42.8	+4.2	+7.7	-0.9	+11.1

*कोष्ठकों के आंकड़ों संबंधित मुख्य समूहों के लिये निर्धारित वजन के प्रतिशत वितरण को दर्शाते हैं।

स्रोत : आर्थिक परामर्शदाता, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय।

थी। पहली बात यह है कि पिछले दो वर्षों में विशेष रूप से 1973 में जल कमन की संभावनाएँ निश्चित रूप से बेहतर की ऐसी मौसमी गिरावट नहीं आयी। वास्तव में 1972-73 और 1973-74 की तदनुरूप अवधियों में मूल्यों में क्रमशः 5 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई; दूसरी बात यह है कि यद्यपि 1974-75 में अधिक मात्रा में गेहूँ की फसल होने की आशा थी, फिर भी ऐसे संकेत पाये गये कि वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का समग्र स्तर 1973-74 की अपेक्षा अधिक नहीं होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि "खाद्य वस्तुओं" में से बाजरे को छोड़कर दालों से भिन्न सभी अनाजों के मूल्यों में 6.5 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत के बीच गिरावट आयी; दालों के मूल्यों में 20.3 प्रतिशत की कमी आयी। मूंगफली के कम उत्पादन की संभावनाओं के बावजूद मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के मूल्यों में क्रमशः 14.2 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत की गिरावट आयी। वनस्पति के उत्पादन में मूंगफली के तेल के प्रयोग पर लगाये गये प्रतिबंध और बाजार में बहुत अधिक मात्रा में इन वस्तुओं के आ जाने के कारण उनके मूल्यों में गिरावट आयी। रुई और पटसन के मूल्यों में भी क्रमशः 31.9 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी। रुई के मामले में विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में बिजली की पूर्ति में कटौती लागू किये जाने से तथा अंतिम बाजारों में अधिक मात्रा में रुई आ जाने के परिणामस्वरूप विश्व का भारी वबाव उत्पन्न होने के कारण उक्त गिरावट आयी इसके अलावा, सूती वस्त्रों के उच्च मूल्यों के प्रति उपभोक्ताओं के विरोध के परिणामस्वरूप भी ऐसा प्रतीत होता है कि भारी मात्रा में स्टॉक संचित हो गये थे और बाद में कतिपय मामलों में उत्पादन में कटौती कर दी गयी थी। यद्यपि समग्र रूप से 85 लाख से 89 लाख गांटों तक का पटसन (मेस्ता सहित) उपलब्ध होने का अनुमान था फिर भी अंशतः सितंबर तक विद्यमान उच्च मूल्यों में सुधार के रूप में तथा अंशतः 6 जनवरी 1975 से 22 फरवरी 1975 तक अट्ट उद्योग क्षेत्र में हुई ठंडताप के कारण मियों की पटसन की खपत में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप उसके मूल्यों में गिरावट आयी; जूट से बनी वस्तुओं के लिए विदेशी मांग में गिरावट आने से भी पटसन के मूल्यों में उक्त कमी आयी।

पुनः मूल्य वृद्धि—अप्रैल से जून 1975 तक

91. 5 अप्रैल और जून 1975 के अंत के बीच मूल्य सूचकांक में हुई 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की अंशतः मौसमी माना जा सकता है; यह वृद्धि अधिकांशतः खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में हुई 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण हुई। इसके विपरीत 'औद्योगिक कच्ची सामग्री' के समूह के मूल्यों में 1.8 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित हुई। 'खाद्य वस्तुओं' के अंतर्गत भी केवल खाद्य के मूल्यों में 8.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई इसके विपरीत गेहूँ के मूल्यों में 10.3 प्रतिशत की गिरावट आयी। इस संदर्भ में इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि अप्रैल 1975 के पहले सप्ताह के बाद मूल्यों में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति आ गयी है फिर भी वृद्धि की मात्रा काफी कम है; उदाहरण के लिए 5 अप्रैल और जून 1975 के बीच हुई केवल 1.5 प्रतिशत की वृद्धि 1974 और 1973 की तदनुरूप अवधियों के दौरान क्रमशः पायी गयी 8.0 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में नगण्य है।

उपभोक्ता मूल्य

92. शोक मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप औद्योगिक कर्मचारियों के अस्थिर भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) में जून 1974 और मई 1975 के बीच 8.6 प्रतिशत वृद्धि पायी गयी जो 1973-74 की उसी अवधि के दौरान पायी गयी 26.2 प्रतिशत की

वृद्धि के मुकाबले में काफी कम थी। शहरी अमेतर कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) में जून 1974 और मार्च 1975 के बीच 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1973-74 की उसी अवधि में उसमें 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

बचत और निवेश

बचत की समग्र प्रवृत्तियाँ

93. यद्यपि अर्थव्यवस्था में 1974-75 में की गयी बचत और निवेश के संबंध में पूरे आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं फिर भी प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर स्थूल प्रवृत्तियों का संकेत दिया जा सकता है। परन्तु हम बात को ध्यान में रखा जाय कि जब थोरे-थोरे आंकड़े उपलब्ध होंगे तब इन अनुमानों में उल्लेखनीय संशोधन हो सकते हैं। निम्नलिखित सारणी 16 में दिये गये आंकड़ों से यह विधित होता है कि राष्ट्रीय आय में देशी बचत का अनुपात 1973-74 के 12.1 प्रतिशत से काफी घटकर 1974-75 में 11.8 प्रतिशत रह गया। बचत में हुई कमी प्रमुख रूप से घरेलू क्षेत्र में पायी गयी। मार्जिनल क्षेत्र की बचत में हुई सामान्य वृद्धि से घरेलू क्षेत्र की बचत में हुई कमी कुछ सीमा तक समायोजित हो गयी। इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत की राशि 1973-74 के 431 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में लगभग 669 करोड़ रुपये हो गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि निजी कंपनी क्षेत्र ने भी कुल बचत में अपने अंश में काफी वृद्धि की है।

सारणी 16—देशी बचत और निवेश : वर्तमान मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत (अंतिम अनुमान)*

संकेत	त्रितीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)		
	1972-73	1973-74	1974-75
1. देशी बचत (शुद्ध)	12.6	12.1	11.8
2. विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि (शुद्ध)	0.8	0.8	2.0
3. कुल निवेश (शुद्ध) (1+2)	13.4	12.9	13.8

*राज्य सरकारों के बजटों के पुनर्वर्गीकरण और अन्य परिवर्तनों के कारण ये अनुमान इसके पहले प्रकाशित अनुमानों से निश्चित रूप से मेल नहीं खाते।

निवेश और विदेशी स्रोत

94. फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि देशी बचत में जो कमी आयी उससे अर्थव्यवस्था में किये जानेवाले कुल निवेश प्रभावित नहीं हुए उनमें वास्तव में सीमांत वृद्धि पायी गयी है। विदेशी स्रोतों से पर्याप्त राशि प्राप्त होने से अर्थव्यवस्था में निवेश की दर को बनाये रखा जा सका; यह अनुमान है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि की मात्रा 1974-75 में 2.0 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पहले वह 0.8 प्रतिशत थी। यह तथ्य इस बात का संकेत देनेवाले मूल्यों में से एक है कि देशी अर्थव्यवस्था के विकास में 1974-75 में विदेशी क्षेत्र ने कितनी सहायता प्रदान की है।

निजी क्षेत्र की बचत से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त राशि

95. सरकारी क्षेत्र (सरकारी उद्यमों सहित सरकारों) द्वारा बाजार ऋणों के रूप में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल) से ली गयी राशि, सरकार पर किये जाने वाले शुद्ध ऋणों, राज्य अधिपत्य निधियों, जीवन

बीमा निगम से लिये गये ऋणों, वाणिज्य बैंकों से लिये गये उधारों और मुद्रा विस्तार की राशि जहाँ 1973-74 में 2587 करोड़ रुपये थी वहाँ 1974-75 में अनुमानतः 2043 करोड़ रुपये थी : इस कमी का मुख्य कारण यह था कि चयमुद्रा में 1973-74 की अपेक्षा 1974-75 में अपेक्षाकृत कम विस्तार हुआ ⁽²⁰⁾ ।

96. अब सरकारों के बाजार ऋणों के बारे में संक्षेप में कहा जाये। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को बाजार ऋणों से संयुक्त रूप से 1974-75 में 708 करोड़ रुपयों की शुद्ध राशि प्राप्त हुई जबकि 1973-74 में 638 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हुई थी। 1974-75 में हुई 70 करोड़ रुपयों की इस वृद्धि में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का अंश क्रमशः 23 करोड़ रुपये और 47 करोड़ रुपये था। 1974-75 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने तीन बार ऋणों के लिये बाजार में प्रवेश किया और उसने शुद्ध रूप से 495 करोड़ रुपये जुटाये। पहले निर्गम में नकदी और ऋण परिवर्तनों की व्यवस्था थी; दूसरे दो निर्गमों में पूर्ण रूप से नकदी अभिधान स्वीकार किये गये। राज्य सरकारों ने दो निर्गमों में शुद्ध रूप से 213 करोड़ रुपये जुटाये। पहले निर्गम में नकदी और ऋण परिवर्तन के आधार पर राज्य सरकारों ने 130 करोड़ रुपये जुटाये और दूसरे निर्गम में जिसके लिये पूर्ण रूप से नकदी का अभिधान स्वीकार किया गया, 83 करोड़ रुपये जुटाये गये।

विदेशी क्षेत्र की भूमिका

97. 1974-75 की अर्थव्यवस्था के विकास पर अब तक जो विचार-विमर्श किये गये हैं उनमें यह केन्द्रीय तत्व उभरता है कि अर्थ-व्यवस्था स्थायित्व की ओर ध्रुवसर हो रही थी ; और इस संक्रमण में विदेशी क्षेत्र ने जो उल्लेखनीय भूमिका अदा की है वह कम महत्वपूर्ण नहीं थी। पहली बात यह है कि वर्ष 1974-75 भुगतान संतुलन के भारी घाटे के साथ समाप्त हुआ-मा प्रतीत होता और आकड़ों के अभाव में उक्त घाटे की सुनिश्चित मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रागत साधनों से काफी राशि प्राप्त होने के कारण हमारी अपनी प्रारक्षित निधियों में भारी गिरावट लाये बिना घाटे की वित्तीय पूर्ति की जा सकी। दूसरी बात यह है कि जूँकि अर्थ-व्यवस्था में खाद्यान्नों की कमी बराबर रहित है, विषय बनी रही अतः खाद्यान्नों का काफी मात्रा में आयात करना आवश्यक हो गया और इस कारण मुद्रा और मूल्य की प्रवृत्तियों में स्थायित्व लायी जा सकी। अब इन दो पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा सकता है।

व्यापार और भुगतान स्थिति

98. वाणिज्यिक मूखता और अब संकल्पन महाविदेशान्तर्गत के आकड़ों के अनुसार 1974-75 के राजकोपीय वर्ष के दौरान व्यापार घाटे की राशि बढ़कर लगभग 1096 करोड़ रुपये हो गयी जो 1973-74 के दौरान स्थित 402 करोड़ रुपयों के घाटे के मुकाबले में दुगुनी से अधिक थी। यद्यपि निर्यातों में हुई 29 प्रतिशत की वृद्धि महत्वपूर्ण थी, फिर भी आयातों में उससे भी अधिक तेजी से 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयातों के मूल्य में हुई अधिक वृद्धि प्रमुख रूप से ईंधन खाद्यान्नों और उर्वरकों के आयातों के कारण हुई। 1974 के प्रारम्भ से तेल के के मूल्यों का सीढ़ी हो जाने से 1973-74 में भुगतान का केवल एक अंश प्रभावित हुआ था ; परन्तु 1974-75 में उसका पूरा प्रभाव महसूस किया गया। इसके अलावा खाद्यान्नों के आयात केवल परिमाण में ही नहीं, बल्कि मूल्यों की दृष्टि से भी अधिक थे। उर्वरकों के संदर्भ में भी यही स्थिति पायी गयी। अंतिम बात यह है कि उपलब्ध निर्देशकों के अनुसार आयातों के संदर्भ में हुई मूल्य वृद्धि निर्यातों के संदर्भ में

में हुई मूल्य वृद्धि की तुलना में औसतन अधिक थी ; उसके परिणाम स्वरूप निर्यात-आयात मूल्य स्थिति में गिरावट आ गयी। अप्रैल से दिसम्बर 1971 तक के आकड़े हम बात का संकेत देते हैं कि निर्यात-आयात मूल्य स्थिति में लगभग 21 प्रतिशत की गिरावट आयी।

निर्यात

99. यह अनुमान है कि 1974-75 के राजकोपीय वर्ष में निर्यातों की राशि लगभग 3253 करोड़ रुपयों के स्तर पर पहुँच गयी है। परन्तु निर्यातों के पण्यवार आकड़े फरवरी 1975 तक उपलब्ध हैं और इनसे यह विदित होता है कि 1974-75 के पहले ग्यारह महीनों (अप्रैल-फरवरी) के दौरान निर्यातों की कुल राशि 2919 करोड़ रुपये थी जबकि 1973-74 की वस्तुसम अंश में उक्त राशि 2143 करोड़ रुपये थी (सारणी 17)। यद्यपि निर्यातों में हुई वृद्धि सभी वस्तुओं के संदर्भ में पायी गयी, फिर भी अधिकतम वृद्धि चीनी के मामले में हुई ; ग्यारह महीनों की अवधि में हुई शुद्ध वृद्धि में चीनी का अंश एक चौथाई से थोड़ा अधिक था। इंजीनियरी वस्तुओं (मशीनों और परिवहन उपकरण, धातु से बनी वस्तुएं और अन्य इंजीनियरी वस्तुएं), जूट से बनी वस्तुओं चाँदी, चाय, कपड़े, काजू की गिरी, प्रमुख रूप से गलक लाख और गुबार पिसान सहित अपरिष्कृत पण्य तथा और वनस्पतिजन्य वस्तुओं के संदर्भ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीनी और इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों में हुई तीव्र वृद्धि जहाँ परिमाण और इकाई मूल्य दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण उत्पन्न हुई वहाँ अन्य वस्तुओं के निर्यातों के संदर्भ में प्रमुख रूप से उच्चतर इकाई मूल्यों के कारण अधिक राशि प्राप्त हुई। चाँदी के मामले में निर्यातों पर 1943 से लागू किये गये प्रतिबंधों को 19 फरवरी 1974 से हटा दिया गया। कतिपय महत्वपूर्ण वस्तुओं अर्थात् खनी, चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं तथा मछली और मछली से बनी वस्तुओं के निर्यातों में काफी अधिक गिरावट आयी जो निर्यातों की समग्र प्रवृत्ति के विपरीत थी।

100. यदि विनावार देखा जाये तो सभी क्षेत्रों को किये गये निर्यातों के मूल्य में वृद्धि हुई। परन्तु कुल निर्यातों में अमेरिका, यूरोपीय साक्षा बाजार के देशों और जापान को किये गये निर्यातों का अनुपात 1973-74 के पहले ग्यारह महीनों में घटकर 52 प्रतिशत था वहाँ 1974-75 के पहले ग्यारह महीनों में घटकर 42 प्रतिशत हो गया। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ सब से बड़े बाजार के रूप में उभर आया जबकि पिछले वर्ष जापान का स्थान सर्वप्रथम था। परन्तु पूर्वी यूरोपीय देशों का अंश 21 प्रतिशत के आसपास अपरिवर्तित रहा। इस प्रकार मुक्त मुद्रा देशों को किये जाने वाले भारत के निर्यातों का अनुपात लगभग अपरिवर्तित रहा।

आयात

101. 1974-75 के राजकोपीय वर्ष के दौरान भारत के आयातों की राशि काफी मात्रा में बढ़कर 4349 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें 1973-74 के स्तर की तुलना में 1123 करोड़ रुपयों या 49 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। आयातों में इस प्रकार तेजी से वृद्धि होने का प्रमुख कारण यह था कि अनेक पण्यों, विशेष रूप से खाद्यान्नों, उर्वरकों एवं पेट्रोलियम की वस्तुओं के मूल्य विदेशों में काफी अधिक थे। 1974-75 के दस महीनों के लिये आयातों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों से यह विदित होता है कि अधिक मात्रा में खाद्य और खाद्योत्पन्न, दोनों प्रकार की वस्तुओं का आयात किये जाने के कारण आयात बिल बढ़ गया था (सारणी 18)। जिन प्रमुख वस्तुओं में शुद्ध रूप से काफी अधिक वृद्धि पायी गयी वे इस प्रकार थी : गेहूँ (218 करोड़ रुपये), खनिज वस्तुएं, ईंधन, चिकनाई के पदार्थ और अन्य संबंधित वस्तुएं (560 करोड़ रुपये), उर्वरकों सहित रासायनिक वस्तुएं (281 करोड़

(20) इस गणना में न तो निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को किये जाने वाले संभाव्य अंतरणों के संदर्भ में कोई समायोजन किया गया है और न ही विदेशी सहायता से प्राप्त शुद्ध राशि का हिसाब में लिया गया है।

रूपये), लोहा और इस्पात (211 करोड़ रुपये) तथा मशीनें एवं परिवहन उपकरण (82 करोड़ रुपये)। इन पांच मदों के आयातों के कुल मूल्य में कुल आयातों के मूल्य में हुई संपूर्ण वृद्धि पायी गयी। अपरिष्कृत और अंशतः परिष्कृत पेट्रोलियम और उर्वरकों के आयातों में लगभग तिगुनी वृद्धि हुई जब कि गेहूँ के आयात में लगभग दुगुनी वृद्धि पायी गयी।

102. भारत के कुल आयातों का लगभग एक तिहाई अंश ईरान, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और जापान के संवर्ध में पाया गया। इन देशों के अंश में 1974-75 के पहले दस महीनों में वृद्धि हुई और वह लगभग 10-11 प्रतिशत थी। भारत के आयातों में पूर्वी यूरोपीय देशों का अंश अप्रैल-जनवरी 1974-75 के दौरान 15.3 प्रतिशत था और इस क्षेत्र के संवर्ध में भारत के व्यापार में नाममात्र के अधिशेष की स्थिति पायी गयी। यह इस तथ्य का संकेत है कि अप्रैल-जनवरी 1974-75 के दौरान देश के व्यापार घाटे का अधिकांश भाग मुक्त मुद्रा देशों के संदर्भ में विद्यमान था।

विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि

103. भुगतान के क्षेत्र में जो भारी घाटा था उसका वित्तपोषण प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गयी राशि से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1974-75 के दौरान निम्न प्रकार 485 करोड़ रुपये निकाले

गये 72.2 करोड़ रुपये का स्वर्ण कोटा, 220.3 करोड़ रुपये का पहला ऋण कोटा और तेल सुविधा के अंतर्गत 192.1 करोड़ रुपये। 1973-74 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गयी राशि केवल 62 करोड़ रुपये थी और वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्यातों के लिये प्रदान अतिपूर्वक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत प्राप्त हुई। इसकी प्रलावा 1974-75 में विदेशी सहायता के रूप में शुद्ध रूप से 480 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो 1973-74 में प्राप्त 254 करोड़ रुपये के लगभग दुगुने थे। यह स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार भारी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त न हुई होती तो मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि-दर को नियंत्रित करने के लिये लागू की गयी मुद्रागत और राजकोषीय नीतियां कम प्रभावकारी सिद्ध हुई होती।

104. व्यापार घाटे का परिणाम 1966-67 और 1967-68 का संकरण दिखाता है जब घाटे की राशि 750 करोड़ रुपये और 950 करोड़ रुपये के बीच पायी गयी थी। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार घाटे की राशि न्यून स्तर पर 99 करोड़ रुपये और 430 करोड़ रुपये के बीच रहने के बावजूद वृद्धि की ओर अग्रसर हो रही है। वास्तव में चिंता की बात यह है कि कम से कम घाटे का काफी अधिक अंश देशी उपभोग के स्तरों को बनाये रखने के लिये किये गये आयातों के कारण उत्पन्न हुआ है।

सारणी 17 : भारत के प्रमुख निर्यात

(राशि करोड़ रुपये में)

पण्य	अप्रैल से फरवरी तक			(2) की तुलना में (3) में वृद्धि (+)/कमी (—)	
	1973-74	1973-74	1974-75	वास्तविक	प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. खाद्यान्न और जीवित जीव जंतु	666	584	868	+ 284	+ 49
1. मछली और मछली से बनी वस्तुएं	88	76	59	--17	--22
2. काजू की गिरी	74	72	111	+ 39	+ 54
3. काफी	46	42	50	+ 8	+ 19
4. चाय (काली)	142	131	199	+ 68	+ 46
5. मसाले	55	43	54	+ 11	+ 26
6. खली	171	149	86	--63	--42
7. चीनी	43	34	256	+ 222	+ 653
II. शराब और तम्बाकू	71	60	76	+ 16	+ 27
अपरिष्कृत तमाख	68	58	74	+ 16	+ 28
III. ईंधन को छोड़कर कच्ची और अक्काय वस्तुएं	357	305	376	+ 71	+ 23
1. रुई (कच्ची और अपरिष्कृत)	37	32	16	-16	--50
2. अभ्रक	13	12	16	+ 4	+ 33
3. कच्चा लोहा (लोहे के टुकड़ों सहित)	133	118	135	+ 17	+ 14
4. पशुजन्तु और वनस्पति जन्तु अपरिष्कृत वस्तुएं (जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं किया गया है)	73	62	108	+ 46	+ 74
IV. खनिज ईंधन चिकनाई के पदार्थ और संबंधित वस्तुएं	15	12	18	+ 6	+ 50
V. पशु जन्तु और वनस्पति जन्तु तेल और जरबी	31	29	34	+ 5	+ 17
वनस्पति तेल	31	29	33	+ 4	+ 14
VI. रसायन	57	46	93	+ 47	+ 102

पण्य	1	2	3	4	5
VII. निर्मित वस्तुएं	988	859	1052	+193	+22
1. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	171	149	132	-17	-14
2. सूती वस्त्र	235	207	201	-6	-3
3. जूट से बनी वस्तुएं @	227	209	281	+72	+34
4. मोती तथा अपरिष्कृत या परिष्कृत बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर	108	89	80	+9	+10
5. लोहा और इस्पात	58	49	73	+24	+49
6. चांदी (बुलियन वेट)	6	—	65	+65	—
VII. मशीनें और परिवहन उपकरण	117	94	185	+91	+97
1. बिजली की मशीनों से इतर मशीनें	47	39	79	+40	+102
2. बिजली की मशीनें, उपकरण और साधन	29	24	50	+26	+108
3. परिवहन उपकरण	41	31	56	+25	+81
IX. विविध निर्मित वस्तुएं	173	147	210	+63	+43
1. कपड़े	95	80	117	+37	+46
2. जूते	13	12	18	+6	+50
कुल निर्यात (दूसरे निर्यातों सहित)	2483	2143	2919	+776	+36

@ इसमें देशा और धागा शामिल हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक सूचना और अंकसंकलन महानिदेशालय

सारणी 18 : भारत के प्रमुख आयात

(राशि करोड़ रुपये में)

पण्य	अप्रैल से जनवरी तक			(2) की तुलना में (3) में वृद्धि (+) या कमी (—)	
	1973-74	1973-74	1974-75	वास्तविक	प्रतिशत
I. खाद्यान्न तथा जीवित जीव जन्तु	547	428	623	+195	+46
1. गेहूं	346*	267	485	+218	+82
2. काजू	29	21	34	+13	+62
II. शराब और तमाखू	नग.	नग.	1	+1	—
III. ईंधन को छोड़कर कच्ची और अखाद्य वस्तुएं	184	147	177	+30	+20
रेणों को छोड़कर रुई	52	49	22	-27	-55
IV. खनिज ईंधन, चिकनाई के पदार्थ तथा संबंधित वस्तुएं	561	370	930	+560	+151
1. अपरिष्कृत तथा अशतः परिष्कृत पेट्रोलियम	417	267	770	+503	+188
2. पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं	143	102	160	+58	+57
V. पशु जन्म तथा वनस्पति जन्म तेल और चरबी	65	55	35	-20	-36
VI. रसायन	352	268	549	+281	+105
1. रसायनिक तत्व तथा मिश्र	105	84	145	+61	+73
2. बवाइयां और औषधीय वस्तुएं	26	21	28	+7	+33
3. निर्मित उर्वरक	162	105	317	+212	+202
VII. निर्मित वस्तुएं	531	408	627	+219	+54
1. लोहा और इस्पात	243	182	339	+211	+165
2. अलौह धातुएं	140	103	151	+48	+47
VIII. मशीनें और परिवहन उपकरण	629	488	570	+82	+17
1. बिजली की मशीनों से इतर मशीनें	417	328	340	+12	+4
2. बिजली की मशीनें, उपकरण और साधन	124	91	124	+33	+36
3. परिवहन उपकरण	88	69	105	+36	+52
IX. विधि निर्मित वस्तुएं	41	32	37	+5	+16
कुल आयात	2921	2192	3559	+1367	+62

*सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से अणु के रूप में आयातित।

नग = नगण्य

स्रोत : वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

मूल्यों पर संतोषजनक प्रभाव

105. विदेशी स्रोतों से अधिक राशि प्राप्त होने का प्रभाव देशी मूल्यों पर भी पड़ा। 1974-75 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में खाद्यान्नों के आयात किये जाने से अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हुए। इस कारण मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा विफल हुई। इसके अलावा खाद्यान्नों की वसूली की निराशाजनक स्थिति के संघर्ष में, यदि अधिक मात्रा में आयात न किये गये होते तो सार्वजनिक वितरण की प्रणाली बिलकुल शोचनीय हुई होती; कुल वितरित खाद्यान्नों में आयातित खाद्यान्नों का भ्रम लगभग आधा था। दूसरा पहलू यह है कि पेट्रोलियम, खाद्यान्नों और उर्वरकों के अधिक आयातों से प्रारंभिक धन पर अंततः प्रभाव पड़ा; इस पहलू पर पहले ही अन्यत्र विचार किया जा चुका है। दूसरे शब्दों में पेट्रोलियम, खाद्यान्नों और उर्वरकों के अधिक आयातों से मुद्रा विस्तार को नियंत्रित करने में सहायता मिली और इससे परोक्ष रूप से ही सही, मूल्यों पर संतोषजनक प्रभाव पड़ा।

1975-76 में विकास की संभावना

106. अंत में 1975-76 में विकास की संभावनाओं का स्थूल रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाये।

107. कई निर्देशक तत्वों से यह विदित होता है कि 1975-76 में अर्थव्यवस्था तीव्र विकास की ओर अग्रसर है। 1975-76 में औद्योगिक क्षेत्र अधिकान्तः मूलभूत वस्तुओं के उद्योगों के विकास के कारण अपेक्षाकृत अधिक विकास की ओर उन्मुख है। अब तक जो अनुकूल वर्षा हुई है उससे कई राज्यों में बिजली की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है और इसके साथ-साथ परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कम हो जाने से औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता का अधिक उपयोग होना चाहिये। समय पर वर्षा होने से अच्छी खरीक फसल होने की संभावना भी बढ़ गयी है। खेती में काम आनेवाली उर्वरक जैसी अग्र्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह संभावना और बढ़ गयी है। 1975-76 के योजना परिषद में 23 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है अर्थात् उसकी राशि को बढ़ाकर 5978 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सामान्यतः सरकारी क्षेत्र के निवेश से गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश के लिये वातावरण निर्मित हो जाता है। योजना परिषद में काफी अधिक वृद्धि होने से गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश पर स्वागत योग्य प्रभाव पड़ेगा।

108. दिनांक 26 जून 1975 को की गयी आपातकाल की घोषणा और 1 जुलाई 1975 को घोषित किये गये नये आर्थिक कार्यक्रम से अर्थ-व्यवस्था को नयी दिशा प्राप्त हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के निर्माण और अन्यथा संघी की स्थिति से ग्रस्त पूंजी बाजार में पुनः सुधार आने के संकेतों से उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट हुआ है। राजकोषीय क्षेत्र में कर-प्रशासन को मजबूत बना देने से पहले से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की वसूली को स्थगित करने, ग्रामीण लोगों के ऋण को छोड़ देने, भूमि की उच्चतम सीमाओं को कार्यान्वित करने और भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के संबंध में जो कदम उठाये जा रहे हैं उनसे उच्चतर कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित हो सकता है।

109. जमाबंदी और नसकरी के विपक्ष सफलतापूर्वक जो कार्रवाइयाँ की गयी उनके कारण मूल्य-स्थिति पर आपतकालीन घोषणा का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। 28 जून और 19 जुलाई 1975 के बीच थोक मूल्यों में एक प्रतिशत की गिरावट पायी गयी। 1974 के उक्त दो महीनों में उनमें वास्तव में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि थोक मूल्य सूचकांक 19 जुलाई 1975 को एक वर्ष पहले के स्तर की

अपेक्षा 2.7 प्रतिशत कम था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने और समीकरण भंडार को बढ़ाने के उद्देश्य से 1975-76 के दौरान काफी अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किये जाने की घोषणा के कारण मूल्यों में स्थिरता की इस प्रवृत्ति के बने रहने की संभावना है। मुद्रागत और राजकोषीय नीतियों को मॉग-प्रबंधन के अनुरूप बनाया जाता रहेगा। अतः समग्र रूप से 1975-76 में मूल्य स्थिरता के प्रति-प्रेक्ष्य में 5 या 6 प्रतिशत विकास होने की संभावना है।

110. विदेशी क्षेत्र में निर्यातों की संभावना काफी अधिक स्पष्ट है। विश्व के पथ बाजार में तेजी कम हो जाने से यह आशा करना अवास्तविक होगा कि चालू वर्ष में निर्यातों में जो तेजी पायी गयी वह 1975-76 में भी रहेगी यह सत्य है कि 1975 के उत्तरार्ध में मंदी की स्थिति से औद्योगिक देशों के उभरने की आशा की जाती है। किन्तु केवल इस कारण भारतीय निर्यातों पर कोई महत्वपूर्ण बाध पड़ना संभव नहीं है। अतः यदि निर्यातों की मात्रा में 8 से 10 प्रतिशत तक की न्यूनतम वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना को साकार करना है तो विशेष कदम उठाने होंगे। ऐसे कठिन प्रयास किये जा चुके हैं जिनसे निर्यातों की मात्रा बढ़े इन प्रयासों में निर्यातों के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनके लिए अतिरिक्त मूलभूत वस्तुओं की पूर्ति करने और आयात लाइसेंसों की क्रियाविधियों को सरल बनाने के लिए की गयी विशेष व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं।

111. यह असंभव नहीं है कि खाद्यान्नों और उर्वरकों के विश्व मूल्यों में हाल ही में कमी आने के बावजूद आयातों के लिए की जाने वाली प्रयासियों में सीमांत रूप से वृद्धि हो। किन्तु इस कारण कि विश्व बाजारों में दूसरे देश अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीद रहे हैं, खाद्यान्नों के मूल्यों की यह प्रवृत्ति अधिक समय तक नहीं रह सकती। अतः खाद्यान्नों के आयातों का एक कार्यक्रम शीघ्र बनाने से बोझ-सा लाभ हो सकता है। तेल के मूल्यों में सीमांत रूप से वृद्धि हो सकती है भले ही उनमें स्थायित्व न आये। अतः 1975-76 में व्यापार क्षेत्र का बाटा समग्र रूप से थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है और विदेशी वित्तीय साधनों की आई 1974-75 की ही तरह व्यापक हो सकती है भले ही वह अपेक्षाकृत अधिक व्यापक न हो। विदेशी सहायता की संभावना संतोषजनक प्रतीत होती है। 'सिल मुद्रिश्वा' के अंतर्गत अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होनेवाली सहायता के अलावा भारत सहायता संघ द्वारा सहायता के जो वचन दिये गये उनसे 17750 लाख डालर प्राप्त होंगे। इसके अलावा सहायता संघीय व्यवस्था द्वारा 1975-76 में जो राशि वितरित की जायेगी वह भी संभवतः अपेक्षाकृत अधिक होगी। इस प्रकार जो विदेशी वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे उनसे 1975-76 में विकास में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा।

112. जब हम मध्यावधि विकास की संभावना की ओर देखते हैं तब बहुत और निवेश की हाल ही की प्रवृत्ति वास्तव में शोचनीय रही है और इस कारण आगामी वर्षों में मुद्रास्फीतिरोधक नीतियों की प्रभाव-शीलता में कमी आने दिये बिना कुल निवेश स्तर को बढ़ाने की महत्वपूर्ण समस्या रहेगी। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि एक ओर वित्तीय साधन जुटाने के प्रयासों को मजबूत बनाया जाये और दूसरी ओर कृषि और कृषि-संबद्ध उद्योगों, रंधन और पावर जैसे छोड़ क्षेत्रों और निर्यात क्षेत्रों में किये जानेवाले निवेश को बढ़ाया जाये। सरकारी क्षेत्र के लिए यह संभव है कि प्रत्यक्ष योगदान द्वारा और गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिकतर निवेशों को बढ़ाने और क्षमता का बेहतर उपयोग कराये जाने के लिये बनायी गयी नीतियों द्वारा ऐसे निवेशों को प्रोत्साहित कर समग्र निवेश-स्थिति में तीव्रता लायी जाये। वास्तव में उद्योगों के ऐसे कठिन सहायक क्षेत्रों में जहाँ बेसी मॉग की मंदी के कारण विकास में बाधा पड़

रही है, यदि रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के मूलसत लक्ष्य की पूर्ति में बाधा नहीं पड़नी चाहिये तो अधिक तीव्र राजकोषीय प्रयासों पर विचार करना होगा ; इन प्रयासों में उत्पादन शुल्क-दरों और अन्य शुल्क-दरों के विन्यास में उपयुक्त संशोधन करना सम्मिलित है । यदि इस प्रकार की मिश्रित नीतियों का अनुपालन किया जाये और अनुशासन की वर्तमान जेतना को बनाये रखा जाये तो पाँचवी योजना के শেষ वर्षों में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि-दर को जारी रखना कठिन नहीं होगा ।

113. मध्यावधि विकास की संतोषजनक संभावनाओं का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि संप्रति लागू रहनेवाली प्रविधिशुद्ध मुद्रागत और ऋण नीतियों में ढिलाई करने की कोई गुंजाइश है । यदि मुद्रास्फीति के निरोधन और भुगतान संतुलन की महत्त्व स्थिति के विकास के बुद्धि लक्ष्यों

की पूर्ति करनी है तो 1974-75 में सावधानी से निर्मित मुद्रागत और राजकोषीय अनुशासन को बनाये रखने की आवश्यकता है । इससे स्पष्ट होता है कि राजकोषीय प्रयासों के संदर्भ में अनुत्पादक और अनावश्यक व्यय को कम करने पर जोर देना होगा । व्यय में कृपायत लाने की दिशा में संतोषजनक ढंग से प्रारंभिक कार्रवाइयों की जा चुकी है और उन्हें आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है । उत्पादन व्यय और आय को बढ़ाने वाले व्यय पर अधिकाधिक जोर देना होगा । मुद्रागत प्रबंधक दृष्टि से यह आवश्यक होता है कि प्राथमिकता प्राप्त और उत्पादक क्षेत्रों को ऋण वितरित करने के उद्देश्य से बनायी गयी ऋण-प्रायोजना-प्रतिक्रिया में और तेजी लानी होगी । यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे राजकोषीय और मुद्रागत तिर्यक्चरण परस्पर एक दूसरे से संशक्त होंगे ताकि मूल्यों में कुछ सीमा तक स्थिरता उत्पन्न हो सके ।

II वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रगति

114. जून 1975 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों की समग्र प्रवृत्ति सतोपजनक थी। यद्यपि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों में हुई वृद्धि 1973-74 के 17.4 प्रतिशत से घटकर 1974-75 में 14.9 प्रतिशत हो गयी थी फिर भी मीयादी जमा राशियों की वृद्धि-दर की बनावे रखना संभव था। कठोर ऋणनीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के कारण 1974-75 में बैंक ऋण में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा निश्चित ही कम थी। शाखा विस्तार कार्यक्रम में और प्रगति हुई और बैंक रहित क्षेत्रों में शाखाएं खोली गयीं। गुणवत्ता की दृष्टि से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को किये गये ऋण वितरण में स्पष्ट प्रगति पायी गयी। ऋणनीति के कार्यान्वयन के संदर्भ में ग्राम्य साधनों के साथ-साथ ऋण प्राधिकरण योजना और प्रमुख ऋण सीमाओं की जांच पड़ताल के कार्यक्रमों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के लाभ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

शाखा विस्तार कार्यक्रम

115. वाणिज्य बैंकों के योजनाबद्ध शाखा विस्तार कार्यक्रम में इस वर्ष के दौरान काफी अधिक तीव्रता पायी गयी। पहले की तरह इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकिंग सुविधाओं के संबंध में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को क्रमिक रूप से कम किया जाये। यह स्मरण होगा कि बैंकों से पहले कहा गया था कि 1972 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आयाती योजनाएं बनायें। 1974 के लिए बनायी गई योजना के अधीन बैंकों को विभिन्न राज्यों में 993 कार्यालय खोलने की अनुमति रिजर्व बैंक से प्राप्त हुई। इसके अलावा योजना के बाहर भ्रमण-भ्रमण बैंकों के आवेदन पत्रों पर सामान्य रूप से नये कार्यालय खोलने के लिए अनुमति दी गयी। आगामी वर्षों में शाखा विस्तार की प्रगति को बनावे रखने के लिए 1975, 1976 और 1977 के तीन वर्षों के लिए 5000 शाखाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बैंकों से कहा गया है कि वे 1975 में शाखाएं खोलने के लिए व्यापक योजनाएं और 1976 और 1977 के लिए अस्थायी योजनाएं प्रस्तुत करें। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिकांश कार्यालय बैंक रहित/कम बैंकयुक्त/ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों, बैंक रहित खंड/तालुका/तहसील मुख्यालयों और कम बैंक युक्त जिलों/राज्यों में हों ताकि बैंकिंग सुविधाओं के संबंध में राज्यों के बीच और साथ ही जिलों के बीच भी विद्यमान विषमताएं कम हों। अधिकांश बैंकों ने 1975 के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं और बैंक द्वारा अब तक परीक्षित प्रस्तावों में से लगभग 1995 नये कार्यालय खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।

116. 1974 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों ने भारत में 1693 कार्यालय खोले और उनसे बैंक कार्यालयों की संख्या दिसंबर 1974 के अंत में बढ़कर 18,180 हो गयी। इसके परिणामस्वरूप प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या में और कमी आयी। जून 1969 के अंत में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत 65,000 (1961 की जनगणना आधार पर) था। यह औसत क्रमशः कम होता हुआ दिसंबर 1973 के अंत में (1971 की जनगणना के आधार पर) 33,000 और दिसंबर 1974 के अंत में (1971 की जनगणना के आधार पर) 30,000 तथा जून 1975 के अंत में 29,000 हो गया। फिर भी 30 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में से 8 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (1971 की जनगणना के आधार पर) 50,000 से अधिक है और

वास्तव में मणिपुर और मिजोरम के संदर्भ में यह जनसंख्या एक लाख से अधिक है; अतः इन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में अधिक कार्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

117. 1974-75 (जुलाई-जून) में वाणिज्य बैंकों ने 1803 कार्यालय खोले जबकि पिछले वर्ष 1593 कार्यालय खोले गये थे (सारणी 19)। इन नये कार्यालयों में से 492 कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा, 851 कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, 459 कार्यालय गैर-सरकारी भारतीय बैंकों द्वारा और 1 कार्यालय सोनाली बैंक (बंगला देश) द्वारा खोले गये।

बैंक रहित क्षेत्र

118. इस वर्ष बैंक की क्षेत्रीय व्यापकता में और प्रगति पायी गयी। इस वर्ष खोले गये 1803 कार्यालयों में से 547 कार्यालय अब तक के बैंक रहित केन्द्रों में खोले गए। चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि पर समग्र रूप से विचार किया जाए तो इस संबंध में हुई प्रगति वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जुलाई 1969 से जून 1975 के अंत तक 10468 कार्यालय खोले गये और उनमें से 5202 (49.6 प्रतिशत) कार्यालय बैंक रहित केन्द्रों में थे। कम बैंक सुविधा प्राप्त राज्यों अर्थात् असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का अंश कुल नये कार्यालयों में 31.6 प्रतिशत था (सारणी 20)।

119. बैंक क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों पर जो विशेष ध्यान देने लगे थे वह इस वर्ष भी जारी रहा और इस संबंध में वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के केन्द्रवार वितरण के आंकड़े सारणी 21 में दिये गये हैं। कुल बैंक कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों का अनुपात जहां जून 1972 के अंत में 35.3 प्रतिशत था वहां जून 1973 के अंत में बढ़कर 36.2 प्रतिशत और जून 1974 तथा जून 1975 के अंत में और बढ़कर 36.4 प्रतिशत हो गया।

विदेश स्थित कार्यालय

120. शाखा विस्तार कार्यक्रम का प्रभाव भारतीय बैंकों के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में भी पाया गया। दिसंबर 1974 के अंत में 17 देशों (पाकिस्तान और बंगला देश को छोड़कर) में 8 भारतीय बैंकों के 63 कार्यालय कार्यरत थे जबकि 1973 के अंत में 12 देशों में 7 बैंकों के 55 कार्यालय विद्यमान थे। भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यालयों की कुल संख्या में पश्चिम जर्मनी फ्रांस, मालदीव द्वीपसमूह, भूटान और दुबई में नये कार्यालय खोले जाने से यह वृद्धि हुई। ब्रिटेन में 2 प्रतिरिक्त कार्यालय और हांगकांग में एक प्रतिरिक्त कार्यालय खोले गये। पश्चिम एशिया में भारतीय बैंकों की व्यापकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1974 के अंत में विदेश स्थित कार्यालयों में अधिकतम संख्या (28) बैंक ऑफ इंडिया की थी; उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (13) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (8) का स्थान था। ग्लोबल कार्यालयों का वितरण इस प्रकार था: यूनाइटेड कमर्शियल बैंक—6, इंडियन ओवरसीज बैंक—4, इंडियन बैंक—2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड का एक-एक। यदि देशवार देखा जाए तो भारतीय बैंकों के 15 कार्यालय ब्रिटेन में, 9 कार्यालय केन्या में, 8 कार्यालय फिजी द्वीप समूह में, 6 कार्यालय सिंगापुर में, हांगकांग और मॉरिशस में पांच-पांच कार्यालय

सारणी 19 : 1973-74 और 1974-1975 के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय

बैंक समूह	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय						बैंक कार्यालयों की संख्या				
	1973-74			1974-75							
	जुलाई- दिसंबर	जनवरी- जून	जुलाई- जून	जुलाई- दिसंबर	जनवरी- जून	जुलाई- जून	जून 30	जून 30	जून 30	दिसंबर 31	जून 30
	1973	1974	1973-74	1974	1975	1974-75	1969	1973	1974	1974	1975
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	135 (42)	73 (23)	208 (65)	311 (128)	93 (49)	404 (177)	1569	2867	3072	3382	3475
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक	64 (23)	25 (8)	89 (31)	58 (21)	30 (6)	88 (27)	893	1563	1652	1710	1739
3. चौवह राष्ट्रीयकृत बैंक	697 (263)	212 (55)	909 (318)	607 (187)	244 (55)	851 (242)	4133	8109	9017	9621	9863
4. अन्य अनुसूचित बैंक	250 (90)	128 (42)	378 (132)	264 (55)	180 (33)	444 (88)	1320	2580	2943	3206	3385
5. विदेशी बैंक	—	—	—	1 (—)	—	1 (—)	130	130	130	131	131
6. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1146 (418)	438 (128)	1584 (546)	1241 (391)	547 (143)	1788 (534)	8045	15249	16814	18050	18593
7. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3 (1)	6 (1)	9 (2)	8 (6)	7 (7)	15 (13)	217	113	122	130	137
8. सभी वाणिज्य बैंक	1149 (419)	444 (129)	1593 (548)	1249 (397)	554 (150)	1803 (547)	8262	15362	16936	18180	18730

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े बैंक रहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या को दर्शाते हैं।

सारणी 20 : जून 1973, जून 1974 और जून 1975 के अंत में विद्यमान बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य	निम्नलिखित अवधि के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या						निम्नलिखित अवधि के अंत में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या					
	1973-74			1974-75								
	जून 1973	जून 1974	दिसंबर 1974	जून 1975	के	के						
							दौरान	उनमें	दौरान	उनमें	(हजार में)	
							खोले गये	से बैंक	खोले गये	से बैंक		
							(जुलाई	रहित	(जुलाई	रहित		
							1973 से	केंद्रों में	1974 से	केंद्रों में	जून 1974	दिसंबर 1974
							जून	खोले गये	जून	खोले गये	जून 1975	जून 1976
							1974		1975			
							तक)		तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ग्रामीण प्रदेश	1103	1234	1338	1373	131	48	142	42	35	32	32	
प्रसम	168	184	207	214	16	8	28	10	81	71	68	
बिहार	593	672	755	796	79	36	126	66	84	75	71	
गुजरात	1320	1436	1525	1552	116	25	117	18	18	18	17	
हरियाणा	338	390	425	438	52	17	48	21	26	24	23	
हिमाचल प्रदेश	136	150	176	181	26	17	22	9	22	20	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जम्मू और काश्मीर	139	164	174	189	26	9	26	7	28	27	24
कर्नाटक	1479	1621	1700	1750	143	59	130	26	18	17	17
केरल	1072	1163	1247	1296	89	37	133	46	19	17	16
मध्य प्रदेश	748	820	882	914	80	28	95	27	51	47	46
महाराष्ट्र	1866	2005	2144	2188	140	19	183	41	25	24	23
मणिपुर	9	9	10	10	—	—	1	—	119	107	107
मेघालय	17	18	21	21	1	1	3	2	56	48	48
नागालैंड	6	7	8	8	1	—	1	1	74	65	65
उड़ीसा	225	255	291	301	30	16	46	26	86	75	74
पंजाब	772	869	937	961	97	57	93	34	16	14	14
राजस्थान	664	743	775	792	79	33	49	14	35	33	33
तामिलनाडु	1650	1784	1880	1935	134	36	152	35	23	22	21
त्रिपुरा	14	18	20	20	4	2	2	1	86	78	78
उत्तर प्रदेश	1497	1673	1823	1896	177	57	223	94	53	48	47
वैश्वम्प बंगाल	882	987	1059	1090	108	35	103	20	45	42	41
अंदमान और निकोबार द्वीप											
समूह	4	5	5	5	1	1	—	—	23	23	23
अरुणाचल प्रदेश	5	6	7	7	1	1	1	1	78	67	67
चंडीगढ़	41	44	52	53	3	1	9	—	6	5	5
दादरा और नगर हवेली	4	4	4	4	—	—	—	—	19	19	19
दिल्ली	455	502	548	563	50	—	61	—	8	7	6
गोवा दमन और दीव	125	133	136	140	8	4	7	2	6	6	6
लक्ष द्वीप	4	4	4	4	—	—	—	—	8	8	8
मिजोराम	1	1	1	1	—	—	—	—	332	332	332
पांडिचेरी	25	26	26	28	1	—	2	1	18	18	16
औड़	15,362	16,936	18,180	18,730	1,593	547	1,803	547	32	30	29

सारणी 21 : वाणिज्य बैंक कार्यालयों का क्षेत्रवार वितरण

निम्नलिखित अधिकांश के क्षेत्र में कार्यालयों की संख्या

क्षेत्र	जून 1969	जोड़ में प्रतिशत	जून 1971	जोड़ में प्रतिशत	जून 1972*	जोड़ में प्रतिशत	जून 1973	जोड़ में प्रतिशत	जून 1974	जोड़ में प्रतिशत	जून 1975	जोड़ में प्रतिशत
1. ग्रामीण	1832	22.4	4279	35.6	4814	35.3	5561	36.2	6165	36.4	6806	36.4
2. अर्ध शहरी	3322	40.1	4016	33.4	4385	32.2	4723	30.8	5089	30.0	5570	29.7
3. शहरी	1447	17.5	1778	14.8	2323	17.1	2573	16.7	2899	17.1	3266	17.4
4. महानगर/पतन शहर	1661	20.0	1940	16.2	2100	15.4	2505	16.3	2783	16.5	3088	16.5
औड़	8262	100.0	12013	100.0	13622	100.0	15362	100.0	16936	100.0	18730	100.0

* 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनर्वर्गीकृत।

टिप्पणियाँ :—ग्रामीण केन्द्र—दस हजार तक की जनसंख्यायुक्त स्थान।

अर्ध शहरी केन्द्र :—दस हजार से अधिक और एक लाख तक की जनसंख्यायुक्त स्थान।

शहरी केन्द्र :—(क) महानगर : दस लाख से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान।

(ख) अन्य : एक लाख से अधिक और दस लाख तक की जनसंख्यायुक्त स्थान।

और 3 कार्यालय श्रीलंका में थे। शेष 12 कार्यालय दूसरे दस देशों में विद्यमान थे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ोदा के विदेशी महायुक्त बैंक के 5 कार्यालय नाइजीरिया और युगांडा में विद्यमान थे।

121. विश्व स्थित भारतीय बैंकों के कार्यालयों की कुल जमा-राशियाँ दिसंबर 1973 के अंत में स्थित 274 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 1974 के अंत में 427 करोड़ रुपये हो गयी। मांग

जमा राशियाँ 119 करोड़ रुपये से बढ़कर 205 करोड़ रुपये और सीमांशी जमा राशियाँ 155 करोड़ रुपये से बढ़कर 222 करोड़ रुपये हो गयी। भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यालयों द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि जहाँ दिसंबर 1973 में 183 करोड़ रुपये थी वहाँ दिसंबर 1974 में बढ़कर 252 करोड़ रुपये हो गयी। अमराशियों में अधिक वृद्धि होने के कारण दिसंबर 1973 में स्थित 66.7 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात घटकर दिसंबर 1974 में 58.9 प्रतिशत हो गया।

अग्रणी बैंक योजना

122. यह स्मरण होगा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अग्रणी बैंक योजना का प्रथम चरण सभी जिलों में पूर्णतः प्रभावशाली संयोजन कार्य समाप्त हो जाने से पूरा हो गया था। किन्तु 14 राज्यों में जिलों का पुनर्गठन किये जाने के परिणामस्वरूप कतिपय नये जिले बनाने पड़े। पुनर्गठन के बाद जिलों की कुल संख्या बढ़कर 373 हो गयी। अतः इस योजना के अधीन बैंकों के लिए इस नये जिलों को वितरित करना आवश्यक हो गया। चूंकि बैंक अपने जिलों में आवश्यक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम करने, ग्रहण क्षेत्र में विद्यमान खाद्यों या पशु लगान, विकास कार्यक्रम बनाने और शाखाओं को फैलाने के संबंध में काफी अधिक प्रयास कर चुके थे अतः इस स्थिति में अग्रणी बैंकों के शायद ही कोई बड़ा परिवर्तन करने से योजना की सफलता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। अतः यह निश्चय किया गया कि 14 राज्यों में नये सिरे से गठित किये गये अधिकांश जिलों को उन्हीं बैंकों में वितरित किया जाए जो मूल जिलों के अग्रणी बैंकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और सुविधारहित वर्गों को ग्रहण

123. वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर कृषि क्षेत्र को प्रदान किये जाने वाले ग्रहण में और वृद्धि हुई। निर्यात क्षेत्र को भी अधिक सुविधा प्रदान की गयी। अनुसूचित जातियों

और जनजातियों के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए लागू की गयी विभेदक ब्याज दर योजना के कार्यान्वयन में और प्रगति हुई।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ग्रहण

124. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किये गये ग्रहणों का ग्रंथ दिसम्बर 1973 में कुल ग्रहणों का 24.8 प्रतिशत था जो दिसम्बर 1974 में बढ़कर 26.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 22) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किये गये कुल ग्रहणों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ग्रंथ दिसम्बर 1974 के अंत में 89 प्रतिशत था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान कुल ग्रहणों में स्टेट बैंक समूह और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों का ग्रंथ क्रमशः 30.8 प्रतिशत और 59 प्रतिशत था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्राप्त ग्रहणों में लघु उद्योगों का ग्रंथ जहां दिसम्बर 1973 में 49.0 प्रतिशत था वहां दिसम्बर 1974 में बढ़कर 48.2 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान ग्रहणों में कृषि के लिए प्रदान ग्रहणों का ग्रंथ 24.1 प्रतिशत से बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया।

कृषि क्षेत्र को सहायता

125. कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में न केवल कृषि के लिए प्रदत्त प्रत्यक्ष वित्त का अनुपात बढ़ा, बल्कि बैंक छन किसानों

सारणी 22 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गए अग्रिम

(राशि करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर 1973 (अन्तिम)				दिसम्बर 1974 (अन्तिम)			
	स्टेट बैंक समूह	चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	स्टेट बैंक समूह	चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. कुल बैंक ग्रहण	2004	3911	5915	7062	2225	4441	6666	7914
II. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गए अग्रिम								
(क) कृषि :—								
(i) प्रत्यक्ष वित्त	105	264	369	423	156	323	479	539
(ii) परोक्ष वित्त	58	120	178	195	73	154	227	242
(ख) लघु उद्योग	317	450	767	859	370	540	910	1017
(ग) सड़क तथा जल परिवहन वाहक	11	68	79	98	15	80	95	121
(घ) श्रोक व्यापार तथा छोटे कारोबार	27	89	116	141	32	93	125	149
(ङ) व्यावसायिक तथा स्वनिर्योजित व्यक्ति	3	26	29	34	4	30	34	40
(च) शिक्षा	—	4	4	4	—	4	4	4
जोड़ (क से च तक)	521	1021	1542	1754	650	1224	1874	2112
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सभी बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों में बैंक समूह का प्रतिशत ग्रंथ	29.7	58.2	87.9	100.0	30.8	58.0	88.7	100.0
बैंक समूह द्वारा दिये गये कुल ग्रहण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का प्रतिशत	26.0	26.1	26.1	24.8	29.2	27.6	26.1	26.7

की सहायता में भी अधिकाधिक योगदान देते रहे जिन्हें दूसरी वित्तीय संस्थाओं से सुविधा प्राप्त होती थी। उदाहरण के लिए बैंक चुने हुए जिलों में छोटे कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक और कृषि श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत आनेवाले कृषकों की सहायता करते रहे। इन क्षेत्रों में पता लगाये गये कृषकों को वितरित की गयी ऋण राशि दिसंबर 1974 के अंत में 17.69 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राशि दिसंबर 1973 में 10.78 करोड़ रुपये थी।

126. वाणिज्य बैंकों द्वारा गठित कृषक सेवा समितियों के माध्यम से कृषकों का वित्तपोषण करने की जो योजना प्रायोगिक रूप से कतिपय चुने हुए छोटे कृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक और कृषि श्रम परियोजना क्षेत्रों में लागू की गयी थी उसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। अब तक ऐसी 25 समितियाँ नौ राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के ग्यारह बैंकों द्वारा गठित की गयीं। ये समितियाँ कृषकों को विभिन्न प्रकार का समन्वित ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करेगी। उन सेवाओं में खेती में काम आनेवाली मूल वस्तुएं और उत्पादित वस्तुओं के विपणन की सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित हैं।

127. अनुसूचित वाणिज्य बैंक ऐसी योजनाओं में अधिकाधिक मात्रा में अपना योगदान अर्पित करते रहे जिनके लिए कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मई 1975 तक मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या और घायदा की गयी वित्तीय सहायता क्रमशः 1140 और 218.40 करोड़ रुपये थी। कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा वाणिज्य बैंकों को वितरित की गयी राशि जहाँ जून 1974 के अंत में 29.54 करोड़ रुपये थी वहाँ मई 1975 तक 40.36 करोड़ रुपये हो गयी। जहाँ वाणिज्य बैंकों द्वारा अधिकांशतः लघु सिंचाई योजनाओं का वित्तपोषण किया गया वहाँ उनकी सहायता प्राप्त अन्य योजनाएं इस प्रकार थीं : बागान/बागबानी, कृषि का मशीनीकरण, डेरी विकास, मृगीपालन और बकरी पालन, भूमि-विकास, भंडारण/बाजार यादें और मत्स्यपालन का विकास।

128. आलोच्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंक छाठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में लघु सिंचाई, भूमि-विकास, कृषि के मशीनीकरण आदि के कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से मंजूर की गयी परियोजनाओं में योगदान देते रहे। 1974-75 के दौरान चंबल और राजस्थान नहर क्षेत्र विकास की परियोजनाएं कारगर सिद्ध हुईं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के चुने हुए जिलों में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से एक सुखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा है।

कृषि अभिनों की वसूली

129. 1973-74 में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण इस वर्ष के दौरान कृषि अभिनों (प्रत्यक्ष वित्त) की वसूली में स्पष्टतः सुधार पाया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्रत्यक्ष कृषि अभिनों के लिए की गयी मांग की राशि (अर्थात् पिछले जून के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान अति-देय राशि और जुलाई-जून, 1973-74 के दौरान विद्यमान वर्तमान मांग) बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये हो गयी जबकि पिछले वर्ष उक्त मांग की राशि 27.6 करोड़ रुपये (संशोधित) थी। इसके साथ ही 1973-74 के दौरान बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि 1972-73 के 9.7 करोड़ रुपयों (संशोधित) के मुकाबले में तेजी से बढ़कर 28.4 करोड़ रुपये हो गयी।

130. यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से की गयी कुल मांग में वसूली का अनुपात जून 1973 के अंत में विद्यमान 48.0 प्रतिशत से केवल थोड़ा-सा बढ़कर जून 1974 के अंत में 48.7 प्रतिशत हुआ फिर भी कई राज्यों में वसूली के अनुपात में काफी अधिक सुधार पाया गया। 1973-74 के दौरान मांग में वसूली का अनुपात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल में उल्लेखनीय था। इसके विपरीत असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, वमण और दीव तथा पांडिचेरी के संघशासित क्षेत्रों में वसूली में विराट आयी।

131. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंकों के क्षेत्र-अभिस्वीकरण कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अभिस्वीकृत गांवों की कुल संख्या जहाँ जून 1973 के अंत में 9631 थी वहाँ जून 1974 के अंत में बढ़कर 14063 हो गयी। मार्च 1974 के अंत तक स्टेट बैंक समूह ने ग्राम अभिस्वीकरण योजना के अंतर्गत कुल 12597 गांवों को अभिस्वीकृत किया था।

विशेषक व्याज दर योजना

132. इस वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषक व्याज दर योजना में और रियायतें की गयीं। यह स्मरण होगा कि इस योजना के अधीन केवल भूमिहीन व्यक्ति और छोटी जोतभूमि युक्त व्यक्ति ही (जिनके पास एक एकड़ से अनधिक सिंचित भूमि और 2.5 एकड़ की असिंचित भूमि है) ऋण प्राप्त करने के पात्र थे। पात्रता के इस मानदंड में रियायत की गयी जिससे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य अब इस योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं चाहे उनकी जोत भूमि कुछ भी क्यों न हो। बल्कि उन्हें योजना में निर्धारित शर्तों की पूर्ति करनी होगी। इस योजना के अधीन ऋण प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने और प्रगति की। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है कि दिसंबर 1973 और दिसंबर 1974 के बीच ऋण-खातों की संख्या और बढ़ाया ऋण राशि, दोनों में तीव्र वृद्धि हुई। बढ़ाया ऋण राशि 10.00 करोड़ रुपयों से बढ़कर 13.35 करोड़ रुपये हो गयी तथा ऋण-खातों की संख्या भी 230661 से बढ़कर 313026 हो गयी। प्रति खाते औसत ऋण राशि जहाँ दिसंबर 1973 के अंत में ₹ 433 थी वहाँ दिसंबर 1974 के अंत में सीमांत रूप से घटकर ₹ 428 हो गयी।

निर्यात क्षेत्र

133. हाल ही के वर्षों में जिस दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा वह निर्यात क्षेत्र है। इस वर्ष के दौरान इस संदर्भ में जो संशोधन किये गये वे उल्लेखनीय हैं। बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की व्याज दरों में वृद्धि किये जाने के कारण निर्यात ऋण संबंधी व्याज की अधिकतम दर को जुलाई 1974 में 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दिया गया; किन्तु यह वृद्धि प्रास्थगित भ्रदायगी की शर्तों से इतर शर्तों पर दिये जाने वाले पोतलवानोत्तर ऋण पर लागू नहीं है। प्रास्थगित भ्रदायगी की शर्तों पर दिये जानेवाले ऋण पर व्याज की उच्चतम दर 24 सितंबर 1974 तक 7 प्रतिशत ही रही। उसके बाद बैंकों द्वारा अर्जित व्याज पर कर लागू किये जाने के बाद उस दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही दूसरे निर्यात ऋणों की अधिकतम व्याज दरों को भी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत किया गया। एक साल से अधिक अवधि के लिए केवल प्रास्थगित भ्रदायगी के आधार पर दिये गये पोतलवानोत्तर ऋण पर 8 प्रतिशत की

रियायती उच्चतम दर लागू है जाहे ऋण राशि एक मुश्तवेय हो या किश्तों में देय हो। शुल्क वापसी और नकदी प्रोत्साहनों पर पोतलदानपूर्व या पोतलदानोत्तर चरण पर दिये जानेवाले ऋणों और अग्रियों के संबंध में 90 दिनों से अनधिक अवधि तक के लिए उच्चतम व्याज दर लागू की गयी।

13.4. पैकिंग ऋण के लिए जो रियायती व्याज दर उपलब्ध थी उसकी अवधि को 90 दिनों तक सीमित किया गया और बैंकों को उक्त अवधि के आगे बकाया रहने वाली ऋण राशि पर 'सामान्य' दरों पर व्याज लेने की अनुमति दी गयी। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण निर्यात क्षेत्र को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता थी अतः 1975 के कम कामकाज के समय की नीति के अंश के रूप में यह घोषित किया गया कि जिस अवधि के लिए 11.5 प्रतिशत की रियायती व्याज दर लागू होगी उसे निदिष्ट मसौली और भारी इंजीनियरी वस्तुओं तथा विदेशों में किये गये निर्माण ठेकों के मामले में 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाएगा। जब निर्यात के निर्वहन से बाहर के कारणों से पोतलदानोत्तर ऋण के लिए दीर्घतर अवधि की आवश्यकता हुई तब बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे निदिष्ट मसौली और भारी इंजीनियरी वस्तुओं तथा विदेशों में किये गये निर्माण ठेकों के मामले में 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए 13.5 प्रतिशत से अधिक दर पर व्याज न लें। सूची में निर्यात योग्य 44 उद्योगों को सम्मिलित किया गया और उन पर यह रियायत लागू होगी।

13.5. दूसरे पैकिंग ऋणों के मामले में जिस अवधि के लिए 11.5 प्रतिशत की रियायती व्याज दर लागू है वह 90 दिन ही रहेगी। किंतु यदि ऐसे ही कारणों से पोतलदानोत्तर ऋण दीर्घतर अवधि के लिए देना पड़े तो बैंकों को सूचित किया गया कि वे 45 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए 13.5 प्रतिशत से अधिक दर पर व्याज न लें।

13.6. ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन पोतलदान पूर्व निर्यात ऋण के लिए पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने से जो छूट दी जाती थी उसे जुलाई 1974 में वापस ले लिया गया। जहां पोतलदानोत्तर ऋण के संबंध में छूट जारी रही वहां निर्यात पैकिंग ऋण (शुल्क वापसी, नकदी सहायता आदि पर दिये जानेवाले अग्रियों सहित) के लिए की जानेवाली मंजूरी को ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत लाया गया। इस प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पोतलदान पूर्व निर्यात ऋण सीमाएं पहले किए गये निर्यातों को देखते हुए उचित हैं और कुल ऋण सीमाएं कुल उत्पादन के अनुरूप हैं। किन्तु एक बैंक द्वारा (उक्त योजना के अधीन आनेवाले) किसी एक ऋणकर्ता को दी जाने वाली 5 लाख रुपये से अधिक निर्यात पैकिंग ऋण सीमाओं पर पूर्व प्राधिकरण की अपेक्षा की लागू किया गया है। 25 लाख रुपये से अधिक वर्तमान पैकिंग ऋणों के संदर्भ में बैंकों को चाहिए कि वे ऐसी सुविधाओं को जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक को प्राधिकरण की मांग करते हुए आवेदन करें।

निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना, 1968

13.7. निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना, 1968 के अधीन वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा से अनधिक व्याज दर पर दिये गये निर्यात ऋण के लिए वे वार्षिक 1.5 प्रतिशत के व्याज उपदान के पात्र हैं। इस योजना के अधीन 7.53 करोड़ रुपये के उपदान के लिए 43 पात्र बैंकों से प्राप्त दावे जुलाई 1974 में जून 1975 तक निपटा दिये गये। इनमें पोतलदान पूर्व ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण की राशि क्रमशः 4.21 करोड़ रुपये और 3.32 करोड़ रुपये थी। इस योजना के प्रारंभ से 30 जून 1975 तक विवरित की गयी कुल उपदान राशि 30.97 करोड़ रुपये थी।

निर्यात वित्त संबंधी स्थायी समिति

13.8. निर्यात वित्त की समस्याएं न केवल जटिल हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में उनके स्वरूप में परिवर्तन भी हो सकते हैं। जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी तब उनपर कार्रवाई करने के लिए सांस्थानिक सुविधा प्रदान करने के निमित्त रिजर्व वित्त बैंक ने निर्यात वित्त संबंधी एक स्थायी समिति गठित की है। इस समिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, केन्द्रीय वाणिज्य और वित्त संस्थानों तथा वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। स्थायी समिति से आशा की जाती है कि वह न केवल निर्यात ऋण संबंधी नितियों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं पर विचार करें, बल्कि ऐसी समस्याओं की परिकल्पना कर उनपर भी विचार करें और उनके लिए उचित समाधान सुझाएं।

सहायता संघ/सहभागिता की व्यवस्थाएं

अध्ययन दल

13.9. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि दिसंबर 1973 में रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल गठित किया था उसके उद्देश्य निम्न प्रकार थे: सहायता संघ/सहभागिता के आधार पर ऋण सीमाएं प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी मित्रता बनाए जाएं और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के गुणितों में अग्रियों को वितरित करने, कमजोर यूनिटों के पुनर्गठन के लिए बैंकों के बीच सहभागिता की व्यवस्था करने तथा विविध बैंकों के संदर्भ में बैंकों के बीच बेहतर समन्वयन और सहयोग की स्थापना करने के लिए सकारिणें प्रस्तुत की जाएं। अध्ययन दल की सकारिणों के परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को यह सुझाव दिया है कि निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र (बिजली बोर्ड सहित) के किसी एक ऋणकर्ता को बैंकों द्वारा उसकी जमा राशियों से 1.5 प्रतिशत अधिक ऋण सीमाएं सामान्यतः सहभागिता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। बैंकों से यह कहा गया कि वे इन मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान अग्रियों की जांच पड़ताल करें और जहां आवश्यक हो, सहभागिता की व्यवस्थाएं करें। जहां ऋण सीमाएं नभीकरणीय हो जाती हैं या जहां ऋण सीमाओं में काफी अधिक वृद्धि की मांग की गयी है या ऋणकर्ताओं के कार्य में ह्रास के संकेत पाये जाते हैं वहां ऋणकर्ता की ऋण संबंधी अपेक्षाओं की संयुक्त जांच पड़ताल करने का सुझाव भी दिया गया।

सहभागिता प्रमाणपत्र योजना

14.0. आलोच्य वर्ष के दौरान सहभागिता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित णतों में संशोधन किया गया। मूलतः प्रायोगिक रूप से प्रारंभ की गयी इस योजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया और अब उसकी अवधि को जून 1976 के अंत तक और बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बैंकों की संख्या जहां जून 1974 के अंत में 34 थी वहां जून 1975 के अंत में बढ़कर 37 हो गयी है (जुलाई 1975 में एक और बैंक को अनुमोदित किया गया है)। जारी किये गये तथा बकाया रहनेवाले सहभागिता प्रमाणपत्रों की राशि अप्रैल 1975 के अंत में 87.07 करोड़ रुपये थी।

14.1. बैंकों को केवल अन्य वाणिज्य बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय सामान्य बीमा निगम, सामान्य बीमा कंपनियों तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड के साथ सहभागिता व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी गयी। उक्त योजना के अंतर्गत सहभागिता व्यवस्थाएं करने के उद्देश्य के लिए उपर्युक्त संस्थाओं का छोड़कर अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं का हटा दिया गया है।

142. यह भी निश्चित किया गया कि सहभागिता प्रमाणपत्रों की समाप्ति अवधि 30 दिनों से कम और 180 दिनों से अधिक न हो। अर्थात् कि बैंक ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी न करें जिसकी समाप्ति अवधि 30 जून 1976 के बाद हो। कोई बैंक जिस अधिकतम व्याज दर पर प्रमाणपत्र जारी कर सकता है उसे व्याज दर विन्यास में हुई वृद्धि के अनुरूप। अगस्त 1974 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। फिर भी वाणिज्य बैंकों द्वारा किसी दूरे वाणिज्य बैंक को जारी किये गये सहभागिता प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम और अधिकतम अवधियों तथा व्याज दर की उच्चतम सीमा से संबंधित नियन्त्रण लागू नहीं थे। चाहे संबंधित दूसरा वाणिज्य बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो या नहीं।

वाणिज्य बैंकों द्वारा किये गये मीयादी ऋण

143. अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने पास उपलब्ध वित्तीय साधनों के भीतर तथा मीयादी ऋण संबंधी नीति के अनुरूप अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को दिये जाने वाले मीयादी ऋणों में वृद्धि करें। मीयादी ऋण में वृद्धि करते समय बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष महत्व दें: आस्थगित अभावगी को भातों पर किये जानेवाले निर्यात; ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन का काफी अधिक भाग निर्यात के लिए है या जिनमें निर्यात के लिए नयी अमता सीमा से निमित्त की जा सकती है; विशेष रूप से क्रीड क्षेत्र के ऐसे उद्योग जिनकी प्रारंभिक अवधि कम है और ऐसे उद्योग जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं; कृषि क्षेत्र— औद्योगिक रूप से अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग; 25,000 रुपये तक के निवेश युक्त लघु उद्योग; पूंजीगत मान के उद्योग और देशी बाजारों में पूंजीगत मास खरीदने के लिए आस्थगित अभावगी की व्यवस्थाएं।

ऋण आयोजना और ऋण प्राधिकरण योजना

144. यदि किसी भी ऋण योजना को प्रभावकारी तथा सोद्देश्य रूप से कार्यान्वित करना है तो उसके लिए न केवल रिजर्व बैंक के स्तर या व्यापक स्तर पर अर्थात् अलग-अलग बैंकों के स्तर या सूक्ष्म स्तर पर भी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़कर यह कह सकता है कि ऐसा ऋण कार्यक्रम बनाने का कार्य अंतिम रूप से ऋण-कारियों को सौंप देना चाहिए। ऋण प्राधिकरण योजना तथा प्रमुख ऋणकर्ताओं के खातों की जांच पड़ताल उन प्रक्रियाओं में से है जिनके माध्यम से रिजर्व बैंक वर्षों में इस प्रकार की त्रिस्तरीय ऋण आयोजना प्रक्रिया बनाने का प्रयत्न करता आ रहा है।

ऋण प्राधिकरण योजना

145. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में ऋण प्राधिकरण योजना के औचित्य तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा की गयी थी। उक्त योजना दस वर्ष से कार्यरत है तथा इस योजना के अंतर्गत आनेवाली पाटियों की संख्या तिगुनी हो गयी है अर्थात् जहाँ योजना के प्रारंभ में उक्त संख्या 650 थी वहाँ अब लगभग 1800 हो गयी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योजना को इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि ऋण नीति का ऋण नियंत्रण संबंधी जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में वह सहायक हो सके। अतः प्रतिरिक्त ऋण सुविधाओं को प्राधिकरण प्रदान करने समय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की प्रणाली बनायी गयी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके खातों में किये जाने वाले ऋण केवल अपनी ही राशि तक सीमित हों। अतः ऋणकर्ता की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध हो तथा वे निधियों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के संबंध में भी नितांत सावधानी बरते।

146. अब आलोच्य वर्ष के दौरान इस संदर्भ में हुई प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की जाए। योजना के अंतर्गत आनेवाली पाटियों की संख्या जहाँ जून 1974 के अंत में 1622 थी वहाँ जून 1975 के अंत में बढ़कर 1786 हो गयी और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या 166 से बढ़कर 192 हो गयी। प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या 1973-74 के 953 से बढ़कर 1974-75 में 1058 हो गयी; उनकी राशि 967 करोड़ रुपये से बढ़कर 1022 करोड़ रुपये हो गयी। 1974-75 के दौरान प्राप्त कुल आवेदन पत्रों में 120 आवेदन पत्र सरकारी क्षेत्र के थे तथा उनसे संबंधित राशि 256 करोड़ रुपये थी। वित्तीय अनुशासन तथा समग्र ऋण नियंत्रण पर अधिक जोर दिये जाने के परिणामस्वरूप प्राधिकृत मामलों की कुल संख्या तथा उनकी राशि में 1974-75 के दौरान गिरावट पायी गयी। प्राधिकृत मामलों की संख्या 1973-74 के 644 से घटकर 1974-75 में 528 हो गयी और उनकी राशि 469 करोड़ रुपये से घटकर 429 करोड़ रुपये हो गयी।

147. ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाले मामलों से संबंधित कुल चालू ऋण सीमाएं जून 1975 के अंत में 7253 करोड़ रुपये थीं जो जून 1974 के अंत में स्थित सीमाओं की तुलना में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि की संकेत थीं। इनमें से सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में चालू ऋण सीमाओं की राशि 2644 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक थी। जून 1975 के अंत में चालू ऋण सीमाओं में से लगभग 89 प्रतिशत कार्यकारी पूंजीगत उद्देश्यों के लिए 8 प्रतिशत मीयादी ऋण के लिए और 3 प्रतिशत आस्थगित अभावगी के आधार पर मशीनों की बिक्री के लिए था। जून 1975 के अंत में कुल चालू ऋण सीमाओं में इंजीनियरी उद्योग, व्यापार तथा सूती वस्त्र उद्योग का अंश क्रमशः 24 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 10 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र से संबंधित चालू ऋण सीमाओं में व्यापार, इंजीनियरी उद्योग और बिजली के प्रतिष्ठानों का अंश क्रमशः 32 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत था।

148. इस वर्ष के दौरान उद्योग क्षेत्र में स्टॉक का बेहतर प्रबंध करने की स्पष्ट प्रवृत्ति पायी गयी। ऋण प्राधिकरण योजना इस दिशा में अधिकाधिक तथा प्रभावकारी भूमिका अदा कर रही है और वह ऋण अनुशासन के माध्यम के रूप में भी कार्य कर रही है तथा वह बैंकों की ऋण मूल्यांकन प्रणालियों और क्रियाविधियों में कुछ सुधार लायी है।

बैंक ऋण संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के लिये गठित अध्ययन दल

149. इस वर्ष की उल्लेखनीय गतिविधि यह थी कि बैंक ऋण के संदर्भ में अधिक स्थायी नीति बनाने के आधार के रूप में बैंक ऋण की मंजूरी के लिए कतिपय अस्थायी मानक निर्दिष्ट किये गये। बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई तथा उनके पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित अध्ययन दल ने उक्त मानकों का संकेत किया है। नवंबर 1974 में अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गयी अंतरिम रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों को कच्चे माल, तैयार वस्तुओं और प्राप्य वस्तुओं पर 10 प्रमुख उद्योगों⁽²¹⁾ को अग्रिम प्रदान करने के लिए अपनाये जाने वाले मानकों की सूचना देते हुए तत्संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये। इन मानकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्र के यूनिटों के लिए लागू करना था। बैंकों से यह कहा गया कि वे सभी नये प्रस्तावों तथा साथ ही वर्तमान

(21) ये उद्योग इन प्रकार थे: सूती वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र, जूट के वस्त्र, औद्योगिक वस्तुएं, रबर से अर्थात् बरतूएँ, उर्वरक (नाइट्रोआमोनियम और फास्फेटयुक्त), बनस्पति, कागज (बॉट और लकड़ी तथा रसायन), लकड़ी इंजीनियरी वस्तुएं और मशीनी इंजीनियरी वस्तुएं।

ऋणकर्ताओं से अधिक ऋण सीमाओं के लिए प्राप्त होनेवाले प्रस्तावों के लिए भी इन मानकों को लागू करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे उन सभी वर्तमान ऋणकर्ताओं से विचार-विमर्श करें जिनके स्टॉक और प्राप्य वस्तुएं निश्चित मानकों से अधिक हों तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप से कम करने के लिए कार्यक्रम बनायें। ऋण-सीमाओं में प्रकटमातृ कटौती कर ऋणकर्ताओं के नियमित कार्यक्रमों में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए; साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि उचित अवधि अर्थात् दो महीनों के बाद अतिरिक्त माने गये ऋणों के अंश पर उच्चतर ध्यान दिया जा सकता है। मानकों को लागू कर लक्ष्यित ढंग से और परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रण लगाया जाना चाहिए; हो सकता है कि परिस्थितियों के अनुसार थोड़े समय के लिए मानकों में ढिलाई करने की आवश्यकता हो।

150. यद्यपि अध्ययन दल द्वारा सुझाये गये मानक केवल 10 प्रमुख उद्योगों से ही संबंधित थे, फिर भी बैंकों से यह कहा गया कि वे अन्य उद्योगों से प्राप्त ऋण संबंधी प्रस्तावों का भी इन मानकों के उद्देश्य एवं मूल भावना के अनुसार मूल्यांकन करें। ऋण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय बैंकों से यह भी कहा गया कि वे कंपनियों के लाभांश वितरण पर लगाये गये नियंत्रणों को भी ध्यान में रखें जिससे उनके द्वारा अभिरक्षित लाभ में वृद्धि होगी और इस कारण निधियों के बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहने की उनकी आवश्यकता भी कम हो जाएगी।

151. चूंकि सुझाये गये मानक प्रयोगात्मक थे, अतः उनके व्यावहारिक प्रयोग की जांचकारी के आधार पर पुनः कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे इन मानकों को लागू करते हुए प्राप्त अपने अनुभवों पर उद्योगवार टिप्पणियां प्रस्तुत करें। बैंकों से प्राप्त ऐसी जानकारी से यह विदित होता है कि सुचित किये गये मानकों का अच्छा स्वागत हुआ है। अध्ययन दल ने मिश्र-भिन्न प्रकार के औद्योगिक ऋणकर्ताओं से भी संपर्क स्थापित कर मानकों के संबंध में उनकी राय प्राप्त की है। इन विचार-विमर्शों से प्राप्त जानकारी तथा मानकों के प्रयोग से बैंकों को प्राप्त अनुभवों के आधार पर उक्त अध्ययन दल मानकों में और संशोधन करने की संभावनाओं को जांच कर रहा है। अध्ययन दल ने कुछ ऐसे फार्म बनाये हैं जिन्हें बैंक ऋण का मूल्यांकन और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाई करने तथा ऋणकर्ताओं के उत्पादन कार्यक्रमों के साथ ऋण को संबद्ध करने में प्रयोग में ला सके।

152. रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने तथा कतिपय प्रमुख वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों की एक निदेश समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं पर भी विचार करेगी। जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि की जमा राशियां हैं उनसे भी कहा गया है कि वे अध्ययन दल की सिफारिशों को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने और उनका पुनरीक्षण करने के लिए इसी प्रकार समितियां गठित करें।

पचास शीर्षस्थ ऋणकर्ताओं के खातों की जांच पड़ताल

153. ऋण की प्रभावकारी अनुवर्ती कार्रवाई और पर्यवेक्षण की उपयुक्त प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य के अनुरूप बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने सबसे बड़े 50 ऋणकर्ताओं के खातों की जांच पड़ताल करें। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक से कहा गया कि यह ऐसी जांच पड़ताल के मानक तैयार करने के लिए एक निदेशक समिति (अध्यक्ष, सरकारी निवेशक और रिजर्व बैंक के निदेशक के साथ) गठित करें। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक ने जांच पड़ताल की प्रगति का पता लगाने और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की सूचना देने के लिए अधिकारियों को प्रतिनिधित्व किया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जिन खातों की

जांच पड़ताल की जाती है उनमें से कुछ नमूना-खातों (10 से 20 तक के सबसे बड़े) का जांच-पर्यवेक्षण रिजर्व बैंक के अधिकारियों में भी किया।

154. उक्त जांच पड़ताल के उद्देश्य निम्न प्रकार थे: (क) यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक ऋणों का उपयोग स्टॉक संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप हो; (ख) इस बात की जांच की जाए कि क्या विशेष रूप से नकदी ऋणों के रूप में मंजूर की गयी ऋण सीमाएं अपेक्षाओं के अनुपात में अधिक हैं; (ग) यदि अत्यधिक राशियां निष्कासी गयीं हों तो ऋण सीमाओं में कटौती कर उनको विनियमित कर दिया जाए और (घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋणों का अधिकांश ऋणकर्ता मूल्यों के आंतरिक स्त्रोतों का इस प्रकार दिशान्तरण नहीं हो कि बैंकों पर वे और अधिक निर्भर हों।

155. बैंकों द्वारा की गयी जांच पड़ताल से यह विदित हुआ कि सामान्यतः बैंक-ऋणों का प्रयोग कर अमामान्य रूप से स्टॉक जमा नहीं किये गये थे। जहां कहीं भी अतिरिक्त मात्रा में स्टॉक जमा किये जाते या अपेक्षाओं से अधिक ऋण-सीमाओं के प्रमाण पाये गये वहां उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की गयी। इस जांच पड़ताल का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ यह हुआ कि बैंकों के संबंध को प्रभावकारी ढंग से बैंक ऋणों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाने योग्य बनाया गया और बैंक-निधियों का प्रयोग करने के संदर्भ में ऋणकर्ताओं में कुछ हद तक अनुशासन लाया गया।

जूट उद्योग को अधिक

156. ऋण नीति संबंधी उपायों में उचित सुधार लाने के लिए पहले की तरह अलग-अलग उद्योगों द्वारा अनुभव की जानेवाली विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। पहले जूट उद्योग को देखा जाए; 1974-75 में हुई जूट की कम फसल को देखते हुए सितंबर 1974 में बैंकों से यह कहा गया कि तर्ज के प्रारंभ से चार महीनों की खपत के बराबर के पटसन के स्टॉकों का वित्तपोषण करने की जो अनुमति उन्हें दी गयी थी वह थामे लागू नहीं होगी। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि जूट मिलों को दिये गये ऋण की मात्रा इतनी अधिक न हो जिससे मिल जूट आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट स्टॉक स्तरों से अधिक नये स्टॉक खरीद सके।

157. इसके बाद निर्यात संबंधी मांग में मंदी आने के कारण मिलों के पास तैयार वस्तुओं के काफी अधिक स्टॉक गठित हो गये। अगस्त 1975 में बैंकों से यह कहा गया कि वे 6 सप्ताहों के उत्पादन के अनुमत स्तर के विपरीत 9 सप्ताहों के उत्पादन के बराबर के निर्यातों के लिए अपेक्षित स्टॉक के आधार पर जूट मिलों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करें। बैंकों से यह भी कहा गया कि योग्य मामलों में रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति के साथ वे स्टॉक के अधिकतम स्तर में सीमांत वृद्धि कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की यह पूर्ण अनुमति केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक थी जहां प्रस्तावित उच्चतर ऋण सीमाएं स्टॉकों पर स्वीकृत वर्तमान ऋण सीमाओं के 10 प्रतिशत से अधिक थीं। उच्चतर ऋण सीमाओं की अनुमति प्रारंभ में जून 1975 के अंत तक दी गयी थी; परन्तु साथ में उक्त अधिकार को बढ़ाकर दिसंबर 1975 के अंत तक कर दिया गया। जूट उद्योग द्वारा भाजियों में कटौती करने के लिए किये गये अनुरोध पर विचार करते हुए मई 1975 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि पटसन और जूट से बनी वस्तुओं से संबंधित भाजियों में अलग-अलग मामलों के गुण-दोषों के आधार पर रियायत की जा सकती है; परन्तु ऐसी रियायत दिसंबर 1973 का निर्देश जारी किये जाने के पहले विद्यमान स्तरों से कम रहनेवाले भाजियों पर लागू न हो। उक्त रियायतें सितंबर 1975 के अंत तक लागू हैं।

चीनी उद्योग को प्रतिबंध

158. चीनी उद्योग के संदर्भ में 1974-75 के मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन की संभावनाओं का पुनरीक्षण किया गया और तबसे 1974 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि चीनी मिलों को पेरार्ड के पिछले दो मौसमों में (अर्थात् 1972-73 और 1973-74 के मौसम) उनके लिए संजूर की गयी नियमित सीमाओं की अधिकतम बकाया राशि की सीमा तक ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत पूर्व प्राधिकरण दिये बिना ऋण सीमाएं संजूर की जा सकती हैं। इन स्तरों से अधिक सीमाओं के लिए पूर्व प्राधिकरण आवश्यक है। बैंकों को इस बात से भी अवगत कराया गया कि वे चीनी मिलों से श्रद्धा तक की तरह आवश्यक आंकड़े प्राप्त करते रहें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चीनी मिलों के उत्पादकों की गन्ने के सम्बंध में देय राशियाँ अखिलेश्वर प्रदा करती हैं। 1974-75 के मौसम में उत्पादन में हुई काफी अधिक वृद्धि को देखते हुए ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत प्रतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गयी। 1974-75 के पेरार्ड के मौसम में जून 1975 के अंत तक रिजर्व बैंक ने चीनी मिलों को उनके अभि-संधित उत्पादन का वित्तपोषण करने के निमित्त 41.04 करोड़ रुपये का प्रतिरिक्त ऋण प्राधिकृत किया।

वस्त्र उद्योग को प्रतिबंध

159. वस्त्र उद्योग के मामले में रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गयी कमजोर वस्त्र मिलों का वित्तपोषण करने के लिए आवश्यक कदम उठाये। वित्तपोषण करनेवाले बैंकों, राष्ट्रीय वस्त्र निगम और सार्वजनिक उद्यम केन्द्र के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किये गये। इन विचार-विमर्शों के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि प्रमुख रूप से जनता के उपभोग के लिए नियंत्रित किस्मों के कपड़े का उत्पादन करनेवाली इन मिलों को प्रयाप्त ऋण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया गया कि ऋण संबंधी अपेक्षाओं की स्वीकार्यता जांच होने तक प्रत्येक मिल के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप अल्प अवधि के लिए उचित तदर्थ ऋण-सीमाएं प्रदान करने के संबंध में बैंक विचार कर सकते हैं।

160. इस उद्देश्य से कि बैंक इन कमजोर यूनिटों की ऋण संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति अविलंब कर सकें, यह निश्चय किया गया कि अलग-अलग मिलों के लिए कतिपय ऋण सीमाएं संजूर करने के संबंध में ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की जो अपेक्षा थी उससे जून 1975 के अंत तक छूट दी जाए। उक्त अवधि को बाद में सितम्बर 1975 के अंत तक बढ़ा दिया गया। किन्तु जहाँ यह है कि अस्थायी ऋण सीमाएं प्रत्येक वस्त्र मिल के संदर्भ में कुल 25 लाख रुपये से अधिक नहीं। छूट प्राप्त इन ऋण सीमाओं में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिकार में ली गयी किसी कमजोर मिल को वास्तविक उत्पादन/व्यापार संबंधी गतिविधियों के निमित्त 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए प्रदान की गयी 25 लाख रुपये तक की अस्थायी ऋण सीमा भी शामिल है। किसी बैंक द्वारा नियमित रूप से संजूर की जाने वाली उच्चतर ऋण सीमाओं के लिए रिजर्व बैंक का प्राधिकरण प्राप्त होने तक किसी कमजोर मिल को 25 लाख रुपये तक की अंतरिम विधीय सहायता प्रदान किये जाने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा संजूर की गयी सीमा के 10 प्रतिशत तक की प्रतिरिक्त राशि या 25 लाख रुपये में से जो भी कम हो, उसे अस्थायी रूप से निवाहने की अनुमति दी गयी।

161. जनवरी से जून 1975 तक की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक ने ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत कमजोर वस्त्र मिलों को उनकी अपनी कार्यकारी पंजी संबंधी बड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के

निमित्त कुल 2.04 करोड़ रुपये की प्रतिरिक्त ऋण-सीमाएं संजूर की हैं।

उर्वरकों के लिए ऋण

162. उर्वरक उद्योग क्षेत्रों में हाल ही में भारी मात्रा में तैयार वस्तुओं के संचित हो जाने की समस्या उत्पन्न हुई थी। रिजर्व बैंक ने स्टाक संचित हो जाने से उत्पन्न उर्वरक उद्योग की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर जून 1975 में उर्वरकों के उत्पादकों, वितरकों एवं बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किये। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप तथा इस उद्योग को दी गयी प्राथमिकता के कारण यह निश्चय किया गया कि स्टाकों तथा प्राप्य वस्तुओं के वित्तपोषण तथा इस उद्योग पर लागू होने वाले वाले मार्जिनों से संबंधित मानकों को अस्थायी रूप से दिसंबर 1975 के अंत तक संशोधित किया जाए। तैयार वस्तुओं के स्टाकों तथा प्राप्य वस्तुओं का वित्तपोषण करने के लिए 2½ महीनों की बिक्री के बराबर की मात्रा का स्वीकृत स्तर निर्धारित किया गया। तैयार वस्तुओं तथा प्राप्य वस्तुओं के बीच अधिकतम स्तर के भीतर ऋण सीमाओं को अपने विवेकानुसार आबंटित करने के लिए बैंकों से कहा गया। बैंकों से यह भी कहा गया कि मार्जिन के संबंध में भी अपने विवेक का प्रयोग करे और यह संकेत भी दिया कि मार्जिन 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच हों।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

163. मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक था कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के स्थूल स्वरूप को इस वर्ष के दौरान बनाये रखा जाए। जब अभिर्माण की न्यूनतम व्याज-दर को जुलाई 1974 में वार्षिक 11 प्रतिशत से बढ़ाकर वार्षिक 12.5 प्रतिशत कर दिया गया तब चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर दिये जाने वाले अभिर्माणों की न्यूनतम व्याज दर को भी 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। सूची मिलों को कच्ची रूई के स्टाकों पर दिये जाने वाले ऐसे अभिर्माणों, जो न्यूनतर मार्जिन के पात्र हैं, तथा मुख्य बिक्री की चीनी के ऐसे स्टाकों पर जिन्हें सरकार ने बिक्री के लिए बाहर नहीं निकाला है, चीनी के कारखानों को दिये जाने वाले अभिर्माणों के मामले में न्यूनतम व्याज-दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया।

164. चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर दिये जाने वाले अभिर्माणों की उच्चतम सीमा पारिवारिक निर्धारित की जाती रही; परन्तु स्वीकार्य स्तर को निर्धारित करने के लिए अपेक्षित आधार अवधि पिछले तीन वर्षों, अर्थात् (नवंबर-अक्तूबर) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान बकाया रहने वाले अभिर्माणों के गिन्नर स्तर से संबंध रखी। यद्यपि चयनात्मक ऋण नियंत्रणों का स्वरूप स्थूल से अपरिवर्तित रहा, फिर भी उनमें समय-समय पर कतिपय सामान्य संशोधनों/स्पष्टीकरणों का संकेत दिया गया। वनस्पति निर्माताओं द्वारा सैनिकी खरीद संगठन को प्रदान करने के लिए धारित वनस्पति के स्टाकों पर दिये जाने वाले अभिर्माणों को चयनात्मक ऋण नियंत्रणों से फिलहाल जो छूट दी जाती है उसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण किए जाने के लिए धारित वनस्पति के स्टाकों पर भी लागू कर दिया गया। थोक तथा फुटकर व्यापारियों को तिलहनों और तेलों (वनस्पति सहित) के स्टाकों पर दिये जाने वाले अभिर्माणों को भी सार्वजनिक वितरण के लिए निश्चित मात्रा तक पूरी छूट दी गयी। पश्चिम बंगाल और बिहार में वसूली योजना के अंतर्गत आने वाली धाबल भिनों को उच्चतम ऋण सीमा तथा मार्जिन से संबंधित बातों से कुछ और छूट दी गयी।

हुंडी पुनर्भुनाई योजना और ऋण नियंत्रण

165. यद्यपि ऋण प्रलेख के रूप में विनियम हुंडी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की नीति बराबर जारी रही, फिर भी ऋण नियंत्रण की समग्र अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया कि रिज़र्व बैंक में ऐसी हुंडियों की पुनर्भुनाई किये जाने की जो सुविधा प्राप्त है उसे कुछ कम किया जाए। 1974 के कम कामकाज के समय तथा 1974-75 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति के अनुसार स्पष्टतः इस प्रकार की कमी पायी गयी।

1974 का कम कामकाज का समय

166. 1974 के कम कामकाज के समय के प्रारंभ में ऋण नीति का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित कर लेना था कि बैंकों को हुंडियों की पुनर्भुनाई के द्वारा प्राप्त होने वाले निमित्त धन से उन्हें ऋण विस्तार का निरंतर आधार न मिले; अतः बैंकों से यह कहा गया कि वे अक्टूबर 1974 के अन्त तक पुनः भुनाई जाने वाली हुंडियों की सीमा को अप्रैल 1974 के बकाया स्तर के 40 प्रतिशत तक कम कर दें।

167. बैंकों ने सामान्य रूप से इस अपेक्षा की पूर्ति की और पुनः भुनाई गई हुंडियों की राशि को अक्टूबर 1974 के अंत तक 279 करोड़ रुपये से घटाकर 108 करोड़ रुपये कर दिया अर्थात् उसमें 171 करोड़ रुपये की कमी लायी गयी। इस प्रकार 1974 के कम कामकाज के समय में हुंडी पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी निधियों के प्रत्यावर्तन की मात्रा काफी संतोषजनक थी। जुलाई 1974 में जब अधिमों की न्यूनतम व्याज दर को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया तब आदेशकों की हुंडियों की पुनर्भुनाई पर 9.5 प्रतिशत की न्यूनतम बट्टा दर को बढ़ाकर वार्षिक 11 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया। आदेशितियों की हुंडियों से संबंधित बट्टा दर को 11 प्रतिशत से बढ़ा कर वार्षिक 12.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया। इस उद्देश्य से कि स्टॉक खरीदने के लिए हुंडी बिल नकदी ऋण की अपेक्षा सस्ता न हो, यह भी शर्त निर्दिष्ट की गयी कि आदेशितियों की हुंडियों की व्याज दर उसी ऋणकर्ता को प्रदान की जाने वाली नकदी ऋण सहायता पर ली जाने वाली व्याज दर के समान हो।

1974-75 का अधिक काम काज का समय

168. हुंडियों की पुनर्भुनाई की सुविधा पर लगाये गये इस प्रतिबंध को 1974-75 के अधिक कामकाज के समय में अधिकांशतः विवेकाधीन बनाकर और कठोर बना दिया गया। खरीदी और भुनाई गई बैंकों की कुल देवी हुंडियों के 10 प्रतिशत के बराबर का मूलभूत पुनर्भुनाई कोटा 27 सितंबर 1974 को प्रत्येक योग्य बैंक के लिए नियत किया गया। यह सहायता (जिसकी राशि 122 करोड़ रुपये थी) बैंक दर पर उपलब्ध करायी गयी पुनर्भुनाई की कोई भी अतिरिक्त सीमा, राशि तथा व्याज दर, जो 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच थी, दोनों ही संदर्भों में केवल रिज़र्व बैंक के विवेक के आधार पर मंजूर की गयी। विवेकाधीन सीमाएं मंजूर करते समय जिन बातों पर ध्यान दिया गया उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थीं: बैंक के ऋण का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार का था, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी कुल सहायता कितनी थी और खरीदारों की हुंडियों और विक्रेताओं की हुंडियों के रूप में बैंक की कितनी हुंडियां थीं। 1974-75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान बैंकों के लिए मंजूर की गयी मूलभूत सीमाओं को 1975 के कम कामकाज के समय के लिए जारी रहने दिया गया है।

169. ऋण नियंत्रण की नीति तथा पुनर्भुनाई की उच्चतर लागत के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक में पुनः भुनायी गयी हुंडियों में गिरावट आयी। 27 जून 1975 को 132 करोड़ रुपये की जो राशि बकाया थी वह जून 1974 के स्तर की तुलना में 142 करोड़ रुपये की 145GI/75—8

कमी की छोटक थी जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में उसमें 259 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

पुनर्भुनाई सुविधा का विस्तार

170. अंत में पुनर्भुनाई सुविधा से संबंधित दो गतिविधियां उल्लेखनीय हैं। यह निश्चय किया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव केवल निम्नलिखित संस्थाओं, अर्थात् वाणिज्य बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सामान्य बीमा निगम/कंपनियों तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड में अपने द्वारा धारित वार्षिक व्यापार विनियम हुंडियों की पुनर्भुनाई करें। उपर्युक्त संस्थाओं को छोड़ कर किसी भी राज्य स्तरीय मियादी ऋण देने वाली संस्था या दूसरी संस्थाओं में हुंडियों को पुनः भुनाने की अनुमति बैंकों को नहीं है। दूसरी गतिविधि यह है कि हुंडी पुनर्भुनाई सुविधाएं 1 अप्रैल 1975 से भारतीय रिज़र्व बैंक के अहमदाबाद कार्यालय में भी उपलब्ध करायी गयी।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशें

171. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बैंकिंग आयोग की कई सिफारिशों पर भारत सरकार ने निर्णय किये हैं। इन सिफारिशों तथा बाव में सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी अन्य सिफारिशों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुझावे हुए विभिन्न परिपत्र जारी किए गए हैं कि उनको कार्यान्वित करने के लिए शीघ्रतापूर्वक कदम उठाये जाएं। उक्त परिपत्र निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:

(क) जमा संचयन तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटे कारीगरों और लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों से संबंधित रिपोर्ट के अध्याय 6 और 7 में दी गयी सिफारिशें।

(ख) "बैंकों की परिचालन प्रणालियां और क्रियाविधियां" शीर्षक के रिपोर्ट के अध्याय 11 में दी गयी सिफारिशें जो बैंकों के परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे ग्राहक सेवा, ऋण संबंधी क्रियाविधि, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा संगठन और प्रबंध; उक्त सिफारिशें प्रमुख रूप से इस उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी हैं कि उक्त क्षेत्रों में बैंकों की क्रियात्मक तथा परिचालनगत क्षमता में सुधार लाया जाए।

(ग) बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित अध्याय 14 में दी गयी सिफारिशें: यह प्रणाली की जाती है कि संबंधित सिफारिशों में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों से बैंकों को वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी ढंग से अपने कर्मचारियों की प्रतिभा का पता लगाने, उनको बढ़ाने तथा उसका उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

बैंकिंग विधान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन

172. संसद के दोनों सदनो द्वारा पारित किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 को 13 दिसंबर 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली तथा वह उसी तारीख से अमल में आया। उसमें किये गये संशोधनों से (i) अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को पुनः वित्त सुविधाएं प्रदान करने की रिज़र्व बैंक की शक्तियों को व्यापक बनाया

गया है (2) "कृषि संबंधी कार्यकलाप" शब्द के अर्थ को व्यापक बनाया गया है ताकि शिखर सहकारी बैंकों द्वारा ऐसी सहकारी समितियों को जो संयुक्त रूप से नहीं बल्कि कृषि से संबंधित किये बिना स्वतंत्र रूप से सहायक कार्यकलापों के लिए गठित की गई हों, दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में रिजर्व बैंक उन शिखर सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान कर सके, (3) रिजर्व बैंक एजेंट के रूप में जो कार्य करता है उसे व्यापक बनाया गया है ताकि कृषि पुनर्वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे सांविधिक निगमों की ओर से रिजर्व बैंक ऋण और डिबेंचर जारी कर सके और उसका प्रबंध कर सके, (4) बैंक के ऋण विभाग में प्रास्तियों के रूप में धारित किये जाने योग्य विवेधी प्रतिभूतियों की सूची को विस्तारित किया गया है, (5) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में आने वाले "वेयताएँ" शब्द की परिभाषा को संशोधित किया गया है, (6) बैंकों को आपस में मुक्त रूप से ऋण सूचना का परस्पर आदान प्रदान करने के लिए सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है और (7) जमाशायियां स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक को बेहतर शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा उसके नियमों में किये गये संशोधन

173. बैंककारी विनियमन, अधिनियम, 1949 के प्रयोग से प्राप्त अनुभवों के संदर्भ में तथा सांख्यिकी आंकड़ों को संकलित करने में अधिक सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949 में कतिपय संशोधन किए जाएँ। इन संशोधनों को अन्तिम रूप दिया गया है और उन्हें विनांक 4 जनवरी 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है तथा उनसे संबंधित आपत्तियों या सुझावों को धारित किया गया है जिन पर 31 जुलाई 1975 को या उसके बाद विचार किया जाएगा। जो संशोधन सुझाये गये वे आन्कारी की सूचना देने के लिए निर्दिष्ट फार्मों के स्वरूप तथा उनमें से कतिपय फार्मों की विषयवस्तु को उपयुक्त बनाने से संबंधित हैं।

बैंकिंग विधि समिति

174. भारत सरकार द्वारा गठित बैंकिंग विधि समिति (बैंकिंग लॉज कमिटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट, अर्थात् "बैचनीय प्रपक्ष विधि रिपोर्ट" प्रस्तुत की है। ये सिफारिशें सामान्य रूप से बैचनीय प्रपत्रों से संबंधित विधियों में समिति द्वारा पायी गयी कमियों को दूर करने के लिए की गयी हैं। रिजर्व बैंक इन सिफारिशों की ग्योरेवार जांच कर रहा है।

राज्यों के विधान

175. आठ राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने विधेयक पारित किये हैं ताकि वाणिज्य बैंक कृषि क्षेत्र को अधिकार मात्रा में ऋण प्रदान कर सकें। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मेघालय तथा उड़ीसा की सरकारों ने प्राप्ति विधेयक बना लिये हैं। षष्ठ राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को ऐसे विधेयक तैयार करने की आवश्यकता पर पुनः जोर देते हुए सूचित किया गया है।

निरीक्षण, विलयन और संबंधित संगठनात्मक विषय

176. पिछले तीन वर्षों (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों तथा बैंक कार्यालयों का जो निरीक्षण किया गया उसकी तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

	1972-	1973-	1974-
	73	74	75
वितीय निरीक्षण			
निरीक्षण किये गये/निरीक्षणार्थ लिये गये बैंकों की संख्या	44	24	28
निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या	1,013	752	506
केन्द्रवार निरीक्षण			
केन्द्रों की संख्या	194	614	1,271
कार्यालयों की संख्या	789	2,218	2,362
प्रणालियों का निरीक्षण			
निरीक्षण किये गये बैंकों की संख्या	1	1	2

177. इस वर्ष के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षणों का जो कार्यक्रम बनाया गया उसमें 22 अनुसूचित बैंक और 6 गैर-अनुसूचित बैंक शामिल थे। व्यापक पैमाने पर केन्द्रवार निरीक्षण करने की जो नीति पिछली रिपोर्ट में उल्लिखित की गयी थी उसके अनुसार इस वर्ष किये गये वितीय निरीक्षण की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कम थी।

178. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 ए के अंतर्गत परिसमापन के अधीन रहनेवाले दो बैंकों (अर्थात् कलकत्ता कमर्शियल बैंक लिमिटेड और बंगाल बैंक लिमिटेड) का निरीक्षण इस वर्ष के दौरान समाप्त किया गया।

179. श्रीलंका, अमेरिका और गयाना में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है और ब्रिटेन स्थित शाखाओं का निरीक्षण किया जा रहा है।

180. अलग-अलग बैंकों की प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच करने और जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, उनमें सुधारों का सुझाव देने के निमित्त उन बैंकों का अध्ययन करने का कार्यक्रम जारी रहा। इस वर्ष के दौरान और दो बैंकों का इस प्रकार का निरीक्षण समाप्त किया गया। उनमें से एक बैंक सरकारी क्षेत्र का तथा दूसरा बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र का था। 1971 में जब यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तब से लेकर अब तक छः बैंकों की प्रणालियाँ और क्रियाविधियों का अध्ययन किया गया है। शीघ्र ही एक और बैंक का इसी प्रकार का अध्ययन प्रारंभ किया जाने-वाला है।

सम्मेलन

181. सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के चार बैंकों (जिनमें से प्रत्येक की 150 से अधिक शाखाएँ थीं) के आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा विभागों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन अगस्त 1974 में आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि तेजी से होनेवाले शाखा विस्तार और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के निमित्त बैंकों द्वारा अब किये जाने वाले कारोबार के व्यापक वैविध्य के संदर्भ में उनके आंतरिक निरीक्षण तंत्र को मजबूत बनाने की नितांत आवश्यकता की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित किया जाए।

बैंकों का विलयन और परिसमापन

182. स्वेच्छिक समामेलन, देयताओं और आस्तियों के अंतरण और सहभागिता व्यवस्थाओं के द्वारा देश की बैंकिंग व्यवस्था को समेकित करने के प्रयत्न जारी रहे। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत भारत सरकार ने अब तक 49 बैंकों के समामेलन की योजनाएँ मंजूर की हैं। संबंधित समामेलन योजनाओं के उपबंधों के अनुसार हस्तांतरित बैंकों को 6/12 वर्षों की अवधि या केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर मंजूर की गयी उसके पहले की अवधि के बाद हस्तांतरक बैंकों की आस्तियों का अंतिम मूल्यांकन करना होगा। संबंधित समामेलन योजनाओं के उपबंधों के अनुसार 17 बैंकों की आस्तियों के अंतिम मूल्यांकन का कार्य पूरा किया गया है जबकि 11 बैंकों के मामले में अंतिम मूल्यांकन की रिपोर्टें विचाराधीन हैं।

183. आलोच्य अवधि के दौरान 7 गैर-अनुसूचित बैंकों को विघटित कर दिया गया और प्राप्त सूचना के अनुसार जिन दो और गैर-अनुसूचित बैंकों को पिछले वर्ष के दौरान विघटित किया गया था उनके संबंध में रिपोर्टें वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त हुईं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 (1) के अंतर्गत एक गैर-अनुसूचित बैंक को प्रमाणपत्र जारी किया गया ताकि वह स्वेच्छिक परिसमापन कर सके।

184. केन्द्रीय सरकार से आवश्यक निदेश प्राप्त करने के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 ब के अंतर्गत (परिसमापनाधीन) एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एण्ड इकोनॉमिक्स लिमिटेड की बहियों और खातों का निरीक्षण प्रारंभ किया गया और उसे समाप्त किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियाँ भारत सरकार तथा उच्च न्यायालय, बंबई के पंजीयक को भेजी गयीं। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ब के अंतर्गत एसोसिएटेड बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बंबई का निरीक्षण कार्य पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सका। क्योंकि निरीक्षण के लिए संबंधित अभिलेख निरीक्षण अधिकारी की अब तक उपलब्ध नहीं करायें गये हैं।

समाशोधन गृह सुविधाएँ

185. 1 जुलाई 1974 से 30 जून 1975 तक की अवधि के दौरान अठारह समाशोधन गृह स्थापित किये गये। इनसे देश में स्थित समाशोधन गृहों की कुल संख्या बढ़कर 212 हो गयी; इनमें 9 समाशोधन गृहों का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, 170 का प्रबंध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और 33 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महायुक्त बैंकों द्वारा किया जाता है।

186. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि बंबई स्थित समाशोधन गृह के परिवर्तन के समय आदि के संबंध में कतिपय क्रियाविधि संबंधी समायोजनों की परिकल्पना करते हुए रिजर्व बैंक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर भारतीय बैंक संघ की समाशोधन सुधार समिति के कतिपय निर्णय संघ की प्रबंध समिति के विचाराधीन थे। बंबई में स्थित वर्तमान समाशोधन व्यवस्थाओं के संबंध में संघ की प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित सुधारों को बंबई बैंकर समाशोधन गृह को विचारार्थ भेजा गया। समाशोधन गृह के सदस्यों के परामर्श से उन सुधारों की ओर जांच की जा रही है। कलकत्ता बैंक समाशोधन गृह और मद्रास बैंक समाशोधन गृह भी कतिपय सुधारों पर विचार कर रहे हैं।

187. बैंकों की शाखाओं का तेज़ी से विस्तार होने के परिणामस्वरूप क्षेत्रों को बैंकवार तथा शाखावार छाटना जटिल हो गया था; अतः बैंकों की समिति ने 1968-69 में इस सुझाव पर विचार किया था कि बैंक कामों पर बैंकों की संकेत संख्या के साथ शाखाओं की भी संकेत

संख्या दी जानी चाहिए ताकि बैंकों को बैंकवार तथा शाखावार संकेत संख्याओं के आधार पर क्षेत्रों को छांटने, भेजने, उनकी सूची बनाने और उनको दर्ज करने में सुविधा हो। भारतीय बैंक संघ के परामर्श के साथ वर्तमान संकेत प्रणाली को सुधारने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

बैंकों का लाइसेंसीकरण

188. आलोच्य अवधि के दौरान किसी भी बैंक को भारत में बैंकिंग का कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया। किन्तु एक भारतीय अनुसूचित बैंक अर्थात् कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड को प्रदान किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया; क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उक्त बैंक का कारोबार अपने अधिकार में ले लिया था और उसके पश्चात् उस बैंक ने बैंकिंग कारोबार बन्द कर दिया था। इस प्रकार जहाँ एक ओर लाइसेंसीकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या घटकर 48 हो गयी (इनमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है जो शत्रु-संपत्ति के अधिग्रहण के अधिकार में है) वहाँ दूसरी ओर उन बैंकों की संख्या, जिनके मामले में लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं, बढ़कर जून 1975 के अंत तक 53 हो गयी। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड का नाम भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में से हटा दिया गया है।

189. आलोच्य अवधि के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत किसी भी कार्यरत बैंक को भारत में बैंकिंग का कारोबार करने के लिए लाइसेंस देने से अस्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार जिन बैंकों को लाइसेंस देने से अस्वीकार किया गया है उनकी संख्या जून 1975 के अंत में बिना किसी परिवर्तन के 283 ही रही।

सूचना तथा सांख्यिकीय आंकड़े

ऋण सूचना

190. बैंकों तथा अन्य अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को उनके अनुसूचित गैर-अनुसूचित ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण-सुविधाओं के संबंध में सूचना दी जाती रही। 1974-75 (जुलाई 1974 से जून 1975 तक) के दौरान 953 आवेदनपत्रों के संबंध में ऋण संबंधी सूचना प्रदान की गयी जबकि 1973-74 में 1090 आवेदनपत्रों के संबंध में ऋण सूचना प्रदान की गयी थी।

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणीय योजना

191. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से जमाराशियों तथा अधिमों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए दिसम्बर 1972 में शुरू की गयी मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी योजना ने आलोच्य वर्ष के दौरान और अधिक प्रगति की है। बैंकों ने इस नयी सूचना प्रणाली के अनुकूल अपने को बना लिया है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और अधिमों का 99 प्रतिशत सम्मिलित है। अब तक "मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी" शीर्षक की श्रृंखला के अंतर्गत बैंकिंग सांख्यिकी के तीन खण्ड प्रकाशित किये गये हैं जिनमें क्रमशः दिसम्बर 1972, जून 1973 और दिसम्बर 1973 की अवधियों की जमाराशियों तथा अधिमों के व्यापक आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। जून 1974 में समाप्त हुई छमाही के लिए जमाराशियों और अधिमों के संक्षिप्त आंकड़ों के साथ एक पुस्तिका भी मई 1975 में प्रकाशित की गयी।

192. सूचना प्रणाली में और अधिक सुधार लाने तथा उक्त योजना के अंतर्गत आंकड़ों की सूचना देने में बैंकों की होनेवाली समस्याओं का परीक्षण करने के लिए समय समय पर प्रलग प्रलग बैंकों की बैठकें बुलाई गयीं।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य-परिणाम

193. सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों (स्टेट बैंक समूह तथा 14 राष्ट्रीय-कृत बैंक), गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जिनमें से प्रत्येक के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशियाँ हैं तथा विदेशी बैंकों के कार्य परिणामों का विश्लेषण करने पर विवक्षित होता है कि 1974 के कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके लाभों⁽²²⁾ में उल्लेखनीय सुधार पाया गया। 1974 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभ राशि में लगभग 27 प्रतिशत तथा विदेशी बैंकों की लाभ राशि में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र के 25 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभ राशि कुलीनी से भी अधिक हुई (सारणी 23)।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

194. सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभ राशि जहाँ 1973 में 12.3 करोड़ रुपये थी वहाँ 1974 में बढ़कर 15.6 करोड़ रुपये हो गयी। 1974 के दौरान इन बैंकों की कुल आय में 296.1 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि (37.9 प्रतिशत) हुई जबकि 1973 में 149.6 करोड़ रुपये की वृद्धि (24.7 प्रतिशत) हुई थी। आय में हुई इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि बैंकों द्वारा उधारों पर लिये जाने वाले व्याज की न्यूनतम दर को 1 दिसम्बर 1973 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत तथा 23 जुलाई 1974 से 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। 1974 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल व्यय में 282.8 करोड़ रुपये की काफी अधिक वृद्धि (38.1 प्रतिशत) पायी गयी जब कि 1973 में 149.2 करोड़ रुपये की वृद्धि (25.2 प्रतिशत) पायी गयी थी। व्यय राशि में इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि अप्रैल और जुलाई 1974 से जमा राशियों की व्याज दरों को बढ़ा दिया गया था तथा साथ ही आलोच्य वर्ष के अधिकांश भाग में निर्बाह व्यय सूचकांक में तीव्र वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप उच्चतर सहभाई भत्ता दिया गया था।

(22) कराधान और कर्मचारियों को वेतन बोनस के लिए व्यवस्था करने के बाव विद्यमान लाभ।

सारणी 23 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणाम

(राशि करोड़ रुपये में)

	स्टेट बैंक समूह		राष्ट्रीयकृत बैंक		सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक		अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक*		विदेशी बैंक	
	1973	1974	1973	1974	1973	1974	1973	1974	1973	1974
	1	2	3	4	5(1+3)	6(2+4)	7	8	9	10
कुल आय	265.73 (23.0)	358.57 (34.9)	488.67 (25.7)	681.94 (39.6)	754.40 (24.7)	1040.51 (37.9)	70.50 (37.2)	102.16 (44.9)	75.70 (13.6)	107.29 (41.7)
उसमें से										
(क) व्याज तथा बट्टा	216.83 (22.4)	297.69 (37.3)	430.16 (25.8)	600.96 (39.7)	646.99 (24.6)	898.65 (38.9)	61.65 (38.2)	90.05 (46.1)	58.78 (12.3)	84.34 (43.4)
कुल व्यय	261.07 (23.3)	353.34 (35.3)	481.01 (26.2)	671.55 (39.6)	742.08 (25.2)	1024.89 (38.1)	69.12 (37.9)	99.26 (43.6)	71.50 (13.8)	101.00 (41.3)
उसमें से :—										
(ख) उधारों, जमा राशियों आदि पर दिया गया व्याज	117.29 (25.4)	173.61 (48.0)	257.78 (30.8)	388.12 (50.6)	375.07 (29.1)	561.73 (49.8)	36.31 (39.1)	51.68 (42.3)	30.55 (19.0)	45.27 (48.2)
(ग) वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि तथा बोनस	114.28 (21.7)	145.12 (26.9)	169.48 (22.7)	218.12 (28.7)	283.76 (22.4)	363.24 (28.0)	24.01 (37.2)	34.19 (42.3)	18.57 (11.3)	22.78 (22.6)
कराधान और कर्मचारियों को देय बोनस के लिये व्यवस्था करने के बाद लाभ	4.66 (8.6)	5.23 (12.2)	7.65 (1.3)	10.39 (35.8)	12.31 (3.3)	15.62 (26.9)	1.38 (7.8)	2.90 (110.1)	4.20 (8.0)	6.29 (49.8)

*ये आंकड़े गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशियाँ हैं।

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में षट-शुद्ध के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : बैंकों के लाभ-हानि लेखे।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

195. समूहवार विश्लेषण से यह विदित होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल आय में जहाँ 1973 में 38.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ 1974 में 74.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुल व्यय में भी 1973 में हुई 38.1 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1974 में 74.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाभ राशि 1974 में 4.6 करोड़ रुपये थी जो 49 लाख रुपये की वृद्धि की द्योतक थी जब कि 1973 में उसमें केवल 27 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी। 1974 में हुए लाभ में से स्टेट बैंक ने 3.9 करोड़ रुपये की राशि प्रारक्षित निधि में अन्तर्गत की और शेषरधारियों को लाभांश अदा करने के लिए 68 लाख रुपये की व्यवस्था की।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक

196. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सात सहायक बैंकों की कुल आय में 1973 में हुई 11.3 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1974 में 18.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1974 के दौरान उनके कुल व्यय में भी काफी अधिक वृद्धि हुई। फिर भी इन बैंकों ने अपनी लाभ राशि में 8 लाख रुपये की वृद्धि की अर्थात् उक्त लाभ राशि 1973 में स्थित 54 लाख रुपये से बढ़कर 1974 में 62 लाख रुपये हो गयी। 1974 की अपनी लाभ राशि में से इन बैंकों ने 50 लाख रुपये प्रारक्षित निधियों में अन्तर्गत किये और स्टेट बैंक को लाभांश अदा करने के लिए 12 लाख रुपये की व्यवस्था की।

राष्ट्रीयकृत बैंक

197. 1974 के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आय 681.9 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें 193.3 करोड़ रुपये की वृद्धि (39.6 प्रतिशत) हुई जब कि 1973 में उसमें 99.9 करोड़ रुपये की वृद्धि (25.7 प्रतिशत) हुई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि व्याज और बट्टे से प्राप्त आय में वृद्धि हुई। 1974 में इन बैंकों के कुल व्यय की राशि 671.6 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें 190.6 करोड़ रुपये की वृद्धि (39.6 प्रतिशत) पायी गयी जबकि पिछले वर्ष उसमें 99.8 करोड़ रुपये (26.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। इन बैंकों की व्यय राशि में जो वृद्धि हुई उसके दो प्रमुख कारण जमा राशियों और उधारों पर अदा किये गये व्याज तथा वेतन, भत्तों, भविष्य निधि तथा बोनस पर किये गये खर्च थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ राशि में 1974 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 2.7 करोड़ रुपये की वृद्धि पायी गयी।

198. अपनी लाभ राशि में से 14 राष्ट्रीयकरण बैंकों ने सांविधिक प्रारक्षित निधियों में 6.2 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार को बैंकिंग कामों (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 (7) के अन्तर्गत 3.9 करोड़ रुपये अन्तर्गत किये। 1974 में भारत सरकार को अन्तर्गत की गयी अधिशेष राशि इन बैंकों के अभिग्रहण के लिए अदा की गयी कुल क्षतिपूर्ति राशि का 4.5 प्रतिशत थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

199. गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, जिनमें से प्रत्येक की जमा राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, के कार्य परिणामों से उनकी लाभ राशि में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी। 1974 के दौरान इन बैंकों की कुल आय में 31.7 करोड़ रुपये (44.9 प्रतिशत) तथा व्यय में 30.1 करोड़ रुपये (43.6 प्रतिशत) की वृद्धि

पायी गयी। इन बैंकों की लाभ राशि दुगुनी से भी अधिक हो गयी अर्थात् जहाँ 1973 में उक्त राशि 1.4 करोड़ रुपये थी वहाँ 1974 के दौरान 2.9 करोड़ रुपये हो गयी। 1974 के दौरान इस प्रकार लाभ राशि में वृद्धि होने के कारण ये बैंक अपनी सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अधिक राशि अन्तर्गत कर सके तथा अन्य प्रारक्षित निधियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक विनियोजन कर सके। सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अन्तर्गत राशि 1973 के 48 लाख रुपये से बढ़कर 1974 में 141 लाख रुपये हो गयी जब कि अन्य प्रारक्षित निधियों में विनियोजित राशि 36 लाख रुपये से बढ़कर 75 लाख रुपये हो गयी। शेषरधारियों को अदा किये गये लाभांश की राशि भी 1974 में पिछले वर्ष (42 लाख रुपये) की अपेक्षा अधिक (48 लाख रुपये) थी।

विदेशी बैंक

200. विदेशी बैंकों की कुल आय 1974 में 75.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 107.3 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें 41.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनके कुल व्यय में भी 1974 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 29.5 करोड़ रुपये की वृद्धि (41.3 प्रतिशत) परिलक्षित हुई। विदेशी बैंकों की लाभ राशि 1973 में स्थित 4.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974 में 6.3 करोड़ रुपये हो गयी।

ऋण गारंटी निगम तथा जमा बीमा निगम

201. प्राचीन वर्ष के दौरान भारतीय ऋण गारंटी नियम तथा जमा बीमा निगम की जो प्रगति हुई उसको अब संक्षेप में समीक्षा की जाए।

भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

202. ऋण गारंटी निगम की तीन योजनाओं अर्थात् (1) लघु ऋण गारंटी योजना, (2) वित्तीय निगम गारंटी योजना तथा (3) सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना के अन्तर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की राशि दिसम्बर 1974 के अंतिम शुक्रवार को 529.64 करोड़ रुपये थी। इसमें से लगभग सारी राशि (526 करोड़ रुपये) लघु ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत गारंटीकृत अग्रिम राशि थी।⁽²³⁾ इस योजना के अन्तर्गत ऋणकों और काश्तकारों, परिवहन वाहनों, वस्तुओं (उत्तरों तथा खनिज तेलों को छोड़कर) के व्यापारियों तथा व्यावसायिक या स्व-नियोजित व्यक्तियों को प्रदत्त गारंटीकृत अग्रिमों की राशि क्रमशः 346 करोड़ रुपये, 64 करोड़ रुपये, 58 करोड़ रुपये तथा 31 करोड़ रुपये थी। वित्तीय निगम गारंटी योजना तथा सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना के अन्तर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की राशि केवल 4.0 करोड़ रुपये⁽²⁴⁾ थी।

203. निगम को जून 1975 के अंत तक लगभग 58 लाख रुपये की कुल राशि के दावों के 1748 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 47 लाख रुपये की राशि के लिए केवल ऋणकों और काश्तकारों के ही 1284 आवेदन-पत्र थे। प्राप्त कुल दावों में से 2,34,626 रुपये के कुल राशि के 68 दावों को निपटा दिया गया। और 1,65,989 रुपये की राशि के 33 दावों को प्रसवीकार कर दिया गया। ऋण संस्थाओं ने 1,75,146 रुपये

(23) ये आंकड़े उक्त योजना में सम्मिलित 73 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 70 बैंकों के हैं। 9 बैंकों के आंकड़े अनन्तित हैं; 3 बैंकों ने विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं।

(24) ये आंकड़े 12 वित्तीय निगमों तथा 4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के हैं।

की कुल राशि के 84 बावें वापस ले लिये थे; क्योंकि ऋणकर्ताओं ने बाव में अपने ऋण खातों की समायोजित कर दिया था। शेष बावों की जाँच पड़ताल की जा रही थी। जिन मामलों में निगम ने बावों की राशि अदा कर दी है उन मामलों में ऋण-संस्था को उतनी ही राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तदनुसार जून 1975 के अंत तक अदा किये गये बावों के संबंध में निगम को कुल 34,275 रुपये वापस मिले।

204. उक्त योजना के अन्तर्गत सोने तथा चांदी के आभूषणों पर प्रवृत्त ग्रामियों को सम्मिलित करने के दायित्व से तमिलनाडू तथा केरल के छोटे आकार के वस अनुसूचित बाणिज्य बैंकों को जो छूट दी गयी थी उसकी प्रवृत्ति को 1976 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए उन पाँच गैर अनुसूचित बैंकों को जो योजना में सम्मिलित हुए हैं और एक ऐसे बैंक को भी जिसने योजना में सम्मिलित होने का अस्थायी प्रस्ताव पेश किया है, इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे 1976 के अंत तक अपने ऐसे ग्रामियों का इस योजना के क्षेत्र से बाहर रहें।

205. यह स्मरण होगा कि 1972 में निगम ने सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए गारंटी योजनाओं को लागू करने की व्यवहार्यता की जाँच पड़ताल करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था। उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह सिफारिश की गयी है कि इस समय सहकारी बैंकों तथा कृषि सहकारी ऋण समितियों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण के संबंध में उत्पन्न होने वाले जोखिम के लिए सुरक्षा प्रदान करना व्यवहार्य अथवा आवश्यक नहीं है। किन्तु यह सुझाव दिया गया है कि कतिपय कृष्येतर समितियों की ऋण सुविधाओं को गारंटी प्रदान की जा सकती है। निगम उक्त दल की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार कर रहा है।

जमा बीमा निगम

206. आलोच्य वर्ष के दौरान जमा बीमा निगम की व्याप्ति के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया गया। एक नये बाणिज्य बैंक अर्थात् सोनाली बैंक, कलकत्ता को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप बीमाकृत बाणिज्य बैंकों की संख्या 80 से बढ़कर 81 हो गयी।

207. इस बीमा योजना को केरल राज्य और पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्र के सहकारी बैंकों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस प्रकार अब इस योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, केरल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा दिल्ली, गोवा, दमन तथा दीव और पांडिचेरी के संघशासित क्षेत्रों के 513 योग्य सहकारी बैंक आते हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक ने अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियम में उचित रीति से संशोधन कर लिये हैं अतः इन राज्यों में योग्य सहकारी बैंकों के लिए भी जमा बीमा योजना को यथासमय लागू कर दिया जाएगा। अधिकाधिक सहकारी बैंकों के लिए उक्त योजना को लागू कर देने के कारण निगम के कारोबार में हुई वृद्धि के अनुक्रम स्थापना व्यय में होने वाली वृद्धि की पूर्ति करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा संपूर्णतः धारित निगम की पूंजी को 1 जनवरी 1975 से 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

गैर-बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण

208. आलोच्य वर्ष के दौरान जमा और वित्तीय संस्थाओं से जमा राशियाँ प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखने

के लिए 31 दिसम्बर 1974 से लागू किये गये भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को और अधिक शक्तियाँ प्रदान की गयीं। उक्त संशोधन इस प्रकार है—

(क) रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो कि जब कभी बैंक आवश्यक या उपयुक्त समझे तब वह गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण करे;

(ख) गैर-बैंकिंग संस्था के लेखा परीक्षक पर यह सांविधिक दायित्व हो कि यदि उक्त संस्था ने अपेक्षित विवरणी प्रादि प्रस्तुत नहीं की हो तो वह उक्त संस्था द्वारा धारित कुल जमा राशियों की सूचना रिजर्व बैंक को दे;

(ग) अधिनियम में ही 'जमा राशि' शब्द की परिभाषा शामिल की जाए जिससे इस संभव में संदेह की कोई गुंजाहश न रहे कि गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा शेयर पूंजी विश्व किमी दूमरे रूप में प्राप्त कोई भी राशि जमा राशि के अन्तर्गत आणी;

(घ) "वित्तीय संस्था" शब्द की परिभाषा को स्पष्ट और व्यापक बनाया जाए जिससे कमियों को दूर किया जा सके;

(ङ) न केवल गैर-बैंकिंग संस्थाओं अपितु दलालों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे जमा राशियों की प्रत्यर्थता करने से पहले तत्संबन्धी सभी विवरण और सूचनाएँ प्रस्तुत करें; और

(च) अधिनियम के उपबन्धों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन के लिए अधिक बंड की व्यवस्था की जाए।

209. निदेशकों द्वारा गारंटीकृत प्रारक्षित ऋणों, शेयरधारियों से ली गयी जमा राशियों (इनमें गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारियों से कतिपय शर्तों पर ली गयी जमा राशियाँ शामिल नहीं हैं) प्रादि के रूप में गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्वीकृत जमा राशियों के संदर्भ में उन कंपनियों की यदि कोई संचित हानि-शेष हो तो उसे षटाने पर विद्यमान चुकता पूंजी और निबन्ध प्रारक्षित निधियों के 25 प्रतिशत की जो उच्चतम सीमा भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1972 से लागू की थी उसे 27 जनवरी 1975 से रिजर्व बैंक ने प्रचलित निदेशों में संशोधन करते हुए जारी की गयी तीन अधिसूचनाओं द्वारा षटकर 15 प्रतिशत कर दिया है। जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय और वित्तेतर कंपनियों की जमा राशियाँ कम की गयी उच्चतम सीमा से अधिक हैं उनको उस अधिक राशि की समाप्त करने के लिए 31 दिसम्बर 1975 तक समय दिया गया है। विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों अर्थात् इसामी चिट/लकी ड्रा/ वचन योजनाएं प्रादि चलाने वाली कंपनियों को पहले निर्धारित की गयी 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से अधिक राशि को समाप्त करने के लिए सितम्बर 1976 के अंत तक समय दिया गया था; उन कंपनियों को 15 प्रतिशत की षटायी गयी उच्चतम सीमा के भीतर प्रारक्षित ऋणों प्रादि के संदर्भ में बकाया राशि को कम करने के लिए 31 दिसंबर 1976 तक और अधिक समय दिया गया है।

210. दिनांक 1 फरवरी 1975 से प्रमल में आये कंपनी (संशोधन) अधिनियम 1974 द्वारा कंपनी अधिनियम 1955 में गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा राशियों के स्वीकरण को विनियमित करते हुए एक नयी धारा 58अ समाविष्ट की गयी है। उपर्युक्त धारा के अनुसार प्रवृत्त शक्तियों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा राशियों के स्वीकरण से संबंधित नियम बनाये हैं। ये नियम 3 फरवरी 1975 से प्रमल में आये। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा वित्तेतर कंपनियों को जारी किये गये निर्देशों को अब वापस ले लिया गया है।

211. 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिये गैर बैंकिंग कंपनियों में विद्यमान जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया गया उसके अंतर्गत सूचना देनेवाली कंपनियों की कुल संख्या काफ़ी अधिक प्रवृत्ति 3155 थी जब कि उसके पूर्व वर्ष के सर्वेक्षण के लिये 2240 कंपनियों में सूचनाएं दी थीं। जहाँ एक ओर 1971-72 के दौरान सूचना देनेवाली वित्तेतर कंपनियों की संख्या 762 से बढ़कर 2234 हो गयी वहाँ दूसरी ओर सूचना देनेवाली वित्तीय कंपनियों की संख्या 153 से बढ़कर 921 हो गयी। वित्तीय तथा वित्तेतर कंपनियों द्वारा सूचित किये गये लेखों की संख्या मार्च 1971 के अंत तक विद्यमान 8.16 लाख से बढ़कर मार्च 1972 के अंत में 10.70 लाख हो गयी। कुल जमाराशियों (जो छूट प्राप्त ऋण जमाराशियों के रूप में नहीं माने जाते उनको मिलाकर) में भी 123.1 करोड़ रुपये की काफ़ी अधिक वृद्धि पायी गयी अर्थात् जहाँ मार्च 1971 के अंत में उक्त राशियाँ 568.7 करोड़ रुपये थीं वहाँ मार्च 1972 के अंत में 691.8 करोड़ रुपये हो गयीं। 691.8 करोड़ रुपये की कुल राशि में से जमाराशियों तथा छूट प्राप्त ऋणों का अधिकांश भाग (480.8 करोड़ रुपये) वित्तेतर कंपनियों के पास तथा शेष राशि (211.0 करोड़ रुपये) वित्तीय कंपनियों के पास थी। 1971-72 के दौरान गैर बैंकिंग कंपनियों के पास बाकाया रहनेवाली कुल जमाराशियों में 187.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जमाराशियों में हुई यह वृद्धि छूट प्राप्त ऋणों में हुई। 64.6 करोड़ रुपये की कमी के कारण आंशिक रूप से समायोजित हो गयी।

212. जमाराशियों और छूट प्राप्त ऋणों का अधिकांश भाग थोड़ी सी ऐसी बड़ी गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में पाया गया जिनमें से प्रत्येक के पास 25 लाख रुपये से अधिक बाकाया जमाराशियाँ तथा छूट प्राप्त

ऋण थे। इस प्रकार सूचना देनेवाली 3155 कंपनियों में से 490 कंपनियों के पास कुल जमाराशियों 75.3 प्रतिशत और बाकाया जमाराशियों तथा छूट प्राप्त ऋणों का 78.2 प्रतिशत था।

213. सूचना देनेवाली कंपनियाँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित थीं। इन तीन राज्यों में स्थित गैर बैंकिंग कंपनियों के पास मार्च 1972 के अंत में कुल बाकाया जमाराशियों और छूट प्राप्त ऋणों का लगभग 71 प्रतिशत था।

214. गैर बैंकिंग कंपनियों पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण रखने तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि बंबई, बंगलूर और नयी दिल्ली में गैर बैंकिंग कंपनी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएँ। इस दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में उक्त विभाग का एक क्षेत्रीय कक्ष अक्टूबर 1974 से बंबई में कार्यरत है। इस कक्ष ने गैर बैंकिंग कंपनियों से संबंधित अध्ययन दल की सचिवालयीन सहायता प्रदान की।

215. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग कंपनियों पर लगाये गये नियंत्रण संबंधी कार्य की गंभीरतापूर्वक जाँच करने और उसमें विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार विनियमों को कठोर बनाने के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के निमित्त जून 1974 में एक अध्ययन दल का गठन किया था। अध्ययन दल ने 14 जुलाई 1976 को अपनी रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत की रिज़र्व बैंक ने उक्त दल की सिफारिशों की जाँच की और तत्संबंधी अपने विचार हाल ही में सरकार को प्रेषित किये हैं।

III. सहकारी बैंक व्यवसाय की गतिविधियाँ

216. 1974-75 के दौरान सहकारी बैंक व्यवसाय की नीति का विशेष उद्देश्य यह था कि दूसरी एजेंसियों को ऋण संबंधी खाई को पाटने के लिये प्रोत्साहित कर क्षेत्रीय असंतुलनों को कम कर दिया जाये और छोटे/आंशिक वृष्टि से कमजोर कृषकों को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किये जाएं। आधार स्तर पर ही सहकारी ऋण विन्यास को पुनर्गठित करने और उसे मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन संस्थाओं के कारोबार को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया गया कि वह मुद्रागत अनुशासन की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप हो और साथ ही उससे राष्ट्रीय विकास के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति भी हो।

सहकारी ऋण नीति

217. जहां कहीं रबी का मौसम प्रमुख था वहां रिजर्व बैंक ने खरीफ तथा रबी मौसम के लिये अलग-अलग ऋण सीमाएं मंजूर करने की प्रपत्ति नीति को जारी रखा। सहकारी संस्थाओं को कृषि संबंधी कार्यकलापों, विपणन तथा कुटीर और लघु उद्योगों का वित्तपोषण करने के लिये अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण प्रदान किये गये। 1973-74 में समाप्त हुए तीन वर्षों की अवधि के दौरान सहकारी ऋण अभियान और 1973-74 तथा 1974-75 में रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं को प्रदान किये गये ऋण के संदर्भ में हुई प्रगति का चित्र सारणी 24 और 25 में प्रस्तुत किया गया है।

अल्पावधि वित्त

218. अल्पावधि वित्त के क्षेत्र में पिछले वर्षों की तरह केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सब तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही जब तक अधस्तन सहकारी वर्ष के अंत में उन बैंकों की मांग जमाराशियों में उनकी कुल अतिरिक्त राशियों का अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए रिजर्व बैंक ने कई केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 1974-75 के दौरान खरीफ मौसम के लिये अतिरिक्त ऋण सीमाएं मंजूर कीं। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा मंजूर की गयी ऋण सीमाओं से मार्च से मई तक की तिमाही में निर्दिष्ट महीने के बाद उसी संवर्ष में राशि निकालने की अनुमति दी जब केन्द्रीय सहकारी बैंक ने राज्य सहकारी बैंक से लिये जानेवाले अपने उधारों की प्रत्येक बैंक के लिये निर्धारित स्तर तक कम कर दिया हो। अलग-अलग मामलों में जहां वास्तविक कठिनाइयों के कारण बैंक इस शर्त का पालन नहीं कर सके वहां उचित रियायतें की गयीं।

219. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के साथ पड़ी जाने वाली धारा 17 (2) (ख)/17 (4) (ग) के अंतर्गत कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों के लिए मंजूर की जानेवाली अल्पावधि ऋण सीमाओं की व्याज दर पहले की तरह बैंक दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम थी और जमा संचयन के साथ ऋणों को संबद्ध करने की शर्त की पूर्ति किये जाने पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट देने की भी व्यवस्था थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) (क) के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों को कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिये सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर बैंक दर से दो प्रतिशत कम दर पर ऋण सीमाएं मंजूर की जाती रहीं। परंतु इस धारा के अंतर्गत सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिये राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर पर अग्रिम प्रदान किये जाते रहे। वस्तुओं की जमाखोरी के लिये अधिक मात्रा में ऋण लिये जाने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से कई और कपास सहित फसलों के विपणन के लिये प्रदान की जानेवाली ऋण सीमाओं की व्याज दर को

1974-75 से बढ़ाकर बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इसके अलावा ऋणों को फसलों के विपणन से अधिक प्रभावकारी ढंग से संबद्ध करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि कृषि संबंधी मौसमी ऋणों आदि के अंतर्गत विद्यमान सहकारी समितियों की जो अतिरिक्त राशियां विपणन ऋण में से बसूल की गयीं उनकी सीमा तक हाल रिजर्व बैंक द्वारा विपणन के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं से राशियां निकालने की अनुमति दी जायेगी।

220. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) के अंतर्गत रिजर्व बैंक कृषि पुनर्वित्त निगम को अपने द्वारा धारित विशेष विकास डिबेंचरों की जमानत पर बैंक दर पर अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान करता रहा। बुनकर समितियों के उत्पादन एवं विपणन संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर से वार्षिक $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर पर और शिखर/क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर समितियों द्वारा किये जानेवाले रेशे के व्यापार का वित्तपोषण करने के लिये राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर पर ऋण सीमाएं मंजूर करने से संबंधित रिजर्व बैंक की भूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां राज्य सहकारी बैंकों को उर्वरक खरीदने, उनका स्टॉक और वितरण करने के लिये कोई ऋण सीमा या पर्याप्त ऋण सीमाएं मंजूर नहीं की गयीं वहां रिजर्व बैंक ने उक्त उद्देश्यों के लिये बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर ऋण सीमाएं मंजूर कीं। 1974 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान उर्वरकों के कारोबार के लिये सात राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गयी 28.20 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाओं के संवर्धन में पांच राज्य सहकारी बैंकों को 22.45 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किये गये।

'अर्वाचित' आहरण

221. रिजर्व बैंक ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि स्वीकृत ऋण सीमाओं से राज्य सहकारी बैंक अर्वाचित आहरण न करें और इस प्रकार आहरित अधिक राशि को आकर्षक व्याज दरों पर वाणिज्य बैंकों में मांग जमाराशियों के रूप में नहीं रखें, 1 जुलाई, 1974 से वण्ड स्वरूप व्याज लगाने का जो निर्णय किया था, उसका उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था। इस निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक के लिये वाणिज्य बैंकों के पास रखी जानेवाली मांग जमाराशियों की उचित उच्चतम सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। ये उच्चतम सीमाएं सामान्य रूप से संबंधित राज्य सहकारी, बैंक की मांग और मीयादी वेयताओं का लगभग 3 प्रतिशत निर्धारित की गयी है बशर्ते कि बैंक की जमाराशियों के स्वरूप, निधियों की आवश्यकताओं और साधन क्षमता को देखते हुए बैंक की समग्र चल निधि उसकी कुल वेयताओं का 35 प्रतिशत हो। यदि यह निर्दिष्ट सीमा किसी एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान 30 दिनों से आनुधिक अवधि तक बढ़ जाये तो बैंक को सूचित किया जाता है कि जितने अधिक दिनों के लिये वास्तव में ऐसी अतिरिक्त राशि जारी रही उनके लिये वह वार्षिक 12 प्रतिशत की दर पर वण्ड स्वरूप व्याज भरा करे। यदि ऐसी जमाराशियों की अवधि किसी एक वर्ष में 30 दिनों से अधिक हो जाये तो उसपर 15 प्रतिशत का वण्ड स्वरूप व्याज लिया जाता है।

जमाराशियां : व्याज दरें

222. सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों पर वेय व्याज दरों को विनियमित करने के उद्देश्य से बचत खातों और मीयादी जमाराशियों पर न्यूनतम व्याज दरें निर्धारित करते हुए 16 अगस्त, 1974 को एक निदेश जारी किया गया। बचत खातों की न्यूनतम व्याज दर को वार्षिक $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम

व्याज दर जमाराशि की अवधि के अनुसार 3 से 10 प्रतिशत तक होगी। इसके बाद 22 नवम्बर, 1974 को जारी किये गये निदेश के अनुसार वचन खाते और मीयादी जमाराशियों पर वेब व्याज दरों के लिये भी उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है। राज्य, केन्द्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों की जमाराशियों पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से क्रमशः $\frac{1}{2}$ प्रतिशत, $\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 1 प्रतिशत अधिक दर पर व्याज अदा करने की अनुमति दी गयी है। चापू खातों, 14 दिनों तक की जमाराशियों और 14 दिनों की या उनसे कम अवधि की ऐसी जमाराशियों पर भी जिन्हें नोटिस द्वारा निकाला या वापस अदा किया जा सकता है, वेब व्याज के संबंध में वार्षिक $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है।

जमा संचयन को ऋण से संबद्ध करना

223. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लिये जाने वाले उधारों पर रिजर्व बैंक द्वारा ली जाने वाली व्याज दर के साथ उनके द्वारा जुटायी जाने वाली जमा राशियों को संबद्ध करने की जो योजना 1 जुलाई, 1973 से प्रमल में रही है, उसके अंतर्गत कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों तथा पसलों के विपणन के लिये रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की जानेवाली ऋण सीमा की व्याज दर को बैंक दर से 2 प्रतिशत कम लिये जाने वाले व्याज के स्थान पर प्रारंभ में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम निर्धारित किया गया; परंतु कतिपय शर्तों की पूर्ति किये जाने पर संबंधित बैंकों को $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट दी गयी। 3 वर्षों के लिये प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ की गयी इस योजना को 1973-74 से 249 बैंकों के लिये लागू कर दिया गया है। 1973-74 के लिये निर्धारित आधार स्तर 1974-75 के लिये भी जानी रखे गये। परंतु सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अतिरिक्त छूट प्रदान करने के उद्देश्य से बकाया परिवर्तन ऋणों के 15 प्रतिशत के उपर मध्यावधि परिवर्तन ऋणों में विद्यमान उनके अतिरिक्त योगदान को शामिल कर रियायत प्रदान की गयी है।

224. व्याज कर अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को उनके कर योग्य व्याज के संबंध में 7 प्रतिशत की दर पर कर अदा करना पड़ता है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंकों को एक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधिकांश ऋणों पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट देने और दूसरी ओर वसूल किये गये व्याज पर उपर्युक्त छूट को हिसाब में लिए बिना व्याज कर अदा करने से दुगुनी प्रभुविधा होती है। ऋणों को जमा संचयन के साथ संबद्ध करने पर विचार करने वाली स्थायी समिति द्वारा 4 अप्रैल, 1975 को बंबई में हुई अपनी दूसरी बैठक में इस समस्या पर विचार किया गया और 1 जुलाई, 1975 से उक्त योजना में संशोधन करने का निर्णय किया गया। समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों के लिए सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले ऋणों और अधिमों की रिजर्व बैंक की व्याज दर को 1 जुलाई, 1975 से निम्नलिखित के संदर्भ में बैंक दर से 2 प्रतिशत कम निर्धारित किया जाएगा : (क) राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों के उस अंश के संदर्भ में जो ऋणों के 'आधार स्तर' का घटक है और (ख) 'आधार स्तर' से अधिक ऋण के संदर्भ में, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने ही वित्तीय साधनों से प्रदान किये गये कृषि ऋणों में हुई वृद्धि की दुगुनी राशि की सीमा तक या उनके द्वारा छोटे/सीमांत कृषकों को प्रदान किये गये ऋणों में हुई वृद्धि की पूरी सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक हो, उपर्युक्त दर लागू होगा। यदि कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक उपर्युक्त राशि से अधिक ऋण ले तो उस पर बैंक दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर पर व्याज लिया जाएगा। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिया जानेवाला व्याज भी इसी प्रकार होगा।

अधिमों की अधिकतम सीमाएं

225. किसी बैंक द्वारा निदेशक या निदेशकों के समूह की या किसी दूसरी एक पार्टी की प्रदान किये जाने वाले कुल अधिमों की उच्चतम सीमाएं निर्धारित करते हुए तथा किसी बैंक द्वारा अपने सभी सदस्यों का प्रदान किये जानेवाले गैर जमानती अधिमों की समग्र सीमाएं निर्धारित करते हुए 31 जनवरी, 1975 को प्राथमिक सहकारी बैंकों के नाम एक निदेश जारी किया गया। उसके बाद 27 मार्च, 1975 को प्राथमिक सहकारी बैंकों को जारी किये गये निदेश में एक ऐसे समयबद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार ऐसे प्राथमिक सहकारी बैंकों को जिनके पास 31 जनवरी, 1975 को गैर जमानती अधिमों के संबंध में कुल बकाया राशि 31 जनवरी, 1975 के पुराने निदेश में निर्धारित सीमा से अधिक हो, निविष्ट समय सीमा के भीतर अपने गैर जमानती अधिमों के स्तर को कम करना होगा।

वसूली कार्यकलापों का वित्तपोषण

226. वसूली तथा समीकरण भंडार संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के संबंध में सहकारी बैंकों की भूमिका पर पहले लगाये गये नियंत्रण में सहकारी बैंकों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि उन्हें इस संबंध में अपना योगदान देने की अनुमति दी जाए, संशोधन किया गया। यह निश्चय किया गया कि समीकरण भंडारों के लिए नहीं परंतु वसूली संबंधी कार्यकलापों के वित्तपोषण में सहकारी बैंक कतिपय शर्तों पर अपनी यह निधियों का निवेश कर सकते हैं; उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नप्रकार हैं : (1) ऐसे वित्त की राशि बैंक की मीयादी और मांग देयताओं के 5 प्रतिशत या राज्य सहकारी बैंकों के मामले में 1 करोड़ रुपये या केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में 50 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक न हो, (2) इस प्रकार निकाली जानेवाली प्रत्येक राशि की प्रभुधि 6 सप्ताह से अधिक न हो और (3) ऐसे भंडारों के बंधक और दृष्टि-बंधक पर तब तक क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित किया जाए जब तक कि भारतीय खाद्य निगम/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदे न गये हों या उनकी वसूली नहीं की गयी हो तथा उनके प्रबंध, भंडारण और परिवहन जैसे प्रासंगिक कार्यों के शुल्क निर्धारित नहीं किये गये हों; उपर्युक्त संदर्भों में 10 प्रतिशत के मार्जिन पर वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

227. गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों और चुने हुए 25 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को रूई और कपास की जमानत पर उनके द्वारा दिये जाने वाले अधिमों को वित्तियमित करने के लिए 1974-75 के दौरान विविष्ट निदेश जारी किये गये थे। इन निदेशों में इन पण्यों के संदर्भ में न्यूनतम मार्जिन, व्याज दर तथा ऋण-स्तर निर्धारित किये गये हैं।

अन्य संवेदनशील पण्यों का वित्तपोषण

228. ऋण नियंत्रण संबंधी सामान्य उपायों के एक अंश के रूप में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे खाद्यान्नों, तिलहनों, वनस्पति तेलों (वनस्पति संहित), बीनी, गुड़, खांडसरी तथा अन्य संवेदनशील कृषि पण्यों पर दिये जाने वाले उनके अधिमों के संबंध में कतिपय मानकों का पालन करें। इन मानकों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

(1) जहाँ किसी एक पार्टी को दिये जाने वाले अधिमों की राशि राज्य सहकारी बैंकों के मामले में 1 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में 50 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना हो

वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाये; (2) ऐसे ग्रामियों के संबंध में बंधक और वृष्टिबंधक के लिये क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन बनाये रखा जाये ; परंतु जहाँ ऐसे ग्रामिण पूर्ण रूप से सरकार द्वारा गारंटीकृत हों वहाँ बैंक उक्त मार्जिनों को घटाकर क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर सकते हैं ; (3) चीनी और खाद्यान्नों की जमानत पर दिये जाने वाले ग्रामियों पर 13 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम ध्याज लिया जा सकता है जब कि अन्य सभी प्रकार के कृषि उत्पादनों के मामले में ध्याज की न्यूनतम दर 14 प्रतिशत हो ; और (4) विपणन समितियों को प्रदान किये जानेवाले ऐसे ग्रामियों की न्यूनतम अवधि सामान्यतः 90 दिनों से अधिक न हो ।

229. इसी प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को यह अनुदेश दिया गया है कि उपर्युक्त पण्यों पर ग्रामियों के लिये प्राप्त प्रस्तावों की वे कड़ाई से जांच करें और विशेष रूप से प्रति सदस्य 10,000 रुपये से अधिक राशि के ऐसे ग्रामियों पर सावधानी से निगरानी रखे । प्राथमिक बैंकों को निम्नलिखित बातों की पूर्ति करने के लिये कहा गया है : (1) किसी भी सदस्य को उपर्युक्त किसी पण्य पर दी जाने वाली ग्रामिण राशि नवंबर-अक्तूबर में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1973-74, 1972-73 और 1971-72 में से किसी एक वर्ष में उस सदस्य के नाम बकाया रहनेवाली अधिकतम राशि के 100 प्रतिशत से अधिक न हो । जिस सदस्य ने इन तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान उधार नहीं लिए हों, उसे दी जाने वाली ग्रामिण राशि 20,000 रुपये से अधिक न हो ; (2) ऐसे ग्रामियों पर 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर ध्याज लिया जाये ; (3) इन में से किसी पण्य के संबंधित स्टार्कों को बंधक/वृष्टि बंधक रखने पर दिये जाने वाले ग्रामियों के संबंध में 40 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन बनाये रखा जाये ; (4) जिन निराश्रित मूनिटों और अन्य ऋणकर्ताओं (लघु उद्योगों सहित) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी बैंक से ऋण लिया हो उनको उस बैंक द्वारा उपर्युक्त पण्यों पर प्रदत्त भारतीय ऋण गारंटी निगम की ऋण गारंटी योजना के अधीन गारंटीकृत ऋण प्रत्येक ऋण सीमा के अंतर्गत अधिकतम रु० 20,000 की सीमा तक उपर्युक्त (1) और (3) में निर्धारित ऋण स्तर और मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं से छूट प्राप्त हैं । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि मार्च 1975 में इन बैंकों द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त/लाइसेंसीकृत और/या संबंधित राशन व्यवस्था/उचित मूल्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों को तिसहूनों और उनके तेलों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋणों के संबंध में सार्वजनिक वितरण के लिये अपेक्षित मात्रा की सीमा तक इन अपेक्षाओं से छूट दी गयी ।

ऋण प्राधिकरण योजना

230. सहकारी क्षेत्र में अधिक संख्या में जोभी के कारखानों, कताई, मिलों आदि की स्थापना के वित्तपोषण के निमित्त अपेक्षित थोक पूँजीगत उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा की गयी मीयादी ऋणों की प्राधिकारिक मांग को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि इन बैंकों के मीयादी ऋणों के संदर्भ में कुछ अनुशासन लाया जाये । तदनुसार राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सितंबर 1974 में यह निर्देश दिया गया कि वे अपने सदस्यों को निविष्ट राशियों से अधिक मीयादी ऋण और अंतरिम सहायता प्रदान करने से पहले या किसी निर्माण या अभिसंस्करण यूनिट को थोक पूँजी के लिये 25 लाख रुपये से अधिक वित्त या गारंटी प्रदान करने के लिये साक्ष्यपत्रों के रूप में या किसी करार के रूप में वित्तीय सहायता के वायदे करने से पहले लिखित रूप में पूर्व प्राधिकरण के लिये रिजर्व बैंक को लिखें ।

ऋण गारंटी योजना

231. जून 1975 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करने वाले 9 राज्य सहकारी बैंक, 68 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 48 प्राथमिक सहकारी बैंक (42 गैर लाइसेंसीकृत और 6 लाइसेंसीकृत) अपेक्षित करार निष्पादित कर इस योजना में शामिल हुए ।

232. सहकारी बैंकों और समितियों के कृषि संबंधी ऋणों को गारंटी योजनाओं के अंतर्गत लाने के प्रश्न की जांच करने के लिये भारतीय ऋण गारंटी निगम द्वारा गठित कार्यकारी दल ने फरवरी 1975 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में इस बात के लिये अपनी सहमति नहीं दी और यह सुझाव दिया कि जहाँ तक ऋणों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने का प्रश्न है, वर्तमान स्थिति को जारी रखने दिया जाए । उक्त दल ने यह भी सुझाव दिया है कि पांच वर्षों की अवधि के बाद इस संबंध में स्थिति का पुनरीक्षण किया जाये ।

केरल में सहकारी नारियल रेशा समितियाँ

233. रिजर्व बैंक द्वारा पहले दिये गये सुझावों के अनुसार केरल में सहकारी नारियल रेशा समितियों का पुनर्गठन करने की योजना जनवरी 1975 में क्रमशः लागू की गयी । जिन प्राथमिक नारियल रेशा समितियों और केन्द्रीय नारियल रेशा विपणन समितियों को सक्षम और सक्षम होने की संभावनायुक्त समितियों के रूप में पाया गया उनके कार्यकारी पूँजीगत प्रयोजनों के लिये संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिये रिजर्व बैंक सहमत हो गया है । उक्त योजना में निम्नलिखित परिकल्पना भी गयी है (1) वर्तमान प्राथमिक नारियल रेशा समितियों को उत्पादन और विक्रय समितियों के रूप में परिवर्तित किया जाये और (2) सक्षम और सक्षम होने की संभावनायुक्त समितियों को राज्य सरकार तीन वर्षों की अवधि के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि उक्त समितियाँ क्रमबद्ध रूप से संस्थागत वित्त की ओर अग्रसर हो सकें । केरल सरकार के साथ किये गये करार के अनुसार रिजर्व बैंक ने 8 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से केरल राज्य सहकारी बैंक को 1974-75 के लिये कुल 1.25 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएं मंजूर कर जनवरी 1975 में सहकारी बैंकों के लिये ऋण व्यवस्था कर दी है ; उक्त ऋण सीमाओं में सक्षम समिति के रूप में पता लगायी गयी 21 प्राथमिक नारियल रेशा समितियों के वित्तपोषण के लिये 42 लाख रुपये, 4 केन्द्रीय नारियल रेशा विपणन समितियों के वित्तपोषण के लिये 55.50 लाख रुपये और 8 निर्माण समितियों के वित्तपोषण के लिए 27.60 लाख रुपये शामिल हैं ।

कर्नाटक में रेशम उत्पादन

234. कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के रेशम उत्पादकों, रेशम-बुनकरों और दूसरों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किये गये सघन कार्यक्रम के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर बैंक ने कर्नाटक सरकार को समितियों की शेरार पूँजी में प्रवेशान करने के लिये प्रति समिति 50,000 रुपये से अधिक राशि के दीर्घावधि ऋण मंजूर करना स्वीकार किया है । प्राप्ता की जाती है उक्त समितियों का वित्तपोषण प्रमुख रूप से राज्य के वाणिज्य बैंक करेंगे और उनके लिये कृषि पुनर्वित्त निगम पुनर्वित्त प्रदान करेगा । अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 67 समितियाँ स्थापित की गयी हैं जब कि 125 से 150 तक की समितियों की स्थापना की परिकल्पना की गयी थी । परंतु समितियों का वास्तविक वित्तपोषण कार्य अभी किया जाना बाकी है ।

औद्योगिक समितियों का पुनर्गठन

235. औद्योगिक यूनिटों को सक्षम/सक्षम होने की संभावना-युक्त यूनिटों के रूप में वर्गीकृत करने के निमित्त प्रारंभ किया गया सर्वेक्षण कार्य केवल 7 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा में समाप्त हुआ है। तमिलनाडु, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। परंतु अब तक केरल, उड़ीसा और असम राज्यों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कर्नाटक के मामले में केवल बुनकर समितियों के मामले में सर्वेक्षण कार्य समाप्त हुआ है। आशा है कि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार मानक निर्धारित करेगी और रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर सर्वेक्षण कार्य करेगी। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में औद्योगिक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन का कार्य अभी हो रहा है।

236. दिसंबर 1974 में राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अलग-अलग व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी गयी ताकि उन लघु उद्योग यूनिटों को संस्थागत वित्त उपलब्ध हो सके जिन्हें उस क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों के अभाव में ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। सहकारी बैंकों के पंजीयनों को भी यह सूचित किया गया है कि यदि इन संबंध में केन्द्रीय/राज्य सहकारी बैंकों के मार्ग में विधि संबंधी कोई बाधा उपस्थित होती हो तो वे राज्य सरकारों से राज्य सहकारी समिति अधिनियम/नियमावली में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करें। रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से जो पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, उन्हें प्राप्त करने में इससे सहकारी बैंकों को सुविधा हो सकती है।

मध्यावधि वित्त

237. मध्यावधि कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण सीमाएं प्रदान किये जाने से संबंधित बैंक की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; परंतु यह निश्चय किया गया कि निविष्ट छोटे कृषकों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए दिये जानेवाले ऋणों को सहजता से परिश्रेय उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रवृत्त ऋण के रूप में माना जाए। रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया है कि सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदान किये जानेवाले मध्यावधि ऋणों को पुनर्वित्त के लिए पाल 'ग्रनुमोदित उद्देश्य' के रूप में माना जाए। जहां कहीं आवश्यक हो वहां बैंक मध्यावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने की सुविधाएं प्रदान करता रहा।

हथकरघा वित्त

238. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को हथकरघा (सूती, रेशमी और ऊनी) और बिजली चालित करघा बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17(2)(खख) के अंतर्गत बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम रियायती दर पर अर्थात् फिलहाल $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा। यह वित्तीय सहायता इस शर्त पर प्रदान की गयी कि हथकरघा बुनकर समितियों से ली जानेवाली ब्याज दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा (हथकरघा सूती, रेशमी और ऊनी समितियों को भारत सरकार द्वारा दिये जानेवाले 3 प्रतिशत के ब्याज उपदान को देखते हुए) समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली ब्याज दर से

अधिक नहीं हो और बिजली चालित करघा बुनकर समितियों के मामले में ली जानेवाली ब्याज दर अनुचित रूप से अधिक नहीं हो (बिजली चालित करघा समितियों को ब्याज उपदान उपलब्ध नहीं है)।

239. हथकरघा उद्योग और बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए दिसंबर 1973 में भारत सरकार ने जो उच्च स्तरीय अध्ययन बल गठित किया था उसने जुलाई 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; उक्त अध्ययन का उद्देश्य यह था कि पांचवीं योजना अवधि में इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम सुझाया जाए। हथकरघा वित्त की अपनी योजना के अंतर्गत बुनकर समितियों के वित्तपोषण के लिए ऋण सीमाएं निर्धारित करने की रिजर्व बैंक की वर्तमान प्रणाली का समर्थन करते हुए उक्त दल ने रिजर्व बैंक के विचारार्थ यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि नयी समितियों या पुनः कार्यरत की जानेवाली निष्क्रिय समितियों को मंजूर की जानेवाली ऋण सीमाओं में वृद्धि की जाए। बैंक इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। दल ने एक सिफारिश यह भी की है कि रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह बुनकरों को मध्यावधि वित्त की सुविधाएं प्रदान करे ताकि वे सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में अभिदान कर सकें; इस सिफारिश पर बैंक ने जनवरी 1975 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46क(2)(ख) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17(4कक) के अंतर्गत बिजली चालित करघा बुनकर समिति के सदस्यों को जिला केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से और अलग-अलग बिजली चालित करघा मालिकों को प्राथमिक (शहरी) बैंकों के माध्यम से उप-भोक्ता सहकारी कताई मिलों के शेयर खरीदने के लिए मध्यावधि ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता बैंक दर पर और राज्य सरकार की गारंटी पर उपलब्ध होगी। हथकरघा मालिकों को भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

वीर्षावधि वित्त

240. रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने और छोटे कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजना के क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तपोषण की योजना अमल में थी, कार्यरत संस्थाओं के मामले में तथा पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत लाये गये बैंकों के मामलों में दी जानेवाली रियायतों को जारी रखा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने, उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ओर से जिनमें केन्द्रीय सहकारी बैंक या उक्त उद्देश्य के लिए गठित जिला समिति द्वारा बनाये रखे गये संवर्ग से पूर्णकालिक वित्तनिक सचिव नियुक्त किये गये हों, शेयर पूंजीगत ऋण मंजूर करना स्वीकार किया बशर्ते कि उनकी प्रतिव्यय राशियां उनकी मांग राशि के 50 प्रतिशत से अधिक न हों। 3 राज्य सहकारी बैंकों, 69 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 2252 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 2 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 55 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और 11 शहरी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए 16 राज्य सरकारों को कुल 8.37 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये गये; 31 मार्च 1975 को इस संबंध में बकाया राशि 70 करोड़ रुपये थी।

241. सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को मंजूर किये जानेवाले वीर्षावधि ऋणों के संबंध में विभिन्न ब्याज दरों की जो सुविधा उपलब्ध थी उसे 1 अप्रैल 1974 से वापस ले लिया गया है और यह निश्चय किया गया है कि ऐसे ऋणों

पर 6 प्रतिशत की एक समान दर पर ब्याज लिया जाए। परन्तु राज्य सरकारों को प्रदान किये गये अधिमों में से 31 मार्च 1974 को कारो-बार बन्द होने तक बकाया रहनेवाले अधिमों पर उनके प्रतिदेय होने तक उसी दर पर ब्याज लिया जाता रहेगा जिस दर पर वे प्रदान किये गये थे।

242. रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त निगम को भी राष्ट्रीय कृषि ऋण (बीर्धकालीन प्रवर्तन) निधि में से 1973-74 के दौरान 23 करोड़ रुपये और 1974-75 के दौरान 40 करोड़ रुपये की बीर्धकालीन सहा-यता मंजूर की (सारणी 25)। ऐसे ऋणों पर लिये जानेवाले ब्याज की दर को 9 नितम्बर, 1974 से 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया।

भूमि विकास बैंक

243. 1974-75 के वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय भूमिविकास बैंकों के लिए कुल 125.23 करोड़ रुपये का सामान्य ऋण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसमें से बैंकों के आन्तरिक स्रोतों से 18.51 करोड़ रुपये, ग्रामीण डिबेंचर जारी कर/सावधि जमाराशियां से 4.33 करोड़ रुपये और सामान्य डिबेंचर जारी कर 102.39 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया जाएगा। केन्द्रीय भूमिविकास बैंकों ने वास्तव में 66.67 करोड़ रुपये के डिबेंचर जारी किये और 68.33 करोड़ रुपये की अभि-दान राशि एकत्रित की; इसमें से 45.59 करोड़ रुपये का अभिदान भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह, अन्य वाणिज्य बैंकों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने किया। विभिन्न राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की योजना प्रारंभ की गयी और इसके परिणामस्वरूप सामान्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण प्रदान किये जाने की संभावना में कमी आ गयी, अतः 1974-75 के लिए निर्धारित डिबेंचर निर्गम कार्यक्रम की पूर्ति में उल्लेखनीय कमी आयी। 1975-76 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य भूमि-विकास बैंकों के लिए 229.55 करोड़ रुपये का ऋण कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसमें से 119.80 करोड़

रुपयों और 109.75 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था क्रमशः कृषि पुनर्वित्त निगम की विशेष योजनाओं और सामान्य ऋणों के अंतर्गत की जाएगी। यह आशा की जाती है कि सामान्य ऋण कार्यक्रम का वित्त-पोषण निम्न प्रकार किया जाएगा : (1) बैंकों के आन्तरिक स्रोत (26.62 करोड़ रुपये), (2) ग्रामीण डिबेंचर/सावधि जमाराशियां (3.38 करोड़ रुपये), और (3) सामान्य डिबेंचर (79.75 करोड़ रुपये)। परन्तु वित्तीय साधन संबंधी कठिनाई के कारण 72.50 करोड़ रुपये से अधिक राशि के सामान्य डिबेंचर जारी करना संभव नहीं होगा। भूमि विकास बैंकों को 10 प्रतिशत की जो अतिरिक्त अभिदान राशि रख लेने की अनुमति दी जाएगी उसको सम्मिलित करने पर कुल 79.75 करोड़ रुपये के सामान्य डिबेंचर जारी किये जा सकेंगे। यह आशा की जाती है कि 1975-76 के दौरान केन्द्रीय भूमि विकास बैंक अपने द्वारा जारी किये जानेवाले सामान्य डिबेंचरों के लिए अपने प्रयासों से 5.23 करोड़ रुपये की अभिदान राशि प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि शेष 67.27 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित प्रकार से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होगी :

(राशि करोड़ रुपये में)

स्रोत	आवंटित सहायता
1. भूमि-विकास बैंकों की शोधन पूंजी (परस्पर सहायता)	29.27
2. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें	12.00
3. संस्थागत एजेंसियां :	
(i) भारतीय जीवन बीमा निगम	12.00
(ii) वाणिज्य बैंक	10.00
(iii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह	4.00
	67.27

सारणी 24 : सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्थाओं के प्रकार	सहकारी वर्ष		
	1971-72	1972-73	1973-74*
(क) राज्य सहकारी बैंक			
(1) संख्या	26	26	26
(2) स्वाधिकृत निधियां	103	116	125
(3) जमाराशियां	330	406	493
(4) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण	211	246	235
(क) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण	153	155	154
(5) कार्यकारी पूंजी	731	849	931
(6) जारी किये गये ऋण	947	1133	1227
(7) बकाया ऋण	553	635	679
(क) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण	343	367	351
(8) (7क) में (4क) का प्रतिशत	44	42	44

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक								
(1) संख्या						341	344	341@
(2) स्वाधिकृत निधियां						226	254	274
(3) जमाराशियां						510	647	720
(4) रिजर्व बैंक/गिखर बैंक से लिये गये उधार						358	398	451
(5) कार्यकारी पूंजी						1194	1412	1542
(6) जारी किये गये ऋण						1056	1246	1412
(7) बकाया ऋण						889	1028	1085
(ग) केन्द्रीय भूमि विकास बैंक								
(1) संख्या						19	19	19
(2) स्वाधिकृत निधियां						70	98	110
(3) बकाया डिबेंचर						880	1015	1146
(4) कार्यकारी पूंजी						1016	1202	1409
(5) जारी किये गये ऋण						146	171	133
(6) बकाया ऋण						729	849	896
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां								
(1) संख्या (हजारों में)						157	155	156
(2) सवस्मणा (बही)						32009	33528	36785
(3) स्वाधिकृत निधियां						292	323	355
(4) जमाराशियां						75	84	90
(5) उधार						740	858	944
(6) जारी किये गये ऋण						615	776	815
(7) बकाया ऋण						858	979	1062

@ 9 केन्द्रीय बैंकों के प्रांकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*अनंतिम।

सारणी 25 : सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण—1973-74 और 1974-75

(राशि करोड़ रुपयों में)

बिस्तीय सहायता का उद्देश्य	1973-74 (जुलाई-जून)				1974-75 (जुलाई-जून)			
	मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशि	चुकोतियां	बकाया राशि	मंजूर की गयी सीमाएं	निकाली गयी राशि	चुकोतियां	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8

I. अल्पावधि

(1) कृषि संबंधी मौसमी कार्यक्रम (बैंक दर से $\frac{1}{2}\%$ कम दर पर) ⁰	430.83	619.44*	612.84	151.51*	489.52	811.79	751.15	212.15
(2) रुई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन	40.58	12.09	10.73	1.94	40.30	18.13	19.58	0.49
(3) रुई और कपास का विपणन ⁵		6.55	8.62	0.85		46.94	37.54	10.25

	1	2	3	4	5	6	7	8
(4) उर्वरकों की खरीद और वितरण (बैंक दर से 3% अधिक दर पर) ¹	—	—	2.75	—	28.20	22.45	3.65	18.80
(5) हथकरघे पर बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन और विपणन (बैंक दर से 1½ कम दर पर) ³	14.49	13.38	16.08	5.03	15.69	29.43	23.37	11.09
(6) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्तपोषण ³	0.79	0.47	0.22	0.28	2.52	1.33	0.28	1.33
(7) घास की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर) ³	0.40	0.30	0.33	—	0.65	0.47	0.43	0.04
(8) कृषि पुनर्वित्त निगम को ऋण (बैंक दर पर)	15.00	12.86	4.96	11.60	15.00	—	11.60	—
(9) चीनी के बंधक पर दिया गया ऋण	—	—	—	—	22.00	67.12	45.12	22.00

II. मध्यावधि :

(1) कृषि उद्देश्य (बैंक दर से 1½% कम दर पर) ⁷	11.77	6.03	10.43	19.91	9.87	4.58	8.83	15.65
(2) प्रभावग्रस्त क्षेत्रों के भ्रष्टावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करना (बैंक दर से 1½% कम दर पर)	22.47 ²	41.26 ²	20.82 ²	51.19 ²	81.32	55.04	21.56	79.10
(3) सहकारी चीनी कारखानों/प्रसिंस्करण समितियों के ऋणों की खरीद (बैंक दर पर) ⁷	0.18	0.97 ⁴	0.40	1.19	0.53	0.16	0.34	1.01

III. दीर्घावधि :

(1) सहकारी ऋण संस्थाओं की ऋण पूजी में भ्रष्टादान करने के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण ³	8.02	8.02	5.57	68.00	8.37	8.37	6.37	70.00
(3) कृषि पुनर्वित्त निगम को दिये गये ऋण (वार्षिक 4½%/4½% की दर पर) [†]	23.00	23.00	3.50	54.00	40.00	40.00	5.80	£8.20

(1) 1972 के पहले उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर पर वित्तीय सहायता दी जाती थी। परंतु ब्याज दर को वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों के अनुसंधान बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढ़ाकर बैंक दर से 2% अधिक बना दिया गया। इस दर को पुनः 1974 के लिए बढ़ाकर बैंक दर से 3% अधिक बना दिया गया। आंकड़े 1972 और 1973 के कैलेंडर वर्षों से संबंधित हैं।

(2) पुनर्व्यवस्था को मिलाकर

(3) आंकड़े वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं।

(4) 30 जून 1974 तक की गयी पिछले वर्ष की ऋण सीमा से निकाला गया।

(5) रूई की एकाधिकार बसूली को मिलाकर।

(6) छूट योजना के अनुसार दी गयी 1½% की छूट के अधीन 1973-74 से बैंक दर से ½ प्रतिशत कम दर पर; परन्तु धारा 17(4) (क) के अधीन बैंक दर से 2% कम दर जारी रही।

(7) आंकड़े कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।

*संशोधित; जून 1974 में निकाले गये 75 लाख रुपये की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के प्रबंधक ने काफी विलंब से अर्थात् अक्टूबर 1974 में दी।

£31 मार्च 1975 की स्थिति।

† 9 सितम्बर 1974 से ब्याज दर को 4½% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया।

244. 1975-76 के वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम के संदर्भ में मई 1975 में तमिलनाडु और हरियाणा राज्य भूमि-विकास बैंकों से सामान्य डिबेंचर जारी करने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए; रिजर्व बैंक ने क्रमशः 130 लाख रुपये और 50 लाख रुपये की सीमा तक उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया। साथ ही अनिश्चित भ्रणदान का 10 प्रतिशत रख लेने का विकल्प भी दिया गया।

245. रिजर्व बैंक दीर्घकालीन ऋणों की उत्पादन अभिसूच प्रणाली पर जोर देता रहा और उसने इस बात पर भी जोर दिया कि 1975-76 के दौरान बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले ऋणों (जहां कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पुनर्वित्त पोषित योजनाएं/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाएं भ्रमन में हों वहां उनके अंतर्गत जारी किये गये ऋणों सहित) का कम से कम 90 प्रतिशत भ्रण उत्पादक उद्देश्यों के लिए हो। इसमें से 70 प्रतिशत से अनूयन भ्रण सुस्पष्ट उत्पादक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।

246. इस वर्ष प्राथमिक भूमि विकास बैंक/केन्द्रीय भूमि विकास बैंक की शाखा का ऋण कार्यक्रम पिछले वर्ष की गयी वसूली के आधार पर निर्धारित किया जाता रहा। सामान्य ऋण कार्यक्रम और कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पुनर्वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक बैंकों/शाखाओं को प्रदान किये जानेवाले ऋणों को विनियमित करने से संबंधित मानकों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक संशोधित कार्यक्रमप्रणाली 1 जुलाई 1975 से क्रमशः लागू की गयी है। नयी कार्य प्रणाली के अनुसार 75 प्रतिशत और अधिक ऋण की वसूली करनेवाले प्राथमिक बैंकों/शाखाओं के लिए अनिवार्य ऋण कार्यक्रम स्वीकार किया जाता है। मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम होने लगने ही इस कार्यक्रम में क्रमशः कटौती की जाएगी ताकि मांग के 60 प्रतिशत से अधिक अतिदेय राशियों से युक्त प्राथमिक बैंक/शाखाएं किसी भी ऋण कार्यक्रम के योग्य नहीं हों। प्राथमिक बैंकों/शाखाओं की पात्रता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक बैंक या केन्द्रीय भूमि विकास बैंक की शेरर पूंजी में निविष्ट किसी भी शाखा के लिए भ्रणदान कर सकती है। किन्तु वास्तव में किसी भी राशि का भ्रणदान किये जाने के बावजूद उस वर्ष की मांग के 10 प्रतिशत की अनुमानिक सीमा तक अतिदेय राशियों को कम करने के लिए ऐसे भ्रणदान को हिसाब में लिया जाएगा। उन शाखाओं/प्राथमिक बैंकों के संदर्भ में जिनकी अतिदेय राशियां मांग राशि के 60 प्रतिशत से अधिक हैं और जिनकी शेरर पूंजी में सरकार ने उक्त अतिदेय राशियों को अनुमानिक रूप से कम करने के लिए कोई भ्रणदान नहीं किया है, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक अपने वित्तीय साधनों से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सकता है बशर्ते कि उस बैंक द्वारा भ्रमि दिये गये ऋणों को भ्रमले 10 वर्षों में जारी किये जाने वाले सामान्य/विशेष डिबेंचरों के लिए रक्षा की व्यवस्था करते हुए बंधको से मुक्त कर दिया जाए। किन्तु यदि ऐसे बैंक/शाखा की अतिदेय राशियां उसी स्तर पर विद्यमान हैं और भ्रमले वर्ष में भी उनमें सुधार न आये तो केन्द्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा अपने वित्तीय साधनों से प्रदान की जानेवाली क्षतिपूर्ति सुविधा भी नहीं दी जाएगी।

247. केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा सामान्य डिबेंचर जारी किये जाने के लिए निर्धारित शर्तों में संशोधन किया गया है। अब तक उक्त बैंक ऐसे सामान्य डिबेंचर जारी किया करते थे जिनकी समाप्ति अवधि 10, 12 तथा 15 वर्ष होती थी। 10 वर्षों के डिबेंचरों के प्रति संस्थागत निवेशकों की अभिरुचि को देखते हुए अब यह निश्चय किया गया है कि क्रमशः 10 तथा 15 वर्षों की समाप्ति अवधि-युक्त दो प्रकार के सामान्य डिबेंचर जारी किये जायें। दोनों प्रकार के डिबेंचरों की ब्याज-दर 6.25 प्रतिशत और निगम राशि 10 और 15 वर्षों के डिबेंचरों के लिए क्रमशः ₹० 98.85 और ₹० 97.50 है।

248. आलोच्य वर्ष के दौरान नीतियों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न प्रकार थे :

(1) केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों द्वारा स्वीकार की जानेवाली सावधि जमाराशियों की ब्याज दरों को एक वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्षों तक के लिए जमाराशियों के संदर्भ में बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। बैंकों को सूचित किया गया कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकार करना लाभदायक नहीं है। इस उद्देश्य से कि केन्द्रीय भूमि विकास बैंक आकर्षक ब्याज दरें प्रस्तुत कर सकें, यह भी निश्चय किया गया कि 25 जुलाई, 1974 से केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक एक वर्ष की जमाराशियों पर (क) केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक के मुख्य कार्यालयों में राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तावित यदि कोई उच्चतर दरें हो तो उन दरों पर ; (ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जिस क्षेत्र में प्राथमिक बैंक/शाखाएं स्थित हैं उस क्षेत्र के केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा यदि कोई उच्चतर दरें प्रस्तावित हों तो उन दरों पर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों में ब्याज भ्रदा करें ; (2) केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की ऋण शोधन निधियों में किये जानेवाले निवेश के संबंध में प्रवृत्त अनुदेशों के अनुसार भूमि विकास बैंक डिबेंचरों में केन्द्रीय भूमि विकास बैंक ऋण शोधन निधि के 60 प्रतिशत तक, राज्य सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों के पास रहनेवाली सावधि जमाराशियों में 20 प्रतिशत तक तथा सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों (इनमें भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर शामिल नहीं हैं) में 20 प्रतिशत से अनूयन राशि निवेशित कर सकते हैं। सामान्य डिबेंचरों के निर्गम में हुई कमी को देखते हुए सहयोग की संस्थाओं के डिबेंचरों में ऋणशोधन निधि के निवेश की संभावना तेजी से कम होती जा रही है। अतः यह निश्चय किया गया है कि संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केन्द्रीय भूमि विकास बैंक राज्य सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों के पास रहने वाली सावधि जमाराशियों में अपनी ऋण शोधन निधि के 30 प्रतिशत तक तथा भूमि विकास बैंकों के डिबेंचरों में 50 प्रतिशत तक की राशि निवेशित कर सकते हैं; (3) कुछ केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के पास पुराने ऋणों से संबंधित ऐसी अतिदेय राशियां विद्यमान थीं जो 5 वर्षों अथवा अधिक अवधि तक वसूल नहीं की गयीं। बैंकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी ध्यान में रखते हुए निश्चय किया गया है कि यदि प्राथमिक भूमि विकास बैंक/केन्द्रीय भूमि विकास बैंक की शाखाएं चाहें तो 5 वर्षों या अधिक अवधि की अतिदेय राशियों को अलग-अलग खातों में पृथक् कर दें तथा मांग में अतिदेय राशियों के प्रतिशत की गणना करते समय कुल अतिदेय राशियों में उन्हें शामिल न करें। प्रति वर्ष हम प्रकार अवरोध राशि के 20 प्रतिशत को उस वर्ष की मांग के रूप में माना जाए। किन्तु इस मांग की तुलना में वसूली में यदि कोई कमी रह गयी तो उसे पूरा करने के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की प्रारक्षित निधि की पूरी व्यवस्था करनी होगी। इस छूट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 5 वर्षों के अंत में या तो बैंकों ने अवरोध राशि के रूप में पृथक् की गयी पूरी राशि की वसूली कर ली है अथवा इस प्रणाली के अधीन वसूल की गयी राशि के लिए उचित व्यवस्था कर ली है; (4) ट्रैक्टर खरीदने के लिए जिन लोगों ने दीर्घकालीन ऋण लिये उनकी होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के विचार से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित बातों से संबंधित मानकों को निर्दिष्ट करते हैं; कितना न्यूनतम कार्यभार आवश्यक हो, ऋणकर्ताओं के पास कितनी भूमि हो, अव्यवस्था का निर्धारण करते समय अधिकतम कितना मार्जिन रखा जाए, आदि।

सहकारी भूमि विकास बैंकों के संबंध में समिति

249. भूमि विकास बैंकों की कार्यप्रणाली के परीक्षण के लिए अप्रैल 1973 में गयनर द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों के संबंध में गठित

की गयी समिति ने 31 दिसंबर 1974 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि सहकारी ऋण विन्यास की क्षमता में सुधार लाने के लिए असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू और काश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा पाकिस्तान में अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण विन्यासों में समन्वय होना चाहिए। इस दोनों ऋण विन्यासों का समन्वय किये जाने तक उन राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि वे अपने राज्यों में भूमि विकास बैंकों संबंधी विन्यास की वित्तीय और परिचालन संबंधी क्षमता में सुधार लाने के कुछ कदम उठावें। छोटे कृषकों को ऋण-सुविधा प्रदान करने के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि भूमि विकास बैंकों से संबंधित वर्तमान अधिनियम में संशोधन कर बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए अधिक प्रतिभूति की अपेक्षा को छोड़ दिया जाये। इसके साथ-साथ समिति ने भूमि विकास बैंकिंग के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों को सुदृढ़ बनाने, अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में अपेक्षित दीर्घकालीन कृषि ऋण की व्यवस्थाओं, भूमि विकास बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के समन्वय की व्यवस्थाओं, छोटे कृषकों के वित्तपोषण तथा भूमि विकास बैंकों के वित्तीय साधनों और ऐसे बैंकों में पायी जानेवाली अतिरिक्त राशियों के संबंध में भी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। साथ ही समिति ने बैंकों में प्रबंधक कर्मचारियों की भरती तथा प्रशिक्षण के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पूना में स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय तथा सहकारी प्रशिक्षण समिति के तत्वावधान में चलाये जानेवाले प्रशिक्षण केन्द्रों की वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं को विस्तारित करना आवश्यक होगा।

प्राथमिक स्तर पर विन्यास संबंधी परिवर्तन

250. एक संस्था द्वारा ऋण की व्यवस्था किये जाने तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि संबंधी मूल वस्तुओं और तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था किये जाने से संबंधित वर्तमान विचारधारा की प्रवृत्तियों के अनुरूप उद्योग और नागरिक पूँति के केन्द्रीय मंत्री श्री टी० ए० पी० के नेतृत्व में गठित एक उच्चस्तरीय दल ने इस बात पर बल दिया है कि छोटे/सीमांत कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी समितियों की सुनिश्चित नीति और कार्यक्रम के आधार पर सक्षम और सुव्यवस्थित बहु-उद्देशीय समितियाँ निर्मित की जाएँ। इस संदर्भ में उक्त दल का यह विचार था कि यद्यपि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सिफारिश की गयी कृषक सेवा समितियाँ उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रादर्श सिद्ध होंगी फिर भी वर्तमान अधिकांश समितियों के सम्मेलन से उत्पन्न होनेवाली जटिल संगठनात्मक समस्याओं तथा उनके परिणामस्वरूप उच्चस्तरीय प्रबंध क्षमता की आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त समितियाँ देश-भर में गठित नहीं जा सकतीं।

251. अतः उक्त दल ने यह सिफारिश की है कि बहु-उद्देशीय समितियों का पुनर्गठन करना तथा अंततः उन्हें कृषक सेवा समितियों के स्तर तक पहुँचाना ही लक्ष्य होना चाहिए। किन्तु कृषि ऋण समितियों के कार्य के अध्ययन से यह विदित हुआ कि इन समितियों के पुनर्गठन के कार्यक्रम पर कम ध्यान दिया गया था। अतः कृषि मंडल ने 24 दिसंबर, 1974 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर विचार किया। मंडल ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में प्राथमिक कृषि समितियों के पुनर्गठन के लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम तत्काल तैयार किया जाये और उसे सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार करवाया जाए। इस कार्यक्रम में पहले की तरह समितियों के परिमामान या सम्मेलन पर नहीं बल्कि ऐसी समितियों का पता लगाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिन्हें आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से बनाये रखने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि वे समितियाँ अपने अपने क्षेत्रों की और अधिक प्रभावकारी ढंग से सेवा कर सकें। अतः राज्य सरकारों

को सूचित किया गया है कि वे समितियों की संख्या का खंडवार सर्वेक्षण उनकी ऋण क्षमता के संदर्भ में करें तथा आगामी महीनों में समितियों के पुनर्गठन के लिए कार्यवाई की सम्पूर्ण रूपरेखा तैयार करें।

अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋण व्यवस्था का एकीकरण

252. ऋण विन्यास संबंधी जिस प्रमुख सुधार पर अब विचार किया जा रहा है वह यह है कि एक और दीर्घावधि ऋण की कम गुंजाइश और दूसरी और समन्वित विकास कार्यक्रम की आवश्यकता के संदर्भ में अंततः अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋण विन्यासों को समन्वित किया जाए। राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा बैंकिंग आयोग दोनों के अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋणों के समन्वयन का सुझाव दिया है। पैदल ने भी यह सिफारिश की है कि प्रारंभ में अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में इस प्रकार के प्रयास किये जाने चाहिए कि सहकारी विन्यास में एक सशक्त शाखर वित्तीय संस्था का स्वरूप प्रदान करने के लिए केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों में समन्वित कर दिया जाए। नागालैंड, दिल्ली तथा गोवा जैसे कुछ अपेक्षाकृत छोटे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जहाँ आजकल एकात्मक बैंकिंग विन्यास है, इस प्रकार के एकीकृत सहकारी बैंकिंग विन्यास का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है। कृषि ऋण मंडल ने 24 दिसम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर विचार किया था। उसका यह मत रहा कि जहाँ एक और छोटे राज्यों में सभी स्तर पर इस प्रकार के एकीकरण पर विचार किया जा सकता है वहाँ दूसरी और अन्य राज्यों में प्राथमिक स्तर पर एकीकरण पर विचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए मंडल ने यह सुझाव दिया है कि न केवल अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण बल्कि दीर्घावधि ऋण के वितरण के लिए भी सशक्त और सुदृढ़ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पता लगाया जाना चाहिए। उक्त मंडल ने सिफारिश की कि इन प्रस्तावों के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की जाँच की जाए। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के साथ विन्यास संबंधी परिवर्तनों से संबंधित उक्त दोनों विषयों पर विचार-विमर्श शुरू कर दिये हैं।

कमजोर क्षेत्रों को वित्त

253. आलोच्य वर्ष के दौरान छोटे कृषकों के लिए सहकारी बैंकों की ऋण नीतियों को सुस्पष्ट रूप से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये प्रयास जारी रहे। प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास राज्य सहकारी बैंक से उसके द्वारा लिये गये उधारों का कम से कम 20 प्रतिशत छोटे सीमांत/आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों का वित्तपोषण करने वाली समितियों के बकाया ऋणों के संदर्भ में होना चाहिए; रिजर्व बैंकों ने उपर्युक्त आशय का जो अनुदेश दिया था उसका पालन कराने के उद्देश्य से बैंक ने कुछ मामलों में स्वीकृत ऋण सीमा से बिना किसी प्रतिबंध के राशि ग्राहकित किये जाने के स्तर को 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया; कमजोर क्षेत्रों को देय अग्रिमों के संबंध में लगायी गयी शर्त का पूर्ण अनुपालन किये जाने पर ही शेष भाग का ग्राहण किया जा सकता है। 1975-76 से उक्त शर्त का अनुपालन कराने के उद्देश्य से संबंधित वर्ष के दौरान इस प्रकार के कृषकों के वित्तपोषण के लिए प्राथमिक ऋण समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा जारी किये गये नये ऋणों का आधार स्वीकार कर लिया गया है।

कृषक सेवा समितियाँ

254. पैदल की सिफारिशों से पहले ही राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव के अनुसार कृषक सेवा समितियों के गठन का प्रयोग प्रारंभ किया जा चुका था; 31 मार्च 1975 तक 69 समितियाँ लगभग 12 राज्यों में पंजीकृत की जा चुकी हैं; इनमें से 39 समितियाँ कर्नाटक में थीं।

69 समितियों में से 26 समितियों का वित्तपोषण वाणिज्य बैंकों द्वारा तथा अन्यो का वित्तपोषण सहकारी बैंकों द्वारा किया जाएगा। फिर भी कृषक सेवा समितियों के गठन की प्रगति काफी धीमी रही है। गठित समितियों के मामले में उस क्षेत्र में स्थित अन्य समितियों के भावी स्वरूप से संबंधित निर्णयों तथा समितियों के लिए प्रबंध और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था की अत्यावश्यक पूर्व-शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। इस कारण रिजर्व बैंक अभी तक उन समितियों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बावजूद दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से शेषर पूंजी संजूर नहीं कर सका है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को वित्त

255. अभी कुछ समय से कई राज्यों में विभिन्न वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के अलग-अलग व्यक्तियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समांतर सहकारी ऋण संस्थाओं या निगमों का गठन करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। किन्तु सरकार द्वारा प्रदत्त पर्याप्त शेषर पूंजी के साथ सहकारी संस्थाओं अथवा कंपनियों के रूप में पंजीकृत निगमों को निधियों के लिए मुख्य रूप से सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित हितयुक्त संस्थाओं विशेषकर सहकारी तथा वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए अलग अलग सहकारी समितियों का गठन करने के बदले उन्हें वर्तमान समितियों के सदस्यों के रूप में स्वीकार किये जाने के संबंध में अपने विचार से अवगत कराया। रिजर्व बैंक इन जातियों की सुविधा के लिए निगमों का गठन किये जाने के लिए सहमत था बशर्ते कि इस प्रकार की एजेंसियां विकासकार्य और/या विपणन कार्य करें और ऋण संबंधी किसी प्रकार के लेनदेन का कार्य न करें।

छोटे कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेंसी योजनाएं

256. अप्रैल 1975 के अंत तक 46 छोटे कृषक विकास एजेंसी तथा 41 सीमांत कृषक और कृषि श्रम एजेंसी परियोजनाओं की सुविधाओं के पात्र व्यक्तियों के रूप में 46.36 लाख छोटे कृषकों, सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का पता लगाया गया। इनमें से 23.70 लाख व्यक्तियों को सहकारी समितियों के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया। 1974-75 के दौरान (30 अप्रैल, 1975 तक) सहकारी समितियों और वाणिज्य बैंकों के माध्यम से इन सदस्यों को श्रमण: 28.33 करोड़ रुपये और 3.17 करोड़ रुपये के अत्यावधि ऋण वितरित किये गये। इनके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के आरंभ से अब तक उक्त सदस्यों को 72.26 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण तथा दीर्घावधि ऋण प्रदान किये जा चुके हैं। उसी अवधि के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 17.30 करोड़ रुपये के सीमांत ऋण प्रदान किये थे।

257. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रम को ऐसे 160 जिलों पर लागू किया जाएगा जहां वर्तमान परियोजनाएं श्रमण में हैं। प्रत्येक परियोजना एक राजस्व जिले तक सीमित रहेगी जिससे 50,000 लोग लाभान्वित होंगे। छोटे कृषक विकास एजेंसियों और सीमांत कृषक और कृषि श्रम एजेंसियों के बीच विद्यमान विभेद को दूर कर दिया गया है और भाग से उनके स्थान पर छोटे कृषक विकास एजेंसी कहलाने-वाली एक संयुक्त एजेंसी होगी। पांचवीं योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों के विकास पर अधिक जोर दिये जाने के कारण आशा है कि ये एजेंसियां इन वर्गों को परियोजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनायेंगी।

ऋण समितियों के लिए वाणिज्य बैंकों का वित्त

258. वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण किये जाने की जो योजना 1973-74 के अंत तक 8 राज्यों में कार्यरत थी उसे 1974 के खरीफ मौसम से और दो राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र और बिहार में लागू किया गया। इस प्रकार जून 1975 के अंत में यह योजना 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कार्यन्वित की जा रही थी। इस योजना की राजस्थान में भी लागू करने का प्रस्ताव है तथा क्षेत्रों के चुनाव और वाणिज्य बैंकों को समितियों के अंतरण के संबंध में क्रियाविधिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस योजना में बिहार तथा महाराष्ट्र को छोड़कर आठ राज्यों में 360 शाखाओं के माध्यम से 21 वाणिज्य बैंक सम्मिलित हुए थे—उक्त दो राज्यों के विषय में अभी तक विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर 2683 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर इस योजना को लागू किया गया जिनमें से 1666 समितियों को 1974 के खरीफ मौसम के लिए 1071.79 लाख रुपये तथा 1974-75 के खरीफ मौसम के लिए (31 मार्च, 1975 तक) 281.90 लाख रुपये के अत्यावधि ऋण प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त बैंक ने 305 समितियों को (31 मार्च, 1975 तक) कृषि निवेश के लिए 67.20 लाख रुपये का मध्यावधि ऋण वितरित किया था। योजना के आरंभ से लेकर अब तक वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने अधिकार में ली गयी समितियों में लगभग 1.79 लाख नये सदस्यों को शामिल किया गया। इससे कुल सदस्यों की संख्या विसम्बर 1974 के अंत तक बढ़कर 5.15 लाख हो गयी। यदि सभी राज्यों को एक साथ लिया जाये तो प्रति समिति सदस्य संख्या में औसत वृद्धि 88 रही। किन्तु ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या केवल 2.34 लाख थी जो कुल सदस्यों का 45 प्रतिशत थी।

259. किन्तु समितियों को प्रदान किये गये ऋणों के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों के वसूली कार्यक्रम में सीमांत वृद्धि पायी गयी अर्थात् 1973-74 के दौरान वसूलियां मांग का 58 प्रतिशत थी जबकि 1972-73 के दौरान 56 प्रतिशत थी।

260. सहकारी समितियों द्वारा तथा अलग-अलग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने में वाणिज्य बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका तथा वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों द्वारा अपनायी गयी नीतियों तथा क्रियाविधियों में समन्वय और एकरूपता लाने की आवश्यकता के संदर्भ में रिजर्व बैंक के कृषि ऋण मंडल ने "कृषि के वित्तपोषण में सहकारी तथा वाणिज्य बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में स्थायी समिति" का गठन किया। पै की अध्यक्षता में गठित दल ने ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की भूमिका की भी जांच की। उक्त दल के संबंध में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। उक्त दल को यह विवित हुआ है कि वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के परिचालन व्यय तथा संगठन संबंधी कमियों के वर्तमान स्तर को देखते हुए उनके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे बहु-उद्देश्यीय कृषि ऋण समिति जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं की सहायता के बिना कृषकों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर सकें। अतः दल ने यह सिफारिश की है कि वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे मंडी स्तर के नीचे ग्रामीण शाखाएं खोलने का निश्चय करने से पूर्व स्थिति का सावधानी से मूल्यांकन करें। उनका प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि उस क्षेत्र में सक्षम बहु-उद्देश्यीय समितियों या इस प्रकार की सक्षम समितियों के समूह का पता लगाया जाये या उनका गठन किया जाये। ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्य कर सकते हैं तथा वाणिज्य

बैंक ऋण संबंधी खाई की पूर्ति कर सकते हैं। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक को राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की व्यवस्था तथा भावी अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए। कार्य के इस पहलू पर कार्यवाही की जा रही है।

कमजोर सहकारी बैंकों का पुनर्गठन

261. 30 जून, 1974 को विद्यमान वित्तीय स्थिति के आधार पर महाराष्ट्र के 2 बैंकों तथा राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के एक-एक बैंक के अलावा जो अपनी परिचालन संबंधी कमजोरियों के कारण पुनर्गठन के अन्तर्गत विद्यमान थे, 16 राज्यों में 144 केन्द्रीय सहकारी बैंक पुनर्गठन के कार्यक्रम के अन्तर्गत थे। इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा दिल्ली के 4 ऐसे राज्य सहकारी बैंकों को भी जो द्विस्तरीय ऋण विन्यासवाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं, पुनर्गठन के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उनके पुनर्गठन के लिये उचित कदम उठावें।

262. केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने 7 राज्यों में 71 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके प्रशोध्य और संविन ऋणों, संविन हानि तथा तीन वर्षों से अधिक अवधि की अन्य अतिवैय राशियों को बढ़े छाते लिख देने के लिए 237.89 लाख रुपयों की सहायता प्रदान करना स्वीकार किया। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 30 जून, 1975 तक संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से सहायता के अपने अंश के रूप में 161.98 लाख रुपयों की राशि प्रदान की। मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंकों को केन्द्रीय सहायता के लिये अनुमोदित किया गया है तथा इन बैंकों को भारत सरकार ने 30 जून, 1975 तक 4.40 लाख रुपये प्रदान किये हैं।

263. 1974-75 के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि विकास बैंकों/केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं के पुनर्गठन का कार्यक्रम जारी रहा। 30 जून, 1973 को विद्यमान वित्तीय स्थिति के आधार पर 28 प्राथमिक सहकारी बैंक, 92 प्राथमिक भूमि विकास बैंक तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की 18 शाखाएं पुनर्गठन कार्यक्रम में सम्मिलित की गयी थीं।

क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना

264. जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, श्रेणी 'ग' के राज्यों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने एक नयी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत उन बैंकों की अतिवैय राशियों को समाप्त करने के लिए अपेक्षित उनके वित्तीय साधनों में प्रत्याशित घाटों की पूर्ति की जाएगी। राज्य सहकारी बैंकों को मीयादी ऋण के रूप में सहायता दी जाएगी जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का समान अंश होगा; राज्य सहकारी बैंक उक्त सहायता राशि का प्रयोग निविष्ट केन्द्रीय सहकारी बैंकों के आंतरिक साधनों को बढ़ाने के लिये करेंगे। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने 14 करोड़ रुपयों के परिचय की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी है तथा संबंधित राज्य सरकारें समान राशि की व्यवस्था करेंगी। इस योजना के अन्तर्गत ऋण 9 वर्षों की अवधि के लिये दिये जाएंगे। इनमें से पहले तीन वर्षों तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकारों को प्रदान किये जाने वाले ऋणों के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर निर्धारित ब्याज की दर इन ऋणों पर भी लागू होगी तथा उसी दर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उक्त राशि प्रदान की जायेगी।

265. 1974-75 के वित्तीय वर्ष से उक्त योजना की कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 6 राज्यों में 18 बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 75 लाख रुपये वितरित किये।

कमजोर शहरी बैंकों का विकास

266. हाल ही के वर्षों में कई छोटे शहरी सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। देश में प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 1 मार्च, 1966 को 403 थी जब बैंककारी विनियमन अधिनियम को सहकारी समितियों पर भी लागू किया गया था और उनकी संख्या सितम्बर, 1974 के अंत तक बढ़कर 877 हो गयी है। इनमें से 718 अर्थात् लगभग 82 प्रतिशत प्राथमिक सहकारी बैंक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में थे। 1966 तथा 1974 के बीच स्थापित नये बैंकों में से केवल 48 बैंकों को रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्रदान किया। शेष बैंक (426) प्राथमिक ऋण समितियों की श्रेणी के थे। उक्त समितियां पहले 1 लाख रुपयों के कम शेयर पूंजी के साथ गठित और पंजीकृत की गयी थी, किन्तु जब उनकी शेयर पूंजी एक लाख रुपये या अधिक हो गयी तब वे अपने आप प्राथमिक सहकारी बैंक हो गये। बाद में देखा गया कि इस प्रकार के अनेक बैंक प्रमुखतः अपर्याप्त वित्तीय साधनों तथा अक्षम प्रबंधन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम के अत्यावश्यक उपबंधों तक का अनुपालन करने में असमर्थ थे। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये कुछ अध्ययनों से विदित हुआ कि समितियों की शेयर पूंजी के स्तर को जान बूझकर एक लाख रुपयों से कुछ कम रखकर उन्हें पंजीकृत किया जाता था ताकि रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना वे अपना बैंकिंग कारोबार शुरू कर सकें। इन परिस्थितियों में इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ करना आवश्यक समझा गया जिससे पंजीयन के समय ही शहरी सहकारी बैंकों के अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके। चूंकि शहरी सहकारी बैंकों का पंजीयन सहकारी समितियों के पंजीयन का सांख्यिक उत्तरदायित्व है, अतः रिजर्व बैंक ने सभी पंजीयकों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह सूचित किया गया था कि वे तब तक राज्य के किसी भाग के शहरी बैंक को पंजीकृत न करें जब तक कि उसके द्वारा एकत्रित प्रारंभिक शेयर पूंजी कम से कम एक लाख रुपये न हो। इस सूचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नये बैंक रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना बैंकिंग कारोबार शुरू न करें; लाइसेंस जारी करते समय संबंधित क्षेत्र की बैंकिंग-आवश्यकताओं तथा आवश्यक बैंक की समक्ष यूनिट करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने वर्तमान बैंकों को सक्षम संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कदम उठाते हुए भारत सरकार से यह सिफारिश की कि बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1965 के वर्तमान उपबंधों में ऐसे संशोधन किये जाने चाहिए जिनके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हों :-

- (क) बैंकिंग कारोबार शुरू करने या चलाने के हद्द तक सभी सहकारी बैंकों के पास 3 लाख रुपयों से अन्यून शेयर पूंजी तथा प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए।
- (ख) बैंकिंग कारोबार चलाने की हद्द तक कोई भी सहकारी समिति रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही कारोबार प्रारंभ कर सकती है या चला सकती है।
- (ग) भविष्य में प्राथमिक ऋण समितियां जनता से जमा-राशियां स्वीकार कर सकती हैं जो बैंक द्वारा ग्राहणीय न हों। वे अपनी स्वाधिकृत निधियों की दुगुनी राशि या 6 लाख रुपयों में से जो भी कम हो, उस सीमा तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं; किन्तु उन समितियों को अपने नामों में बैंक, बैंकर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

267. भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं तथा विभिन्न अधिनियमों को संशोधित करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

निम्नलिखित से संबंधित अध्ययन दल

268. (i) प्रतिवेद्य राशियाँ

प्रतिवेद्य राशियों के संबंध में गठित अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बैंकों के पास प्रेषित किया गया है। इन सिफारिशों पर अगस्त, 1974 में नयी दिल्ली में हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में तथा सितम्बर, 1974 में पूना में हुई राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की विचारगोष्ठी में चर्चा की गयी तथा उनमें भाग लेने वालों को उन सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता से अवगत कराया गया। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही पर सावधानी से ध्यान दिया जा रहा है।

269. (ii) कृषि ऋण संस्थाएं—महाराष्ट्र

24 मार्च, 1975 को प्रस्तुत की गयी अध्ययन दल की अंतिम रिपोर्ट में मार्च, 1973 में प्रस्तुत की गयी अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये की गयी कार्यवाहियों की समीक्षा की गयी तथा उनमें अन्य निम्नलिखित विचारणीय विषयों पर ध्यान दिया गया। यथासंभव अधिकतम सीमा तक ऋण की खाई को पाटने के लिये सांस्थानिक ऋण की व्यवस्थाएं, विशेषरूप से बीनी कारखानों तथा कताई मिलों जैसे बड़े अभिसंस्करण यूनिटों के वित्तपोषण के संदर्भ में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण नीतियां, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन तथा उनके प्रबंध और पर्यवेक्षण की व्यवस्थाएं।

270. उक्त रिपोर्ट से निम्नलिखित कतिपय महत्वपूर्ण तत्व प्रकाश में आए हैं :

(1) अध्ययन दल ने यह अनुमान लगाया था कि महाराष्ट्र राज्य के लिये 1978-79 में समग्र रूप से कुल 450 करोड़ रुपये के अत्यावधि कृषि ऋण की आवश्यकता होगी ; उसमें से सहकारी संस्थाएं लगभग 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकेंगी। दल ने यह अनुभव किया कि यदि वाणिज्य बैंक ऐसे क्षेत्रों में, जहां काफी अधिक मात्रा में ऋण की खाई विद्यमान है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण प्रदान करने का कार्य संभाले तो 200 करोड़ रुपये की खाई को कुछ सीमा तक पूरा किया जा सकता है। दल ने वाणिज्य बैंकों से यह भी अपेक्षा की कि राज्य के शेष भागों में वे सीधे कृषकों को ही अधिक मात्रा में ऋण सुविधाएं प्रदान करें। (2) अभिसंस्करण यूनिटों विशेष रूप से बीनी कारखानों में मांग और मियादी देयताओं के लगभग 60 प्रतिशत का जो निवेश किया गया है उसे देखते हुए उक्त दल ने राज्य सहकारी बैंक के लिए यह अनुपयुक्त समझा है कि वे राज्य में स्थित बीनी के सभी सहकारी कारखानों की थोक और कार्यकारी पूंजी की आनश्यकताओं को पूरा करने का भार उठाएँ तथा दल ने यह सुझाव दिया है कि बैंक को चाहिए कि वह कुछ समय के लिये और अधिक मात्रा में दीर्घावधि ऋण और अधिम, विशेषकर बीनी कारखानों को प्रदान करता बंद कर दे; (3) प्राथमिक ऋण विन्यास के पुनर्गठन के मामले में दल ने यह सिफारिश की है कि महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वह सक्षमता और संभाव्य क्षमता के आधार पर प्राथमिक समितियों के पुनर्गठन का कार्य संभाले तथा ऐसी प्रत्येक समिति के लिए एक स्वतंत्र योग्यता प्राप्त तथा पूर्णकालिक वित्तनिक सचिव नियुक्त करे। दल ने यह सुझाव दिया है कि पुनर्गठन का यह कार्य 30 जून, 1977 तक समाप्त हो जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक ने दल की इन सिफारिशों को कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है तथा इन सिफारिशों को स्वीकार करने तथा शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार तथा सहकारी और वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है।

271. (iii) कृषि ऋण संस्थाएं—राजस्थान

राजस्थान की कृषि ऋण संस्थाओं के संबंध में गठित अध्ययन दल ने रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट मई 1975 में प्रस्तुत की है। दल ने राज्य के 23 केन्द्रीय बैंकों में से 10 बैंकों को अक्षम तथा क्षमता की संभावना विहीन देखा, क्योंकि उनके बकाया ऋण न्यून थे। दल ने यह अनुभव किया कि यदि बकाया ऋण की राशि 150 लाख रुपये से अधिक हो तो केन्द्रीय बैंक को सक्षम माना जा सकता है तथा 100 लाख रुपये से अधिक हो तो सक्षम होने की संभावनायुक्त माना जा सकता है। दल ने यह देखा कि इन बैंकों के क्षेत्र में ऐसी क्षमता है कि उनका कारोबार 150 लाख रुपये तक पहुँचे और वहाँ ऐसी क्षमता भी है कि जमाराशियाँ ऐसे स्तर पर पहुँचें जिनसे ऋण संबंधी लेन-देनों की 150 लाख रुपये या 100 लाख रुपये तक रखा जा सके। इस आधार पर राज्य के 10 अक्षम बैंकों में से 2 बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में सम्मिलित कर देने की सिफारिश की गयी है। शेष बैंकों के मामले में दल ने यह सिफारिश की कि 1978-79 में राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करे। दल ने अन्य 8 केन्द्रीय बैंकों के मामले में भी, यदि उनके कारोबार का स्तर उस वर्ष 200 लाख रुपये तक पहुँच नहीं पायें तो इसी प्रकार स्थिति की समीक्षा करने की सिफारिश की। दल ने क्षमता के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक व्यापक क्षेत्र की व्यवस्था कर प्राथमिक ऋण विन्यास का पुनर्गठन करने की भी सिफारिश की, किन्तु शर्त यह थी कि इस प्रकार की समिति की 2 लाख रुपये के ऋण संबंधी लेन-देन करने की क्षमता हो तथा पूर्णकालिक वित्तनिक सचिव हो। दल ने चार कृषक सेवा समितियों और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार की चालीस समितियों का गठन करने तथा जून 1978 तक पुनर्गठन कार्य को समाप्त कर देने की सिफारिश की है। जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपर्युक्त सिफारिश दल की इस धारणा का परिणाम थी कि जनजातीय क्षेत्र में स्थित सहकारी समिति न केवल कृषि के लिए बल्कि शरू आवश्यक्तताओं तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए भी मीयादी ऋण प्रदान करे तथा ऋण को कृषि के काम आने वाली मूल वस्तुओं, तकनीकी मार्गदर्शन तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के साथ समन्वित किया जाए। उक्त दल ने प्राथमिक समितियों के ऋणस्तर कारोबार का समन्वयन करने और उसकी सहायता करने के निमित्त एक जनजातीय विकास निगम का गठन करने और जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में जनजातियों के विकास से संबंधित परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के निमित्त एक जनजातीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कृषकों को बकरी पालन से अपनी आय में स्थिरता लाने और उसे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। दल ने यह सिफारिश की है कि बकरियाँ खरीदने के लिए सहकारी समितियों द्वारा मध्यावधि ऋण प्रदान किए जाएँ और उन तथा मांस के विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ की जाएँ। दल की यह धारणा है कि इस राज्य में 1978-79 के अंत तक कृषि के लिए अपेक्षित अत्यावधि ऋण की राशि 200 करोड़ रुपए होगी और यह प्रत्याशा है कि सहकारी समितियाँ इसमें से 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकेंगी। दल ने यह महसूस किया कि राज्य में स्थित वाणिज्य बैंक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से 25 करोड़ रुपये तक के ऋण और प्रत्यक्ष वित्त के रूप में 10 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में 70 करोड़ रुपये की खाई को पाटना होगा।

272. (iv) कृषि ऋण संस्थाएं—बिहार

अप्रैल 1974 में हुई अपनी पहली बैठक में अध्ययन दल ने आंकड़े संकलित करने के निमित्त विभिन्न प्रपत्रों को अंतिम रूप दिया। विशिष्ट विचारणीय विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कतिपय अध्ययन शुरू करने का भी दल ने निश्चय किया था। आंकड़ों के संकलन और अध्ययनों का कार्य जारी है।

273. रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में कृषि ऋण संबंधी संस्थागत व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया जाए। इस उद्देश्य के लिए दो अलग अध्ययन दल गठित किये जा रहे हैं।

सहकारी बैंककारी विनियमन

274. आलोच्य वर्ष के दौरान एक केन्द्रीय सहकारी बैंक और 12 प्राथमिक सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान कर उन्हें भारत में बैंकिंग कारोबार करने का प्राधिकार दिया गया है। इससे लाइसेंसीकृत सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1975 के अंत में 73 हो गयी जबकि पिछले वर्ष उक्त संख्या 60 थी। सहकारी बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या 30 सितम्बर 1973 को 6102 थी वह 31 मार्च 1974 को बढ़कर 6,209 (राज्य सहकारी बैंकों के 239 कार्यालय, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 4759 कार्यालय, और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के 1211 कार्यालय) हो गयी। 1 जुलाई 1974 से 30 जून 1975 तक की अवधि के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को नये कार्यालय खोलने के लिए 59 लाइसेंस प्रदान किये गये जब कि पिछले वर्ष 76 लाइसेंस प्रदान किये गये थे। 1 जुलाई 1974 से 30 जून 1975 तक 752 सहकारी बैंकों का (20 राज्य सहकारी बैंक, 212 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 510 शहरी सहकारी बैंक, 5 राज्य भूमि विकास बैंक, 5 शिक्षर बुनकर विपणन समितियाँ) निरीक्षण किया गया। इनमें से 100 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का निरीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(1) के अंतर्गत रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सहकारी बैंकों के अधिकारियों ने किया। 16 राज्य सहकारी बैंकों, 192 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 472 प्राथमिक सहकारी बैंकों, 14 राज्य भूमि विकास बैंकों और 4 शिक्षर बुनकर विपणन समितियों के निरीक्षण की रिपोर्टें उक्त अवधि के दौरान जारी की गयीं। 30 जून 1975 को 1494 सहकारी बैंक (28 राज्य, 368 केन्द्रीय और 1098 प्राथमिक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आये जबकि इस वर्ष के आरंभ में ऐसे सहकारी बैंकों की संख्या 1432 थी।

275. सात केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 11(1) के उपबंधों की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया। इनमें से 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक असम में स्थित थे और असम राज्य सरकार ने उन्हें तथा अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों को असम शिक्षर सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ विलयित करने का निर्णय किया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 11 के उपबंधों का पालन न करने वाले 26 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से दो बैंक परिसमापनाधीन थे। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली पर निगरानी रखी जा रही है।

जमा बीमा योजना

276. 1974-75 के दौरान पांडिचेरि के संघशासित क्षेत्र और केरल राज्य में स्थित सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 1 अक्टूबर 1974 और 1 अप्रैल 1975 से जमा बीमा योजना लागू कर दी गयी है।

जून 1975 के अंत तक जमा बीमा निगम द्वारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और काश्मीर और केरल राज्यों तथा गोवा, दमन और दीव, विल्ली तथा पांडिचेरि के संघशासित क्षेत्रों में 513 सहकारी बैंक पंजीकृत किये गये जबकि इस वर्ष के आरंभ में पंजीकृत सहकारी बैंकों की संख्या 423 थी। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और त्रिपुरा ने अपने सहकारी समिति अधिनियमों में आवश्यक संशोधन पारित कर अधिक्रमण, परिसमापन, सम्मेलन, पुनर्गठन आदि के संबंध में रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान किये हैं। यह आशा की जाती है कि इन राज्यों में भी उक्त योजना लागू की जाएगी। शेष राज्य सरकारों से उनके सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किये जाने की बात पर विचार-विमर्श हो रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र में स्थित सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना लागू की जा सके।

कृषि पुनर्वित्त निगम

कार्यकलाप

277. आलोच्य वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त निगम ने 106.4 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया जबकि 1973-74 के दौरान 97.8 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया था। निगम की स्थापना से लेकर जून 1975 के अंत तक कुल 423 करोड़ रुपये वितरित किये गये। आलोच्य वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं के अंतर्गत 61.8 करोड़ रुपये वितरित किये गये। इन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 187 करोड़ रुपये वितरित किये गये। इसके फलस्वरूप देश में लगभग 1450 लाख डालर की विदेशी मुद्रा का आगमन हुआ।

278. इस वर्ष के दौरान निगम ने 236 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता युक्त 623 योजनाएं संभूरी कीं। इस राशि में से निगम द्वारा किये गये वायदे की राशि 204 करोड़ रुपये थी। पुनर्वित्त का प्रमुख उद्देश्य पहले की तरह लघु सिंचाई योजना रहा; इस प्रकार की 312 योजनाएं (50 प्रतिशत) विद्यमान थीं। इन योजनाओं के संदर्भ में निगम के वायदे की राशि 151 करोड़ रुपये या कुल वायदा राशि का 74 प्रतिशत थी। साथ ही विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों में अधिकाधिक निवेश किये जाते रहे। आलोच्य वर्ष के दौरान लघु सिंचाई से भिन्न उद्देश्यों के लिये स्वीकृत योजनाओं की संख्या 311 थी और उनमें निगम के वायदे की राशि 53 करोड़ रुपये थी। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से डेरी विकास, भूमि संरक्षण, खेती के मशीनीकरण, बागान तथा बाग-बानी, मुर्गीपालन, बकरी पालन, मत्स्यपालन विकास तथा भण्डारण और बाजार केन्द्र की योजनाएं शामिल हैं। संज्ञानात्मक रूप से निगम ने आंध्र प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में तीन नए विकास परियोजनाओं को भी अनुमोदित किया है। वाणिज्य बैंक इन परियोजनाओं का वित्त-पोषण करेंगे।

279. निगम की स्थापना से लेकर अब तक कुल वितरण के 10 प्रतिशत से अधिक राशि उत्तर प्रदेश (58 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (50 करोड़ रुपये), गुजरात (48 करोड़ रुपये) तथा महाराष्ट्र (46 करोड़ रुपये) ने ली। चार अन्य राज्यों अर्थात् हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश (प्रत्येक 42 करोड़ रुपये), पंजाब (38 करोड़ रुपये) तथा कर्नाटक (35 करोड़ रुपये) ने कुल वितरण के 8 से 10 प्रतिशत तक की राशि ली। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उत्तरी, पूर्वी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में अधिक वितरण किये गये। किन्तु पूर्वोत्तर, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में वितरण में गिरावट परिलक्षित हुई। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में स्थित उद्योगों की प्रवृत्ति जारी रही। पिछले वर्ष की तरह निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने के संदर्भ में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश अग्रणी था।

क्षेत्रीय असन्तुलनों में लायी गयी कमी

280. निगम ने कम विकसित/कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किये, उनके अष्टोपरिणाम अब नजर आने लगे हैं। इस वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने पश्चिम बंगाल के छः जिलों से संबंधित ग्रामीण विकास परियोजना को अनुमोदित किया। राजस्थान में अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त चार परियोजनाएं प्रमल में हैं; किसी एक राज्य में प्रमल में रहने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के संदर्भ में यह संख्या अधिकतम है। ये परियोजनाएं लघु सिंचाई से भिन्न अन्य कार्यों से संबंधित हैं और लघु सिंचाई से संबंधित निवेश के लिए निगम से अब सक्रिय सहायता प्राप्त होने से राजस्थान राज्य में विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी है। उड़ीसा में इस वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त निगम के पुनर्वित्त के साथ मंजूर की गयी योजनाओं की राशि 17 करोड़ रुपये थी और ये योजनाएं विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। जम्मू और कश्मीर में निगम ने यह निश्चय किया है कि वह बागबानी के विकास संबंधी योजना तैयार करने में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और राज्य सरकार को सहयोग देगा। जून 1975 के अंत में निगम द्वारा कम विकसित/कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों में मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या 703 थी और उनके संबंध में वित्तीय सहायता की राशि 407.13 करोड़ रुपये थी जिसमें से निगम ने 360.29 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान करने का वायदा किया है। यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो निगम द्वारा इन क्षेत्रों में मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या मंजूर की गयी कुल योजनाओं की एक तिहाई थी। निगम ने अब तक कम विकसित/कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों में 117.35 करोड़ रुपये वितरित किये हैं जो निगम द्वारा किये गये कुल वितरणों का 27.7 प्रतिशत था।

281. अंशतः निगम द्वारा किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की कृषिपर राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बागान योजनाओं का प्रवर्तन करने के लिए बागान विकास निगमों और वन के विभिन्न स्रोतों का समुचित उपयोग करने के लिए वन विकास निगमों का गठन करने की विधा में कदम उठाये हैं।

282. निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्र कृषि में बहुत अधिक निवेश किये जाने के लिए जो प्रयास किये गये उन्हें सक्रियतापूर्वक बढ़ाया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागबानी, बागान और वन के विकास का निवेश-पूर्व अध्ययन करने के लिए निगम के अधिकारियों के साथ एक बल गठित किया गया ताकि विभिन्न एजेंसियों को उक्त क्षेत्र में बैंकों द्वारा निवेश किये जाने योग्य ठोस प्रस्ताव बनाने में सहायता मिल सके। अप्रैल 1975 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में उक्त बल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जहां बागबानी और वाणान संबंधी फसलों के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी गुंजाइश है वहां उन राज्यों में उनकी वास्तविक प्रगति अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करेगी कि किसरी शीघ्रता से अपेक्षित संगठन का निर्माण होता है। बागबानी के संबंध में बल ने इस क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्रीय प्रतिष्ठान के रूप में बागबानी विकास और अभिसंस्करण कंपनी की स्थापना करने का सुझाव दिया है ताकि अच्छी किस्म के उत्पादन और लाभप्रद विपणन के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा सकें। चाय के बागानों के लिए बल ने यह सिफारिश की है कि कमजोर बागों के पुनर्गठन के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के निमित्त कृषि पुनर्वित्त निगम में एक आवर्ती निधि का निर्माण किया जाए।

283. तकनीकी परामर्शदाताओं की एक फर्म ने निगम की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुअर-विकास का एक निवेश-पूर्व अध्ययन किया। परामर्श-दाताओं की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा

चार राज्यों, अर्थात् असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में क्षेत्रीय अध्ययन किये गये। इन अध्ययनों के आधार पर नागालैंड और मणिपुर राज्यों के लिए समेकित सुअर विकास के ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं और इन प्रस्तावों को वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

छोटे कृषक विकास एजेंसी योजनाएं

284. जून 1975 के अंत में छोटे कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रम एजेंसियों के तत्वावधान में निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की कुल संख्या 104 थी और इस संबंध में निगम के वायदे की राशि 43.6 करोड़ रुपये थी; इन योजनाओं के अंतर्गत निगम द्वारा सबसे बैंकों को वितरित की गयी कुल राशि 13 करोड़ रुपये थी। इन एजेंसियों के तत्वावधान में प्रवर्तित योजनाओं के लिए उपलब्ध 100 प्रतिशत पुनर्वित्त की रियायती सुविधा की अवधि को 31 दिसंबर 1975 तक बढ़ा दिया गया है।

एजेंसी द्वारा पुनर्वित्त का वितरण

285. भूमि विकास बैंक पिछले वर्ष की तरह निगम से अधिकांश पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करते रहे। 1974-75 के दौरान 106.4 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त का जो वितरण किया गया उसमें भूमि विकास बैंकों का अंश 77 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष के लगभग 78 करोड़ रुपयों के वितरण से सीमांत रूप से कम था। परंतु निगम द्वारा किये गये कुल वितरणों में भूमि विकास बैंकों का अंश पिछले वर्ष के 79 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष 72 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत वाणिज्य बैंकों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 28 करोड़ रुपयों की राशि का जो पुनर्वित्त प्राप्त किया वह इसके पूर्व के सभी वर्षों के दौरान उनके द्वारा ली गयी कुल राशि के लगभग समान थी। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा लिये गये पुनर्वित्त की राशि में कमी पायी गयी और उक्त राशि 1.5 करोड़ रुपये थी। ये संस्थायें कृषि उद्देश्यों के लिए अपेक्षित मध्यावधि ऋणों के लिए प्रमुख रूप से भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भर करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनाएं

286. आलोच्य वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने चार विशिष्ट परियोजनाओं अर्थात् राजस्थान डेरी विकास परियोजना, मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना, मध्य प्रदेश चंबल घाटी क्षेत्र विकास परियोजना और पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की। निगम ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से अपनी ऋण परियोजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली; उक्त ऋण परियोजना से निगम के ऋण संबंधी कार्यक्रम को सहायता होती है।

287. कृषि पुनर्वित्त निगम की ऋण परियोजना के अंतर्गत अप्रैल 1975 में जो करार हस्ताक्षरित हुए उनके अधीन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने द्विवर्षीय कृषि ऋण कार्यक्रम के लिए 740 लाख डालर का ऋण प्रावर्तित किया है। इससे लघु सिंचाई से संबंधित निवेशों और दूसरे विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के लिए निगम को सहायता मिली है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं और परियोजनागत ऋणों से संबंधित अन्य एजेंसियों के प्रवर और मध्य स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण, भूमि विकास बैंकों के अवर स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए और अल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के विलयन की संभावना का अध्ययन करने के लिए 10 लाख डालर की राशि भी प्रदान की गयी है।

288. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ राज्यों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ उनका भ्रमण से मूल्यांकन करता है और उनके लिए मंजूरी देता है; इसके विपरीत कृषि पुनर्वित्त निगम की ऋण परियोजनाओं में काफी लचीलेपन की गुंजायश है। यह प्रमुख रूप से कृषि पुनर्वित्त निगम की जिम्मेदारी होगी कि वह परियोजनाओं का पता लगाये, निधियों का बायबा करे और परियोजना की प्रगति के अनुरूप वितरण करे। जिन क्षेत्रों में निवेशों की आवश्यकता और उपयुक्त माना जाए उन क्षेत्रों में कृषि पुनर्वित्त निगम अपने विवेकानुसार निधियों का वितरण करेगा। इसके परिणामस्वरूप जिन क्षेत्रों और उद्देश्यों के लिए अब तक भ्रमण ऋण मंजूर नहीं किये गये हैं उनके लिए निगम निवेश राशि प्रदान कर सकेगा। जिन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की विशिष्ट परियोजनाएं उसी उद्देश्य के लिए कार्यन्वित की जा रही हैं उन क्षेत्रों में पहले प्रदान किये गये ऋणों का पूरी तरह से उपयोग किये जाने के बाद कृषि पुनर्वित्त निगम अपने निवेशों को जारी रख सकेगा।

289. इस ऋण की प्रमुख विशेषता यह है कि छोटे कृषकों के हितों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। लघु सिंचाई और विभिन्न प्रकार के दूसरे निवेशों के लिए प्रदान किये जाने वाले ऋणों का लगभग 50 प्रतिशत अंश अर्थात् 370 लाख डालर छोटे कृषकों के लिए नियत किये गये हैं। छोटे कृषकों की परिभाषा को वर्तमान परिभाषा की अपेक्षा अधिक उदार बना दिया गया है। 1972 के मूल्यांकन के आधार पर जिन कृषकों की विकास-पूर्व शुद्ध आय 2000 रुपये से अधिक न हो उन्हें अब छोटे कृषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जिस राज्य में भूमि स्थित हो वहां के कृषि श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक के अनुरूप मूल्यांकन में बाय में होने वाले किसी परिवर्तन के अनुसार उक्त सीमा को समायोजित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की इसके पहले की ऋण परियोजनाओं में छोटे कृषक की परिभाषा यह थी कि सभी स्त्रियों से उसकी विकासोत्तर आय वार्षिक 2400 रुपये से अधिक न हो और यदि निवेश की लागत 10,000 रुपये से अधिक हो तो तत्काल नकदी प्रवायगी और अधिक पुर्गाई अवधि की सुविधा उपलब्ध नहीं करानी थी। कृषि पुनर्वित्त निगम की ऋण परियोजना के अंतर्गत छोटे कृषकों को ऋण दिये जाने के लिए निवेश व्यय की कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी। छोटे कृषक के अपने निवेश (जिनमें उसके द्वारा भूमि विकास बैंकों के शेयरों की भविष्य की खरीद नकदी में या वस्तुओं के रूप में संग्रहण शामिल है) की राशि निवेश व्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित है। दूसरे कृषकों को निवेश व्यय अधिक न करना पड़े; अतः छोटे कृषकों सहित सभी कृषकों को तीन वर्गों में रखा गया है: (1) छोटे कृषक जिनकी विकास-पूर्व शुद्ध आय ₹० 2000 से अधिक न हो; (2) ऐसे कृषक जिनकी शुद्ध आय ₹० 2001 और ₹० 3500 के बीच में हो (3) दूसरे ऐसे कृषक जिनकी शुद्ध आय ₹० 3501 और अधिक हो। निवेश व्यय में उनका निजी योगदान क्रमिक रूप से 5,10 और 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

290. कृषि पुनर्वित्त निगम की ऋण परियोजना के अलावा निगम ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ 21 ऋण योजनाओं के लिए बातचीत की है। उनमें से 11 योजनाएं लघु सिंचाई और खेती के मशीनीकरण, 3 योजनाएं व्यापक क्षेत्र विकास, 2 योजनाएं बाजार केन्द्रों, एक योजना बीज उत्पादन, 3 योजनाएं डेरी विकास और एक योजना सेवा भविसंस्करण तथा विपणन से संबंधित थीं; निगम की ऋण परियोजना सहित विषय बैंक समूह द्वारा बायबा की गयी राशि 401.5 करोड़ रुपये थी और उसमें से निगम ने 117 करोड़ रुपये लिये हैं।

291. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की कुछ और परियोजनाएं तैयार हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का एक मिशन मई 1975 में समेकित यह विकास परियोजना के संबंध में आंकड़ों की प्रशस्त बनाने के लिए भारत आया। देश में वृक्षों तथा समुद्री मछली विकास में निवेशों की बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए भारत सरकार के अनुरोध पर विषय बैंक/बाय और कृषि संगठन के दो सर्वेक्षण मिशन भारत आये। इनके अलावा मध्य प्रदेश में एक वन विकास परियोजना, जम्मू और काश्मीर में बागवानी की परियोजना और एक अखिल भारतीय बीज परियोजना के संबंध में परियोजना तैयार करने वाले मिशन भी भारत आये।

प्रमुख निर्णय

292. निगम ने जुलाई 1974 में बैंक दर में वृद्धि किये जाने के कारण व्याज दर विन्यास में सामान्य वृद्धि हो जाने से व्याज दरों की स्थिति की समीक्षा की। यह निश्चय किया गया कि 13 अगस्त 1974 को या उसके पहले मंजूर की गयी सभी योजनाओं के संबंध में योग्य संस्थाओं के लिए निगम के पुनर्वित्त की व्याज दर लघु सिंचाई और भूमि विकास की योजनाओं के संबंध में वार्षिक 7½ प्रतिशत तथा दूसरी योजनाओं के संबंध में वार्षिक 8 प्रतिशत होगी। सदस्य बैंकों द्वारा प्रतिम ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋण की व्याज दरें लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं के संबंध में वार्षिक 10½ प्रतिशत और दूसरी योजनाओं के संबंध में वार्षिक 11 प्रतिशत होगी। छोटे किसानों के मामले में विशेष रूप से मुर्गीपालन, डेरी और पशुपालन की योजनाओं के संबंध में यदि बैंक चाहें तो वार्षिक 10½ प्रतिशत की दर पर व्याज ले सकते हैं।

293. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 22(4) में किये गये संशोधन का उल्लेख किया गया था जिसके अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पात्र संस्थाओं को प्रवर्त पुनर्वित्त के संबंध में प्रत्येक मामले की परिस्थिति के आधार पर अपेक्षित 'सरकारी गारंटी' तथा 'अन्य जमानत' दोनों से छूट प्रदान करे। इसके लिए लिखित रूप से कारण दर्ज करने होंगे। इस संशोधन के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक मामले की परिस्थिति के आधार पर स्टेट बैंक आफ इंडिया, उसके सहायक बैंकों तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य किन्हीं लाइ-सेंसित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जो निगम के शेरधारक हैं, ऐसी योजनाओं के लिए जिनके संबंध में बैंकों को निगम के पक्ष में जमानत प्रस्तुत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, प्रवर्त पुनर्वित्त की सुविधाओं के लिए कोई सरकारी गारंटी या अन्य जमानत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आलोच्य वर्ष के दौरान निगम ने यह भी निश्चय किया कि राज्य सहकारी बैंकों को प्रवर्त की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में भी अन्य जमानत और/या सरकारी गारंटी प्रस्तुत करने से छूट दी जाए बशर्तकि (1) जिस योजना के संबंध में इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो वह योजना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त तथा प्राथमिक रूप से सक्षम हो, (2) संबंधित राज्य सहकारी बैंक 'क' वर्ग के लेखापरीक्षा बर्गीकरण के अंतर्गत अनुसूचित बैंक हो, (3) इस योजना में भाग लेने वाला केन्द्रीय सहकारी बैंक और/या प्राथमिक सहकारी ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी बैंक 'क' वर्ग के लेखापरीक्षा बर्गीकरण के अंतर्गत आये और उसके द्वारा मांग के कम के कम 80 प्रतिशत की बसूली की जाये, और (4) सहकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली जमानत भारतीय विजय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुकूल हो।

मूल्यांकन

294. पिछली रिपोर्ट में निगम द्वारा पुनर्वित्त-पोषित परियोजनाओं का निरंतर अध्ययन करने के लिए एक परियोजना प्रवर्तक और मूल्यांकन कक्ष की स्थापना करने का उल्लेख किया गया था। मूल्यांकन कार्य के अंश के रूप में निगम ने चार योजनाओं का अध्ययन कार्य शुरू किया। उक्त योजनाएं इस प्रकार हैं : सोलापुर जिले (महाराष्ट्र) के चार तालुकों में पंप सेटों से युक्त नये कुओं की योजनाएं, करनाल I योजना (हरियाणा) के अधीन सतही मलकूप लगाना, नालगोंडा जिले (आंध्र प्रदेश) के मियांलरुडा तालुक के नागार्जुन सागर भूमि-विकास परियोजना और कर्नाटक के बिन्नपुर जिले के डावणगेरी और हरिहर तालुकों में भद्रा भूमि-विकास परियोजना। तबनुसार चार क्षेत्र युनिट स्थापित किये गये हैं। एकत्र किये गये आंकड़ों के अध्ययन स्तरीकरण का कार्य जारी है।

IV. औद्योगिक वित्त की गतिविधियां

295. औद्योगिक वित्त की प्रमुख विशेषता यह थी कि मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा 1974-75 के दौरान प्रदान की गयी वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी ; उनके द्वारा मंजूर की गयी राशि जहां 1973-74 के 412 करोड़ रुपये से बढ़कर 504.0 करोड़ रुपये हो गयी वहां उनके द्वारा वितरित की गयी राशि 274 करोड़ रुपये से बढ़कर 364.9 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 26)। मंजूरीयों और वितरणों के रूप में प्रदान की गयी सहायता में हुई वृद्धि का अधिकांश भाग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा०प्रो०वि०बैंक) और राज्य वित्तीय निगमों का था।

296. इसके अलावा मंजूर की गयी और वितरित राशि में रुपया ऋणों का अंश काफी अधिक था जबकि कुल राशि में विदेशी मुद्रा ऋणों का अनुपात कम ही था। मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा हमीवारी तथा शेयरों के प्रत्यक्ष अभिधान के रूप में मंजूर की गयी सहायता की राशि में सीमांत वृद्धि हुई और प्रमुख रूप से भा० प्रो० वि० बैंक के कारण डिबेंचरों के लिए स्वीकृत अभिदानों में वृद्धि हुई।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

297. 1974-75 में सभी पिछड़े राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के सर्वेक्षण का अंतिम चरण समाप्त हुआ। अंशमान और निकोबार का सर्वेक्षण अंतिम है और वह सुप्रगामी है। कतिपय विकसित राज्यों में राज्य-स्तरीय एजेंसियों द्वारा अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण कार्य किया गया है। सर्वेक्षणों से पता लगायी गयी विभिन्न औद्योगिक संभावनाओं में से लगभग 200 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेशयुक्त 52 परियोजनाएं या तो कार्यान्वित की गयी हैं या कार्यान्वित की जा रही हैं।

अंतर संस्थागत दल

298. महाराष्ट्र का अंतर संस्थागत दल इस वर्ष के दौरान कार्य करने लगा। इस प्रकार के दल अब देश के 17 राज्यों में कार्यरत हैं। ये अंतर संस्थागत राज्य दल संबंधित राज्य के विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संबंधी समस्याओं पर ठोस विचार विमर्श करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में काम आते हैं। उनमें से अधिकांश दल विभिन्न राज्यस्तरीय संगठनों के प्रयत्नों को समन्वित तथा प्रोत्साहित करने के लिए सफल तंत्र का निर्माण करने में सामान्यतः सफल हुए हैं। उनके कतिपय महत्वपूर्ण कार्य निम्नप्रकार थे : सर्वेक्षणों के द्वारा परियोजनाओं का पता लगाना, परियोजनाओं की रूपरेखाएं बनाना या

उपयोगिता संबंधी विस्तृत अध्ययन करना और परियोजनाओं के वित्तपोषण संबंधी प्रयत्नों का समन्वय करना, आदि। कतिपय अंतर संस्थागत दलों ने विशिष्ट पहलुओं पर कार्रवाई करने के लिए उप समितियों/ जांच समितियों का भी गठन किया है ; उक्त कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं : जुने हुए क्षेत्रों के सर्वेक्षण करना, नयी परियोजनाओं का पता लगाना, पता लगायी गयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं तत्संबंधी अनुसूची कार्रवाई के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना, उद्यम-कर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाना, उपयोगिता संबंधी अध्ययनों के लिए परियोजना संकल्पनाओं को चुनना, उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन करना आदि। उद्यमकर्ताओं के विकास के संदर्भ में आंध्र प्रदेश, असम, केरल, गुजरात और बिहार के अंतर संस्थागत दलों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कदम उठाये हैं जब कि कतिपय अन्य अंतर संस्थागत दल इस दिशा में योजनाएं बना रहे हैं।

तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र

299. पटना में बिहार औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड की स्थापना के साथ अब तीन तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र विद्यमान हैं। अन्य दो सेवा केन्द्र इस प्रकार हैं : कोचीन स्थित केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड एवं गौहाटी स्थित पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड।

व्यवहार्यता-अध्ययन

300. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के सहयोग के साथ भाप्रोवि बैंक द्वारा किये गये व्यवहार्यता संबंधी कुछ अध्ययनों के आधार पर कतिपय परियोजनाएं साकार हो गयी हैं। भाप्रोवि बैंक की वित्तीय सहायता के साथ असम औद्योगिक विकास निगम द्वारा असम में एक दानेदार उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है जबकि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा केन्द्रीय परिष्करण और बिजली चालित करघा परियोजना स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। मेघालय सरकार का प्रस्ताव है कि सहकारी क्षेत्र में आलू के लिए शीत भंडारण संयंत्र स्थापित किया जाए।

छोटे उद्यमकर्ताओं का अध्ययन

301. अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान के प्रोफेसर एच० एन० पाठक के ज़रिये भाप्रोवि बैंक ने गुजरात में छोटे उद्यमकर्ताओं की समस्याओं का जो अध्ययन प्रारंभ किया था उसकी रिपोर्ट इस वर्ष के दौरान जनता के लिए प्रकाशित की गयी। विभिन्न राज्यस्तरीय संस्थाओं तथा राज्य के अंतर संस्थागत दलों को भी उक्त रिपोर्ट की प्रतियां प्रेषित की गयी। उक्त अध्ययन ने काफी विश्वस्वी पैदा की है और यह आशा की जाती है कि इससे अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ताकि उद्यमकर्ता के स्वरूप का निर्माण करने वाली परिस्थितियों और उसकी समस्याओं से वे अधिकाधिक अवगत हों।

उद्यमकर्ताओं की सहायता

302. भाप्रोवि बैंक परियोजनाओं का पता लगाने, उनको बनाने तथा कार्यान्वित करने में उद्यमकर्ताओं तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों की सहायता करता रहा। भाप्रोवि बैंक के पास रहनेवाली तकनीकी परामर्शदाता सूची में परामर्शदाताओं के अतिरिक्त नाम सम्मिलित किये गये और उक्त सूची राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों आदि वित्तीय और प्रवर्तक संस्थाओं को प्रेषित की गयी। संभाव्य उद्यमकर्ताओं को भी परामर्शदाताओं की सूची प्रेषित की गयी ताकि वे अपनी परियोजनाओं के लिए उचित परामर्श ढाला चुन सकें।

303. भाषावि बैंक ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और संस्थानों के साथ विशेष रूप से उनके द्वारा विकसित की गयी नयी प्रक्रियाओं/वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने एवं उसका अध्ययन करने के उद्देश्य से पहले की तरह संपर्क बनाये रखा।

304. इस वर्ष के दौरान भाषावि बैंक ने यह निश्चय किया कि उद्यमकर्ताओं की सुविधा के लिए अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर परियोजना की रूपरेखाएं बनायी जाएं। विभिन्न परियोजनाओं की लगभग 100 रूपरेखाएं बनायी गयीं और अपने कार्यालयों के बीच उद्यमकर्ताओं को सूचित करने के लिए परिचालित की गयी। देश के छोटे और छोटे-मझोले यूनितों के बीच प्रबंध संबंधी अच्छी प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाषावि बैंक ने औद्योगिक विकास बैंक, कनाडा द्वारा 'माप अपना कारोबार करें' शीर्षक की श्रृंखला में जारी की गयी पुस्तिकाओं के महत्व को स्वीकार कर उन्हें राज्य वित्तीय निगमों और राज्यस्तरीय अंतर संस्थागत दलों के बीच प्रचारित किया। उपर्युक्त एजेंसियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे उक्त पुस्तिकाओं में राज्य विभागों से संबंधित तथ्यों को शामिल करें और आवश्यकता होने पर उन्हें स्थानीय भाषा में अनुवाद करें और छोटे उद्यमकर्ताओं को वितरित करें। अल्प अवधि में पायी गयी प्रतिक्रिया काफी संतोषजनक रही है।

305. आलोच्य वर्ष के दौरान भाषावि बैंक ने पिछड़े राज्यों के औद्योगीकरण की समस्याओं का नियमित रूप से विशेष अध्ययन करने के लिए कबम उठाये हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रारंभ में अधिक पिछड़े हुए छः राज्यों को चुना गया है। इन अध्ययनों के अंतर्गत आनेवाले विषयों में अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं : क्षेत्रीय पिछड़ेपन के कारणों का गहराई से विश्लेषण करना, वर्तमान औद्योगिक स्थिति, विभिन्न प्रोत्साहनों के प्रति उद्यमकर्ताओं का रुझान, औद्योगीकरण का उभरता हुआ स्वरूप और सम्बंधित क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास का कार्यक्रम। आशा की जाती है कि इन अध्ययनों से संबंधित क्षेत्र के औद्योगीकरण से संबंधित नीतियों का पुनरीक्षण तथा निर्माण करने में सुविधा होगी।

भाषावि बैंक के कार्यक्रमलाप

306. आलोच्य वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान भाषावि बैंक के कार्य-कलापों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ और उसकी मंजूरीयों और वितरणों दोनों की राशियां नये उच्च स्तर तक पहुँच गयीं। गारंटियों

को छोड़कर मंजूर की गयी सहायता की कुल राशि में 1974-75 में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह राशि बढ़कर 7,593 आवेदनपत्रों के संबंध में 351.4 करोड़ रुपये हो गयी जबकि 1973-74 में उक्त राशि 3,550 आवेदनपत्रों के संबंध में 213.7 करोड़ रुपये थी। कुल वितरणों की राशि 1974-75 में 213.0 करोड़ रुपये थी जो 1973-74 के 162.2 करोड़ रुपये के मुकाबले में 31 प्रतिशत अधिक थी। औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त से संबंधित मंजूरीयों की राशि 1973-74 के 2,665 आवेदनपत्रों से संबंधित 41.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 6,390 आवेदनपत्रों के संबंध में 105.7 करोड़ रुपये हो गयी। पुनर्वित्त सम्बन्धी मंजूरीयों का दो-तिहाई से अधिक अंश लघु उद्योगों और छोटे-मझोले परिवहन वाहनों से संबंधित था। भाषावि बैंक द्वारा ऋणियों की पुनर्भुनाई के लिए 1,062 खरीदार-उपयोगकर्ताओं के संबंध में 114.4 करोड़ रुपये की जो राशि मंजूर की गयी वह 1973-74 के दौरान 804 खरीदार-उपयोगकर्ताओं के संबंध में मंजूर किये गये 76.3 करोड़ रुपये से 50 प्रतिशत अधिक थी। राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों जैसे सरकारी निकायों ने जो सहायता प्राप्त की उसकी राशि 1973-74 के 20.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 23.2 करोड़ रुपये हो गयी। भाषावि बैंक द्वारा अपनी स्थापना से लेकर जून 1975 के अंत तक मंजूर की गयी कुल राशि 1,308.3 करोड़ रुपये थी जबकि 939.4 करोड़ रुपये की सहायता का उपयोग किया गया था।

307. भाषावि बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिए मंजूर की गयी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 1974-75 के दौरान 66 परियोजनाओं के संबंध में 78.4 करोड़ रुपये थी जबकि 1973-74 में उक्त राशि 49 परियोजनाओं के संबंध में 57.5 करोड़ रुपये थी। सहायता प्राप्त यूनितों के संबंध में उर्वरक, कागज, इस्पात के बिलेट और/या सिलिलियाँ, वस्त्र, मशीनें, स्कूटर आदि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने वाले वर्तमान यूनितों की नयी क्षमता बढ़ाने और/या उनका विस्तार करने/तरह-तरह की वस्तुओं का निर्माण करने की परिकल्पना की गयी है। इसके अलावा सहायता प्राप्त 66 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएँ तकनीशन-उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित की गयी थीं और 34 परियोजनाएँ पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित थीं। निविष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनितों के लिये रियायती शर्तों पर 26.1 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष परियोजनागत सहायता मंजूर की गयी।

सारणी 26 : 1973-74 तथा 1974-75 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मियादी वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी और वितरित की गयी सहायता

संस्थाएं	मंजूर की गयी सहायता								(करोड़ रुपये)	
	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा ऋण		हामीदारी और प्रत्यक्ष अधिदान				जोड़	
					सामान्य और अधिमान शेष		डिबेंचर			
	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	163.75* (30.77)	222.79 (67.41)	—	—	8.21	6.00	—	3.00	171.96 (30.77)	231.79 (67.41)
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	34.51	23.36	4.26	3.64	3.11	3.60	—	—	41.88	30.60
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	19.76	16.00	34.68	41.29	5.05	3.77	1.63	1.80	61.12	62.86
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम @	7.21	7.59	—	—	—	—	—	—	7.21	7.59
राज्य वित्तीय निगम\$	96.61	129.82	4.43	8.36	0.72	0.49	—	—	101.76	138.67
राज्य औद्योगिक विकास निगम\$	23.04	21.61	—	—	5.02	10.90	—	—	27.06	32.51
जोड़	344.88 (30.77)	421.17 (67.41)	43.37	53.29	22.11	24.76	1.63	4.80	411.99 (30.77)	504.02 (67.41)
भारतीय यूनितेड ट्रस्ट + जीवन बीमा निगम	—	—	—	—	3.81	2.96	4.11	3.21	7.92	6.17
	17.08	24.96	—	—	4.90	5.51	3.95	15.01	25.93	45.48

सारणी 26: 1973-74 तथा 1974-75 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मीयाबी वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी और वितरित की गयी सहायता—जारी

(करोड़ रुपये)

संस्थाएं	रपवा ऋण		विदेशी मुद्रा ऋण		वितरित की गयी सहायता						जोड़
					हानीबारी और प्रत्यक्ष अधिदान						
	सामान्य और अधिमान शेष		डिबेंचर								
	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	113.40 (22.79)	164.67 (35.09)	—	—	4.79	1.72	—	0.99	118.19 (22.79)	167.38 (35.09)	
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	27.32	32.50	3.01	3.48	1.54	0.83	—	0.14	31.87	36.95	
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	13.76	13.71	26.30	29.09	1.94	1.82	1.54	0.77	43.54	45.39	
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (a)	5.15	8.05	—	—	—	—	—	—	5.15	8.05	
राज्य वित्तीय निगम\$	54.08	78.19	—	1.82	0.48	0.21	—	—	54.56	80.22	
राज्य औद्योगिक विकास निगम\$	16.21	20.05	—	—	4.46	6.84	—	—	20.67	26.89	
जोड़	229.92 (22.79)	317.17 (35.09)	29.31	34.39	13.21	11.42	1.54	1.90	273.98 (22.79)	364.88 (35.09)	
भारतीय यूनिट ट्रस्ट +	—	—	—	—	2.29	2.22	5.49	5.21	7.78	7.43	
जीवन बीमा निगम	10.65	45.49	—	—	3.72	4.59	5.59	5.69	19.96	55.77	

* इसमें प्रत्यक्ष ऋण, बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त तथा पुनर्भुनाई शामिल हैं। राज्य वित्तीय निगमों को प्रदान किये गये पुनर्वित्त को कोष्ठकों में अलग से दर्शाया गया है और उसे इसमें दुहरे संगणन से बचने के लिए शामिल नहीं किया गया है; क्योंकि राज्य वित्तीय निगमों के ऋणों में उसे जोड़ दिया गया है।

(a) इसमें मंजूर की गयी तथा वितरित की गयी गारंटी की राशि शामिल है।

\$ आंकड़े अनंतिम हैं।

+ 1974-75 के आंकड़े अनंतिम हैं तथा 1973-74 के आंकड़े संशोधित हैं।

308. निर्यात वित्त (सहभागिता योजना और निर्यात ऋण का पुनर्वित्त) योजनाओं के अंतर्गत मंजूर की गयी राशि 1973-74 के 10.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 33.7 करोड़ रुपये हो गयी। इस संबंध में भी पुनर्वित्त के लिए मंजूर की गयी राशि अधिक थी। आलोच्य वर्ष के दौरान बंगला देश के लिए कुल 8 करोड़ रुपये के तीन अतिरिक्त विभिन्न ऋण मंजूर किये गये / इससे उसकी स्थापना से लेकर अब तक मंजूर किये गये कुल ऋणों की संख्या बढ़कर छः और उनकी राशि बढ़कर 25.5 करोड़ रुपये हो गयी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण

309. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के अंतर्गत भारत सरकार को 250 लाख डालर के और ऋण मंजूर किये गये; इस ऋण के सममूल्य की रूपया राशि भाषावि बैंक को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा छोटे और मझोले औद्योगिक यूनिटों को विदेशों से उपकरणों और तकनीकी जानकारी के आयातों का वित्त-पोषण करने के निमित्त किये जाने वाले ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए उपलब्ध होती है। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मंजूर की गयी सहायता की राशि जून, 1974 में समाप्त हुए सत्रह सप्ताहों की अवधि में जहाँ 11.3 करोड़ रुपये थी वहाँ 1974-75 में 145 GL/75—11

बढ़कर 17.0 करोड़ रुपये हो गयी। इसी अवधि में भाषावि बैंक द्वारा मंजूर किये गये पुनर्वित्त की राशि 4.52 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 9.88 करोड़ रुपये हो गयी। भाषावि बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता के लिए मंजूर किये गये प्रस्तावों की संख्या 84 से बढ़कर 1974-75 के दौरान 177 हो गयी।

पिछड़े क्षेत्रों को सहायता

310. निदिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को भाषावि बैंक से प्राप्त सहायता की राशि में भी 1974-75 में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रत्यक्ष सहायता और औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के रूप में रियायती शर्तों पर मंजूर की गयी सहायता की कुल राशि इस वर्ष के दौरान 59.8 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राशि 1973-74 में 47.3 करोड़ रुपये थी। इससे जून, 1975 के अन्त तक रियायती शर्तों पर मंजूर की गयी कुल सहायता की राशि बढ़कर 139.9 करोड़ रुपये हो गयी।

शेयरों और बांडों में अभिवान

311. इस वर्ष के दौरान भाषावि बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गमों में 1.4 करोड़

धन्यों और विशेष निर्गमों में 1.9 करोड़ रुपये का अभिदान किया। इन राशि के साथ भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना से लेकर 1975 के अंत तक भाषाविक बैंक द्वारा उसे दी गयी सहायता की राशि 28.0 करोड़ रुपये हो गयी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा इसके पूर्व लिये गये ऋणों की किश्तों के रूप में 1.2 करोड़ रुपये चुकाये गये। उसके बाद भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के डिबेंचरों में भाषाविक बैंक द्वारा धारित राशि जून, 1975 के अंत में 24.0 करोड़ रुपये रह गयी। भाषाविक बैंक ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की चुकता पूंजी में 1.3 करोड़ रुपये का अभिदान किया। इसके अलावा भाषाविक बैंक ने छः राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी में 2.8 करोड़ रुपये का अभिदान किया; इनसे सभी राज्य वित्तीय निगमों के शेयरों और बांडों में भाषाविक बैंक के कुल अभिदान की राशि बढ़कर 11.9 करोड़ रुपये हो गयी।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड

312. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्यकाल के चौथे वर्ष की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसके द्वारा अधिकाधिक मात्रा में सहायता का प्रयोग किया गया। जून, 1975 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान निगम द्वारा वितरित की गयी कुल राशि 8.7 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष उक्त राशि 5.9 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा जून, 1975 के अंत में निगम की स्थापना से लेकर वितरित की गयी कुल राशि 21.1 करोड़ रुपये थी जबकि मंजूर की गयी कुल सहायता की राशि 28.1 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को पुनर्निर्माण संबंधी सहायता के लिए 49 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। निगम की स्थापना से लेकर अब तक प्राप्त 529 प्रस्तावों में से 495 प्रस्तावों का अध्ययन कार्य पूरा किया गया; इनमें से योग्य पाये गये 92 मामलों में सहायता मंजूर की गयी। यह परिकल्पना है कि जिन मामलों में सहायता मंजूर की गयी उनमें कुल 72,793 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अगला की जाती है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्रवर्तित भारतीय वस्त्र अभिसंस्करण निगम लि० अप्रैल, 1976 तक अपना कार्य प्रारंभ करेगा।

केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड

313. 1974-75 के दौरान केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन को परियोजनाओं के संबंध में पूछताछ करते हुए 342 पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 315 पत्र उद्यमकर्तृओं से और शेष पत्र वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुए। परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त इक्कीस पत्रों के आधार पर परियोजनागत संकल्पनाएं निर्मित हुईं। पिछले वर्ष प्राप्त 25 योजनाओं सहित निगम के विचारार्थ प्राप्त योजनाओं की कुल संख्या जून 1975 के अंत में 46 हो गयी। इनके अलावा निगम को मूल्यांकन संबंधी 42 मामले प्राप्त हुए। अपनी स्थापना से लेकर अब तक केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन द्वारा परियोजना संबंधी जो रिपोर्टें पूरी की गयीं उनकी संख्या 52 थी और उनसे संबंधित निवेश राशि 8.6 करोड़ रुपये थी। इनके अलावा पूरी की गयी मूल्यांकन रिपोर्टों की कुल संख्या 69 थी और उनसे संबंधित निवेश राशि 18.6 करोड़ रुपये थी। अब तक केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन की सहायता प्राप्त परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ हो गया है, जबकि 46 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड

314. 1974-75 के दौरान पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन को परियोजनाओं की पूछताछ करते हुए निजी उद्यमियों

(68 प्रतिशत) और सरकार तथा सरकारी निकायों से 87 पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 13.8 करोड़ रुपये के निवेशयुक्त 17 पत्रों के आधार पर परियोजनागत संकल्पनाओं/मूल्यांकन सम्बन्धी मामलों का निर्माण हुआ। पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन को अपनी स्थापना से लेकर अब तक 189 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 107.2 करोड़ रुपये के निवेशयुक्त 105 पत्रों के आधार पर परियोजनागत संकल्पनाओं/मूल्यांकन सम्बन्धी मामलों का निर्माण हुआ। इस संगठन ने अब तक 72 करोड़ रुपये से अधिक निवेशयुक्त 74 परियोजनाओं को पूरा किया है जिनमें लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड

315. बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 15 अक्टूबर 1974, को कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। निगम को उसके पहले वर्ष के कार्यकाल के दौरान परियोजनाओं की पूछताछ करते हुए 249 पत्र प्राप्त हुए। अब तक 5.2 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेशयुक्त छः मामले परियोजनाओं में परिवर्तित हो गये हैं। इनमें से 1.8 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यययुक्त दो परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं।

राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप

316. तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित 18 राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलापों में 1974-75 (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रगति जारी रही। मार्च 1975 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान उनके द्वारा मंजूर किये गये ऋणों की कुल राशि 1973-74 (अप्रैल-मार्च) में मंजूर किये गये 96.8 करोड़ रुपये की तुलना में 134.8 करोड़ रुपये थी। वितरणों की राशि भी पिछले वर्ष के 54.1 करोड़ रुपये की तुलना में 1974-75 में बढ़कर 79.3 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च 1975 के अंत में वकाला ऋणों की राशि 277.5 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष पहले की तुलना में 28.5 प्रतिशत अधिक थी। अधिकांश वित्तीय सहायता लघु उद्योग क्षेत्र के यूनिटों को दी जाती रही तथा ऐसी सहायता का अंश कुल मंजूरियों और वितरणों का क्रमशः 53 प्रतिशत और 64 प्रतिशत था।

राज्य वित्तीय निगमों का सम्मेलन

317. राज्य वित्तीय निगमों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों का 17वां सम्मेलन दिनांक 10 तथा 11 मई, 1975 को बंबई में हुआ। इस सम्मेलन में अंतराष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के उपयोग तथा निगमों के उच्चस्तरीकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्य वित्तीय निगमों द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा की गयी तथा वित्तीय साधनों, प्रतिदेय राशियों, स्वीकृत की गयी सहायता के उपयोग में विद्यमान कमी आदि के संबंध में पायी गयी निगमों की प्रमुख समस्याओं और साथ ही बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के समन्वय पर विचार विमर्श किये गये।

अंतराष्ट्रीय विकास संघ ऋण

318. अंतराष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत सरकार को प्रदान किये गये 250 लाख डॉलर ऋण का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उक्त ऋण के समान राशि रुपये में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उपलब्ध होगी ताकि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा छोटे और मझोले औद्योगिक यूनिटों को विदेशों से संयंत्रों और मशीनों तथा/या तकनीकी जानकारी का आयात करने के लिये प्रदान किये जाने वाले ऋणों के पुनर्वित्त की व्यवस्था की जा सके। यह ऋण क्षेत्रीय विकास बैंकों के रूप में राज्य वित्तीय निगमों को सशक्त और अधिक प्रभावकारी बनाने के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है।

319. पूँजीगत माल संबंधी तदर्थ समिति को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण योजना के अंतर्गत आयात लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों को निपटाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त समिति ने 30 जून, 1975 तक 18.79 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की अपेक्षा करने वाले 662 आवेदन-पत्रों का निपटान किया है। राज्य वित्तीय निगमों को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण योजना के अंतर्गत 56.13 करोड़ रुपयों की कुल राशि के (रुपये तथा विदेशी मुद्रा दोनों में) ऋण की सहायता के लिये 701 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 28.28 करोड़ रुपयों (रुपये तथा विदेशी मुद्रा दोनों में) की अपेक्षा करनेवाले 398 आवेदन-पत्रों के संदर्भ में मंजूरी दी गयी तथा 10.27 करोड़ रुपयों की अपेक्षा करने वाले 122 आवेदन-पत्रों को सहायता के लिये उनके पात्र न होने के कारण (30 जून, 1975 तक) अस्वीकृति/निरस्त कर दिया गया। 17.58 करोड़ रुपयों की सहायता की अपेक्षा करने वाले शेष 181 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 252 मामलों में पुनर्वित्त मंजूर किया। उनके संदर्भ में राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि 15.83 करोड़ रुपये थी; इसमें 8.87 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा सम्मिलित थी। इस वर्ष के अनुभव से यह विवक्षित होता है कि राज्य वित्तीय निगम अपने लिये तैयार किये गये उच्च-स्तरीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये प्रायः कबम उठा चुके हैं।

लघु उद्योगों का वित्तपोषण

ऋण गारंटी योजना

320. इस योजना के अधीन सुविधाओं के लिये पात्र अनुमोदित ऋण संस्थाओं की सूची में 1 लाइसेंसित अनुसूचित वाणिज्य बैंक और 25 गैर लाइसेंसित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सम्मिलित करने से उक्त ऋण संस्थाओं की कुल संख्या जून 1974 के अंत में विद्यमान 583 से बढ़कर जून 1975 के अंत में 609 हो गयी। इन गैर-लाइसेंसित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में से तीन बैंक अपेक्षित करार निष्पादित कर अभी-अभी योजना में सम्मिलित हुए हैं। ऋण गारंटी योजना में भाग लेने वाली संस्थाओं की कुल संख्या जुलाई 1974 से जून 1975 तक की अवधि के दौरान 201 से बढ़कर 217 हो गयी। इस योजना के अंतर्गत बकाया गारंटियों की राशि जहाँ जून 1973 के अंत में 1145 करोड़ रुपये और जून 1974 के अंत में 1497 करोड़ रुपये थी वहाँ जून 1975 के अंत में बढ़कर 1726 करोड़ रुपये हो गयी; यह वृद्धि लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदान किये जानेवाले संस्थागत ऋण की मात्रा में निरंतर हुई वृद्धि की झलक थी। योजना के प्रारंभ से लेकर जून 1975 के अंत तक 1097 खातों के संदर्भ में दावों के लिये कुल 127.90 लाख रुपयों की अदायगी की गयी है। इनमें से जुलाई 1974-जून, 1975 के दौरान की गयी अदायगियों की राशि 226 खातों के संदर्भ में 27.83 लाख रुपये थी। इनमें से अधिकांश अदायगी बंबई और दिल्ली क्षेत्रों में की गयी। दावों के रूप में अदा किये गये कुल 127.90 लाख रुपयों की राशि में से 25.87 लाख रुपयों की राशि की बसुली की गयी है। इससे दावों के संदर्भ में अदा की गयी राशि जून 1975 के अंत में 102.03 लाख रुपये रह गयी। 1975 के दौरान 1.40 करोड़ रुपये गारंटी शुल्कों के रूप में प्राप्त हुए तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार को अंतरित किया गया।

योजना का उवारीकरण

321. इस विचार से कि ऋण संस्थाएं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के सहयोग से अपनी सहायता प्राप्त कमजोर यूनिटों को पर्याप्त वित्त प्रदान कर सकें, गारंटी रक्षा की उच्चतम सीमा को 7.5

लाख रुपयों से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह उच्चतम सीमा कार्यकारी पूँजी अग्रिमों और ऐसे अग्रिमों पर लागू है जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण से पहले ऋण गारंटी योजना के अधीन प्रदान किये गये हों। उच्चतम सीमा में की गयी यह वृद्धि प्रारंभ में 15 जनवरी, 1975 से दो वर्षों तक की अवधि के लिये प्रयोगात्मक रूप से जारी रहेगी तथा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व स्थिति की पुनः समीक्षा की जायेगी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहायता

322. 1974-75 (अप्रैल-मार्च) की पहली तीन तिमाहियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों (कारिगरों और अन्य योग्यता प्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी ऋणों और अग्रिमों को मिलाकर) की राशि में 113 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई; इस प्रकार उक्त राशि बढ़कर 1017 करोड़ रुपये हो गयी। आलोच्य अवधि में इस क्षेत्र के बकाया ऋण में जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुई वृद्धि (173 करोड़ रुपये) की केवल दो-तिहाई थी। सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या में भी 17621 की वृद्धि हुई जबकि 1973-74 की तदनु रूप अवधि में 45141 की वृद्धि हुई थी। किन्तु कुल बैंक ऋण में लघु उद्योगों को प्राप्त अंश दिसम्बर 1973 के अंत में स्थित 12.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 1974 के अंत में 12.9 प्रतिशत हो गया। प्रति यूनिट मंजूर की गयी जिस औसत ऋण राशि से सहायता प्राप्त छोटे यूनिटों के आकार और संख्या का निरूपण होता है उसे बनाये रखा गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दिसम्बर 1974 के अंत में मंजूर की गयी 68,000 रुपयों की जो औसत सीमा विद्यमान थी वह दिसम्बर 1973 में विद्यमान स्तर की तुलना में केवल 1,000 रुपये अधिक थी। इसके प्रसारित औद्योगिक वृष्टि से पिछड़े सभी राज्यों में लघु उद्योग यूनिटों को प्रदत्त बैंक ऋण की मात्रा में वृद्धि पायी गयी। यह उल्लेखनीय है कि छोटे यूनिटों के लिये मंजूर किये गये बैंक ऋण के अखिल भारतीय योग में कुछ राज्यों अर्थात् बिहार मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छोटे यूनिटों को प्रदत्त बैंक ऋण के अंश में वृद्धि पायी गयी।

323. यदि समूहवार देखा जाये तो दिसम्बर 1974 के अंत में इस क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण की जो कुल बकाया राशि (1017 करोड़ रुपये) विद्यमान थी उसमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया समूह और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का अंश 89 प्रतिशत (910 करोड़ रुपये) था। स्टेट बैंक समूह ने इस क्षेत्र को कुल 370 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किये अर्थात् उक्त ऋण राशि में मार्च 1974 के स्तर की तुलना में 32 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि 1973 की तदनु रूप अवधि में 44 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी थी। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में मार्च-दिसम्बर 1973 में हुई 116 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में मार्च-दिसम्बर 1974 में 71 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। दिसम्बर 1974 में समाप्त हुए नौ महीनों की अवधि में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों (किश्ती ऋणों को मिलाकर) में 27 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और उनकी राशि बढ़कर 216 करोड़ रुपये हो गयी। बकाया ऋणों की जो राशि मार्च 1974 के अंत में 43,520 यूनिटों के संदर्भ में 146 करोड़ रुपये थी वह दिसम्बर 1974 के अंत में बढ़कर 49,432 यूनिटों के संदर्भ में 175 करोड़ रुपये हो गयी। लघु उद्योग क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण में मीयादी ऋणों (बकाया) का अनुपात दिसम्बर 1974 में 17.2 प्रतिशत था जबकि दिसम्बर 1973 में उक्त अनुपात 16.0 प्रतिशत था। पन्द्रह वर्षों के लिये लघु उद्योग क्षेत्र को औद्योगिक वस्तियों की स्थापना के लिये

मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि दिसम्बर 1974 के अन्त में 38 यूनिटों के सन्दर्भ में 16.9 करोड़ रुपये थी और उनकी बनाया राशि 9.1 करोड़ रुपये थी।

324. कारीगरों तथा अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमियों के लिये मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की कुल राशि दिसम्बर 1974 के अन्त में 21,018 यूनिटों के सन्दर्भ में 47 करोड़ रुपये थी। बकाया ऋणों की राशि 33 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 44 प्रतिशत ग्रेन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया समूह द्वारा दिये गये ऋण का था।

325. दिसम्बर 1974 के अन्त तक छोटे सड़क और जल परिवहन बालकों के लिये मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि 74,276 यूनिटों के सन्दर्भ में 160 करोड़ रुपये थी। 121 करोड़ रुपयों की जो राशि बकाया थी वह मार्च 1974 के स्तर की अपेक्षा 20 करोड़ रुपयों की वृद्धि की दायक थी जबकि 1973 की तदनुसृत अवधि में 23 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

326. 1974-75 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट को काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूनिटों के विक्रय में काफी अधिक गिरावट आयी और उनके पुनः क्रय में तीव्र वृद्धि पायी गयी। इस ट्रस्ट के ग्यारह वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर था जब यूनिटों के विक्रय से अधिक यूनिट पुनः खरीदे गये। हालांकि जुलाई 1974 के आरम्भ में यूनिटों का सन्तोषजनक विक्रय होने के कारण भविष्य के सम्बन्ध में आशावादिता का वातावरण निर्मित हुआ था फिर भी सरकार द्वारा अनेक मुद्रास्फीतिरोधक प्रयासों की घोषणा किये जाने के कारण निवेश सम्बन्धी वातावरण में अकस्मात् शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गयी। विशेषकर 6 जुलाई, 1974 को कम्पनियों द्वारा अर्द्ध किये जाने वाले लाभांश पर प्रतिबन्ध लगाते हुए की गयी घोषणा, कर्मचारियों तथा आयकर दाताओं के लिये लागू की गयी अनिवार्य जमा योजनाओं तथा निवेश के अन्य लाभप्रद माध्यमों के लिए बढ़ायी गयी व्याज दरों के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि यूनिटों में निवेश किये जाने के प्रति आकर्षण कम हो गया। दिनांक 23 जुलाई, 1974 से बैंकों तथा डाकघरों में रहने वाली जमा राशियों और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित व्याज दरों को बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली आकर्षक व्याज दरों के कारण भी ट्रस्ट में निवेश करने वाले अनेक निवेशकर्ताओं का रुख बदल गया। इन कारणों का यूनिटों के विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा काफी अधिक मात्रा में यूनिटों को पुनः खरीदना पड़ा।

327. जनवरी 1975 के आरम्भ में सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर केवल यूनिटों में किये जाने वाले निवेशों के लिए आय और सम्पत्ति करों में रियायतें की। इस कार्यवाई से उक्त प्रतिकूल प्रवृत्ति को रोकना गया। कर सम्बन्धी इन रियायतों का अनुकूल प्रभाव यूनिटों के विक्रय तथा पुनः क्रय की प्रवृत्ति में परिलक्षित हुआ। अतः 1964 योजना के अन्तर्गत यूनिटों की जो विक्रय राशि अगस्त तथा दिसम्बर 1974 के बीच औसतन प्रति माह 0.22 करोड़ रुपये थी, वह जनवरी तथा मई 1975 के बीच औसतन प्रति माह 1.06 करोड़ रुपये हो गयी। यूनिटों के मासिक औसत पुनः क्रय की राशि भी कम हो गयी अर्थात् जहाँ अगस्त और दिसम्बर 1974 के बीच उक्त राशि 3 करोड़ रुपये थी वहाँ जनवरी और जून 1975 के बीच 0.75 करोड़ रुपये रह गयी।

328. आसन्न वर्ष के दौरान 1964 और 1971 योजनाओं के अन्तर्गत यूनिटों के विक्रय की राशि 67 हजार आवेदन-पत्रों के सन्दर्भ

में 17.2 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष 1.03 लाख आवेदन-पत्रों के सन्दर्भ में उक्त राशि 30.6 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष पुनः क्रय की राशि 1973-74 के 3.7 करोड़ रुपयों की तुलना में 20.4 करोड़ रुपये थी। बेचे गये यूनिटों की कुल राशि और ट्रस्ट में बकाया रहने वाली राशि जून 1975 के अन्त में 6 लाख से अधिक खातों के सन्दर्भ में 118.8 करोड़ रुपये थी। यूनिट पूंजी में 3.2 करोड़ रुपयों की शुद्ध कमी हो गयी है। ट्रस्ट 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 8.60 प्रतिशत का उच्चतर लाभांश घोषित कर सका जबकि पिछले वर्ष उक्त लाभांश यूनिट योजना 1964 के सम्बन्ध में 8.50 प्रतिशत था और यूनिट योजना 1971 के सम्बन्ध में ट्रस्ट ने 7 प्रतिशत का लाभांश बनाये रखा।

यूनिट योजना

329. ट्रस्ट की कुल निवेश योग्य निधियां 30 जून, 1975 को 170.6 करोड़ रुपये थी। उनमें से सामान्य शेयरों, अधिमान शेयरों, डिबेंचरों और दूसरे निवेशों में क्रमशः 47.4 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और शेष अंश लगाये गये। निवेश करने वाली जनता के बीच यूनिटों की लोकप्रिय बनाने के लिए कतिपय कदम उठाये गये। अल्पवयस्क बच्चों के मामले में अब उनके मां-बाप में से कोई उनकी ओर से यूनिटों में निवेश करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बालो-पहार योजना में भाग लेने वाले बच्चों को इनाम प्रदान करने की एक योजना शुरू की गयी है। भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में संशोधन कर यूनिटों को अब 'न्यासी प्रतिभूति' बनाया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप विभिन्न न्यास यूनिटों में निवेश कर सकेंगे और अपने निवेशों से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यूनिट से सम्बद्ध बीमा योजना की समीक्षा की जा रही है। जिससे निवेश करने वाली जनता को आकर्षित किया जा सके। ट्रस्ट ने यूनिटों की बिक्री के लिए सभी राज्य सहकारी बैंकों तथा कतिपय चुने हुए केंद्रीय और शहरी सहकारी बैंकों को सम्मिलित करते हुए अपनी अखिल भारतीय एजेंसियों के स्वरूप को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाये हैं। बिक्री को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों को तीव्र बनाने और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठाये गये हैं। जहाँ-जहाँ सम्भव हो, क्रियाविधियों को सरल बनाया जा रहा है। विशेष रूप से यूनिटों की बिक्री प्रणाली में तीव्रता लाने के लिए विचार-गोष्ठियों द्वारा एजेंटों के समूह को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। ट्रस्ट ने प्रचार सम्बन्धी अपने प्रयत्नों को भी सशक्त और व्यापक बनाया है ताकि उसकी सेवाओं को अधिक व्यापक रूप से मान्यता मिल सके।

V. विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां

330. आसन्न वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में पायी गयी महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार थीः देश में विदेशी मुद्रा लाये जाने के लिए भारत सरकार ने प्रोत्साहन प्रदान किया; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से कतिपय वर्गों की कम्पनियों को छूट दी गयी तथा बंगला देश, पाकिस्तान और पुर्तगाल के साथ व्यापार और प्रदायगी सम्बन्धी समझौते किये गये।

भारत में विदेशी कंपनियों के कार्यकलाप

331. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) के अनुसार विदेशों में निगमित सभी कम्पनियों (बैंकिंग कम्पनियों को छोड़कर) या ऐसी कम्पनियों जिनमें गैर-रिहायशी हित 40 प्रतिशत से अधिक हो और साथ ही ऐसी कम्पनियों की शाखाओं को चाहिए कि

वे भारत में इस प्रकार की अपनी व्यापारिक, आणविक या औद्योगिक गतिविधियों को चलाने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करें जिन्हें वे 1 जनवरी 1974 को कर रही थीं। दिसम्बर 1974 में भारत में नियमित उन कंपनियों को, जिनमें गैर-रिहायशी हित उनकी कुल ईकविटी शेयर पूंजी के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, उपर्युक्त आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों पर सामान्य छूट प्रदान की गयी:

(क) इस प्रकार की कम्पनी केवल निम्नलिखित कार्यों में लगी हुई हो:

(1) 2 फरवरी 1973 को बोधित भारत सरकार की औद्योगिक लाइसेंसिकरण नीति के परिशिष्ट I में निर्दिष्ट वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का उत्पादन या

(2) निर्यातमुख्य उद्योग अर्थात् ऐसा उद्योग जिसमें उत्पादित और पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से बाहर किसी भी स्थान को (नेपाल और भूटान को छोड़कर) निर्यातित वस्तुओं की कारखानों के बाहर की लागत का वार्षिक औसत वार्षिक उत्पादन की कारखानों के बाहर की कुल लागत के 60 प्रतिशत से कम नहीं हो।

(ख) इस प्रकार के कार्य करने के लिए ऐसी कम्पनी को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत फरवरी 1970 के पञ्चात् लाइसेंस प्रदान किया गया हो।

(ग) ऐसी कम्पनी का उत्पादन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 1 जनवरी 1974 को स्वीकृत लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक नहीं हो, और

(घ) ऐसी कम्पनी ने रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति बिना अपना गतिविधियों को व्यापक नहीं बनाया हो या दिशांतरित नहीं किया हो।

332. इस प्रकार की छूट प्राप्त कंपनियों को चाहिए था कि वे रिजर्व बैंक को 24 फरवरी, 1975 से पहले निर्धारित काम में घोषणापत्र प्रस्तुत करें।

विदेशी सौपरिवहन कंपनियाँ

333. अक्टूबर, 1974 में उन सौपरिवहन कंपनियों को, जो भारत में नियमित नहीं थीं या भारत में जिनका कोई शाखा-कार्यालय या दूसरा व्यापार केन्द्र नहीं था, द्वारा 29(1) के अधीन भारत में प्रान्ते स्थानीय एजेंटों द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन और भाड़ा शुल्क और करों की वसूली जैसे सामान्य आणविक कार्य करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी।

अचल संपत्ति का क्रय तथा विक्रय

334. यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत में विदेशी कंपनियों तथा विदेशी नागरिकों या 40 प्रतिशत से अधिक गैर-रिहायशी हितयुक्त भारतीय कंपनियों द्वारा अचल संपत्ति का क्रय या विक्रय करने, या स्टॉक कंपनियों के स्वामित्व में भारत में रहने वाली लाय/काफी/रखड़े के धारकों से प्राप्त बिक्री राशि को प्रेषित करने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति के निमित्त प्रस्तुत किये जाने वाले सभी आवेदन-पत्रों के साथ संबंधित संपत्ति की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए। यह रिपोर्ट व्यापक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण संपत्ति का मूल्य तथा मूल्य-निर्धारण प्रणाली उल्लिखित हो तथा उक्त रिपोर्ट संपत्ति कर अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये स्वीकृत मूल्यांकनकर्ता की होनी चाहिए।

मोटर/स्कूटर/कृषि ट्रैक्टर/सीमेंट का प्राथमिकता प्राप्त आरबंटन

335. भारत सरकार ने एक योजना बनायी है जिसके अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों को विदेशों से भारत में विदेशी मुद्रा प्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त योजना के अधीन भारत में कम से कम 2 वर्षों तक लगातार रहने के लिए आने वाले विदेशी राष्ट्रकों, विदेशों से लौटे भारतीय राष्ट्रकों तथा विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीयों के विस्तेदारों को जिन्होंने अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, प्राथमिकता के आधार पर मोटरकार या स्कूटर आरबंटित किया जाएगा। किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित प्राधिकृत व्यापारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि भारतीय कार/स्कूटर के मूल्य के समान विदेशी मुद्रा प्राप्त हो गयी है। इस उद्देश्य के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा को प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अलग-अपरिवर्तनीय खाते में रखा जाएगा। पारिवारिक भरण पोषण, बीमा कंपनियों की अदायगी, भविष्य निधि तथा भारत में स्थित अन्य अधिवारिकी विधियों में किये जाने वाले अंशदान या विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए निष्पादित बैंक गारंटियों की पूर्ति के लिए सामान्य रूप से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसके लिये इस योजना के अधीन सुविधा प्राप्त नहीं है।

336. इसी प्रकार विदेश से लौटकर आये हुए भारतीय राष्ट्रकों तथा उन भारतीयों को जिन्हें विदेश में स्थित उनके रिस्तेदारों से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, प्राथमिकता के आधार पर सिमेंट और कृषि ट्रैक्टर भी आरबंटित किये जाएंगे। इसके लिये इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उपर्युक्त वस्तुएं खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम राशि के बराबर की विदेशी मुद्रा भारत में लायी या प्राप्त की गयी है।

व्यापार/भुगतान संबंधी व्यवस्थाएं बंगला देश

337. भारत तथा बंगला देश की सरकारों के बीच संतुलित व्यापार और भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने पर यह स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार तथा तत्संबंधी लेनदेनों के लिए सारी अदायगियां उनमें से प्रत्येक देश में समय-समय पर लागू विदेशी मुद्रा विनियमों और क्रियाविधियों तथा सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं के अनुसार 1 जनवरी, 1975 से मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में की जाएंगी। उसी तारीख से बंगला देश की यात्रा के लिए पीड स्टलिंग में भी मुद्रा दी जाएगी जबकि पहले अपरिवर्तनीय रुपयों में अपेक्षित मुद्रा दी जाती थी। किन्तु संतुलित व्यापार तथा भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं में परिलक्षित वर्तमान भुगतान व्यवस्थाओं को उग आणविक ठेकों के संघर्ष में जो पहले ही कोयले, जूट, तमाखू, अजवायन, कागज तथा ताजे फलों के निर्यात/आयात के लिए संतुलित व्यापार तथा भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित किये गये हैं, 28 फरवरी, 1975 तक बढ़ाया गया ताकि इस संघर्ष में वस्तुओं की अपूर्ण दलितियों को पूरा किया जा सके। अपेक्षित संदर्भों में ठेके की अवधि को वर्तमान शर्तों पर 28 फरवरी, 1975 तक बढ़ाया जावेगा।

पाकिस्तान

338. 23 जनवरी, 1975 को भारत सरकार ने पाकिस्तान को साथ जो व्यापार करार किया उसके अनुसार उक्त देश के साथ व्यापार गारंटी स्तर पर अथवा दोनों देशों की सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यापार नियमों के माध्यम से दोनों देशों में प्रचलित विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किया जावेगा। दोनों देशों के बीच किया गया व्यापार करार हमनाधार की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा; किन्तु दोनों में किसी भी एक सरकार द्वारा एक वर्ष की प्रारंभिक वैध अवधि समाप्त होने से पूर्व 3 महीनों की नोटिस दी जाए तो उसके पश्चात्

सारणी 27 : जुलाई 1974 से जून 1975 तक की अवधि के सांख्यिकीय आंकड़े

I विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए जारी किए गए विदेशी मुद्रा परमिट

देश	तकनीकी पाठ्यक्रम		गैर तकनीकी पाठ्यक्रम	
	विद्यार्थियों/ प्रशिक्षण- धियों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)	विद्यार्थियों/ प्रशिक्षण- धियों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
ब्रिटेन और यूरोप	554	4860	557	2585
अमेरिका और कनाडा	1163	30768	716	12762
अन्य देश	149	878	119	554
जोड़	1866	36506	1392	15901

स्वयमेव उक्त करार की अवधि और दो वर्षों के लिए बढ़ जायेगी। अदायगी संबंधी व्यवस्थाओं को क्रम में लाने के लिए दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार (क) भारत/पाकिस्तान से किये जाने वाले निर्यात परिवर्तनीय मुद्रा में अभिव्यक्त अटल प्रलेखी ऋण पत्रों के अंतर्गत किये जाएंगे तथा (ख) फिलहाल स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान के द्वारा पौड स्टलिंग तथा अमरीकी डालर में इस प्रकार के लेन-देन किये जाएंगे। दोनों देशों ने एक संघिपत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 15 फरवरी, 1975 से दोनों देशों के बीच नौपरिवहन सेवाएं पुनः शुरू की गयीं। नौभार परिवहन के संबंध में यह प्रतिबंध लगाया गया कि वह केवल दोनों में से किसी एक देश के ध्वजयुक्त जलयान में ही ले जाया जा सकता है तथा नौपरिवहन से संबंधित सभी भुगतान और व्यय की पूर्ति परिवर्तनीय मुद्राओं में ही किये जाएंगे।

पुर्तगाल

339. भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हुए पहले जो आदेश दिया गया था उसे 1 जनवरी, 1975 से निरस्त कर दिया गया।

निर्बंध विदेशी मुद्रा परमिट

340. निर्यात विकास तथा अन्य अनुमोदित उद्देश्यों के लिए विदेश साद्रा करों के निमित्त निर्बंध विदेशी मुद्रा परमिट प्राप्त करने की पाल्ता के लिए निर्यातों की जो न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित है उसे बढ़ाकर 9 जनवरी, 1975 से परंपरागत निर्यातों के लिए 75 लाख रुपये तथा परंपरेंतर निर्यातों के लिए 15 लाख रुपये कर दिया गया; किन्तु निर्यात प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत निर्यातकों को निर्बंध परमिट प्राप्त होगा भले ही उक्त पिछला निर्यात कार्य कुछ भी क्यों न हो।

विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार करने के लिए लाइसेंस

341. बंगला देश के सोनाली बैंक को 2 गितंबर, 1974 से दो वर्षों की अवधि तक भारत में विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया।

II. विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण से इतर उद्देश्यों के लिए जारी किये गए यात्रा परमिट

उद्देश्य	उन व्यक्तियों की संख्या जिनको परमिट जारी किये गये हैं	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
1. कारोबार	14821	104866
2. डाक्टरी शिक्षा	441	5960
3. अध्ययन दौरे	718	4516
4. सम्मेलनों में भाग लेना	1367	3694
5. विविध	6375	13254
जोड़	23722	132290

III. अनुमोदित 'पी' फार्म आवेदनपत्रों की संख्या*

उद्देश्य	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके आवेदनपत्र अनुमोदित किये गये
1. परिवार के प्रभु से मिलना	16260
2. रिश्तेदारों से मिलना	19531
3. निर्यात विकास	397
4. विदेशों में नौकरी	21753
5. विदेशों में स्थायी निवास के लिए उत्प्रेषण	10069
6. विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी	2897
7. विविध	17659
जोड़	88566

*इन मामलों में कोई विदेशी मुद्रा प्रदान नहीं की जाती।

VI. रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा विचार गोष्ठियाँ

सर्वेक्षण

342. आगोष्म वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राज्य सरकारों के सांख्यिकीय विभागों के सहयोग से किये जाने वाले अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण 1971-72 में काफी प्रगति हुई। इस वर्ष के दौरान सर्वेक्षण के कार्य की प्रगति का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त की गयी निरीक्षण समिति की बैठकें दो बार हुई और उक्त समिति ने सर्वेक्षण की प्रगति का मूल्यांकन किया और इस संदर्भ में बनाये गये विभिन्न भूमिका-प्रपञ्चों पर विचार किया। जहाँ तक पूर्ति पक्ष की जाँच पड़ताल का संबंध है, सहकारी क्षेत्र में किये गये विभिन्न छोटे-छोटे सर्वेक्षणों की जाँच पड़ताल तथा सारणीकरण में काफी प्रगति पायी गयी। आणित्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण किये जाने से संबंधित छोटे से सर्वेक्षण के संदर्भ में भरी गयी अनुसूचियों की प्रतिष्ठा की जा रही है; उक्त सर्वेक्षण पाँच राज्यों के चुने हुए आणित्य बैंकों और कृषिपय ऐसी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन बैंकों पर अधिकार में ले ली गयी समितियों से संबंधित था। निरीक्षण समिति ने यह सुझाव दिया कि सरकारी एजेंसियों और अनुसंधान संगठनों के उपयोग के लिए सांख्यिकीय सारणियों के रूप में क्रमबद्ध रूप से सर्वेक्षण के मुख्य परिणामों को प्रकाशित किया जाए। तबनुसार संपूर्ण भारत और असम-प्रलय राज्यों के संदर्भ में ग्रामीण घरेलू परिवारों की आहिस्त्यों और वेय-ताओं के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए पहले प्रकाशन का खंड I 1 अगस्त 1975 को प्रकाशित किया गया। उक्त राज्यों के भीतर स्थित कृषि क्षेत्रों के संबंध में इसी प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने वाले उक्त प्रकाशन के खंड II तथा राज्यवार पुस्तिकाओं की तैयार करने का कार्य प्रगति कर रहा था। सांख्यिकीय विभाग द्वारा जुलाई 1970-जून 1971 के दौरान आहरी क्षेत्रों के श्रेतर कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता पर किये गये सर्वेक्षण से जो निष्कर्ष निकले उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के नवम्बर अंक में प्रकाशित किया गया।

343. आर्थिक विभाग के ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने "बढ़ते हुए कृषि उत्पादन में सहकारी ऋण की भूमिका" (1963-64 से 1965-66 तक) पर छठी अनुवर्ती सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की। सातवें अनुवर्ती सर्वेक्षण को "छोटे कृषक और सहकारी ऋण का अध्ययन" (1967-69) शीर्षक की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसके मुद्रण का कार्य जारी है। "कृषकों की वचन क्षमता" (1969-70) के क्षेत्रीय अध्ययन के आंकड़ों की जाँच की जा रही है और उन्हें सारणीबद्ध किया जा रहा है। "चुने हुए छोटे कृषकों की विकास एजेंसियों के कार्यकलापों" (1972-73) के सर्वेक्षण की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया गया और उसे भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया तथा उसके प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। "सीमांत कृषक और कृषि श्रम एजेंसियों के कार्यकलापों" (1973) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। (राज्य और केन्द्रीय) सहकारी बैंकों के अधियों का तैमासिक सर्वेक्षण कार्य ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा किया जाता रहा।

344. आर्थिक विभाग के व्यापार प्रभाग ने "भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग के द्वितीय सर्वेक्षण" के प्रमुख निष्कर्षों को प्रकाशित किया और उग प्रकाशन में 1964-65 से 1969-70 तक की अवधि ली गयी। इस सर्वेक्षण-क्रम में 1970-71 से 1972-73 तक की अवधि से संबंधित तीसरा सर्वेक्षण कार्य प्रगति कर रहा है।

345. आर्थिक विभाग का अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग अग्रणीकृत प्राप्तियों अर्थात् रु० 10,000 या उनके बराबर की राशि तक की विदेशी मुद्रा की ऐसी प्राप्तियों, जिनके लिए वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत कोई प्रयोजनवार विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, का सर्वेक्षण कार्य करता रहा। अक्टूबर-दिसंबर 1973 की तिमाही से संबंधित सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1974 के तीन महीनों अर्थात् जुलाई, अगस्त और सितम्बर का सर्वेक्षण कार्य किया गया और तत्संबंधी आंकड़ों की जाँच की जा रही है। 1975 की अप्रैल-जून की तिमाही का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके अलावा यह प्रभाग विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और विदेशी नियंत्रित भारतीय सप्या कम्पनियों से विदेशी निवेशों से संबंधित तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त करता रहा।

विचार गोष्ठियाँ

346. कृषि पुनर्गठित निगम ने दिसंबर 1974 में विसपुर (असम) में राज्य और जिला अधिकारियों के लाभार्थ असम राज्य की कृषि विकास परियोजनाओं के आयोजन और गठन पर एक विचारगोष्ठी आयोजित की। रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 1974 को बैंक ऋण के उचित मूल्यांकन और उसके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गठित अध्ययन दल द्वारा सुझाये गये उपयोग पर विचार-विमर्श करने के निमित्त एक विचार-गोष्ठी आयोजित की। इस विचार-गोष्ठी में स्टेट बैंक, उसके सात सहायक बैंकों, चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी क्षेत्र के चारह बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

347. केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की पाँचवीं विचार-गोष्ठी 26 से 29 सितम्बर 1974 तक पूना में हुई। इस विचार-गोष्ठी में विचार-विमर्श किये गये कृषिपय महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित से संबंधित थे। (1) अत्यावधि और वीथीविधि सहकारी ऋण विन्यास में अतिवेय राशियों की समस्या (2) वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन, (3) राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों में कर्मचारी वर्ग की समस्याएं, (4) (क) अत्यावधि और मध्यावधि सहकारी ऋण विन्यास तथा दोषावधि सहकारी ऋण विन्यास के बीच और (ख) सहकारी बैंकों एवं आणित्य बैंकों के बीच समन्वयन और (5) राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों की विकासपरक भूमिका।

VII. शिक्षा तथा प्रशिक्षण

348. भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न स्तरों अर्थात् अवर, पर्यवेक्षी और प्रवर स्तरों के अनेक कार्यपालक अधिकारियों को सामान्य और गहन प्रशिक्षण प्रदान करता रहा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बक के अपने कर्मचारी तथा आणित्य बैंकों, सहकारी संस्थाओं और कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारी लाभान्वित हुए। इस वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति को समीक्षा आगे प्रस्तुत है।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंबई

349. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय में ऋण विश्लेषण संबंधी पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता रहा। यहाँ के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख विषय सम्मिलित थे : शीघ्रोगिक संबंध, सामान्य बैंकिंग, उच्च-स्तरीय विदेशी मुद्रा कार्यक्रम और विदेशी मुद्रा अभिन्यसन कार्यक्रम। एगियाई विकास बैंक के सहयोग से भारत

और बारह एशियाई देशों के प्रतिनिधियों के लिए अक्टूबर-दिसम्बर 1974 में विकास बैंकिंग पर एक क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। पुनः जनवरी-फरवरी 1975 में विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान के सहयोग से भारतीय विकास और वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों के लिए विकास बैंकिंग पर एक दूसरा कार्यक्रम चलाया गया। इन महाविद्यालय में पहली बार भारतीय आर्थिक सेवा के परीक्षार्थी अधिकारियों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक और उसकी सहायकी संस्थाओं की नीतियों और कार्यप्रणालियों पर एक कार्यक्रम चलाया गया। नागालैंड की सरकार के अधिकारियों के लिए औद्योगिक वित्त पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समेकित पाठ्यक्रम, कर्मचारी प्रवेश पाठ्यक्रम और विधि अधिकारियों के पाठ्यक्रम भी चलाए गये। बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने नियत वित्त, स्वयंयोजित व्यक्तियों और छोटे ऋणकर्ताओं के वित्तपोषण तथा बैंकों के आंतरिक निरीक्षण पर विचार-गोष्ठियाँ आयोजित कीं। रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए इस महाविद्यालय ने केन्द्रीय बैंकिंग, उच्चतर केन्द्रीय बैंकिंग और प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की। वाणिज्य बैंकों के कुछ अधिकारियों/संकाय सदस्यों को भी उच्चतर केन्द्रीय बैंकिंग और प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों में भर्ती किया गया।

350. इस महाविद्यालय ने बैंक ऑफ़ आईलैंड के गवर्नर के अनुरोध पर उनके बैंक परीक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने में बैंक ऑफ़ आईलैंड की सहायता करने के लिए अपने दो संकाय सदस्यों को भेजा।

351. विदेशी मुद्रा संबंधी प्रकाशन और "आंतरिक निरीक्षणों की संदर्शिका" शीर्षक के प्रकाशन के संशोधन से संबंधित कार्य शुरू किया गया है और धारा है कि यह कार्य 1975-76 में समाप्त होगा।

352. इस वर्ष के दौरान कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के 1185 अधिकारियों ने श्रम-श्रम प्रकार के 22 पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इस प्रकार 1954 में जब इस महाविद्यालय की स्थापना हुई तब से आज तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या 8418 हो जाती है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पूना

353. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय कृषि वित्त और परियोजना आयोजन तथा मूल्यांकन के दो प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता रहा। इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम बैंकों के वरिष्ठ और मध्यम-स्तरीय अधिकारियों, रिजर्व बैंक के अधिकारियों, बिहार राज्य सरकार के अधिकारियों और सहकारी बैंकों तथा कृषि महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए चलाये गये। इन पाठ्यक्रमों में छोटे कृषक विकास एजेंसियों/सीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेंसियों के परियोजना अधिकारियों के लिए संस्थागत विषय संबंधी पाठ्यक्रम, जनजातीय विकास एजेंसियों के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम, डेरी, मूर्गी पालन, सुअर पालन और गन्धक पालन की कृषि बैंकिंग योजनाएँ सम्मिलित थीं।

354. इस वर्ष इस महाविद्यालय ने सहकारी, भूमि-विकास और वाणिज्य बैंकों तथा रिजर्व बैंक के 894 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया और इससे अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या बढ़कर 3764 हो गयी।

355. इस महाविद्यालय में प्राप्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:

(1) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय को कृषि बैंकिंग के क्षेत्र में श्रम-श्रम प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विभिन्न बैंकों के प्रशिक्षण तंत्रों द्वारा किये

जाने वाले प्रयासों को संगठित करने वाली एक सशक्त केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा। उसे कृषि ऋण संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/विचार-धानी गोष्ठियाँ/सम्मेलन आयोजित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करने योग्य भी बनाना होगा।

(2) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में एक समय पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पाँच कर दिया जाए ताकि एक ही समय पर उसमें 150 प्रशिक्षणार्थियों को स्थान मिल सके।

(3) परियोजना आयोजन तथा मूल्यांकन के कार्यक्रमों की विषय वस्तुओं को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि उनमें कृषि पुनर्वित्त निगम/विश्व बैंक की विशिष्ट अपेक्षाएँ सम्मिलित हों। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ और मध्यम स्तरीय कर्मचारियों के लिए दो श्रम-श्रम पाठ्यक्रम हों और दोनों पाठ्यक्रमों की विषय वस्तुओं में उपयुक्त परिवर्तन किये जाएँ।

(4) कनिष्ठ नये विषयों के प्रति भी अधिक ध्यान दिया जाए और सहकारी बैंकों के बोर्डों के ऐसे सदस्यों जो अधिकारी नहीं हैं, इन बैंकों के मुख्य कार्यवाहक अधिकारियों आदि को भी इस महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए ताकि वे अपनी संस्थाओं की दिक्कत करने के संदर्भ में अपनी सशक्त भूमिका अदा कर सकें। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय को कृषि बैंकिंग संबंधी शोध कार्य भी प्रारम्भ करना चाहिए, साथ ही कृषि बैंकिंग महाविद्यालय और वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय के बीच निकटतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

356. बैंक ने समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

स्टाफ, प्रशिक्षण महाविद्यालय, मद्रास

357. इस वर्ष के दौरान ग्रेड II स्टाफ अधिकारियों और सहायकों के लिए चलाये जाने वाले सामान्य पाठ्यक्रम को स्टाफ अधिकार विकास कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस पुनर्गठित कार्यक्रम का उद्देश्य स्टाफ अधिकारियों के दृष्टिकोणों और पर्यवेक्षण क्षमता को सुधारना है। इस महाविद्यालय की महत्वपूर्ण दूसरी गतिविधि यह थी कि बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग/औद्योगिक वित्त विभाग/कृषि ऋण विभाग/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/कृषि पुनर्वित्त निगम, ऋण आयोजना कक्ष और बैंकिंग प्रभाग (आर्थिक विभाग) के ग्रेड II स्टाफ अधिकारियों के लक्ष्य एक ऋण प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। स्टाफ अधिकारियों को सभी विभागों की जानकारी प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष ओ गतिशीलता पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। उसमें इस वर्ष और प्रगति हुई। गतिशीलता पाठ्यक्रम शुरू कर देने से बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग और कृषि ऋण विभाग के अधिकारियों के लिए संचालित निरीक्षण अभिमुख पाठ्यक्रम की विषय-वस्तुओं का पुनरीक्षण किया गया। उक्त पाठ्यक्रम को अब अधिकारिक विचार-विमर्श प्रदान बनाया गया है जिससे निरीक्षण अधिकारियों को अपनी निरीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मंच मिल सके। अलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रकार छः पाठ्यक्रम आयोजित किये गये। अब तक इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या 4609 है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

358. बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में लिपिक ग्रेड I, लिपिक ग्रेड II, आदि के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते रहे। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में अनुवांशिक आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक केन्द्र में लिपिक ग्रेड II स्तर के ऐसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक प्रायोगिक पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। बैंक इस

घात पर विचार कर रहा है कि प्रायोगिक पाठ्यक्रम को जारी रखा जाए या उसमें कोई परिवर्तन किया जाए। इस बीच कार्यालयों को इस आणय के अनुदेश दिये गये हैं कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के काफी अधिक प्रतिशत के कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए। स्टाफ आफ़िसर ग्रेड II के रूप में पदोन्नत किये जाने योग्य उम्मीदवारों के लिए विचार-निर्माण प्रधान और दो सप्ताहों की अवधि का एक विशेष कार्यक्रम भी सभी केन्द्रों में चलाया गया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक स्टाफ की कुल संख्या 10,254 है।

राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान

359. वर्ष 1974 के दौरान राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने अधिक व्यापक क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया। उनमें निम्नलिखित शामिल थे: साधन आयोजना, ऋण प्रबंधन, शाखा विस्तार, ग्रामीण बैंकिंग, लागत और लाभप्रवृत्ता, संगठन-आयोजना, सूचना प्रणालियाँ, महाभागी प्रबंध और श्रमशक्ति की भर्ती तथा विकास। इस वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा समाप्त/प्रवर्तित/प्रारम्भ की गयी अनुसंधान परियोजनाओं में उद्योग, एक राज्य, एक बैंक और क्षेत्रों तथा शाखाओं के लिए कार्य संबंधी बजट प्रणाली द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंकिंग योजना सम्मिलित थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में संस्थान के प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार था:

(1) संस्थागत वित्तरोपण के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत आधार को मजबूत बनाना और (2) बैंकों की अधिकाधिक महायता की अपेक्षा करने वाले अधिक समस्या युक्त क्षेत्रों अर्थात् छोटे किसानों, सूखे क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण उद्योगों, छोटे ऋणकर्ताओं आदि के संदर्भ में प्रयोग करना। संस्थान ने बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्तुलीकरण का वित्त-पोषण कराये जाने से संबंधित अध्ययन भी शुरू किया। इस वर्ष के दौरान 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विचार-गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 500 अधिकारियों ने भाग लिया। संस्थान के कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित थे: महाप्रबंधकों का सम्मेलन, बैंकों में आयोजना और विकास पर विचारगोष्ठी, कार्य संबंधी धजटों पर कार्यशालाएँ, आदि। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के लिए जिला योजनाएँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गयी। अप्रैल 1975 में संस्थान ने पहली बार बैंकों के प्रबंध अध्ययन से संबंधित प्रणाली पर एक पाठ्यक्रम चलाया। बैंकों के स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए दो सम्मेलनों, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाँच क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। संस्थान वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा लिपिक और अधिकारी स्तरों के व्यक्तियों की भर्ती करने में बैंकों को सहायता प्रदान करता रहा और आन्तरिक पदोन्नतियों के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित करता रहा। संस्थान ने पड़ोसी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाया और बंगला देश, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड के बैंकों के लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की।

कर्मचारी वर्ग की प्रतिनियुक्ति

360. अखिल भारतीय/राज्य-स्तरीय संघों, प्रबंध संस्थानों तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित प्रबंध विकास आदि से संबंधित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करता रहा। बैंक ने अपने अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय और पुनर्निर्माण विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंकाक स्थित एशियाई आर्थिक विकास और आयोजना संस्थान, टोकियो स्थित एशियाई सांख्यिकीय संस्थान और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों और दक्षिण-पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया पाठ्यक्रम में भाग

लेने के लिए प्रतिनियुक्ति किया। इसके अलावा पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण के लिए भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक विदेशी बैंकिंग/केन्द्रीय बैंकिंग संस्थाओं के अधिकारियों/वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रशिक्षण/अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करता रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक में हिन्दी की प्रगति

361. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक द्वारा किये गये कई प्रयासों का उल्लेख किया गया था। इस वर्ष इस संबंध में जो प्रयास किये गये उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे: (1) हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए कार्यालय आदेशों/परिपत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाए; (2) बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित जन-रक्षि के अखिल भारतीय सम्मेलनों की कार्यसूचीगत टिप्पणियों और कार्य विवरणों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाए; (3) अधिकारियों के नाम/पदनाम पट्टों तथा विभागों/प्रभागों के नाम पट्टों को द्विभाषिक रूप में प्रदर्शित किया जाए; (4) जनता के संपर्क बिन्दुओं में द्विभाषिक रजिस्ट्रार की मोहरों का प्रयोग किया जाए; (5) जिन क्षेत्रों में व्यापक रूप से हिन्दी बोली जाती है वहाँ के कार्यालयों द्वारा उन राज्य सरकारों के साथ जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार किया है और महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब राज्यों की सरकारों के साथ द्विभाषिक रूप में पत्राचार किया जाए; (6) बैंक के नाम और पते के साथ द्विभाषिक लिफाफे मुद्रित किये जाएँ; (7) बैंक के हिन्दी नाम अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयोग किया जाए; सहयोगी संस्थाओं को भी उसके अपने-अपने हिन्दी नाम का प्रयोग करने के लिए सूचित किया गया है और (8) हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में लिपिक ग्रेड II लिक्का-नोट परीक्षक ग्रेड II के पदों के लिए संचालित साक्षात्कारी में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। इन क्षेत्रों में सामान्य ज्ञान, अंकगणित और वाणिज्यिक भूगोल से संबंधित प्रश्नपत्रों को द्विभाषीकृत करने का प्रस्ताव है। हिन्दी का प्रचार करने के उद्देश्य से सभी कार्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किये जा रहे हैं।

362. राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के पालन में प्रगति जारी रही। इस वर्ष के दौरान बैंक का बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग हिन्दी भाषी क्षेत्रों और महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब राज्यों में शाखाएँ खोलने के लिए द्विभाषिक रूप में लाइसेंस जारी करने लगा। विदेशी मुद्रा निर्यात विभाग ने अपने कुछ परमिट फार्मों को दोनों भाषाओं में मुद्रित किया। बैंक ने अपने सभी कार्यालयों को सूचित किया कि बैंक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रकार के ठेकों और करारों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए।

363. बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं में होने वाले हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति पर ध्यान देने के लिए आवधिक रूप से बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती रही। यह निश्चय किया गया है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन पर ध्यान देने के लिए कानपुर और नयी दिल्ली में स्थित बैंक के कार्यालयों में प्रयोगात्मक रूप से स्थानीय समितियाँ गठित की जाएँ।

364. रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण प्रकाशनों के हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित करता रहा। उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे: बैंक और सहयोगी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टें, मुद्रा और वित्त की रिपोर्टें (संक्षिप्त रूपान्तर) और भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन। बुलेटिन के हिन्दी खंड में हर तिमाही में

कतिपय चुनी हुई सांख्यिकीय सारणियाँ दी जाने लगी हैं; इससे उक्त खंड की उपयोगिता बढ़ गयी है। बैंक के तैमासिक गृह पत्र "विवाउट रिजर्व" में अक्टूबर 1974 से हिन्दी खंड सम्मिलित किया जाने लगा है। "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेश और कम्पनी जमा राशियाँ," शीर्षक की पुस्तिक का हिन्दी रूपांतर भी प्रकाशित किया गया। रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रयोग में रहने वाले पदनामों की अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली को अंतिम रूप दिया गया और उसे रिजर्व बैंक के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गदर्शनार्थ प्रेषित किया गया। हिन्दी में बैंकिंग शब्दावली तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। बैंक ने भारत सरकार की बैंकिंग विधि समिति को, बैंकिंग को प्रभावित करने वाले विधान की समीक्षा करने के लिए उसके द्वारा बनायी गयी प्रस्तावली का हिन्दी रूपांतर प्रकाशित करने में सहायता दी।

365. हिन्दी अध्ययन मंडल (हिन्दी कक्षाएं) खलाये जा रहे और स्वीकृत हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर देय मासवेय की योजना जारी रही। कतिपय कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचालित हिन्दी पञ्चाचार पाठ्यक्रम की सुविधाओं का लाभ उठाया। बैंक के ग्रेड क, ख और ग के जिम अधिकारियों की आयु 1 जनवरी 1974 को 45 वर्ष की या उससे कम थी उनके लिए एक अनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना कार्यान्वित की गयी है। भारत सरकार और राज्य सरकारों की हिन्दी टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बैंक के टंकियों को प्रोत्साहन के रूप में देय मासवेय को रु० 100 से बढ़ाकर रु० 250 कर दिया गया है। भारतीय बैंकर संस्थान द्वारा संचालित बैंकिंग अभिमुख ऐच्छिक हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बैंक के श्रेणी I, II और III के सभी कर्मचारियों को रु० 150 का मासवेय प्रदान करने का निश्चय किया गया है।

366. बैंक ने जनवरी 1975 में नागपुर में संपन्न विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में बैंक ने 'बैंकों में हिन्दी' शीर्षक की प्रदर्शनी की व्यवस्था की और उसमें रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का चित्र प्रस्तुत किया गया। उस अवसर पर रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्टें आदि, बैंकों के साथ अपने व्यवहार में जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले हिन्दी/हिन्दी-अंग्रेजी फार्मों के नमूने, हिन्दी में पोस्टर, विज्ञापन और अन्य प्रचार सामग्री तथा फोटो प्रदर्शित किये गये।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी

367. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस वर्ष के दौरान अधिक व्यापक रूप से और प्रभावशाली ढंग से हिन्दी का प्रगामी प्रयोग कराने के लिए आधिकारिक प्रयत्न किये गये। बैंकिंग विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में किये गये मुख्य निर्णयों की सूचना सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके मार्गदर्शनार्थ और शीघ्र अनुपालन के लिए दी गयी। इन निर्णयों के अनुसार सभी बैंकों ने राजभाषा अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए व्यवस्थाएँ की हैं। बैंक विशेष रूप से हिन्दी-भाषी राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग द्वारा ग्राहक सेवा बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

368. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग करने के संदर्भ में जो प्रगति की है उसकी समीक्षा की गयी और भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में नियुक्त की गयी संसदीय समिति के उपयोगार्थ नवम्बर 1974 में एक समेकित रिपोर्ट सरकार को भेजी गयी। इससे यह विवित हुआ कि बैंकों ने सामान्यतः राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कदम उठाये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आधिकारिक रूप से प्रेषित की जाने वाली सूचना के आधार पर इन बैंकों में हिन्दी

के प्रगामी प्रयोग के संदर्भ में हुई प्रगति से नियमित रूप से सरकार को अवगत कराया जा रहा है।

VIII. लेखे और अन्य विषय

369. 30 जून 1975 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिये समायोजन करने के बाद बैंक की आय 448.01 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की आय 310.48 करोड़ रुपये थी। विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :

370. राष्ट्रीय कृषि ऋण (शीर्षकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्फुरीकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (शीर्षकालीन प्रवर्तन) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि जहाँ 1973-74 के दौरान क्रमशः 45 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये थी वहाँ 1974-75 के दौरान 50 करोड़ रुपये, 45 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये थी।

371. इस वर्ष के दौरान 78.01 करोड़ रुपयों का कुल व्यय होने के बाद 228.01 करोड़ रुपयों की जो आय शेष थी (पिछले वर्ष 50.48 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ था तथा 195.48 करोड़ रुपयों की आय शेष थी) उसमें से केन्द्रीय सरकार को भ्रवा करने के लिए रखी गयी लाभ राशि 150 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष भ्रवा की गयी राशि 145 करोड़ रुपये थी।

372. पिछले वर्ष की 310.48 करोड़ रुपयों की आय की तुलना में इस वर्ष प्रायः बढ़कर 448.01 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार उसमें 137.53 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे : (1) आलोच्य वर्ष के दौरान प्रारम्भित विदेशी मुद्रा निधियों में हुई वृद्धि के कारण अर्जित उच्चतर म्याज और (2) खजाना बिलों पर अर्जित उच्चतर बट्टा और हुण्डी बाजार योजना के अधीन अनुसूचित बैंकों के लिये भुनायी गयी वाणिज्यिक हुण्डियों में वृद्धि। व्यय में 27.53 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे : (1) श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों की देय महंगाई भत्ते में वृद्धि, (2) अधिकारी वर्ग का तबर्ष अतिरिक्त महंगाई भत्ते की भ्रवायगी, (3) 1970-75 की अवधि के दौरान सरकारी लन-देनों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों को देय बकाया कमीशन, और (4) अनिवार्य जमा योजना, 1974 से संबंधित कार्य करने के लिये एजेंसी बैंकों को देय पारिश्रमिक।

लेखा परीक्षक

373. बैंक के लेखों की परीक्षा मेसर्स वलाल एण्ड शाह, बंबई, मेसर्स पी० के० मित्रा एण्ड कंपनी, कलकत्ता, मेसर्स रघुनाथ राय एण्ड कंपनी, नयी दिल्ली और मेसर्स एम० के० दाण्डेकर एण्ड कंपनी, मद्रास द्वारा की गयी जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी दिनांक 23 दिसंबर, 1974 की अधिसूचना सं० एफ० 7/5/74-बी०ओ०-1 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में पुनर्नियुक्त किया था। इस वर्ष बैंक के सांख्यिक लेखा परीक्षकों द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली के कार्यालयों के अलावा जयपुर तथा तिरुवनंतपुरम के कार्यालयों की लेखा बहियों की भी परीक्षा की गयी है। लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक बंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली के कार्यालयों के लिये प्रति कार्यालय रु० 15,000 और

(राशि करोड़ रुपयों में)

सद	वर्ष	
	1974-75	1973-74
(1) राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अधिमों पर ब्याज	13.01	5.85
(2) राज्य सरकारों [उपर्युक्त मंत्र (i) में उल्लिखित अर्थोपाय अधिमों पर प्राप्त ब्याज को छोड़कर] और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये गये ऋणों और अधिमों पर ब्याज	65.54	34.88
(3) रुपया प्रतिभूतियों पर ब्याज और रुपया खजाना बिलों पर बट्टा	290.35	229.70
(4) विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशों और खजाना बिलों पर ब्याज और बट्टा	59.81	42.11
(5) धिनियम से प्राप्त कमीशन और लाभ या उपलब्धि	4.13	6.65
(6) अन्य आय	18.98	8.83
	451.82	328.02
घटाइये :—रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों द्वारा रखी गयी अतिरिक्त औसत दैनिक जमाराशियों पर उन बैंकों को दिया गया ब्याज	3.81	17.54
	448.01	310.48
घटाइये :—अनुच्छेद 370 के उल्लेखानुसार निधियों में किये गये अंतरण	220.00	115.00
	228.01	195.48

जयपुर तथा तिरुवनंतपुरम के कार्यालयों के लिये प्रति कार्यालय रु० 10,000 निश्चित किया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड

374. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत, बंगलादेश तथा श्रीलंका के कार्यपालक निवेशक के रूप में नियुक्त होने पर श्री एस० जगन्नाथन ने 19 मई, 1975 को कारोबार बंद होने के समय से बैंक के गवर्नर का पद-भार छोड़ दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल में श्री जगन्नाथन द्वारा की गयी अमूल्य सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति बोर्ड अपना आभार व्यक्त करता है।

375. श्री एन० सी० सेन गुप्ता तीन महीनों की अवधि के लिये रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किये गये (दिनांक 17 मई, 1975 को भारत सरकार की अधिसूचना सं० एक० 7-2-75 बी० प्रो०-I देखिये) और उन्होंने 19 मई 1975 को कारोबार बंद होने के समय से पद-भार संभाला।

376. केन्द्रीय सरकार ने उप-गवर्नर के रूप में डा० आर० के० हजारी की पदावधि को 27 नवम्बर 1974 से तीन वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

377. डॉ० पी. वी. गजेंद्रगडकर, प्रो० एम. एल. दांतवाला और डॉ० भवतोष दत्त ने क्रमशः 22 मई, 2 जुलाई तथा 16 जुलाई 1975 से रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिया।

378. विदेश मंत्रालय में नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के कारण श्री जी० पार्थसारथी ने भी 3 जुलाई, 1975 से बैंक के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।

379. डॉ० पी० वी० गजेंद्रगडकर, प्रो० एम० एल० दांतवाला, डॉ० भवतोष दत्त और श्री जी० पार्थसारथी द्वारा की गयी अमूल्य सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति बोर्ड अपना आभार व्यक्त करता है।

380. इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं; उनमें से तीन बैठकें बंबई में और एक-एक बैठक मद्रास, भिमला, कलकत्ता तथा बंगलूर में हुईं। केन्द्रीय बोर्ड की समिति की पचास बैठकें हुईं जिनमें से एक-एक बैठक मद्रास और नयी दिल्ली में तथा शेष बैठकें बंबई में हुईं।

स्थानीय बोर्ड

381. 24 जनवरी 1975 से डॉ० पी० टी० बोरसे, प्रधानाचार्य सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, बंबई तथा डॉ० सी० पर्वतम्मा, प्राचार्य और अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के अधीन क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।

382. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित प्रो० एम० एल० दांतवाला ने बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड की सदस्यता से जो त्यागपत्र दिया उसे केन्द्रीय बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। अतः वे 2 जुलाई 1975 से रिजर्व बैंक के पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

प्रेस सम्पर्क

383. प्रेस सम्पर्क अनुभाग बैंक और उसके कार्यकलापों के बारे जनता को अवगत कराने की अपनी उपयोगी भूमिका अदा करता रहा। इस अनुभाग ने नवंबर 1974 में आर० बी० आई० न्यूज लेटर नामक एक पाक्षिक प्रकाशन प्रारंभ किया। देश के विभिन्न भागों में रहनेवाले कर्मचारियों को बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं की गतिविधियों से अवगत कराने की जो आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी उसकी पूर्ति इस न्यूज लेटर से हो जाती है।

बैंक के भवन

384. बैंक की कतिपय भवन निर्माण परियोजनाओं को चालू वर्ष के दौरान स्थगित करना पड़ा था; क्योंकि 1973 में भारत सरकार द्वारा परिचलनेतर उद्देश्यों के लिए भवनों के निर्माण पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे और एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च 1975 तक के लिये बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा घोषित सीमेंट (संरक्षण और उपयोग का विनियमन) अधिनियम 1974 के अधीन सीमेंट के उपयोग पर लागू किये गये प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष के दौरान कोई नयी परियोजना प्रारंभ नहीं की जा सकी। जिन परियोजनाओं का निर्माण हो रहा था उनमें से अधिकांश परियोजनाओं के कार्य की प्रगति में भी सीमेंट की प्रतिबंधित पूर्ति के कारण बाधा पड़ी। निर्माणाधीन नयी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में दर्शायी गयी है :

नये कार्यालय भवन

385. आलोचना वर्ष के दौरान बंबई स्थित टकसाल के भूखंडों में बहु-मंजिलावाले कार्यालय भवन की नींव डालने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा हाल ही में भवन निर्माण का देका दिया गया है। गौहाटी स्थित दशू विभाग के उप-कार्यालय के लिये नये बॉल्ट का निर्माण कार्य तथा डाक बंगला भवन का पुनर्निर्माण कार्य अब समाप्त हो गया है। हैदराबाद में मुख्य कार्यालय भवन का निर्माण कार्य जारी है।

आवास भवन

386. अब तक रिजर्व बैंक अपने क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों को विभिन्न केन्द्रों में 3,890 क्वार्टर प्रदान कर चुका है। इनके अतिरिक्त क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिये 609 क्वार्टरों अर्थात् कलकत्ता में 112 क्वार्टरों, ऊरु अडयार और कोडम्बाकम पूर में 311 क्वार्टरों तथा बंगलूर में 186 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है; किन्तु आलोच्य वर्ष के दौरान सीमेंट की अपर्याप्त पूर्ति के कारण कार्य की प्रगति बहुत धीमी रही है। बंबई में अधिकारियों के लिये 152 क्वार्टरों का निर्माण कार्य दिसंबर 1975 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर

387. कार्यालय भवन के लिये गांधीनगर, गुजरात में भूमि ले ली गयी है तथा कोचिन में भूमि के लिये राशि भुगतान कर दी गयी है और शोध ही नगर आयोजना न्यास से भूमि प्राप्त कर ली जायेगी। कर्मचारी क्वार्टर बनाने के लिये हैदराबाद और गांधीनगर में भूमि खरीद ली गयी है और उसे अपने अधिकार में ले लिया गया है। चंडीगढ़, भोपाल, तथा कोचिन में सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों ने उन केन्द्रों में हमारे कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये पर्याप्त भूमि प्रदान की है और उसकी राशि भी भुगतान की जा चुकी है।

मालिक कर्मचारी संबंध बातचीत और विचार-विमर्श

388. केन्द्रीय कार्यालय में जुलाई 1974, फरवरी 1975 तथा अप्रैल 1975 में बैंक के कर्मचारियों (श्रेणी II, III और IV) का प्रतिनिधित्व करनेवाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ और बैंक के बीच विचार-विमर्श हुए। श्रेणी IV के कर्मचारियों के मामले में प्रमुख विषय बंबई केन्द्र की कतिपय स्थानीय समस्याओं से संबंधित थे जिनका अखिल भारतीय महासंघ भी था। उन समस्याओं पर सर्वसम्मति समझौता हुआ।

389. दोनों अखिल भारतीय संगठनों ने वर्तमान उभयपक्षी करारों की अवधि समाप्त होने पर अपने-अपने सदस्यों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिये मांग सूचियां प्रस्तुत कीं। बैंक ने अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ (श्रेणी II तथा III के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले) के साथ अप्रैल 1975 में प्रारंभिक विचार-विमर्श किये। उस समय बैंक ने संघ को मांग सूची में उल्लिखित प्रमुख विषयों पर देश की सामान्य आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से अवगत कराया। जहाँ तक अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ (श्रेणी IV के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला) द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग सूची का प्रश्न है, बैंक उक्त महासंघ से अन्य विवरण प्राप्त होने पर प्रारंभिक विचार-विमर्श करेगा।

390. रिजर्व बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ आफिसर संघ (जिसका नाम पहले पर्यवेक्षक स्टाफ संघ था) ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते की बढ़ावा जाये और अन्य स्टाफ की तुलना में अधिकारियों के सर्वमं विद्यमान असंगतियों को दूर किया जाये। इस विषय पर कई बार उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किये गये और बैंक ने अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन करने के लिये कुछ प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये। सरकार ने उन प्रस्तावों पर अपनी वर्तमान नीति के अनुसार विचार किया और यह स्वीकार किया कि तदर्थ रूप से कुछ रकम प्रदान की जाए।

391. अगस्त 1974 में अखिल भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ आफिसर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बंबई में वरिष्ठता के समन्वयन, स्थायीकरण और पवोश्रति, प्रशिक्षण, कुछ भत्तों की मात्रा, अन्य फुटकर सुविधाओं आदि कतिपय महत्वपूर्ण और सामान्य बातों पर विचार-विमर्श किये गये।

392. शाखा-स्तर पर कार्यलयों के प्रबंधकों/प्रभारी अधिकारियों ने अपने-अपने केन्द्रों के स्थानीय कर्मचारी संघों/कामगार यूनियनों के यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता सम्मेलन/विचार-विमर्शों का आयोजन किया।

393. पिछले वर्षों की तरह 1974-75 में भी रिजर्व बैंक विभिन्न कल्याण कार्यों के लिये संरक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा। उक्त सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित थे; खेलकूद और अस्वाहा, गृह सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, विभिन्न स्टाफ क्वार्टरों में स्थित कल्याण संगठनों की सहायता आदि।

394. बैंक एक त्रैमासिक गृह पत्र प्रकाशित करता आ रहा है। यह पत्र बैंक के कर्मचारियों की अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्ति प्रदान करने तथा सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के कार्यकलापों को प्रचारित करने के लिए एक लोकप्रिय माध्यम प्रस्तुत करता है। बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी कर्मचारी सुसाव योजना के अधीन सुसाव प्राप्त होते रहे। इस योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्टें समय समय पर कर्मचारियों के नाम सुसाव योजना की समिति के अध्यक्ष के पत्र के रूप में जारी की जाती हैं।

कर्मचारी आवास ऋण योजना

395. आलाभ्य वर्ष के दौरान निम्न प्रकार गृह निर्माण ऋण मंजूर किये गये :

	समितियों की संख्या	राशि रु०
(अ) नई सहकारी गृह निर्माण समितियाँ	16	1,39,65,181
पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियों को प्रतिरिक्त ऋण	6	5,89,691
		1,45,54,872
	कर्मचारियों की संख्या	राशि रु०
(आ) अलग-अलग कर्मचारियों को प्रदत्त नये ऋण	234	56,71,572
उन कर्मचारियों को प्रदत्त प्रतिरिक्त ऋण जिन्होंने पहले ही ऋण प्राप्त किये थे	108	31,51,227
		88,22,799

396. 1961 में इस योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक मंजूर किये गये समिति और व्यक्तिगत ऋण की कुल राशि क्रमशः रु० 5,69,58,799.00 और रु० 3,12,44,140.00 है। कुल 3,958 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

बैंक की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

397. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बैंक की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष उपाय किये गये हैं, जैसे पात्रता-संबंधी मूल मानदंडों तथा योग्यता संबंधी मानकों में छूट दी जाए, बैंक की सेवाओं में प्रारक्षित पदों के संबंध में अधिक व्यापक प्रचार किया जाए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ केवल अनुसूचित जातियों/जनजातियों से विशेष भर्ती की जाए।

इसके अलावा प्रत्येक कार्यालय में विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत 1 जनवरी 1967 से 31 दिसंबर 1973 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भर्ती में जो कमी रह गयी थी उसका निर्धारण किया गया तथा उन कार्यालयों को यह सजित किया गया कि आगामी 2/3 वर्षों में वे उस कमी की पूर्ति कर दें। इन उपायों तथा समय-समय पर जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों का संयुक्त प्रभाव यह हुआ है कि विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है और उसमें जो कमी रह गयी थी वह बाकी सीमा तक दूर हो गयी है। उदाहरण के लिये श्रेणी III के पदों की भर्ती के मामले में निविष्ट वर्तमान कोटे की पूर्ति करने के अलावा पहले विद्यमान कमी में से 45 प्रतिशत को जून 1975 तक दूर किया जा सका। परंतु बैंक अनुसूचित जनजातियों के कोटे की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

398. 1 जनवरी 1974 को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारी श्रेणी IV में 896, श्रेणी III में 1242 तथा श्रेणी II और I में 36 थे और उक्त संख्या बढ़कर 1 जनवरी 1975 को क्रमशः 1043, 1412 और 48 हो गयी है।

399. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों की नियुक्ति के लिए दिये गये प्रारक्षित पदों से संबंधित अनुदेशों का विधिवत् पालन होता है, प्रशासन और कामिक विभाग में इन जातियों के हितों का ध्यान रखने के निमित्त गठित विशेष कक्ष के एक अधिकारी कार्यालयों का दौरा करते हैं और इस उद्देश्य के लिये रखे गये रोस्टरों की जाँच करते हैं। उक्त अधिकारी ने इस वर्ष बंगलूर, भायखला (बंबई) हैदराबाद, हैदर, मद्रास, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम का दौरा कर जो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं उनकी सावधानी से जाँच की गयी और जहाँ-जहाँ आवश्यक था, सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।

400. अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से इन जातियों के 30 से 40 तक के उम्मीदवारों को ग्रेड 'अ' के अधिकारियों के रूप में भर्ती करने के लिए कदम उठाये गये हैं; इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैंक ने यह भी निश्चय किया है कि श्रेणी I में उन उच्चतर पदों में जिनके लिए विशेष अनुभव और/या योग्यताएँ अपेक्षित हैं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये प्रारक्षण किये जाएँ बशर्ते कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध हों।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1975 तक का तुलन-पत्र

इस विभाग

देयताएं	राशि		विवरण	प्राप्ति	
	रु०	पै०		रु०	पै०
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	15,49,78,757.00		सोने का सिक्का और मुद्रियाँ :—		
संचालन में नोट	6584,76,76,595.50		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,58,101.88	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—	
जारी किये गये कुल नोट			विदेशी प्रतिभूतियाँ जोड़	121,73,97,234.21	
		6600,26,55,352.50	स्वयं का सिक्का		304,26,55,336.09
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		5,59,96,917.65
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		6290,40,03,098.76
कुल देयताएं		6600,26,55,352.50	कुल प्राप्ति		6600,26,55,352.50

बैंकिंग विधान

देयताएं	रु०	पै०	आस्तियां	रु०	पै०
शुक्ता पूंजी	5,00,00,000.00		नोट	15,49,78,757.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00		रुपये का सिक्का	5,01,112.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000.00		छोटा सिक्का	2,79,617.24	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000.00		खरीदे और धुनाये गये बिल		
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000.00		(क) देशी	126,12,80,388.35	
जमा राशियां :—			(ख) विदेशी	---	
(क) सरकारी :			(ग) सरकारी खजाना बिल	332,15,67,737.92	
(1) केन्द्रीय सरकार	77,69,36,995.84		विदेशों में रखा हुआ ऋण*	410,95,25,397.68	
(2) राज्य सरकारें	8,44,73,019.23		निवेश**	677,45,14,553.66	
(ख) बैंक :			ऋण और अग्रिम :—		
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	603,50,24,866.97		(1) केन्द्रीय सरकार को	---	
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	42,99,13,458.16		(2) राज्य सरकारों को@	359,90,72,000.00	
(3) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,45,98,463.70		ऋण और अग्रिम :—		
(4) अन्य बैंक	1,74,10,401.96		(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	385,26,87,000.00	
(ग) अन्य	982,43,69,501.90		(2) राज्य सहकारी बैंकों को††	286,74,36,215.00	
देय बिल	97,97,68,768.31		(3) दूसरों को	59,88,45,001.00	
अन्य देयताएं	750,66,31,290.04		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश		
			(क) ऋण और अग्रिम :—		
			(1) राज्य सरकारों को	69,70,59,860.92	
			(2) राज्य सहकारी बैंकों को	13,33,72,365.66	
			(3) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को	---	
			(4) कृषि पुनर्वित्त निगम को	88,20,00,000.00	
			(ख) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,65,45,520.00	
			राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम		
			राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	82,54,99,828.00	
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—		
			(क) विकास बैंक के ऋण और अग्रिम	264,64,55,619.00	
			(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/ डिबेंचरों में निवेश	---	
			अन्य आस्तियां ‡	402,75,05,794.68	
कुल देयताएं	3585,91,26,766.11		कुल आस्तियां	3585,91,26,766.11	

अंशतः शुक्ता शेषों पर आकस्मिक देयता रु० 9,39,999.81 (पौण्ड 50,000 के स्टॉकिंग निवेशों को रु० 100 = 5.31915 पौण्ड की दर पर बढ़ाया गया)।

*नकदी, सावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं। ** (1) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं। (2) रु० 5,57,42,281.96 (विदेशों में रखे हुए 50,000 पौण्ड, 6,005,000.00 अमेरिकी डॉलर और 9,22,650.00 इयूरो मार्क के समान राशि) शामिल हैं। @ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। † भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 208,37,00,000 शामिल हैं। †† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। ‡ कतिपय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विदेशों में उनके द्वारा किये गये निवेशों के संदर्भ में विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अग्रिम दी गयी रु० 188,20,00,000 की राशि शामिल है।

हस्ताक्षर: जे० एफ० बाज०
मुख्य लेखाकार
तारीख 31 जुलाई, 1975

एन० सी० सेन गुप्ता गवर्नर
आर० के० हजारी उप-गवर्नर श्री० बी० चारी उप-गवर्नर
एस० एस० शिरालकर उप-गवर्नर आर० के० गोपात्रि उप-गवर्नर

30 जून 1975 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ हानि लेखा

प्राय	रु०	पै०
व्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि*	228,00,56,335.37	
	228,00,56,335.37	
व्यय		
स्थापना	34,65,01,633.44	
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	1,05,246.11	
लेखा परीक्षकों की फीस	80,000.00	
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि	1,24,49,577.27	
विधि प्रभार	87,719.80	
डाक और तार खर्च	16,32,353.18	
कोय-प्रेषण	94,38,912.02	
लेखन सामग्री, आदि	57,20,982.75	
प्रतिभूति-छपाई (बैंक, नोट फार्म, आदि)	5,82,42,274.86	
बैंक सम्पत्ति का मूल्यह्रास और सरम्मत	1,30,46,628.84	
एजेंसी प्रभार	31,24,70,222.44	
कर्मचारी और अधिवाषिकी निधियों में प्रणदान	40,00,000.00	
विविध व्यय	1,62,79,950.34	
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	150,00,00,834.32	
जोड़	228,00,56,335.37	
केन्द्रीय सरकार को वेय अधिशेष	150,00,00,834.32	
प्रारक्षित निधि लेखा		
	रु०	पै०
30 जून 1975 को शेष	150,00,00,000.00	
लाभ-हानि लेखों से अन्तरित किया गया		कुछ नहीं
जोड़	15,00,00,000.00	

* भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद ।

एम० सी० सेम गुप्ता गवर्नर

प्रार० के० हजारो उप-गवर्नर

बी० बी० चारी उप-गवर्नर

एस० एस० शिरालकर उप-गवर्नर

प्रार० के० शेषाग्रि उप-गवर्नर

डब्ल्यू० जे० एफ० बाज

मुख्य लेखाकार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम भारतीय रिज़र्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1975 तक के रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ।

हमने, केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई (फोर्ट), मद्रास, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और जयपुर के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही, दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबन्धकों द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलनपत्र में समाविष्ट किया गया है, उर्युक्त तुलनपत्र की जाँच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और यह सन्तोषजनक है । हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है; इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य-निर्धारण किया गया है । जहाँ तक हमारी जानकारी है, यह तुलनपत्र हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके ।

मेसर्स बलाल एण्ड शाह
मेसर्स पी०के० मिश्रा एण्ड कंपनी
मेसर्स रघुनाथ एण्ड कंपनी
मेसर्स एम० के० बांडेकर एण्ड कंपनी

लेखा परीक्षक

तारीख 31 जलाई, 1975

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की विवरणी

विवरण	निम्नांकित तारीख को समाप्त हुआ वर्ष							
	जून 30, 1974				जून 30, 1973			
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
द्रव्य विभाग								
देयताएं								
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	37,17,59,161.00				36,45,28,788.00			
संचालन में नोट	6472,72,04,191.50				5698,95,49,930.50			
जारी किये गये कुल नोट			6509,89,63,352.50				5735,40,78,718.50	
कुल देयताएं			6509,89,63,352.50				5735,40,78,718.50	
भ्रातृस्तियां								
सोने का सिक्का और बुलियन								
(क) भारत में रखा हुआ	182,53,04,731.42				182,53,07,821.82			
(ख) भारत के बाहर रखा हुआ								
विदेशी प्रतिभूतियां	166,73,97,234.21				177,36,80,055.13			
रुपये का सिक्का	7,50,63,787.68				8,38,06,402.14			
भारत सरकार की रपया प्रतिभूतियां	6153,11,97,599.19				5367,12,84,439.41			
वैशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र								
कुल भ्रातृस्तियां			6509,89,63,352.50				5735,40,78,718.50	
बैंकिंग विभाग								
देयताएं								
शुक्ता पूंजी	5,00,00,000.00				5,00,00,000.00			
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00				150,00,00,000.00			
राष्ट्रीय कृषि ऋण (बीर्षकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000.00				239,00,00,000.00			
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000.00				85,00,00,000.00			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (बीर्षकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000.00				205,00,00,000.00			
(क) सरकारी :								
(i) केन्द्रीय सरकार	61,57,98,480.17				57,04,56,105.17			
(ii) राज्य सरकारें	26,36,81,522.93				29,48,26,324.36			
(ख) बैंक :								
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	553,50,77,103.97				537,70,49,336.10			
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	26,26,10,122.81				22,75,49,813.28			
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,48,06,487.84				1,05,13,846.77			
(iv) अन्य बैंक	1,09,04,310.40				3,10,35,415.92			
(ग) अन्य	512,57,15,516.12				207,69,34,439.69			
देय बिल	125,52,38,985.22				54,03,75,419.80			
अन्य देयताएं	483,81,97,868.98				334,55,91,293.62			
कुल देयताएं			2591,20,30,398.44				1931,43,31,994.71	

भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र की विवरणी—(आरी)

विवरण	निम्नांकित तारीख को समाप्त हुआ वर्ष							
	जून 30, 1974				जून 30, 1973			
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
प्रास्तियां								
नोट	37,17,59,161.00				36,45,28,788.00			
रुपये का सिक्का	3,49,127.00				9,48,063.00			
छोटा सिक्का	2,51,761.34				2,66,968.46			
खरीदे और भुनाये गये बिल								
(क) देशी	274,37,78,289.83				15,22,91,040.89			
(ख) विदेशी								
सरकारी खजाना बिल	128,67,52,866.15				301,59,21,815.74			
विवेशों में रखा हुआ बकाया	596,33,23,105.29 ¹				266,82,82,995.02 ²			
निवेश	217,37,84,159.20 ²				540,20,49,769.16 ³			
ऋण और अग्रिम :—								
(i) केन्द्रीय सरकार को								
(ii) राज्य सरकारों को	177,82,73,164.18 ³				39,88,00,000.00 ⁴			
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	420,99,85,000.00 ¹				140,54,20,000.00 ⁵			
(iv) राज्य सहकारी बैंकों को	166,52,34,128.00 ⁶				189,52,75,475.00 ⁶			
(v) दूसरों को	38,16,95,000.00				11,32,75,000.00			
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)								
निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :								
(क) ऋण और अग्रिम								
(i) राज्य सरकारों को	67,87,33,623.72				66,41,05,471.13			
(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,65,67,755.33				17,97,47,227.00			
(iii) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को								
(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	54,00,00,000.00				34,50,00,000.00			
(ख) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के डिबचरों में निवेश	11,13,13,970.00				11,24,91,225.00			
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	52,87,68,118.00				41,06,37,914.00			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश								
(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	178,69,55,519.00				129,09,35,519.00			
(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश								
अन्य प्रास्तियां	153,45,05,650.40 ⁶				89,43,54,723.31			
कुल प्रास्तियां			2591,20,30,398.44				1931,43,31,994.71	

अंशतः चुकता होयों पर आकस्मिक देयता रु० 9,48,388.69 (पौंड 50,000 के स्टैलिंग निवेशों को रु० 100 = 5.2721 पींड की दर पर बदला गया) ।

- नकदी, सावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।
- (i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं ।
(ii) रु० 5,39,54,792.90 (विदेशों में रखे हुए 50,000 पौंड, 6,247,475 अमेरिकी डॉलर और 1,110,375 इयूरो मार्क के समान राशि) शामिल हैं ।
- राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर-ड्राफ्ट शामिल हैं ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 156,63,73,000 शामिल हैं ।
- राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।
- कमिशन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विदेशों में उनके द्वारा किये गये निवेशों के सन्दर्भ में विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अग्रिम दी गयी रु० 50,00,00,000 की राशि शामिल है ।
- (i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं ।
(ii) रु० 5,17,39,176.19 (विदेशों में रखे हुए 50,000 पौंड, 6,298,175 अमेरिकी डॉलर और 1,494,112.50 इयूरो मार्क के समान राशि) शामिल हैं ।
- राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 31,30,00,000 शामिल हैं ।

30 जून 1973 और 1974 को समाप्त हुए वर्षों का लाभ-हानि लेखा

	1974		1973	
	रु०	पै०	रु०	पै०
आय				
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन, आदि	195,47,95,113.00		171,29,18,131.22	
	195,47,95,113.00		171,29,18,131.22	
व्यय				
स्थापना	28,53,25,934.78		22,89,24,841.34	
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	66,346.31		66,520.16	
लेखा परीक्षकों की फीस	80,000.00		90,000.00	
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि	1,16,05,263.44		1,07,82,931.00	
विधि प्रभार	1,68,540.71		2,89,496.64	
डाक और तार खर्च	14,04,042.18		13,31,396.50	
कोष प्रेषण	81,33,581.59		81,87,102.19	
लेखन सामग्री आदि	40,22,877.04		32,00,280.92	
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट फार्म, आदि)	5,19,42,441.13		4,95,97,945.84	
बैंक सम्पत्ति का मूल्यांकन और सरम्भते	1,10,81,345.49		1,03,67,923.13	
एजेंसी प्रभार	11,19,19,385.81		8,30,83,593.94	
कर्मचारी और अधिवाषिकी निधियों में भ्रंशवान	50,00,000.00		50,00,000.00	
विविध व्यय	1,40,45,191.20		1,19,95,478.22	
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	145,00,00,163.32		130,00,00,621.34	
जोड़	195,47,95,113.00		171,29,18,131.22	
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	145,00,00,163.32		130,00,00,621.34	
प्रारक्षित निधि लेखा				
30 जून को शेष	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
लाभ-हानि लेखों से प्रक्षरित किया गया	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
जोड़	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	

† भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के बाद ।

वेबकी नन्दन सक्सेना, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 751.—Annual Report on the Working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year July 1, 1974—June 30, 1975.

In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following report on the Working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1975 :—

I. Performance of the Economy in 1974-75

Introduction : An overall Assessment

If the unprecedented rate of inflation constituted the central problem of the economy in 1973-74 overshadowing all others, the central fact which emerges from an assessment of its performance in 1974-75 is the restoration of a measure of balance in the economy. Effective fiscal, monetary and administrative measures helped to bring prices down from the high levels reached earlier and, together with steps to improve raw material supplies and transport facilities, enabled the resumption of industrial growth. It was possible to sustain the level of investment notwithstanding a decline in domestic savings. On the external front, the deterioration in India's terms of trade posed a formidable payments problem but it was also possible to meet it partly with the help of buoyancy in export earnings and partly from the sizeable inflow of external resources.

2. To appreciate fully the significance of this move towards normalcy it is necessary to view the performance of the economy in 1974-75, not in isolation, but in relation to developments in more recent years. It may be recalled that the economy had veered from its normal growth path since 1971-72, primarily because of the serious set-back to agricultural production during two successive years following natural calamities. This strain on the economy was further intensified by the burden imposed by massive relief outlays, first to benefit refugees and later to ameliorate drought conditions. Subsequently, with a progressive intensification of world inflation, domestic inflationary forces also assumed such serious proportions that the two years 1972-73 and 1973-74 together recorded a price rise of as much as 41 per cent.¹ In 1974-75, therefore the task of containing these mounting pressures of inflation and of meeting short-run exigencies caused by a considerable payments problem became far more urgent than the longer term problem of growth.

3. Since the year 1974-75 was technically the first year of the Fifth Five-Year Plan, there is the temptation to judge the economy from the standpoint of the various targets of savings, investment and growth envisaged in the Draft Plan. If so judged, the achievements would admittedly appear to be far from satisfactory: the economy recorded a real growth of about 2 per cent in national product, as against the targetted average annual growth of 5.5 per cent. But it would be incorrect to assess the performance in terms of Plan targets, for the reason that the economy had inherited the problems mentioned above, which had practically disrupted the process of long-term growth. The rise in the world prices of foodgrains and fertilizers, the imports of both of which had to be stepped up, accentuated difficulties already being faced by the economy in the year 1974-75 because of drought and floods. Judged against this background the progress towards restoration of normalcy in itself becomes an impressive achievement.

4. The most notable feature of 1974-75 was the moderation of the upward thrust in prices: in contrast to the price rise (Wholesale Price Index) of 25 per cent witnessed in 1973-74, the rise in average prices during the current year has been only 17 per cent.² Indeed, the contrast is sharper if comparison is made on a point-to-point basis: between end-June 1974 and end-June 1975 wholesale prices showed only a nominal rise of 0.6 per cent as against a rise of as much as 27.8 per cent during the previous year. In fact the year 1974-75 marked a departure from an uninter-

rupted phase of price rise which had commenced since March 1972, prices recording an actual decline between the third week of September 1974 and the first week of April 1975. The deceleration of inflation was a consequence of the cumulative impact of strict monetary and fiscal policies, both of which were geared to limiting aggregate demand. These policies were further buttressed by a number of administrative measures designed to curb hoarding and smuggling.

5. In the sphere of fiscal policy, three aspects deserve to be highlighted namely, mobilisation of a record level of resources through greater tax effort, fiscal discipline evidenced in the curtailment of expenditure and consequent containment of the magnitude of deficit finance. The scale of additional mobilisation of resources by the Centre in 1974-75 at Rs. 690 crores was unprecedented. The Centre's efforts in this direction were strengthened by the States which together were able to mobilise resources of the order of Rs. 358 crores. These resource mobilisation efforts were further reinforced by another set of measures designed to mop-up additional purchasing power: impounding of one-half of additional dearness allowances and almost all of any other wage and salary increases, ceiling on the amount of distributable profits and compulsory savings for tax payers in the higher income brackets. However, despite the restraint exercised by the Government in respect of non-development expenditure several factors like food and fertilisers subsidies, payment of dearness allowances to Government employees, drought relief expenditure enlarged the budget deficit in 1974-75 to Rs. 697 crores.³ Although the deficit was larger than that of the previous year, it should be pointed out that there was a difference; the 1974-75 deficit contained a sizeable non-inflationary component in the sense that a part of it was attributable to the purchase by the Centre from the Reserve Bank of foreign exchange resources accruing from IMF draws for the purpose of imports. If this factor is separated, the expansionary part of the deficit becomes much smaller.

6. These fiscal measures were reinforced by monetary measures designed to contain expenditure without impeding production. The effectiveness with which the credit policy was implemented could be seen from the fact that for the year July 1974—June 1975 the increase in the bank credit at Rs. 1105 crores or 14 per cent was significantly lower than the increase of Rs. 1446 crores or 23 per cent in 1973-74. In terms of gross credit (i.e., inclusive of bills rediscounted) the growth was even lower at only 12 per cent as against 27 per cent in the previous year. The incremental credit-deposit ratio came down significantly from the previous year's level of 91 per cent to only 69 per cent.

7. A striking aspect of credit policy in 1974-75 was the emergence of interest rate as an important instrument of monetary management: the demand for credit was sought to be restrained not only by limiting the recourse to the Reserve Bank but also through an increase in the cost of credit. Consequent on raising the Bank Rate 9 per cent in July 1974, the overall interest rate structure was levered up with twin objectives of imparting an element of discipline in the use of credit and assisting the task of deposit mobilisation. While the lower pace of bank credit expansion, mentioned above, is indicative of the disciplinary aspect, the relatively higher time deposits growth in 1974-75 reflects the mobilisation impact.

8. The effect of these restrictionary fiscal and monetary policies is seen in the significant slow down in the rate of monetary expansion. During the period July 1974 to June 1975 money supply with the public recorded a small rise of Rs. 725 crores or 6.3 per cent as compared with the level during 1973-74: the extent of the rise was less than one-half of the rise of Rs. 1488 crores or 14.9 per cent witnessed during 1973-74. In fact the rate of increase in money supply is the lowest witnessed during the last fourteen years.

9. More impressive was the behaviour of one component of money supply viz., currency which expanded by 2.4 per cent in 1974-75 in contrast to a 13.3 per cent increase during the previous year. Besides the impact of domestic policies, the slowing down of monetary expansion also derives from

¹ and ² Monthly Averages : July-June basis.

³ In fact the increase in net bank credit to Government at Rs. 831 crores in 1974-75 was lower than the figure of Rs. 957 crores in 1973-74. (31st March basis).

a drawing-down of foreign exchange assets—a factor which in fact acted as the single largest depressant of money supply. This element provides an explanation not only for the slower rate of monetary expansion in general, but in particular, for the sharp fall in the rate of currency expansion.

10. On the external front, although exports evidenced an impressive growth by 29 per cent during the financial year 1974-75, imports rose even faster by 49 per cent, thereby widening the trade gap; the estimated trade deficit of Rs. 1096 crores was more than double the deficit of Rs. 402 crores for 1973-74. The bulk of the rise in the value of imports was attributable primarily to imports of fuel, food and fertilisers. Mainly as a result of the trade deficit, the year 1974-75 ended up with a massive balance of payments deficit, which was financed through larger inflow of external resources, both from IMF drawals and external assistance. The nominal increase in foreign exchange reserves from Rs. 947 crores in March 1974 to Rs. 969 crores in March 1975 conceals this larger inflow of external resources.

11. The net inflow of foreign exchange resources in 1974-75 was larger than in 1973-74 by about Rs. 649 crores : Rs. 423 crores under drawals from IMF and Rs. 226 crores as net additional inflow of external assistance. The injection of such a large dose of additional external resources assisted considerably in imparting an element of stability to the domestic economy. Because of the relatively larger imports of foodgrains in 1974-75, it was possible to maintain the level of total supply of foodgrains : in the absence of larger imports, therefore, it would have been difficult to sustain the public distribution system. Since, despite lower level of procurement, public distribution of foodgrains was maintained at a satisfactory level, there was a salutary impact on price expectations. Furthermore, because the import component of total public distribution of foodgrains in 1974-75 was larger, there was an eventual reduction in primary money through sale of food. On the whole, it is more than probable that in the absence of such a large inflow of external resources, the fiscal and monetary policies undertaken in 1974-75 would have been much less effective.

12. In what follows a detailed discussion of sectoral growth, fiscal and monetary policies, price trends, savings and investment and the role of the external sector is presented. In the last section, on the basis of available indicators, an attempt has also been made to assess the prospects for growth in 1975-76.

National Income, Agricultural and Industrial Growth

National Income

13. According to the latest estimates of the Central Statistical Organisation, national income (at 1960-61 prices)

increased by 3.1 per cent during 1973-74; this was in contrast to an actual decline of 0.9 per cent witnessed in 1972-73. Although no estimates of national income are as yet available for 1974-75, it appears that national income would have recorded a growth of about 2 per cent. When compared with the targetted average annual rate of growth of 5.5 per cent in the Fifth Five-Year Plan, the actual growth is admittedly disappointing : it does not even compare favourably with the 3 per cent growth achieved during the previous year. But its significance consists in atleast continuing some rate of positive growth for the second year in succession and thereby imparting an element of stability to the economy, which was distracted from its normal growth path during the two earlier years primarily by problems caused by natural disasters.

Agricultural Production

14. The deceleration in the growth rate of national income during 1974-75 is, again, attributable to the set-back suffered by the agricultural sector. Although the performance in respect of foodgrains production was somewhat reassuring especially when viewed against the background of serious supply-demand imbalance of 1972-73, it appears that aggregate farm output during 1974-75 would show a marginal decline over the previous year's level; this is primarily due to a precipitate fall in the output of raw jute and to a certain extent a decline in oilseeds.

15. The year 1974-75 had its share of drought and floods. Despite these unfavourable climatic factors, total foodgrains production is estimated at 104 to 105 million tonnes—a level which compares favourably with the output of 103.6 million tonnes in 1973-74. Of course, the output was considerably lower than the target of 118 million tonnes set for the year. The total kharif grains output estimated at 62 million tonnes was 4.7 million tonnes lower than that of last year : while kharif rice production at 40 to 41 million tonnes was at the last year's level, production of bajra declined sharply from 7 million tonnes to 4 million tonnes, thus, accounting for the bulk of the fall in total production. This shortfall in kharif crop was more than offset by larger output of rabi grains : total output of rabi grains is estimated to touch a record level of 42 to 43 million tonnes, that is, 5 to 6 million tonnes higher than in the previous season. Favourable rains and weather from the very start of the sowing operations in almost all the regions and the timely diversion of electric power to agricultural purposes in Punjab and Haryana—two of the main wheat producing States—were responsible for the peak production. Of the total rabi output, wheat production is likely to be 27 million tonnes as compared with 22 million tonnes during the previous year. Data relating to the output of selected commodities in recent years are set out in Table 1.

TABLE 1 :—AGRICULTURAL PRODUCTION : SELECTED COMMODITIES

	Unit	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75 (Estimated)
Total Foodgrains	Million tonnes	105.2	97.0	103.6	104.0-105.0
<i>Kharif</i> foodgrains	"	63.0	58.6	66.7	62.0
<i>Rabi</i> foodgrains	"	42.2	38.4	36.9	42.0-43.0
Cereals	"	94.1	87.1	93.9	N.A.
Rice	"	43.1	39.2	43.7	N.A.
Wheat	"	26.4	24.7	22.1	27.0
Pulses	"	11.1	9.9	9.7	N.A.
Non-Foodgrains					
Cotton	Million bales of 180 Kgs.	6.6	5.4	5.8 (6.8@)	— (7.0@)
Jute and Mesta	"	6.8	6.0	7.3@@	5.5*
Oilseeds	Million tonns	8.7	6.9	8.7* (8.9@)	— (8.3@)
Groundnuts	"	6.2	4.1	5.8 (6.0@)	— (5.0@)
Sugarcane (in terms of Gur)	"	11.6	12.8	14.0	N.A.

*Final estimate.

@Trade estimates.

@@Partially revised estimates.

N.A.=Not Available.

16. As mentioned earlier, the decline in agricultural output in 1974-75 is accounted for by commercial crops but here again the record is mixed: according to tentative estimates, production of raw cotton is expected to have risen marginally from 67.5 lakh bales to 69.5 lakh bales and sugar production is likely to reach a record level of 48 lakh tonnes as compared to 39 lakh tonnes in 1973-74. Production of tea is also likely to show an increase. On the other hand, production of five major oilseeds would be lower at 8.3 million tonnes, as against 8.9 million tonnes last year. The decline is much sharper in the case of raw jute and mesta, the production of which is likely to decline from 73 lakh bales in 1973-74 to 55 lakh bales.

Procurement and Public Distribution

17. The system of public distribution of foodgrains was under considerable pressure during 1974-75, because of near constancy of domestic production and more importantly, inadequacy of procurement. In this context, it is necessary to recall the main developments in respect of procurement policy. There was no major change in procurement policy in respect of *khari* foodgrains during the 1974-75 (November-October) procurement season, except that the Union Government revised upwards the procurement price for standard variety of paddy from Rs. 70 to Rs. 74 per quintal. The procurement prices of jowar, maize, ragi and bajra were fixed at Rs. 74 per quintal, as against the previous year's price of Rs. 70 for jowar, maize and ragi and Rs. 72 for bajra. Procurement of *khari* foodgrains in 1973-74 aggregated 4.3 million tonnes. During the 1974-75 season procurement upto July 15, 1975 amounted to 3.5 million tonnes.

18. It is in respect of wheat procurement that a major change in procurement policy occurred: for the 1974-75 *rabi* season (April-March), the policy of Government monopoly in wholesale trade was given up and both private wholesalers and co-operatives were permitted to operate under a system of licensing and control. Under this system it was obligatory on the part of the wholesalers to hand-over to the Government 50 per cent of their purchases at a fixed price of Rs. 105 per quintal, leaving the remaining 50 per cent for sale by wholesalers at open market prices, which of course, were subject to certain maxima. It was expected that private traders/wholesalers would deliver about 5 million tonnes of wheat for purposes of public distribution. Not only traders failed to fulfil this obligation but also there were indications that market arrivals of grains were manipulated by farmers and traders with a view to avoiding the incidence of levy. In any case, a consequence of this approach to procurement was a sharp decline in total procurement of wheat from 4.3 million tonnes during the previous season to only 1.9 million tonnes. Such a substantial shortfall in procurement necessarily meant that the public distribution system had to be buttressed by larger imports. Imports of foodgrains during 1974 were stepped up to 4.9¹ million tonnes from 3.6 million tonnes in 1973. With this the total quantity of foodgrains distributed through the public distribution system during 1974 was maintained at the 1973 level of about 11 million tonnes. Further, imports during January-June 1975 were also higher at 3.5 million tonnes compared to 2.5 million tonnes in the corresponding period of 1974. During the period January-June 1975 the quantum of public distribution was higher at 5.7 million tonnes as compared with 5.2 million tonnes in the corresponding period of 1974.

Procurement Policy: 1975-76

19. The main contours of procurement policy for 1975-76 *rabi* season (April-March) may now be sketched. Although the procurement price of wheat would continue to be Rs. 105 per quintal as recommended by the Agricultural Prices Commission, the Union Government has formulated a bonus scheme under which an average bonus of Rs. 4.75 per quintal would be paid to the State Governments in which procurement of wheat would be undertaken. The State Governments, in turn, would utilise the bonus so received for providing incentives to farmers in kind, such as subsidised fertilizers, seeds, diesel oil, etc. The procurement target for the season has been set at 5.5 million tonnes, as recommended by the

Agricultural Prices Commission. Actual procurement till mid-July 1975 was of the order of 3.6⁵ million tonnes; this was sizeably larger than the entire 1974-75 season's procurement of 1.9 million tonnes.

20. Further, restrictions on inter-State movement of wheat would be continued by treating each State as a separate zone. No movement of wheat outside the State would therefore, be permissible, except on Central Government account. The mode of procurement i.e., whether purchases to be made in regulated markets and/or through a system of levy is left to individual State Governments to decide.

Industrial Production

21. The performance of the industrial sector was somewhat better than that of the agricultural sector. Although the actual growth rate of around 3 per cent in 1974 was by no means spectacular, it is noteworthy because it marked a recovery from the state of semistagnation of 1973.

22. Data relating to industrial production are available only upto September 1974: during the period January-September 1974, the monthly average level of General Index of Industrial Production (with 1970 as the base)⁶ showed a rise of 1.2 per cent compared with a fractional rise of only 0.7 per cent during the corresponding period of 1973. Available advance indicators suggest that the overall growth in industrial production during 1974 might be in the region of 3 per cent as compared to a growth of 1.0 per cent in 1973. Sluggishness of industrial growth was attributable to a variety of factors, the more important of which were continued power and fuel shortage in different parts of the country, transport bottlenecks, shortages of essential commodities, especially agricultural raw materials and labour unrest. These factors cumulatively led to a considerable under-utilisation of installed capacities in a wide range of industries. In the absence of infra-structure constraints, industrial growth in 1974 could have been much more impressive. Not only was industrial growth in 1974 relatively higher than that during the previous year but it also had a wide spread. The total weightage of industries showing a rise in output rose from 34 per cent in 1973 to 60 per cent in 1974, while the weightage of industries showing a decline in output came down from 63 per cent in 1973 to 37 per cent (Table 2).

23. The trends in different categories of industries can be seen from the data set out in Table 3. Production in basic, intermediate goods and consumer goods industries recorded rises of 1.8 per cent, 6.0 per cent and 3.8 per cent, respectively. In the case of basic industries, the increase was largely contributed by a rise in production of coal and in electricity generated. Production of cement, however, recorded a sharp decline for the second year in succession; heavy inorganic chemicals, aluminium and brass manufactures also suffered declines. Among intermediate goods industries, production in respect of cotton spinning, fittings, fixtures and fasteners, tyres and tubes, petroleum refinery products, structural clay products and batteries recorded significant increases ranging between 5.6 per cent and 59.6 per cent. In the case of consumer goods industries, output of sugar refined and tea was up by 11.1 per cent and 10.3 per cent, respectively; among other industries which showed a rise were paper and paper products, fine chemicals and pharmaceutical products, soaps and other washing and cleaning compounds, metal products and communication equipment. However, production levels of certain mass consumption goods like vanaspathi, weaving of cotton textiles and footwear (rubber) were lower.

24. On the other hand, production in capital goods industries declined by 2.3 per cent during January-July 1974 in contrast to an increase of 13.9 per cent in the corresponding period of 1973. Although the decline was shared by most of the industries, the more conspicuous among them were industries producing rail-road equipment, motor vehicles and machinery components and accessories, which

⁵ Out of the 1975-76 marketing season.

⁶ Recently, Central Statistical Organisation, Calcutta (CSO) has revised the index of industrial production with 1970 as the base. The revised data relate only to the General Index. Data in respect of production of individual industries and groups of industries are not yet available with 1970 as base. Hence, group-wise and industry-wise production trends are discussed on the basis of the old index with 1960 as the base; these data are available upto July 1974.

¹ The reference is to the calendar year.

TABLE 2 :—CLASSIFICATION OF INDUSTRIES BY THEIR GROWTH RATES

Range of Growth Rates@	In terms of weights in the General Index (Base : 1960=100)				
	Full Year			January—July	
	1971	1972	1973	1973	1974†
1	2	3	4	5	6
A. Increase					
1. Moderate : Less than 5 per cent	27.99	31.98	20.57	25.11	16.78
2. Marked : 5 per cent and above	31.96	55.16	12.74	8.97	42.74
Of which :					
10 per cent and above	15.72	15.89	7.18	7.57	13.21
3. Weight (1+2)	59.95	87.14	33.31	34.08	59.52
B. Decline					
4. Moderate : Less than 5 per cent	19.98	5.53	42.93	39.29	20.97
5. Marked : 5 per cent and above	17.59	4.85	20.65	23.52	16.40
Of which :					
10 per cent and above	5.30	1.99	6.01	7.60	9.10
6. Weight (4+5)	37.57	10.38	63.58	62.81	37.37
C. Constant			0.63	0.63	0.63
Total Weight (A+B)	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*

@Growth rates represent percentage increases in output over the respective preceding years.

†Provisional.

*C.S.O. does not regularly publish the index of industries with the balance of 2.48 percentage points of weightage.

TABLE 3 :—TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION—GROUP-WISE (BASE : 1960=100)

(BASED ON C.S.O.'s INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION)

(Variations during the year : per cent)

Groups	Weights	January-July*					
		1970	1971	1972	1973	1973	1974
1	2	3	4	5	6	7	8
General Index (Crude)	100.00	+4.8	+2.9	+7.1	+0.7	— 0.2	+2.3
Use-Based Classification							
1. Basic Industries	25.11	+4.6	+5.5	+8.8	—1.5	— 1.3	+1.8
2. Capital Goods Industries	11.76	+5.0	—0.1	+8.6	+12.4	+13.9	—2.3
3. Intermediate Goods Industries	25.88	+2.8	+1.0	+6.7	+2.2	+ 0.8	+6.0
4. Consumer Goods Industries	37.25	+6.5	+3.2	+5.3	—3.7	— 5.0	+3.8
Input-Based Classification							
1. Agro-based Industries	44.08	+4.5	—0.3	+ 5.1	—1.8	— 2.8	+2.2
2. Metal-based Industries	16.55	+5.7	+2.5	+ 7.0	+6.6	+ 7.9	+0.4
3. Chemical-based Industries	8.94	+8.0	—6.9	+12.9	+2.7	— 1.0	+3.2
Sectoral Indicators							
1. Transport Equipment and Allied Industries	10.90	—	+0.5	+ 6.4	+6.5	+ 4.0	+5.3
2. Electricity and Allied Industries	8.42	+11.5	+9.0	+ 8.4	—1.0	— 3.0	+5.8

*Provisional.

together accounted for more than one-half of the total weights of all capital goods industries. The fall in production of rail-road equipment was mainly due to a decline in production of railway wagons.

25. The size and range of increases in industrial production do not support the view held in some quarters of a general recession in that sector. Even among industries experiencing declines in output, the main factors hampering growth have often been power and transport bottlenecks and shortage of agricultural raw materials. It is only some sub-sectors of engineering industries and jute textiles industry which appear to be going through a recessionary phase attributable to slackness in demand. However, it is also true that part of the jute goods industry's problems are attributable to a price-disadvantage in comparison with other competitors in the international market. So also the

apparent slackness in domestic demand for textiles may be a consequence of consumer resistance to higher prices. Thus, even in respect of these isolated pockets of the sector, the explanation for low offtake has to be sought not just in slackness of demand but in other factors as well.

26. In point of fact, the pace of industrial growth has shown signs of acceleration since towards the close of 1974. What is more, output in some core sector industries like electricity generation, steel and coal has shown a sizeable rise and since this sector has an important bearing on the performance of other industries it augurs well for faster industrial growth during 1975-76.

Fiscal Policy and Demand Management

27. Marginally higher level of foodgrains production, reinforced by larger imports and recovery in industrial

production, discussed in the previous section, did not, however, fully correct the basic supply-demand imbalance in the economy. In fact, despite some abatement of the unprecedented rates of inflation witnessed during the previous year, demand pressures continued to be a matter of concern in 1974. It became therefore imperative to gear both fiscal and monetary policies to hold these pressures in check.

Budget Deficit: Centre and States

28. The major thrust of fiscal policy in 1974-75 was towards containing budgetary deficit. However, because of increased dearness allowance payments to Government employees, increased food subsidies, larger purchases of fertilizers and additional outlay on capital formation, aggregate Government expenditure rose to a higher level than anticipated in the budget. Consequently, notwithstanding the mobilisation of a record level of resources amounting to Rs. 1048 crores in 1974-75 by the Central and State Governments, their combined deficit in 1974-75 reached Rs. 727 crores⁷ or Rs. 234 crores higher than in 1973-74. Since the details of the receipts and disbursements corresponding to this deficit of Rs. 727 crores are not available, the analysis that follows is in terms of revised estimates (R.E.) for 1974-75. The combined budgetary deficit⁸ at Rs. 567 crores (R.E.) was only marginally higher than in 1973-74 (Rs. 547 crores). However, it was substantially higher than

⁷ According to the latest available information, as per the Reserve Bank of India records, the overall combined deficit for 1974-75 works out to Rs. 727 crores, comprising Rs. 697 crores on Centre's account (i.e., net increase in outstanding Treasury bills and variation in cash balance) and Rs. 30 crores on account of States (i.e., variations in cash balances, ways and means advances from the Reserve Bank and holdings of Treasury bills).

TABLE 4 :—COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Amounts in Rupees Crores)

	1973-74 (Accounts)	1974-75 (Budget Estimates)@		1974-75 (Revised Estimates)		1975-76 (Budget Estimates)@	
	Amount	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year
	1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	12945*	14329	+10.8	15518	+19.9	16982	+ 9.4
A. Revenue Receipts	9286	10227	+10.1	11366	+22.4	12548	+10.4
Of which :							
Tax Receipts	7363	8020	+ 8.9	8872	+20.5	9917	+11.8
B. Capital Receipts	3659*	4102	+12.1	4152	+13.5	4434	+ 6.8
II. Total Disbursements	13492*	14439	+ 7.0	16085	+19.2	17236	+ 7.2
Of which :							
A. Developmental Outlay (a+b)	6560	6933	+ 5.7	7648	+16.6	8248	+ 7.8
(a) Revenue	4778	4971	+ 4.0	5266	+10.2	5847	+11.0
(b) Capital	1782	1962	+10.1	2382	+33.7	2401	+ 0.8
B. Non-Developmental Outlay (a+b)	4526	5045	+11.5	5329	+17.7	5921	+11.1
(a) Revenue	4315	4764	+10.4	5092	+18.0	5650	+11.0
(b) Capital	211	281	+33.2	237	+12.3	271	+14.3
III. Overall Surplus (+)/Deficit (—) (I—II)	—547	—110		—567		—254**	

Notes :

1. Figures are adjusted for inter-Governmental transfers on the basis of data available in the State Government Budgets. The combined overall position, however, remains unchanged.

2. Figures given here are not comparable with those given in the Reports for the years prior to 1973-74 due to changes in budgetary classification adopted in 1974-75. Figures for the year 1973-74 are also presented in this table according to the revised classification. To maintain uniformity, data available for Haryana and Tamil Nadu on the basis of old classification for 1973-74 (Accounts) have been broadly classified into the revised classification.

3. Data do not include the effect of raising the exemption limit for Income tax and the Supplementary Demands for Grants of Centre announced in July 1975.

@Includes effect of Budget proposals. However, the figures of aggregate receipts, revenue receipts and tax receipts for 1974-75 (B.E.) do not include the yield of Rs. 136 crores from the additional tax proposals incorporated in the Finance Bill No. 2 of the Central Government presented to the Parliament on July 31, 1974.

*Excludes P.L. 480 transactions under the Indo-US Agreement, 1974.

**The deficit would go up by Rs. 28 crores if unbudgeted outlay of Rs. 11 crores by Bihar, Maharashtra and Orissa and additional burden on account of higher D.A. of Rs. 17 crores of Kerala is taken into account as no provision has been made for these in their budget.

Rs. 110 crores anticipated in the Central and State Governments' budgets at the beginning of the year (Table 4).

29. Although the size of the Centre's deficit in 1974-75 was much larger than anticipated, it should be pointed out that a sizeable part of it was accounted for by non-inflationary component: viz., the purchase by the Central Government from the Reserve Bank of India foreign exchange resources accruing from IMF drawals for the purpose of imports.

30. The combined total disbursements in 1974-75 were 19.2 per cent higher than in 1973-74; a substantial part of the increase in disbursements was in respect of food subsidy, cash outgo on account of fertiliser transaction, payment of additional dearness allowance to Government employees, increase in the costs of core sector projects, advance Plan assistance to States towards drought relief and financing of an unusually large Railway deficit. The increase in non-developmental expenditure at 17.7 per cent was higher than in the case of developmental expenditure which increased by 16.6 per cent. Total receipts went up by Rs. 2573 crores or by 19.9 per cent over 1973-74. The increase in non-developmental outlay absorbed 31.1 per cent of the increase in total receipts.

⁸ In the case of Centre the deficit is measured by net increase in outstanding Treasury bills and withdrawal from cash balances and in the case of States by decline in cash balances, net sales of securities held by the States in their cash balance investment account, encashment of securities held in revenue reserve funds and net increase in RBI credit in the form of ways and means advances and overdrafts (repayable within 7 working days with effect from May 1, 1972) as presented in State budgets.

Mobilisation of Resources: Central Government⁹

31. Sometime after the Central Budget for 1974-75 was presented in February 1974, it was realised that because of requirements for food subsidies, payment of dearness allowance and drought reliefs, there would be a much larger deficit than anticipated unless steps were taken to mobilise additional resources. The Central Government, therefore, introduced a supplementary budget at the end of July 1974 to mobilise Rs. 136 crores more through additional taxes during the remaining period of the year and Rs. 232 crores in a full year on top of the additional taxation of Rs. 211 crores proposed in the February 1974 budget. Subsequently, a supplementary Railway budget was also introduced which revised freight rates and passenger fares upwards to finance its increasing expenditure. Altogether, the additional resources mobilised by the Centre in 1974-75 are expected to yield Rs. 690 crores¹⁰ in 1974-75 and Rs. 935 crores in a full year (including the effect of changes in Railway passenger fares, freight rates and postal rates). At this rate, over five year period these measures alone will net an amount higher than what is envisaged in the Fifth Plan.

32. Total receipts comprising current receipts, capital transfers, repayments of loans and internal resources of departmental undertakings in 1974-75 at Rs. 7365 crores financed 75.5 per cent of total expenditure in 1974-75. The gap of Rs. 2388 crores between total expenditure and total receipts was financed to the extent of Rs. 847 crores by domestic borrowings and Rs. 916 crores by external borrowings. The remaining amount of Rs. 625 crores was covered by deficit financing¹¹—the magnitude of which was, as already observed, larger than Rs. 125 crores envisaged in the 1974-75 budget estimates and almost double that of Rs. 328 crores in 1973-74.

33. As mentioned earlier, the domestic impact of this deficit would be much less expansionary because of payments

⁹ Figures on the basis of the Economic and Functional Classification of the Central Government budget.

¹⁰ Economic Survey, 1974-75.

¹¹ According to the Reserve Bank records the actual budgetary deficit for 1974-75 amounted to Rs. 697 crores.

for food and fertilizer imports. Further, as part of its overall policy package for demand management, the Government attempted to keep in check disposable consumer incomes by impounding one-half of additional dearness allowance, the entire increases arising from revision of wages and salaries, compulsory deposits for tax payers in higher income brackets and restrictions on declaration of dividends by companies. The deposits so immobilised aggregated, as on June 27, 1975, Rs. 209.6 crores under Dearness Allowance, Rs. 33.1 crores under Additional Emoluments (wage account) and Rs. 56.9 crores under Compulsory Deposit Scheme (Income Tax Payers).

Central Government Expenditure

34. Of the total expenditure of the Central Government at Rs. 9753 crores for 1974-75 (R.E.) the proportion of expenditure for purposes other than capital formation was lower at 63.3 per cent of total expenditure as compared with 67.2 per cent in 1973-74. The total expenditure increase by Rs. 1622 crores or 19.9 per cent over that of 1973-74. The deterioration in the Railway finances also contributed to the increase in the total expenditure of the Centre. The deficit of Railways is estimated at Rs. 144 crores (R.E.) for 1974-75 as against Rs. 53 crores anticipated in the budget and a deficit of Rs. 100 crores in 1973-74. Direct expenditure on consumption and capital formation by the Central Government in 1974-75 increased by Rs. 951 crores over the previous year and financial disbursements to the rest of the economy by Rs. 671 crores. The increase in the former was more under consumption expenditure which at Rs. 2897 crores showed a rise of Rs. 584 crores over that of the previous year and accounted for 61.4 per cent of the rise in direct expenditure. The increase in consumption expenditure was mainly on wages and salaries which accounted for 78.4 per cent of the increase, the remaining 21.6 per cent of the increase being on purchase of commodities and services. Developmental expenditure¹² increased by 30.8 per cent in 1974-75 (Table 5).

¹² According to the Economic and Functional Classification, expenditure on food subsidy and assistance to the States for natural calamities is non-developmental while as per the new accounting classification of the budget adopted from 1974-75, expenditure on these items is treated as developmental.

TABLE 5 :—DEVELOPMENTAL AND NON-DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

					(Amounts in Rupees Crores)					
					1974-75		1974-75		1975-76**	
					(Budget Estimates)		(Revised Estimates)		(Budget Estimates)	
					Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year
					Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total Expenditure (A+B)	8131 (100.0)	+3.6	32993@	6599 (100.0)	8654 (100.0)	+6.4	9753 (100.0)	+19.9	10577 (100.0)	+8.4
A. Developmental Expenditure (i+ii)	3754 (46.2)	-4.9	15756	3151 (47.7)	4244 (49.0)	+13.1	4912 (50.4)	+30.8	5353 (50.6)	+9.0
(i) Social Services	601 (7.4)	-9.5	2385	477 (7.2)	625 (7.2)	+4.0	610 (6.3)	+1.5	705 (6.7)	+15.6
(ii) Economic Services*	3153 (38.8)	-4.0	13371	2674 (40.5)	3619 (41.8)	+14.8	4302 (44.1)	+36.4	4648 (43.9)	+8.0
B. Non-Developmental Expenditure (i+ii)	4377 (53.8)	+12.2	17237	3448 (52.3)	4410 (51.0)	+0.8	4841 (49.6)	+10.6	5224 (49.4)	+7.9
(i) General Services	2452 (30.1)	+5.3	9954	1991 (30.2)	2509 (29.0)	+2.3	2623 (26.9)	+7.0	2810 (26.6)	+7.1
(ii) Unallocable	1925 (23.7)	+22.5	7283	1457 (22.1)	1901 (22.0)	-1.2	2218 (22.7)	+15.2	2414 (22.8)	+8.8

Note :—Figures in brackets are percentages to total expenditure.

@Excludes compensation paid to nationalised banks estimated at Rs. 84 crores and additional subscription to the IMF and IBRD paid in the form of non-negotiable, non-interest bearing rupee securities estimated at Rs. 114 crores during 1970-71.

*Include Block grants and loans.

**Data do not include the supplementary demands for Grants of Central Government announced in July 1975.

Budgetary Resources and Capital Formation

35. Total capital formation expenditure at Rs. 3578 crores out of the budgetary resources rose by 34.3 per cent and constituted 36.7 per cent of the total expenditure in 1974-75 as compared with 32.8 per cent in 1973-74. This is mainly due to a substantial rise of 46.9 per cent in direct gross capital formation expenditure, the major part of which is attributed to increase in inventories, particularly in stocks of foodgrains and fertilizers. Similarly, net direct capital formation or net investment (gross direct fixed capital formation minus expenditure on renewals and replacements plus increase in inventories) at Rs. 1010 crores recorded a substantial rise of 60.6 per cent from Rs. 629 crores in 1973-74. Excluding inventories the gross fixed capital formation rose

by 20 per cent in 1974-75. Financial assistance for capital formation at Rs. 2429 crores during 1974-75 increased by 29.0 per cent from Rs. 1883 crores in 1973-74 (Table 6).

36. Net savings of the Central Government rose to Rs. 669 crores in 1974-75 from Rs. 431 crores in 1973-74. This rise occurred inspite of a decline of Rs. 48 crores in depreciation provision and retained profits of departmental undertakings because the savings of the Government administration rose by Rs. 270 crores to Rs. 726 crores due to higher tax receipts. Net savings were, however, not adequate to finance fully net capital formation and hence the gap between the two widened from Rs. 198 crores in 1973-74 to Rs. 341 crores (Table 7).

TABLE 6 :—EXPENDITURE ON CAPITAL FORMATION BY GOVERNMENT OF INDIA

(Amounts in Rupees Crores)

	1973-74 (Accounts)	Fourth Five Year Plan Total (1969-70 to 1973-74)	Annual Average of the Fourth Plan	1974-75 (Budget Estimates)	1974-75 (Revised Estimates)	1975-76** (Budget Estimates)
1	2	3	4	5	6	7
I. Gross Direct Fixed Capital Formation	711	2857	571	865	856	887
II. Increase in Inventories	71	111	23	3	293	131
III Net Direct Capital Formation (Gross Direct Fixed Capital Formation minus Expenditure on Renewals and Replacements plus Increase in Inventories)	629	2419	484	721	1010	86
IV. Financial Assistance for Capital Formation (a + b + c)	1883	7901*	1580	2226	2429	2913
(a) States and Union Territories	1191	4570	914	1091	1204	1223
(b) Non-Departmental Commercial Undertakings (1 + 2)	593	2761*	552	996	1103	1555
1. Financial Concerns	111	425*	85	190	133	135
2. Others	482	2336	467	806	970	1420
(c) Other Parties@	99	570	114	139	122	135
Total (I+II+IV)	2665	10869*	2174	3094	3578	3931

Note :—In this table expenditure on capital formation is shown on gross basis.

*Excluding compensation paid to nationalised banks estimated at Rs. 84 crores during 1970-71.

@Comprising assistance to local authorities and others.

**Data not include the supplementary demands for Grants of Central Government announced in July 1975.

Centre's Budgets : 13 1975-76

37. In the Centre's Budget for 1975-76 the total expenditure

13 In July 1975 the Central Government raised the exemption limit of income-tax from Rs. 6000 to Rs. 8000 with suitable adjustment of tax rate in certain income brackets. Also, Supplementary Demands for Grants for expenditure amounting to Rs. 285.76 crores were also approved by the Parliament. The effect of these developments is not included in the discussion on the 1975-76 budget estimates of the Central Government.

of the Central Government at Rs. 10577 crores shows a rise of 8.4 per cent during 1975-76 as compared with a rise of 19.9 per cent in 1974-75. Expenditure for developmental purposes at Rs. 5353 crores would be higher by Rs. 441 crores showing a rise of 9.0 per cent as against 30.8 per cent in the previous year. Non-developmental expenditure is anticipated to rise also at a lower rate of 7.9 per cent as against 10.6 per cent in the previous year but this has been made possible by not providing for additional dearness allowance payment to Central Government employees. Consequently, the proportion of developmental expenditure to total has increased marginally from 50.4 per cent in 1974-75 to 50.6 per cent in 1975-76.

TABLE 7 :—SAVINGS OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(Amounts in Rupees Crores)

	1973-74 (Accounts)	Fourth Plan Total (1969-70 to 1973-74)	Annual Average of the Fourth Plan	1974-75 (Budget Estimates)	1974-75 (Revised Estimates)	1975-76* (Budget Estimates)	Percentage of (5) over (1)	Vari- ation Column (6) over (5)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Revenue Receipts of the Government Administration (i+ii)	4828	18995	3799	5290	6057	6709 (6687)	25.5	10.8 (10.4)
(i) Tax Revenue	3876	14820	2964	4278	4882	5436 (5414)	26.0	11.3 (10.9)
(ii) Non-tax Revenue	952	4175	835	1012	1175	1273	23.4	8.3
2. Current Expenditure	4372	17812	3563	4938	5331	5887	21.9	10.4
3. Savings of the Government Administration (1—2)	456	1183	236	352	726	822 (800)	59.2	13.2 (10.2)
4. Depreciation Provision and Retained Profits of Departmental Commercial Undertakings (i+ii)	129	923	185	220	81	244	—37.2	201.2
(i) Depreciation Provision	150	658	132	157	156	162	4.0	3.8
(ii) Retained Profits	—21	265	53	63	—75	82		
5. Gross Savings of the Central Government (3+4)	585	2106	421	572	807	1066 (1044)	37.9	32.1 (29.4)
6. Expenditure on Renewals and Replacements	154	550	110	148	138	156	—10.4	13.0
7. Net Savings (5—6)	431	1556	311	424	669	910 (888)	55.2	36.0 (32.7)
8. Net Investment	629	2419	484	721	1010	862	60.6	—14.7
9. Excess (+) or shortfall (—) of Net Savings over Net Investment (7—8)	—198	—863	—173	—297	—341	48 (26)		
10. Item (3) as per cent of item (1)	9.4	6.2	6.2	6.7	12.0	12.3 (12.0)		

Figures in brackets take into account the effects of tax concessions announced on April 30, 1975.

*Data do not include the supplementary demands for Grants of Central Government announced in July 1975.

38. The Budget envisages a substantial rise in the resources provided for the Plan; they are expected to rise from Rs. 2966 crores in 1974-75 to Rs. 3612 crores—a rise of about 22 per cent. Larger financial allocations for Plan projects have been made on a selective basis, particularly in respect of agriculture and allied services, water and power development and industry and minerals; and the Plan outlay is expected to be up by 23 per cent.

39. Reflecting the deceleration in the growth of total expenditure of the Government the rate of growth of its direct expenditure on consumption and capital formation would be substantially lower at 2.4 per cent as against 30.7 per cent in 1974-75 and that of financial disbursements to the rest of the economy would be only fractionally lower at 12.8 per cent than 13.3 per cent. The rate of growth in the former is estimated to be considerably lower due to a significant decline in expenditure for direct gross capital formation resulting from a lower provision for inventories of foodgrains and fertilizers.

40. Total provision for capital formation at Rs. 3931 crores in 1975-76 is anticipated to be higher by Rs. 353 crores over the level of 1974-75. Capital formation expenditure for developmental purposes at Rs. 3896 crores is anticipated to account for 72.8 per cent of the developmental expenditure as compared to 72.3 per cent in 1974-75.

41. Savings of the Government administration at Rs. 800 crores in 1975-76 are expected to be Rs. 74 crores more than in 1974-75 because the current receipts are expected to be higher than current expenditure. In spite of an increase in expenditure on renewals and replacements, net savings of the Central Government at Rs. 888 crores are expected to be higher than in 1974-75 by Rs. 219 crores mainly due to a positive contribution of Rs. 82 crores by way of retained profits

of departmental undertakings during 1975-76, in marked contrast to a net outgo of Rs. 75 crores in 1974-75. While net savings are thus placed at a higher level in 1975-76, the provision for net investments shows a decline of 14.7 per cent, resulting in excess of the former over the latter.

42. Inclusive of net investment of Rs. 862 crores and net increase in financial assets and capital transfers (Rs. 2324 crores) total net capital expenditure at Rs. 3186 crores is anticipated to be higher by Rs. 129 crores during 1975-76. It is expected to be financed through domestic liabilities to the extent of Rs. 1489 crores and through external liabilities of the order of Rs. 801 crores. Market borrowings at Rs. 325 crores are placed lower than the level of Rs. 495 crores in 1974-75. The budgetary deficit to bridge the gap in expenditure is estimated at Rs. 247 crores¹⁴ in the 1975-76 budget.

Budgetary Operations : State Governments—1974-75

43. The finances of the States may now be briefly discussed. Reserve Bank data indicate a final deficit of Rs. 30 crores for 1974-75. The revised estimates of the State Government budgets for 1974-75, however, indicate a surplus of Rs. 58 crores as compared with a surplus of Rs. 16 crores anticipated in the budget estimates and a deficit of Rs. 219 crores incurred in 1973-74 (Table 8). The final deficit for 1974-75 would have been higher still but for the efforts made by the State Governments for raising additional resources, some economy effected in both Plan and non-plan expenditures and debt relief and additional grants-in-aid given by the Central Government in pursuance of the recommendations of the Sixth Finance Commission.

(14) This takes into account the effects of tax concessions announced on April 30, 1975.

44. The details of final receipts and disbursements are not available. Hence the following analysis has been made in terms of the revised estimates. The measures taken by the State Governments for raising additional resources in 1974-75 budgets as well as in the post-budget period would bring in an additional amount of Rs. 358 crores⁽¹⁵⁾ in 1974-75 and Rs. 540 crores in a full year. As against the additional resource mobilisation of Rs. 1058 crores in the entire Fourth

(15) Inclusive of Rs. 110 crores raised by the State Electricity Boards and Road Transport Corporations. This amount, however, does not get reflected in the States' revenue receipts.

Plan period by the State Governments, the efforts made by them in 1974-75 look quite impressive and over the five year period these might almost yield the Fifth Plan target of Rs. 2550 crores set for the States in this respect. As a result of the substantial resource mobilisation and buoyancy in tax receipts partly on account of the price rise, the States achieved an appreciable growth of 19.0 per cent in their own tax receipts as against the rise of 8.3 per cent anticipated in the budgets. The States' own non-tax revenue increased by 12.2 per cent which was almost the same as that envisaged in the budget estimates. States' own capital receipts rose by as much as 23.1 per cent, though the budgets had anticipated only an increase of 7.2 per cent.

TABLE 8 :—OVERALL BUDGETARY POSITION OF STATES

(Amounts in Rupees Crores)

	1973-74 (Accounts)	1974-75 (B.E.)		1974-75 (R.E.)		1975-76 (B.E.)	
	Amount	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year's revised estimate
	1	2	3	4	5	6	7
I. Aggregate Receipts (A+B)	8052	7946 (8136)	-1.2 (+1.1)	8611	+7.0	9068 (9230)	+5.3 (+7.2)
A. Revenue Receipts (i+ii)	5552	5897 (6087)	+6.2 (+9.6)	6271	+13.0	6800 (6962)	+8.4 (+11.0)
(i) States' Own Revenue Receipts	3452	3622 (3786)	+4.9 (+9.7)	4029	+16.7	4397 (4518)	+9.1 (+12.1)
Of which :							
Tax Receipts	2305	2364 (2497)	+2.6 (+8.3)	2742	+19.0	3001 (3116)	+9.4 (+13.6)
(ii) Resources Transferred from the Centre (a+b)	2100	2275 (2301)	+8.3 (+9.6)	2242	+6.8	2403 (2444)	+7.2 (+9.0)
(a) Shared Taxes	1163	1197 (1223)	+2.9 (+5.2)	1226	+5.4	1324 (1365)	+8.0 (+11.3)
(b) Grants from the Centre	937	1078	+15.0	1016	+8.4	1079	+6.2
B. Capital Receipts (i+ii)	2500	2049	-17.8	2340	-6.4	2268	-3.1
(i) States' Own Capital Receipts	947	1015	+7.2	1166	+23.1	1125	-3.5
Of which :							
Market Borrowings (Gross)	1663 [‡]	265	+59.6	309 [‡]	+86.1	291	-5.8
(ii) Loans from the Centre (Gross)	1553	1034	-33.4	1174	-24.4	1143	-2.6
II. Aggregate Disbursements	8271	8120	-1.8	8553	+3.4	9237	+8.0
Of which :							
(a) Developmental Outlay (i+ii)	4696	4906	+4.5	5081	+8.2	5526	+8.8
(i) Social and Community Services	2428	2443	+0.6	2521	+3.8	2689	+6.7
Of which :							
Expenditure on Natural Calamities	372	71	-80.9	119	-68.0	99	-16.8
(ii) Economic Services	2268	2463	+8.6	2560	+12.9	2837	+10.8
(b) Non-Developmental Outlay	1899	1908	+0.5	1936	+1.9	2205	+13.9
(c) Repayment of Loans to the Centre	934	511	-45.3	506	-45.8	642	+26.9
(d) Loans and Advances to Third Parties	603	574	-4.8	810	+34.3	740	+8.6
(e) Repayment of Market Loans	3 [§]	100		102 [§]		1 [@]	
III. Overall Surplus (+) or Deficit (-) (I-II)	-219	-174 (+16)*		+58		-169† (-7)	

Notes:—1. Data given here are not comparable with those published in earlier Annual Reports except 1973-74 Report due to changes in budgetary classification.

2. In the case of Haryana and Tamil Nadu the data given for 1973-74 (Accounts) on the basis of old classification have been broadly converted into revised classification.

3. Figures in brackets for 1974-75 (B.E.) are after taking into account estimated yield from budget proposals by the States (Rs. 164 crores) and their share in Centre's additional taxation (Rs. 26 crores).

4. Figures in brackets for 1975-76 (B.E.) are after taking into account estimated yield from budget proposals by the States (Rs. 83 crores), their share in Centre's additional taxation (Rs. 41 crores) including the effect of tax concessions announced by the Centre on April 30, 1975 and revision in Central Sales Tax (Rs. 38 crores).

* This does not take into account the States' share in Centre's additional taxation (Rs. 13 crores) proposed in Finance Bill No. 2.

§ In the case of Nagaland figures are as per RBI records.

‡ Includes receipts on account of land compensation bonds in respect of Tamil Nadu.

@ Excludes the figures in the case of Nagaland as details are not available.

† This deficit would go up by Rs. 28 crores if unbudgeted outlay (Rs. 11 crores in respect of Bihar, Maharashtra and Orissa) and additional burden on account of higher D.A. in the case of Kerala, Rs. 17 crores are taken into account for which no provision has been made in the budget.

45. As a result of substantial improvement in States' own resources both on revenue and capital accounts, States could, after meeting their non-developmental expenditure, finance 51.1 per cent of developmental expenditure and loans to third parties for developmental purposes from their own resources during 1974-75 as compared to 44.1 per cent in 1973-74.

46. The net transfer of resources from the Centre to the States in the form of loans, grants-in-aid and shared taxes showed a rise of 7.0 per cent (Rs. 191 crores) as against a decline of 3.8 per cent (Rs. 108 crores) in 1973-74. These transfers constituted 35.9 per cent of total receipts of State Governments in 1974-75 whereas in 1973-74 they accounted for 38.2 per cent of the total.

47. Aggregate disbursements at Rs. 8553 crores were higher only by 3.4 per cent over 1973-74. Non-developmental expenditure at Rs. 1936 crores showed a marginal increase of 1.9 per cent as against an increase of 18.4 per cent in 1973-74. On the other hand, developmental expenditure which had registered an increase of 15.4 per cent in 1973-74 reflected a rise of only 8.2 per cent in 1974-75. The declaration in developmental expenditure in 1974-75 was on account of lower outlay on natural calamities which under the new budgetary classification is treated as developmental expenditure; the expenditure on natural calamities was Rs. 119 crores in 1974-75 as against Rs. 372 crores in 1973-74. Exclusive of expenditure on natural calamities, the rise in developmental expenditure during 1974-75 at 14.8 per cent was more or less the same as in 1973-74.

Budgetary Operations : State Governments—1975-76.

48. Compared to the revised estimates of 1974-75, the budgetary position of State Governments in 1975-76 shows a deterioration; the overall position will change from an apparent surplus of Rs. 58 crores to a deficit of Rs. 7 crores. If the unbudgeted outlay and the additional dearness allowance to Government employees, not provided for by some States in their budgets, are taken into account, it would show a further deterioration. A noteworthy feature of State Governments' budgets for 1975-76 is the stepping up of their Plan outlay by Rs. 594 crores (28.1 per cent) to Rs. 2711 crores.⁽¹⁶⁾ However, this is not matched by greater efforts to raise additional resources. As against the additional resources mobilisation⁽¹⁷⁾ of Rs. 248 crores in 1974-75, the measures announced in 1975-76 are expected to yield only Rs. 83 crores. Besides stepping up of the Plan outlay, the sharp increase in non-developmental expenditure would also strain the budgetary position of State Governments in 1975-76. The budgeted rise in non-developmental expenditure is mainly due to increase in cost of administration, increase in interest payments and higher appropriation for reduction or avoidance of debt.

49. Aggregate receipts of State Governments budgeted at Rs. 9068 crores (at 1974-75 rates of taxation) show an increase of Rs. 457 crores i.e., 5.3 per cent over 1974-75 as against an increase of 7.0 per cent in 1974-75. After taking into account the yield from fresh measures (Rs. 83 crores) as well as the States' share in Centre's additional taxation (Rs. 41 crores), additional revenue on account of upward revision in Central sales tax rates (Rs. 38 crores), the aggregate receipts would show a rise of 7.2 per cent over the preceding year. States' own revenue receipts which had recorded a rise of 16.7 per cent in 1974-75 are budgeted to rise by 12.1 per cent. States' own tax receipts at 1974-75 rates of taxes are expected to show a rise of 9.4 per cent as compared with a rise of 19.0 per cent in 1974-75; inclusive of the yield from fresh measures, the tax receipts would show a rise of 13.6 per cent. The rise in States' own revenue receipts would be offset to the extent of Rs. 41 crores on account of a decline in States' own capital receipts. As regards the transfer of resources from the Centre to States, it may be noted that while States' share in Central taxes and grants would be higher by Rs. 202 crores, the loans (net) would be lower by Rs. 167 crores resulting in a net transfer of resources of Rs. 35 crores.

(16) Including a plan outlay of Rs. 631 crores for the State of Sikkim.

(17) Exclusive of the resources raised by State Electricity Boards and Road Transport Corporations.

50. Aggregate disbursements at Rs. 9237 crores show a sharp rise of Rs. 684 crores (8.0 per cent) as against an increase of Rs. 282 crores (3.4 per cent) in 1974-75. Developmental outlay would go up by 8.8 per cent as compared to a rise of 8.2 per cent in 1974-75. The provision for expenditure on natural calamities has been placed at Rs. 99 crores as compared to Rs. 119 crores in 1974-75. Non-developmental expenditure which had shown a nominal rise of 1.9 per cent in 1974-75, is budgeted to rise by 13.9 per cent. Exclusive of repayment of loans to the Centre, the disbursements would show a rise of Rs. 548 crores. For financing this additional expenditure, the additional resources (net) from the Centre would be only Rs. 35 crores; and the rest would be financed from States' own resources. In spite of the anticipated substantial rise in non-developmental expenditure, States would, however, meet 52.4 per cent of their developmental expenditure and loans for developmental purposes out of their own resources.

51. Thus, the State Governments by raising sizeable additional resources in 1974-75 could impart a better balance to their budgetary position. In 1975-76, although State Governments have already taken measures to raise Rs. 83 crores, they would be required to raise further additional resources to avert any pressure on their budgetary position that might arise on account of additional dearness allowance to Government employees and increase in project costs etc. For raising the additional resources, most of the States have yet to take vigorous steps particularly in respect of resources from the farm sector on the lines of the recommendations of the Raj Committee.

Monetary and Credit Policy

52. The fiscal measures, discussed in the previous section, were reinforced by monetary measures designed to contain inflationary pressures. In this section, an assessment is made of the effectiveness of the various regulatory measures taken in 1974-75 firstly, on aggregate credit expansion and secondly, on the commercial banks' pattern of use of funds and recourse to the Reserve Bank. The cumulative impact of both fiscal and monetary policies is, in the final analysis, reflected in the trends in money supply—an aspect which is taken up for discussion at the end of the section.

Objectives of Credit Policy

53. The principal objectives of credit policy, as before, were that bank credit had to be viewed as a scarce resource and that the use of created money, through recourse to the Reserve Bank to supplement deposits in credit dispensation, had to be kept at a minimum, in terms of both amount and duration of use. To these ends, an indication was given to banks of the broad priorities to be observed in the deployment of credit: the interest rates structure was adjusted upwards and recourse to the Reserve Bank, through both refinancing and rediscount of bills, was allowed almost entirely on a discretionary basis, with the requirements of banks being evaluated individually.

Credit Policy : Slack Season—1974

54. Even at the outset of the slack season of 1974, banks were asked to give prime attention to the liquidation of their obligations to the Reserve Bank, which had increased substantially in the preceding busy season. While the addition of 2 per cent of statutory cash reserves introduced in June 1973 was allowed to expire at the end of June 1974, the minimum statutory liquidity ratio (under section 24 of the Banking Regulation Act) was raised by 1 percentage point, from 32 to 33 per cent of total demand and time liabilities. These requirements of borrowings, liquidation and additional investment did not permit much further scope for credit expansion and it was clearly spelt out that over the slack season period as a whole, no more than 33 to 35 per cent of the additional deposits could be used for increasing credit.

Structure of Interest Rates

55. Before reviewing the trends in credit in the slack season, another important measure taken in the middle of the slack season needs to be underlined. Concerned with the need to check the growth in money and credit, the Reserve Bank announced on July 22, 1974 a general hike in the structure of

interest rates, covering both lending and deposit rates. The Bank Rate was raised by 2 percentage points from 7 per cent to 9 per cent and the minimum lending rate on bank advances from 11 per cent to 12.5 per cent. The minimum rate on advances against commodities covered by selective credit controls was also raised by 2 percentage points. The maximum lending rates applicable to export credit and food procurement advances were also increased from 9 to 10.5 per cent and from 9 to 11 per cent, respectively. Subsequent to the introduction of interest tax, the rates were further revised to 12 per cent in the case of food procurement advances and 11.5 per cent for export credit. The rate on deferred payments exports were also raised from 7 to 8 per cent.

56. The revision of deposit rates had the principal objective of encouraging savings. Hence, while the rate on savings deposits (which was raised by one percentage point in April 1974), was retained at 5 per cent, the rates on various categories of fixed deposits were increased. The increase was 0.5 per cent in respect of short-term deposits but was as much as 2 percentage points for deposits of above 5 years and 1.25 per cent for deposits in the category of 3 to 5 years.

1974 Slack Season Trends

57. Reverting to trends in credit during the slack season, schedules for repayment of obligations were worked out for each bank and compliance closely monitored. It was thus possible to reduce borrowings from the Reserve Bank by Rs. 270 crores, an amount which was more than the increase during the busy season (Table 9). The outstanding amount of bank borrowings from the Reserve Bank was lower at the commencement of the busy season of 1974-75 than in the previous busy season (Rs. 63 crores as against Rs. 80 crores). Banks were asked to reduce the limits of bills rediscounted with the Reserve Bank to about 40 per cent of the outstanding level at the end of the busy season and this was brought about with the the outstandings coming down from Rs. 279 crores to Rs. 108 crores. As a result, gross bank credit recorded a decline of Rs. 99 crores over the slack season period. However, total bank credit (exclusive of bills rediscounted) increased by Rs. 72 crores as against an increase of Rs. 346 crores in 1973. Food advances declined by Rs. 170 crores which meant that other advances (to sectors other than food procurement) increased by Rs. 242 crores. This figure has to be compared with the corresponding increase of Rs. 403 crores in the slack season of 1973 and of Rs. 923 crores in the busy season of 1973-74. Deposits rose during the season by Rs. 914 crores which meant a lower pace (8.8 per cent) of growth than in 1973 (10.3 per cent). The credit-deposit ratio at the end of the season was 68.3 per cent, while in the previous slack season it was precisely one percentage point lower. However, the incremental credit-deposit ratio for the slack season as a whole was only 7.9 per cent which was considerably lower than the indicative limit of 33-35 per cent given at the beginning of the season.

Credit Policy Busy Season 1974-75

58. The main elements of the policy for the busy season of 1974-75 were firstly, an indication of the priorities to be observed in credit deployment and secondly, a further extension of the principle of discretionary lending by the Reserve Bank. Again, in view of the continued need to curb speculative pressures on the prices of sensitive commodities, the structure of selective controls on such commodities was maintained.

59. It was, however, stressed that while the need for overall restraint continued, banks had to assist production and investment with available resources. Certain broad guidelines were given on the priorities to be adopted in extending credit. The building up of an adequate public distribution system for food and the requirements of agricultural credit and exports were to be accorded top priority. In the private industrial sector, units in the "core" sector and those engaged in the production of wage goods were to be given preference. Selectivity was introduced in the small-scale industrial sector also and it was indicated that the extension of scarce bank credit was to be governed not only by the size of the borrowing unit but also by the type of production in which it was engaged. In the public sector, preference was to be given to manufacturing units as against those engaged in trading operations.

Discretionary Accommodation

60. As a part of the overall objective of limiting the use of created money for credit expansion, a portion of the enhanced statutory cash reserves was released, thus augmenting banks' own resources. The minimum statutory balances with the Reserve Bank was reduced from 5 to 4 per cent of demand and time liabilities. This reduction was effected in two instalments of 0.5 per cent each, the first with effect from December 14, 1974 and the second from December 28, 1974. This provided banks with lendable resources of Rs. 120 crores.

61. Automatic access to Reserve Bank funds was further restricted with the extension of the policy of discretionary accommodation to the rediscounting of bills. As before, in respect of borrowings any amount in excess of 1 per cent of a bank's demand and time liabilities (as on the last Friday of September, 1974) was to be allowed at the discretion of the Reserve Bank, at rates determined by the net liquidity ratio. The minimum net liquidity ratio, relevant to borrowings at the Bank Rate was reduced from 40 to 39 per cent but the maximum rate charged on borrowings continued at 18 per cent. The corresponding basic quota for bills was fixed at 10 per cent of the total inland bills purchased and discounted (as on the last Friday of September, 1974). Rediscount limits in excess of this were to be allowed at the Reserve Bank's discretion, not only in regard to amount but in respect of rates of interest also, within the range of 10 to 15 per cent.

62. Special refinance continued to be allowed in respect of credit for public food procurement. However, this was to be limited to 50 per cent of the increase when outstanding food credit rose above Rs. 300 crores and full refinance when the outstanding crossed Rs. 450 crores level. As before, the refinance was allowed without impairment of the net liquidity ratio at a fixed rate of 10 per cent.

63. It may be noted that no indicative ceiling for credit expansion was prescribed for the busy season, as was done in 1973-74. It was felt that the objective of keeping credit expansion to a minimum, while also ensuring the flow of adequate credit for the legitimate needs of production, distribution and investment in accordance with the priorities specified would be better achieved through discussions with individual banks. While detailed discussions on their credit budgets were held separately with each of the banks, close touch was also maintained with the major banks right through the year which enabled the Reserve Bank to have a "feel" of the situation. The strict limitation of automatic recourse to the Reserve Bank and the emphasis placed on discretion in allowing the use of its borrowing facilities added significance to this version of "moral suasion".

64. The effectiveness of the restrictionary credit policy followed throughout the year may be seen in terms of the pace of credit expansion. During the slack season of 1974, as already stated, the increase in total bank credit was lower at only 0.9 per cent as against 5.6 per cent recorded in the previous slack season. Considered in gross terms (i.e., inclusive of bills rediscounted), bank credit in the season recorded an actual decline.

65. During the busy season of 1974-75, gross credit (including bills rediscounted) expanded by Rs. 1009 crores or 12.9 per cent as against Rs. 1355 crores or 20.7 per cent in the corresponding season of the previous year (Table 9). Account has also to be taken of the fact that the increase in food credit during the season amounted to Rs. 317 crores, which was considerably higher than the corresponding increase of Rs. 188 crores in the 1973-74 busy season. Excluding food procurement credit the rate of increase in gross credit was even lower at 9.2 per cent, as against 18.5 per cent in 1973-74. The pace of deposit accretion during the busy season of 1974-75 was slightly lower at 6.3 per cent than the 7.0 per cent increase in the previous year. There was a marked change in the composition of the increase. In 1973-74, about 60 per cent of additional deposits had been in the form of demand deposits. In the 1974-75 season, however, almost the same proportion was accounted for by time deposits, reflecting perhaps a preference for time deposits following the increase in interest rates on fixed deposits. The credit-deposit ratio, at the end of the busy season, stood lower at 72.2 per cent as against 73.7 per cent a year ago.

TABLE 9 :—SEASONAL VARIATIONS IN SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DATA
(Amounts in Rupees Crores)

	Seasonal Variations						Slack Season up to	
	Slack Season 1972	Busy Season 1972-73	Slack Season 1973	Busy Season 1973-74	Slack Season 1974	Busy Season 1974-75	August 1, 1975@	August 2, 1974
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Aggregate Deposits	+705	+811	+899	+677	+914	+714	+800	+624
(a) Demand	+262	+335	+251	+407	+300	+292	+368	+294
(b) Time	+443	+476	+648	+270	+614	+422	+432	+330
2. Bank Credit	+67	+897	+346	+1111	+72	+950	+204	+199
Of which								
(a) Public Food Procurement Advances	—1	+5	—57	+188	—170	+317	+137	+45
(b) Other Advances	+68	+892	+403	+923	+242	+633	+67	+154
3. Inland Bills purchased and discounted by the Reserve Bank of India	—10	+19	+15	+244	—171	+59	—107	—48
4. Gross Bank Credit (2+3)	+57	+916	+361	+1355	—99	+1009	+97	+151
5. Investments in Government and other approved securities	+620	+4	+282	+157	+472	+269	+275	+269
(a) In Government Securities	+519	+89	+187	+73	+349	+223	+138	+190
(b) In other approved Securities	+101	+93	+95	+84	+123	+46	+137	+79
6. Cash and Balances with R.B.I.	+57	+60	+444	—214	+144	—98	+68	+60
(a) Cash in hand	+27	+20	+25	+4	+21	+12	—4	—11
(b) Balances with R.B.I.	+30	+40	+419	—218	+93	—110	+72	+71
7. Money at Call and Short notice	+13	+72	—41	—96	+61	+29	—13	+26
8. Borrowings from R.B.I.	—16	+17	+56	+253	—270	+183	—191	—122
Credit-Deposit Ratio (end-season)	66.2	70.3	67.3	73.7	68.3	72.2	69.3	71.3
Credit (Excluding food procurement)—Deposit Ratio (end-season)	62.6	67.0	64.9	69.6	66.1	67.4	63.7	67.0
Investment-Deposit Ratio (end-season)	36.3	33.0	32.9	32.2	33.8	34.0	34.1	32.8

Notes : 1. Data are based on weekly returns submitted by banks under section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India, which are based on weekly borrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India.

2. The variations are based on the last Friday figures on April and October.

@ Provisional.

Overall Assessment : 1974-75

66. During the year July 1974—June 1975, seen as a whole, the pattern of use of funds was very different from the previous year. Deposit growth was only marginally higher, in terms of amount (Rs. 1606 crores as against Rs. 1591 crores) and lower in terms of percentage (14.9 per cent as against 17.4 per cent). The increase in bank credit, on the other hand, was much lower, at Rs. 1105 crores or 14.1 per cent as against Rs. 1446 crores or 22.6 per cent in 1973-74. In terms of the growth in gross credit the increase was even lower at only 11.8 per cent as against 26.5 per cent in the previous year. On the other hand, both borrowings and bills rediscounted recorded a decline during 1974-75 as against an increase in the previous year. In other words, while Reserve Bank facilities were a net source of funds in 1973-74, in 1974-75 the liquidation of such obligations was one of the uses to which available funds were put. This is also reflected in the incremental credit-deposit ratio which was 68.8 per cent in 1974-75 as against 90.9 per cent in the previous year.

Borrowings : Busy Season

67. The peak level of total recourse to the Reserve Bank (in terms of both refinance and rediscount) touched during the busy season was Rs. 656 crores. This was not only lower than the previous season's peak of Rs. 698 crores, but it was also brought down substantially to Rs. 413 crores at the close of the season, while in the previous year the reduction was less sharp, to Rs. 612 crores. A further point of significance relates to the composition of refinance. The peak level of borrowings from the Reserve Bank during the 1974-75 busy season was touched at Rs. 473 crores of which Rs. 227 crores was given on account of food procurement credit, while a further Rs. 22 crores was the special refinance allowed in respect of credit to oil companies. In the previous busy season, the borrowings at Rs. 422 crores consisted of Rs. 42

crores for food procurement and Rs. 16 crores on account of oil. Thus, the extent of support that had to be provided for nonspecified purposes was much lower than in the last busy season.

Bills Rediscounted with the Reserve Bank

68. Another notable feature is the smaller use made of the rediscounting facility during the past busy season. In the 1973-74 busy season, additional assistance from the Reserve Bank was almost equally divided between borrowings and rediscount (Rs. 253 crores and Rs. 244 crores, respectively). In 1974-75, however, only about a quarter of the incremental use of Reserve Bank facilities was through rediscount (Rs. 59 crores as against Rs. 183 crores by way of borrowings). This could be attributed to the streamlining of the terms of the facility during the year. While the promotion of a genuine trade bill market and the use of bill financing in preference to the cash credit system has been and continues to be an objective of long-term policy, it was also considered necessary to prevent the use of the preferential treatment accorded to bills as a means of circumventing overall credit restraint. Hence, in June 1974, a distinction was made between drawees' and drawers' bills, with a higher minimum rate in respect of the former. It was further stipulated that the rate of interest on drawees' bills should be on par with the rate of interest on the cash credit accommodation extended to the same borrower. This was done to prevent bill finance for inventory purchase being cheaper than that under the cash credit system. At the time of the upward revision of the minimum lending rate in July, 1974, the minimum rate on drawees' bills was raised to 12.5 per cent and that on drawers' bills to 11 per cent. Further, a return flow of Reserve Bank funds utilised through rediscount of bills was ensured by the requirement that the outstandings of bills rediscounted should be reduced by 40 per cent during the slack season. To ensure the proper use of the rediscount facility, the 1974-75 busy season policy placed this almost wholly on a discretionary basis.

Sectoral Pattern of Credit: Busy Season 1974-75

69. The sectoral deployment of credit during the 1974-75 busy season shows a broad compliance with the priorities specified (Tables 10 and 11). The most prominent feature is the larger share, as compared to the previous busy season, of food credit. Credit for public food procurement accounted for as much as 31.2 per cent of the total increase in gross credit in the 1974-75 busy season as against only 13.3 per cent in the busy season of 1973-74. The share of the priority sectors in 1974-75 busy season (19.7 per cent) was also larger than in the previous busy season (15.4 per cent). Among the priority sectors, the larger increase in agriculture is especially significant, accounting for 8.4 per cent of the total credit as against 2.4 per cent. The smaller share of small-scale industry (7.9 per cent in 1974-75 busy season as against 11.2 per cent in the previous busy season) resulted among other things from the qualitative check on advances to this

sector. Also significant is the decline in the share of export credit. This, however, is not to be taken as a symptom of the neglect by banks of the export sector. Other reasons could be attributed to this decline. The reduction, since last year, of the duration for which preferential credit may be extended to exports has had the desired effect of a faster circulation of the credit used by the sector, which would naturally be reflected in a reduction in the outstanding level on any particular date. Further, it could be argued that the present level of export credit is adequate to sustain the current quantum of exports. With the annual value of exports at around Rs. 3200 crores, an outstanding figure of credit at about Rs. 750 crores represents, roughly, an average turn-round of credit every 3 months, which is in keeping with the limit set by policy for the availability of credit at preferential rates. However, in view of the crucial importance of exports, certain relaxations in the duration of credit at preferential rates have now been allowed, in terms of the slack season credit policy announced on May 8, 1975.

TABLE 10 :—SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT
(Including Bills Rediscounted with the Reserve Bank of India)

(Amounts in rupees crores)

	Variations During					
	BUSY SEASON 1973-74			BUSY SEASON 1974-75		
	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
	1	2	3	4	5	6
1. Public Food Procurement Credit	+187 (49.3)	—	+187 (13.3)	+306 (68.6)	—	+306 (31.2)
2. Priority Sectors (including Export Credit)	+13 (3.4)	+203 (19.8)	+216 (15.4)	+8 (1.8)	+186 (34.7)	+194 (19.7)
(a) Small scale Industries	+4 (1.0)	+154 (15.0)	+158 (11.2)	+1 (0.2)	+77 (14.4)	+78 (7.9)
(b) Agriculture	+8 (2.1)	+25 (2.4)	+33 (2.4)	+7 (1.6)	+76 (14.2)	+3 (8.4)
(c) Other Priority Sectors	+1 (0.3)	+24 (2.4)	+25 (1.8)	—	+33 (6.1)	+33 (3.4)
3. All Other Sectors* (including export credit)	+179 (47.2)	+824 (80.2)	+1003 (71.3)	+132 (29.6)	+350 (65.3)	+482 (49.1)
4. Non-Food Credit (2+3)	+192 (50.7)	+027 (100.0)	+1219 (86.7)	+140 (31.4)	+536 (100.0)	+676 (68.8)
5. Of item 4—Export Credit	+42 (11.1)	+179 (17.4)	+221 (15.7)	+9 (2.0)	—22	—13
6. Total Gross Credit (1+4)	+379 (100.0)	+1027 (100.0)	+1406 (100.0)	+446 (100.0)	+536 (100.0)	+982 (100.0)

*Includes large and medium industries and wholesale trade.

Notes: 1. Figures in brackets are proportions to Gross Bank Credit.

2. This table is based on data collected from 59 major banks. Hence the figures of total credit are not strictly comparable with the figures in the previous table.

TABLE 11.—SECTORAL DEPLOYMENT OF OUTSTANDING GROSS BANK CREDIT
(Including Bills Rediscounted with the Reserve Bank of India)

(Amounts in Rupees Crores)

	As on April 26, 1974			As on April 25, 1975		
	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
	1	2	3	4	5	6
1. Food Procurement Credit	423.3	0.5	423.8	564.1	..	564.1
2. Priority Sectors (including Export Credit)	136.9	1665.1	1802.0	149.8	2000.3	2150.1
(a) Small scale Industries	8.4	918.2	926.6	7.7	1035.2	1042.9
(b) Agriculture	121.5	477.3	598.8	136.4	648.6	785.0
(c) Other Priority Sectors	7.0	269.6	276.6	5.7	316.5	322.2
3. All other Sectors* (including Export Credit)	722.6	4881.3	5603.9	970.5	5101.8	6072.3
4. Non-Food Credit (2+3)	859.5	6546.4	7405.9	1120.3	7102.1	8222.4
5. Of item 4—Export Credit	94.8	740.0	834.8	90.1	659.3	749.4
6. Gross Bank Credit (1+4)	1282.8	6547.0	7829.8	1684.4	7102.1	8786.5

*Includes large and medium industries and wholesale trade.

Note : This table is based on data collected from 59 major banks. Hence the figures of Gross Bank Credit are not strictly comparable with the figures in Table No. 9.

Credit Policy : Slack Season—1975

70. Turning to credit policy for the slack season 1975 no major change in policy was effected at the close of the conventional busy season of 1974-75. As in the previous year, banks were asked to bring down their indebtedness to the Reserve Bank in stages. While the basic refinance quota of 1 per cent of demand and time liabilities was continued for the slack season period, it was stressed that this should not be viewed as a resource for credit expansion but as a temporary recourse to be used only when unavoidable. In respect of rediscount, greater manoeuvrability was allowed, with scope for minimal additional discretionary accommodation over and above the basic quota. The special refinance for food procurement was allowed at the busy season formula (50 per cent of the increase in the credit between the levels of Rs. 300 crores and Rs. 450 crores and full refinance thereafter) but it was indicated that this extent of support might not continue in the next busy season.

71. The general structure of controls remained unchanged. In laying stress on the continuing need for restraint, banks were told to plan their operations in such a way that for the year 1975-76 (May-April) as a whole credit expansion would be limited to around 63 to 64 per cent of the accretion to deposits. The importance of export credit was reiterated and some relaxations in the terms of credit were announced, as referred to earlier. Formerly banks were allowed to charge "normal" rates of interest on pre-shipment credit for outstandings in excess of 90 days. It was now directed that in such cases the rate may be increased by not more than 2 per cent for a further period of 45 days. Also, the duration of the application of the concessionary rate for pre-shipment credit was increased from 90 to 180 days in the case of specified medium and heavy engineering goods. When factors beyond the control of the exporter require an even longer period for pre-shipment credit, banks were asked to charge not more than 2 per cent over the ceiling rate for a further period of 90 days. The list of categories eligible for these benefits covers forty-four export items.

72. The priorities to be observed in credit deployment, indicated earlier were reiterated with special emphasis on the financing of fertilizer distribution. In view of the need to stimulate investment, banks were also asked to increase their involvement in term-lending for high priority projects. But it was made clear that this was to be done out of the banks' own resources and in keeping with the policies governing term-lending.

1975 Slack Season Trends

73. The trend in the current slack season thus far (August 1, 1975) has been satisfactory. Deposit growth continues to be at relatively higher pace. The increase so far has amounted to Rs. 800 crores (6.7 per cent) as against Rs. 624 crores (6.0 per cent) in the corresponding period of last year. The preference for time deposits continues to be prominent. While in the corresponding period of 1974 time deposits constituted 53 per cent of the increase in deposits, in the current season, they accounted for 54 per cent of the total increase. The expansion in bank credit at Rs. 204 crores (up to August 1, 1975) was marginally higher compared to Rs. 199 crores in the corresponding period of the previous year. The increase in food procurement advances at 137 crores is much larger than the increase of Rs. 45 crores recorded last year. Due to a larger decline in bills rediscounted with the Reserve Bank, the increase of Rs. 97 crores in gross bank credit was much smaller than Rs. 151 crores recorded last year. When gross bank credit is adjusted for procurement advances, there is a decline of Rs. 40 crores as against an increase of Rs. 106 crores in the corresponding period of the 1974 slack season. Borrowings from the Reserve Bank have declined by Rs. 191 crores as compared to Rs. 122 crores in 1974.

Credit Policy and Implementation**Interest Rates : Instrument of Policy**

74. As a summing up, the main features of credit policy implementation over the past two years may be indicated: three aspects are discussed, namely, emergence of interest rate as an instrument of credit policy, better inventory control and discretionary element in Reserve Bank lending. The most striking feature is the emergence, in an inflationary context of interest rate as an important instrument of monetary

management. As outlined earlier, the overall structure of interest rates has been levered up to a considerable extent in 1974-75. This has been done with the twin objectives of imparting discipline in the use of credit and aiding deposit mobilisation. One of the prominent aspects of inflationary psychology is the attraction that the expectation of price increase gives to the accumulation of inventories. It is of vital importance in a scarcity economy that, apart from physical controls on distribution, the cost of holding goods should be maintained at a sufficiently high level so as to discourage this tendency. At the same time, it is of equal importance that the return on bank deposits should not be allowed to drop to such unattractive levels, in real terms, as to affect the pace of deposit growth. These factors have been kept in view in the formulation of recent policy. The impact of higher deposit rates may be seen in the pronouncedly higher rate of increase in time deposits as against demand deposits. The rate of interest generally charged on loans by banks on most categories of borrowers is higher than the minimum lending rate prescribed. The latest data on the distribution of credit according to interest charged, from the Basic Statistical Returns for June 1974, show that as on the last Friday of that month, when the prescribed minimum lending rate was 11 per cent, as much as 33.8 per cent of all larger loans and advances (i.e., with credit limits of over Rs. 10,000) were at rates higher than 12 per cent. In June 1973, on the other hand, the corresponding proportion was only just over 3 per cent. A further increase in the effective lending rate following the imposition in August 1974 of a tax of 7 per cent on the interest income from bank loans, which has pushed up the cost of credit by about one per cent. The raising of the cost of credit seems to have induced the desired effect of reducing demand for credit.

Inventory Control

75. Cost rises in credit cannot be entirely expected to bring about the desired changes in inventories: in fact banks have been taking more direct action in effecting better inventory control. The Study Group appointed by the Reserve Bank to establish inventory norms has made interim recommendations in respect of the norms to be followed in making advances against raw materials, finished goods and receivables for ten major industries. Banks have been asked to apply these norms and report on their practical experience. In cases where credit already extended is in excess of the recommended norms, it has been suggested that banks should arrive at an agreement with borrowers for a phased programme of reduction. Apart from this, the general tightness of credit has underlined the importance of close pre-sanction scrutiny and post-sanction follow-up. Both banks and borrowers in the public as well as private sectors, have come to understand this in growing measure and the general standard of financial discipline has improved considerably.

Discretionary Element in Reserve Bank Lending

76. Yet another aspect of the development of policy relates more directly to the "weapons" of a central bank. The arrangements in regard to the use of Reserve Bank facilities and the growing emphasis on the discretionary element have imparted a special significance to the "lender of the last resort" function of the Reserve Bank. This use of discretion makes for a degree of flexibility necessary to assist the flow for essential purposes, while retaining overall restriction. Alongside this, the Reserve Bank has also taken the leading role in arranging for the flow of an adequate quantum of credit to vital sectors and even to major individual borrowers usually through the formation of formal or informal consortia. In the past such arrangements were made for food procurement, oil companies and certain key units in the public sector. In the year under review, the minimum requirements of the jute industry and trade and fertilizer distribution were also assessed and sought to be met.

77. The overall trend has been towards greater selectivity in the actual operation of general policy. This has given to the banks a degree of awareness of the importance of planning their credit operations. For its part, the Reserve Bank has, in the past two years, given advance intimation of the expectations of the monetary authority in regard to the overall trends in banking. Thus, banks have been told of the limits of their incremental credit-deposit ratio over a twelve month period and also given an idea of the extent of Reserve Bank assistance that could be expected. While these are, no doubt, only broad indications and subject to revisions in keeping with changing requirements, they do

provide some guidelines to banks for planning operations. Thus, a beginning has been made in shifting from seasonal to annual credit plans. Banks too are becoming increasingly aware of the need to shift from the "micro" or account-wise approach to the "macro" or sector-wise approach for overall planning purposes. The need to build up an effective internal management information system in each bank cannot be overstressed. The Reserve Bank is taking steps to formulate guidelines to assist banks in this regard.

Trends in Money Supply

78. The trends in money supply in 1974-75 demonstrate the cumulative impact of restrictionary fiscal and monetary policies pursued during the year. During the period July, 1974 to June 1975, money supply with the public recorded a small rise of Rs. 725 crores or 6.3 per cent, as compared with the level of 1973-74; the rise was less than one-half of the rise of Rs. 1488 crores or 14.9 per cent witnessed during the previous year (See Tables 12 and 13). Such a deceleration in money supply in 1974-75 from the previous year's rate of 14.9 per cent to only 6.3 per cent is a remarkable achievement indeed, especially when viewed against the background of the 2 per cent real growth recorded by the economy during the year. In point of fact, this is the lowest rate of expansion witnessed during the last fourteen years.

79. More impressive was the trend in one component of money supply, namely, currency: the increase in currency in 1974-75 was only Rs. 159 crores or 2.4 per cent in contrast to a sharp rise of Rs. 774 crores or 13.3 per cent witnessed during the previous year. Demand deposits showed an increase of Rs. 566 crores or 11.7 per cent as against an expansion of Rs. 714 crores or 17.3 per cent in the previous year.

80. The decelerating trend holds true even if one were to use the concept of broad money⁽¹⁸⁾ the expansion in aggregate monetary resources at Rs. 1832 crores or 10.2 per cent in 1974-75 was decidedly smaller than that of Rs. 2454 crores or 15.9 per cent witnessed in 1973-74—this notwithstanding the fact that time deposits growth at Rs. 1107 crores was marginally higher than Rs. 968 crores during 1973-74.

⁽¹⁸⁾ Broad money refers to aggregate monetary resources which comprise money supply with public and time deposits held by banks.

TABLE : 12—TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES (ANNUAL)

(Amounts in Rupees crores)

	Outstanding at the end of June				Variations
	1973	1974	1975	1973-74	
	1	2	3	4	5
A. Monetary Supply with the Public (1+2)	9962	11450	12175	+1488	+725
				(+14.9)	(+6.3)
1. Currency with the Public	5829	6603	6762	+774	+159
				(+13.3)	(+2.4)
2. Demand Deposits	4133	4847	5413	+714	+566
				(+17.3)	(+11.7)
B. Factors affecting Money Supply Variations (1+2+3+4—5)					
1. Net Bank Credit to Government (a+b)	8416	9102	10491	+686	+1389
(a) Reserve Bank's Net Credit to Government	6149	6570	7515	+421	+945
(b) Other Bank's Credit to Government	2268	2532	2976	+264	+444
2. Bank Credit to Commercial Sector (a+b)*	7580	10014	11242	+2134	+1228
(a) Reserve Bank's Credit to Commercial Sector	290	652	625	+362	—27
(b) Other Bank's Credit to Commercial Sector	7590	9362	10617	+1772	+1255
3. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	601	683	310	+71	—362
4. Government's Net Currency Liabilities to Public	482	521	543	+39	+22
5. Non-Monetary Liabilities of Banking Sector (a+b+c)	7409	8870	10411	+1450	+1552
(a) Time Deposits with Banks	5491	6459	7566	+968	+1107
(b) Net Non-Monetary Liabilities of RBI	1143	1474	1955	+331	+481
(c) Residual	783	926	890	+143	—36
C. Aggregate Monetary Resources (A+B5(a))	15455	17909	19741	+2454	+1832

*Includes advances made to Public Sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

TABLE 13 :—MONETARY RESOURCES

Year (July-June)	KEY INDICATORS						KEY RATIOS	
	Currency	Bank money [£]	Money Supply	Time Deposits	Aggregate Monetary Resources	Reserve Money	Currency to Money Supply	Currency to Monetary Resources
Outstanding as on last Friday (Rs. crores)							Average Ratios (Per cent)	
1971-72	4979	3544	8523	4476	12999	5604	58.4	38.3
1972-73	5829	4133	9962	5491	15454	6743	58.5	37.7
1973-74	6603	4847	11450	6459	17909	7575	57.7	36.9
1974-75*	6762	5413	12175	7566	19741	7656	55.5	34.3
Increase over previous year (Rs. crores)							Marginal Ratios (Per cent)	
1971-72	388	673	1061	816	1877	570	36.6	20.7
1972-73	850	589	1439	1015	2454	1139	59.1	34.6
1973-74	774	714	1488	968	2454	841	52.0	31.5
1974-75*	159	566	725	1107	1832	72	21.9	8.7
Percentage variation over the year								
1971-72	8.5	23.4	14.7	22.3	16.9	11.3		
1972-73	17.1	16.6	16.9	22.7	18.9	20.3		
1973-74	13.3	17.3	14.9	17.6	15.9	12.5		
1974-75*	2.4	11.7	6.3	17.7	10.2	0.9		

*Provisional.

£Including other deposits with RBI.

Factors Affecting Money Supply

81. Although the earlier discussion on fiscal and monetary policies provides the broad explanation of deceleration in money supply, a more precise analysis in terms of factors affecting money supply appears warranted. In this context, three major factors may be analysed, namely, net bank credit to the Government sector, bank credit to the commercial sector and net foreign exchange assets of the banking system. It is clear from the data in Table 12 that the increases in both Reserve Bank's and commercial bank's credit to Government were larger than those in the previous year: the increase in Reserve Bank's credit to Government in 1974-75 was Rs. 945 crores⁽¹⁰⁾ as compared with Rs. 421 crores and the increase in commercial banks' credit was Rs. 444 crores as against Rs. 264 crores. The increase in bank credit to the commercial sector was significantly lower at Rs. 1228 crores as compared with the last year's expansion of Rs. 2134 crores. The expansionary impact of credit of the banking system to the Government and the commercial sector was, however, moderated by a sizeable decline by Rs. 362 crores in the net foreign exchange assets of the banking sector: during the year 1973-74, the net foreign exchange assets had actually shown a rise of Rs. 71 crores. Thus the fall in foreign exchange assets acted as the single largest depressant of money supply in 1974-75.

82. There is yet another factor which had a contractionary impact on money supply, namely, non-monetary liabilities of the banking sector: there took place in 1974-75 a larger net increase in these liabilities of Rs. 1552 crores as compared with an increase of Rs. 1450 crores during the last year. Among the components of these liabilities time deposits and net non-monetary liabilities of RBI showed a relatively larger increase.

83. At this stage, a specific explanation for the extremely smaller rate of currency expansion during 1974-75 is necessary. Currency expansion in 1974-75 at Rs. 159 crores was nearly one-fifth of the expansion of Rs. 774 crores witnessed during the previous year. The explanation is not far to seek and in fact is linked to the significant decline in the

foreign exchange assets of the banking system referred to above. A sizeable part of the foreign exchange was utilised for financing imports of food, fertilizers and fuel—which alone accounted for the bulk of the increase in the country's import bill for the year 1974-75 (For details see the Section—"Role of the External Sector"). The eventual sale of these goods/commodities to the public helped in siphoning off a sizeable amount of currency in circulation. The raising of the domestic retail prices, during the year, of food, fertilizers, petrol and kerosene, further assisted the process of withdrawal of currency. In other words, the drawing down of foreign exchange not only assisted in slowing down monetary growth in general but more specifically, as a consequence of the use to which the bulk of foreign exchange was put, brought about a sharp fall in the rate of expansion of currency.

Slack Season—1974

84. The impact of restrictionary fiscal and monetary policies on money supply may be somewhat blurred in the trends for the year as a whole partly because of the overlapping of the financial and accounting year. Such impact would be more clearly discernible if the trends are analysed separately for the slack and busy seasons. For the first time since 1969, the slack season of 1974 was characterised by an actual decline in money supply with the public (See Table 14). The contraction in money supply of the order of Rs. 159 crores during the slack season of 1974 contrasts sharply with an actual increase of Rs. 322 crores witnessed during the slack season of 1973. The contraction in 1974 is wholly attributable to a decline in currency with the public of the order of Rs. 444 crores. On the other hand, the increase in deposit money was somewhat larger. In terms of factors affecting money supply, the two factors which provide an explanation for contraction in money supply are: a fall in the net foreign exchange assets of the banking sector of Rs. 150 crores and a rise in non-monetary liabilities of the banking sector of Rs. 699 crores. The contractionary impact of these factors was partly off-set by rise in net bank credit to the Government of Rs. 527 crores and bank credit to the commercial sector of Rs. 171 crores.

Busy Season 1974-75

85. During the busy season 1974-75, money supply with the public recorded a rise of Rs. 838 crores: the order of expansion was about two-thirds of the expansion of Rs. 1219 crores witnessed during the busy season 1973-74. Both the

(10) Even here, as has been pointed out earlier, a sizeable part of the Reserve Bank's credit to Government in 1974-75 was attributable to a non-inflationary component. (See the Section—Fiscal Policy and Demand Management).

components i.e., currency and deposit money showed relatively smaller rises. In terms of factors affecting money supply, increases in both Reserve Bank's credit and the commercial banks' credit to the Government were much higher at Rs. 578 crores and Rs. 221 crores, respectively, as compared with the corresponding rises of Rs. 193 crores and Rs. 74 crores, during the busy season of 1973-74. On the other hand, expansion in bank credit to the commercial sector was significantly lower at Rs. 1180 crores, as compared with Rs. 1451 crores. Again, a sharp decline of Rs. 130 crores in net foreign exchange assets and a substantial rise of Rs. 1043 crores in non-monetary liabilities exerted a contractionary impact on money supply.

The Price Situation

86. The year 1974-75 marked a departure from the uninterrupted phase of price rise which had commenced since March 1972. It may be recalled that even the seasonal decline in prices, particularly agricultural commodity prices, to which the Indian economy is traditionally accustomed, did not take place during the last two years. It is in this sense that

restoration of the traditional pattern of prices during 1974-75 may be taken as an indication of the move of the economy towards normalcy.

87. What is more, it has been possible in 1974-75 to moderate the upward thrust in prices. The monthly average level of prices (Wholesale Price Index : 1961-62=100) recorded a rise of 16.9 per cent in 1974-75 in contrast to a rise of 25.3 per cent in 1973-74. The contrast becomes sharper if a point-to-point comparison is made : between end-June 1974 and end-June 1975, wholesale prices showed only a nominal rise of 0.6 per cent as against a rise of as much as 27.8 per cent (Table 15), during the comparable period of the previous year. The price situation as it emerged in 1974-75 may thus be said to reflect the cumulative impact of effective implementation of restrictionary monetary and fiscal policies. Further, these policies were buttressed by a number of administrative measures taken to curb hoarding and smuggling. The year 1974-75 thus offered some respite from the unprecedented rate of inflation which corroded the economy in 1973-74.

TABLE 14 :—TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES (SEASONAL)

(Amounts in Rupees crores)

	Variations during			
	Slack Season		Busy Season	
	1973	1974	1973-74	1974-75
A. Money Supply with the Public (1+2)	+322	—159	+1219	+838
1. Currency with the Public	+96	—444	+783	+508
2. Demand Deposits	+227	+286	+435	+331
B. Factors affecting Money Supply Variations (1+2+3+4—5)				
1. Net Bank Credit to Government (a+b)	+603	+527	+267	+799
(a) Reserve Bank's Net Credit to Government	+412	+168	+193	+578
(b) Other Banks' Credit to Government	+191	+359	+74	+221
2. Bank Credit to Commercial Sector (a+b)*	+588	+171	+1451	+1180
(a) Reserve Bank's Credit to Commercial Sector	+54	—76	+290	+134
(b) Other Banks' Credit to Commercial Sector	+534	+247	+1160	+1047
3. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+7	—150	+77	—130
4. Government's Net Currency Liabilities to the Public	+26	—7	+19	+31
5. Non-Monetary Liabilities of Banking Sector (a+b+c)	+903	+699	+595	+1043
(a) Time Deposits with Banks	+681	+647	+295	+436
(b) Net Non-monetary Liabilities of RBI	+60	+64	+206	+433
(c) Residual	+162	—12	+94	+176
C. Aggregate Monetary Resources (A+B5(a))	+1003	+488	+1514	+1272

*Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

TABLE 15 :—TRENDS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES : PERCENTAGE VARIATIONS

(BASE : 1961-62=100)

Group/Sub-Group/Commodity	Weights*	Percentage Variations between							
		1973-74				1974-75			
		End-June 1973 and Sep-tember 22, 1973	Sep-tember 22, 1973 and April 6, 1974	April 6, 1974 and End-June 1974	End-June 1973 and End-June 1974	End-June 1974 and Sep-tember 21, 1974	Sep-tember 21, 1974 and April 5, 1975	April 5, 1975 and End-June 1975	End-June 1974 and End-June 1975
All Commodities	1000	+3.7	+14.1	+8.0	+27.8	+7.0	-7.4	+1.5	+0.6
I. Food Articles	413	+4.6	+7.9	+11.6	+26.0	+8.6	-8.3	+3.4	+2.9
Foodgrains	(35.8)	+4.4	+16.1	+12.6	+36.6	+15.6	-11.1	+1.1	+3.8
(a) Cereals	(29.3)	+4.7	+16.7	+15.8	+41.4	+14.3	-8.3	+1.0	+5.9
(i) Rice	(16.2)	+9.1	+15.8	+8.1	+36.7	+12.6	-9.9	+8.9	+20.4
(ii) Wheat	(7.8)	..	+18.1	+40.3	+65.7	+17.3	-7.1	-10.3	-2.3
(iii) Jowar	(2.2)	+0.5	+9.2	+18.2	+29.7	+11.0	-6.5	-1.8	+1.9
(iv) Bajra	(1.1)	-24.0	+12.2	+18.0	+0.7	+27.4	+13.4	-7.4	+33.6
(b) Pulses	(6.5)	+3.8	+14.3	+2.9	+22.0	+19.8	-20.3	-1.2	-3.4
II. Liquor and Tobacco	25	-0.1	+9.9	+12.6	+23.9	+0.4	+1.3	+2.3	+4.1
III. Fuel, Power, Light and Lubricants	61	+2.3	+59.2	-0.2	+62.4	+3.3	+1.0	+0.5	+4.8
IV. Industrial Raw Materials	121	-1.3	+9.3	+5.6	+13.8	+6.5	-20.8	-1.8	-17.1
(i) Cotton Raw	(18.5)	+7.2	+25.9	+6.9	+44.3	+14.5	-31.9	-3.5	-24.8
(ii) Jute Raw	(9.6)	-17.3	-6.6	+7.6	-16.9	+43.7	-18.9	+8.7	+26.7
(iii) Oilseeds	(43.3)	-2.6	+6.0	+8.1	+11.6	+4.3	-21.7	-2.5	-20.3
(iv) Groundnuts	(20.8)	-13.8	-2.4	+11.8	-5.9	+4.2	-14.2	+2.0	-8.8
V. Chemicals	7	+1.7	+28.4	+4.8	+36.9	+4.7	+9.2	+0.5	+14.9
VI. Machinery and Transport Equipment	79	+2.1	+21.6	+7.7	+33.7	+11.2	+2.3	+0.7	+14.5
VII. Manufactures	294	+6.3	+18.8	+4.7	+32.2	+4.8	-3.8	-0.2	+0.6
(a) Intermediate Products	(19.5)	+10.2	+19.5	+8.6	+43.0	-2.2	-11.2	+1.2	-12.1
(b) Finished Products	(80.5)	+5.0	+18.5	+3.5	+28.9	+7.3	-1.4	-0.7	+5.1
Textiles	(38.6)	+5.2	+20.6	+1.3	+28.7	+6.5	-5.8	-1.5	-1.2
(i) Cotton Manufactures	(26.8)	+2.9	+14.1	+6.0	+24.4	+5.5	-3.3	+0.3	+2.2
(ii) Jute Manufactures	(8.1)	+8.5	+42.9	-7.7	+43.1	+15.0	-14.2	-6.9	-8.2
Metal Products	(13.0)	+6.2	+17.2	+0.2	+24.6	+9.3	+3.6	..	+13.2
Chemical Products	(9.2)	+4.4	+19.8	+14.2	+42.8	+4.2	+7.7	-0.9	+11.1

*Figures in brackets refer to the percentage distribution of the weightage assigned to the respective main groups.

Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Industrial Development, Government of India.

88. The price trend during the year 1974-75 could be more meaningfully analysed in three distinct phases: the first phase between end-June upto the third week of September 1974, when wholesale prices recorded a rise of 7 per cent; the second phase commencing from 21st September 1974 to 5th April 1975 when prices declined by 7.4 per cent, and the third phase after the first week of April 1975 when the prices resumed their upward trend and showed a rise of 1.5 per cent.

Price Trends : June—September 1974

89. During the first quarter of the year, the index of wholesale prices recorded a rise of 7 per cent (upto September 21) on top of the increase of 27.8 per cent recorded during the whole year of 1973-74. The extent of the rise was even larger than the 3.7 per cent rise witnessed during the comparable period of 1973-74. The price rise was shared by all major commodity groups, the more conspicuous among which were 'Food Articles' (8.6 per cent) and Machinery and Transport Equipment (11.2 per cent). Under the group 'Food Articles' prices of almost all foodgrains recorded increases ranging between 11.0 per cent (jowar) and 27.4 per cent (bajra). The shortfall in production of bajra and wheat during 1973-74 provides in part an explanation for the sharp increase in foodgrains prices; the inadequacy of sub-

ply stemming from lower output of wheat was accentuated by changes in Government's procurement policy for the 1974-75 marketing season which ultimately resulted in hoarding of grains at the village level, thereby reducing market arrivals. Cumulatively, these developments led to a disappointingly low level of procurement and a sharp rise in the open market wheat prices. The rise in prices of 'Machinery and Transport Equipment' partly reflected Government's action in respect of administered prices and partly the impact of higher prices of raw materials, fuel and power. Among commodities showing a substantial rise in prices during the period were raw cotton (14.5 per cent) and raw jute (43.7 per cent). The rise in raw cotton prices, despite better crop prospects, may be attributed to sustained mill demand for medium staple cotton for fulfilling obligations in respect of production of controlled cloth; in the case of raw jute, the price rise was largely influenced by reports of heavy damage of the crop due to floods.

Seasonal Decline : September 1974 to April 1975

90. The decline in prices between September 21, 1974 and April 5, 1975 was quite widespread, but it was particularly prominent in respect of 'Industrial Raw Materials' (20.8 per

cent), followed by 'Food Articles' (8.3 per cent) and 'Manufactures' (3.8 per cent). Although the phenomenon of price decline could be considered broadly as seasonal in character, it was unique in some respects. Firstly, such seasonal declines did not take place in the last two years, particularly in 1973 when the crop prospects were decidedly better in point of fact prices rose by 5 per cent and 14 per cent during the corresponding periods of 1972-73 and 1973-74; secondly, although the wheat crop was expected to be larger in 1974-75, there were indications that the overall level of foodgrains production during the year would not be any higher than in 1973-74. It is also significant that among 'Food Articles', prices of all cereals except bajra recorded declines ranging between 6.5 per cent and 9.9 per cent, and prices of pulses declined by 20.3 per cent. Despite prospects of lower output of groundnuts, prices of groundnuts and groundnut oil also declined by 14.2 per cent and 10.2 per cent, respectively. Restrictions on the use of groundnut oil in the manufacture of vanaspati and a significant rise in market arrivals were the two factors responsible for the decline. Prices of raw cotton and raw jute also declined sharply by 31.9 per cent and 18.9 per cent, respectively. In the case of cotton, restricted mill demand due to imposition of power-cuts, especially in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, together with heavy selling pressures arising out of increased arrivals of cotton at the terminal markets brought about the decline; further, consumer resistance to high prices of cotton textiles seems to have led to accumulation of stocks and the consequent curtailment of production in some cases. In respect of raw jute (including mesta), although the overall availability was estimated somewhat lower at 85 to 89 lakh bales, prices declined partly as a corrective to the high prices prevailing upto September and partly as a result of reduction in mill consumption of raw jute as a lagged impact of strike in the jute industry during January 6, 1975 to February 22, 1975; an equally important factor was the sagging external demand for jute manufactures.

Resumption of Price Rise : April to June 1975

91. The rise of 1.5 per cent in the price index between April 5, and end-June, 1975 may again be considered as partly seasonal; it was largely accounted for by a rise of 3.4 per cent in prices of 'Food Articles'. On the other hand, the group 'Industrial Raw Materials' showed a decline of 1.8 per cent. Even under 'Food Articles' only rice prices edged up by 8.9 per cent; prices of wheat on the other hand, declined by 10.3 per cent. At this stage, it needs to be underlined that although prices have resumed an upward trend after the first week of April 1975, the extent of the rise is much smaller; for instance, the rise of only 1.5 per cent between April 5, to end-June, 1975 is negligible compared with the rises of 8.0 per cent and 10.1 per cent witnessed during the corresponding periods of 1974 and 1973, respectively.

Consumer Prices

92. Reflecting the trend in Wholesale Price Index, the All India Consumer Price Index (1960=100) for Industrial Workers recorded a much smaller increase of 8.6 per cent between June 1974 and May 1975, as compared with 26.2 per cent during the same period of 1973-74. The Consumer Price Index for Urban non-Manual Employees (1960=100) rose between June 1974 and March 1975 by 8.2 per cent as compared with 12.8 per cent in the same period of 1973-74.

Savings and Investment

Overall Trends : Savings

93. Although fuller data regarding savings and investment in the economy in 1974-75 are not yet available, on the basis of preliminary data, it is possible to indicate the broad trends. It must be, however, cautioned that these estimates may undergo significant revision when detailed data become available. The data set out in Table 16 below show that the ratio of domestic saving to national income declined significantly from 12.1 per cent in 1973-74 to 11.8 per cent in 1974-75. The decline in saving was mainly accounted for by household sector. The decline in household sector saving was offset to some extent by the public sector saving, which has increased. Reference has already been made to the fact that net saving of the Central Government rose from Rs. 431 crores in 1973-74 to as much as Rs. 669 crores in 1974-75. The private corporate sector appears to have increased its share in total saving substantially.

TABLE 16:—DOMESTIC SAVINGS AND INVESTMENT : PERCENT OF NET NATIONAL PRODUCT AT CURRENT PRICES (PROVISIONAL ESTIMATES)*

Item	Financial year (April-March)		
	1972-73	1973-74	1974-75
1. Domestic Saving (Net)	12.6	12.1	11.8
2. Inflow of Foreign Resources (Net)	0.8	0.8	2.0
3. Aggregate Investment (Net) (1+2)	13.4	12.9	13.8

*Because of reclassification of budgets of State Governments and other revisions, that estimates are not strictly comparable with the estimates published earlier.

Investment and External Resources

94. The decline in domestic saving, however, does not seem to have affected aggregate investment in the economy which, in fact, showed a marginal increase. Substantial inflow of foreign resources was able to sustain the rate of investment in the economy: the size of inflow has been estimated at 2.0 per cent of net national product in 1974-75 in contrast to 0.8 per cent in the previous year. This factor is one of the indicators of the support afforded by external sector to the domestic economic growth during the year 1974-75.

Public Sector's Draft on Private Savings

95. The public sector's (Governments including Government enterprises) draft on household sector financial savings (gross) in the form of market borrowings, net claims on Government, State Provident Funds, negotiated loans from LIC, borrowings from commercial banks and currency expansion amounted approximately to Rs. 2043 crores in 1974-75 as against Rs. 2587 crores in 1973-74: this decline is mainly attributable to a significantly smaller expansion in currency in 1974-75 than that in 1973-74⁽²⁰⁾.

96. A word about Governments' market borrowings. The combined net receipts of the Centre and States from market borrowings amounted to Rs. 708 crores in 1974-75 as against Rs. 638 crores raised in 1973-74. Of this rise of Rs. 70 crores in 1974-75, the share of the Centre was Rs. 23 crores and of the States Rs. 47 crores. During 1974-75, the Centre entered the market on three occasions and raised Rs. 495 crores on a net basis. While the first floatation was a cash-cum-conversion offer, the other two floatations were wholly based on cash subscriptions. State Governments raised Rs. 213 crores on a net basis in two floatations. In the first floatation States raised Rs. 130 crores on a cash-cum-conversion basis while in the second floatation which was wholly on a cash basis, the amount raised was Rs. 83 crores.

Role of the External Sector

97. If one central theme runs through the discussion so far of the growth of the economy in 1974-75, it is the move towards stability of the economy; and this is in no small measure attributable to the significant role that the external sector has played. In the first place the year 1974-75 seems to have ended up with a massive balance of payments deficit, the magnitude of which cannot be precisely assessed in the absence of data, and thanks to the sizeable inflow of foreign exchange resources it was possible to finance the deficit without a serious depletion of our own reserves. Secondly, since the economy continued to be threatened by food shortages, sizeable imports of foodgrains became necessary and this in itself exerted a stabilising influence on the monetary and price trends. These two aspects may now be taken up for detailed discussion.

Trade and Payments Position

98. According to DGCI & S data, the trade deficit during the fiscal year 1974-75 widened to about Rs. 1096 crores—a size which is more than double the deficit of Rs. 402 crores⁽²⁰⁾ In these calculations no adjustment has been made for possible transfers from the public sector to private sector nor are net inflow of foreign resources taken into account.

for 1973-74. Although the growth in exports at 29 per cent was impressive, imports rose at an even faster rate of 49 per cent. The large increase in the value of imports was primarily attributable to imports of fuel, food and fertilizers. Quadrupling of oil prices since early 1974 had affected only a part of the payments in 1973-74 but its full impact was felt in 1974-75. Further, not only were imports of foodgrains larger in volume but the import prices were also higher. This held true in respect of fertilizers also. Finally, according to available indicators, the price increase in respect of imports tended on an average to be higher than that in the case of exports, resulting in a deterioration in our terms of trade. Data for the period April to December 1974 indicate that the terms of trade worsened by about 21 per cent.

Exports

99. For fiscal year 1974-75, exports are estimated to have reached a record level of about Rs. 3253 crores. Commodity-wise details of exports, however, are available upto Febru-

ary 1975 and these indicate that during the first eleven months of 1974-75 (April-February), exports totalled Rs. 2345 crores as against Rs. 2143 crores in the corresponding period of 1973-74 (Table 17). Although the rise in exports was spread over a wide front, the largest increase occurred in sugar accounting for a little more than one-fourth of the net increase during the eleven month period. The rise was significant also in engineering goods (machinery and transport equipment, manufacture of metals and other engineering goods), jute manufactures, silver, tea, clothing, cashew kernel, crude animal and vegetable materials comprising mainly shellac and guar flour. While the steep rise in exports of sugar and engineering goods emanated from significant increases in both the quantum and unit value, the larger realisation in respect of other products was mainly due to the higher unit values. In the case of silver, the ban on exports imposed in 1943 was lifted with effect from February 19, 1974. There was a sizeable decline in the export of some important products, viz., oilcakes, leather and leather products and fish and fish preparations which was in contrast to the overall trend in exports.

TABLE 17 : —INDIA'S PRINCIPAL EXPORTS

Commodities	April to February			(Amounts in Rupees crores)	
				Increase (+)/ Decrease (—) of (3) over (2)	
	1973-74	1973-74	1974-75	Actual	Percentage
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Food and Live Animals	666	584	868	+284	+49
1. Fish and Fish preparations	88	76	59	—17	—22
2. Cashew Kernel	74	72	111	+39	+54
3. Coffee	46	42	50	+8	+19
4. Tea (Black)	142	131	199	+68	+46
5. Spices	55	43	54	+11	+26
6. Oilcakes	171	149	86	—63	—42
7. Sugar	43	34	256	+222	+653
II. Beverages and Tobacco	71	60	76	+16	+27
Tobacco unmanufactured	68	58	74	+16	+28
III. Crude Materials, Inedible except Fuels	357	305	376	+71	+23
1. Cotton (raw and waste)	37	32	16	—16	—50
2. Mica	13	12	16	+4	+33
3. Iron Ore (including concentrates)	133	118	135	+17	+14
4. Crude, animal and vegetable materials n.e.s.	73	62	108	+46	+74
IV. Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials	15	12	18	+6	+50
V. Animal and Vegetable Oils and Fats	31	29	34	+5	+17
Vegetable Oils	31	29	33	+4	+14
VI. Chemicals	57	46	93	+47	+102
VII. Manufactured Goods	988	859	1052	+193	+22
1. Leather and leather manufactures	171	149	132	—17	—14
2. Cotton textiles	235	207	201	—6	—3
3. Jute manufactures@	227	209	281	+72	+34
4. Pearls and precious and semi-precious stones unworked or worked	108	89	80	+9	+10
5. Iron and Steel	58	49	73	+24	+49
6. Silver (bullion bar)	6	..	65	+65	..
VIII. Machinery and Transport Equipment	117	94	185	+91	+97
1. Machinery other than electrical	47	39	79	+40	+102
2. Electrical machinery, apparatus and appliances	29	24	50	+26	+108
3. Transport equipment	41	31	56	+25	+81
IX. Miscellaneous Manufactured Articles	173	147	210	+63	+43
1. Clothing	95	80	117	+37	+46
2. Footwear	13	12	18	+6	+50
Total Exports (including others)	2483	2143	2919	+776	+36

@Includes yarn and thread.

Source : DGCI & S.

100. Direction-wise, there was expansion in value of exports to all regions. However, as a proportion of total exports, the share of USA, the ECM countries and Japan together declined from 52 per cent in the first eleven months of 1973-74 to 42 per cent in the first eleven months of 1974-75. The U.S.S.R. emerged as the largest market, taking its place from Japan which had ranked first last year. However, the share of East European countries remained unchanged at around 21 per cent. Thus the proportion of India's exports to free currency countries remained almost unchanged.

Imports

101. During the fiscal year 1974-75 India's imports rose substantially to Rs. 4349 crores recording a rise of Rs. 1423

crores or 49 per cent over the level during 1973-74. The steep increase in imports was principally due to considerably higher prices abroad of a number of commodities and in particular of foodgrains, fertilizers and petroleum goods. Commodity-wise details of imports available for the ten months of 1974-75 show that the high import bill was due to higher imports of both food and non-food items (Table 18). Major items which showed substantial net increases were wheat (Rs. 218 crores), minerals, fuels, lubricants and related materials (Rs. 560 crores), chemicals including fertilizers (Rs. 281 crores), iron and steel (Rs. 211 crores) and machinery and transport equipment (Rs. 82 crores). The net increase in the total value of imports of these five items taken together accounted for almost the entire increase in total imports. Imports of petroleum, crude and partly refined and fertilizers increased nearly three-fold, while imports of wheat nearly doubled.

TABLE 18 : —INDIA'S PRINCIPAL IMPORTS

Commodities	April to January			(Amounts in Rupees Crores)	
	1973-74	1973-74	1974-75	Actual	Increase (+)/ Decrease (—) of (3) over (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Food and Live Animals	547	428	623	+195	+ 46
1. Wheat	346*	267	485	+218	+ 82
2. Cashewnuts	29	21	34	+ 13	+ 62
II. Beverages and Tobacco	Neg.	Neg.	1	+ 1	—
III. Crude Materials, Inedible except Fuels	184	147	177	+ 30	+ 20
Cotton raw, other than linters	52	49	22	— 27	— 55
IV. Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials	561	370	930	+560	+151
1. Petroleum, crude and partly refined	417	267	770	+503	+188
2. Petroleum products	143	102	160	+ 58	+ 57
V. Animal and Vegetable Oils and Fats	65	55	35	—20	— 36
V. Chemicals	352	268	549	+281	+105
1. Chemical elements and compounds	105	84	145	+ 61	+ 73
2. Medicinal and pharmaceutical products	26	21	28	+ 7	+ 33
3. Fertilizers manufactured	162	105	317	+212	+202
VII. Manufactured Goods	531	408	627	+219	+ 54
1. Iron and Steel	243	182	339	+211	+165
2. Non-ferrous metals	140	103	151	+ 48	+ 47
VIII. Machinery and Transport Equipment	629	488	570	+ 82	+ 17
1. Machinery other than electrical	417	328	340	+ 12	+ 4
2. Electrical machinery, apparatus and appliances	124	91	124	+ 33	+ 36
3. Transport equipment	88	69	105	+ 36	+ 52
IX. Miscellaneous Manufactured Articles	41	32	37	+ 5	+ 16
Total Imports	2921	2192	3559	+1367	+ 62

* Imported on loan basis from the U.S.S.R.

Sources : DGCI & S.

102. About one-third of India's total imports was accounted for by Iran, the U.S.S.R. and Japan, the respective shares of these countries increased during the first ten months of 1974-75 and formed about 10—11 per cent. The share of East European Countries in India's imports was 15.3 per cent during April-January 1974-75 and India enjoyed a nominal trade surplus with this region. This is indicative of the fact that bulk of the trade deficit of the country during April-January 1974-75 was with the free currency countries.

Inflow of External Resources

103. The massive payments deficit was financed primarily by draws from the IMF which aggregated Rs. 485 crores during 1974-75: the drawings were made up of gold tranche of Rs. 72.2 crores, first credit tranche of Rs. 220.3 crores and drawings under the oil facility of Rs. 192.1 crores; in 1973-74 the only draw from the IMF amounted to Rs. 62 crores and was made under its export compensatory financing fac-

ility. Further, the net inflow of external assistance at Rs. 480 crores in 1974-75 was nearly double the figure of Rs. 254 crores for 1973-74. Clearly without the contribution of this massive dose of external finance, the impact of monetary and fiscal policies to containing rate of growth of money supply would have been much less effective.

104. The size of the trade deficit is reminiscent of the years 1966-67 and 1967-68 when the deficit ranged between Rs. 750 to Rs. 950 crores. In other words, the pendulum seems to be swinging back after an interregnum of smaller deficits ranging between Rs. 99 crores to Rs. 430 crores, to a period of larger deficits. What is really worrying is that at least a sizeable slice of the deficit is ascribable to sustaining domestic consumption-levels.

Salutary Impact on Prices

105. The impact of larger inflow of foreign resources was also reflected on domestic prices. Relatively larger imports of

foodgrains in 1974-75 meant larger availability of foodgrains, which factor itself acted as a restraint on price expectations. Further, in the context of a disappointing performance on the food procurement front, the public distribution system would have practically collapsed but for larger imports which in fact accounted for as much as one-half of the total quantum distributed. The second aspect relates to the eventual impact that larger imports of petroleum, foodgrains and fertilizers produced on primary money—an aspect which has already been discussed elsewhere. In other words, larger imports of petroleum, foodgrains and fertilizers, by assisting in restraining monetary expansion exerted, though indirectly, a salutary impact on prices.

Outlook for Growth : 1975-76

106. Finally, an attempt may be made to assess, in broad terms, the prospects for growth in 1975-76.

107. There are several indicators which suggest that the economy is poised for faster growth in 1975-76. To begin with, the industrial sector is geared to achieve a higher growth rate in 1975-76, thanks largely to the recovery staged in infra-structure industries. With the favourable rains so far the power situation in many States has shown a significant improvement and this coupled with the easing of transport bottlenecks should promote better capacity utilisation. Timely rains have also brightened the prospects for a good kharif crop; adequate availability of other agricultural inputs like fertilisers and seeds has reinforced this prospect. The Plan outlay for 1975-76 has been raised by 23 per cent to Rs. 5978 crores; since, generally public sector investment sets the pace for private investment such a significant set-up in outlay should have a salutary impact on private sector investment.

108. Further, the declaration of emergency on the 26th June, 1975 and the new economic programme announced on the 1st July, 1975 have imparted a new sense of direction to the economy. This is reflected, in the industrial sector, in the creation of harmony in industrial relations and also in the signs of revival of the otherwise depressed capital market. In the fiscal sphere, tightening of tax administration might result in higher revenue receipts. In the rural sector, measures relating to liquidation of rural indebtedness with a moratorium on recovery of debt, effective implementation of land ceilings, improvement in the conditions of landless labourers might provide the necessary environment for attaining higher agricultural production.

109. The impact of the emergency is more pronounced on the price situation, consequent on effective measures taken against hoarding and smuggling. Wholesale prices witnessed a decline of 1 per cent between June 28 and July 19, 1975 : during the corresponding period of 1974 prices had actually recorded an increase of 2.4 per cent. More importantly, the Index number of Wholesale Prices on 19th July, 1975 was lower by 2.7 per cent as compared to the level a year ago. This element of price stability is likely to be sustained in view of the announcement that a sizeable quantity of foodgrains would be imported during 1975-76 with a view to maintaining the public distribution system as also to building up a buffer stock. Both monetary and fiscal policies would continue to be geared to demand management. On the whole, the outlook for 1975-76, therefore, is one of a 5 or 6 per cent growth attainable against the background of price stability.

110. On the external front, the outlook for exports is fairly clear : with the cooling off of the world commodity boom, it will be unrealistic to expect the export buoyancy experienced during the current year to repeat itself in 1975-76. It is true that industrial countries are expected to begin recovering from recession during the latter half of 1975, but this factor alone is unlikely to have any significant impact on Indian exports. Special measures would, therefore, be needed if the minimum annual rate envisaged of export growth of 8 to 10 per cent, in terms of volume, is to be achieved. Of course, some measures like improved arrangements for supply of inputs of export production and simplifying procedures for import licences have already been taken to boost exports.

111. It is not unlikely that import payments might show a marginal rise, notwithstanding the recent easing of the

world prices of foodgrains and fertilizers. However because of large purchases by other countries in world markets, this trend in food prices may not be sustained for long. Hence there would be some advantage in concluding a programme of food imports early. Oil prices may witness a marginal rise, if not stay stable. On the whole, therefore, the trade deficit in 1975-76 may widen somewhat and the foreign resources gap may turn out to be as large as in 1974-75, if not large. The outlook for foreign aid appears bright : besides availability from IMF under the 'Oil Facility', total pledges of commitments by Aid India Consortium amount to \$ 1775 million. Further-more, the disbursements in 1975-76 from the Consortium pipeline are also likely to be relatively higher. Thus availability of foreign resources may not prove to be a constraint on growth in 1975-76.

112. Turning to medium-term growth prospects, the recent trend in savings and investment, in real terms, has been disappointing and hence the central problem in the coming years would be one of raising the level of aggregate investment, without at the same time reducing the effectiveness of anti-inflationary policies. This involves on the one hand further strengthening resource mobilisation efforts and on the other enlarging investment in core sectors like agriculture and agriculture-related industries, fuel and power, and export sectors. It is possible for the public sector to set the tone for overall investment by giving impetus in respect of such investments both through direct participation and through adoption of policies designed to promote large investments and better capacity utilisation in the private sector. In fact in some sub-sectors of industry in which slackness of domestic demand is acting as a deterrent to growth, more vigorous fiscal measures including rationalisation of excise and tariff structure may have to be considered, if the achievement of the basic objective of providing adequate employment opportunities is not to be impaired. Given such a policy-mix and the sustenance of the present sense of discipline it should not be difficult to ensure a sustained annual growth of 5.5 per cent in the remaining years of the Fifth Plan.

113. The fact that medium-term growth prospects are encouraging, should not be construed to mean that there is scope for relaxing the present restrictionary monetary and credit policies. If the twin objectives of containing inflation and promoting balance of payments viability are to be achieved, the apparatus of monetary and fiscal discipline, so assiduously built-up in 1974-75, needs to be maintained. This implies that in terms of fiscal measures the accent will have to be on cutting down unproductive and unnecessary expenditure. A good beginning towards economy in expenditure has already been made which needs to be sustained. The emphasis will have to be tilted in favour of productive and income-yielding expenditure. In terms of monetary management, this implies further sharpening of the tools of credit planning designed to deploy credit to priority and productive sectors. It is only such an approach whereby fiscal and monetary restraint reinforce each other, that can provide a degree of price stability.

II. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING

114. The overall progress of commercial banking during the year ended June 1975 was satisfactory. Although the growth in aggregate deposits of scheduled commercial banks decelerated from 17.4 per cent in 1973-74 to 14.9 per cent in 1974-75, it was possible to sustain the rate of growth of time deposits. The expansion in bank credit no doubt was relatively lower in 1974-75 than that during the previous year, reflecting effective implementation of a tighter credit policy. The branch expansion programme made further inroads into unbanked areas. Qualitatively, distinct progress was evident in the deployment of credit to priority sectors. In the implementation of credit policy, among other instruments, the Credit Authorisation Scheme and the scrutiny of credit limits of major borrowers also played an important role. Further, judged in terms of profitability, the performance was impressive, with both public and private sector banks showing a remarkable rise in profits.

Branch Expansion Programme

115. The programme of branch expansion by commercial banks in a planned and systematic manner was further intensified during the year. The emphasis was, as in the past, on progressive reduction of regional imbalances in respect of

banking facilities. It may be recalled that banks were advised earlier to draw up rolling plans for the three-years period commencing from 1972. Under the plan drawn up for 1974, banks received permission by the Reserve Bank to open 993 offices in various States; besides, out-side the plan, new offices were also permitted to be opened in the normal course against individual bank's applications. To maintain the tempo of branch expansion in future years, a target of 5000 branches has been fixed for the three years 1975, 1976 and 1977 and banks have been asked to submit detailed plans for opening offices in 1975 and tentative plans for 1976 and 1977. Banks have been asked to ensure that a large number of offices would fall in the unbanked/underbanked rural and semi-urban areas, unbanked block/taluka/tehsil headquarters and underbanked districts/States, so that the inter-State and inter-district disparities in respect of banking facilities are reduced. Most of the banks have submitted their plans for the year 1975 and permission has already been granted to open about 1695 new offices from out of proposals so far scrutinised/considered by the Bank.

116. During the calendar year 1974, commercial banks opened 1693 new offices in India raising the total number of bank offices to 18,180 at the end of December 1974. In the result, the average population per bank office has been further reduced. At the end of June 1969, the national average of population per bank office was 65,000 (1961 census); this average came down progressively to 33,000 at the end of December 1973 (1971 census) and to 30,000 at the end of

December 1974 (1971 census) and further to 29000 at the end of June 1975. Nevertheless, in 8 out of the 30 States and Union Territories, population per bank office is still above 50,000 (1971 census) and in fact above 1 lakh in the case of Manipur and Mizoram. Special efforts are, therefore, being made to open more bank offices in these States/Union Territories.

117. Taking the year 1974-75 (July-June), commercial banks opened 1803 offices as against 1593 offices opened during the last year (Table 19). Of these new offices, 492 were opened by the State Bank of India and its subsidiaries, 851 by the nationalised banks, 459 by private sector Indian banks and 1 by Sonali Bank (Bangladesh).

Unbanked Centres

118. The year also witnessed further progress in regard to territorial spread of banking; of the 1803 offices opened during the year, 547 were at the hitherto unbanked centres. The progress achieved becomes all the more impressive if the period since nationalisation of the 14 banks is considered as a whole; of the 10468 offices opened during the period July 1969 till the end of June 1975, as many as 5202 offices (49.6 per cent) were in unbanked centres. The underbanked States of Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal accounted for 31.6 per cent of the total number of new offices (Table 20).

TABLE 19 :—NEW OFFICES OPENED BY COMMERCIAL BANKS DURING 1973-74 AND 1974-75

Bank Group	New Offices opened by Commercial Banks						Bank Offices as on				
	1973-74			1974-75							
	July-Dec. 1973	Jan.-June 1974	July-June 1973-74	July-Dec. 1974	Jan.-June 1975	July-June 1974-75	June 30, 1969	June 30, 1973	June 30, 1974	Dec. 31, 1974	June 30, 1975
1. State Bank of India	135 (42)	73 (23)	208 (65)	311 (128)	93 (49)	404 (177)	1569	2867	3072	3382	3475
2. Subsidiaries of SBI	64 (23)	25 (8)	89 (31)	58 (21)	30 (6)	88 (27)	893	1563	1652	1710	1739
3. Fourteen Nationalised Banks	697 (263)	212 (55)	909 (318)	607 (187)	244 (55)	851 (242)	4133	8109	9017	9621	9863
4. Other Scheduled Banks	250 (90)	128 (42)	378 (132)	264 (55)	180 (33)	444 (88)	3120	2580	2943	3206	3385
5. Foreign Banks	—	—	—	1 (—)	—	1 (—)	130	130	130	131	131
6. All Scheduled Commercial Banks	1146 (418)	438 (128)	1584 (546)	1241 (391)	547 (143)	1788 (534)	8045	15249	16814	18050	18593
7. Non-Scheduled Commercial Banks	3 (1)	6 (1)	9 (2)	8 (6)	7 (7)	15 (13)	217	113	122	130	137
8. All Commercial Banks	1149 (419)	444 (129)	1593 (548)	1249 (397)	554 (150)	1803 (547)	8262	15362	16936	18180	18730

Note :—Figures in brackets relate to number of offices opened at un-banked centres.

TABLE 20 :—STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1973, JUNE 1974 AND JUNE 1975

State	No. of Offices as at the end of				Opened during 1973-74 (July-1973 to June 1974)	Of which un-banked centres	Opened during 1974-75 (July 1974 to June 1975)	Of which un-banked centres	Population per bank office (in thousands) as at the end of		
	June 1973	June 1974	December 1974	June 1975					June 1974	December 1974	June 1975
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Andhra Pradesh	1103	1234	1338	1373	131	48	142	42	35	32	32
Assam	168	184	207	214	16	8	28	10	81	71	68
Bihar	593	672	755	796	179	36	126	66	84	75	71
Gujarat	1320	1436	1525	1552	116	25	117	18	18	18	17
Haryana	338	390	425	438	52	17	48	21	26	24	23

TABLE 20 :—STATE-WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1973, JUNE 1974 AND JUNE 1975—(Contd.)

State	No. of Offices as at the end of				Opened during 1973-74 (July-1973 to June 1974)	Of which un-banked centres	Opened during 1974-75 (July 1974 to June 1975)	Of which un-banked centres	Population per bank office (in thousands) as at the end of		
	June 1973	June 1974	December 1974	June 1975					June 1974	December 1974	June 1975
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Himachal Pradesh	136	159	176	181	26	17	22	9	22	20	19
Jammu & Kashmir	139	164	174	189	26	9	26	7	28	27	24
Karnataka	1479	1621	1700	1750	143	59	130	26	18	17	17
Kerala	1072	1163	1247	1296	89	37	133	46	19	17	16
Madhya Pradesh	748	820	882	914	80	28	95	27	51	47	46
Maharashtra	1866	2005	2144	2188	140	19	183	44	25	24	23
Manipur	9	9	10	10	—	..	1	..	119	107	107
Meghalaya	17	18	21	21	1	1	3	2	56	48	48
Nagaland	6	7	8	8	1	..	1	1	74	65	65
Orissa	225	255	291	301	30	16	46	26	86	75	74
Punjab	772	869	937	961	97	57	93	34	16	14	14
Rajasthan	664	743	775	792	79	33	49	14	35	33	33
Tamil Nadu	1650	1784	1880	1935	134	36	152	35	23	22	21
Tripura	14	18	20	20	4	2	2	1	86	78	78
Uttar Pradesh	1497	1673	1823	1896	177	57	223	94	53	48	47
West Bengal	882	987	1059	1090	108	35	103	20	45	42	41
Andaman & Nicobar Islands	4	5	5	5	1	1	23	23	23
Arunachal Pradesh	5	6	7	7	1	1	1	1	78	67	67
Chandigarh	41	44	52	53	3	1	9	..	6	5	5
Dadra & Nagar Haveli	4	4	4	4	19	19	19
Delhi	455	502	548	563	50	..	61	..	8	7	6
Goa, Daman & Diu	125	133	136	140	8	4	7	2	6	6	6
Lakshadweep	4	4	4	4	8	8	8
Mizoram	1	1	1	1	332	332	332
Pondicherry	25	26	26	28	1	..	2	1	18	18	16
Total	15,362	16,936	18,180	18,730	1,593	547	1,803	547	32	30	29

119. More specifically, the thrust by banks into rural areas has been sustained as reflected in the data regarding centre-wise distribution of commercial bank offices set out in Table 21. The proportion of bank in rural areas to the

total had risen from 35.3 per cent at end-June 1972 to 36.2 per cent at end-June 1973 ; the proportion rose further to 36.4 per cent as at the end of June 1974 and June 1975.

TABLE 21 :—CENTRE-WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES

Centre	Number of Offices as at the end of											
	June 1969	% to Total	June 1971	% to Total	June* 1972	% to Total	June 1973	% to Total	June 1974	% to Total	June 1975	% to Total
1. Rural	1832	22.4	4279	35.6	4814	35.3	5561	26.2	6165	36.4	6806	36.4
2. Semi-Urban	3322	40.1	4016	33.4	4385	32.2	4723	30.8	5089	30.0	5570	29.7
3. Urban	1447	17.5	1778	14.8	2323	17.1	2573	16.7	2899	17.1	3266	17.4
4. Metropolitan/Port-town	1661	20.0	1940	16.2	2100	15.4	2505	16.3	2783	16.5	3088	16.5
Total	8262	100.0	12013	100.0	13622	100.0	15362	100.0	16936	100.0	18730	100.0

* Re-classified on the basis of 1971 census population figures.

Notes : Rural Centre : Places with population upto 10,000

Semi-Urban Centres : Places with population over 10,000 and upto 1,00,000

Urban Centres:

(a) Metropolitan Towns : Places with population over 10,00,000.

(b) Others : Places with population over 1,00,000 and upto 10,00,000.

Offices Abroad

120. The impact of the expansion programme was also evident in respect of offices abroad of Indian banks. At the end of December 1974 there were 63 offices of 8 Indian banks operating in 17 countries, (excluding Pakistan and Bangladesh) as compared with 55 offices of 7 banks in 12 countries towards the end of 1973. The increase in the total number of foreign offices of Indian banks was due to the opening of new offices in West Germany, France, Maldives Islands, Abu-Dhabi and Dubai. Besides, 2 additional offices were opened in the U. K. and 1 in Hongkong. The extension of Indian banking to West Asia is particularly significant. At the end of 1974 Bank of Baroda had the largest number of offices abroad (28) followed by Bank of India (13) and the State Bank of India (8). Of the remaining offices, United Commercial Bank had 6, Indian Overseas Bank 4, Indian Bank 2, Central Bank of India and Bharat Overseas Bank Ltd. one each. Country-wise, Indian banks had 15 offices in the U. K., 9 in Kenya, 8 in Fiji Islands, 6 in Singapore, 5 each in Hongkong and Mauritius and 3 Sri Lanka. The remaining 12 offices were spread over 10 other countries. Besides, the foreign subsidiary of Bank of India and Bank of Baroda had a total of 5 offices in Nigeria and Uganda.

121. The aggregate deposits of Indian banks' offices abroad increased from Rs. 274 crores at the end of December 1973 to Rs. 427 crores at the end of December 1974; while demand deposits rose from Rs. 119 crores to Rs. 205 crores, time deposits rose from Rs. 155 crores to Rs. 222 crores. The credit extended by foreign offices of Indian banks increased from Rs. 183 crores in December 1973 to Rs. 252 crores in December 1974. Due to the higher rate of deposit growth the credit-deposit ratio declined from 66.7 per cent in December 1973 to 58.9 per cent in December 1974.

Lead Bank Scheme

122. It may be recalled that the previous Annual Report had mentioned that the first phase of the operation of the Lead Bank Scheme was completed, with the completion of impressionist surveys in virtually all the districts. However as a

consequence of reorganisation of districts in 14 States, certain new districts have had to be found. After reorganisation, the total number of districts rose to 373. It became necessary, therefore to allot these new districts to banks under the Scheme. Since banks had already put in considerable efforts in their respective districts in regard to gathering the necessary socio-economic data, identifying credit gaps, formulating development programmes and establishing a network of branches, any major change in the lead responsibility at this stage would have adversely affected the success of the Scheme. It was, therefore, decided to allot most of the newly formed districts in the 14 States to banks which were already functioning as lead banks for the parent districts.

Lending to Priority Sectors and Disadvantaged Classes

123. Commercial banks showed further progress in respect of improving the relative share of credit to priority sectors, in particular, to the agricultural sector. Preferential treatment was also extended to the export sector and further progress was evident in the implementation of the scheme of differential interest rates to benefit members of the Scheduled castes and tribes.

Advances to Priority Sectors

124. Taking priority sectors first, the share of advances to these sectors by scheduled commercial banks rose from 24.8 per cent of total advances in December 1973 to 26.7 per cent in December 1974 (Table 22). Public sector banks accounted for 89 per cent of the total priority sector advances at the end of December 1974. The shares of State Bank Group and that of the fourteen nationalised banks in total priority sector advances worked out to 30.8 per cent and 58 per cent, respectively. The share of small-scale industries in total priority sector advances decreased from 49.0 per cent in December 1973 to 48.2 per cent in December 1974. During the same period, the share of direct agricultural finance in the total priority sector advances increased from 24.1 per cent to 25.5 per cent.

TABLE 22:—SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' ADVANCES TO PRIORITY SECTORS

(Amounts in Rupees Crores)

	December 1973 (Provisional)				December 1974 (Provisional)			
	State Bank Group	Fourteen Nationalised Banks	Public Sector Banks	All Scheduled Commercial Banks	State Bank Group	Fourteen Nationalised Banks	Public Sector Banks	All Scheduled Commercial Banks
I. Total Bank Credit	2004	3911	5915	7062	2225	4441	6666	7914
II. Advances to Priority Sectors								
(a) Agriculture								
(i) Direct Finance	105	264	369	423	156	323	479	539
(ii) Indirect Finance	58	120	178	195	73	154	227	242
(b) Small Scale Industries	317	450	767	859	370	540	910	1017
(c) Road and Water Transport Operators	11	68	79	98	15	80	95	121
(d) Retail Trade and Small Business	27	89	116	141	32	93	125	149
(e) Professional and Self-employed Persons	3	26	29	34	4	30	34	40
(f) Education		4	4	4		4	4	4
Total (a to f)	521	1021	1542	1754	650	1224	1874	2112
Percentage share of the bank group in all banks' advances to Priority Sector	29.7	58.2	87.9	100.0	30.8	58.0	88.7	100.0
Percentage of advances to Priority Sectors in total group credit	26.0	26.1	26.1	24.8	29.2	27.6	28.1	26.7

Assistance to Agricultural Sector

125. In regard to financing of agriculture, not only the proportion of direct finance to agriculture increased but banks continued to be involved in an increasing degree in assisting farmers who derived benefit from other financial institutions. For instance, banks continued to assist the identified participants of the SFDA and MFAL projects in selected districts; loans disbursed to identified farmers in these areas amounted to Rs. 17.69 crores at the end of December 1974, as compared with Rs. 10.78 crores in December 1973.

126. Reference was made in the last year's Report to a scheme of financing farmers through Farmers' Service Societies organised by commercial banks, put into operation on an experimental basis in a few selected SFDA/MFAL areas. So far 25 such societies have been organised by 11 public sector banks in 9 States, viz., Bihar, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu & Kashmir, Karnataka, Tripura, Manipur and Rajasthan. The Societies are intended to provide to farmers an integrated package of credit and other services including supply of inputs, facilities for marketing the produce.

127. Scheduled commercial banks continued to participate in an increasing measure in schemes for which refinance facilities are available from the Agricultural Refinance Corporation (ARC). The cumulative figures of number of schemes sanctioned and financial assistance committed upto May 1975, worked out to 1140 and Rs. 218.40 crores, respectively. The ARC's disbursements to commercial banks amounted to Rs. 46.36 crores upto May 1975 as against Rs. 29.54 crores as at the end of June 1974. While minor irrigation schemes constituted the major activity financed by the commercial banks, the other schemes assisted by them were plantation/horticulture, farm mechanisation, dairy development, poultry and sheep breeding, land development, storage/market yards and fisheries development.

128. During the year under review, commercial banks continued to participate in projects sanctioned with assistance from IBRD/IDA for financing programmes of minor irrigation, land development, farm mechanisation, etc., in eight States viz., Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar. During 1974-75, the Chambal and Rajasthan Canal Command Area Development Projects became effective. A Drought Prone Area Project is expected to be launched with IDA's assistance covering selected districts in the States of Maharashtra, Karnataka, Rajasthan and Andhra Pradesh.

Recovery of Agricultural Advances

129. With the improvement in agricultural production in 1973-74, recovery of agricultural advances (direct finance) showed distinct improvement during that year. Total demand (i.e., overdue amount as on the last Friday of previous June plus current demand during July-June, 1973-74) in respect of direct agricultural advances of the public sector banks increased by Rs. 56.2 crores, as compared to Rs. 27.6 crores (Revised) in the previous year. At the same time, the amount of recovery by these banks during 1973-74 increased sharply by Rs. 28.4 crores as against Rs. 9.7 crores (Revised) in 1972-73.

130. Although the proportion of recovery to total demand in respect of public sector banks at the all-India level increased only fractionally from 48.0 per cent at the end of June 1973 to 48.7 per cent at the end of June 1974; there was significant improvement in the recovery ratio in a number of States. The proportion of recoveries to demand showed improvement during 1973-74 in Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Manipur, Meghalaya, Tripura, Bihar, Orissa, West Bengal, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala. On the other hand the recovery position deteriorated in Assam, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu and in the Union Territories of Chandigarh, Delhi, Goa, Daman and Diu and Pondicherry.

131. Mention was made of the adoption-of-area approach by banks in the last year's Report. Total number of villages adopted by the nationalised banks increased from 9631 at the end of June 1973 to 14063 at the end of June 1974. By the end of March 1974, the State Bank Group adopted a total number of 12597 villages under the Village Adoption Scheme.

Differential Rates of Interest

132. Further relaxations were made during the year in the scheme of differential interest rates with a view to widening the scope of benefit to scheduled castes and tribes. It may be recalled that only landless persons and those with small holdings (of not more than 1 acre in the case of irrigated land and 2.5 acres of unirrigated land) were eligible for loans under the Scheme. This criterion of eligibility was relaxed so that members belonging to scheduled castes and tribes are now eligible to borrow under the Scheme, irrespective of the extent of their land holdings provided they satisfy the other conditions stipulated in the Scheme. Public sector banks recorded further progress in lending under the Scheme. This is reflected in the number of borrowal accounts and the amount outstanding both of which rose sharply during the period December 1973—December 1974: while the amount outstanding increased from Rs. 10.00 crores to Rs. 13.35 crores, the number of account increased from 230661 to 313026. The average amount of loan per account declined marginally from Rs. 433 at the end of December 1973 to Rs. 426 at the end of December 1974.

Export Sector

133. Another sector which has been claiming preferential treatment in recent years is the export sector. Some modifications introduced during the year may be noted. Consequent on the general increase in the lending rates of banks, the maximum rate of interest on export credit was raised in July 1974 from 9 per cent to 10.5 per cent excepting in the case of post-shipment credit given on deferred payment terms. The ceiling rate of interest on post-shipment credit given on deferred payment terms was maintained until the 24th September 1974 at 7 per cent, when, following the introduction of a tax on interest earned by banks, it was raised to 8 per cent. Simultaneously, the maximum rate of interest on other export credits was also stepped up from 10.5 per cent to 11.5 per cent. The concessional ceiling rate of 8 per cent is applicable only for post-shipment credit given on deferred payment basis for more than one year irrespective of whether the amount is payable in lumpsum or in instalments. In respect of loans and advances granted against duty drawbacks and cash incentives, at the pre-shipment or post-shipment stage, the ceiling rate was made applicable upto a period not exceeding 90 days.

134. The duration of the concessional rate of interest which was available for packing credit was limited to 90 days and banks were allowed to charge 'normal' rates on outstandings beyond this period. Since international developments warranted provision of some additional incentives to the export sector, it was announced as a part of the 1975 slack season policy, that the period for which concessional rate of interest at 11.5 per cent would apply would be extended from 90 days to 180 days in the case of pre-shipment credit for specified medium and heavy engineering goods and construction contracts abroad. When factors beyond the control of the exporter necessitated a longer period of pre-shipment credit, banks were directed not to charge a rate of interest exceeding 13.5 per cent for a further period of 90 days in the case of specified medium and heavy engineering goods and construction contracts abroad. Forty-four export categories were included in the list for which this relaxation would be applicable.

135. In the case of other packing credits the period for which concessional rate of interest at 11.5 per cent is applicable would continue to be 90 days. However, if for similar reasons, pre-shipment credit had to be given for a longer period, banks were advised not to charge a rate of interest exceeding 13.5 per cent for a further upto 45 days.

136. The prevailing exemption from prior authorisation of pre-shipment export credit under the Credit Authorisation Scheme (CAS) was withdrawn in July 1974. While the exemption continued in respect of post-shipment credit, sanction of export packing credit (including advances made against duty drawback, cash assistance, etc.) has been brought under the purview of the CAS. The objective of this measure is to ensure that pre-shipment export credit limits are reasonable in relation to the past and projected exports and total credit limits are related to total projected production. However, the requirement of prior authorisation has been made applicable to export packing credit limits exceeding Rs. 5 lakhs to a single borrower (covered under the Scheme) from one bank. As regards existing packing credits exceeding Rs. 25 lakhs, banks are required to apply to the Reserve Bank for authorisation for continuance of such facilities.

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

137. Under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme 1968, commercial banks are eligible for interest subsidy at 1.5 per cent per annum for export credit given by them at a rate of interest not exceeding the prescribed ceiling. The claims for subsidy under the Scheme amounting to Rs. 7.53 crores received from 43 eligible banks were settled during the period July 1974—June 1975: pre-shipment credit accounted for Rs. 4.21 crores and post-shipment credit for Rs. 3.32 crores. The total subsidy disbursed under the Scheme since its inception upto June 30, 1975 amounted to Rs. 30.97 crores.

Standing Committee on Export Finance

138. Problems of export finance are not only complex but their character may undergo changes in the light of international developments. To provide an institutional means for dealing the problems as they arise, the Reserve Bank has set up a Standing Committee on Export Finance. The Committee includes representatives of Industrial Development Bank of India, Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., Foreign Exchange Dealers' Association of India, Union Ministries of Commerce and Finance and commercial banks. The Standing Committee is expected not only look into problems, as they arise out of the implementation of export credit policies but also to anticipate such problems and suggest suitable solutions.

Consortium/Participation Arrangements—Study Group

139. It was mentioned in the last years' Report that a Study Group was set up by the Reserve Bank in December 1973 to formulate guidelines for extension of credit limits on consortium/participation basis and make recommendations for sharing of advances to units in public and private sectors, for participation amongst banks for revival of sick units and for better co-ordination and co-operation amongst banks in respect of multiple banking. In the light of recommendations of Study Group, the Reserve Bank had suggested to the commercial banks that large credit limits by banks to any single borrower in the private sector or public sector (including Electricity Boards) in excess of 1.5 per cent of its deposits should normally be extended on a participation basis. Banks were asked to review their existing advances in the light of these norms and enter into participation arrangements where necessary. Joint review of credit requirements of the borrower was also suggested when the limits become due for renewal or a substantial increase in the limits was sought or the borrower's performance showed signs of deterioration.

Participation Certificates Scheme

140. The terms and conditions governing the issue of participation certificates were modified during the year under review. This Scheme which was originally introduced on an experimental basis was extended from time to time and has further been extended till the end of June 1976. The number of banks approved by the Reserve Bank under the Scheme has increased from 34 at the end of June 1974 to 37 at the end of June 1975 (one more bank has been approved in July 1975). Participation certificates issued and remaining outstandings amounted to Rs. 87.07 crores at the end of April 1975.

141.—Banks were permitted to enter into participation arrangement only with other commercial banks, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, General Insurance Corporation of India, General Insurance Companies and with the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. All financial institutions other than those mentioned above have been excluded for the purpose of entering into participation arrangements under the Scheme.

142. It was also stipulated that the period of maturity of participation certificates should not be less than 30 days nor more than 180 days, subject to the condition that banks should not issue any certificate whose maturity extends beyond June 30, 1976. In keeping with the rise in the interest rates structure, the maximum rate of interest at which a bank can issue the certificate was raised to 12 per cent with effect from August 1, 1974. However, the restrictions regarding the minimum and maximum periods and the ceiling on the rate of interest were not applicable to participation

certificates issued by commercial banks to any other commercial bank irrespective of whether the latter was authorised to issue participation certificates or not.

Term-Lending : Commercial Banks

143. In view of the need for stimulating investment in the economy, commercial banks were urged to increase the term-lending for projects of high priority, within the resources available to them and consistent with the policy framework for term-lending. While stepping up term-lending, banks were advised to give particular importance to the following areas—deferred payment exports; industries where a substantial part of the output is meant for export or where new potential for export could be quickly built-up; industries with short gestation period particularly in the core sector and those producing mass consumption goods; agricultural sector; industries in industrially very backward areas; small scale industries involving an investment of upto Rs. 25,000; capital goods industries and deferred payment arrangements for purchase of capital goods in the domestic markets.

Credit Planning and Credit Authorisation Scheme

144. Any credit plan, if it is to be implemented effectively and meaningfully requires planning not only at the Reserve Bank or the 'macro' level but also at the individual bank's or the 'micro' level. In fact, one could go a step further and state that such a credit planning process must be eventually transmitted to the borrowers. The Credit Authorisation Scheme and the scrutiny of major borrowers' accounts are among the instruments through which the Reserve Bank has been attempting, over the years, to evolve such a three-tier credit planning process.

Credit Authorisation Scheme

145. The rationale and working of the Credit Authorisation Scheme (CAS) was reviewed in the last year's Report. The Scheme has entered the tenth year of its operation, and the number of parties covered by it has increased nearly three-fold from 650 at the commencement of the Scheme to about 1800. The Scheme has of course been so tuned as to subserve the overall credit policy objective of credit restraint. Thus, the practice was introduced of advising banks, while conveying authorisation for additional credit facilities, to ensure that drawals in their accounts were restricted to amounts necessary for the essential requirements of borrowers and to exercise utmost caution in ensuring the proper use of funds.

146. The progress during the year may now be specifically reviewed. The number of parties covered by the Scheme increased from 1622 at the end of June 1974 to 1786 at the end of June 1975 and the number of public sector undertakings increased from 166 to 192. The number of applications received increased from 953 during 1973-74 to 1058 during 1974-75; and the amount involved from Rs. 967 crores to Rs. 1022 crores. Of the total number of applications received during 1974-75, 120 belonged to the public sector involving an amount of Rs. 256 crores. The total number of cases authorised and the corresponding amount involved showed a decline during 1974-75 reflecting the greater emphasis on financial discipline and the overall credit restraint. The number of cases authorised declined from 644 in 1973-74 to 528 in 1974-75, and the amount from Rs. 469 crores to Rs. 429.

147. Total limits in force relating to the cases covered by the CAS at Rs. 7253 crores at the end of June 1975 showed an increase of 8.3 per cent over the limits obtained at the end of June 1974. Of this, limits in force in respect of public sector undertakings amounted to Rs. 2644 crores or 6.5 per cent higher than the previous year's level. Of the total limits in force at the end of June 1975, about 89 per cent were for working capital purposes, 8 per cent for term finance and 3 per cent for sale of machinery on deferred payment basis. Industry wise, of the total limits in force at the end of June 1975, the engineering industry accounted for about 24 per cent, trading for 14 per cent and cotton textiles for about 10 per cent. Of the credit limits in force relating to the public sector, trading accounted for 32 per cent, the engineering industry for 20 per cent and electricity undertakings for 10 per cent.

148. During the year, there was a perceptible trend towards better inventory management in industry. The CAS, which is playing an increasing and effective role in this regard, is acting as a means of credit discipline and has brought about some improvement in the systems and procedures of credit appraisal by banks.

Study Group for Follow-up of Bank Credit

149. A significant development during the year was the prescription of some tentative norms for the sanction of bank credit, as a basis for evolving a firmer policy in this regard. The norms were indicated by the Study Group set up by the Reserve Bank to examine the various aspects of follow-up and supervision by banks of the credit extended by them. In November 1974, following the interim report submitted by the Study Group, the Reserve Bank issued guidelines to banks indicating the norms to be adopted in providing advance to 10 major industries²¹ against raw materials, finished goods and receivables. These norms were to be applied to units in the public as well as the private sector. Banks were asked to apply the suggested norms in respect of all fresh proposals, including those seeking enhancement of credit limits from existing borrowers. Banks were also advised to establish a dialogue with all existing borrowers where inventories and receivables were in excess of the norms indicated and work out a programme for phased reduction. While the normal functioning of the borrower should not be upset by any abrupt reduction of limits, it was suggested that after a reasonable period, or say two months, a higher rate of interest could be charged on the portion of borrowings considered excessive. Control, through the application of the norms, should be exercised with flexibility and understanding of conditions which might warrant temporary deviations.

150. Although the norms suggested by the Study Group related to only 10 major industries, banks were asked to observe the purpose and spirit behind these norms while appraising credit proposals from other industries. In appraising credit requirements banks were also advised to keep in mind the restrictions placed on the distribution of dividends by companies, which would increase the retention of profits and hence would reduce the need for dependence on external sources of funds.

151. Since the suggested norms were in the nature of an experiment, the importance of feed-back information on their practical application was stressed and banks were requested to furnish industry-wise comments on their experience in applying the norms. Such information received from banks show that the norms indicating have been well received. The Study Group has also met a cross-section of industrial borrowers and obtained their views on the norms. In the light of the information gathered in these discussions and through the feed-back material received from banks the Study Group is examining the scope for further refinement of the norms. A set of forms has been designed by the Group for use by banks in appraisal, follow-up and relation of bank credit to production plans of borrowers.

152. The Reserve Bank has recently set-up a Committee of Direction comprising representatives from the Bank and some major commercial banks to consider, inter alia, the problems that may arise in the implementation of the recommendation of the Study Group. Banks with deposits of Rs. 50 crores and above have also been advised to set-up similar committees to ensure effective implementation and review of the Study Group's recommendations.

Scrutiny of Fifty Top Borrowers' Accounts

153. In further pursuance of the object of evolving an appropriate system of effective follow-up and supervision of credit, banks were advised to undertake a scrutiny of the accounts of their 50 biggest borrowers. Each of the

public sector banks was advised to form a Committee of Directors (consisting of the Chairman, the Government Director and the Reserve Bank Director) to frame norms for such scrutiny while in respect of private sector banks, the Reserve Bank deputed officers to ascertain the progress of the scrutiny and monitor the important findings. Reserve Bank officials also carried out test checks of a sample (of the largest 10 to 20) of the accounts under scrutiny of the public sector banks.

154. The objects of the scrutiny were (a) to ensure that the utilisation of bank credit was related to minimum inventory requirements; (b) to examine whether sanctioned limits, especially by way of cash credits, were out of proportion to requirements; (c) to regulate drawals at the peak by pruning limits and (d) to ensure that there was no diversion either of credit or of the internal resources of the borrowing units, thereby increasing their dependence on banks.

155. The scrutiny conducted by the banks revealed that, by and large, there was no abnormal inventory built-up with the use of bank credit. Where there was evidence either of excessive inventory built-up or of credit limits disproportionate to requirements, appropriate corrective action was taken. An important result of the scrutiny was the long-term benefit of tuning the banks' machinery to the steps necessary for effective follow-up and imparting to the borrowers a degree of discipline in the use of bank funds.

Advances : Jute Industry

156. As in the past, the special problems facing individual industries were taken into account for suitably modifying credit policy measures. To take the jute industry first, in view of the smaller jute crop in 1974-75, banks were told in September 1974, that the permission given to them earlier in the year, to finance inventories of raw jute equivalent to four month's consumption would no longer apply. Banks were also advised to ensure that credit extended to jute mills was not such as would permit the mills to effect fresh purchases over and above the stock levels prescribed by the Jute Commissioner.

157. Subsequently, on account of slackening of export demand, mills came to accumulate sizeable stocks of finished goods. Hence, banks were advised in April 1975 to work out the credit needs of jute mills on the basis of inventory intended for exports equal to 9 weeks' production, as against 6 weeks' permitted level. Banks were also told that in deserving cases, they could marginally exceed the maximum inventory level with the prior approval of the Reserve Bank. This prior authorisation of the Reserve Bank was needed only in cases where the higher limits proposed were in excess of 10 per cent of the existing credit limit against inventories. The higher limits were permitted initially until end-June 1975 but later, extended to end-December, 1975. In consideration of the jute industry's request for a reduction in margins, banks were advised in May 1975 that relaxation in margins against raw jute and jute goods could be allowed in individual cases on merits, but the reduction was not to take margins below the levels obtaining prior to the issue of the directive of November 1973. These relaxations are operative till the end of September 1975.

Advances : Sugar Industry

158. In respect of sugar industry the prospects of sugar production during the 1974-75 season were reviewed and banks were advised in November, 1974 that credit limits could be sanctioned to sugar mills to the extent of the maximum outstanding in the regular limits sanctioned to them in the last two crushing seasons (viz : 1972-73 and 1973-74 seasons), without obtaining prior authorisation under the Credit Authorisation Scheme. Limits the excess of these levels required the prior authorisation. It was also impressed on the banks that they should continue to obtain from the sugar mills, control data, as hitherto, so that prompt payment of cane dues by the sugar mills to the sugarcane growers is ensured. In view of the substantial increase in production during the 1974-75 season, applications received under the Credit Authorisation Scheme for additional credit limits for sugar mills were

²¹These industries were Cotton Textile, Synthetic Textile, Jute Textiles, Pharmaceutical, Rubber Products, Fertilizers (Nitrogenous and Phosphatic), Vanaspathi, Paper (Bamboo and Wood and Chemicals), Light Engineering and Medium Engineering.

given top priority. During the 1974-75 crushing season till the end of June 1975 the Reserve Bank authorised an additional credit of Rs. 41.04 crores to the sugar mills to finance their increased production.

Advances : Textile Industry

159. In the case of textile industry, the Reserve Bank took necessary steps to provide finance to the sick textile mills taken over by the National Textile Corporation. Discussions were held with the representatives of the financing banks, the National Textile Corporation and the Bureau of Public Enterprises. The need for providing adequate credit to these mills which mainly produce controlled varieties of cloth meant for consumption of the masses was emphasised. It was suggested that banks might consider granting reasonable ad-hoc limits related to the production programme of each mill for short periods, pending detailed examination of the credit requirements.

160. To enable banks to meet the minimum needs of these sick units expeditiously, it was decided to exempt, from prior authorisation under the Credit Authorisation Scheme upto end of June 1975, and since extended upto end-September 1975 the sanction of the certain types of limits to individual mills subject to the condition that the temporary credit limits should not in the aggregate exceed Rs. 25 lakhs per each textile mill. These exempted limits include a temporary limit upto Rs. 25 lakhs to a sick textile mill taken over by the National Textile Corporation for a period not exceeding 6 months for genuine production/trade operations. Interim accommodation upto Rs. 25 lakhs to a sick mill pending Reserve Bank's authorisation for higher limits sanctioned by a bank on a regular basis was allowed. Further, temporary excess drawings over sanctioned limit upto 10 per cent or Rs. 25 lakhs, whichever was lower, was also permitted.

161. During the period January to June 1975, additional credit limits aggregating Rs. 2.04 crores have been authorised by the Bank under Credit Authorisation Scheme to sick textile mills for meeting their increased working capital requirements.

Fertilizer Credit

162. The fertilizer industry has had to face recently the problem of accumulation of finished goods. In June 1975, the Reserve Bank discussed with representatives of fertilizer manufacturers and distributors and those of banks, the credit requirements of the industry arising out of stock accumulation. Consequent on these discussions and in view of the priority accorded to the industry, it was decided to modify the norms for financing inventory and receivables and the margins applicable to the industry, temporarily upto the end-December 1975. A permissible level equivalent to 2½ months' sales was indicated for financing inventory of finished goods and receivables. Banks were advised to use their discretion in allocating limits between finished goods and receivables within the maximum. The determination of margins was also left to the discretion of banks, with the indication of a range of 15 per cent to 25 per cent.

Selective Credit Controls

163. The over-riding object of containing inflationary pressures required that the broad structure of Selective Credit Controls be maintained during the year. When the minimum lending rate on advances was raised from 11 per cent per annum to 12.5 per cent per annum in July, 1974, the minimum lending rate on advances against commodities covered by selective credit controls was also raised from 13 per cent to 15 per cent. In the case of advances to cotton mills against raw cotton stocks which are entitled for a lower margin and advances to sugar factories against stocks of free sale sugar which have not been released by Government for sale, the minimum lending rate was increased from 12 per cent to 14 per cent.

164. The ceiling limit for advances against commodities covered under selective credit controls continued to be fixed on a partywise basis; the base period for determining the permissible level, however, related to the peak level of advances outstanding during the preceding three years viz., (November-October) 1971-72, 1972-73 and 1973-74. Al-

though the structure of selective credit controls broadly remained unaltered, certain minor modifications/clarifications were indicated from time to time. The prevailing exemption from selective credit controls for advances against stocks of vanaspati held by vanaspati manufacturers intended for delivery to Army Purchase Organisation was extended to stocks of vanaspati meant for public distribution by Central and State Governments. Complete exemption was also given for advances against stocks of oilseeds and oils (including vanaspati) to wholesale and retail dealers to the extent of the quantum specified for public distribution. Some more exemptions were given from ceiling and margin stipulations to rice mills covered by procurement levy in the case of West Bengal and Bihar.

Bills Rediscounting Scheme and Credit Restraint

165. Although the policy of encouraging the use of the bill of exchange as an instrument of credit continued to operate, the overall requirements of credit restraint necessitated some moderation of the facility of rediscounting of such bills with the Reserve Bank. Such moderation was evident both in the 1974 slack season and in the 1974-75 busy season credit policy.

1974 Slack Season

166. At the commencement of the 1974 slack season, the main thrust of policy was to ensure that availability to banks of created money through rediscount of bills should not provide a continuing base for credit expansion; hence banks were asked to reduce rediscount bill limits by the end of October 1974 to 40 per cent of the level outstanding in April 1974.

167. Banks generally complied with this requirement and the amount of bills rediscounted was brought down from Rs. 279 crores to Rs. 108 crores or by Rs. 171 crores by the end of October 1974. Thus, during the 1974 slack season, the return flow of funds under the bills rediscounting scheme was quite satisfactory. When the minimum lending rate on advances was raised from 11 per cent to 12.5 per cent in July 1974, the minimum rate of discount of 9.5 per cent on bill finance for drawers' bills was refixed at 11 per cent per annum; the rate on drawees' bills which was at 11 per cent was refixed at 12.5 per cent per annum. To prevent bill finance for inventory purchase becoming cheaper than cash credit, it was also stipulated that the rate of interest on drawees' bills should be on par with the rate of interest on the cash credit accommodation extended to the same borrower.

1974-75 Busy Season

168. This constraint on rediscounting of bills facility was further tightened in the policy for the 1974-75 busy season, when this facility was placed largely on a discretionary basis. A basic rediscount quota equal to 10 per cent of the bank's total inland bills purchased and discounted as on September 27, 1974 was allowed to each eligible bank. This accommodation (amounting to Rs. 122 crores) was made available at the Bank Rate. Any additional limit for rediscount was allowed only at the discretion of the Reserve Bank, both in regard to amount and interest, the rates ranging from 10 per cent to 15 per cent. In allowing discretionary limits, the considerations that were taken into account included the sectoral deployment of credit of a bank the total assistance provided by the Reserve Bank and the composition of bank's bill portfolio as between buyers' and sellers' bills. The basic quotas sanctioned to banks during the 1974-75 busy season have been allowed to be continued for the 1975 slack season.

169. As a combined result of the policy of credit restraint and higher costs of rediscounting, bills rediscounted with the Reserve Bank recorded a decline. The amount outstanding as on June 27, 1975 at Rs. 132 crores showed a decrease of Rs. 142 crores over the end-June 1974 level as against an increase of Rs. 259 crores during the corresponding period of the previous year.

Extension of Rediscount Facility

170. Finally, two developments relating to the rediscount facility may be noted. It was decided to restrict the scheduled commercial banks to rediscount genuine trade

bills of exchange held by them, with any of the following institutions viz., commercial banks, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, General Insurance Corporation/Companies and Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., besides the Reserve Bank. Banks are not permitted to rediscount bills with any State-level term-lending institutions or other institutions, excepting those specified above. Secondly, bills rediscounting facilities were also made available, with effect from April 1, 1975, at the Ahmedabad Office of the Reserve Bank of India.

Banking Commission's Recommendations

171. It was mentioned in the last Report that the Government of India have taken decisions on a number of recommendations of the Banking Commission. In regard to these recommendations and a few others subsequently accepted by the Government, various circulars have been issued to commercial banks suggesting that expeditious steps might be taken to implement them. The circulars deal with the following matters :

- (a) Recommendations contained in Chapters 6 and 7 of the Report relating to deposit mobilisation and advances to the priority sectors, particularly small artisans and small-scale industries.
- (b) Recommendations contained in Chapter 11 of the Report entitled "Bank Operating Methods and Procedures" covering various areas in the functioning of banks, viz., Customer Service, Credit Procedures, Internal Control System and Organisation and Management which are primarily designed with a view to improving the functional and operational efficiency of banks in the said areas.
- (c) Recommendations contained in Chapter 14 relating to training of bank-employees : the guidelines contained in the relevant recommendations are expected to be helpful to banks in locating, developing and using the talents of their staff more effectively than at present.

Banking Legislation

Amendments : Reserve Bank of India Act, 1934

172. The Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1974, as passed by both the Houses of Parliament, received the assent of the President on the 13th December 1974 and came into force on the said date. The amendments have (i) widened the powers of the Bank to provide refinance facilities to scheduled banks and state co-operative banks, (ii) enlarged the scope of the term "agricultural operations" so as to permit extension of concessional refinance facilities by the Bank to apex co-operative banks in respect of loans to co-operatives exclusively formed for subsidiary activities undertaken not jointly but independently of farming, (iii) widened the scope of the Bank to act as agent so as to enable the Bank to issue and manage bonds and debentures on behalf of statutory corporations like the Agricultural Refinance Corporation and the Industrial Development Bank of India, (iv) enlarged the list of foreign securities eligible to be held as assets of the Issue Department of the Bank, (v) modified the definition of the term "liabilities" in the explanation below sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, (vi) provided statutory protection to banks to exchange freely credit information mutually among themselves and (vii) vested the Bank with better powers to exercise control over non-banking institutions receiving deposits.

Amendments : Banking Regulation Act, 1949—Rules

173. In the light of the experience in administration of the Banking Regulation Act, 1949 and in order to facilitate the compilation of statistics, certain amendments to the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949, were considered necessary. These amendments have been finalised and published in the Gazette of India dated the 4th January 1975, inviting objections or suggestions which will be taken into account on or after the 31st July 1975. The suggested amendments relate to the rationalisation of the format and contents of some of the forms prescribed for reporting of information.

Banking Laws Committee

174. The Banking Laws Committee set up by the Government of India has submitted its first report, viz., 'Report on Negotiable Instruments Law'. These recommendations generally relate to the elimination of deficiencies noticed by the Committee in the laws relating to negotiable instruments. These recommendations are being examined in detail by the Bank.

States' Legislations

175. The following eight States, viz., Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal have passed Bills to enable commercial banks to lend to the agricultural sector on a bigger scale. Draft bills have been prepared by the Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar Jammu & Kashmir, Meghalaya and Orissa. The need for such a legislation was again emphasised to the remaining State Governments/Union Territories.

Inspections, Mergers and Related Organisational Matters

176. The comparative position in regard to the inspection of banks and bank offices carried out during the last three years (July-June) is indicated below:

	1972-73	1973-74	1974-75
Financial Inspection			
Number of banks inspected/taken up for inspection	44	24	28
Number of Offices inspected	1,013	752	506
Centre-wise Inspection			
Number of centres	194	614	1,271
Number of Offices	789	2,218	2,362
Systems Inspection			
Number of banks inspected	1	1	2

177. During the year, the programme of inspections under section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 covered 22 scheduled banks and 6 non-scheduled banks. The coverage of financial inspections was less than those in the previous years which is in keeping with the policy as indicated in the last Report, of carrying out centre-wise inspections on a larger scale.

178. The inspection of two banks in liquidation (viz., Calcutta Commercial Bank Ltd. and Bengal Bank Ltd.) under section 45Q of the Banking Regulation Act, 1949 was completed during the year.

179. The inspection of the branches of Indian banks in Sri Lanka, U.S.A. and Guyana has been completed and that of the branches in the U. K. is in progress.

180. The programme of study of individual banks for examining their systems and procedures and suggesting improvement, where necessary, was continued. Such studies of two more banks, one each in the public sector and private sector, were completed during the year. The systems and procedures of six banks have so far been studied since the introduction of this programme in 1971. It is proposed to take up a similar study of one more bank shortly.

Conference

181. A conference of the heads of internal inspection/audit departments of 22 public sector banks and four private sector banks (each having more than 150 branches) was organised in August 1974. The main purpose of the conference was to focus the attention of the banks on the imperative need to strengthen their internal inspection machinery in the context of the rapidly expanding branch network and the wide diversity of the business now handled by them to fulfil the social objectives.

Bank Mergers and Liquidations

182. Efforts to consolidate the banking system in the country through a process of voluntary amalgamations, transfer

of liabilities and assets and participation arrangements were continued. The Government of India have so far sanctioned schemes of amalgamation under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, in respect of 49 banks. In terms of the provisions of the relative schemes of amalgamation, the transferee banks are required to make a final valuation of the assets of the transferor banks after a period of 6/12 years or such earlier period as sanctioned by the Central Government in consultation with the Reserve Bank. The final valuation of the assets of 17 banks as provided in the respective schemes of amalgamation has been completed, while in the case of 11 banks, the final valuation reports are under consideration.

183. During the period under review, 7 non-scheduled banks were dissolved and reports on 2 more non-scheduled banks, stated to have been dissolved during the last year, were also received during the current year. A certificate under section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949, was issued to one non-scheduled bank to enable it to go into voluntary liquidation.

184. After obtaining the necessary directive from the Central Government, the inspection of the books and accounts of the Exchange Bank of India and Africa Ltd. (in liquidation) under section 45Q of the Banking Regulation Act, 1949, was taken up and completed. Copies of the inspection report were forwarded to the Government of India and the Registrar of High Court, Bombay. The inspection under section 45Q of the Banking Regulation Act, 1949, of the Associated Banking Corporation of India Ltd., Bombay, could not be resumed as the relative records are still not made available to the Inspecting Officer for the purpose.

Clearing House Facilities

185. Eighteen Clearing Houses were established during the period 1st July 1974 to 30th June 1975 bringing the total number of Clearing Houses in the Country to 212; of these, 9 are managed by the Reserve Bank of India, 170 by the State Bank of India and 33 by the subsidiaries of the State Bank of India.

186. It was mentioned in the last Report that certain decisions of the Clearing Reforms Committee of the Indian Bank's Association on the proposal of the Reserve Bank envisaging certain procedural adjustments in timings, etc., of the Clearing House in Bombay were under the consideration of the Managing Committee of the Association. The reforms in the existing clearing arrangements at Bombay as approved by the Managing Committee of the Association were communicated to the Bombay Bankers' Clearing House for consideration. They are being further examined in consultation with the members of the Clearing House. The Calcutta Bankers' Clearing House and the Madras Bankers' Clearing House are also considering certain reforms.

187. Consequent upon the rapid branch expansion, sorting of cheques bank-wise and branch-wise had become cumbersome and the Committee of Bankers considered in 1968-69 a suggestion that cheque forms should display the code numbers of the branches in addition to code numbers of the banks so as to facilitate banks to sort, route, list and record cheques by these code numbers both bank-wise and branch-wise. The revision of the present coding system is under consideration in consultation with the Indian Banks' Association.

Licensing of Banks

188. During the period under review, no licence to carry on banking business in India was granted to any bank, while the licence granted to one of the Indian scheduled banks so as to facilitate banks to sort, route, list and record consequent upon its business having been taken over by the State Bank of India and the former having ceased transacting banking business thereafter. Thus, the number of licensed commercial banks stood reduced to 46 (including National Bank of Pakistan which is under the Custodian

of Enemy Property) while the number of banks in whose cases licences have been cancelled increased to 53 as at the end of June 1975. It may be mentioned that 22 public sector banks do not require licences. The name of the Krishnaram Baldeo Bank Ltd. has also been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

189. During the period under review, no licence under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949, to carry on banking business in India was refused to any existing bank. The total number of banks to whom licence has been refused remained unchanged at 283 as at the end of June 1975.

Information and Statistics

Credit Information

190. Banks and other notified financial institutions continued to receive, on request, information on credit facilities allowed to individual borrowers. During the year 1974-75 (July 1974 to June 1975), credit information in respect of 953 applications was furnished as against 1099 applications during 1973-74.

Basic Statistical Returns Scheme (BSR)

191. The Basic Statistical Returns Scheme (BSR), for collection of data on deposits and advances from scheduled commercial banks introduced in December 1972, has made further progress during the year under review. Banks have adapted themselves well to the new system of reporting. The coverage under the scheme represents 99 per cent of the total deposits and advances of all scheduled commercial banks. Three volumes of Banking Statistics under the series 'Basic Statistical Returns', presenting comprehensive data on deposits and advances for the periods December 1972, June 1973 and December 1973, have been published so far. A brochure containing summary data on deposits and advances for the half-year ended June 1974 was also released in May 1975.

192. Meetings were held periodically with individual banks in order to bring about further improvements in the quality of reporting and also to examine problems which the banks encountered in reporting data under the scheme.

Working Results of Scheduled Commercial Banks

193. An analysis of the working results of 22 public sector banks (State Bank group and the 14 nationalised banks), 25 Indian scheduled commercial banks in the private sector with deposits of over Rs. 10 crores each and foreign banks, shows a marked improvement in their profits⁽²²⁾ during the calendar year 1974. During 1974, profits of public sector banks increased by about 27 per cent and that of foreign banks rose by about 50 per cent. Further, profit of 25 scheduled commercial banks in the private sector more than doubled in the year (Table 23).

(22) Profits after provision for taxation and for bonus to staff.

TABLE 23 :—WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Amounts in Rupees Crores)

	State Bank Group		Nationalised Banks		Total Public Sector Banks		Other Indian Scheduled Commercial Banks@		Foreign Banks	
	1973	1974	1973	1974	1973	1974	1973	1974	1973	1974
	1	2	3	4	5(1+3)	6(2+4)	7	8	9	10
I. Total Earnings .	265.73 (23.0)	358.57 (34.9)	488.67 (25.7)	681.94 (39.6)	754.40 (24.7)	1040.51 (37.9)	70.50 (37.2)	102.16 (44.9)	75.70 (13.5)	107.29 (41.7)
Of which :										
(a) Interest and Discount	216.83 (22.4)	297.69 (37.3)	430.16 (25.8)	600.96 (39.7)	646.99 (24.6)	898.65 (38.9)	61.65 (38.2)	90.05 (46.1)	58.78 (12.3)	84.34 (43.4)
II. Total Expenditure	161.07 (23.3)	353.34 (35.3)	481.01 (26.2)	671.55 (39.6)	742.08 (25.2)	1024.89 (38.1)	69.12 (37.9)	99.26 (43.6)	71.50 (13.8)	101.00 (41.3)
Of which :										
(b) Interest paid on borrowings deposits, etc	117.79 (25.4)	173.61 (48.0)	257.78 (30.8)	388.12 (50.6)	375.07 (29.1)	561.72 (49.8)	36.31 (39.1)	51.68 (42.3)	30.55 (19.0)	45.27 (48.2)
(c) Salaries, Allowances Provident Fund and Bonus	114.28 (21.7)	145.12 (26.9)	169.48 (22.7)	218.12 (28.7)	283.76 (22.4)	363.24 (28.0)	24.01 (37.2)	34.19 (42.3)	18.57 (11.3)	22.78 (22.6)
III. Profits after Provision for Taxation and Bonus to Staff	4.66 (6.6)	5.23 (12.2)	7.65 (1.3)	10.39 (35.8)	12.31 (3.3)	15.62 (29.6)	1.38 (7.8)	2.90 (110.1)	4.20 (8.0)	6.29 (49.8)

@Figures relate to 25 Indian scheduled commercial banks in the private sector with deposits of over Rs.10 crores.

Note : Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year.

Source : Profit and Loss Accounts of banks.

Public Sector Banks

194. Profits of public sector banks increased from Rs. 12.3 crores in 1973 to Rs. 15.6 crores in 1974. The total income of these banks increased sharply by Rs. 286.1 crores (37.9 per cent) during 1974 as compared to an increase of Rs. 149.6 crores (24.7 per cent) in 1973. This increase in income was largely due to the stepping up of the minimum lending rate of banks from 10 per cent to 11 per cent from December 1, 1973 and from 11 per cent to 12.5 per cent per annum from July 23, 1974. The total expenses of public sector banks showed a sizeable increase by Rs. 282.8 crores (38.1 per cent) in 1974 as compared to Rs. 149.2 crores (25.2 per cent) in 1973. This rise in expenses was attributable mainly to the increase in interest rates on deposits effected from April and July 1974 and payment of higher dearness allowance following a sharp rise in the cost of living index during greater part of the year.

State Bank of India

195. The group-wise analysis shows an increase of Rs. 74.7 crores in the total earnings of State Bank of India during 1974 as compared to a rise of Rs. 38.4 crores in 1973. Total expenditure was also higher by Rs. 74.2 crores in 1974 as compared to an increase of Rs. 38.1 crores in 1973. The profits of the State Bank of India at Rs. 4.6 crores in 1974 recorded an increase of Rs. 49 lakhs as compared to an increase of Rs. 27 lakhs in 1973. Out of the profits for 1974, the bank transferred Rs. 3.9 crores to reserve fund and provided Rs. 68 lakhs for dividend to shareholders.

State Bank of India : Subsidiaries

196. The total income of the seven subsidiaries of the State Bank of India increased by Rs. 18.2 crores in 1974 as compared to a rise of Rs. 11.3 crores in 1973. Their

total expenses also rose quite substantially during 1974. Even so, these banks improved their profit by Rs. 8 lakhs from Rs. 54 lakhs in 1973 to Rs. 62 lakhs in 1974. Out of the profits made in 1974, these banks transferred an amount of Rs. 50 lakhs to reserves and provided Rs. 12 lakhs for payment of dividend to the State Bank.

Nationalised Banks

197. The total income of the 14 nationalised banks at Rs. 681.9 crores in 1974 recorded an increase of Rs. 193.3 crores (39.6 per cent) as compared to Rs. 99.9 crores (25.7 per cent) in 1973; this was mainly on account of the rise in earnings from interest and discount. Total expenses of these banks, at Rs. 671.6 crores in 1974 also rose by Rs. 190.6 crores (39.6 per cent) as compared to Rs. 99.8 crores (26.2 per cent) in the preceding year. The two main components which contributed to the rise in the expenditure of these banks were the 'interest paid on deposits and borrowings' and 'expenditures incurred on salaries, allowances, provident fund and bonus'. The profits of nationalised banks recorded a rise of Rs. 2.7 crores in 1974 over the previous year.

198. Out of their profits, the 14 nationalised banks transferred Rs. 6.2 crores to the statutory reserves and Rs. 3.9 crores to the Government of India under Section 10(7) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The surplus amount transferred to Government of India during 1974 represents 4.5 per cent of the aggregate compensation paid for the acquisition of these banks.

Private Sector Banks

199. The working results of 25 Indian Scheduled Commercial Banks in the private sector with deposits of over Rs. 10 crores each displayed a distinct improvement in their profits. During 1974, the total income of these

banks increased by Rs. 31.7 crores (by 44.9 per cent) and expenditure by Rs. 30.1 crores (by 43.6 per cent). These banks more than doubled their profits from Rs. 1.4 crores in 1973 to Rs. 2.9 crores during 1974. Increased profits during 1974 enabled these banks to transfer higher amounts to statutory reserves and make larger appropriations for other reserves. Transfers to statutory reserves increased from Rs. 48 lakhs in 1973 to Rs. 141 lakhs in 1974, while appropriations for other reserves rose from Rs. 36 lakhs to Rs. 75 lakhs. Dividend payments to shareholders were also higher in 1974 (Rs. 48 lakhs) as compared to the previous year (Rs. 42 lakhs).

Foreign Banks

200. The total income of the foreign banks increased from Rs. 75.7 crores to Rs. 107.3 crores or by 41.7 per cent during 1974. Their total expenditure also recorded a rise of Rs. 29.5 crores in 1974 (41.3 per cent) over the previous year. The profits of foreign banks showed a marked rise from Rs. 4.2 crores in 1973 to Rs. 6.3 crores in 1974.

Credit Guarantee Corporation and Deposit Insurance Corporation

201. The progress recorded during the year by the Credit Guarantee Corporation of India and the Deposit Insurance Corporation may now be briefly reviewed.

Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

202. The advances guaranteed under the Credit Guarantee Corporation's three schemes, viz., (1) Small Loans Guarantee Scheme, (2) Financial Corporations Guarantee Scheme and (3) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme amounted to Rs. 529.64 crores as on the last Friday of December 1974. Almost the entire amount (Rs. 526 crores) was accounted for by Small Loans Guarantee Scheme.²³ Advances guaranteed under this Scheme to farmers and agriculturists, transport operators, traders of goods (other than fertilisers and mineral oils), and professionals and self-employed persons amounted to Rs. 346 crores, Rs. 64 crores, Rs. 58 crores and Rs. 31 crores, respectively. The sum of advances guaranteed under the Financial Corporations Guarantee Scheme and Service Co-operatives Guarantee Scheme amounted only to Rs. 4.0 crores²⁴.

203. The Corporation received 1748 claim applications for an aggregate amount of about Rs. 58.0 lakhs up to the end of June 1975. Of this, farmers and agriculturists alone accounted for 1284 applications for an amount of Rs. 47.0 lakhs. Of the total claims received, 68 claims for an aggregate sum of Rs. 2,34,626 were discharged, 33 claims for an amount aggregating Rs. 1,65,989 were rejected. Eighty-four claims for an aggregate amount of Rs. 1,75,146 were withdrawn by the credit institutions, as the borrowers had adjusted their loan accounts subsequently. The remaining claims were being examined. In cases where the Corporation has made payment in respect of a claim, it becomes subrogated to the rights of the credit institution to the extent of such payment. Accordingly, amounts aggregating Rs. 34,275 towards repayments on account of claims paid, were received by the Corporation till the end of June 1975.

204. The exemption given to the ten small-sized scheduled commercial banks in Tamil Nadu and Kerala from the obligation to cover their advances against gold and silver ornaments under the Scheme has been extended up to the end of 1976. Taking into account all relevant factors, the five non-scheduled banks which have joined the Scheme and the one which has tentatively proposed to do so, have also been permitted to exclude such advances from the purview of the Scheme till the end of the year 1976.

(23) Figures relate to 70 banks out of 73 scheduled commercial banks which have joined the Scheme. Figures relating to 9 banks are provisional; 3 banks have not submitted the returns.

(24) Figures relate to 12 Financial Corporations and 4 scheduled commercial banks.

205. It may be recalled that in 1972 the Corporation constituted a Working Group to examine the feasibility of extending the guarantee schemes to co-operative credit institutions. The Group has submitted its report wherein it has recommended that it may not be practicable or necessary at this stage to cover the risk in respect of credit provided through co-operative banks and agricultural co-operative credit societies. However, it has suggested that credit facilities of certain non-agricultural societies could be covered. The recommendations of the Group are being considered by the Corporation in consultation with the Reserve Bank.

Deposit Insurance Corporation

206. During the year under review, coverage of the Deposit Insurance Corporation was further extended. One new commercial bank viz., Sonali Bank, Calcutta was registered as an insured bank. As a result, the number of insured commercial banks increased from 80 to 81.

207. The insurance scheme has been extended to the co-operative banks in the Kerala State and the Union Territory of Pondicherry. Thus, at present 513 eligible co-operative banks in the States of Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra and the Union Territories of Delhi, Goa, Daman and Diu and Pondicherry are covered by the Scheme. Since West Bengal, Karnataka and Tripura have already amended their respective co-operative societies Acts suitably, the Deposit Insurance Scheme would be extended, in due course, to eligible co-operative banks in these States. To meet the commensurate establishment expenses with the increased volume of business following the extension of the Scheme to more co-operative banks, the capital of the Corporation which is held entirely by the Reserve Bank, has been raised from Rs. 1.50 crores to Rs. 2 crores with effect from January 1, 1975.

Control Over Non-Banking Companies

208. During the year under reference, more powers were vested with the Reserve Bank to exercise control over non-banking institutions receiving deposits from the public and financial institutions under the Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1974 which came into force on the 13th December 1974. The amendments :

- (a) empower the Reserve Bank to inspect non-banking financial institutions whenever such inspection is considered necessary or expedient by the Bank ;
- (b) cast a statutory obligation on the auditor of a non-banking institution to report to the Reserve Bank the aggregate amount of deposits held by it where the institution had failed to furnish the return etc., required to be submitted by it ;
- (c) insert the definition of the term 'deposit' in the statute itself so as to place beyond any doubt that any money received by non-banking institutions otherwise than by way of share capital constitute deposits ;
- (d) make the definition of the term "financial institution" precise and comprehensive so as to plug the loopholes ;
- (e) make it compulsory not only for non-banking institutions but also for brokers to disclose full particulars and information before soliciting deposits and
- (f) provide for enhanced penalties for contravention of the provisions of the Act and the directions issued by the Bank.

209. The ceiling of 25 per cent of the paid-up capital and free reserves less the balance of accumulated loss, if any, imposed by the Reserve Bank with effect from January 1972 in respect of deposits accepted by non-banking companies in the form of unsecured loans guaranteed by the directors, deposits raised from shareholders (excluding those received by private companies from their shareholders subject to certain stipulations) etc., has been lowered by the Bank to 15 per cent with effect from the 27th January 1975, by issue of three notifications amending the directions

in force. Non-banking financial and non-financial companies having deposits in excess of the reduced ceiling have been given time till 31st December 1975 to wipe out the excess. Miscellaneous non-banking companies viz., those conducting prize chits/lucky draws/savings schemes etc., which are allowed time upto the end of September 1976 to wipe out excess over the ceiling of 25 per cent fixed earlier have been allowed further time upto the 31st December 1976 to bring down their outstandings in respect of the unsecured loans, etc. within the reduced ceiling of 15 per cent.

210. The Companies (Amendment) Act, 1974 which came into force from the 1st February 1975 has inserted a new section 58A in the Companies Act, 1955 regulating acceptance of deposits by non-banking companies. Under the powers vested in terms of the aforesaid section, the Central Government have, in consultation with the Reserve Bank, framed Rules governing acceptance of deposits by non-financial companies. The Rules came into force with effect from the 3rd February 1975. Consequently, the directions issued by the Reserve Bank to non-financial companies have since been withdrawn.

211. The total number of reporting companies under the Survey of Deposits with Non-Banking Companies for the year ended 31st March 1972 was substantially higher at 3155 as compared to 2240 reporting for the previous year's Survey. The number of reporting non-financial companies increased by 762 to 2234 during the year 1971-72 while the number of reporting financial companies increased by 153 to 921. The number of accounts reported both by financial and non-financial companies increased from 8.16 lakhs at the end of March 1971 to 10.70 lakhs at the end of March 1972. The total amount of deposits (including exempted loans not counting as deposits) also recorded a sizeable increase of Rs. 123.1 crores to Rs. 691.8 crores at the end of March 1972 as against Rs. 568.7 crores at the end of March 1971. Of the total of Rs. 691.8 crores, the bulk (Rs. 480.8 crores) of the deposits and exempted loans are with the non-financial companies and the balance (Rs. 211.0 crores) with financial companies. The total amount of deposits outstanding with non-banking companies increased during 1971-72 by Rs. 187.7 crores. This increase in deposits was partly offset by a decline in exempted loans by Rs. 64.6 crores.

212. A relatively small number of large non-banking companies with outstanding deposits and exempted loans of more than Rs. 25 lakhs each accounted for the bulk of deposits and exempted loans. Thus, out of 3155 reporting companies, 490 companies accounted for 75.3 per cent of the total deposits and 78.2 per cent of the outstanding deposits and exempted loans.

213. The reporting companies were mainly concentrated in the States of Maharashtra, West Bengal and Tamil Nadu. The non-banking companies in these three States accounted for about 71 per cent of the total outstanding deposits and exempted loans at the end of March 1972.

214. In order to deal effectively with non-banking companies and to take appropriate follow-up action, it has been decided to open Regional Offices of the Department of Non-Banking Companies at Bombay, Bangalore and New Delhi. As a first step in this direction, a Regional Cell of the Department started functioning in Bombay from October 1974. The Cell also provided secretarial assistance to the Study Group on Non-Banking Companies.

215. As mentioned in the last year's Report the Bank had constituted in June 1974 a Study Group to examine in depth the working of the control over non-banking companies and to make suitable recommendations to plug the loop-holes and tighten the regulations wherever necessary. The Study Group submitted its report to the Bank on the 14th July, 1975. The recommendations of the Group were examined by the Bank and its views thereon have since been conveyed to the Government.

III. DEVELOPMENTS IN CO-OPERATIVE BANKING

216. Co-operative banking policy during 1974-75 was particularly directed towards ensuring reduction in regional imbalances by inducing other agencies to fill in the credit

gap and extending higher levels of credit to the small/economically weak farmers. Special emphasis is being laid on restructuring and strengthening of the co-operative credit structure at the base level. The business of these institutions was reoriented in such a manner that it is in tune with the present need for monetary discipline while at the same time it subverts the main objectives of national development.

Cooperative Credit Policy

217. The Bank continued its policy of sanctioning separate kharif and rabi limits, wherever rabi was an important season. Funds were provided on short, medium and long-term basis to co-operative institutions for financing agriculture and cottage and small scale industries. An overall view of the progress of co-operative credit movement during the three years ended 1973-74 and of the Reserve Bank credit to co-operatives in 1973-74 and 1974-75 can be obtained from Tables 24 and 25.

Short-Term Finance

218. In the sphere of short-term finance, financial accommodation was made available to central co-operative banks, as in the previous years, so long as the percentage of their total overdues to demand at the end of the latest co-operative year did not exceed 60. To take care of the rise in the prices of chemical fertilizers, the Bank sanctioned additional credit limits to a number of central co-operative banks for the kharif season during 1974-75. As mentioned in the last Report, the Bank allowed drawings on its credit limits after a specified month in the quarter March to May, if the central banks brought down their borrowings from the state co-operative banks to a stipulated level for each bank. Suitable relaxations were granted in individual cases where banks were unable to comply with this stipulation on account of genuine difficulties.

219. The rate of interest on short-term credit limits for seasonal agricultural operations under Section 17(2)(b) read with Section 17(4) (c)/17(4) (c) of the RBI Act continued to be 1/2 per cent below the Bank Rate, with a provision for grant of a rebate of 1/2 per cent upon fulfillment of the stipulation of linking borrowings with deposit mobilisation. Credit limits to state co-operative banks for agricultural operations against Government and other trustee securities under Section 17(4)(a) of the RBI Act were being sanctioned at 2 per cent below the Bank Rate. Advances under this Section to state co-operative banks for general banking business, however, continued to be sanctioned at the Bank Rate. In order to discourage borrowings for hoarding of produce, the rate of interest on credit limits for marketing of crops including cotton and kapas was increased from the year 1974-75 to 3 per cent above the Bank Rate. Further, for an effective linking of credit with marketing of crops, it was decided that draws on the marketing limit of the Bank would be permitted only to the extent of co-operative dues under seasonal agricultural loans, etc., recovered out of marketing credit.

220. The Bank continued to provide short-term credit limit to the Agricultural Refinance Corporation at the Bank Rate under Section 17(4E) of the RBI Act against the security of special development debentures held by it. There was no change in the basic policy of the Bank governing the sanction of credit limits of state co-operative banks for financing the production and marketing activities of weavers' societies at 1-1/2 per cent below the Bank Rate and credit limits to state co-operative banks at the Bank Rate for financing trading in yarn by apex/regional handloom weavers' societies. The Bank sanctioned credit limits at 3 per cent above the Bank Rate to state co-operative banks for the purchase, stocking and distribution of fertilizers, if the commercial banks did not sanction any or adequate limits for the purpose. During the calendar year 1974, as against the limits of Rs. 28.20 crores sanctioned to seven state co-operative banks for fertilizer business, Rs. 22.45 crores were availed of by five state co-operative banks.

TABLE 24 :--PROGRESS OF CO-OPERATIVE CREDIT MOVEMENT

(Amounts in Rupees Crores)

Type of Institutions	Co-operative Year		
	1971-72	1972-73	1973-74*
(a) State co-operative banks :			
(i) Number	26	26	26
(ii) Owned Funds	103	116	125
(iii) Deposits	330	406	493
(iv) Borrowings from the Reserve Bank of India	211	246	235
(a) Of which, short-term agricultural	153	155	154
(v) Working Capital	731	849	931
(vi) Loans issued	947	1135	1227
(vii) Loans outstanding	553	635	679
(a) Of which short-term agricultural	343	367	351
(viii) Percentage of (iv a) to (vii a)	44	42	44
(b) Central Co-operative Banks:			
(i) Number	341	344	341@
(ii) Owned Funds	226	254	274
(iii) Deposits	510	647	720
(iv) Borrowings from the Reserve Bank/apex bank	358	398	451
(v) Working Capital	1194	1412	1542
(vi) Loans issued	1056	1246	1412
(vii) Loans outstanding	889	1028	1085
(c) Central land development banks :			
(i) Number	19	19	19
(ii) Owned Funds	70	98	110
(iii) Debentures outstanding	880	1015	1146
(iv) Working Capital	1016	1202	1409
(v) Loans issued	146	171	133
(vi) Loans outstanding	729	849	896
(d) Primary agricultural credit societies:			
(i) Number (in thousands)	157	155	156
(ii) Membership (—do—)	32009	33528	36785
(iii) Owned Funds	292	323	355
(iv) Deposits	75	84	90
(v) Borrowings	740	858	944
(vi) Loans issued	615	776	815
(vii) Loans outstanding	858	979	1062

@ Data in respect of nine central banks not available.

* Provisional.

TABLE 25 :—RESERVE BANK CREDIT TO CO-OPERATIVES 1973-74 AND 1974-75

(Amounts in Rupees Crores)

Propose of finance	1973-74 (July-June)				1974-75 (July-June)			
	Limits sanctioned	Drawals	Repay-ments	Out-stand-ings	Limits Sanc-tioned	Drawals	Repay-ment	Out-stand-ings
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Short-term								
(i) Seasonal agricultural operations (at $\frac{1}{2}$ % below Bank Rate) ^a	430.83	619.44*	612.84	151.51*	489.52	811.79	751.15	212.15
(ii) Marketing of crops other than cotton and kapas	40.58	12.09	10.73	1.94	40.30	18.13	19.58	0.49
(iii) Marketing of cotton and kapas ^b		6.55	8.62	0.85		46.94	37.54	10.25
(iv) Purchase and distribution of fertilizers (at 3% above Bank Rate) ^c	2.75	..	28.20	22.45	3.65	18.80
(v) Production and marketing of handloom products (at $1\frac{1}{4}$ % below Bank Rate) ^d	14.49	13.38	16.08	5.03	15.69	29.43	23.37	11.09
(vi) Financing other cottage and small scale industries ^e	0.79	0.47	0.22	0.28	2.52	1.33	0.28	1.33
(vii) Purchase and sale of yarn (at Bank Rate) ^f	0.40	0.30	0.33	..	0.65	0.47	0.43	0.04
(viii) Loans to ARC (at Bank Rate)	15.00	12.86	4.96	11.60	15.00	..	11.60	..
(ix) Against pledge of sugar	22.00	67.12	45.12	22.60
II. Medium-term								
(i) Agricultural purposes (at $1\frac{1}{2}$ % below Bank Rate) ^g	11.77	6.03	10.43	19.91	9.87	4.58	8.83	15.65
(ii) Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas (at $1\frac{1}{4}$ % below Bank Rate)	22.47 ^h	41.26 ^h	20.82 ^h	51.19 ^h	81.32	55.04	21.56	79.10
(iii) Purchase of shares in co-operative sugar factories/processing societies (at Bank Rate) ^g	0.18	0.97 ^h	0.40	1.19	0.53	0.16	0.34	1.01
III. Long-term								
(i) Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions ⁱ	8.02	8.02	5.57	68.00	8.37	8.37	6.37	70.00
(ii) Loans to ARC (at $4\frac{1}{4}$ %/ $4\frac{1}{2}$ % per annum) [†]	23.00	23.00	3.50	54.00	40.00	40.00	5.80	8.20 [‡]

¹. Prior to 1972, purchase and distribution of fertilisers was financed at Bank Rate by the Bank. However, from January, 1972, the interest rate was raised by 2% above the Bank Rate with a view to aligning it to the lending rates of the commercial banks. Again it was further raised by 3% above Bank Rate for 1974. Data relate to calendar year 1972 and 1973.

². Including rephasing.

³. Date relate to financial years.

⁴. Drawn out of last year's limit extended upto June, 30, 1974.

⁵. Including monopoly procurement of cotton.

⁶. At $\frac{1}{2}$ % below Bank Rate from 1973-74 subject to rebate of $1\frac{1}{2}$ per cent as per Rebate Scheme existing under section 17(4) (a) which continued to be at 2 per cent below Bank Rate.

⁷. Data relate to calendar year.

⁸. Revised. A drawal of Rs. 75 lakhs in June, 1974 reported by the Manager, RBI, Kanpur as late as in October, 1974.

[†] The interest rate was raised from $4\frac{1}{4}$ % to 6% from September 9, 1974.

[‡] Position as on 31 March, 1975.

'Unwarranted' Drawals

221. Mention was made in the last Report of the Bank's decision to impose penal interest with effect from July 1, 1974, with a view to discouraging unwarranted drawals on the Bank's credit limits by state co-operative banks and investing the surplus amounts as call deposits with commercial banks at lucrative rates of interest. In pursuance of this decision, suitable ceilings for call deposits with commercial banks have been fixed for each state co-operative bank. These ceilings are fixed normally at about 3 per cent of the total demand and time liabilities of the concerned state co-operative bank subject to an overall liquidity of 35 per cent of the total liabilities with due regard to the pattern of a bank's deposits, requirements of funds and resources potential. If this prescribed limit is exceeded for a period not exceeding 30 days during the calendar year, the bank is called upon to pay a penal interest at 12 per cent per annum for the amount in excess for the actual number of days for which such excess was maintained. A penal rate of 15 per cent is charged if such deposits exceeded 30 days in a year.

Deposits: Interest Rates

222. In order to regulate the interest payable by co-operative banks on deposits, a directive was issued on August 16, 1974 prescribing the minimum rates of interest on savings accounts and term deposits. The minimum rate of interest on saving accounts has been fixed at 5-1/2 per cent per annum while it varies from 3 to 10 per cent per annum on term deposits according to the period of deposit. Subsequently, in terms of the directive issued on November 22, 1974, a ceiling has also been prescribed on the rates of interest payable on savings account and term deposits. The state, central and primary co-operative banks have been permitted to pay interest on deposits upto but not exceeding 1/4 per cent, 1/2 per cent and 1 per cent, respectively, over and above the minimum rates prescribed by the Bank. A ceiling of 1/2 per cent per annum has also been prescribed in respect of interest payable on current accounts, deposits upto 14 days and deposits subject to withdrawal or repayment by notice for a period of 14 days or less.

Deposit Mobilisation: Linking

223. Under the scheme of linking deposit mobilisation with the rate charged by the Bank on the borrowings of central co-operative banks which has been in force since July 1, 1973, the lending rate on credit limits sanctioned by the Bank for seasonal agricultural operations and marketing of crops was fixed initially at 1/2 per cent below the Bank Rate instead of the usual 2 per cent below the Bank Rate; however, a rebate of 1 1/2 per cent was allowed to the concerned banks upon fulfilment of certain conditions. This scheme, introduced on an experiment basis for 3 years, has been extended to 249 banks since 1973-74. The base levels fixed for 1973-74 were continued for the year 1974-75. A concession, however, has been extended to all the central co-operative banks by including their excess involvement in medium-term conversion loans, over and above 15 per cent of the conversion loans, outstanding, for the purpose of granting additional rebate.

224. Under the Interest Tax Act, 1974, scheduled state co-operative banks are liable to pay tax at the rate of 7 per cent in respect of their chargeable interest. The state co-operative banks have thus to suffer a double disadvantage, first by granting rebate to district central co-operative banks at 1 1/2 per cent on most of the borrowings of the central co-operative banks and then paying interest tax on the amount of interest collected without taking into account the rebate. This problem was considered by the Standing Committee on Linking Borrowings with Deposit Mobilisation, at its second meeting held at Bombay on April 4, 1975, and it was decided to modify the scheme with effect from July 1, 1975. The revised scheme, as proposed by the Committee, envisaged that the Bank's rate of interest on loans and advances to state co-operative banks, on behalf of all central co-operative banks for seasonal agricultural operations, would be fixed at 2 per cent below the Bank Rate with effect from July 1, 1975 on : (a) that part of the borrowings of the state co-operative bank which represents the 'base level' borrowings, and (b) the borrowings over and above the 'base level' upto twice the increase in the involvement of the

central co-operative banks out of their own resources in agricultural loans, or to the full extent of increase in the loans granted by it to the small/marginal farmers, whichever is higher. The borrowings of a central cooperative bank in excess of the above amount, if any, will be charged interest at 1/2 per cent below the Bank Rate. The interests charged by state co-operative banks to central co-operative banks will also be on the same pattern.

Maximum Limits on Advances

225. A directive was issued to primary co-operative banks on January 31, 1975 stipulating maximum limits on the total advances a bank may make to a director or directors as a group or to any other single party and also stipulating overall limits in respect of unsecured advances made by a bank to all its members put together. A subsequent directive issued to primary co-operative banks on March 27, 1975 provides a phased programme for reducing the level of unsecured advances within a specified time limit to such primary co-operative banks as had the aggregate of the amounts outstanding as on January 31, 1975 in respect of unsecured advances exceeding the limit stipulated in the earlier directive of January 31, 1975.

Financing Procurement Operations

226. The earlier restrictions on the role of co-operative banks in financing procurement and buffer stocking operations had been modified on receipt of representations by co-operative banks that they may be allowed to participate in this operation. It was decided that co-operative banks might invest their funds in financing procurement operations, but not buffer stocking, subject to certain conditions, the more important of which were that : (i) such finance should not exceed 5 per cent of the bank's time and demand liabilities, or Rs. 1 crore in the case of state co-operative banks or Rs. 50 lakhs in the case of central co-operative banks, whichever was less, (ii) the period of each such drawal should not exceed 6 weeks and (iii) a margin of 25 per cent and 40 per cent should be stipulated against pledge and hypothecation respectively of such stocks, unless the purchases of foodgrains were made or procured at prices fixed by the Food Corporation of India/Government and the incidental costs such as handling, storage and transportation had been settled, when the accommodation could be made at a 10 per cent margin.

Selective Credit Controls

227. Specific directives were issued during 1974-75 to the state/central co-operative banks and 25 selected primary (urban) co-operative banks in Gujarat, Maharashtra and Karnataka for regulating their advances against the security of cotton and Kapas. These directives stipulated minimum margins, rate of interest and the level of credit against these commodities.

Financing Other Sensitive Commodities

228. As part of the general credit control measures, the state and central co-operative banks have been advised to follow certain norms in respect of their advances against foodgrains, oilseeds, vegetable oils (including vanaspati), sugar, gur, khandasari and other sensitive agricultural commodities. Among the norms, mention may be made of the following : (i) Where the amount of such advances to a single party is likely to exceed Rs. 1 crore in the case of a state co-operative bank and Rs. 50-lakhs in the case of a central co-operative bank, prior approval of the Reserve Bank of India should be obtained ; (ii) A minimum margin of 25 per cent and 40 per cent for pledge and hypothecation, respectively, should be maintained in respect of such advances ; however, where these advances are fully guaranteed by the Government, the banks may reduce the margins to 10 per cent and 20 per cent, respectively ; (iii) A minimum rate of 13 per cent may be charged on advances against the security of sugar and foodgrains, while in respect of all other types of agricultural produce, the minimum rate of interest should be 14 per cent and (iv) The minimum period of such advances granted to marketing societies should not normally exceed 90 days.

229. Similarly, all the primary (urban) co-operative banks in Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu have been instructed to scrutinise the proposals for advances against the above commodities rigorously and to keep close watch on all such advances particularly those in excess of Rs. 10,000

per member. The primary banks have been advised to observe the following conditions : (i) No advance to a member against any of the above commodities should exceed 100 per cent of the highest outstanding amount against the member in any of the three preceding years, (November-October), viz., 1973-74, 1972-73 and 1971-72. Advance to a member who had not borrowed during any of these three years should not exceed Rs. 20,000, (ii) A minimum rate of interest of 15 per cent should be charged on such advances, (iii) A minimum margin of 40 per cent in respect of advances against pledge/hypothecation of the relative stocks of any of these commodities should be maintained, (iv) Advances granted by a bank against the above commodities to the manufacturing units and other borrowers (including small-scale industries) who have borrowed from that bank during the last 3 years, which are covered by credit guarantee scheme of the Credit Guarantee Corporation of India subject to a maximum of Rs. 20,000 for each such limit are exempt from requirements relating to the level of credit and margin to be maintained as stipulated under items (i) and (ii) above. It may, however, be mentioned here that in March 1975, exemption was granted from these stipulations in respect of credit granted by these banks against the security of stocks of oilseeds and oils thereof to wholesale and retail dealers appointed/licenced by the Government and/or rating under statutory rationing/fair price distribution system to the extent of the quantum meant for public distribution.

Credit Authorisation Scheme

230. In the context of the increasing demand for term loans from co-operative banks for block capital purposes for financing the setting up of a large number of sugar factories, spinning mills etc., in the co-operative sector, it was felt necessary to introduce certain discipline in the term loans of these banks. Accordingly, the state and central co-operative banks were directed in September 1974 to seek the authorisation of the Bank in writing before providing finance to their members beyond specified amounts by way of term loans, interim finance or before making financial commitments in the form of opening letters of credit or any such agreement to finance or give guarantee in excess of Rs. 25 lakhs for block capital purposes to any manufacturing or processing unit.

Credit Guarantee Scheme.

231. Till June 1975, 9 state co-operative banks, 68 central co-operative banks and 48 primary urban banks (42 unlicensed and 6 licensed) satisfying the norms laid down by the Government of India had joined the Scheme by executing the necessary agreement.

232. The Working Group constituted by the Credit Guarantee Corporation of India to examine the question of extending the guarantee schemes to cover agricultural loans of co-operative banks and societies submitted its report in February 1975. The Group did not favour such extension and suggested that so far as direct financing of agriculturists is concerned, the present position may be continued. The Group has further suggested that the position in this regard may be reviewed after a period of five years.

Coir Co-operative in Kerala

233. The Scheme for restructuring the coir co-operative societies in Kerala on the lines earlier suggested by the bank was launched in January 1975. The Bank has agreed to provide institutional finance for working capital purposes to the primary coir societies and central coir marketing societies which are identified as viable and potentially viable. The Scheme envisages (i) conversion of the existing primary coir societies into production-cum-sales societies, and (ii) provision of assistance by the State Government to viable and potentially viable societies for a period of three years to enable them to switch-over to institutional finance in a phased manner. Following an agreement reached with the Government of Kerala, the Bank has already opened a line of credit to co-operative banks in January 1975 by sanctioning to the Kerala State Co-operative Bank on behalf of 8 central co-operative banks, credit limits for the year 1974-75 aggregating Rs. 1.25 crores comprising Rs. 42 lakhs for financing 21 primary coir societies identified as viable, Rs. 55.50 lakhs for 4 central coir marketing societies and Rs. 27.60 lakhs for financing 8 manufacturing societies.

Sericulture in Karnataka

234. On the basis of the study conducted by the Bank on the crash programme launched by the Government of Karnataka for providing credit facilities to sericulturists, silk reelers and others in the State, the Bank has agreed to sanction long-term loans to the Karnataka Government not exceeding Rs. 50,000 per society for contributing to the share capital of the societies. The societies are expected to be financed mainly by the commercial banks in the State which may be refinanced by the Agricultural Refinance Corporation. So far, 67 societies have been established as against 125 to 150 contemplated under the programme. However, actual financing of the societies is still to be taken up.

Industrial Societies : Re-organisation

235. The survey to identify industrial units into viable/potentially viable units has been completed only in respect of seven States/Union Territories viz., Gujarat, Haryana, Maharashtra, Punjab Rajasthan, Nagaland and Tripura. The survey work is in progress in the States of Tamil Nadu, Bihar Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and West Bengal. However, no survey has been taken up so far in the States of Kerala, Orissa and Assam. In the case of Karnataka, the survey has been completed only in respect of weavers' societies. In Andhra Pradesh, the State Government is expected to lay down norms and conduct a survey shortly on the basis of the study report sent by the Bank. The re-organisation of industrial co-operative banks in Gujarat, Karnataka, Rajasthan and Tamil Nadu is still in progress.

236. In December 1974, state/central co-operative banks have been allowed to enroll individuals as members with a view to opening a line of institutional finance to those small-scale industrial units which might not be availing of such facilities due to non-existence of urban co-operative banks in that area. The Registrars of Co-operative Societies have also been advised to move State Governments to make suitable amendments in the State Co-operative Societies Act/Rules, if any legal impediments stood in the way of central/State co-operative banks in this regard. This may be helpful to co-operative banks in availing of refinance facilities provided by the Bank through state co-operative banks.

Medium-Term Finance

237. There was no change in the Bank's policy in regard to sanctioning of credit limits for medium-term agricultural purposes except that it was decided to treat loans to identified small farmers for the purchase of bullock-carts as an easily identifiable productive purpose. The Bank has agreed to treat medium-term loans granted by co-operative banks to agriculturists for setting up gohar gas plants as an 'approved purpose' eligible for refinance. The Bank continued to provide facilities for conversion of short-term loans into medium-term loans, whenever necessary.

Handloom Finance

238. The Bank continued to provide financial accommodation to state co-operative banks under Section 17(2)(bb) read with Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act for financing the production and marketing activities of handloom (cotton, silk and woollen) and powerloom weavers' societies at a concessional rate of 1½ per cent below the Bank Rate, i.e., 7-1/2 per cent at present. The finance was provided with the stipulation that the rate of interest charged to the handloom weavers, societies should not exceed 7½ per cent or such other rate of interest as may be fixed by the Government of India from time to time (in view of the interest subsidy of 3 per cent provided by the Government of India to handloom cotton, silk and woollen societies) and in the case of powerloom weavers' societies, the rate of interest charged should not be unreasonably high (interest subsidy is not available to powerloom societies).

239. The High Powered Study Team constituted by the Government of India in December 1973 to go into the problems of the handloom industry and the weavers in order to suggest a programme for development of this sector in the Fifth Plan period, submitted its report in July, 1974. The Team, while upholding the present system of fixing credit limits by the Bank for financing the weavers' societies under its scheme for handloom finance, has also recommended for

the Bank's consideration, upward revision of the limits sanctioned to new societies or dormant societies to be re-activated. The matter is already engaging the attention of the Bank. On its other recommendation that the Bank should give facilities for medium-term financing to the weavers to enable them to contribute to the share capital of co-operative spinning mills, the Bank has extended assistance in January, 1975, by way of medium-term loans to members of powerloom weavers' societies through the central banks and to individual powerloom owners through primary (urban) banks, for purchase of shares in the consumer type of co-operative spinning mills under Section 17(4 AA) read with Section 46A(2)(b) of the Reserve Bank of India Act. The accommodation will be at the Bank Rate and against the guarantee of the State Government. The question of extending similar assistance to handloom owners is engaging the attention of the Bank.

Long-Term Finance

240. The Bank continued its policy of sanctioning loans to the State Governments from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund for contributing to the share capital of various types of co-operative credit institutions, as also the usual concessions to institutions operating in SFDA/MFAL/Tribal Areas and in areas where the scheme of financing of primary agricultural credit societies by commercial banks was in operation and in the case of banks which had been brought under a scheme of rehabilitation. Besides, the Bank agreed to sanction share capital loans on behalf of primary agricultural credit societies having full-time paid secretaries appointed from a cadre maintained by a central co-operative bank or a district society formed for the purpose, provided their overdues did not exceed 50 per cent of demand. Loans aggregating Rs. 8.37 crores were advanced to 16 State Governments for contribution to the share capital of 3 state co-operative banks, 69 central co-operative banks, 2252 primary agricultural credit societies, 2 central land development banks, 55 primary land development banks and 11 urban banks; the outstanding on this account as on 31st March 1975 amounted to Rs. 70 crores.

241. The facility of graded rate of interest on long-term loans sanctioned to the State Governments for contribution to the share capital of co-operative credit institutions has been withdrawn from April 1, 1974 and it has been decided to charge a flat rate of 6 per cent per annum on such loans. The outstandings of the advances made to the State Governments up to the close of business on March 31, 1974, however, would be continued to be charged at the rate of interest at which these were made until they are due for re-payment.

242. The Bank also sanctioned to the Agricultural Refinance Corporation long-term accommodation of Rs. 23 crores from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund during 1973-74 and Rs. 40 crores during 1974-75 (Table 25). The rate of interest on such loans was raised from 4½ per cent to 6 per cent on September 8, 1974.

Land Development Banks

243. For the financial year 1974-75 aggregate ordinary lending programme of Rs. 125.23 crores was fixed for the central land development banks (CLDBs); this was to be financed to the extent of Rs. 18.51 crores from the bank's internal resources, Rs. 4.33 crores through the issue of rural debentures/ fixed deposits and Rs. 102.39 crores by way of floatation of ordinary debentures. The CLDBs actually floated debentures for Rs. 66.67 crores and collected subscription amounting to Rs. 68.33 crores, of which Rs. 45.59 crores were contributed by the Life Insurance Corporation of India, the State Bank of India Group, other commercial banks and the Central and State Governments. There was a significant shortfall in the fulfilment of the debenture floatation programme for the year 1974-75 on account of the introduction of the IDA scheme in various States and the consequent shrinkage in the scope for lending under the normal programmes. The lending programme of the state land development banks for the financial year 1975-76 was approved at Rs. 229.55 crores—Rs. 119.80 crores to be financed under special scheme of the Agricultural Refinance Corporation and Rs. 109.75 crores under normal loans. The normal lending programme is expected to be financed from out off (i) International resources of banks (Rs. 26.62 crores) (ii) Rural debentures/ fixed deposits (Rs. 3.38 crores) and (iii) Ordinary debentures (Rs. 79.75 crores). But

owing to resource constraints, it may not be possible to allow the banks to issue ordinary debentures beyond Rs. 72.50 crores. With 10 per cent excess contributions that will be allowed to be retained by the land development banks the aggregate ordinary debentures that could be issued would be Rs. 79.75 crores. The CLDBs are expected to canvass contributions by way of self-help to the ordinary debentures to be issued by them during 1975-76 to the extent of Rs. 5.23 crores. For the balance of Rs. 67.27 crores support is assumed to be available from the different sources as indicated below :

(Amount in Rupees Crores)

Source	Support allotted
1. Sinking funds of LDBs (mutual support)	29.27
2. Central and State Governments	12.00
3. Institutional agencies	
(i) LIC of India	12.00
(ii) Commercial Banks	10.00
(iii) SBI Group	4.00
	67.27

244. As against the approved ordinary debenture programme for the financial year 1975-76, the proposals for floatation of ordinary debentures were received from Tamil Nadu and Haryana State Land development banks in May 1975; these were approved by the Bank to the extent of Rs. 130 lakhs and Rs. 50 lakhs, respectively, with option to retain 10 per cent of excess subscription.

245. The Bank continued to lay emphasis on the production-oriented system of long-term lending and insisted that at least 90 per cent of the loans issued by the banks during 1975-76 (including those issued under the ARC—refinanced schemes/ IDA projects wherever operating) will have to be for productive purposes, of which not less than 70 per cent should be for identifiable productive purposes.

246. The lending programme of the primary land development bank/branch of central land development bank for the year continued to be determined with reference to the recovery performance of the previous year. With a view to bringing about uniformity in the norms prescribed regarding regulation of advances to primary banks/branches both under normal loaning programme and Agricultural Refinance Corporation—refinanced schemes, a revised formula has been introduced effective from July 1, 1975. According to the new formula primary banks/branches with a recovery performance of 75 per cent and above are allowed an unrestricted lending programme. The programme will be progressively reduced as the percentage of recovery to demand deteriorates so that primary banks/branches where the overdues exceed 60 per cent of demand are not entitled to any lending programme. In order to improve the eligibility of the primary banks/branches the State Government may contribute to the share capital of a primary bank or central land development bank in respect of any of the specified branches. However, such contribution would be reckoned towards reducing the overdues notionally to the extent of 10 per cent of the demand for the year notwithstanding the amount actually contributed. Branches/primaries in which the percentage of overdues to demand exceeds 60 and where there is no contribution to share capital from the Government to enable a notional reduction may be reimbursed by the central land development bank from its own resources provided the loans so advanced by that bank are taken out of the mortgages providing cover for ordinary/special debentures to be issued by it in the next 10 years. However, if the overdues of such bank/branch remain at the same level but do not improve in the following year even this facility i.e., the reimbursement by central land development bank from its own resources will not be allowed.

247. The terms and conditions for floatation of ordinary debentures by the CLDBs have been revised. Hitherto they had been issuing ordinary debentures in three maturity patterns of 10, 12 and 15 years. Having regard to the institutional investors' preference for 10 years debentures, it has been decided

to float ordinary debentures in two patterns having a maturity of 10 and 15 years, respectively. The rate of interest on both the types of debentures is 6.25 per cent, with the issue price of Rs. 98.85 and Rs. 97.50 for 10 and 15 years debentures, respectively.

248. The important policy changes effected during the year were as follows :

(i) The rates for acceptance of fixed deposits by the CLDBs were increased to 8 per cent in respect of deposits for one year and exceeding one year but upto two years. The banks were advised that it may not be worthwhile to accept deposits for a period exceeding one year. With a view to enabling the CLDBs to offer competitive rates, it was further decided that from July 25, 1974 the CLDBs may pay interest on deposits for one year (a) at the headquarters of the CLDB at the higher rates, if any, offered by the State Co-operative Bank and (b) at their branches or the offices of primary land development banks at the higher rates, if any, offered by the central co-operative banks in whose area the primaries/branches are situated. (ii). The CLDBs are permitted to invest up to 60 per cent of the sinking fund in land development bank debentures and up to 20 per cent in fixed deposits with state co-operative banks/commercial banks and not less than 20 per cent in Government and other Trustee Securities (excluding debentures of land development banks) as per the instructions regarding investment of sinking funds of the CLDBs. In view of the decrease in the floatation of ordinary debentures, the scope for investment of sinking fund in the debentures of sister institutions is progressively shrinking. It has, therefore, been decided that the CLDBs may be permitted, as a transitional measure, to invest upto 30 per cent of their sinking fund in fixed deposits with the state co-operative bank/commercial banks and up to 50 per cent in the debentures of land development banks. (iii) Some of the CLDBs had a legacy of overdues pertaining to old loans which had remained uncollected for a period of 5 years or even more. In view of the difficulties faced by the banks, it has been decided that the primary land development banks/branches of the CLDBs, if they so desire, may segregate overdues of 5 years and more into a separate account and exclude the same from the total overdues while calculating the percentage of overdues to demand. Every year 20 per cent of the blocked amount may be treated as demand for the year. They will, however, have to make full provision for the reserves for bad and doubtful debts to cover the shortfall if any in the recoveries against this demand. The object of this relaxation is to ensure that at the end of 5 years the banks should have either recovered the entire amount segregated as blocked amount or would have made adequate provision to cover the full amount not recovered under this procedure. (iv) With a view to mitigating the hardships caused to the borrowers of long-term loans for purchase of tractors, revised guidelines have been issued. These guidelines specify the norms for minimum work load necessary, the extent of land to be possessed by borrowers, the maximum quantum of cushions that were to be taken into account while working out the economics, etc.

Committee on Co-operative Land Development Banks

249. The Committee on Co-operative Land Development Banks constituted in April 1973 by the Governor to examine the working of land development banks submitted its report on December 31, 1974. The Committee has recommended integration of the short-term and long-term credit structures in Assam, West Bengal, Tripura, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Pondicherry in order to improve the efficiency of the co-operative credit structure. Pending integration of the two structures the State Governments are advised to take certain measures to improve the financial and operational efficiency of the land development banking structure in these States. One of the important recommendations of the Committee for facilitating lending to small farmers is to give up the mortgage security for loans provided by banks by amendment to the existing statute relating to land development banks. The Committee has, inter alia, made detailed recommendations regarding the strengthening of the federal and unitary structures of land development banking, the arrangements for provision of long-term agricultural credit in smaller States, the arrangements for co-ordination between land development

banks and other institutions, the financing of small farmers, the resources for land development banks and overdues in the banks. Besides, the Committee has made several recommendations regarding the recruitment and training of management personnel in the banks ; the implementation of this recommendation may necessitate expansion of the existing training facilities at the College of Agricultural Banking at Poona as also the training centres run under the auspices of the Committee on Co-operative Training.

Structural Changes at the Primary Level

250. In line with the trends in current thinking about provision, at a single point, of credit as well as agricultural inputs and technical guidance at the primary level, a high level expert Group headed by the Union Minister for Industry and Civil Supplies, Shri T. A. Pai has laid emphasis on building up of viable and well-managed multi-purpose societies responsive to the needs of small/marginal farmers on the basis of a definite policy and programme on the part of the State Governments, commercial banks and co-operative societies. The Group observed in this context that while farmers' service societies, as recommended by the National Commission on Agriculture, would be ideal for the purpose, they cannot be set-up all over the country in view of the complex organisational problems that arise from amalgamation of a large number of existing societies and the consequent requirements of high level managerial competence.

251. The Group, therefore, has recommended that the aim should be to reorganize multi-purpose societies and take them ultimately to the level of farmers' service societies. A review, however, of the performance of agricultural credit societies revealed that inadequate attention was bestowed upon the programme of reorganisation of these societies. This issue was, therefore, referred to the Agricultural Credit Board at its meeting held on December 24, 1974. The Board has recommended that a definite time-bound programme of reorganisation of primary credit societies in each State should be drawn up immediately and got accepted by all the concerned agencies. The programme should lay emphasis not so much on liquidation or amalgamation, as in the past, but on identification of societies which should be retained and strengthened financially and administratively so that they could serve their respective areas more effectively. The State Governments have, therefore, been advised to conduct block-wise surveys of the number of societies vis-a-vis the credit potential and draw up a complete blue print of action for re-organisation of societies in the ensuing months.

Unification of Short, Medium and Long-Term Credit

252. Another major structural reform now being considered relates to an eventual integration of the short-term and the long-term credit structures, in view of the dwindling scope for long-term credit on the one hand and the emphasis on the integrated development programmes on the other. Both the National Commission on Agriculture and the Banking Commission have suggested such an integration of short, medium and long-term credit. The Pai Group has also recommended that attempts should be made, initially in the comparatively backward States, to merge the Central land development banks with the State co-operative banks to form one strong apex financing institution in the co-operative structure. The idea of having such a unified co-operative banking structure has already been accepted for some smaller States and Union Territories like Nagaland, Delhi and Goa where there are at present unitary structures. The Agricultural Credit Board which considered the subject at its meeting held on December 24, 1974, was of the view that whereas such an integration at all levels could be considered in smaller States, unification at the primary level, could be considered for other States as well. For this purpose, the Board has suggested that strong and sound primary agricultural credit societies should be identified for undertaking the dispensation of not only short and medium-term but also long-term credit. The Board recommended that the reactions of the State Governments to the proposals may be ascertained. The Bank has taken up both the items relating to the structural changes with the State Governments.

Finance to Weaker Sections

253. The efforts of the Bank to deliberately reorient lending policies of co-operative banks in favour of small farmers continued during the year under review. With a view to ensur-

ing strict compliance with the Bank's instructions that each central co-operative bank should have at least 20 per cent of its borrowings from the state co-operative bank covered by the outstanding loans to societies against farmers belonging to the small/marginal/economically weak farmers, the Bank reduced the level of free operations on the credit limit from the bank from 70 per cent to 60 per cent of limits in some cases, drawals on the remaining portion being permitted after full compliance with the condition regarding advances to the weaker sections. From 1975-76, for the purpose of satisfying the stipulation, the basis of fresh loans issued by a central co-operative bank to primary credit societies for financing such farmers during the concerned year has been adopted.

Farmers' Service Societies

254. Prior to the recommendations of the Pai Group, an experiment had already been launched to organise farmers' service societies as recommended by National Commission on Agriculture; 69 societies are reported to have been registered in 12 States till March 31, 1975, of which as many as 39 societies were in Karnataka. Out of the 69 societies, 26 are to be financed by commercial banks and the others by co-operative banks. The progress made in organising farmers' service societies, however, has been somewhat tardy. Certain essential pre-conditions in the way of decisions regarding the future status of other existing societies in the area and provision of managerial and technical support to the societies were not complied with in the case of the societies organised. Consequently, the Bank has not so far been able to sanction share capital from the Long-term Operations Fund to the societies where applications had been received.

Finance to Scheduled Castes/Tribes

255. Of late there has been a move in several States to set up parallel co-operative credit institutions or corporations to cater exclusively to the credit needs of particular classes of individuals such as scheduled castes, scheduled tribes etc. The corporations registered as co-operatives or companies with substantial share capital contributed by the Government would, however, have to rely primarily on the co-operative and commercial banks for funds. The Bank's views in the matter which have been conveyed to the State Governments and other concerned interests, particularly co-operative and commercial banks, were broadly in favour of absorbing persons belonging to scheduled castes/tribes as members of the existing societies, instead of having distinct co-operative societies for these communities. The Bank was agreeable to the setting up of corporations for the benefit of these communities providing such agencies undertook promotional activities and/or marketing operations and did not perform any credit function.

SFDA/MFAL Schemes

256. Till the end of April 1975, as many as 46.36 lakhs small and marginal farmers and agricultural labourers were identified as eligible for benefits under the 46 SFDA and 41 MFAL projects. Of these, 23.70 lakhs were enrolled as members of co-operatives. During the year 1974-75 (upto April 30, 1975) short-term loans to the tune of Rs. 28.33 crores were disbursed to these members through co-operatives and Rs. 3.17 crores was disbursed through commercial banks. In addition, medium-term and long-term loans to the tune of Rs. 72.26 crores have been issued to them since the inception of these projects. The term-loans advanced by commercial banks during the same period were to the tune of Rs. 17.30 crores.

257. During the Fifth Five Year Plan the programme would be extended to cover 160 districts including those with the existing projects. Each project will be confined to one revenue district covering 50,000 beneficiaries. The distinction between the small farmers and marginal farmers agencies has been abolished and there will be a combined agency known as the Small Farmers' Development Agency. In view of the emphasis in the Fifth Plan on development of persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes, the agencies are expected to adopt a positive approach to extend benefits of the projects to these classes.

Commercial Banks' Finance for Credit Societies

258. The scheme of financing primary agricultural credit societies by commercial banks which was in operation in 8 States at the end of 1973-74 was extended to two more States, viz., Maharashtra and Bihar from the Kharif season of 1974. Thus at the end of June 1975, the Scheme was under implementation in 10 States viz., Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal. The Scheme is proposed to be introduced in Rajasthan also and procedural formalities regarding selection of areas and transfer of societies to commercial banks are being completed. Twenty-one commercial banks were participating in the Scheme through 360 branches in the 8 States other than Bihar and Maharashtra about which details are not yet available. In all, 2683 primary agricultural credit societies were taken over, of which 1666 were provided short-term loans aggregating Rs. 1071.79 lakhs for Kharif 1974 and Rs. 281.90 lakhs for rabi 1974-75 (till March 31, 1975). Besides, the banks had disbursed medium-term loans for investment in agriculture aggregating Rs. 67.20 lakhs to 305 societies (upto March 31, 1975). Since the introduction of the Scheme, 1.79 lakhs new members were admitted in the societies taken over by commercial banks, bringing the total membership to 5.15 lakhs at the end of December 1974. The average increase in membership per society worked out to 88 for all the States taken together. However, the borrowing membership was only 2.34 lakhs which formed 45 per cent of the total membership.

259. The recovery performance of commercial banks in respect of loans granted to societies, however, showed only marginal improvement with the recoveries during 1973-74 forming 58 per cent of the demand for the year as compared with 56 per cent during 1972-73.

260. In the context of the expanding role of commercial banks in providing finance for agriculture on a long-term basis, both through co-operatives and directly to individuals, and of the need for bringing about a co-ordination and uniformity in regard to policies and procedures followed by the commercial and co-operative banks, the Agricultural Credit Board of the Bank constituted a 'Standing Committee on Co-ordination between Co-operative and Commercial banks in Financing Agriculture'. The role of commercial banks in the sphere of rural credit was also examined by the Pai Group about which a mention was made earlier. The Group has observed that it would not be possible for rural branches of commercial banks, at their present level of operational costs and organisational constraints, to provide a package of service to farmers without an effective link-up with an institutional intermediary such as the multipurpose agricultural credit society. The Group has therefore, recommended that commercial banks should very carefully assess the situation before they decide to open rural branches below the mandi level. Their first attempt should be to find or organise viable multipurpose societies in the area or a cluster of such viable societies. The areas in which the central co-operative banks are capable of operating and where commercial banks are to be inducted for filling in the credit gaps are to be identified and the Reserve Bank has to arrange meetings with representatives of the State Governments and future follow-up action. This aspect of the work is being pursued.

Weak Co-operative Banks : Rehabilitation

261. On the basis of their financial position as on June 30, 1974, 144 central co-operative banks in 16 States were under the programme of rehabilitation, apart from 2 banks in Maharashtra and 1 each in Rajasthan and West Bengal which were under rehabilitation on account of operational weaknesses in their working. Besides these central co-operative banks, 4 state co-operative banks viz., Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Delhi functioning in areas served by the two-tier credit structure totally or partially, were also brought under the programme of rehabilitation. The banks have been advised to take suitable steps for their rehabilitation as per the guidelines issued by the Bank.

262. Under the Central Sector Plan Scheme the Government of India had agreed to provide assistance aggregating Rs. 237.89 lakhs in respect of 71 central co-operative banks

in 7 States for writing off their bad and doubtful debts, accumulated losses and other overdues over three years. Till June 30, 1975, the Government of India had released to the State Governments a sum of Rs. 161.98 lakhs as their share of assistance on behalf of the concerned central co-operative banks. The Manipur and the Tripura State Co-operative Banks have been approved for central assistance and by June 30, 1975, a sum of Rs. 4.40 lakhs has been released by the Government of India in respect of these banks.

263. The programme of rehabilitation of primary co-operative banks, primary land development banks/branches of the central land development banks continued during the year 1974-75. Based on their financial position as on June 30, 1973, 28 primary co-operative banks, 92 primary land development banks and 18 branches of the central land development banks were under the rehabilitation programme.

Removal of Regional Imbalances

264. As mentioned in the last year's Report, a New Central Sector Plan Scheme has been drawn up by the Government of India for providing assistance to central co-operative banks in group C States for meeting the expected deficits in their resources required to cover the overdues. The assistance is in the form of a term loan to be shared equally by the Central and State Governments to state co-operative banks which would use the amount to augment the internal resources of specified central co-operative banks. The Planning Commission have agreed to an outlay of Rs. 14 crores during the Fifth Five Year Plan with a matching amount to be provided by the concerned State Governments. The loans under the scheme will be for a period of 9 years, with a moratorium for the first 3 years. The rate of interest prescribed by the Ministry of Finance from time to time for loans to State Governments will be applicable on these loans and the funds are to be passed on to the central co-operative banks at the same rate.

265. The Scheme is being implemented with effect from the financial year 1974-75 during which the Central Government allocated a sum of Rs. 75 lakhs for providing assistance to 18 banks in 6 States.

Growth of Weak Urban Banks

266. In recent year, a large number of small urban co-operative banks have come under the purview of the Banking Regulation Act. The number of primary co-operative banks in the country which was 403 as on March 1, 1966 when the Banking Regulation Act was extended to co-operative societies had increased to 877 at the end of September 1974. Of these, as many as 718, i.e., about 82 per cent were concentrated in the States of Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Out of the new banks which came into existence between 1966 and 1974, only 48 obtained licences from the Bank, while the rest (426) belonged to the Category of primary credit societies which were initially organised and registered with a share capital of less than Rs. 1 lakh, but later became primary co-operative banks automatically after having reached or exceeded the level of Rs. 1 lakh. Many such banks were later on found to be unable to comply with even the essential provisions of the Banking Regulation Act, mainly because of inadequate resources and inefficient management. Certain studies conducted by the Bank revealed that societies were being got registered by deliberately keeping the level of share capital at slightly less than Rs. 1 lakh so that they could commence banking business without obtaining a licence from the Bank. In the circumstances it was considered necessary to initiate action which would prevent an unplanned growth of urban co-operative banks at the time of their registration itself. Since the registration of urban co-operative banks is the statutory responsibility of the Registrar of Co-operative Societies, the Bank issued a circular letter to all the Registrars indicating that they might not register an urban bank in any part of the State unless the initial share capital collected was at least Rs. 1 lakh. The objective of this advice was to ensure that new banks did not commence banking business without obtaining a licence from the Bank, which would, while issuing the licence, be led by considerations in regard to the banking needs in the area and the prospects of the applicant bank becoming a viable unit. Simultaneously, the Bank took steps to convert the existing banks into viable institutions

by recommending to the Government of India that the existing provisions of the Banking Laws (as applicable to co-operative societies) Act 1965 should be amended with the following main objectives :—

- (a) All co-operative banks to commence or carry on banking business should have a minimum share capital and reserves of not less than Rs. 3 lakhs.
- (b) Any co-operative society intending to do banking business may commence and carry on such business only after obtaining a licence from the Bank.
- (c) In future, primary credit societies may accept deposits from the public not withdrawable by cheque upto twice their owned funds or Rs. 6 lakhs whichever is less but should not use the words bank, banker, etc., in their names.

267. The Government of India have accepted the proposals and steps are being taken to amend the various Acts.

Study Teams on Overdues

268. (i) The various recommendations of the Study Team on Overdues have been communicated to the State Governments and State co-operative banks for necessary action. These recommendations were also discussed during the State Ministers' Conference held in New Delhi in August 1974 and at the Seminar of the Chief Executives of State co-operative banks held at Poona in September 1974. The need for early implementation of the recommendations had also been impressed on the participants. The follow-up action taken by the various agencies to implement these recommendations is being closely watched.

Agricultural Credit Institutions : Maharashtra

269. (ii) The Study Team's final report submitted on March 24, 1975 reviewed the action taken to implement the recommendations made in the interim report which was submitted in March 1973 and applied itself to the remaining terms of reference, viz., the arrangements for institutional credit for meeting the credit gaps to the maximum possible extent, the lending policies of the State and central co-operative banks with particular reference to the financing of big processing units like sugar factories and spinning mills, the reorganisation of primary agricultural credit societies and the arrangements for their management and supervision.

270. Some of the important points that emerged from the report are: (1) The team had estimated the short-term agricultural credit needs at Rs. 450 crores in 1978-79 for the State as a whole, of which the co-operatives might be able to meet about Rs. 250 crores. The Team felt that the gap of Rs. 200 crores can to some extent be met if commercial banks undertake to provide credit through primary agricultural credit societies in the identified areas where large credit gaps existed. The Team also expected the commercial banks to step up their lendings directly to the farmers in the rest of the State. (2) Taking note of the large investment of nearly 50 per cent of the demand and time liabilities in processing units, particularly sugar factories, the Team has considered it inadvisable for the State co-operative bank to continue to shoulder the burden of meeting block and working capital needs of all co-operative sugar factories in the State and has suggested that the bank should defer for some time its further involvement in loans and advances particularly of a long-term nature to the sugar factories. (3) In the matter of reorganisation of primary credit structure, the Team has recommended that the Government of Maharashtra should undertake re-organisation of primary societies on the basis of viability and potential viability and with an independent, qualified and full-time paid secretary for each such society. The Team has suggested that the re-organisation should be completed by June 30, 1977. The Bank has accepted these recommendations of the Team, with certain modifications, and has recommended them to the State Government, the co-operative and commercial banks for acceptance and speedy implementation.

Agricultural Credit Institutions : Rajasthan

271. (iii) The Study Team on Agricultural Credit Institutions in Rajasthan submitted its report to the Bank in May 1975. The Team considered 10 out of the 25 central co-operative banks in the State as inefficient and potentially non-viable, as their loans outstanding were low. The Team felt that a central bank may be deemed viable if its loans outstanding exceeded Rs. 150 lakhs and potentially viable if they exceed Rs. 100 lakhs. On the basis of potentiality in the area of these banks to reach a level of business of Rs. 150 lakhs and the potentiality to reach a certain level of deposits to sustain a loan business of Rs. 150 lakhs or Rs. 100 lakhs, 2 out of the 10 non-viable banks in the State have been recommended for amalgamation with the state co-operative bank. In the case of the remaining banks, the Team recommended that the State Government should review the position in 1978-79. The Team recommended similar review of the position in respect of another 8 central banks if they fail to reach the level of business of Rs. 200 lakhs by that year. The Team also recommended reorganisation of primary credit structure on the basis of viability with relatively wide jurisdiction subject to a potential for loan business of Rs. 2 lakhs and full-time paid secretary for such society. The Team has recommended organisation of four farmers' service societies and forty special types of societies in tribal areas and completion of the reorganisation by June 1978. The latter recommendation was born out of the Team's conviction that a co-operative society in the tribal area should not only provide term credit for agriculture but also for domestic requirements and social obligations and integrate credit with supplies of inputs, technical guidance and marketing of produce. The Team favoured organisation of a Tribal Development Corporation to co-ordinate and support the non-credit business of primaries and also setting up of a Tribal Development Authority for each district in the tribal area for supervision of projects for the development of tribals. In the arid and semi-arid zones, sheep breeding can help in stabilising and increasing the income of farmers particularly those belonging to economically weaker sections. The Team has recommended issue of medium-term loans for purchase of sheep by the co-operatives and institutional arrangements for marketing of wool and mutton. According to the Team, the short-term credit needs for agricultural in the State by the end of 1978-79 would be Rs. 200 crores of which co-operatives are expected to meet Rs. 95 crores. The Team felt that commercial banks in the State could provide credit through primary agricultural credit societies to the extent of Rs. 25 crores and another Rs. 10 crores by direct financing. The gap of Rs. 70 crores would thus have to be covered in the Sixth Five Year Plan.

Agricultural Credit Institutions : Bihar

272. (iv) At the first meeting of the Team held in April 1974, various proforma for collection of data were finalised by the Team. The Team had also decided upon taking certain studies for eliciting information on specific terms of reference. The work relating to collection of data and studies is in progress.

273. The Bank has decided to undertake in-depth studies of institutional arrangements for agricultural credit in the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Two separate study Teams for the purpose are being constituted.

Co-operative Banking Regulation

274. During the year, licences have been granted to one central co-operative bank and 12 primary co-operative banks under section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies) authorising them to carry on banking business in India. The total number of licenced co-operative banks stood at 73 as at the end of June 1975 as against 60 in the previous year. The number of offices of co-operative banks which stood at 5102 as on September 30, 1973 increased to 6209 (239 offices of state co-operative banks, 4759 of central co-operative banks and 1211 of primary (urban) co-operative banks) as on March 31, 1974. During the period July 1, 1974 to June 30, 1975, 59 licences were granted to state co-operative banks and primary co-operative banks for opening new offices as

against the 76 licences granted during the previous year. During the period July 1, 1974 to June 30, 1975, 752 co-operative banks (20 state, 212 central, 510 urban, 5 state land development, 5 apex weavers' marketing societies) were inspected. Of these, 100 primary (urban) co-operatives were inspected by the officers of the state co-operative banks on behalf of the Bank under section 35(1) of the Banking Regulation Act, 1949. Reports relating to inspection of 16 state co-operative banks, 192 central co-operative banks, 472 primary co-operative banks, 14 state land development banks and 4 apex weavers' marketing societies were issued during the above period. As on June 30, 1975, there were 1494 co-operative banks (28 state, 368 central and 1098 primary) coming under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 as against 1432 co-operative banks as at the beginning of the year.

275. Seven central co-operative banks did not comply with the requirements of the provisions of Section 11(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies). Of these, 4 central co-operative banks were in Assam and a decision to merge them as also the other central co-operative banks with Assam Apex Co-operative Bank Ltd. has been taken by the Assam State Government. Of the 26 primary co-operative banks, which failed to comply with the provisions of Section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies) two banks were under the process of liquidation. A close watch is being kept over the financial position and working of these banks.

Deposit Insurance Scheme

276. During the year 1974-75 the Scheme of Deposit Insurance has been extended to the co-operative banks in the Union Territory of Pondicherry and the State of Kerala with effect from October 1, 1974 and April 1, 1975, respectively. As at the end of June 1975, 513 co-operative banks were registered by the Deposit Insurance Corporation in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jammu & Kashmir, Kerala and the Union Territories of Goa, Daman and Diu, Delhi and Pondicherry as against 423 co-operative banks registered at the beginning of the year. West Bengal, Karnataka and Tripura have passed the necessary amendments to their respective Co-operative Societies Acts, vesting in the Bank the power of supersession, winding up, amalgamation, reconstruction, etc. It is expected that the scheme will be introduced in these States very shortly. The matter is being pursued with the remaining State Governments to expedite amendments to their Co-operative Societies Acts for the purpose of extension of the Deposit Insurance Scheme to co-operative banks in their jurisdiction.

Agricultural Refinance Corporation Operations

277. During the year under review, the Agricultural Refinance Corporation (ARC) disbursed refinance of Rs. 106.4 crores as against Rs. 97.8 crores during 1973-74. The aggregate disbursement of the Corporation since its inception upto the end of June 1975 amounted to Rs. 423 crores. During the year, the disbursement under the IDA projects amounted to Rs. 61.8 crores. The total disbursement under IDA projects over the years amounted to Rs. 187 crores resulting in an inflow of nearly \$ 145 million by way of foreign exchange to the country.

278. During the year, the Corporation sanctioned 623 schemes involving financial assistance of Rs. 236 crores of which the ARC's commitment was Rs. 204 crores. Minor irrigation continued to be the major purpose of refinance accounting for 312 schemes (50 per cent); the Corporation's commitment in respect of these schemes amounted to Rs. 151 crores or 74 per cent of the total commitment. At the same time, the trend in favour of diversification of agricultural investments is gaining ground. Schemes sanctioned during the year for purposes other than minor irrigation numbered 311 involving ARC's commitment of Rs. 53 crores. These cover in particular schemes for dairy development, soil conservation, farm mechanisation, plantations and horticulture, poultry farming, sheep breeding fisheries development and storage and market yards. The Corporation

has also approved, in principle, three forestry development projects in the States of Andhra Pradesh, Bihar and West Bengal. The projects would be financed by commercial banks.

279. Since the inception of the Corporation, the largest drawals exceeding 10 per cent each of the total disbursement were made by the States of Uttar Pradesh (Rs. 58 crores), Tamil Nadu (Rs. 50 crores), Gujarat (Rs. 48 crores) and Maharashtra (Rs. 46 crores). Four other States drew funds between 8 and 10 per cent each of the total, namely, Haryana and Andhra Pradesh (Rs. 42 crores each), Punjab (Rs. 38 crores) and Karnataka (Rs. 35 crores). Disbursement exceeded the previous year's performance in the Northern, Eastern and Central regions, but declined in the North-Eastern, Western and Southern regions. The tempo of lending witnessed in the previous year in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar was sustained. As in the previous year, Uttar Pradesh led the other States in regard to availment of refinance from the Corporation.

Reduction of Regional Imbalances

280. The efforts of the Corporation to promote agricultural development in less developed/under-banked areas are beginning to bear results. The IDA approved during the year, a rural development project covering six districts in West Bengal. Rajasthan has now four IDA-assisted projects, the largest number of specific projects for an individual State. These are in fields other than minor irrigation and with the active support available from the Corporation for minor irrigation investment, the stage is now set for development in the State. In Orissa, the schemes sanctioned during the year with ARC refinance amounted to Rs. 17 crores which will be implemented by the various agencies. In Jammu & Kashmir, the Corporation has decided to associate itself with IDA and the State Government in preparing a scheme for horticulture development. At the end of June 1975, the schemes sanctioned by the Corporation in less developed/under-banked areas aggregated 703 involving financial assistance of Rs. 407.13 crores of which the Corporation's commitment was Rs. 360.29 crores. In numerical terms, the schemes sanctioned by the Corporation in these areas constituted more than one-third of the aggregate sanctions. The Corporation has so far disbursed Rs. 117.35 crores in the less developed/under-banked areas which formed 27.7 per cent of the total disbursements made by the Corporation.

281. Due partly to the efforts made by the Corporation, some of the State Governments in the Eastern and North-Eastern regions have initiated measures towards setting up of plantation development corporations for promoting plantation schemes and forest development corporations for exploitation of various forest resources in their region.

282. The promotional efforts made by the Corporation to achieve a break-through in agricultural investment in the North-Eastern region are being actively pursued. A team comprising officials of the Corporation was set-up to conduct a pre-investment study of the development of horticulture, plantation and forestry in the North-Eastern region with a view to helping the various agencies in formulating concrete proposals for bankable investments in the area. The Team, in its report submitted in April 1975, came to the conclusion that while there is large scope for development of horticultural and plantation crops in the North-Eastern region, actual progress in those States would largely depend on how soon the requisite organisational set up was brought into being. In respect of horticulture, the team has suggested the establishment of a horticultural development and processing company for the region as a joint-sector undertaking so that proper arrangements are made for ensuring quality production and competitive marketing. For tea plantations, the Team has recommended the setting up of a revolving fund in the ARC for providing rehabilitation refinance for sick gardens.

283. A pre-investment survey of piggery development in the North-Eastern region was undertaken by a firm of technical consultants on behalf of the Corporation. On receipt of the report of the consultants, field studies were undertaken by the technical staff of the Corporation in four States, viz., Assam, Meghalaya, Manipur and Nagaland. On the basis of the studies, firm proposals for integrated piggery development have been formulated for the State of Nagaland and Manipur to be implemented through commercial banks.

SFDA Schemes

284. As at the end of June 1975, the total number of schemes sanctioned by the Corporation under the aegis of SFDA/MFAL agencies stood at 104 involving Corporation's commitment of Rs. 43.6 crores; the total disbursements made by the Corporation to the member-banks under these schemes was Rs. 13 crores. The concessional 100 per cent refinance facility available for schemes sponsored under the aegis of these agencies has been extended upto December 31, 1975.

Disbursement of Refinance by Agency

285. Land Development Banks continued to avail themselves of the bulk of the re-finance facilities from the Corporation as in the previous year. In the total disbursements of refinance of Rs. 106.4 crores during 1974-75, the share of the LDBs was Rs. 77 crores which was only marginally lower than the previous year's disbursement of about Rs. 78 crores. The LDBs share in the total disbursements made by the Corporation has, however, come down to 72 per cent as against 79 per cent last year. On the other hand, the position of commercial banks has significantly improved; their recourse to refinance during the year at Rs. 28 crores was almost equal to the total drawals made by them during all the preceding years. Refinance availed of by state co-operative banks recorded a decline and amounted to Rs. 1.5 crores. These institutions depend mainly on the Reserve Bank of India for their requirements of medium term loans for agricultural purposes.

IDA/IBRD Projects

286. During the year, the IDA sanctioned four specific projects, namely, Rajasthan Dairy Development Project, Madhya Pradesh Dairy Development Project, Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project and West Bengal Agricultural Development Project. The Corporation also obtained sanction of the ARC Credit Project by IDA which is in the nature of a general line of credit for supporting the lending operations of the Corporation.

287. Under the Agricultural Refinance Corporation Credit Project, relative agreements of which were signed in April 1975, IDA has allocated a credit of \$ 74 million for a two-year programme of agricultural lending supporting the activities of the Corporation for investments in minor irrigation as well as other diversified forms of lending. In addition a sum of \$ million has been provided for training of senior and middle level staff of financing institutions and other agencies concerned with project lending, for training of junior level staff of LDBs and for a study on the feasibility of merging the short-term and long-term co-operative credit institutions.

288. Unlike the on-going IDA Credit Projects which are separately appraised and sanctioned by IDA for specific investments in particular States, the ARC Credit Project provides for considerable flexibility. It will be, primarily, the responsibility of ARC to identify projects, commit funds and make disbursements related to the progress of the project. ARC will have discretion to deploy funds in areas where investments are considered necessary and feasible. Consequently, the Corporation will be able to extend investments to areas and purposes where separate credits have not been sanctioned so far. In areas where specific IDA projects are under implementation for the same purpose, the ARC will be able to continue the investment after the earlier credits are fully utilised.

289. A distinct feature of the credit is the emphasis placed on promoting the interests of small farmers. About 50 per cent of the credit for minor irrigation and diversified investments viz., \$ 37 million has been earmarked for lending to small farmers. The definition of small farmers has been made more liberal than the existing one. Farmers with a pre-development net income not exceeding Rs. 2000 based on 1972 prices will now be categorized as small farmers. This limit may be adjusted for any subsequent changes in prices by applying the Agricultural Labourers' Consumers Price Index in the State in which the land is situated. In the earlier IDA credit projects, the small farmer was defined as (one) having a post-development income from all sources

not exceeding Rs. 2400 per annum, and the concessions of downpayment and longer maturity period were not to be made available if the cost of investment exceeded Rs. 10,000. There will be no ceiling on the investment cost for lending to small farmers under the ARC Credit Project. The Small farmer's own involvement (including his obligatory purchase of LDB shares, contributions in cash or kind) is limited to the extent of 5 per cent of the investment cost. In order not to burden the other farmers with a large involvement, farmers, including small farmers, have been grouped into three categories: (1) small farmers with a pre-development net income not exceeding Rs. 2000; (2) farmers whose net income ranges between Rs. 2001 and Rs. 3500 and (3) other farmers having net income of Rs. 3501 and above. Their own involvement has been fixed in a progressive manner at 5, 10 and 15 per cent of the cost of investment, respectively.

290. Excluding the ARC Credit Project, the Corporation has negotiated with IDA/IBRD, 21 Credit Projects of which, 11 are for minor irrigation and farm mechanisation, 3 for command area development, 2 for market yards, one for seed production, 3 for dairy development and one for apple processing and marketing. The commitments by the World Bank Group including the ARC Credit Project amount to Rs. 401.5 crores of which the Corporation has drawn Rs. 117 crores.

291. Some more IDA projects are in the pipeline. An IDA Mission visited India in May 1975 for updating the data in regard to the integrated cotton development project. Two World Bank/FAO Reconnaissance Missions came to India at the request of the Government of India to identify the possibility of promoting investments in tree-crops and marine fishery development in the country. In addition, project preparation Missions for a forestry project in Madhya Pradesh, a horticulture project in Jammu and Kashmir and an All India Seeds Project had also visited India.

Important Decisions

292. The Corporation reviewed the position in regard to the interest rates with reference to the general rise in interest rate structure consequent on increase in the Bank Rate in July 1974. It was decided that in respect of all schemes sanctioned on or after August 13, 1974, the Corporation's refinancing rate to the eligible institutions would be 7½ per cent per annum for minor irrigation and land development schemes and 8 per cent per annum for other schemes. The lending rates to be charged to the ultimate borrowers by the member-banks is to be 10½ per cent per annum for minor irrigation and land development schemes and 11 per cent per annum for other schemes. In the case of small farmers, especially in regard to schemes for poultry, dairy and animal husbandry, the banks could charge 10½ per cent per annum, if they so desired.

293. Reference was made in the last Report to the amendment to Section 22(4) of the ARC Act, 1963 which vests powers in the Board of Directors of the Corporation to waive both Government guarantee and 'other security' in respect of refinancing provided to eligible institutions for reasons to be recorded in writing depending upon the merits of cases. Pursuant to this amendment, the Board of Directors of the Corporation decided that depending upon the merits of each case, no Government guarantee or other security need be taken for refinancing facilities granted to the State Bank of India, its subsidiaries and 14 nationalised banks and any other licensed scheduled commercial banks which are shareholders of the Corporation in respect of schemes in which the banks encountered difficulty in creating security in favour of the Corporation. During this year, the Corporation also decided to waive 'other security' and/or Government guarantee in respect of accommodation to be granted to state co-operative banks also, subject to the conditions that (i) the scheme in respect of which such accommodation is sought is technically feasible and economically viable, (ii) the concerned state co-operative bank is a scheduled bank having 'A' class audit classification, (iii) the central co-operative bank and/or primary co-operative credit society or the primary co-operative bank participating in the scheme possesses 'A' class audit classification and has a recovery performance of at least 80 per cent of demand and (iv) the security to be obtained by the co-operatives conforms to the norms prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

Evaluation

294. Mention was made in the last Report to the setting up of a project monitoring and evaluation cell for a continuous study of the projects refinanced by the Corporation. As a part of evaluation work, the Corporation took up studies of four schemes, namely, new dugwells with pumpsets schemes in four taluks of Sholapur district (Maharashtra), installation of shallow tubewells under Karnal I scheme (Haryana), Nagarjunasagar Land Development Project in Miryalguda taluk of Nalgonda district (Andhra Pradesh) and Bhadra Land Development Project in Davanagere and Harihar taluks of Chitradurga district of Karnataka and accordingly has set up four field units. The work relating to the processing/tabulation of the data collected is in progress.

IV. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE

295. The industrial finance scene was characterised by a significant increase in the financial assistance provided by term-lending institutions during 1974-75; while total sanctions rose from Rs. 412 crores in 1973-74 to Rs. 504.0 crores, total disbursements rose from Rs. 274.0 crores to Rs. 364.9 crores (Table 26). The Industrial Development Bank of India (IDBI) and State Financial Corporations (SFCs) accounted for the bulk of the increase in total assistance both in terms of sanctions and disbursements.

296. Further, rupee loans dominated both sanctioned and disbursed amounts, foreign currency amounts forming only a small proportion of the total. Sanctioned assistance by way of underwriting and direct subscription to shares by term-lending institutions showed a marginal increase and sanctioned subscriptions to debentures went up mainly due to IDBI.

Industrial Development Bank of India

297. The year 1974-75 marked the culmination of the exploratory phase of surveys of all backward States and Union Territories. The last one—Survey of Andaman and Nicobar—is under print. In some of the developed States, surveys of relatively backward districts have been taken up by State level agencies. Of the various industrial possibilities identified in the Surveys, 52 projects involving a capital investment of about Rs. 200 crores have either been implemented or are under implementation.

Inter-institutional Groups

298. An inter-Institutional Group (IIG) for Maharashtra started functioning during the year. These Groups now function in 17 States in the country. These IIGs serve as an informal forum for a constructive discussion on problems of industrial development, particularly in the backward areas, of the State. Most of them, by and large, have succeeded in creating an effective machinery for co-ordinating and fortifying efforts of various State-level organisations. Some of their significant activities related to project identification through surveys, identification of entrepreneurs to implement projects, commissioning of project profiles or detailed feasibility studies and co-ordination of project financing efforts, etc. Some of the IIGs have also constituted sub-committees/Screening Committees to deal with specific aspects such as, conducting surveys of selected regions, identification of new projects, formulation of time-bound strategy of implementation and follow-up of identified projects, drawing up schemes for training of entrepreneurs, selecting project ideas for feasibility studies, organising seminars for attracting entrepreneurs, etc. In regard to the entrepreneurship development, the IIGs for Andhra Pradesh, Assam, Kerala, Gujarat and Bihar have initiated steps for organising training programmes while some other IIGs are formulating plans in this direction.

Technical Consultancy Service Centres

299. With the setting up of Bihar Industrial Technical Consultancy Organisation Ltd. (BITCO) at Patna, there are now three technical consultancy service centres; the two others are Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd. (KITCO) at Cochin and North Eastern Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd. (NEITCO), at Gauhati.

TABLE 26 :—ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY TERM FINANCING INSTITUTIONS
DURING 1973-74 AND 1974-75 (APRIL-MARCH)

(Rupees Crores)

Institutions	Sanctions									
	Rupee Loans		Foreign Currency Loans		Underwriting and Direct Subscriptions				Total	
	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	Ordinary and Preference Shares		Debentures		1973-74	1974-75
					1973-74	1974-75	1973-74	1974-75		
I.D.B.I.	163.75* (30.77)	222.79 (67.41)	8.21	6.00	..	3.00	171.96 (30.77)	231.79 (67.41)
I.F.C.I.	34.51	23.36	4.26	3.64	3.11	3.60	41.88	30.60
I.C.I.C.I.	19.76	16.00	34.68	41.29	5.05	3.77	1.63	1.80	61.12	62.86
I.R.C.I.**	7.21	7.59	7.21	7.5
S.F.Cs†	96.61	129.82	4.43	8.36	0.72	0.49	101.76	138.67
S.I.D.C.s†	23.04	21.61	5.02	10.90	28.06	32.51
Total	344.88 (30.77)	421.17 (67.41)	43.37	53.29	22.11	24.76	1.63	4.80	411.99 (30.77)	504.02 (67.41)
U.T.I.‡	3.81	2.96	4.11	3.21	7.92	6.17
L.I.C.	17.08	24.96	4.90	5.51	3.95	15.01	25.93	45.48

(Rupees Crores)

	Disbursements								Total	
	Rupee Loans		Foreign Currency Loans		Underwriting and Direct Subscriptions					
	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75	Ordinary and Preference Shares		Debentures		1973-74	1974-75
					1973-74	1974-75	1973-74	1974-75		
I.D.B.I.	113.40 (22.79)	164.67 (35.09)	4.79	1.72	..	0.99	118.19 (22.79)	167.38 (35.09)
I.F.C.I.	27.32	32.50	3.01	3.48	1.54	0.83	..	0.14	31.87	36.95
I.C.I.C.I.	13.76	13.71	26.30	29.09	1.94	1.82	1.54	0.77	43.54	45.39
I.R.C.I.**	5.15	8.05	5.15	8.05
S.F.C.s†	54.08	78.19	..	1.82	0.48	0.21	54.56	80.229
S.I.D.C.s†	16.21	20.05	4.46	6.84	20.67	26.89
Total	229.92 (22.79)	317.17 (35.09)	29.31	34.39	13.21	11.42	1.54	1.90	273.98 (22.79)	364.88 (35.09)
U.T.I.‡	2.29	2.22	5.49	5.21	7.78	7.43
L.I.C.	10.65	45.49	3.72	4.59	5.59	5.69	19.96	55.77

* Comprising direct loans, refinance to banks and rediscounts. Refinance to SFCs indicated separately within brackets is excluded to avoid double counting since this is covered under loans of SFCs.

** Including the amounts of guarantee sanctioned and disbursed if any.

† Data are provisional.

‡ Data for 1974-75 are provisional and those for 1973-74 are revised.

Feasibility Studies

300. Based on a few feasibility studies commissioned by IDBI in collaboration with IFCI and ICICI, some projects have taken shape. A granulated fertilizer plant in Assam has been set up by the Assam Industrial Development Corporation with the financial assistance of IDBI, while Bihar State Industrial Development Corporation has planned to set up a central processing and powerlooms project. The Government of Meghalaya proposes to implement the cold storage plant for potatoes in the co-operative sector.

Study of Small Entrepreneurs

301. A study on Problems of Small Scale Entrepreneurs in Gujarat, commissioned by IDBI through Prof. H. N. Pathak of Indian Institute of Management, Ahmedabad, was released to the public during the year; copies of the Report were also circulated to various State-level institutions and State IIGs. The study has generated considerable interest and it is hoped that it would encourage similar studies in other States to deepen their knowledge about factors that shape an entrepreneur and his problems.

Assistance to Entrepreneurs

302. The IDBI continued to assist entrepreneurs and State Industrial Development Corporations in identification, formulation and implementation of projects. Additional names of Consultants were included in the list of technical consultants maintained by the IDBI, which was circulated to financial and promotional organisations like SFCs, SIDCs, etc. The names of consultants were also furnished to the prospective entrepreneurs for enabling them to select suitable consultants for their projects.

303. IDBI continued to maintain liaison with Regional Research Laboratories and Institutes, particularly with a view to obtaining and disseminating information on the new processes/products developed by them.

304. During the year, IDBI decided to prepare project profiles based on the information available with it for the benefit of the entrepreneurs. About 100 profiles on various projects were prepared and circulated among its Offices for advising the entrepreneurs. With a view to promoting good management practices among small and small-medium units in the country, the IDBI adapted the pamphlets in the series "Minding your own Business" issued by the Industrial Development Bank (IDB), Canada and circulated them among SFCs and the State-level IIGs. A request has been made to the above agencies to adapt them further by incorporating facts about State legislations, translate them in local language if necessary, and distribute them to small entrepreneurs. The response in the short time has been quite encouraging.

305. During the year IDBI initiated steps to make special studies on regular basis of problems of industrialisation of backward States. Initially six of the more backward States have been chosen for the purpose. The subjects to be covered by these studies *inter alia* include analysis in depth of causes of regional backwardness, present industrial status, response of entrepreneurs to various incentives, emerging pattern of industrialisation and strategy of industrial growth for the region. These studies are expected to help in review as well as formulation of policies relating to industrialisation in the region.

IDBI's Operations

306. The IDBI's operations expanded considerably, with both its sanctions and disbursements touching a new high during the year (July-June). Total sanctions including guarantees increased by 64 per cent in 1974-75 to Rs. 351.4 crores in respect of 7593 applications from Rs. 213.7 crores in 1973-74 in respect of 3550 applications. Total disbursements were higher by 31 per cent at Rs. 213.0 crores in 1974-75 as against Rs. 162.2 crores in 1973-74. Sanctions facilitating refinancing of industrial loans increased from Rs. 41.9 crores in respect of 2665 applications in 1973-74 to Rs. 105.7 crores in regard to 6390 applications in 1974-75. More than two-thirds of the refinance sanctions was in respect of small-scale industries and small road transport operators. The amount sanctioned for rediscounting of bills by the IDBI at Rs. 114.4 crores was higher by 50 per cent covering 1062 purchaser users as against Rs. 76.3 crores

covering 804 purchaser users during 1973-74. The assistance availed of by public utilities like the State Electricity Boards and the State Road Transport Corporations increased from Rs. 20.7 crores in 1973-74 to Rs. 23.2 crores in 1974-75. Total effective sanctions since the inception of IDBI upto the end of June 1975 amounted to Rs. 1308.3 crores while the utilisation of assistance aggregated Rs. 939.4 crores.

307. The direct assistance sanctioned by the IDBI for projects during 1974-75 aggregated Rs. 78.4 crores in respect of 66 projects compared to Rs. 57.5 crores for 49 projects in 1973-74. The assisted units envisaged setting up of new capacity and/or expansion/diversification of the existing units in various items of manufacture such as fertilisers, paper, steel billets and/or ingots, textiles, machinery, scooters etc. Further, 6 of the 66 projects assisted were promoted by technician-entrepreneurs and 34 projects pertained to backward areas. The direct project assistance for Rs. 26.1 crores was sanctioned on concessional terms to units in specified backward districts.

308. Sanctions under export finance (participation scheme and refinance of export credit) schemes sprung from Rs. 10.3 crores in 1973-74 to Rs. 33.7 crores in 1974-75. Here again, the sanctions for refinance were preponderant. During the year, three additional lines of credit for an aggregate amount of Rs. 8 crores were sanctioned to Bangladesh, raising the total credits sanctioned from the inception to date to six in number to the tune of Rs. 25.5 crores.

IDA Credit

309. Further progress was made during the year under the IDA Credit of \$ 25 millions sanctioned to the Government of India, the rupee equivalent of which is available to the IDBI for refinancing loans given by SFCs, to small and medium sized industrial units for financing imports of equipment and of technical know-how from abroad. The sanctions of assistance by SFCs increased from Rs. 11.3 crores during the seventeen month period upto June 1974 to Rs. 17.0 crores in the year 1974-75. In the same period refinance sanctions from the IDBI increased from Rs. 4.52 crores to about Rs. 9.88 crores. The number of proposals sanctioned for refinance assistance by the IDBI increased from 84 to 177 during 1974-75.

Assistance to Backward Areas

310. The IDBI assistance to units in specified backward districts/areas has also shown a significant increase in 1974-75. The total assistance—both direct and refinance of industrial loans—sanctioned on concessional terms during the year amounted to Rs. 59.8 crores as compared to Rs. 47.3 crores in 1973-74, raising the total assistance sanctioned on concessional terms to 139.9 crores upto the end of June 1975.

Subscription to Shares and Bonds

311. During the year, the IDBI contributed Rs. 1.4 crores to the public issue of debentures and Rs. 1.9 crores to the special issue of debentures of the ICICI. With this, the total assistance of the IDBI to the ICICI since inception amounted to Rs. 28.0 crores upto the end of June 1975. With repayment of Rs. 1.2 crores being the instalment of loans taken by the ICICI earlier, the IDBI's holdings of the ICICI debentures amounted to Rs. 24.0 crores at the end of June 1975. The IDBI also contributed Rs. 1.3 crores to the paid-up capital of the IRI. Besides, the IDBI subscribed Rs. 2.8 crores to the share capital of six SFCs bringing the cumulative IDBI's total subscription to shares and bonds issues of all the SFCs to Rs. 11.9 crores.

Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.

312. The fourth year of IRCI's operation was characterised by a substantial rise in the pace of utilization of assistance. The disbursements during the year ended June 1975 aggregated Rs. 8.7 crores as compared to Rs. 5.9 crores last year. Again, total disbursements since the inception of the Corporation amounted to Rs. 21.1 crores as at the close of June 1975, against the total effective sanctioned assistance of Rs. 28.1 crores. During the year IRCI received 49

requests for reconstruction assistance. Of the 529 proposals received since the inception of the Corporation, study of 495 requests was completed, of which 92 eligible cases were sanctioned assistance; the total employment envisaged in sanctioned cases is of the order of 72793 persons. The Textile Processing Corporation of India Ltd., promoted by IRCI is expected to be commissioned by April 1976.

Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.

313. During the year, 1974-75, KITCO received 342 project enquiries of which 315 were from entrepreneurs and the rest from financial institutions. Twenty-one project enquiries materialised in to project ideas. Together with the 25 schemes received last year, the total number of cases received for consideration stood at 46 schemes as at the end of June 1975. Besides, KITCO received 42 appraisal cases. The number of project reports completed by KITCO, since its inception totalled 52, involving investment of Rs. 8.6 crores. Further, the number of completed appraisal reports totalled 69, involving investment of Rs. 18.6 crores. Of the projects assisted by KITCO so far, 12 have already gone into production, while 46 are under various stages of implementation.

North-Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.

314. During 1974-75, NEITCO received 87 enquiries from private entrepreneurs (68 per cent) and from Government and Public sector bodies. Of these, 47 enquiries involving investment of Rs. 13.8 crores, materialised into project ideas/appraisal cases. Since its inception, NEITCO received 189 enquiries, of which 105 involving investment of Rs. 107.2 crores materialised into project ideas/appraisal cases. NEITCO has so far completed 74 assignments involving investment of over Rs. 72 crores with an employment potential of nearly 10,000 persons.

Bihar Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.

315. The BITCO was registered as a company under the Companies Act, 1956 on October 15, 1974. During the first year of its operation BITCO received 249 enquiries. So far, six cases, involving total capital investment of Rs. 5.2 crores, have materialised into assignments. Of these, two assignments involving total capital outlay of Rs. 1.8 crores have been completed.

Operations of SFCs

316. The operations of the 18 SFCs including the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited (TIIC) continued to show improvement during 1974-75 (April-March). The total loans sanctioned by them during the year ended March 1975 amounted to Rs. 134.8 crores as compared with Rs. 96.8 crores during 1973-74 (April-March). Disbursements also increased to Rs. 79.3 crores during the year 1974-75 as against Rs. 54.1 crores in the previous year. Loans outstanding as at the end of March 1975 amounted to Rs. 277.5 crores and were 28.5 per cent higher than a year ago. The bulk of the financial assistance continued to be granted to units in the small-scale sector and such assistance formed nearly 53 per cent and 64 per cent of the total sanctions and disbursements, respectively.

Conference of SFCs

317. The 17th Conference of the Chairmen and Managing Directors of the State Financial Corporations which was held at Bombay on May 10 and 11, 1975, reviewed the progress made by the corporations in the matter of utilisation of the IDA Credit and in implementing the programme of up-gradation of the Corporations and discussed the major problems facing the Corporations, such as resources, overdues, lag in utilisation of sanctioned assistance as also co-ordination between banks and SFCs.

IDA Credit

318. Mention was made earlier about the sanction by IDA of a credit of \$ 25 millions to the Government of India, the rupee equivalent of which would be available to

the IDBI for refinancing the loans given by the State Financial Corporations (SFCs) to small and medium scale industrial units, for financing the import of plant and machinery from abroad and/or technical know-how etc. The credit is linked to a programme of strengthening and improving the effectiveness of the SFCs as regional development banks.

319. The Capital Goods Ad-hoc Committee (CGAC) which has been entrusted with the work of clearing import licence applications under IDA Credit has cleared up to June 30, 1975 662 applications involving foreign exchange component of Rs. 18.79 crores. The SFCs had received 701 applications for assistance under IDA line of credit for an aggregate amount of Rs. 56.13 crores (both rupee and foreign exchange components). Of these, 398 applications for Rs. 28.28 crores (both rupee and foreign exchange components) were sanctioned and 122 applications for Rs. 10.27 crores were rejected/closed as being not eligible for assistance (upto June 30, 1975). The remaining 181 applications involving assistance of Rs. 17.58 crores were under consideration. The IDBI sanctioned refinance in respect of 252 cases involving assistance by the SFCs to the extent of Rs. 15.83 crores, inclusive of foreign exchange component of Rs. 8.87 crores. The experience of the year revealed that the SFCs by and large have taken steps to implement the up-gradation programme drawn up for them.

Financing of Small-Scale Industries

Credit Guarantee Scheme

320. The number of credit institutions eligible for facilities under the Scheme increased from 583 at the end of June 1974 to 609 at the end of June 1975 with the inclusion of one licensed scheduled commercial bank and 25 unlicensed primary urban co-operative banks in the approved list. Three of these unlicensed primary urban co-operative banks have since joined the Scheme by executing the necessary agreement. The number of institutions participating in the Scheme increased from 201 to 217 during the period July 1974 to June 1975. The amount of outstanding guarantees, which stood at Rs. 1145 crores at the end of June 1973 and Rs. 1497 crores at the end of June 1974, rose to Rs. 1726 crores at the end of June 1975, reflecting a steady increase in the flow of institutional credit to the small scale industrial sector. Since the inception of the Scheme till the end of June 1975, claims aggregating Rs. 127.90 lakhs have been paid in respect of 1097 accounts; of these, the payment made during July 1974 to June 1975 amounted to Rs. 27.83 lakhs in respect of 226 accounts. The bulk of these claims was paid in the Bombay and Delhi regions. Out of the aggregate amount of Rs. 127.90 lakhs paid as claims a sum of Rs. 25.87 lakhs has been recovered, thereby placing the net amount of claims paid at Rs. 102.03 lakhs as at the end of June 1975. During 1975, a sum of Rs. 1.40 crores was received as guarantee fees and transferred to the Central Government.

Liberalisation of the Scheme

321. With a view to enabling the credit institutions to provide adequate finance to sick units assisted by them in co-ordination with the IRCI, the ceiling on guarantee cover has been raised from Rs. 7.5 lakhs to Rs. 12.5 lakhs in respect of working capital advances including the advance, if any, covered under the Credit Guarantee Scheme prior to the credit extended under the Scheme of the IRCI, the enhancement of ceiling would be operative as an experimental measure initially for a period of two years from January 15, 1975, and the position will be reviewed before the expiry of the period.

Scheduled Commercial Banks' Assistance

322. During the first three quarters of 1974-75 (April-March), the credit extended by scheduled commercial banks to small scale industries (including term-loans and advances granted to craftsmen and other qualified entrepreneurs) rose by Rs. 113 crores to Rs. 1017 crores. The increase in credit outstanding to this sector during the period under review was only about two-third of the increase (Rs. 173 crores) during the corresponding period of the previous year. The number of units assisted rose by 17621 as against 45141 in the comparable period of 1973-74. However, the share of small scale industries in total bank credit rose from 12.2

per cent at the end of December 1973 to 12.9 per cent at the end of December, 1974. The average amount of credit sanctioned per unit which would reflect the size and number of the assisted small units, was maintained; this is evident from the fact that the average sanctioned limit at Rs. 68000 at the end of December 1974 was only Rs. 1000 higher than the level in December 1973. Besides the quantum of bank credit to small-scale units in all the industrially backward States showed a rise. Significantly enough, the share of bank credit to small units in some of the States such as Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh in the all-India total of bank credit sanctioned to this sector had recorded an increase.

323. Group-wise, the State Bank of India Group and the 14 nationalised banks together accounted for 89 per cent (Rs. 910 crores) of the total outstanding bank credit (Rs. 1017 crores) to the sector as at the end of December 1974. The State Bank Group extended credit to this sector for an aggregate amount of Rs. 370 crores showing a rise of Rs. 32 crores over March 1974 level as compared to an increase of Rs. 44 crores in the corresponding period of 1973. The credit extended by the 14 nationalised banks to small-scale industries showed an increase of Rs. 71 crores during March-December 1974 as against Rs. 116 crores during March-December 1973. During the nine month period ended December 1974, the term loans (including instalment credits) sanctioned by banks to small-scale industries rose by Rs. 27 crores to Rs. 216 crores. The outstandings increased from Rs. 146 crores covering 43520 units at the end of March 1974 to Rs. 175 crores spread over 49432 units at the end of December 1974. The proportion of term loans (outstanding) to total bank credit extended to small industry was 17.2 per cent in December 1974 as compared to 16.0 per cent in December 1973. Credit limits sanctioned by the fifteen scheduled commercial banks for setting up of industrial estates at the end of December 1974 amounted to Rs. 16.9 crores covering 38 units and the balance outstanding was Rs. 9.1 crores.

324. The credit limits sanctioned to craftsmen and other qualified entrepreneurs as at the end of December 1974 totalled Rs. 47 crores covering 21018 units. Outstanding credit stood at Rs. 33 crores, 44 per cent of which was accounted for by the SBI Group.

325. As at the end of December 1974, credit limits sanctioned to small road and water transport operators amounted to Rs. 160 crores spread over 74276 units. The amount outstanding at Rs. 121 crores recorded an increase of Rs. 20 crores over the March, 1974 level as compared to Rs. 23 crores during the corresponding period of 1973.

Unit Trust of India

326. The Trust had to go through a difficult period during 1974-75, with a steep fall in the sales of units and a sharp rise in repurchases. For the first time in the eleven-year history of the Trust repurchases exceeded sales. Although the year opened optimistically with encouraging sales in the beginning of July 1974, the investment climate took a sudden turn for the worse following the announcement of a package of anti-inflationary measures by the Government. In particular, the restriction on dividend payments by companies announced on July 6, 1974, introduction of compulsory deposit schemes for employees and income-tax payers and the upward revision of interest rates on other competitive channels of investment brought about a situation in which investment in units became less attractive. Effective July 23, 1974 interest rates on deposits with banks and post offices and national savings certificates were revised upwards. Further, the attractive interest rates offered by non-banking companies diverted many savers away from the Trust. These factors adversely affected the sales of units and even led to heavy repurchases.

327. This adverse trend was, however halted by the Government's announcement, early in January 1975 through an Ordinance, of income and wealth tax concessions exclusively applicable to investment in units. The favourable impact of these tax concessions was reflected in the trend of sales and repurchases of units. Thus, sales of units under the 1964 Scheme which averaged Rs. 0.22 crore per month between August and December 1974, averaged Rs. 1.06 crores per month between January and May 1975. The average monthly purchases of units also came down from

about Rs. 3 crores between August and December 1974 to Rs. 0.75 crore between January and June 1975.

328. During the year under review the sales of units amounted under the 1964 and 1971 Schemes to Rs. 17.2 crores under about 67000 applications as against Rs. 30.6 crores under about 1.03 lakhs applications in the last year. Repurchases amounted to Rs. 20.4 crores as against Rs. 3.7 crores during 1973-74. The total amount of units sold and outstanding with the Trust as at the end of June 1975 amounted to Rs. 148.8 crores in respect of over six lakhs accounts. There has been a net reduction of Rs. 3.2 crores in the unit capital. The Trust could declare a higher dividend of 8.60 per cent for the year ended June 30, 1975 as compared to 8.50 per cent for the previous year in respect of the Unit Scheme, 1964 while it maintained the dividend at 7 per cent in respect of the Unit Scheme, 1971.

Unit Scheme

329. The total investible funds of the Trust as on June 30, 1975, amounted to Rs. 170.6 crores of which 47.4 per cent was invested in ordinary shares, 9.6 per cent in preference shares, 32 per cent in debentures and the balance in other investments. Certain measures were taken to popularise units among the investing public. Industrial unit-holders have been provided with nomination facilities. Also, in regard to minors, either parents viz; father or mother can now make an application for investment in unit on behalf of the minor children. A Scheme of awarding prizes to children participating in the children's Gift Plan has been introduced. Units have now been made a 'trustee security' by an amendment to the Indian Trusts Act, 1882, as a result of which various trusts will be able to invest in units and secure better returns on their investments. The Unit-linked Insurance Plan is being reviewed to improve its appeal to the investing public. The Trust has initiated steps to expand its all-India network of agencies to include all State and some selected Central and Urban Co-operative Banks for the sale of Units. Steps have been taken to intensify sales promotion efforts and to give better service to customers : wherever possible procedures are being simplified. The agents force is being revamped through a series of seminars specially designed to inculcate creativity in the sale technique of units. The Trust has also strengthened and diversified its publicity efforts so that its services are more widely appreciated.

V. DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL

330. In the sphere of exchange control, the main developments during the year were : incentives offered by the Government of India for inward remittances, exemptions given to certain categories of companies from the provisions of the operations of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 and trade and payments arrangements with Bangladesh, Pakistan and Portugal.

Foreign Companies' Operations in India

331. Section 29(2) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 requires all companies (other than banking companies) incorporated abroad or in which non-resident interest was more than 40 per cent, as well as branches of such companies, to obtain permission of the Reserve Bank to carry on their trading, commercial or industrial activities in India in which they were engaged on January 1, 1974. In December 1974, companies incorporated in India in which the non-resident interest did not exceed 74 per cent of their total equity share capital were granted general exemption from this requirement under the following conditions :

- (a) such company was engaged exclusively :
 - (i) in the production of any of the items specified in Appendix I to the Industrial Licensing Policy of the Government of India announced of February 2, 1973 or
 - (ii) in export-oriented industry, that is, an industry the annual average of the ex-factory cost of whose products exported during the last three years to any place outside India (other than Nepal and Bhutan) amounted to not less than 60 per cent of the total ex-factory cost of annual production.

- (b) such company had been granted licence after February 1970 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for carrying on such activities,
- (c) such company's production did not exceed the licensed capacity allowed to it as on January 1, 1974 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and
- (d) such company did not undertake expansion or diversification of its activities without the prior permission of the Reserve Bank.

332. The companies so exempted were to file a declaration with the Reserve Bank in the prescribed form before February, 24, 1975.

Foreign Shipping Companies

333. In October 1974 shipping companies which were not incorporated in India or which did not have a branch office or other place of business in India were granted general permission under Section 29(1) to carry on in India through their local agents their normal commercial activities like transportation of goods and passengers and collection of freight charges and fares.

Purchase and Sale of Immovable Property

334. It has been stipulated that all applications for permission of the Reserve Bank relating to purchase or sale of immovable property in India by foreign companies and foreign citizens, or Indians companies having non resident interest of more than 40 per cent or for the remittance of sale proceeds of tea/coffee/rubber estates in India owned by sterling companies, should be accompanied by a valuation report of the property in question. This report should be comprehensive indicating the value of each of the major assets and also the manner in which valuation has been arrived at and be from an approved valuer appointed by the Government of India under the Wealth Tax Act.

Priority Allotments of Car/Scooter/Agricultural Tractors/Cement

335. Under a scheme drawn by the Government of India to encourage private remittances from abroad, foreign nationals coming to stay in India continuously for at least two years, Indian nationals who have returned from abroad and relatives of Indians staying abroad who have remitted the requisite funds for the purpose would be allotted motor car or scooter on a priority basis on the production of a certificate from the concerned authorised dealer evidencing the receipt of foreign exchange remittance to cover the cost of an Indian car/scooter. Inward remittances received for this purpose are to be credited by the authorised dealers to a separate non-convertible account. Normal remittances received for family maintenance, payment of insurance premia, Indian taxes, contribution to Provident and other Superannuation Funds maintained in India or in fulfilment of bank guarantees executed for repatriation of foreign exchange do not qualify for the benefit under the scheme.

336. Likewise, cement and agricultural tractors, too, would be allotted on priority basis to Indian nationals who have returned from abroad and to Indians who have received remittances from their relatives abroad on the production of the necessary evidence that the foreign exchange equivalents of the minimum amount laid down by the Government of India from time to time for purchase of above articles have been brought to/or received in India.

Trade/Payments Arrangements : Bangladesh

337. On a review of the working of the Balanced Trade and Payments Arrangements (B.T.P.A.) between the Governments of India and Bangladesh, it was agreed that all payments for trade and related transactions between the two countries would be effected as from January 1, 1975

in freely convertible currency in accordance with the foreign exchange regulations and procedures, including customs formalities, in force in each country from time to time. Effective from that date, exchange for travel to Bangladesh also would be released in pound sterling as against the earlier arrangement in non-convertible rupees. However, the existing payments arrangements as envisaged in the Balanced Trade and Payments Arrangements were extended upto February 28, 1975 in respect of commercial contracts which were already concluded under the B.T.P.A. for export/import of coal, jute, tobacco, newsprint, and fresh fruit to enable incomplete deliveries to be completed for this purpose, where necessary the existing contracts would be extended upto February 28, 1975 on existing terms and conditions.

Pakistan

338. Under the trade arrangements entered into by the Government of India with Pakistan on January 23, 1975 the trade with that country would be conducted, on Government-to-Government basis or through Government controlled trade corporations of the two countries, in freely convertible currency in accordance with the foreign exchange regulations in force in both the countries. The Trade Agreement between the two countries would remain valid for one year from the date of signature subject to automatic extension for two years thereafter if 3 months notice prior to the expiry of the initial period of validity of an year is given by either Governments to the other. In terms of the Memorandum of Understanding signed between the two Governments to give effect to the payments provisions, (a) exports from India/Pakistan would be covered by irrevocable documentary letters of credit expressed in convertible currency and (b) the transactions would for the present, be conducted in pound sterling and U.S. dollar through the State Bank of India and the National Bank of Pakistan. A protocol was signed between the two countries under which shipping services were restored between the two countries with effect from February 15, 1975. The carriage of cargo was restricted to vessels sailing under the flag of either country and all payments and expenses connected with the shipping were to be effected in convertible currencies.

Portugal

339. Effective 1st January, 1975 the earlier order prohibiting the trade between India and Portugal was rescinded

Blanket Exchange Permits

340. The minimum requirements of exports for qualifying for blanket foreign exchange permits for travel abroad for export promotion and other approved purposes were raised to Rs. 75 lakhs for traditional exports and Rs. 15 lakhs for non-traditional exports from January 9, 1975, exports who are registered Export Houses would, however, be eligible for grant of blanket permit irrespective of their past export performance.

Licence to deal in Foreign Exchange

341. Sonali Bank Bangladesh, was granted a licence to deal in foreign exchange in India for a period of two years with effect from September 2, 1974.

TABLE 27:—STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD JULY 1974 TO JUNE 1975

I. Fresh Exchange Permits issued for Study/Training abroad

Country	Technical Courses		Non-Technical Courses	
	Number of Students/Trainees	Amount of Exchange Released (Rs. 000's)	Number of Students/Trainees	Amount of Exchange Released (Rs. 000's)
U.K. & Europe	554	4860	557	2585
U.S.A. & Canada	1163	30768	716	12762
Other Countries	149	878	119	554
Total	1866	36506	1392	15901

II. Travel Permits issued for purposes other than Study/Training abroad

Purpose	Number of Persons covered by permits issued	Amount of exchange released (Rs.000's)
1. Business	14821	104866
2. Medical treatment	441	5960
3. Study tours	718	4516
4. Attendance at conferences	1367	3694
5. Miscellaneous	6375	13254
Total	23722	132290

III. 'P' Form Applications Approved*

Purpose	Number of persons covered by approvals granted
1. Joining head of family	16260
2. Visits to relatives	19531
3. Export promotion	397
4. Employment abroad	21753
5. Emigration for permanent settlement abroad	10069
6. Students/Trainees	2897
7. Miscellaneous	17659
Total	88566

*No foreign exchange is released in such cases.

VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE RESERVE BANK

Surveys

342. During the year under review, considerable progress was made in regard to the work of All-India Debt and Investment Survey, 1971-72 conducted by the Bank in collaboration with the National Sample Survey Organisation of the Government of India and Statistical Bureaux of the state Governments. The Steering Committee appointed by the Bank to oversee the conduct of the Survey met twice during the year and assessed the progress of the Survey and considered various background papers prepared in this regard. As regards supply side investigation substantial progress was made in respect of the scrutiny and tabulation of different mini-surveys conducted in the field of co-operative sector. Filled-in schedules are being awaited in respect of a small survey. Financing of Primary Agricultural Credit Societies by Commercial banks—covering selected commercial banks and some primary agricultural co-operative credit societies taken over by them for financing their requirements in five States. The Steering Committee suggested release of main results of the Survey in a phased manner in the form of statistical tables for the use of official agencies and research organisations. Accordingly volume I of the first

publication presenting the statistics on assets and liabilities of rural households for all-India and individual States was published on August 1, 1975. Work on volume II of the publication presenting similar data for agricultural regions within the States as also on preparation of State-wise pamphlets was in progress. The findings of the survey on the indebtedness of non-manual employee households in urban areas conducted by the Department of Statistics during July 1970-June 1971 were published in the November issue of the RBI Bulletin.

343. The Division of Rural Surveys Economic Department, published the report of the Sixth Follow-up Survey on "The Role of Co-operative Credit in Increasing Farm Production" (1963-64 to 1965-66). Report of the Seventh Follow-up Survey on "Study of Small Farmers and Co-operative Credit" (1967-69) has been finalised and its printing is in progress. The data on the field study of "Savings Potential of Farmers" (1969-70) are being processed and tabulated. Reports on the Survey of "Operations of Selected Small Farmers' Development Agencies" (1972-73) was also finalised and submitted to Government of India and is being taken up for publication. The Report on "Operations of the Marginal Farmers' and Agricultural Labourers' Agencies" (1973) is being finalised. The Quarterly Survey of (State and Central) Co-operative Banks' Advances continues to be conducted in the Division.

344. The Division of Trade, Economic Department, published the main findings of the report on "Second Survey of Foreign Collaboration in Indian Industry" covering the period 1964-65 to 1969-70. The third survey in the series covering the period 1970-71 to 1972-73 is in progress.

345. The Division of International Finance of the Economic Department continued to conduct the survey of unclassified receipts, that is, inward receipts of foreign exchange in amounts below Rs. 10,000 or equivalent for which no purpose-wise details are required to be reported under the existing Exchange Control Regulations. The results of the survey for 1973 which covered the quarter October-December are being finalised. The survey for 1974 was carried out for the three-month period July, August and September and the data are being processed. The survey for the April-June quarter of 1975 was initiated. In addition to this, the Division continued to call for quarterly foreign investment survey reports from branches of foreign companies and Indian foreign controlled rupee companies.

Seminars

346. The Agricultural Refinance Corporation convened a seminar at Dispur (Assam) in December 1974 for the benefit of the State and district officials on planning and formulation of agricultural development projects in the State of Assam. The Reserve Bank convened on January 13, 1974 a seminar to discuss the measures contemplated by the Study Group for proper appraisal and follow-up of bank credit. The seminar was attended by senior officials of the State Bank, its seven subsidiaries, fourteen nationalised banks and twelve private sector banks.

347. The fifth seminar of Chief Executive Officers of Central Co-operative Banks and State Co-operative Land Development Banks was held at Poona from 26 to 29 September, 1974. Some of the important topics discussed at the Seminar related to : (i) Problem of overdues in the short-term and the long-term co-operative credit structure, (ii) Management of resources, (iii) Problems of personnel in State Co-operative Banks and Central Land Development Banks, (iv) Co-ordination of activities (a) of short-term and medium-term co-operative credit structure and the long-term co-operative credit structure and (b) of co-operative banks and commercial banks and (v) Developmental role of State Co-operative Banks and Central Co-operative Land Development Banks.

VII. EDUCATION AND TRAINING

348. The Reserve Bank of India through its various training institutions continued to impart both general and intensive training to a number of officers at various levels—junior, supervisory and senior executives. These training programmes covered the Bank's own staff as well as the staff of commercial banks, co-operative institutions and some Government Departments. The progress made by the various institutions during the year in this regard is reviewed below :

Bankers Training College, Bombay

349. The emphasis of course at the Bankers Training College (BTC) continued to be on credit analysis. The important subjects covered by the courses/programmes were Industrial Relations, General Banking, Advance Foreign Exchange and Foreign Exchange Orientation Programme. A Regional Programme on Development Banking was conducted in October-December 1974, in collaboration with the Asian Development Bank for participants from India and twelve Asian countries. Again in January-February, 1975 in collaboration with the Economic Development Institute of World Bank another programme on Development Banking was conducted for participants from Indian Development and Commercial Banks. The BTC conducted for the first time, a programme on policies and working of the Reserve Bank and its associate institutions for the benefit of Probationers of Indian Economic Service. A special programme on Industrial Finance was conducted for officers of the Government of Nagaland. The Integrated, the Personnel Management and the Legal Officers courses were also continued. The BTC organised seminars on export finance, finance for self-employment, small borrowers and internal inspection of banks. For the Bank's officers, the college arranged courses on Central

Banking, Advanced Central Banking and Trainers' Courses. A few officers/faculty members of commercial banks were admitted to the Advanced Central Banking and the Trainers' Courses.

350. At the request of the Governor of the Bank of Thailand, the College deputed two members of its faculty to Bangkok to assist that bank in the conduct of a special programme for their Bank Examiners.

351. The work relating to the publication on foreign exchange and the revision of the publication "Guidelines on Internal Inspections" has been taken up and is expected to be completed in 1975-76.

352. In all, 1185 officers from the R.B.I., commercial banks and other financial institutions participated in 22 different types of courses during the year. This brings the total number of officials trained by the College since its inception in 1954 to 8418.

College of Agricultural Banking, Poona

353. The College of Agricultural Banking (CAB) continued to focus its attention on two major areas, viz., Agricultural Finance and Project Planning and Appraisal. Courses in both the areas were conducted for the benefit of senior and middle level officers of banks for Bank's officers, for officers from the Bihar State Government and for personnel from co-operative banks and agricultural colleges. The courses conducted covered such aspects as institutional credit for the project officers of SFDA/MFAL including a programme for Tribal Development Agencies, agricultural banking schemes of dairy, poultry piggery and fisheries.

354. During the year, the College imparted training to as many as 894 officers from co-operative, land development and commercial banks as also the RBI itself, raising the total number of officers so far trained to 3764.

355. The Committee set up by the Bank to go into enlarged facilities at the College has submitted its report. Among its important recommendations are :

- (i) The CAB should act as a central agency for effective organisation of the training efforts of individual training colleges/apparatus of different banks in the field of agricultural banking. It should also be equipped to serve as a regional centre in South East Asia and Africa for the conduct of training courses/seminars/conferences in agricultural credit.
- (ii) The number of channels at the CAB may be raised from three to five so that it can accommodate 150 trainees at any one time.
- (iii) The course content of the Project Planning and Appraisal Programme may be suitably revised to include the specific requirements of the ARC/World Bank. If necessary, there may be two separate courses for senior and middle level personnel with appropriate differentiation in the content of the two programmes.
- (iv) More attention may be given to certain new subjects as also to bring within CAB's coverage the non-official members of boards of co-operative banks, chief executive officers of these banks etc. so that they can play an effective role in developing their institutions. The CAB should undertake research work in agricultural banking and bring about closer co-ordination between CAB and the training colleges of commercial banks.

356. The Committee's recommendations have been accepted in principle by the Bank and steps have been initiated to implement them.

Staff Training College, Madras

357. During the year, the General Course for Staff Officers Grade II and Assistants was converted into a Staff Officers' Development programme. The restructured programme is intended to improve the perspectives and supervisory skills of the Staff Officers. Another important aspect of the activities

of the College was the institution of a Credit Management Programme for the benefit of Staff Officers Grade II in DBOD/IFD/ACD/IDBI/ARC Credit Planning Cell and Division of Banking (Economic Department). The Mobility Courses, introduced last year for the benefit of Staff Officers to acquire knowledge of all departments, gathered momentum. In the context of introduction of Mobility Courses, the contents of the Inspection Oriented Course for Officers of DBOD, IFD and ACD came under close review. The course has been redesigned so as to make it essentially discussion oriented as a forum for inspecting officers to sharpen their inspection skills. As many as six courses were held during the year under report. The total number of employees who have so far received training at the College is 4609.

Zonal Training Centres

358. The Zonal Training Centres at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi continued to conduct courses for Clerks Grade I, Clerks Grade II, etc. For giving proportional reservation in in-service training to Scheduled Caste/Tribe employees, a pilot refresher course was held at one of the Centres for the benefit of such staff in the cadre of Clerks Grade II. The question of continuing the course on the lines of the pilot course or otherwise is engaging the attention of the Bank. Meanwhile, instructions have been issued to officers to depute a sufficient percentage of Scheduled Caste/Tribe employees to regular training courses. The special two-week discussion-oriented programme for the candidates eligible for promotion to the posts of Staff Officers Grade II was also conducted at all the Centres. The total number of clerical staff who have so far received training at the Zonal Training Centres stood at 10254.

N.I.B.M.

359. During the year 1974, National Institute of Bank Management (NIBM) concentrated its activities in a wide range of areas, like resource planning, credit management, branch expansion, rural banking, cost and profitability, organisational planning, information systems, participative management and manpower recruitment and development. Research projects completed/undertaken/initiated by NIBM during the year included, banking plan for the industry, for a State, a bank and regions and branches through performance budgeting system. In the area of priority sector developments, NIBM's efforts were focussed on (i) strengthening of the institutional base for undertaking institutional financing, particularly in the rural areas, and (ii) experimenting with more difficult areas which need greater attention from banks: e.g. small farmers, dry areas, tribal areas, rural industries, small borrowers, etc. It also undertook studies on financing rural electrification by banks. During the year, 22 training programmes, conferences, seminars and workshops were held in which about 500 officers participated. The programme included General Managers' Conference, Seminar on Planning and Development in Banks, Workshops on Performance Budgets, etc. A Workshop on Formulation and Implementation of District Plan for officers of the Government of Maharashtra was organised. In April 1975, NIBM conducted for the first time a course on Methodology for Management Studies in Banks. Two conferences for the Principals of Staff Training Colleges of banks and Trainers Training Programmes and Five Zonal Training Workshops were also organised. NIBM continued to help banks recruit persons at clerical and officers' level through objective testing and extended the services for internal promotions. The Institute strengthened its ties with the neighbouring countries and those in Africa and special programmes were arranged for bankers from Bangladesh, Sri Lanka, Tanzania and Thailand.

Deputation of Staff

360. The Bank continued to depute its officers to short-term courses on management development etc. organised by the All-India/State-level Associations, Management Institutes and a few other similar bodies. Besides, the Bank deputed its officers to participate in the courses conducted by IBRD, IMF, Asian Institute of Economic Development and Planning, Bangkok, Asian Statistical Institute, Tokyo, Bank of England and SEANZA. Opportunities were also taken to depute officers for study visits/training to banking and financial institutions in West Germany, the U.K., Australia and the South East Asian countries. The Bank continued to ex-

tend training/study facilities to the officials/senior executives of foreign banking/central banking institutions.

Promotion of Hindi in RBI

361. Last year's Report indicated several measures taken by the Bank for progressive use of Hindi. During the year important measures taken include: bilingual issue of (i) office orders/circulars for class III and class IV staff in the offices in Hindi speaking areas; (ii) of agenda, notes and proceedings of All-India Conferences of public interest convened by the Bank and its associate institutions; (iii) bilingual display of name/designation boards of officers and boards indicating the names of departments/divisions; (iv) bilingual use of rubber stamp at points of contact with the public; (v) bilingual correspondence by the offices located in predominantly Hindi speaking areas with State Governments which have adopted Hindi as their official language as well as with the Governments of Maharashtra, Gujarat and Punjab; (vi) printing of envelopes with the Bank's name and address in bilingual form; (vii) use of the Bank's name in Hindi; viz., Bharatiya Reserve Bank; the Bank's associate institutions have been advised to follow suit and (viii) optional use of Hindi for answering questions at the interviews for the posts of Clerks Grade II/Coin-Note Examiners Grade II in the offices in Hindi speaking areas. It is proposed to bilingualise the question papers on General Knowledge, Arithmetic and Commercial Geography in respect of these areas. Hindi libraries are being set up in all offices/training colleges to popularise Hindi.

362. Progress continued to be made in complying with the provisions of the Official Languages Act, 1963. During the year, the Department of Banking Operations and Development of the Bank started issuing licences in bilingual form for opening branches in Hindi speaking areas and in the States of Maharashtra, Gujarat and Punjab. The Exchange Control Department printed some of their permit forms bilingually. The Bank advised all of its offices to use Hindi and English for all types of contracts and agreements executed by the Bank.

363. The Official Languages Implementation Committee of the Bank continued to meet periodically to oversee the progressive use of Hindi in the Bank and its associate institutions. It has been decided to constitute on a trial basis Local Committees in the Bank's offices at Kanpur and New Delhi to watch the implementation of various instructions issued by the Bank from time to time in connection with the progressive use of Hindi.

364. The Bank continued to bring out Hindi versions of important publications: these included the Annual Reports of the Bank and associate institutions, the Report on Currency and Finance (abridged version), and RBI Bulletin. The utility of the Hindi Section of the RBI Bulletin has been enhanced by including a set of selected statistical tables once a quarter in the publication. Hindi Section has been introduced from October, 1974 in the Bank's quarterly house journal "Without Reserve." The Hindi version of the booklet "RBI Directions and Company Deposits" was also published. A glossary of English-Hindi designational terms used in the Bank and in public sector banks was finalised and circulated to all offices of the Bank and public sector banks for guidance. The preparation of a Hindi glossary of banking terms has been undertaken. The Bank also assisted the Banking Laws Committee, Government of India in bringing out a Hindi version of their "Questionnaire" for reviewing the legislation affecting banking.

365. The Hindi Adhyayan Mandal (Hindi Classes) and the Scheme of payment of honorarium for passing the recognised Hindi examinations are continuing. Some of the employees availed of the facilities of the correspondence course in Hindi conducted by the Central Hindi Directorate, Ministry of Education. The Compulsory Hindi Teaching Scheme for Officers of the Bank in grades A, B and C who were 45 years of age or less as on January 1, 1974 has been put into operation. The cash incentive for the Bank's typists for passing the Hindi typewriting examination of the Government of India and State Governments has been raised from Rs. 100 to Rs. 250. A decision has been taken to offer an honorarium of Rs. 150 to all members of the staff of the

Bank in classes I, II and III who pass the banking oriented optional paper in Hindi to be conducted by the Indian Institute of Bankers.

366. The Bank participated in the World Hindi Convention held at Nagpur in January, 1975. At this convention the Bank arranged an exhibition entitled "Hindi in banks" showing the progress made in the use of Hindi in the Reserve Bank and public sector banks. The various publications, annual reports, etc., brought out in Hindi by the Bank and public sector banks, specimen of Hindi/Hindi-English forms used by the public in their dealings with banks, posters, advertisements and other publicity handouts in Hindi and photographs were displayed on the occasion.

Hindi in Public Sector Banks

367. As regards the progressive use of Hindi in the public sector banks, efforts to ensure extensive and effective coverage were stepped up during the year. The important decisions taken in the meeting of the Official Languages Implementation Committee of the Department of Banking were conveyed to the public sector banks for their guidance and early compliance. In pursuance of these decisions, all banks have made arrangements to meet the obligatory requirements of the Official Languages Implementation Act. The banks are also trying to promote customer service by the use of Hindi particularly in semi-urban and rural areas of the Hindi-speaking States.

368. The progress made by the public sector banks in the use of Hindi in their offices was reviewed and a consolidated report was forwarded to the Government of India in November, 1974 for the use of the Parliamentary Committee appointed by the Government for this purpose. It was observed that the banks have generally taken steps to comply with the requirements of the Official Languages Implementation Act. Again, on the basis of information supplied by public sector banks periodically, the Government of India is being appraised regularly of the progress made in the progressive use of Hindi in these banks.

VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS

369. During the accounting year ended 30th June 1975, the Bank's income after making adjustment for various provisions, amounted to Rs. 448.01 crores as compared with the last year's income of Rs. 310.48 crores. The details of the income from various sources are as follows :

Items	(Amounts in Rupees Crores)	
	Year	
	1974-75	1973-74
(i) Interest on Ways and Means Advances to State Governments	13.01	5.85
(ii) Interest on Loans and advances to the State Governments [other than on Ways and Means Advances referred to at item (i) above] and Commercial and Co-operative Banks	65.54	34.88
(iii) Interest on Rupee Securities and Discount on Rupee Treasury Bills	290.35	229.70
(iv) Interest and Discount on Foreign Securities, Investments and Treasury Bills	59.81	42.11
(v) Commission and profit or gain by exchange	4.13	6.65
(vi) Other income	18.98	8.83
	451.82	328.02
Less : Interest paid to the Scheduled banks on the additional average daily balances maintained by them with the Reserve Bank	3.81	17.54
	448.01	310.48

Less : Transfers to Funds as stated in paragraph 370	220.00	115.00
	228.01	195.48

370. The contributions to the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund were Rs. 50 crores, Rs. 45 crores and Rs. 125 crores during the year 1974-75 as against Rs. 45 crores, Rs. 10 crores and Rs. 60 crores, respectively, during the year 1973-74.

371. Out of the balance of income amounting to Rs. 228.01 crores after allowing for total expenditure amounting to Rs. 78.01 crores during the year (as against the balance of income amounting to Rs. 195.48 crores and expenditure of Rs. 50.48 crores in the previous year) the surplus of profit set aside for payment to the Central Government was Rs. 150 crores in comparison with Rs. 145 crores paid last year.

372. The rise of Rs. 137.53 crores in the total income from the level of Rs. 310.48 crores last year to Rs. 448.01 crores was largely due to : (i) higher interest earned due to increase in foreign exchange reserves during the year, and (ii) higher discount earned on treasury bills and an increase in commercial bills discounted for the scheduled banks under the Bill Market Scheme. The rise of Rs. 27.53 crores in the expenditure was mainly due to : (i) an increase in dearness allowance payable to Class III and Class IV staff; (ii) payment of ad-hoc additional dearness allowance to the Officer staff; (iii) arrear commission payable to the State Bank of India and its subsidiaries on Government turn-over transactions during the period 1970-75, and (iv) remuneration payable to agency banks for handling work in connection with the Compulsory Deposit Schemes, 1974.

Auditors

373. The accounts of the Bank have been audited by Messers Dalal & Shah, Bombay, Messers P. K. Mitra & Co., Calcutta, Messers Raghu Nath Rai & Co., New Delhi and Messers M. K. Dandekar & Co. Madras who were reappointed by the Government of India as auditors of the Reserve Bank of India by notification No. F. 7/5/74-BO. I, dated 23rd December, 1974, issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934). In addition to the Bombay Calcutta, Madras and New Delhi Offices, books of accounts at Jaipur and Trivandrum have been audited by the Bank's Statutory Auditors this year. The remuneration of the auditors has been fixed at Rs. 15,000 each for Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi Officers and Rs. 10,000 each for Jaipur and Trivandrum Offices.

The Central Board

374. On his appointment as Executive Director for India, Bangladesh and Sri Lanka on the International Monetary Fund, Shri S. Jagannathan relinquished charge of the office of Governor of the Bank as from the close of business of the 19th May 1975. The Board would like to place on record its appreciation of the eminent services rendered by Shri Jagannathan during his tenure as the Governor of the Bank.

375. Shri N. C. Sen Gupta who was appointed Governor of the Bank for a period of three months (Vide Government of India notification No. F. 7/2/75-BO. I, dated 17th May 1975) assumed charge with effect from the close of business on 19th May, 1975.

376. The term of office of Dr. R. K. Hazari as Deputy Governor has been extended by the Central Government for a further period of three years with effect from 27th November 1974.

377. Dr. P. B. Gajendragadkar, Prof. M. L. Duntwala and Dr. Bhabatosh Datta resigned as Directors of the Central Board of the Bank with effect from 22nd May, 2nd July and 16th July 1975, respectively.

378. Consequent on his appointment as the Chairman of the Policy Planning Committee in the Ministry of External Affairs, Shri G. Parthasarathi also resigned as Director of the Bank with effect from 3rd July, 1975.

379. The Board wish to place on record its appreciation of the valuable services rendered by Dr. P. B. Gajendra-gadkar, Prof. M. L. Dantwala, Dr. Bhabatosh Datta and Shri G. Parthasarathi.

380. Of the seven meetings of the Central Board held during the year, three were held at Bombay and one each at Madras, Simla, Calcutta and Balgalore. The Committee of the Central Board held fifty meetings of which one each was held at Madras and New Delhi and the rest in Bombay.

Local Boards

381 Dr. P. T. Borale, Principal Siddarth Collage of Law, Bombay and Dr. C. Parvathamma, Professor and Head of the Department of Sociology, University of Mysore, Mysore, were appointed by the Central Government under section 9(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934, as Members of the Western and the Southern Area Local Boards of the Bank, respectively, with effect from 24th January, 1975.

382. Prof. M. L. Dantwala, who was nominated as a Director of the Central Board under Section 8(1)(b) of the Reserve Bank of India Act also ceased to be a Member of the Western Area Local Board of the Bank on acceptance of his resignation as a Member of the Local Board by the Central Board with effect from 2nd July, 1975.

Press Relations

383. The Press Relations Section continued to play its useful role in disseminating information to the wider public about the activities of the Bank and its affiliates. The Section started the publication of RBI Newsletter, a fortnightly, in November, 1974. The Newsletter fulfils a long felt need of keeping members of the staff stationed in different parts of the country informed about developments in the Bank and in affiliated institutions.

Bank's Premises

384. The construction of some of the Bank's projects had to be deferred during the current year as the restriction imposed by the Government in 1973 on construction of non-functional buildings was extended by another year i.e., upto 31st March 1975. No new project could also be taken up in the current year due to restrictions on use of cement imposed under Cement (Conservation and Regulation of use) Order, 1974 promulgated by the Government. The progress of work in most of the projects which were under construction stage was affected due to restricted supply of cement. The present position of new projects under construction is given in the following paragraphs.

New Office Premises

385. During the year under review, the foundation work in respect of the Bank's multi-storied office building in the compound of the Mint, Bombay has been completed and the contract for construction of super-structure has been awarded recently. The new vault and renovation of the Dak Bungalow structure for the Sub-Office of Issue Department at Gauhati has since been completed. The construction of the Main Office Building at Hyderabad is in progress.

Residential Quarters

386. The Bank has so far provided 3,890 quarters for its clerical and subordinate staff at various centres. In addition, 609 quarters for clerical and subordinate staff, 112 at Calcutta, 311 at Urur Adyar and Kodambakkam Pudur, Madras and 186 at Bangalore are under construction but the progress has been somewhat slow on account of inadequate supplies of cement during the year under review. The construction of 152 quarters for officers at Bombay is expected to be completed by the end of December 1975.

Office Buildings/Staff Quarters

387. Possession of the plot of land for office building at Gandhinagar, Gujarat has been taken while payment for the plot at Cochin has been made and possession will be taken shortly from the Town Planning Trust. For building Staff Quarters, plots at Hyderabad and Gandhinagar have been purchased and possession taken. The Government/Local Authorities at Chandigarh, Bhopal and Cochin have allotted suitable plots of land for the Bank's staff quarters at those centres and payments for these have been made.

EMPLOYER-EMPLOYEE RELATIONS

Negotiations and Discussions

388. Discussions were held in Central Office between the Bank and the All India Reserve Bank Employees' Association and the All India Reserve Bank Workers' Federation representing workmen staff of the Bank (in Classes II, III & IV) in July, 1974, February, 1975 and April, 1975. In the case of the Class IV staff, the items mainly related to certain local issues of the Bombay centre, which had also an all-India bearing. A general understanding was reached on these issues.

389. Both the All India Organisations had presented Charters of Demands of improvements in the service conditions of their respective members consequent upon the expiry of the existing bi-partite agreements with the Organisations. The Bank held a preliminary round of discussions in April, 1975 with the All India Reserve Bank Employees' Association (representing Classes II and III staff), when the Bank's views on the main item included in the Charter were explained to the Association against the background of the general economic situation in the country, the Government policies and the prevailing conditions in the banking industry. So far as the Charter of Demand submitted by the All India Reserve Bank Worker's Federation (representing Class IV Staff) is concerned, the Bank is likely to hold a preliminary round of discussions on receipt of further material from the Federation.

390. The Reserve Bank Officers Association and the All India Reserve Bank Staff Officers' Association (formerly known as the Supervisory Staff Association) pressed for grant of increased dearness allowance due to rise in the cost of living as well as for the removal of anomalies vis-a-vis the other categories of staff. Discussions in the matter were held at the highest level on several occasions and certain proposals for the revision in the rates of dearness allowance of the Officers made by the Bank to the Government of India were considered by the Government in accordance with their current policy and consequently certain grants were authorised by them on an ad-hoc basis.

391. Discussions were also held with the representatives of the All-India Reserve Bank Staff Officers' Association at Bombay in August, 1974 on certain major and minor issues like combination of seniority, confirmation and promotion, training, quantum of certain allowances, fringe benefits, etc.

392. At the branch level, the Managers/Officers-in-Charge of offices held conciliation conferences/discussions with the representatives of the units of the local Employees' Associations/Workers' Unions at their centres.

393. As in the previous years, during 1974-75 also, the Bank continued to extent patronage and financial assistance in respect of various welfare measures, such as provision of sports and canteen facilities, medical facilities, assistance to welfare organisations in various staff quarters, etc.

394. The Bank is already running a House Magazine which is published quarterly. The Magazine provides a popular forum for the staff of the Bank to give expression to their literary, cultural, academic and artistic talents as well as to publicise the activities in the social and domestic spheres. The Staff Suggestion Scheme introduced by the Bank continues to attract suggestions. Reports on the operation of the Scheme are issued periodically in the form of a letter to the staff from the Chairman of the Committee on Suggestion Scheme.

Employee's Housing Loan Scheme

395. During the year under report, Housing Loans were sanctioned as under :

396. The total amount of 'society' and 'individual' loans sanctioned since the introduction of the scheme in 1961 amounts to Rs. 5,69,58,799.00 and Rs. 3,12,44,140.00, respectively. In all, 3,958 employees have availed themselves of this facility.

	No. of Societies	Amount Rs.
A. New Co-operative Housing Societies	16	1,39,65,181
Additional loans to Co-operative Housing Societies already formed	6	5,89,691
		<u>1,45,54,872</u>
	No. of Employees	Amount Rs.
B. Individual members of staff—		
New loans	234	56,71,572
Additional loans to employees who had already availed of loans earlier	108	31,51,227
		<u>88,22,799</u>

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Bank's Services

397. It was mentioned in the last Report that to improve the representation of Scheduled Castes/Tribes in the services of the Bank, special measures, such as relaxations in basic eligibility standards and qualifying norms, wider publicity of reserved posts in the Bank's services and, where necessary, special recruitments confined to Scheduled Castes/Tribes,

had been initiated. Besides, the back-log in recruitment of Scheduled Castes/Tribes in each office under various groups of cadres for the period 1st January, 1967 to 31st December, 1973 was worked out during the year under review and advised to offices with instructions to bridge the gap within the next 2/3 years. These measures coupled with administrative instructions issued from time to time have resulted in increasing the representation of Scheduled Castes in various cadres and clearing the back-log to a considerable extent. For instance, in the case of recruitment to Class III posts, 45 per cent of the back-log could be cleared by June, 1975 in addition to filling the prescribed current quota. The Bank is, however, experiencing difficulty in filling the quota for Scheduled Tribes.

398. Compared to the position as on 1st January 1974, the representation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees has increased from 896 in Class IV, 1242 in Class III and 36 in Classes II and I to 1043, 1412 and 48, respectively, as on 1st January, 1975.

399. In order to ensure that the instructions regarding reservations in appointment to Scheduled Castes/Tribes are duly implemented, an officer attached to the Special Cell set up in the Department of Administration and Personnel to look after the interests of these communities has been visiting the offices to check the rosters maintained for the purpose. The reports submitted by the officer who visited Bangalore, Byculla (Bombay), Hyderabad, Indore, Madras, New Delhi and Trivandrum during the year were carefully examined and remedial steps, where necessary, have been taken.

400. With a view to increasing the representation of Scheduled Castes/Tribes in the Officer's cadre, steps have been taken to recruit 30 to 40 candidates belonging to these categories as Officers in Grade 'A', the selections for which are being finalised by the Reserve Bank of India Services Board. The Bank has also decided to introduce reservations for Scheduled Castes/Tribes in higher posts in Class I which require special experience and/or qualifications, provided Scheduled Caste/Tribe candidates with requisite qualifications and experience are available.

RESERVE BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1975

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES				ASSETS			
	Rs.	P.			Rs.	P.	
Notes held in the Banking Department	15,49,78,757.00			Gold Coin and Bullion :—			
				(a) Held in India	182,52,58,101.88		
Notes in circulation	6584,76,76,595.50			(b) Held outside India			
Total Notes issued			6600,26,55,352.50	Foreign Securities	121,73,97,234.21		
				Total			304,26,55,336.09
				Rupee Coin			5,59,96,917.65
				Government of India Rupee Securities			6290,40,03,098.76
				Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper			
Total Liabilities			6600,26,55,352.50	Total Assets			6600,26,55,352.50

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES			ASSETS		
	Rs.	P.		Rs.	P.
Capital Paid-up	5,00,00,000.00		Notes	15,49,78,757.00	
Reserve Fund	150,00,00,000.00		Rupee Coin	5,01,112.00	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000.00		Small Coin	2,79,617.24	
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000.00		Bills Purchased and Discounted :—		
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000.00		(a) Internal	126,12,80,388.35	
			(b) External		
			(c) Government Treasury Bills	332,15,67,737.92	
			Balances Held Abroad*	410,95,25,397.68	
			Investments**	677,45,14,553.66	
Deposits :—			Loans and Advances to :—		
(a) Government			(i) Central Government		
(i) Central Government	77,69,36,996.84		(ii) State Governments@	359,90,72,000.00	
(ii) State Governments	8,44,73,019.23		Loans and Advances to :—		
(b) Banks			(i) Scheduled Commercial Banks†	385,26,87,000.00	
(i) Scheduled Commercial Banks	603,50,24,866.97		(ii) State Co-operative Banks††	286,74,36,215.00	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	42,99,13,458.16		(iii) Others	59,88,45,001.00	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,45,98,463.70		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund		
(iv) Other Banks	1,74,10,401.96		(a) Loans and Advances to :—		
(c) Others	982,43,69,501.90		(i) State Governments	69,70,59,860.92	
			(ii) State Co-operative Banks	13,33,72,365.66	
			(iii) Central Land Mortgage Banks		
			(iv) Agricultural Refinance Corporation	88,20,00,000.00	
			(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,65,45,520.00	
Bills Payable	97,97,68,768.31		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund		
Other Liabilities	750,66,31,290.04		Loans and Advances to State Co-operative Banks	82,54,99,826.00	
			Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		
			(a) Loans and Advances to the Development Bank	264,64,55,619.00	
			(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank		
			Other Assets‡	402,75,05,794.68	
Total Liabilities	3585,91,26,766.11		Total Assets	3585,91,26,766.11	

Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,39,999.81 (Sterling Investments of £50,000 converted @ Rs. 100=£5.31915).

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

(ii) Includes Rs. 5,57,42,281.96 (equivalent of £50,000, U.S. \$6,005,000.00 and D.M.9,22,650.00) held abroad.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 203,37,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

‡ Includes an amount of Rs. 188,20,00,000 advanced to certain Scheduled Commercial Banks under special arrangements in respect of their investments abroad.

W.J.F. VAZ
Chief Accountant

Dated the 31st July, 1975.

N.C. SEN GUPTA
R.K. HAZARI
V.V. CHARI
S.S. SHIRALKAR
R.K. SESHADRI

Governor.
Deputy Governor.
Deputy Governor.
Deputy Governor.
Deputy Governor.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1975

INCOME		Rs.	P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.†		228,00,56,335.	37
		228,00,56,335.	37
EXPENDITURE			
Establishment		34,65,01,633.	44
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses		1,05,246.	11
Auditors' Fees		80,000.	00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.		1,24,49,577.	27
Law Charges		87,719.	80
Postage and Telegraph Charges		16,32,353.	18
Remittance of Treasure		94,38,912.	02
Stationery, etc.		57,20,982.	75
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)		5,82,42,274.	86
Depreciation and Repairs to Bank Property		1,30,46,628.	84
Agency Charges		31,24,70,222.	44
Contributions to Staff and Superannuation Funds		40,00,000.	00
Miscellaneous Expenses		1,62,79,950.	34
Net available balance		150,00,00,834.	32
		228,00,56,335.	37
Surplus payable to the Central Government		150,00,00,834.	32

RESERVE FUND ACCOUNT

	Rs.	P.
By Balance on 30th June 1975	150,00,00,000.	00
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil	
Total	150,00,00,000.	00

†After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

W. J. F. VAZ
Chief Accountant.

N.C. SEN GUPTA
R.K. HAZARI
V.V. CHARI
S.S. SHIRALKAR
R.K. SESHADRI

Governor.
Deputy Governor.
Deputy Governor.
Deputy Governor.
Deputy Governor.

Report of the Auditors

TO THE PRESIDENT OF INDIA,

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June 1975.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay (Fort), Madras, New Delhi, Trivandrum and Jaipur and with the returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

Messrs. DALAL & SHAH,
Messrs. P.K. MITRA & CO.,
Messrs. RAGHUNATH RAI & CO.,
Messrs. M.K. DANDEKAR & CO., } Auditors.

Dated the 31st July, 1975.

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET

Particulars	For the year Ended							
	June 30, 1974				June 30, 1973			
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
ISSUE DEPARTMENT								
LIABILITIES								
Notes held in the Banking Department	37,17,59,161.00				36,45,28,788.00			
Notes in circulation	6472,72,04,191.50				5698,95,49,930.50			
Total Notes issued			6509,89,63,352.50				5735,40,78,718.50	
Total Liabilities			6509,89,63,352.50				5735,40,78,718.50	
ASSETS								
Gold Coin and Bullion (a) Held in India	182,53,04,731.42				182,53,07,821.82			
(b) Held outside India								
Foreign Securities	166,73,97,234.21				177,36,80,055.13			
Rupee Coin	7,50,63,787.68				8,38,06,402.14			
Government of India Rupee Securities	6153,11,97,599.19				5367,12,84,439.41			
Internal Bills of Exchange and other Commercial paper								
Total Assets			6509,89,63,352.50				5735,40,78,718.50	
BANKING DEPARTMENT								
LIABILITIES								
Capital Paid-up	5,00,00,000.00				5,00,00,000.00			
Reserve Fund	150,00,00,000.00				150,00,00,000.00			
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	284,00,00,000.00				239,00,00,000.00			
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000.00				85,00,00,000.00			
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	265,00,00,000.00				205,00,00,000.00			
Deposits								
(a) Government								
(i) Central	61,57,98,480.17				57,04,56,105.17			
(ii) State	26,36,81,522.93				29,48,26,324.36			
(b) Banks								
(i) Scheduled Commercial Banks	553,50,77,103.97				537,70,49,336.10			
(ii) Scheduled State Co-op. Banks	26,26,10,122.81				22,75,49,813.28			
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,48,06,487.84				1,05,13,846.77			
(iv) Other Banks	1,09,04,310.40				3,10,35,415.92			
(c) Others	512,57,15,516.12				207,69,34,439.69			
Bills Payable	125,52,38,985.22				54,03,75,419.80			
Other Liabilities	483,81,97,868.98				334,55,91,293.62			
Total Liabilities			2591,20,30,398.44				1931,43,31,994.71	

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET (Contd.)

Particulars	For the Year Ended							
	June 30, 1974				June 30, 1973			
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
ASSETS								
Notes	37,17,59,161.00				36,45,28,788.00			
Rupee Coin	3,49,127.00				9,48,063.00			
Small Coin	2,51,761.34				2,66,968.46			
Bills Purchased and Discounted								
(a) Internal	274,37,78,289.83				15,22,91,040.89			
(b) External			
Government Treasury Bills	128,67,52,866.15				301,59,21,815.74			
Balances held abroad	596,33,23,105.29 ¹				266,82,82,995.02 ⁷			
Investments	217,37,84,159.20 ⁸				540,20,49,769.16 ⁸			
Loans and Advances to								
(i) Central Government			
(ii) State Governments	177,82,73,164.18 ⁹				39,88,00,000.00 ⁹			
(iii) Scheduled Commercial banks	420,99,85,000.00 ⁴				140,54,20,000.00 ⁹			
(iv) State Co-operative Banks	166,52,34,128.00 ⁵				189,52,75,475.00 ⁵			
(v) Others	38,16,95,000.00				11,32,75,000.00			
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund :								
(a) Loans and Advances to								
(i) State Governments	67,87,33,623.72				66,41,05,471.13			
(ii) State Co-operative Banks	15,65,67,755.33				17,97,47,227.00			
(iii) Central Land Mortgage Banks			
(iv) Agricultural Refinance Corporation	54,00,00,000.00				34,50,00,000.00			
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,13,13,970.00				11,24,91,225.00			
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund to State Co-operative Banks	52,87,68,118.00				41,06,37,914.00			
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund								
(a) Loans and Advances to the Development Banks	178,69,55,519.00				129,09,35,519.00			
(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank			
Other Assets	153,45,05,650.40 ⁶				89,43,54,723.31			
Total Assets			2591,20,30,398.44				1931,43,31,994.71	

Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,48,38.869 (Sterling Investments of £50,000 converted @ Rs. 100 = £5.2721).

1. Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.
2. (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.
(ii) Includes Rs. 5,39,54,792.90 (equivalent of £50,000, U.S. \$6,247,475 and D.M. 1,110,375 held abroad).
3. Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.
4. Includes Rs. 156,63,73,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.
5. Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.
6. Includes an amount of Rs. 50,00,00,000 advanced to certain scheduled commercial banks under special arrangements in respect of their investments abroad.
7. (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.
(ii) Includes Rs. 5,17,39,176.19 (equivalent of £50,000, U.S. \$6298,175 and D.M. 1494,112.50 held abroad)
8. Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.
9. Includes Rs. 31,30,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1973 AND 1974

	1974		1973	
	Rs.	P.	Rs.	P.
INCOME				
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.†	195,47,95,113.00		171,29,18,131.22	
	195,47,95,113.00		171,29,18,131.22	
EXPENDITURE				
Establishment	28,53,25,934.78		22,89,24,841.34	
Directors' and Local Board Members' Fees & Expenses	66,346.31		66,520.16	
Auditors' Fees	80,000.00		90,000.00	
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	1,16,05,263.44		1,07,82,931.00	
Law Charges	1,68,540.71		2,89,496.64	
Postage and Telegraph Charges	14,04,042.18		13,31,396.50	
Remittance of Treasure	81,33,581.59		81,87,102.19	
Stationery, etc.	40,22,877.04		32,00,280.92	
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	5,19,42,441.13		4,95,97,945.84	
Depreciation and Repairs to Bank Property	1,10,81,345.49		1,03,67,923.13	
Agency Charges	11,19,19,385.81		8,30,83,593.94	
Contributions to Staff and Superannuation Funds	50,00,000.00		50,00,000.00	
Miscellaneous Expenses	1,40,45,191.20		1,19,95,478.22	
Net available balance	145,00,00,163.32		130,00,00,621.34	
TOTAL	195,47,95,113.00		171,29,18,131.22	
Surplus Payable to the Central Government	145,00,00,163.32		130,00,00,621.34	
RESERVE FUND ACCOUNT				
By Balance on 30th June	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil.		Nil.	
TOTAL	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	

†After making usual or necessary provision in terms of section 47 of the Reserve Bank of India Act.

[No. F10(13/75-B.O.I.)]

Dr. D. N. SAXENA, Jt. Secy.

(अध्यय विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

का० आ० 752.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी एतद्वारा कर्मकार अंशदायी भविष्य निधि को नियमन करने वाले नियमों में और प्रागे संशोधन करते हैं, जैसा कि भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त विभाग के संकल्प संख्या एफ-एफ-33(3)-आर० 11/44 दिनांक 16 अप्रैल, 1945 में संस्थापित किया हुआ है; अर्थात्:—

उक्त संकल्प के पैराग्राफ 1 में प्रविष्टि XXIV के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी और इस प्रविष्टि को पहली अप्रैल, 1973 से जोड़ा हुआ माना जाएगा; अर्थात्:—

“XXV अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग का निर्माण-कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) प्रतिष्ठान”

व्याख्यात्मक भाषण

अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के निर्माण कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) स्टाफ के संबंध में अंशदायी भविष्य निधि योजना पहली अप्रैल, 1973 से, उन कर्मचारियों पर प्रभावी होगी जिन्होंने उक्त तारीख को कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो। इस योजना को पूर्व व्यापी प्रभावी करने से अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एफ० 19(1)—संस्था V (ख) /75]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 15th November, 1975

S.O. 752.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the rules regulating the Workmen's Contributory Provident Fund, as instituted with the Government of India, late Finance Department, Resolution No. F. 33(3)-R. II/44, dated the 16th April, 1945, namely:—

In paragraph 1 of the said Resolution, after entry XXIV, the following entry shall be added, and shall be deemed to have been added with effect from the 1st April, 1973, namely:—

“XXV. Work-charged Establishment of the Civil Engineering Division of the Department of Space.”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Contributory Provident Fund Scheme shall come into force with effect from the 1st April, 1973 in respect of work-charged staff of the Civil Engineering Division, Department of Space, who have rendered at least one year's continuous service on that date. None of the employees of the Civil Engineering Division of the Department of Space will be adversely affected by giving retrospective effect to the Scheme.

[No. F. 19(1)-E. V. (B)/75]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1975

का० आ० 753.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी एतद्वारा कर्मकार अंशदायी भविष्य निधि को नियमन करने वाले नियमों में और प्रागे संशोधन करते हैं, जैसा कि भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त विभाग के संकल्प संख्या 33(3)-आर० II/44 दिनांक 16 अप्रैल 1945 में संस्थापित किया हुआ है; अर्थात्:—

उक्त संकल्प के पैराग्राफ 1 में प्रविष्टि XXV के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी तथा इस प्रविष्टि को पहली अप्रैल 1970 से जोड़ा हुआ माना जाएगा, अर्थात्:—

“XXVI अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग का निर्माण कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) स्टाफ जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग से लिया गया है।”

व्याख्यात्मक भाषण

अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के निर्माण कार्य-प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) स्टाफ जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग से लिया गया है, के संबंध में अंशदायी भविष्य निधि योजना पहली अप्रैल, 1970 से, उन कर्मचारियों पर प्रभावी होगी जिन्होंने उक्त तारीख को कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो। इस योजना को पूर्वव्यापी प्रभावी करने से परमाणु ऊर्जा विभाग में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग से लिये गये किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एफ० 19(1)—संस्था V (ख)/75]

New Delhi, the 17th November, 1975

S.O. 753.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the rules regulating the Workmen's Contributory Provident Fund, as instituted with the Government of India, late Finance Department, Resolution No. F. 33(3)-R. II/44, dated the 16th April, 1945, namely:—

In paragraph 1 of the said Resolution, after entry XXV, the following entry shall be added, and shall be deemed to have been added with effect from the 1st April, 1970, namely:—

“XXVI—Work-charged staff of the Civil Engineering Division of the Department of Space taken over from the Architecture and Civil Engineering Division of Bhabha Atomic Research Centre, Department of Atomic Energy”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Contributory Provident Fund Scheme shall come into force with effect from the 1st April, 1970 in respect of the Work-charged staff of the Civil Engineering Division, Department of Space, taken over from the Architecture and Civil Engineering Division of the Bhabha Atomic Research Centre, Department of Atomic Energy, who have rendered at least one year's continuous service on that date. None of the employees taken over from the Architecture and Civil Engineering Division of the Bhabha Atomic Research Centre, Department of Atomic Energy will be adversely affected by giving retrospective effect to the Scheme.

[No. F. 19(1)-E. V.(B)/75]

New Delhi, the 31st December, 1975

S.O. 754.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following regulations further to amend the Civil Service Regulations, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Civil Service (Third Amendment) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Civil Service Regulations, article 959, article 962 to article 967 (both inclusive), article 970 and article 972 shall be omitted.

[No. F. 6(1)-EV(A)/75]

New Delhi, the 12th January, 1976

S.O. 755.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in sub-rule (i) of rule 16, in the proviso for the figures "1,00,000" the figures "1,25,000" shall be substituted.

[No. F. 10(3)-EV(B)/75-GPF]

S.O. 756.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India) 1962, in sub-rule (1) of rule 17, in the proviso for the figures "1,00,000" the figures "1,25,000" shall be substituted.

[No. F. 10(3)-EV(B)/75]

New Delhi, the 22nd January, 1976

S.O. 757.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in sub-rule (1) of rule 5, for the words "to the Account Officer, a nomination", the word "to the Account Officer through the Head of Office, a nomination" shall be substituted.

[No. F. 13(1)-EV(B)/76-GPF]

New Delhi, the 27th January, 1976

S.O. 758.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, in sub-rule (1) of rule 5, for the words "to the Account Officer, a nomination", the words "to the Account Officer through the Head of Office, a nomination shall be substituted.

[No. F. 13(1)-EV, (B)/76-CPF]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1976

क्र० प्रा० 759.—संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 की खंड 5 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जाये।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा जाएगा) के नियम 38 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"38. असमर्थता पेंशन—(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता, जो उसे सेवा करने के लिए स्थायी रूप से असमर्थ करे, के कारण सेवा-निवृत्त होता है तो असमर्थता पेंशन स्वीकार की जा सकती है।

(2) असमर्थता पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकरण से असमर्थता का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा, अर्थात् :—

(क) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में और ऐसे अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन भूस नियमावली के नियम 9 (21) में जैसा निर्दिष्ट किया हुआ है के अनुसार सात सौ पचास रुपए प्रति माह से अधिक हो, चिकित्सा बोर्ड (मेडिकल बोर्ड)।

(ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समान हैसियत का चिकित्सा अधिकारी।

टिप्पणी 1 :—किसी भी अशक्तता के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जब तक कि आवेदक इस संबंध में यह पत्र पेश न करे कि उनके कार्यालय या विभागाध्यक्ष को इस बात की जानकारी है कि आवेदक चिकित्सा प्राधिकरण के सामने इस आशय से पेश होने जा रहा है। जिस विभाग या कार्यालय में आवेदन कर्ता नियुक्त है उसके अध्यक्ष द्वारा

चिकित्सा प्राधिकरण को सरकारी शिफारिश के अनुसार आवेदन को प्राप्त जितनी प्रतीत होती हो, उसका भी विवरण दिया जाएगा। यदि आवेदन करने के लिए कोई सेवा प्रतिष्ठा रखी जा रही है तो उसमें दर्ज की गई अवस्था भी बतायी जानी चाहिए।

टिप्पणी 2 :—जब किसी महिला उम्मीदवार की जांच की जानी हो तो चिकित्सा बोर्ड में एक महिला डाक्टर को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा भर्जित किए जाने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का फार्म 23 के अनुसार होगा।

(4) यदि किसी मामले में उप नियम (2) में उल्लिखित चिकित्सा प्राधिकरण किसी सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा किए जा रहे कार्य से कम श्रम साध्य कार्य में और आगे सेवा करने के लिए योग्य घोषित कर दे, ब्रॉन कि सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के नियोजन के लिए सहमत हो, तो उसे निम्न पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और यदि उसे निम्न पद पर नियोजित करने के लिए कोई साधन न हो तो उसे असमर्थता पेंशन के लिए स्वीकार किया जाए।

(5) (क) यदि सरकारी कर्मचारी की अशक्तता प्रत्यक्ष रूप से उसके विषम और उग्र स्वभाव के कारण है तो कोई भी असमर्थता पेंशन नहीं दी जाएगी।

(ख) यदि अशक्तता प्रत्यक्षतः इस प्रकार की आघातों के कारण नहीं हुई हो बल्कि उनके कारण तब्रित या उत्तेजित हुई हो तो इसका निर्णय पेंशन संजूर करने वाले प्राधिकरण पर निर्भर होगा कि इस संबंध में क्या कटौती की जानी चाहिए।”

3. उक्त नियमावली में फार्म 22 के पञ्चात् निम्नलिखित फार्म अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

‘फार्म 23’

[कृपया नियम 38 (3) देखिए]

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का फार्म

“प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/(हमने) क. ख. सुपुत्र ग. घ. जो मैंने/हमने की यावधानी पूर्वक जांच की है। उसके कथन के अनुसार उसकी आयु— वर्ष है तथा देखने से लगभग— वर्ष है *मैं/(हम) यह धारणा करते हैं कि— (यहां बीमारी या कारण का उल्लेख कीजिए) के परिणामस्वरूप क. ख. सम्बद्ध विभाग में और आगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः तथा स्थायी रूप से असमर्थ है। * मुझे/हमें ऐसा भासूम नहीं होता कि उसकी अशक्तता विषम और उग्र स्वभाव के कारण हुई है।”

टिप्पणी :— यदि अशक्तता विषम या उग्र स्वभाव के कारण हो तो वाक्य के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“मेरी/हमारी राय में उसकी अशक्तता” प्रत्यक्ष रूप से विषम या उग्र स्वभाव के कारण है/विषम या उग्र स्वभाव द्वारा तब्रित या उत्तेजित हुई है।”

यदि अशक्तता पूर्ण तथा स्थायी न दिखाई देती हो तो तदनुसार प्रमाण-पत्र में संशोधन किया जाना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“मेरी/हमारा यह विचार है कि *क. ख. जो कार्य कर रहा था उसमें कम श्रम साध्य कार्य में और आगे सेवा करने के योग्य है/जो कार्य कर

रहा था.—मेरीने विश्वास करने के पश्चात्, उसमें कम श्रम साध्य कार्य में और आगे सेवा करने के योग्य हो जाएगा।”

* जो कार्य न हो उसे काट दिया जाए।

[सं. एक. 19(3) संस्था 5(क)/74]

श्याम सुन्दर लाल मलहोत्रा, अधिवक्ता

New Delhi, the 29th January, 1976

S.O. 759.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 38, the following rule shall be substituted, namely :—

“38. Invalid pension.—(1) Invalid pension may be granted if a Government servant retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service.

(2) A Government servant applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from the following medical authority, namely :—

(a) a Medical Board, in the case of a Gazetted Government servant and of a non-gazetted Government servant whose pay, as defined in Rule 9(21) of the Fundamental Rules, exceeds seven hundred and fifty rupees per mensem;

(b) Civil Surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

Note 1.—No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the Head of his Office or Department is aware of the intention of the applicant to appear before the medical authority. The medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or Department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant. If a service book is being maintained for the applicant, the age recorded therein should be reported.

Note 2.—A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board, when a woman candidate is to be examined.

(3) The form of the Medical Certificate to be granted by the medical authority specified in sub-rule (2) shall be as in Form 23.

(4) Where the medical authority referred to in sub-rule (2) has declared a Government servant fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he should, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(5) (a) If the incapacity is directly due to the irregular or intemperate habits of a Government servant, no invalid pension shall be granted.

(b) If the incapacity has not been directly caused by such habits but has been accelerated or aggravated by them, it shall be for the pension sanctioning

authority to decide what reduction should be made on this account."

3. In the said rules, after Form 22, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form 23

[See rule 38(3)]

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE

"Certified that I/(We) have carefully examined AB son of CD a ————— in the ————— years, and by His age by his own statement is ————— years, and by appearance about ————— years. I/(We) consider AB to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs in consequence of ————— (here state disease or cause). His incapacity does not appear to me/us to have been caused by irregular or intemperate habits.

NOTE.—If the incapacity is the result of irregular or intemperate habits, the following will be substituted for the sentence :—

"In my/our opinion on his incapacity is directly due to the irregular or intemperate habits/has been accelerated or aggravated by the irregular or intemperate habits."

If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made :

"I am/we are of opinion that AB is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing/may, after resting for months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing."

*Strike out whichever is not applicable.

[No. F. 9(3)-EV(A)/74]

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 760.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Third Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960, in the Fifth Schedule, in paragraph 2, after the entry "Officer on Special Duty or Deputy Director in the Field Organisation Division of the National Sample Survey Organisation in respect of Class III and Class IV Staff under him", the following entry shall be inserted, namely :—

"Senior Deputy Accountant General (Works) in the office of the Accountant General, Madhya Pradesh-II".

[No. F. 13(2)-EV(B)/76]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 15th January, 1976

S.O. 761.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 and clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and

Auditor General in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (First Amendment) Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (2) of rule 38, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) (a) Where a Government servant who is on foreign service in or under any local authority or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Government or a body controlled or financed by the Government (hereinafter referred to as the local body) applies for leave preparatory to retirement, the decision to grant or refuse such leave shall be taken by foreign employer with the concurrence of the lending authority under Central Government.

(b) In case the leave is so refused to the Government servant in public interest, it may be availed of by him to the extent admissible under rule 39 from the date of his quitting service.

(c) In case the lending authority under Central Government is not agreeable to the refusal of leave preparatory to retirement, it shall be granted to the Government servant and if the foreign employer needs the services of the officer during that period, the Government servant may be re-employed by that employer concurrently with leave preparatory to retirement and leave salary regulated in accordance with the provisions of sub-rule (6) of the rule 40."

3. In the First Schedule to the said rules in Serial No. 1 :—

(i) in Note 1, for Clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) Foreign employer.—Power to be exercised only in respect of earned leave not exceeding 120 days and while taking decision to grant or refuse leave preparatory to retirement, prior concurrence of the lending authority under the Central Government shall be obtained as provided in sub-rule (2) of rule 38."

(ii) for Note 2, the following Note shall be substituted, namely :—

"Note 2:—If the Government servant is serving with a State Government, the State Government or such authority as may be specified by that Government:

(a) While taking decision to grant or refuse leave preparatory to retirement, prior concurrence of lending authority under the Central Government shall be obtained;

(b) in case, the leave is so refused in public interest, it may be availed of by the Government servant to the extent admissible under rule 39 from the date of his quitting service;

(c) in case the lending authority under the Central Government is not agreeable to the refusal of leave preparatory to retirement, it shall be granted to the Government servant and if the State Government needs the services of the officer during that period, the Government servant may be re-employed by that Government concurrently with the leave preparatory to retirement and leave salary regulated in

accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 40.”

[No. 5(16)-E. IV(A)/73]

C. N. SUDARSANAN, Under Secy.

(केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय)

पटना, 20 दिसम्बर, 1975

सीमा शुल्क

का० आ० 762.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों, जिनका प्रत्यायोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 79/सीमाशुल्क/मि० सं० 473/2/75-सी० शु० VII वि० 18-7-75 के अन्तर्गत सीमा शुल्क समाहर्ता में किया गया है, का प्रयोग करते हुए मैं बिहार राज्य के सिन्धभूमि जिले के जमशेदपुर स्थित 'गोलमुरी' को भांडागार स्टेशन घोषित करता हूँ।

[सं० 1/सी०शु०/मि० सं० VIII(1) 1-सी०शु०/75]
हरिनारायण साहू, समाहर्ता

(Collectorate of Central Excises)

CUSTOMS

Patna, the 20th December, 1975

S.O. 762.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), as delegated to the Collector of Customs, under the Government of India, Ministry of Finance Notification No. 79/Customs/F. No. 473/2/75-Cus. VII dated the 18th July, 1975, I declare 'GOLMURI' in Jamshedpur town of Singhbhum district in the State of Bihar to be a warehousing station.

[No. 1/Cus./F. No. VIII(1) 1-Cus/75]

H. N. SAHU, Collector

समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मध्य प्रदेश एवं बिहार
नागपुर, 19 जनवरी, 1976

का० आ० 763.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 15 और 16 के अन्तर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अधिसूचित करता हूँ कि इस समाहर्ता क्षेत्र की अधिसूचना सं० 8/68 दिनांक 28 अक्टूबर, 1968 में आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा। क्रमसंख्या 29 (बिलासपुर जिला) के सामने 'तालाब तल क्षेत्र' शब्दावली हटा ली जाएगी।

रवीन्द्रनाथ शुक्ला, समाहर्ता

[अधिसूचना सं० 1/76/प० सं० 1(16) 44/74/सांख्यिकी]

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, M.P. &
VIDARBHA

Nagpur, the 19th January, 1976

S.O. 762.—In exercise of the powers conferred under Rules 15 and 16 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby notify that the following further amendment shall be made in this Collectorate notification No. 8/68-CE dated the 28th October 1968.

Against Serial No. 29 (Bilaspur District) the words "Tank Bed Areas" shall be deleted.

[Notification No. 1/76/C No. IV (16) 44/74/ST]

R. N. SHUKLA, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का० आ० 764.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1968 (1968 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेंढक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम मेंढक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है।

(2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मेंढक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में, नियम 4 के उपनियम (2) में "7 दिन" शब्द तथा शब्द के स्थान पर "पन्द्रह दिन" शब्द रख जायेंगे।

[सं० 6(9)/71/ई० आई० एण्ड ई० पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 764.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Frog Legs (Inspection) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2 In the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, in sub-rule (2) of rule 4, for the figure and word "7 days" the words "fifteen days" shall be substituted.

[No. 6(9)/71/EI&EP]

आदेश

का० आ० 765.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की खनिज तथा अयस्क संबंधी अधिसूचना सं० का० आ० 3978, ता० 20 दिसम्बर, 1963 में नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है।

और केन्द्रीय सरकार ने, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथा-अपेक्षित उन प्रस्तावों को निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उनसे संभावित प्रभावित होने वाली जनता की सूचना के लिए प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की बांछा करने वाला कोई व्यक्ति, उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' 14/1-बी०, एज़रा स्ट्रीट (घाटबी मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3978 ता० 20 दिसम्बर, 1965 में, अनुसूची में, क्रम सं० 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

- "12. लोहे का काला आक्साइड
13. गैर (गैरिक)
14. प्राकृतिक सिएना (कच्ची और पकाई गई)
15. प्राकृतिक अम्बर (कच्चा और पकाया गया)"

[सं० 6(40)/72 नि० नि० तथा नि० सं०]
के० बी० बालसुरबामनियम, उप-निदेशक

ORDER

S.O. 765.—Whereas the Central Govt. in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) is of opinion that it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 3978, dated the 20th December, 1965 regarding minerals and ores group II, in the manner specified below for the development of the export trade of India;

And whereas the Central Government has forwarded the proposals in that behalf of the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality, Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same, within thirty days from the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre' 14/1-B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Proposals

In the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 3978 dated the 20th December, 1965 in the schedule after serial No. 11 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

- "12. Black oxide of iron
13. Red Ochre
14. Natural sienna (raw and burnt)
15. Natural umber (raw and burnt)"

[No. 6 (40)/75EI & EP.]

K. V. BALASURBAMANIAM, Dy. Director

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1976

(इलायची निर्यात)

का० प्रा० 766.—इलायची नियम, 1966 के नियम 3 तथा नियम 5 के उपनियम 2 (घ) के साथ पठित, इलायची अधिनियम,

1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा 3 के खण्ड (इ) (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नोक्त व्यक्तियों को इलायची बोर्ड के सदस्य के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है तथा यह विनिश्चित करती है कि वे सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली तथा 25 अगस्त, 1978 तक की अवधि के लिए उक्त पद धारण करेंगे।

- (1) श्री एम० मुत्तुस्वामी,
सचिव,
दक्षिण भारतीय बागान वर्कर्स यूनियन,
पो० प्रा० मुन्नार, केरल।
- (2) श्री के० के० देवसिया,
उपाध्यक्ष,
उदुम्बुनचोला एस्टेट वर्कर्स यूनियन,
पो० प्रा० वन्दनमेडु (केरल)

[फाइल सं० 32(20)/75-प्लांट (बी)]

एस० महादेव प्रय्यर, प्रवर सचिव

(Department of Export Production)

New Delhi, the 30th January, 1976

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 766.—In exercise of the powers conferred by clause (e) (iv) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), read with sub-rule (2) (d) of rule 3 and rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby appoints the persons mentioned below to be the members of the Cardamom Board to represent the interests of Labour and specifies that they shall hold office as such for a period commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette and upto the 25th August, 1978.

- (1) Shri M. Muthuswamy, Secretary, South Indian Plantation Workers Union, P.O. Munnar, Kerala.
- (2) Shri K. K. Devasia, Vice-President, Udumboonchola Estate Workers' Union, P.O. Vandanmedu (Kerala).

[File No. 32(20)/75-PLANT(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

(मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1975

का० प्रा० 767.—सर्वोच्च लेल और प्राकृतिक गैस आयोग लेल भवन, वेहरादून को अनुमेय ब्लो-माउंट पिसेन्टर्स और लाइसेंस के साथ संलग्न सूची के अनुसार आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या जी/ए/1401636/सी०/एक्स० एक्स०/52/एच०/39-40 दिनांक 25-7-74 प्रदान किया गया था। लेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सूचना दी है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति छोटी गई/अस्थायित्व हो गई है और लाइसेंस को अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है।

अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति छोटी गई है और निवेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाये।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई है। उस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एन० डी०/148/74-75/पी०एच०एस०/बी०/981]

आशुतोष मुखर्जी

उप-मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

द्वितीय संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Import and Export)

ORDER

New Delhi, the 27th December, 1975

S.O. 767.—M/s. Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan Dehradun was granted licence No. G/A/1401636/C/XX/52/H/39-40 dated 25-7-74 for the import of permissible blow-out preventers and as per list attached. The Oil and Natural Gas Commission has reported that the customs copy of the licence has been lost/misplaced and has requested to issue duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the customs copy of the licence has been lost and directs that the duplicate copy of the said customs purpose copy of the licence be issued.

The original customs purpose copy of the licence has been cancelled. A duplicate copy of the same is being issued separately.

Ashatosh Mukherjee, Controller

for Chief Controller.

[No. ND/148/74-75/PLS/B/981]

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1976

क्र० आ० 768.—श्री एस०सी० पौदार सुपुत्र श्री आर०एल० पौदार, 27, दिल्ली प्रशासन क्वार्टर्स, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली को एक .32 बोर रिबोल्वर के आयात के लिए 1000 रुपये (एक हजार रुपये) के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट संख्या पी०जे०/3046866, दिनांक 21-5-1974 प्रदान किया गया था। उन्होंने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट संख्या : पी०जे०/3046866, दिनांक 21-5-1974 खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूँ कि अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परमिट आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट रद्द की जाती है।

[संख्या : 315-4/एस०-26/ए०एस०-75/अर्ब-1831]

एन०सी० काजीलाव, उप-मुख्य निर्यातक

द्वितीय मुख्य निर्यातक

ORDER

New Delhi, the 5th January, 1976

S.O. 768.—Shri S. C. Poddar s/o Shri R. L. Poddar 27, Delhi Administration Flats, Greater Kailash I, New Delhi was granted CCP No. P/J/3046866 dt. 21-5-1974 for Rs. 1000/- (Rupees one thousand) for the import of one .32 Bore Revolver. He has applied for a duplicate copy of the C.C.P. on the grounds that the original C.C.P. has been lost/misplaced. It is further stated that the original C.C.P. was not registered with any Customs House and not utilised. In support of this contention, he has filed an affidavit I am satisfied that the original C. C. P. No. P/J/3046866 dt. 21-5-1974 has been lost/misplaced and direct that a duplicate C.C.P. should be issued to the applicant. The original C.C.P. is cancelled.

[File No. 315. iv/S-26/AM. 75/ADHOC/1831]

N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller

for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1976

क्र० आ० 769.—महेश्वरी हिन्दुस्तान ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, बम्बई को आवश्यक पुर्जों एवं उपसाधक सहित एक 830 केवीए डीजल जनरेटिंग सेट के साथ आयात करने के लिए 5,59,790 रु० (पांच लाख पचास हजार सातसौ नब्बे रुपये मात्र) रुपये के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०सी०जी०/2066344/टी०/ई०आ०/49/एच०/37-38, दिनांक 10-12-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क की मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क की मूल प्रति बम्बई पत्तन पर पंजीकृत कराई गई थी और 5,13,300 रु० रुपये की सीमा तक उपयोग में लाई गई थी। सीमा-शुल्क प्रति की एक अनुलिपि बिना उपयोग किए गए शेष धन 16,490 रुपये के लिए आवश्यक है।

2. लाइसेंसधारी ने अपने तर्कों के समर्थन में महाराष्ट्र राज्य सीटरी के समक्ष शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तबनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन की मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (निर्यात) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी०सी०) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयात लाइसेंस संख्या : पी०सी०जी०/2066344, दिनांक 10-12-1973 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जाँच सर्वश्री हिन्दुस्तान ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बम्बई को जारी की गई थी, एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. उपर्युक्त आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की एक अनुलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या : 5/4(834)/73-74/सी०जी०-1]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य निर्यातक

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1976

S.O. 769.—M/s. Hindustan Transmission Products, Bombay were granted import licence No. P/CG/2066344/1/ER/49/H/37-38, dated 10-12-75 for Rs. 5,59,790/- (Rupees five lakhs fifty nine thousand seven hundred and ninety only) for import of One No. 830 KVA Diesel Generating Set with essential spares and accessories. They have applied for the issue of a duplicate Customs purpose copy of said licence on the ground that the original Customs

Purposes copy of the Import licence has been lost/misplaced. It has further been stated that original Customs copy of import licence was registered with the Bombay Customs House and utilised to the extent of Rs. 5,13,300. The duplicate Customs copy is required for unutilized balance of Rs. 46,490.

2. In support of their contention the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn before a Notary, Maharashtra State. I am accordingly satisfied that the original Customs purpose copy of the licence has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs purpose copy of Import licence No. P/CG/2066344, dated 10-12-1973 issued to M/s. Hindustan Transmission Products, Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said import licence is being issued to the party separately.

[No. 5/4(834)/73-74/CG. I]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1976

का० प्रा० 770.—सर्वश्री तमिल नाडू औद्योगिक विकास निगम लि०, मद्रास को आयात लाइसेंस संख्या: जी०ए०/1413822, दिनांक 26-4-1975 प्रदान किया गया था। तमिल नाडू औद्योगिक विकास निगम लि०, मद्रास ने सूचना दी है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उन्होंने उसकी अनुलिपि प्रति के लिए अनुरोध किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर बचन दिया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी की जाए।

लाइसेंस संख्या : जी०ए०/1413822, दिनांक 26-4-75 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है। उसकी सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या: एस०जी०/291/74-75/पी०एल०एस०/बी०/1157]

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1976

S.O. 770.—M/s. Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd., Madras were granted import licence No. G/A/1413822 dt. 26-4-1975. M/s. Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd., Madras have reported that the Customs Purpose Copy of the said licence has been lost/misplaced and they have requested to issue the duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant have given undertaking on the stamped paper. The undersigned is satisfied that the Customs purpose copy of the subject import licence has been lost and directs that the duplicate Customs Purpose copy of the said licence be issued.

The Original Customs Purpose copy of the licence No. G/A/1413822 dt. 26-4-1975 has been cancelled. Duplicate Customs Purpose copy of the same is being issued.

[No. SG/291/74-75/PLS/B/1157]

आदेश

का० प्रा० 771.—सर्वश्री तमिल नाडू औद्योगिक विकास निगम लि०, मद्रास को आयात लाइसेंस संख्या: जी०ए०/1591519, दिनांक 7-11-1974 प्रदान किया गया था। सर्वश्री तमिल नाडू औद्योगिक विकास निगम लि०, मद्रास ने निवेदन किया है कि उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उन्होंने इस प्रति की अनुलिपि जारी करने की प्रार्थना की है।

आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में स्टाम्प कागज पर बचन दिया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी की जाए।

लाइसेंस संख्या: जी०ए०/1591519, दिनांक 7-11-1974 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई है। सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी की जा रही है।

[संख्या: एस० जी०/188/74-75/पी० एल० एस०/बी०/1157]

ओ०एन० आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 771.—M/s. Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd., Madras were granted import licence No. G/A/1591519 dt. 7-11-1974. M/s. Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd., Madras have reported that the Customs Purpose Copy of the said licence has been lost/misplaced and they have requested to issue the duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant have given undertaking on the stamped paper. The undersigned is satisfied that the Customs Purpose Copy of the subject import licence has been lost and directs that the duplicate customs purpose copy of the said licence be issued.

The Original Customs Purpose Copy of the licence No. G/A/1591519 dt. 7-11-1974 has been cancelled. Duplicate Customs Purpose Copy of the same is being issued.

[No. SG/188/74-75/PLS/B/1157]

O. N. ANAND, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 8 अगस्त, 1975

का० प्रा० 772.—सर्वश्री सखोट नेबोरेट्रीज (इंडिया) प्रा० लि०, पाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ना, बम्बई-400070 को 40645 रुपये (चालीस हजार छः सौ पैंतालीस रुपये मात्र) मूल्य का एक लाइसेंस सं० पी०एल०/1383350 दिनांक 2-3-1974 प्रदान किया गया है और बाद में उनके शान्तिविक उपयोगिता लाइसेंस के अनुसार निर्योमाहमिन सर्फेट के आयात के लिए लाइसेंस पर "आवृत्ति प्रचालन प्लॉकन" किया गया है। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। उक्त लाइसेंस की उन्होंने सीमा-शुल्क कार्यालय बम्बई में पंजीकृत कराया है और 40828 रुपये का उपयोग करना शेष छोड़ते हुए 40642 रुपये की सीमा तक आंशिक उपयोग किया है। अपने दावे के समर्थन में आवेदकों ने मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट, बम्बई के सामने विभिन्न प्रमाण लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

में संयुक्त हैं कि लाइसेंस सं० पी०/एल०/1383350 दिनांक 2-3-1974 को मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति ओ गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूँ कि इस की अनुसंधान प्रति आवश्यक काम को जारी की जाए।

लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रति रद्द की गई समझी जाती है।

[फि० सं० 1134/45308/ए०एम० 74/एल०/आर० ई० पी० आई० बी०ए०

1065 29-12-73 से जारी]

एन० के० जगतप, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

ORDER

Bombay, the 8th August, 1975

S.O. 772.—M/s. Abbott Laboratories (India) Private Ltd., L.B. Shastri Marg, Kurla, Bombay-400070 have been granted licence No. P/L/1383350 dated 2-3-1974 for Rs. 40,645/- (Rs. Forty thousand six hundred and forty-five only) and subsequently "Repeat Operation Endorsement" made on the licence for import of Neomycin Sulfate as per their A. U. Licence. They have applied for the duplicate copy of Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original has been lost/misplaced. They have Registered the said licence with the Customs Authority at Bombay and partly utilised to the extent of Rs. 40,642 leaving an un utilised balance of Rs. 40,828/-. In support of their claim, the applicants, have filed an affidavit duly sworn in before the Magistrate, Esplanade Court, Bombay.

2. I am satisfied that the original Customs Copy of the licence No. P/L/1383350 dated 2-3-1974 has been lost/misplaced and direct that a duplicate of Customs Purposes copy of the licence be issued to the applicant firm.

3. The Original Customs Purpose copy of the licence is treated as cancelled.

[Issued from file No. 1134/45308/AM. 74/L/REP.

IVA/1065 29-12-73 JS. 73]

N. K. JAGATAP, Dy. Chief Controller,
for Jt. Chief Controller

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1975

क्र० आ० 773.—सरकारी परिसर (अनुधिकृत कच्चे की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० बम्बई के सचिव को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के बराबर है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त कारपोरेशन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी परिसर के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा प्रयत्न उसके अस्तित्व प्रवृत्त अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा।

[फाइल सं० आ० 30014/6/75-आ०आर० (ii)]

जी० आर० भल्ला, धवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 15th December, 1975

S.O. 773.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Secretary, Hindustan Petroleum

Corporation Limited, Bombay, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, in respect of public premises under the administrative control of the said Corporation.

[File No. O-30014/6/75-OR(II)]

B. R. BHALLA, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रादेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1976

क्र० आ० 774.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1962 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आदेश देती है कि उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० आ० आ० पी०/डी०सी०/75 दिनांक 29 अक्टूबर, 1975, जिसके द्वारा कागज लुग्दी तथा सम्बन्ध उद्योगों के निर्माण प्रयत्न उत्पादन में लगे अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् पुनर्गठित की गई थी में मूल प्रविष्टियों के स्थान पर तत्काल निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी:—

23. श्री एस० बी० गिरि, संसद् सचिव,

24. श्री ए० ए० मण्डल, संसद् सचिव,

25. श्री रोशन लाल चतुर्वेदी, संसद् सचिव,

[सं० 3(38)/75-पेपर]

कौशल कुमार माथुर, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th February, 1976

S.O. 774.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1962 the Central Government hereby orders that in the Ministry of Industry and Civil Supplies, Deptt. of Industrial Development Order No. S.O. P/DC/75 dated 29th October, 1975 vide which the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture or production of Paper, Pulp and Allied Industries, was reconstituted the following entries shall be substituted in place of the original entries with immediate effect:—

23. Shri S. B. Giri, M.P.

24. Shri A. H. Mondal, M.P.

25. Shri Rohanlal Chaturvedi, M.P.

[No. 3(38)/75-Paper]

K. K. MATHUR, Director.

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1976

क्र० आ० 775.—केन्द्रीय सरकार, बहुएकक सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इस विषय में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, निदेश करती है कि उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी द्वारा प्रयोगतत्त्व सभी शक्तियाँ और प्राधिकार, नई बहुएकक सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी द्वारा पंजीकृत सोसायटियों की उपविधियों में संशोधन करने और किसी सोसायटी की उपविधियों में बहु संशोधन करने, जिसका प्रभाव उसे बहुएकक सहकारी सोसायटी में परिवर्तित करने का हो, की शक्ति के सिवाय, नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सहकारी सोसायटियों के संबंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोगतत्त्व होंगे, अर्थात्:—

I. निम्नलिखित सहकारी सोसायटियों की बाबत इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियाँ और प्राधिकार उक्त अधिकारियों द्वारा केवल विवादों के निपटारे, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन तथा पंचादों, विनिश्चयों, द्विक्तियों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित मामलों के संबंध में प्रयोक्तव्य होंगे, अर्थात्:

- (1) नेशनल कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक फीडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
- (2) आल इंडिया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फीडरेशन लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र।
- (3) नेशनल कोऑपरेटिव यूनिजन आफ इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।
- (4) नेशनल एग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फीडरेशन लिमिटेड, दिल्ली।
- (5) नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फीडरेशन लिमिटेड, दिल्ली।
- (6) नेशनल फीडरेशन आफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीस लिमिटेड, दिल्ली।
- (7) नेशनल फीडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली।
- (8) नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फीडरेशन लिमिटेड, दिल्ली।
- (9) इण्डियन फार्मस फटिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली।
- (10) आल इण्डिया फीडरेशन आफ कोऑपरेटिव स्पनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई।
- (11) आल इण्डिया इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक फीडरेशन लिमिटेड, बंगलौर।
- (12) नेशनल कोऑपरेटिव डेरी फीडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- (13) पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।
- (14) नेशनल हूबी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।

II. उपरोक्त 1 में विनिर्दिष्ट मामलों (अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से भिन्न) से संबंधित इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी द्वारा जारी किए जाएं।

सारणी

क्रम संख्या (1)	अधिकारी (2)	बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ (3)
1.	आंध्र प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो आंध्र प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
2.	आसाम सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन नियुक्त आसाम राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो आसाम राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
3.	बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 के अधीन नियुक्त, बिहार राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो बिहार राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
4.	गुजरात सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त गुजरात राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो गुजरात राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
5.	हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त हरियाणा राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो हरियाणा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
6.	हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो हिमाचल प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
7.	केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त केरल राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो केरल राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
8.	मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त मध्य प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो मध्य प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।
9.	(i) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त महाराष्ट्र राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी। (ii) मण्डल संयुक्त, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मुम्बई मण्डल, मुम्बई। (iii) हथकरघा, विद्युत करघा और सहकारी बस्त्र, निवेशक तथा पदेन अपर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य, नागपुर।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसायटियाँ जो महाराष्ट्र राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।

(1)	(2)	(3)
10. कर्नाटक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1959 की धारा 2 के अधीन नियुक्त कर्नाटक राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो कर्नाटक राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
11. उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अधीन नियुक्त उड़ीसा राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो उड़ीसा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
12. पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त पंजाब राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो पंजाब राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
13. राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन नियुक्त राजस्थान राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो राजस्थान राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
14. (i) तमिलनाडु, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, तमिलनाडु राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी। (ii) संयुक्त, रजिस्ट्रार सहकारी, सोसाइटी (गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम) तमिलनाडु, मद्रास।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो तमिलनाडु राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
15. उत्तर प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो उत्तर प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
16. (i) पश्चिमी बंगाल सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1973 की धारा 9 के अधीन नियुक्त पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी। (ii) अपर रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता (iii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल कलकत्ता।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो पश्चिम बंगाल राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
17. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में यथावत् पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त चण्डीगढ़ के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
18. दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधीन नियुक्त दिल्ली के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
19. गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में लागू महाराष्ट्र, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त गोवा, दमण और दीव के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
20. मणिपुर पर यथा विस्तारित आसाम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन नियुक्त मणिपुर के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो मणिपुर राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
21. पाँडिचेरी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन नियुक्त पाँडिचेरी के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो पाँडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
22. त्रिपुरा सहकारी, सोसाइटी अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन नियुक्त त्रिपुरा के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो त्रिपुरा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	
23. (i) निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, तमिलनाडु। (ii) संयुक्त निदेशक, उद्योग और वाणिज्य तमिलनाडु	ऐसी सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियाँ जो तमिलनाडु राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं।	

[सं० एल० 11011/2/70 एल० एण्ड एम०]

एल० जी० भाटिया, अवर सचिव

(Deptt. of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 30th January, 1976

S.O. 775.—In exercise of the powers conferred by Section 5B of the Multi-Unit Cooperative Societies Act, 1942 (6 of 1942), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Government hereby directs that all the powers and authority exercisable by the Central Registrar of Cooperative Societies under the Act, except the power of registration of a new multi-unit cooperative society, amendment of bye-laws of societies registered by the Central Registrar of Co-operative Societies appointed under sub-section (1) of Section 4 of the said Act and amendment of bye-laws of a society which has the effect of converting it into a multi-unit co-operative society, shall, in relation to the co-operative societies specified in column (3) of the Table below, be exercisable also by the officers specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, subject to the following conditions, namely :—

I. that the powers and authority so delegated shall, in respect of the following co-operative societies, be exercisable by the said officers only in relation to matters pertaining to settlement of disputes, appeals, revision and review and execution of awards, decisions, decrees and orders namely :—

- (1) National Cooperative Land Development Banks Federation Ltd., Hyderabad, Andhra Pradesh
- (2) All India State Cooperative Banks' Federation Ltd., Bombay, Maharashtra,

- (3) National Cooperative Union of India Limited, Delhi.
- (4) National Agricultural Cooperative Marketing Federation Limited, Delhi.
- (5) National Cooperative Consumers' Federation Ltd., Delhi.
- (6) National Federation of Co-operative Sugar Factories Limited, Delhi.
- (7) National Federation of Industrial Co-operatives Limited, Delhi.
- (8) National Co-operative Food Federation Limited, Delhi.
- (9) Indian Farmers' Fertiliser Cooperative Limited, Delhi.
- (10) India Fertiliser Corporation Limited, Bombay.
- (11) Andhra Industrial Co-operative Societies' Federation Limited, Bangalore.
- (12) National Co-operative Entry Order Scheme of India Ltd., New Delhi.
- (13) Petrolis Cooperative Ltd., New Delhi.
- (14) National Heavy Engineering Corporation Ltd., New Delhi.

It shall be the duty of the Registrar to comply with the provisions of the provisions specified in I above (other than appeals, revision and review) and to comply with such other provisions, as may be issued by the Central Registrar of Co-operative Societies.

TABLE

5. Sl.	Office	Multi-unit cooperative societies
(1)	(2)	(3)
1.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Andhra Pradesh appointed under Section 2 of the Andhra Pradesh Co-operative Societies Act, 1964.	All multi-unit Co-operative Societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Andhra Pradesh.
2.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Assam appointed under section 3 of the Assam Co-operative Societies Act, 1962.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Assam.
3.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Bihar appointed under section 3 of the Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, 1955.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Bihar.
4.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Gujarat appointed under section 3 of the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Gujarat.
5.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Haryana appointed under section 3 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the State of Haryana.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Haryana.
6.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Himachal Pradesh appointed under section 3 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1961.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Himachal Pradesh.
7.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Kerala appointed under section 3 of the Kerala Co-operative Societies Act, 1959.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Kerala.
8.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Madhya Pradesh appointed under section 2 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1959.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Madhya Pradesh.
9.	(a) Registrar of Co-operative Societies for the State of Maharashtra appointed under section 3 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1959. (b) Joint Registrar of Co-operative Societies, Bombay, established, Bombay. (c) Registrar of Co-operative Societies for the State of Maharashtra appointed under section 3 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1959.	All multi-unit cooperative societies, which actually are or are deemed to be registered in the State of Maharashtra.
10.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Karnataka appointed under section 2 of the Karnataka Co-operative Societies Act, 1959.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Karnataka.
11.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Orissa appointed under section 2 of the Orissa Co-operative Societies Act, 1952.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Orissa.
12.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Punjab appointed under section 3 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Punjab.
13.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Rajasthan appointed under section 3 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1955.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Rajasthan.
14.	(i) Registrar of Co-operative Societies for the State of Tamil Nadu appointed under section 3 of the Tamil Nadu Co-operative Societies Act, 1957. (ii) Joint Registrar of Co-operative Societies (for the Agricultural Area Programme), Tamil Nadu, Madras.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Tamil Nadu.
15.	Registrar of Co-operative Societies for the State of Uttar Pradesh appointed under section 3 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.	All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Uttar Pradesh.

(1)	(2)	(3)
16. (i) Registrar of Cooperative Societies for the State of West Bengal appointed under section 9 of the West Bengal Cooperative Societies Act, 1973. (ii) Additional Registrar of Cooperative Societies, West Bengal, Calcutta. (iii) Jt. Registrar of Cooperative Societies, West Bengal, Calcutta.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of West Bengal.
17. Registrar of Cooperative Societies for Chandigarh appointed under section 3 of the Punjab Cooperative Societies Act, 1961 as in force in the Union Territory of Chandigarh.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Chandigarh.
18. Registrar of Cooperative Societies for Delhi appointed under section 3 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Delhi.
19. Registrar of Cooperative Societies for Goa, Daman and Diu appointed under section 3 of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 as applied to the Union Territory of Goa, Daman and Diu.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.
20. Registrar of Cooperative Societies for Manipur appointed under section 3 of the Assam Cooperative Societies Act, 1949, as extended to Manipur.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Manipur.
21. Registrar of Cooperative Societies for Pondicherry appointed under section 3 of the Pondicherry Cooperative Societies Act, 1965.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union Territory of Pondicherry.
22. Registrar of Cooperative Societies for Tripura appointed under section 3 of the Tripura Cooperative Societies Act, 1974.		All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Tripura.
23. (i) The Director of Industries and Commerce, Tamil Nadu. (ii) The Joint Director of Industries and Commerce, Tamil Nadu.		All multi-unit Industrial cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in Tamil Nadu.

[No. L11011/2/70-L&M]

L.G. BHATIA, Under Secy.

औद्योगिक विकास विभाग

भारतीय मानक संस्थान

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1976

क्र० आ० 776.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन) चिह्न विनियम 1955 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन मानकों के व्योरे दिए गए हैं, 1 अगस्त 1974 से 31 अगस्त 1974 की अवधि में निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए गए भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक
(1)	(2)	(3)
1. IS : 748—1974 हथकरघे की सूती साड़ियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 748—1955 हथकरघे की कौरी सूती साड़ियों की विशिष्टि ।	
2. IS : 958—1973—1350 लिटर प्रति मिनट वाले आग बुझाने के छोटे इजिनों की कार्यकारी प्रपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण) ।	IS : 938—1964—1350 लिटर प्रति मिनट (प्रथम 350 गैलन वाले आग बुझाने के छोटे इजिनों की विशिष्टि (पुनरीक्षण) ।	
3. IS : 1171—1973 फेरो-मैगनीज की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) ।	IS : 1171—1964 फेरो-मैगनीज की विशिष्टि (पुनरीक्षण) ।	
4. IS : 1239 (भाग 1)—1973 मृदु हस्पात की नलियां, नलियों की बनी वस्तुओं और पिटवां, हस्पात के अन्य फिटिंग की विशिष्टि (भाग 1) मृदु हस्पात की नलियां (तीसरा पुनरीक्षण) ।	*IS : 1239 (भाग 1)—1968 मृदु हस्पात की नलियां, नलियों की बनी वस्तुओं और पिटवां हस्पात के अन्य फिटिंग की विशिष्टि भाग 1 मृदु हस्पात की नलियां (दूसरा पुनरीक्षण) ।	
5. IS : 1528 (भाग 4)—1974 उष्मासह सामग्रियों की बानगी लेने और भौतिक परीक्षणों की पद्धतियां भाग 4 सीत संदलन सामर्थ्य (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 1528—1962 उष्मासह सामग्रियों की बानगी लेने और भौतिक परीक्षणों की पद्धतियां ।	
6. IS : 1923—1973 बिजली रोधन कार्यों के लिए सूती किनारीदार टेप की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) ।	IS : 1923—1963 बिजली रोधन कार्यों के लिए सूती मृदुलेपित टेप की विशिष्टि (पुनरीक्षण) ।	
7. IS : 2013—1974 टी-खांचों के साप (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2013—1962 टी-खांचों के साप ।	
8. IS : 2023—1973 धात्विक क्रोमियम की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2023—1962 धात्विक क्रोमियम की विशिष्टि ।	
9. IS : 2084—1974 कच्चे लोहे की पदनाम संहिता ।	IS : 2084—1962 कच्चे लोहे की पदनाम की संहिता ।	
10. IS : 2093—1974 गर्मटार और बिट्यूमेन फैलाने की मशीन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2093—1972 गर्मटार और बिट्यूमेन फैलाने की मशीन ।	

*भा० मा० संस्था प्रमाणन चिह्न योजना कार्यों के लिए IS : 1239 (भाग 1)—1968 31 दिसम्बर, 1974 तक IS : 1239 (भाग 1)—1973 के साथ-साथ लागू रहेगा ।

1	2	3
11. IS : 2165 (भाग 2)—1973 रोधन समन्वयन भाग 2 100 कि०मी० और ऊपर के अधिकतम बोल्टता उपकरण के लिए (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2165—1962 रोधन समन्वय की मार्गदर्शिका ।	
12. IS : 2200—1973 श्रैतिज तकुरों वाली समंजनीय ऊँचाई की मेज वाली मिश्रित मशीनों के लिए परीक्षण चार्ट (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2200—1962 श्रैतिजनुमा और यूनियर्सस मिश्रित मशीनों के परीक्षण चार्ट ।	
13. IS : 2378—1974 तांबा और तांबा मिश्र धातुओं के पदनामों की संहिता (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2378—1963 तांबा और तांबा मिश्र धातुओं के पदनामों की संहिता ।	
14. IS : 2480—1973 ठोस नली के सामान्य कार्यों के कांच के तापमापियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2480—1964 सामान्य कार्यों के लिए कांच के तापमापियों की विशिष्टि ।	
15. IS : 2949—1974 सादे बी-डलाफ की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 2949—1964 सादे बी-डलाफ की विशिष्टि ।	
16. IS : 3014—1973 फेरोनीग्रोबियम (फेरोकोलमबियम) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 3014—1965 फेरोनीग्रोबियम (फेरोकोलमबियम) की विशिष्टि ।	
17. IS : *3319—1973 सर्जरी के पृथक्नीय ब्लेडों की (वार्ड पार्कर प्रकार के) विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 3319—1965 पृथक्नीय ब्लेड वाले सर्जरी के स्कालेपेस (वार्ड पार्कर प्रकार के) की विशिष्टि ।	
18. IS : 3523—1974 रिंग कट्टाई फ्रेमों के मेटल ट्रेवलरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) ।	IS : 3523—1970 रिंग कट्टाई फ्रेमों के मेटल ट्रेवलरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	
19. IS : 3825—1974 पटसन बुनाई के लिए जड़े नाके वाले तार हील्ड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 3825—1966 पटसन बुनाई के लिए जड़े नाके वाले तार हील्ड की विशिष्टि ।	
20. IS : 5633—1973 वेनैडियम पेटाक्साइड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	IS : 5633—1970 वेनैडियम पेटाक्साइड की विशिष्टि ।	
21. IS : 6652 (भाग 3)—1973 धातु की आकारदायी मशीनों और औजारों की पारिभाषिक शब्दावली भाग 3 धातु की आकारदायी प्रयोगिकी तथा धातु की श्रद्धों सम्बन्धी प्रक्रियाएं ।		
22. IS : 7002—1972 प्रचलित बल-पूर्णक वाली छष्टभुजी तालक द्विवरियों की विशिष्टि ।		
23. IS : 7008 (भाग 4)—1973 आई०एस०ओ० मोटरी समलम्ब्यम चूड़ियों भाग 4 छूट देने की प्रणाली ।		--
24. IS : 7023—1973 पारे वाले उष्ण वाष्प दाब लैम्पों की परीक्षण पद्धतियां ।		--
25. IS : 7028 (भाग 3)—1973 तैयार किए पैकेजों के कार्यप्रवृत्ता परीक्षण भाग 3 श्रैतिज आघात परीक्षण, नल, तल पर और लटकी स्थिति में ।		--
26. IS : 7028 (भाग 4)—1973 तैयार किए परिकल्पन पैकेजों के कार्यप्रवृत्ता परीक्षण भाग 4 ऊपर से गिरने पर आघात परीक्षण ।		--
27. IS : 7054—1973 बकेट एलिबेटर्स में कैसिंग लगाने की विशिष्टि ।		--
28. IS : 7078—1973 औजार उद्योग में उपयोग के लिए प्लास्टिक की विशिष्टि ।		
29. IS : 7093—1973 11-कि०मी० तक के कागज रोधित सीसा के खोलवाले के बर्षों के लिए आरपार वायरिंग के जोड़ बक्से और सीसे के आवरण (स्लीव) की विशिष्टि ।		--
30. IS : 7095—1973 नूप कठोरता परीक्षण मशीनों के सत्यापन की पद्धतियां ।		--
31. IS : 7098 (भाग 2)—1973 आर-पार लिफ वाले पोलिइथाइलीन रोधित पी० बी० सी० खोलवाले केबलों की विशिष्टि भाग 23.3 कि०मी० से 33 कि०मी० तक कार्यकारी बोल्टता के लिए ।		--
32. IS : 7135—1973 डाइमिथाइल सल्फेट तकमीकी की विशिष्टि ।		--
33. IS : 7142—1974 अल्पदाब द्रवित गैसों के 5 लिटर से अनधिक समाई वाले वेल्डकृत प्रत्ये कार्यन इस्पात के गैस सिलेण्डर की विशिष्टि ।		--
34. IS : 7147 (भाग 1)—1973 घरेलू भंडारण के लिए इस्पात की कोठियों की विशिष्टि भाग 1 घरेलू कोठी ।		--
35. IS : 7156—1974 उल्टे परिचालन वाले ड्रिलिंग रिंगों की सामान्य प्रपेक्षाएं ।		--
36. IS : 7157—1974 वायु चालित सुवाह्य घर्षण मशीनों की विशिष्टि ।		--
37. IS : 7164—1974 (डाट) स्टापों की विशिष्टि ।		--

*भा० मा० संस्था (प्रमाणन मुहर) योजना कार्यों के लिए IS : 3319—1973, 1 नवम्बर 1974 से लागू होगा ।

1	2	3
38. IS: 7185--1973 पोली गश्तीय के सरोई डेप से देने द्वाइत की विनिष्टि।		--
39. IS: 7186--1974 सेल्यूलोन ऐसीटेट की चिप्पियों (फॉल) की विनिष्टि।		--
40. IS: 7171--1974 फिल्टर धाने ड्रिप काउन्टर की विनिष्टि।		--
41. IS: 7172--1974 और कलकता परीक्षण मशीनों (विनाईटुम) और उनसे सहायक की विनिष्टि।		--
42. IS: 7173--1974 सिरीयार टैपी वाले टैपिंग रिश्नों की विनिष्टि।		--
43. IS: 7178--1974 टैपिंग रिश्नों के मशीनी गुणधर्म।		--
44. IS: 7183--1973 हाफकाइन कल्पर प्लारको की विनिष्टि।		--
45. IS: 7184--1973 इतिज, चिपिंग समन्वयकनी मातों को सहायक सम्बन्ध रेखाओं सम्बन्धी सिफारिशें		--
46. IS: 7193--1974 गांध के रेसो वाले कोलार धातु और विद्युत्ता तार के नगदे		--
47. IS: 7197--1974 भारी किमाइनों के लिए पूर्ण किमा वाले नगों रिश्नों (विना तेल नियंत्रण) की विनिष्टि		--
48. IS: 7209--1974 ब्रिस्फोटक बनाने के ड्रिज के गंजाधार (रिज) की सामान्य अपेक्षाएं		--
49. IS: 7210--1974 संकेत डायल वाले घूर्णनचल रिश्नों के मध्य केल की विनिष्टि		--
50. SI: 7214--1971 हाथ वाले सफेद रिश्नों में कलकता करने के नगों की विनिष्टि		--
51. IS: 7216--1974 हथकरघा के सूती प्रभावत की विनिष्टि		--
52. IS: 7222--1974 इंजीनियरों के रेसेट बरमों की विनिष्टि		--
53. IS: 7227--1974 खाश पट्टी वाली मशीने लगाने की लकड़ी की रेसों के पहियों के सिफारिशें धारा		--
54. IS: 7228--1974 पूर्णत छेर किए ओजार नगी लकड़ी की मशीनों के लिए तबुओं के सिफारिशें धारा		--
55. IS: 7229--1974 लकड़ी की मशीनों के लिए सिफारिशें कार्यकारी ऊंचाई		--
56. IS: 7232--1974 इन्हांफ कोन परीक्षण की पद्धति		--
57. IS: 7235--1974 खाश पदार्थों में टॉर्कफेसन (पिटाबिल ई) को मात्रा निकालने की पद्धति		--
58. IS: 7237--1974 सेम का गोंद, खाश तेल की विनिष्टि		--
59. IS: 7238--1974 इंग्रान्दीय गोंद, खाश की विनिष्टि		--
60. IS: 7246--1974 कंसेट संघनन में प्रयुक्त मेज कविज सम्बन्धी सिफारिशें		--
61. IS: 7256--1974 गजु जालित चकतीनुमा हल की गारी नखी की विनिष्टि		--
62. IS: 7263--1973 वायुधानों में टॉपिंग रिश्नों के प्रचालन की दिशाएं		--
63. IS: 7264--1974 वायुधानों में दाब पर तेल भरने के कलकता के माप		--
64. IS: 7268--1974 बिलकतुमा कुण्डीधार रिश्नों की विनिष्टि		--
65. IS: 7275--1974 हथकरघे की नगी बिछाने की नारिज की रिबदार मेटिंग की विनिष्टि		--
66. IS: 7279--1974 लकड़ी के कार्यों की एक तबुए वाली छेदक मशीनों के परीक्षण चार्ट		--
67. IS: 7283--1974 नसकदार छड़ों की तैयारी के लिए गर्म वेल्डत सरिसे की विनिष्टि		--
68. IS: 7284--1973 सूत की मोटी जाली की विनिष्टि		--
69. 7287--1974 लकड़ी की मशीनों से सम्बन्धित कार्यकारी मातों की सिफारिशें		--

(1)	(2)	(3)
70. IS : 7298--1974 पिढ और अमिड सूती वेबिन की विशिष्टि		
71. IS : 7317--1974 चट्टान के विकृति गुणों के लिए एकाक्षीय जंक लगाने के परीक्षण की रीतिसंहिता		---
72. IS : 7326 (भाग 2)--1974 पनबिजली केन्द्रों और प्रणालियों के पेन-स्टाक और टरबाइन के भीतरी तिल्लीनुता बाल्व भाग 2. नियंत्रण उपकरण की डिजाइन और चुनाव की मार्गदर्शिका		---
73. IS : 7332 (भाग 2)--1974 पनबिजली केन्द्रों और प्रणालियों के भीतरी गोलाकार टरबाइनों बाल्व भाग 2 नियंत्रण उपकरण की डिजाइन और चुनाव की मार्गदर्शिका		---
74. IS : 7332 (भाग 3)--1974 पनबिजली की प्रणालियों के भीतरी गोलाकार टरबाइनों के बाल्व भाग 3 गोलाकार बाल्वों के प्रवाह और रख-रखाव सम्बन्धी सिफारिशें		---
75. IS : 7333--1974 दन्त चिकित्सा में प्रयुक्त स्प्रिंग बनाने के प्लासों की विशिष्टि		---
76. IS : 7336--1974 दन्त चिकित्सा में प्रयुक्त विद्युत यंत्रों के लिए नाथ प्रकार के प्लासों की विशिष्टि		---

इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 तथा इसके शाखा कार्यालयों : प्रहसदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, हैदराबाद, कागपुर, मद्रास और पटना से प्राप्त की जा सकती हैं।

[मं० सी० एम० सी० / 13 : 2]

(Department of Industrial Development)

INDIAN STANDARD INSTITUTE

New Delhi, the 30 January, 1976

S.O. 776--In pursuance to sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established during the period 1 to 31 August, 1974 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standard Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard
(1)	(2)	(3)
1. IS : 748-1974 Specification for handloom cotton DHOTIS (first revision)	IS : 748-1955 Specification for handloom cotton dhoties, grey	
2. IS : 938-1973 Functional requirements for 1350-1/min small fire engine (second revision)	IS : 938-1964 Specification for 1350-1/min (or 350-gal/min) small fire engine (revised)	
3. IS : 1171-1973 Specification for ferromanganese (second revision)	IS : 1171-1964 Specification for ferromanganese (revised)	
4. IS : 1239 (Pt I)-1973 Specification for mild steel tubes, tubulars and other wrought steel fittings Part I mild steel tubes (third revision)	*IS : 1239 (Part I) 1968 Specification for mild steel tubes, tubulars and other wrought steel fittings Part I mild steel tubes (second revision)	
5. IS : 1528 (Pt IV)-1974 Methods of sampling and physical tests for refractory materials Part IV determination of cold crushing strength (first revision)	IS : 1528-1962 Methods of sampling and physical tests for refractory materials	
6. IS : 1923-1973 Specification for cotton selvage type for electrical insulation purposes (second revision)	IS : 1923-1963 Specification for cotton selvage tape for electrical insulation purposes (revised)	
7. IS : 2013-1974 Dimensions for T-slots (first revision)	IS : 2013-1962 Dimensions for T-slots	
8. IS : 2023-1973 Specification for metallic chromium (first revision)	IS : 2023-1962 Specification for metallic chromium	
9. IS : 2084-1974 Code for designation of pig iron (first revision)	IS : 2084-1962 Code for designation of pig iron	
10. IS : 2093-1974 Specification for distributors for hot tar and bitumen (first revision)	IS : 2093-1962 Specification for distributors for hot tar and bitumen	
11. IS : 2165 (Pt II)-1973 Insulation co-ordination Part II for highest voltages for equipment of 100 kV and above (first revision)	IS : 2165-1962 Guide for insulation co-ordination	
12. IS : 2200-1973 Test chart for milling machines with table of variable height, with horizontal spindle (first revision)	IS : 2200-1962 Test chart for horizontal and universal milling machines.	
13. IS : 2378-1974 Code for designation of copper and copper alloys (first revision)	IS : 2378-1963 Code for designation of copper and copper alloys	
14. IS : 2480-1973 Specification for solidstem general purposes glass thermometers (first revision)	IS : 2480-1964 Specification for general purpose glass thermometers.	
15. IS : 2949-1974 Specification for plain V-blocks (first revision)	IS : 2949-1964 Specification for V-blocks	

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme IS : 1239 (Part I) 1968 shall run concurrently with IS : 1239 (Part I) 1973 up to 31 December 1974

(1)	(2)	(3)
16. IS : 3014-1973 Specification for ferroniobium (ferrocolumbium) (first revision)	IS : 3014-1965 Specification for ferroniobium (ferro columbium)	
17. *IS : 3319-1973 Specification for blades, surgical, detachable (Bard Parker type) (first revision)	IS : 3319-1965 Specification for surgical scalpels with detachable blades (Bard Parker type)	
18. IS : 3523-1974 Specification for metal travellers for ring spinning frames (second revision)	IS : 3523-1970 Specification for metal travellers for ring spinning frames (first revision)	
19. IS : 3825-1974 Specification for inset mail wire healds for jute weaving (first revision)	IS : 3825-1966 Specification for inset mail wire healds for jute weaving	
20. IS : 5633-1973 Specification for vanadium pentoxide (first revision)	IS : 5633-1970 Specification for vanadium pentoxide	
21. IS : 6652 (Pt III)-1973 Glossary of terms relating to metal forming machines and tools Part III metal forming technology and operations relating to sheet metal		---
22. IS : 7002-1972 Specification for prevailing torque type steel hexagon locknuts		---
23. IS : 7008 (Pt IV)-1973 ISO Metric trapezoidal screw threads Part IV tolerancing system		---
24. IS : 7023-1973 Methods of tests for high pressure mercury vapour lamps		---
25. IS : 7028 (Pt III)-1973 Performance tests for complete, filled transport packages Part III horizontal impact test, inclined plane and pendulum		---
26. IS : 7028 (Pt IV)-1973 Performance tests for complete, filled transport packages Part IV vertical impact drop test		---
27. IS : 7054-1973 Specification for casing for bucket elevators		---
28. IS : 7078-1973 Plastics used in instrument industry		---
29. IS : 7093-1973 Specification for straight through joint boxes and lead sleeves for paper insulated lead sheathed cables up to and including 11 kV		---
30. IS : 7095 1973 Method for verification of knoop hardness testing machines		
31. IS : 7098 (Pt II)-1973 Specification for crosslinked polyethylene insulated PVC sheathed cables Part II for working voltages from 3.3 kV up to and including 33 kV		---
32. IS : 7135-1973 Specification for dimethyl sulphate, technical		---
33. IS:7142-1974 Specification for welded low carbon steel gas cylinder for low pressure liquefiable gases, not exceeding 5 litre water capacity.		---
34. IS:7147 (Pt I)—1973 Specification for steel bins for domestic storage Part I GHARELU KOTHI		---
35. IS:7156—1974 General requirements for reverse circulation drilling rigs		---
36. IS:7157-1974 Specification for portable pneumatic grinding machines		---
37. IS:1964-1973 Specification for stopper		---
38. IS:7165-1973 Specification for twines made from twisted tapes of polyethylene.		---
39. IS:7166-1974 Specification for cellulose acetate flakes		---
40. IS:7171-1974 Specification for drip counter with filter		---
41. IS:7172-1974 Specification for shore hardness testing machines (Anvil Type) and their verification		---
42. IS:7173-1974 Specification for slotted pan head tapping screws		---
43. IS:7178-1974 Mechanical properties of tapping screws		---
44. IS:7183-1973 Specification for flask, culture, Haffkine.		---
45. IS:7178-1973 Recommendations for modular co-ordination reference lines of horizontal controlling co-ordinating dimensions		---
46. IS:7193-1974 Specification for glass fibre base coal tar pitch and bitumen felts		---
47. IS:7197-1974 Specification for double action floor springs (without oil check) for heavy doors		---
48. IS:7209-1974 General requirements for blast hole drilling rigs		---
49. IS:7210-1974 Specification for rigid case with indicator dial type torque wrench		---
50. IS:7214-1974 Specification for driving squares for hand socket wrenches		---

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme, IS : 3319-1973 shall come into force with effect from 1 November, 1974.

(1)	(2)	(3)
51.	IS:7216-1974 Specification for handloom cotton ANGAV ASTRAM	
52.	IS:7222-1974 Specification for engineers' ratchet braces	—
53.	IS:7227-1974 Recommended diameters of wheels for wood-working table band-sawing machines	—
54.	IS:7228-1974 Recommended spindle diameters for woodworking machines with roating bored tools	—
55.	IS:7229-1974 Recommended working level heights for wood-working machines	—
56.	IS:7232-1974 Method for Imhoff cone test	—
57.	IS:7235-1974 Method for estimation of tocopherols (vitamin E) in foodstuffs	—
58.	IS:7237-1974 Specification for carob bean gum, food grade	—
59.	IS:7238-1974 Specification for tragacanth gum, food grade	—
60.	IS:7246-1974 Recommendations for use of table vibrators for consolidating concrete	—
61.	IS:7256-1974 Specification for plain spool for animal-driven disc harrows	—
62.	IS:7263-1973 Directions of operation of toggle switches on aircraft	—
63.	IS:7264-1974 Dimensions for aircraft pressure refuelling connection.	—
64.	IS:7268-1974 Specification for clicktype torque wrenches	—
65.	IS:7275-1974 Specification for handloom ribbed coir matting/ mats	—
66.	IS:7279-1974 Test chart for woodworking single spindle boring machines	—
67.	IS:7283-1974 Specification for hot-rolled bars for production of bright bars	—
68.	IS:7284-1973 Specification for coarse cotton webbings	—
69.	IS:7287-1974 Recommended working dimensions of woodworking machines	—
70.	IS:7298-1973 Specification for cotton webbing, proofed and unproofed	—
71.	IS:7313-1974 Code of practice for uniaxial jacking test for deformation modulus of rock	—
72.	IS:7326 (Pt II)—1974 Penstock and turbine inlet butterfly valves for hydro-power stations and systems Part II guidelines for design and selection of control equipment	—
73.	IS:7332 (Pt II)—1974 Turbine inlet spherical valves for hydro-power stations and systems Part II guidelines for design and selection of control equipment	—
74.	IS:7332 (Pt III) —1974 Turbine inlet spherical valves for hydro-power stations and systems Part III recommendations for operation and maintenance of spherical valves	—
75.	IS:7333-1974 Specification for pliers, spring forming, dental	—
76.	IS:7336-1974 Specification for pliers, tie back, Nance type, dental	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110001 and also its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Kanpur, Madras and Patna.

[No. CMD. /13:2]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

क्रा०प्रा० 777.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन निष्ठ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-2864, 4074, 4114, 4115, 4350, 4351, 4352 और 4418 जिनके बारे में सीधे अनुसूची में दिए हैं, फर्म द्वारा अपना नाम बदल लेने के कारण 16 अक्टूबर, 1975 से रद्द कर दिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-2864 1972-01-05	मैसर्स अमेरिकन स्प्रिंग एण्ड प्रेसिंग वर्क्स प्रा० लि०, मलाइ, बम्बई-64 एनबी	एक नली के पोंचवान वाले पम्प	IS: 1971-1965 एक नलीके पोंचवान वाले पम्प की विशिष्टि (पुनरीक्षित)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सी एम/एल-4074 1974-11-28	मेसर्स अमेरिकन स्ट्रिंग एण्ड प्रेसिंग वर्क्स प्रा० लि० मलाड, बम्बई-64 एनवी	हाथ से घुमाने वाला धूलन यंत्र	IS : 2477—1970 कंधे पर रखकर हाथ से घुमाने वाले धूलन यंत्र की विशिष्टि	
3. सी एम/एल-4114 1974-12-31	„	धान निराने की धूमनी मशीन	IS : 1976—1969 धान निराने की धूमनी मशीन की विशिष्टि	
4. सी एम/एल-4115 1974-12-31	„	खेतों के बिलों में धूलन करने के यंत्र	IS : 3634—1966 खेत के बिलों में धूलन करने के यंत्रों की विशिष्टि	
5. सी एम/एल-4350 1975-04-30	„	घागे पीछे होने वाला स्प्रेयर	IS : 3062—1974 घागे पीछे होने वाले स्प्रेयर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	
6. सी एम/एल-4351 1975-04-30	„	भ्रदाबधारी संपीड़न प्रकार के पृष्ठवाह्य हस्तचालित स्प्रेयर	IS : 1970 (भाग 1)—1974 संपीड़न प्रकार के पृष्ठवाह्य हस्तचालित स्प्रेयर की विशिष्टि भाग 1 भ्रदाबधारी	
7. सी एम/एल-4352 1975-04-30	„	पाँव स्प्रेयर	IS : 3652—1974 पाँव स्प्रेयर की विशिष्टि	
8. सी एम/एल-4418 1975-06-05	„	हस्तचालित एटोमाइजर टाइप स्प्रेयर	IS : 3897—1975 हस्तचालित एटो- माइजर टाइप स्प्रेयर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	

[सं० सी० एम० डी०/55 : 2864]

ए० बी० राय, उप-महानिदेशक

New Delhi, 27th January, 1976

S.O. 777.—In pursuance of Sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-2864, 4074, 4114, 4115, 4350, 4351, 4352 and 4418 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 16 October 1975 due to change in the name of the firm.

Sl. No.	Licence No and Date	Name & Address of the License	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. CM/L-2864 1972-01-05	.	M/s. American Sp- ring & Pressing Works, Pvt. Ltd. Malad, Bombay-64 NB.	Single-barrel strirrup-pump	IS:1971-1965 Specification for Single-barrel stirrup pum (revised).
2. CM/L-4074 1974-11-28	.	Do.	Hand rotary duster	IS: 2477-1970 Specification for hand rotary duster shoulder, mounted type.
3. CM/L-4114 1974-12-31	.	Do.	Rotary paddy weeders	IS:1976-1969 Specification for rotary paddy weeders.
4. CM/L-4115 1974-12-31	.	Do.	Dust applicator for burrows	IS:3634-1966 Specification for dust applicator for burrows.
5. CM/L-4350 1975-04-30	.	-Do-	Rocker sprayer	IS: 3062-1974 Specification for rocker sprayer (First Revision)
6. CM/L-4351 1975-04-30	.	-Do-	Hand- operated compression knapsack sprayer part I Non- pressure retaining type	IS:1970 (Part I)-1974 Specifi- cation for hand-operated compression Knapsack spra- yer Part I Non-Pressure retain- ing type
7. CM/L-4352 1975-04-30	.	-Do-	Foot sprayer	IS:3652-1974 Specification for foot sprayer
8. CM/L-4418 1975-06-05	.	-Do-	Sprayer atomizer type, hand- operated	IS:3897-1975 Specification for sprayer atomizer type hand operated (First Revision)

[No. CMD/55:2864]

A. B. RAO, Dy. Dir. Gen.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० प्रा० 778.—केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला नियंत्रक, 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर के क्षेत्रों के लिए, जिन पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इण्डिया लिमिटेड की समनुषंगी) के उद्देश्यों का विस्तार है, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है।

[का० सं० 19(5)/75 सी ई एल]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 778.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby appoints the Coal Controller, 1-Council House Street, Calcutta, to be the competent authority for the purposes of sub-section (2) of section 8 of the said Act for the areas within the territories to which the objects of the Western Coalfields Limited, (a subsidiary of the Coal India Limited) extend.

[F. No. 19(5)/75-CEL]

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976

का० प्रा० 779.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०प्रा० 1552 तारीख 6 मई, 1975 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 2930.00 एकड़ (लगभग) या (1185.71) हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले के पूर्वांश की अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राय है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 2390.00 एकड़ (लगभग) अथवा 967.18 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि अर्जित करने के अपने आशय की सूचना देती है,

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर सिधी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), वरभंगा हाउस, रांची, बिहार के कार्यालय में किया जा सकेगा।

3. कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल स्ट्रीट, कलकत्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अनुसूची

जयस्त बाण्ड विस्तारण

उपखण्ड—1
(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)
(मध्य प्रदेश)

डाइंग सं० राजस्व/33/75

तारीख 8-8-75

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शात है)

सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील सं०	जिला क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1.	मुर्झानी	सिंगरौली	205	सीधी	भाग
2.	सर्वाबाहु राजा टोला	"	224	"	"
3.	सर्वाबाहु लाल टोला	"	223	"	"
4.	गरवा	"	52	"	"
5.	जैतपुर	"	92	"	"
6.	चन्देली	"	66	"	"

कुल क्षेत्र: 3310.00 एकड़ (लगभग)

अथवा 934.81 हेक्टेयर (लगभग)

मुर्झानी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 2 (भाग) 3 (भाग), 4, 12 (भाग), 15 (भाग), 16 (भाग), 17 से 24, 25 तक (भाग) 26 (भाग), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (भाग), 35, 36 (भाग), 37 (भाग), 38 (भाग), तथा 39 से 58 तक।

सर्वाबाहु-राजाटोला ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 1 (भाग), 2 (भाग), 3 (भाग), 4 भाग, 5 (भाग), 6 से 43 तक, 43/1, 43/2, 44 से 58 तक, 59 (भाग), 60 से 99 तक, 100 (भाग), 104 (भाग), 105 (भाग), 106, 107 (भाग), 108 (भाग), 109 (भाग), तथा 163 से 187 तक।

सर्वाबाहु लाल टोला ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 1 से 16 तक, 17/1-17/3, 17/2 तक, 18 से 53 तक, 54 (भाग), 55-56 (भाग), 57 (भाग), 58 (भाग), 60 (भाग), 61, 62, 63 (भाग), 64 (भाग), 73 (भाग), 76 (भाग), 77, 78, 79 (भाग), 80 (भाग), 81, 82 (भाग), 83 (भाग), 88 (भाग), 90 (भाग), 210, 211, 212 तथा 213।

गरवा ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5 से 62, 63 (भाग), 64 (भाग), 65, 66 (भाग), 66/1 (भाग), 67 (भाग), 6/69 तक तथा 72 से 95 तक।

जैतपुर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 1, 2, 3 (भाग), 4 5, 6, 7, 8 (भाग), 10 (भाग), 11 (भाग), 43 (भाग), 47 (भाग), 881, 882 (भाग), 883 (भाग), और 884 (भाग)।

चन्देली ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 1 (भाग), 2 (भाग), 3 (भाग), 4 (भाग), 1273, 1274, 1275 तथा 1276।

सीमा वर्णन :

- ए०बी० लाइन, मुर्झानी ग्राम के प्लाट संख्या 2, 3, 36, 37 तथा 38 से होकर जाती है।
- बी०सी० लाइन, मुर्झानी तथा बिनीली ग्रामों की सामान्य सीमा के भाग के तथा मुर्झानी और गरवा की सामान्य सीमा के भाग के साथ होकर जाती है।
- सी०डी० लाइन, गरदा ग्राम के प्लाट संख्या 5, 4/1, 4/2, 3 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, प्लाट संख्या 63, 64, 66, 66/1 से होकर तथा गरवा ग्राम के प्लाट संख्या 96 की अंशतः उत्तरी और पूर्णतः पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है।
- डी०ई० लाइन, गरवा ग्राम के प्लाट संख्या 66/1, 66 तथा 67 से होकर जैतपुर ग्राम के प्लाट संख्या 47, 3, 43, 11, 883, 884, 882, 10 फिर 882 तथा 8 से होकर तथा सर्सावाह राजाटोला ग्राम के प्लाट संख्या 59, 109, 108, 107, 105, 104, 100 से होकर, सर्सावाह लालटोला ग्राम के प्लाट संख्या 83, 82, 98, 80, 79, 90, 75, 76, 64, 63, 61, 60, 54, 58, 56, 57 से होकर तथा चन्देली ग्राम के प्लाट संख्या 4, 2, 3 तथा 1 से होकर जाती है।
- ई०एफ० लाइन, नदी की मध्यवर्ती लाइन के भाग के साथ-साथ जो मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सामान्य सीमा का भाग है, जाती है।
- एफ०जी० लाइन, नदी की मध्यवर्ती लाइन के साथ-साथ जाती है (जो सर्सावाह राजाटोला तथा दुधी छ्वा ग्रामों की सामान्य सीमा का भाग है।
- जी० एच० लाइन, सर्सावाह राजाटोला ग्राम के प्लाट संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 से, मुर्झानी ग्राम के प्लाट संख्या 15, 16, 12, 25, 26 और 32 से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन जयन्त खण्ड के लिए अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है]।
- एच० ए० लाइन, मुर्झानी नाले की उत्तरी सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो मुर्झानी ग्राम के प्लाट संख्या 32 तथा 31 की सामान्य सीमा का, प्लाट संख्या 33 और 31, 34 और 35, 5 और 4 की सामान्य सीमा का तथा प्लाट संख्या 1 और 2 की सामान्य सीमा का भाग है और प्रारम्भिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

उपखण्ड - II

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
	निगाई	सिंगरीली	288	सीधी		भाग
कुल क्षेत्र : 80.00 एकड़ (लगभग)						
अथवा 32.37 हेक्टेयर (लगभग)						

निगाई ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :—
92 (भाग), 94 (भाग), 95 (भाग), 111 (भाग), 112 (भाग), 114 (भाग), 115 (भाग), 95/167 (भाग) और 95/168 (भाग)।

सीमा वर्णन :

- आई०जे०के०एल० लाइन, निगाई ग्राम के प्लाट संख्या 111, 112, 115 तथा 114 से होकर जाती है [जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17(1) के अधीन, का०आ० सं० 3746 तारीख 3-12-62 के अनुसार 373.10 एकड़ के लिए अधिसूचित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है तथा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन सतह के अर्जन के लिए राज्य सरकार को लागू उसी क्षेत्र के लिए सामान्य सीमा का भी भाग है]।
- एल० एम० लाइन, निगाई ग्राम के प्लाट संख्या 114 से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है]।
- एम० एन० लाइन, निगाई ग्राम के प्लाट संख्या 114, 115, 111, 92, 111, 94, 95, 167 तथा 95 से होकर जाती है।
- एन० ओ० लाइन, निगाई ग्राम के प्लाट संख्या 95, 95/167, 95/168 तथा 111 से होकर जाती है (जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन सतह अर्जन के लिए लागू क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है)।
- ओ० आई० लाइन, निगाई ग्राम के प्लाट संख्या 111 से होकर जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है और प्रारम्भिक बिन्दु (आई०) पर मिलती है]
[सं० 19(15)/75-सैल]
एस० आर० ए० रिजर्वी, उपसचिव

New Delhi, the 4th February, 1976

S.O. 779.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1552 dated the 6th May, 1975 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 2930.00 acres (approximately) or 1185.71 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification.

And Whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in part of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 2390.00 acres (approximately) or 967.18 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto.

2. The plans of the areas covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector Sidhi (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, Bihar.

3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

JAYANT BLOCK (EXTENSION)

Sub-Block-I
(Singrauli Coalfield)
Madhya Pradesh

DRG. No. Rev/33/75

Dated 8-8-75

(Showing lands to be acquired)

All Rights

Serial Number	Village	Tahsil	Tahsil Number	District	Area	Remarks
1. Murhbani		Singrauli	205	Sidhi		Part.
2. Sarsabah Raja Tola		"	224	"		"
3. Sarsabah Lal Tola		"	223	"		"
4. Garda		"	52	"		"
5. Jaitpur		"	92	"		"
6. Chandeli		"	66	"		"
Total area.—2310.00 acres (approximately) or 934.81 hectares (approximately)						

Plot numbers to be acquired in village Murhbani.—2 (Part), 3 (part), 4, 12 (part), 15 (part), 16 (part), 17 to 24, 25 (part), 26 (part), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (Part), 35, 36 (Part), 37 (part), 38 (part) and 39 to 58.

Plot numbers to be acquired in village Sarsabah Raja Tola.—1 (part), 2 (part), 3 (part), 4 (part), 5 (part), 6 to 43, 43/1, 43/2, 44 to 58, 59 (part) 60 to 99, 100 (part), 104 (part), 105 (part), 106, 107 (part), 108 (part), 109 (part), and 163 to 187.

Plot numbers to be acquired in village Sarsabah Lal Tola.—1 to 16, 17/1, 17/3, 17/2, 18 to 53, 54 (part), 55, 56 (part), 57 (part), 58 (part), 59 (part), 60 (part), 61 (part), 62, 63 (part), 64 (part), 75 (part), 76 (part), 77, 78, 79 (part), 80 (part), 81, 82 (part), 83 (part), 88 (part), 90 (part), 210, 211, 212 and 213.

Plot numbers to be acquired in village Garda.—3, 4/1, 4/2, 4/3, 5 to 62, 63 (part), 64 (part), 65, 66 (part), 66/1 (part), 67 (part), 6/69 and 72 to 95.

Plot numbers to be acquired in village Jaitpur.—1, 2, 3 (part), 4, 5, 6, 7, 8 (part), 10 (part), 11 (part), 43 (part), 47 (part), 881, 882 (p), 883 (part), and 884 (part).

Plot numbers to be acquired in village Chandeli.—1 (part), 2 (part), 3 (part), 4 (part), 1273, 1274, 1275 and 1276.

BOUNDARY DESCRIPTION

A-B line passes through plot numbers 2, 3, 36, 37 and 38 of village Murhbani.

B-C Line passes along the part common boundary of villages Murhbani & Binauli, and part common boundary of Murhbani & Garda.

C-D line passes along the western boundary of plot nos. 5, 4/1 4/2, 3, through plot no. 63, 64, 66, 66/1 and along part northern and full eastern boundary of Plot no. 96 of village Garda.

D-E line passes through plot nos. 66/1, 66 and 67 of village Garda, through plot numbers 47, 3, 43, 11883, 884, 882, 10 again 882 and 8 of village Jaitpur and through plot numbers 59, 109, 108, 107, 105, 104, 100 of village Sarsabah Raja Tola, through plot nos. 83, 82, 88, 80, 79, 90, 75, 76, 64, 63, 61, 60, 54, 58, 56, 57, of village Sarsabah Lal Tola and through plot nos. 4, 2, 3 and 1 of village Chandeli.

E-F line passes along the part Central line of the river which forms part common boundary of District Sidhi of Madhya Pradesh and Mirzapur of Uttar Pradesh.

F-G line passes along the part central line of the River (which forms part Common boundary of villages Sarsabah Raja Tola & Dudhi Chuwa).

G-H line passes through plot numbers 1, 2, 3, 4 and 5 of village Sarsabah Raja Tola through plot numbers 15, 16, 12, 25, 26 and 32 of village Murhbani which forms common boundary or the area acquired under section 9 (1) of the Coal Act for Jayant Block.

H-A line passes along the part northern boundary of Murhbani Nala which forms part common boundary of plot Nos. 32 and 31, common boundary of plot nos. 33 and 31, 34 and 35, 5 and 4 and part common boundary of plot nos. 1 and 2 of village Murhbani and meets at Starting points 'A'.

Sub-Block-II

All Rights

Serial Number	Village	Tahsil	Tahsil Number	District	Area	Remarks
1. Nigai		Singrauli	288	Sidhi		Part
Total area.— 80.00 acres (approximately) or 32.37 hectares (approximately)						

Plot numbers to be acquired in village Nigai.—92(part), 94(part), 95 (part), 111 (part), 112 (part), 114 (part), 115 (part), 95/167 (part) and 95/168 (part).

BOUNDARY DESCRIPTION

I-J-K-L lines pass through plot numbers 111, 112, 115 and 114 of village Nigai (which forms part common boundary with the area notified under section 17 (1) of Mines & Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 for 373.10 acres vide S.O. No. 3746 date 3-12-62 and also forms part common boundary for the same area applied to the State Govt. for surface acquisition under L.A. Act).

L-M line passes through plot no. 114 of village Nigai (which forms part common boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Act).

M-N line passes through plot nos. 114, 115, 111, 92, 111, 94, 95/167 and 95 of village Nigai.

N-O line passes through plot numbers 95, 95/167, 95/168 and 111 of village Nigai (which forms part common boundary of the area applied for Surface acquisition under L.A. Act).

O-I line passes through plot number 111 of village Nagai (which forms common boundary of the area acquired under section 9(1) of the Coal Act and meets at starting point 'I'.

[No. 19(15/75-CEL)]

S. R. A. RIZVI, Dy. Secy

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० घा० 780.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) नियमावली 1971 के नियम 1 के उप-नियम (3) के खण्ड (1) तथा इस संबंध में सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त नियमावली को 1 फरवरी, 1976 से मेरठ के निम्नलिखित क्षेत्रों तथा इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू करती है, नामतः :—

कांकर खेरा औषधालय (सं० 4)

इस औषधालय का क्षेत्र कांकर खेरा नगरपालिका की सीमाओं तक सीमित होगा, जो इस प्रकार है :—

पूर्व में रेलवे ग्राउण्ड की दीवार, नाला तथा रेलवे लाइन, पश्चिम में पी० सी० एक० वर्कशॉप के पीछे का रास्ता जो उत्तर से दक्षिण तक भाजू नाला तक जाता है, उत्तर में सरधाना रोड, दक्षिण में भाजू नाला।

[संख्या एक० 3-26/75-के० सं० स्वा० यो०]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 780.—In pursuance of clause (i) of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Meerut) Rules, 1971 and all other powers here-unto enabling, the Central Government hereby extends the said rules with effect from the 1st February, 1976 to the following areas in Meerut and areas contiguous thereto, namely :—

Kankar Khara Dispensary (No. 4)

The area of this Dispensary shall be confined to the limits of Town Area Kankar Khara, which is as under:

In the East, wall of Railway Ground, Nalla and Railway line; in the West the path behind the P.C.F. workshop, which runs North to South up to Abu-Nalla; in the North Sardhana Road; in the South Abu Nalla.

[No. F. 3-26/75-CGHS]

का० घा० 781.—संविधान की धारा 148 के खण्ड (5) तथा धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्

राष्ट्रपति इस के द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) नियमावली, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) संशोधन नियमावली, 1976 कहें जाएंगे।

(2) यह नियम 1 फरवरी, 1976 से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मेरठ) नियमावली 1971 में नियम 1 उप-नियम (3) में खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(1) मेरठ में ऐसे क्षेत्र तथा इससे संबद्ध ऐसे क्षेत्र जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे”।

[संख्या एक० 3-26/75-के० सं० स्वा० यो०]

बी० रामाचन्द्रन, अवर सचिव

S.O. 781.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of the article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules to amend the Central Government Health Scheme (Meerut) Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Government Health Scheme (Meerut) amendment rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st February, 1976.

2. In the Central Government Health Scheme (Meerut) Rules 1971 in rule 1, in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

“(i) such areas in Meerut, and such areas contiguous thereto, as the Central Government may, from time to time, by order in the Official Gazette, specify”.

[No. F. 3-26/75-CGHS]

V. RAMACHANDRAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1976

का० घा० 782.—यत् वन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में पटना विध्वं-विशालय ने पटना वन्त कालेज, ग्राममकुआ, पटना-7 के वन्त माल्य-चिकित्सा के प्रोफेसर डा० आर० पी० सिंह एम० डी० एस०, को 20 नवम्बर, 1975 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य चुन लिया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 अक्टूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-एम-2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 11 के सम्मुख मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, नामतः :-

"डा० आर० पी० सिंह,

एम० डी० एम०

दन्त शल्य चिकित्सा के प्रोफेसर,

दन्त कालेज और अस्पताल,

आगमकुआ, पटना-7"

[पं० सं० बी० 12013/1/75-एम० पी० टी०]

New Delhi, the 7th February, 1976

S.O. 782.—Whereas the Patna University has, in pursuance of the provisions of clause (d) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), elected Dr. R. P. Singh, MDS., Professor of Dental Surgery, Patna Dental College, Agamkuan, Patna-7, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 20th November, 1975;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 3-2/62-MII dated the 17th October, 1962, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (d) of section 3", against serial No. 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. R. P. Singh, MDS, Professor of Dental Surgery, Dental College and Hospital, Agamkuan, Patna-7."

[V. 12013/1/75-MPT]

का० आ० 783.—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में पंजाबी विश्वविद्यालय ने पटियाला स्थित सरकारी मेडिकल कालेज में दन्त चिकित्सा विंग के प्रोफेसर और अध्यक्ष डा० ईशर सिंह, एम० डी० एस० को 10 मार्च से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य चुन लिया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 अक्टूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-एम-2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 6 के सम्मुख मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, नामतः—

"डा० ईशर सिंह, एम० डी० एस०, प्रोफेसर और अध्यक्ष, दन्त चिकित्सा विंग, सरकारी मेडिकल कालेज, पटियाला।"

[पं० सं० बी० 12013/1/76/एम० पी० टी०]

S.O. 783.—Whereas the Punjab University has, in pursuance of clause (d) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), elected Dr. Ishar Singh, MDS, Professor and Head, Dental Wing, Government Medical College, Patiala, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 10th March, 1974;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 3-2/62-MII, dated the 17th October, 1962, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (d) of the section 3", against serial No. 6, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Dr. Ishar Singh, MDS, Professor and Head, Dental Wing, Government Medical College, Patiala."

[V. 12013/1/76-MPT]

का० आ० 784.—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (क) के अनुसरण में गुजरात सरकार ने डा० जे० सी० पारिख के स्थान पर, जिनकी सदस्यता की अवधि 30-9-75 को समाप्त हो गई थी, डा० एम० एम० गुगले, बी० डी० एस०, एफ० डी० एस० आर० सी० एस० (एडिन) को 30-12-1975 से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य चुन लिया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 अक्टूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-एम०-2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 12 के सम्मुख मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, नामतः :-

"डा० एम० एम० गुगले,

बी० डी० एस०, एफ० डी० एस०, आर० सी० एस० (एडिन)।

10, सहयोग, दिनबाई टावर के सामने,

लाल दरवाजा, अहमदाबाद-1"

[सं० बी० 12013/1/76-एम० पी० टी०]

S.O. 784.—Whereas the Government of Gujarat has, in pursuance of clause (a) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), elected Dr. M. M. Gugale, BDS, FDS RCS (Edin.), to be a member of the Dental Council of India with effect from the 30-12-1975 vice Dr. J. C. Parikh whose term of membership expired on 30-9-1975.

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 3-2/62-MII, dated the 17th October, 1962, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (a) of section 3", against serial No. 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. M. M. Gugale, BDS, FDS, RCS (Edin.), 10, Sahyog, Opp: Dinbai Tower, Lal Darwaja, Ahmedabad-1."

[V. 12013/1/76-MPT]

का० आ० 785.—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसरण में नीचे लिखे व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य चुन लिया गया है:

सदस्यों का नाम और पता	जिस अवधि के लिए चुना गया
1	2
डा० बी० सुब्रमनियन,	6-1-76 से 5-1-81 तक
बी० एस० सी०, बी० डी० एम०, एम० डी० एस० (एन जेड),	
डीन, गर्भमैट दन्त कालेज और अस्पताल,	
नागपुर-3, महाराष्ट्र।	

Name and Address of the member	Period for which elected
1	2
Dr. V. Subramanian, B.Sc., BDS, MDS(Nz), Dean, Government Dental College and Hospital, Nagpur-3 (Maharashtra).	From 6-1-76 to 5-1-81.
Dr. K. Ramachandran,	From 6-1-76 to 5-1-81

'[F.No. V. 12013/1/76-MPT]
V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

बीज के प्रकार	बीज की किस्म	क्षेत्र जिसके लिए अधिसूचित किया गया है
(1)	(2)	(3)
1. गोहं	मालाजिका मर्जून (एच-बी- 2009)	महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र

1	2	3	1	2	3
	(जनक (एच-डी-1982)	उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्र		पी० एच० बी०-10	देश के सभी बाजरा उगाने वाले क्षेत्र
	जी० ए० यू० डब्ल्यू-10 (जे-24)	गुजरात		पी० एच० बी०-14	देश के सभी बाजरा उगाने वाले क्षेत्र
	संकर-65 (एच-डी-1467)	मध्य प्रदेश	5. मक्का	गंगा-5	उड़ीसा
	नवदा-4	मध्य प्रदेश		विजय कंपोजिट	उड़ीसा
	सोनासिका	उड़ीसा		बकान-101	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश
	मुक्ता	मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश (दुन्देलखण्ड संभाग) और राजस्थान (कोटा संभाग)	6. ज्वार	जै० एस०-20	हरियाणा
2. सोयाबीन	अंकुर	दिल्ली, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र।		सी० एस० बी०-3 (370)	गुजरात
				सी० एस० बी०-2 (302)	गुजरात 4
3. धान	बासमती-370	हरियाणा		सी० एस० एच०-1	गुजरात
	पलमन-579	हरियाणा		सी० एस० एच०-5	गुजरात, तमिलनाडु
	जी० यू० ए० आर-1	गुजरात		मगुबी ओला (5-4-1)	कर्नाटक
	जी० यू० ए० आर०-10	गुजरात		संकर आर० एस० एच०-1	कर्नाटक
	जी० यू० ए० आर०-100	गुजरात		विधि 60-1	मध्य प्रदेश
	जया	गुजरात		कोइल पट्टी टाल	तमिलनाडु
	महसूरी	गुजरात		सी० एस० बी०-4 (सी० एस०-3541)	तमिलनाडु
	रत्ना	गुजरात, उड़ीसा		हरियाणा चरी]	देश के सभी ज्वार उगाने वाले क्षेत्र
	सोना	गुजरात, कर्नाटक		एस० एल०-44	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
	सकरी-17	मध्य प्रदेश		सी० एस० एच०-5	कर्नाटक
	लालू-14	मध्य प्रदेश	7. जौ	बी० जी०-25	हरियाणा, सिंचित भवस्थानों के लिए
	बाला	उड़ीसा		बी० जी०-105	हरियाणा, वेर से बोई गई सिंचित भवस्थानों के लिए
	जगन्नाथ	उड़ीसा		सी-138	हरियाणा, वर्षा सिंचित भवस्थानों के लिए
	हेमा	उड़ीसा		8. मबादे (कंगनी)	कर्नाटक
	करुणा	तमिलनाडु		ए० के० पी०-2	उड़ीसा
	कांची	तमिलनाडु	9. रागी	विष्णु सिंह	उड़ीसा
	ए० बी० टी०-30	तमिलनाडु		पी० आर०-202	तमिलनाडु
	ए० बी० टी०-31	तमिलनाडु		सारथा	तमिलनाडु
	तिरुवेणी	तमिलनाडु		सी धो-101	तमिलनाडु
	अन्नपूर्णा	तमिलनाडु	10. चना	सी-235	हरियाणा
	आई० आर०-20	तमिलनाडु		सी-214	हरियाणा
	बनी	उड़ीसा के नाथ-मालमिज इन्डे-मिक क्षेत्र, कर्नाटक के भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान		जी-130	हरियाणा
				एल-144	हरियाणा
	बूसा-2-21	पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा और सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी भारत		टी-87	मध्य प्रदेश
	कन्नगी	तमिलनाडु	11. मूंग	पूसा बैसाखी	हरियाणा
4. बाजरा	एच० बी०-3	हरियाणा		बरथा	हरियाणा
	एन० एच० बी०-5	हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश		जवाहर-45	हरियाणा, कर्नाटक
	टी-55	हरियाणा		कोपरगौन	मध्य प्रदेश

1	2	3	1	2	3
12. उड़द	टी-9 खरगोन-3	हरियाणा कर्नाटक	29. तम्बाकू	सी-304	हरियाणा
13. धरहर	प्रभात य० पी० ए० एस०- 120	हरियाणा हरियाणा	30. भालू	कुफरी बंभ्रमुखी कुफरी सिवूरी	हरियाणा हरियाणा
14. लोबिया	हरा लोबिया (एफ० एच० सी०- 42-1) एफ० एस०-88	हरियाणा हरियाणा	31. टमाटर	एच० एस०-101 एच० एस०-102	हरियाणा हरियाणा
15. सूबान खास	मीठी सूबान (59-3)	हरियाणा	32. फूलगोभी	पूसा कल्की हिसार-1	हरियाणा, कर्नाटक हरियाणा
16. गुम्हार	एफ० एस०-277	हरियाणा	33. बैंगन	पूसा पर्पल लोंग एच-4 पूसा पर्पल राजरुड	हरियाणा, कर्नाटक हरियाणा कर्नाटक
17. जई	एफ० एच० एस०-1/29 हरियाणा—जबी- 114	हरियाणा हरियाणा	34. प्याज	हिसार-2	हरियाणा
18. लूसने	सिरसा टाइप-9	हरियाणा	35. फ्रांसबीन	कन्टेंडर	कर्नाटक
19. बरसीम	मैसकबी	हरियाणा	36. बन्व गोभी	गोल्डम एकड़	कर्नाटक
20. सेजी	एफ० एच० एस०-1	हरियाणा	37. मिण्डी	पूसा सावनी	कर्नाटक
21. सैधा	टी-8	हरियाणा	38. पटसन	जे० भार० सी०-212	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल (कूच बिहार, जलपैगुड़ी, और सिलीगुड़ी, उपखण्ड, पश्चिमी बिनांजपुर, मालवा, मुशिवा- बाव के पूर्वी पार्श्व, 24- परगना और नादिया)।
22. तोरिया	इम्पूव्ड सल्फेशन-1 संगम	हरियाणा हरियाणा		जे० भार० सी०-321	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल (कूच बिहार, जलपैगुड़ी, पश्चिम बिनांजपुर और सिलीगुड़ी उपखण्ड, मालवा, नादिया के पूर्वी भाग मुशिवाबाव और 24-परगना)।
23. राया	भार० एल०-18 प्रकाश बस्या (टी-59)	हरियाणा हरियाणा पश्चिमी बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश		जे० भार० सी०-7447	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल (कूच बिहार, जलपैगुड़ी और सिलीगुड़ी उपखण्ड, मुशिवा- बाव का पूर्वी भाग, नादिया और 24-परगना)।
24. धूरी सरसों	बी० एस० एच०-1	हरियाणा		जे० भार० एच०-632	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल (उच्च भूमि और मध्य भूमि के लिए जहाँ पानी ठहरता है)।
25. तारामीरा	टी-27	हरियाणा		जे० भार० एच०- 878	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल (हुगली, 24-परगना, नादिया, मुशिवाबाव और कुलना उपखण्डों, बिनांजपुर और बोरभूम जिले के पूर्वी भाग के लिए)।
26. मूंगफली	पी० बी० सं० 1 फैजपुर 1-5 ए० के० 12-24 ज्योति टी० एम० बी०-2 टी० एम० बी०-10 पोलापी-1	हरियाणा हरियाणा मध्य प्रदेश, उड़ीसा मध्य प्रदेश तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु		जे० भार० एच०- 7835	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल हुगली, हावड़ा, बोरभूम, 24-परगना, नादिया, मुशिवा- बाव, पश्चिमी बिनांजपुर और कुलना उपखण्डों के लिए)।
27. धरणी	भरणा जी० सी० एस०-3 (जे० एच० बी०-67) जी० ए० यू० सी०-1 (बी० एच० बी०-44)	हरियाणा गुजरात गुजरात			
28. कपास	320-एफ एच-14 जी-27 नर्मदा-1 एम० सी० यू०-5 एम० सी० यू०-8 बाराकमी सी० बी० एस०-156	हरियाणा हरियाणा हरियाणा मध्य प्रदेश तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु			

[सं० 7-6/75-एस० बी०]

टी० बालरामन, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 2nd Feb., 1976

S.O. 736.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seeds Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the kinds of seeds specified in the column (i), in respect of the varieties thereof specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be notified varieties for the purposes of the said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Kinds of seed	Variety of seed	Area for which notified
(1)	(2)	(3)
1. Wheat	Malavika	Maharashtra
	Arjun (HD-2009)	Western Region of Uttar Pradesh.
	Janak (HD-1982)	Central and Western Regions of Uttar Pradesh.
	GAUW-10(J-24)	Gujarat
	Hy 65(HD-1467)	Madhya Pradesh
	Narbada-4	Madhya Pradesh
	Sonalika	Orissa
	Mukta	Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh (Bundelkhand and Division) and Rajasthan (Kota Division).
2. Soyabean	Ankur	Delhi, Bihar, West Bengal and plains regions of Uttar Pradesh.
3. Paddy	Basmati-370	Haryana
	Palman-579	Haryana
	GUAR 1	Gujarat
	GUAR-10	Gujarat
	GUAR-100	Gujarat
	Jaya	Gujarat
	Mahsuri	Gujarat
	Ratna	Gujarat, Orissa
	Sona	Gujarat, Karnataka
	Safri-17	Madhya Pradesh
	Lallu-14	Madhya Pradesh
	Bala	Orissa
	Jagannath	Orissa
	Hema	Orissa
	Karuna	Tamil Nadu
	Kanchi	Tamil Nadu
	ADT-30	Tamil Nadu
	ADT-31	Tamil Nadu
	Tiruvani	Tamil Nadu
	Annapoorna	Tamil Nadu
	IR-20	Tamil Nadu
	Vani	Non-gall midge endemic area of Orissa, parts of Karnataka, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan.
	Pusa-2-21	West Bengal, Orissa, Haryana and whole of North Eastern India.
	Kannagi	Tamil Nadu

(1)	(2)	(3)
4. Bajra	HB-3 NHB-5	Haryana Tamil Nadu Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Eastern Rajasthan and Uttar Pradesh.
	T-55	Haryana
	PHB-10	All bajra growing areas of the country.
	PHB-14	All bajra growing areas of the country.
5. Maize	Ganga-5 Vijay Composite Deccan-101	Orissa Orissa Andhra Pradesh, Karnataka and Madhya Pradesh.
6. Sorghum	JS-20 CSV-3(370) CSV-2(302) CSH-1 CSH-5 Muguthi Jola (S-4-1) Hybrid RSH-1 Vidisha 60-1 Loilpatti Tall CSV-4 (CS-3541) Haryana chari	Haryana Gujarat Gujarat Gujarat Gujarat, Tamil Nadu Karnataka Karnataka Madhya Pradesh Tamil Nadu Tamil Nadu All sorghum growing regions of the country.
	SL-44	Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh.
7. Barley	BG-25	Haryana for irrigated conditions.
	BG-105	Haryana for late sown irrigated conditions.
	C-138	Haryana for rainfed conditions.
8. Navane (Italian millet)	RC-128	Karnataka
	K-221-1	Karnataka
9. Ragi	AKP-2 Dibyasing PR-202 Saradha CO-10	Orissa Orissa Tamil Nadu Tamil Nadu Tamil Nadu
10. Gram	C-235 C-214 G-130 L-144 T-87	Haryana Haryana Haryana Haryana Madhya Pradesh
11. Moong	Pusa Baisakhi Varsha Jawahar-45 Kopargaon	Haryana Haryana Haryana, Karnataka Madhya Pradesh
12. Urd	T-9 Khargaon-3	Haryana Karnataka
13. Arhar	Prabhat UPAS-120	Haryana Haryana
14. Cowpea	Hara Lobia (HFC-42-1) FS-68	Haryana Haryana
15. Sudan grass	Meethi Sudan (59-3)	Haryana
16. Guar	FS-277	Haryana
17. Oats	FOS-1/29 Haryana Javi- 114	Haryana Haryana
18. Lucerne	Sirsa Type-9	Haryana
19. Berseem	Mescavi	Haryana

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
20. Semji	FOS-1	Haryana			Eastern part of Murshidabad, Nadia and 24-Parganas).
21. Metha	T-8	Haryana			
22. Toria	Improved Selection-1 Sangam	Haryana	JRO-632		Orissa, West Bengal (for high-land and midland where water does not stagnate).
23. Raya	RL-18 Prakash Varuna (T-59)	Haryana Haryana West Bengal, Gujarat and Uttar Pradesh.	JRO-878		Orissa, West Bengal (for Hooghly, 24-Parganas, Nadia, Murshidabad, Howrah and Kulna sub-divisions, Dinajpur and Eastern part of Birbhum district).
24. Brown Sarson	BSH-1	Haryana			
25. Tara-mira	T-27	Haryana	JRO-7835		Orissa, West Bengal (for Hooghly, Howrah, Birbhum, 24-Parganas, Nadia, Murshidabad, West Dinajpur and Kulna sub-divisions).
26. Ground nut	PB No. 1 Falzpur 1-5 AK 12-24 Jyoti TMV-2 TMV-10 Pollachi-1	Haryana Haryana Madhya Pradesh, Orissa Madhya Pradesh Tamil Nadu Tamil Nadu Tamil Nadu			
27. Castor	Aruna GCS-3 (JHB-67) GAUC-1(VHB-44)	Haryana Gujarat Gujarat			[No. 7-6/75-SD] T. BALARAMAN, Dy. Secr.
28. Cotton	320-F H-14 G-27 Narbada-1 MCU-5 MCU-8 Varalaxmi CBS-156	Haryana Haryana Haryana Madhya Pradesh Tamil Nadu Tamil Nadu Tamil Nadu		(बाबू विभाग) नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1976	
29. Tobacco	C-304	Haryana			का० बा० 787 .--भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्वसंजूरी से, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
30. Potato	Kufri Chander-mukhi Kufri Sindhuri	Haryana Haryana			1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1976 है।
31. Tomato	HS-101 HS-102	Haryana Haryana			(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
32. Cauliflower	Pusa Katki Hissar-1	Haryana, Karnataka Haryana			2. केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 4 के खण्ड (iii) में, "भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2)" शब्दों के पश्चात् "या स्टेट बैंक आफ इंडिया" शब्द जोड़े जायेंगे।
33. Brinjal	Pusa Purple Long H-4 Pusa Purple Round	Haryana, Karnataka Haryana Karnataka			3. उक्त विनियमों में, विनियम 12 के उपविनियम (1) में,— (क) खण्ड (क) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :- “(कक) समिति, विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी को किसी उधार का संशय मंजूर कर सकेगी, यदि वह विनिश्चित किया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी को उधार की आवश्यकता उन कारणों से है जो खण्ड (क) में वर्णित कारणों से भिन्न है।” ; (ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :- “(ग) जब खण्ड (क) के अधीन कोई उधार, किसी पूर्वतन उधार की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय पूरा किये जाने के पहले मंजूर किया जाता है तो किसी पूर्वतन उधार के बसूल न किये गये प्रातशेष को इस प्रकार मंजूर किये गये उधार में जोड़ दिया जायेगा और बसूली के लिये किस्तें समेकित रकम के प्रतिनिर्देशक से नियत की जाएगी।”
34. Onion	Hissar-2	Haryana			
35. French Bean	Contender	Karnataka			
36. Cabbage	Golden Acre	Karnataka			
37. Bhindi	Pusa Sawani	Karnataka			
38. Jute	JRC-212	Orissa, West Bengal (for Cooch-Bihar, Jalpaiguri and Siliguri sub-divisions, West Dinajpur, Malda, Eastern sides of Murshidabad, 24-Parganas and Nadia).			
	JRC-321	Orissa, West Bengal (for Cooch Behar, Jalpaiguri West Dinajpur and Siliguri sub-divisions, Malda, Eastern strips of Nadia, Murshidabad and 24-Parganas).			
	JRC-7447	Orissa, West Bengal (for Cooch Behar, Jalpaiguri and Siliguri sub-divisions,			

4. उक्त विनियमों में, विनियम 12 क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“12 क. निधि में से प्रत्याहरण —

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, समिति विशेष कारणों के लिए उस रकम में से, जो निधि के किसी अभिदाता के नाम जमा है, निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए प्रत्याहरण कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) निम्नलिखित दशाओं में अभिदाता की किसी सन्तान की उच्चतर शिक्षा के खर्च की पूर्ति, जिसके अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, उसके यात्रा व्यय भी आते हैं, अर्थात्:—

(i) हाई स्कूल प्रक्रम से आगे शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा के लिए ; और

(ii) हाई स्कूल प्रक्रम से आगे भारत में किसी चिकित्सा इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए ; परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम कम से कम तीन वर्ष के लिए हो ।

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों, तथा यदि उसके कोई पुत्री न हो तो उस पर प्राजित किसी अन्य महिला नातेदार की पुत्रियों, के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति ।

(ग) अभिदाता या उस पर वस्तुतः प्राजित किसी व्यक्ति की गणता के संबंध में व्ययों की पूर्ति, जिसके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो, उसके यात्रा व्यय भी आते हैं ।

(घ) अपने निवास के लिए उपयुक्त गृह बनाना या प्राजित करना, जिसके अन्तर्गत स्थल की लागत या प्रत्याहरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पहले किन्तु उस तारीख से बारह मास से अपूर्व, अभिव्यक्त रूप से इस प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण लेखे परादेय रकम का प्रतिसंदाय भी आता है, अथवा पहले ही अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्राजित किसी गृह का पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करना ।

(ङ) गृह स्थल खरीदना, या प्रत्याहरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पहले, किन्तु उस तारीख से बारह मास से अपूर्व, अभिव्यक्त रूप से इस प्रयोजन के लिये लिए गए ऋण लेखे परादेय किसी रकम का प्रतिसंदाय करना ।

(च) खण्ड (क) के अधीन प्रत्याहृत की गई धनराशि का उपयोग करते हुए खरीदे गए स्थल पर गृह का सन्निर्माण करना ;

(2) (i) उपविनियम (1) के खण्ड (क) और (ग) के अधीन प्रत्याहरण, अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा के पूरे होने के पश्चात् या अधिवाषिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले दस वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय मंजूर किया जाएगा, तथा एक बार प्रत्याहृत रकम निधि में उसके नाम जमा रकम की दो तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

(ii) उपविनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रत्याहरण, अभिदाता की सेवा के दस वर्ष पूरे होने के तत्पश्चात् या अधिवाषिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले दस वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, मंजूर किया जाएगा तथा प्रत्याहृत रकम उसके नाम जमा रकम की आधी से अधिक नहीं होगी ।

(iii) खण्ड (ब), (ङ) और (च) के अधीन प्रत्याहरण, अभिदाता की सेवा के दस वर्ष पूरे होने के पश्चात् या अधिवाषिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले दस वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय मंजूर की जाएगी, तथा प्रत्याहृत रकम निधि में उसके नाम जमा रकम की दो तिहाई से अधिक नहीं होगी ;

परन्तु ऐसा अभिदाता जिसने गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए उधारा के अनुदान के लिए, निर्माण और आवास विभाग की स्कीम के अधीन कोई उधार ले लिया हो या जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस बारे में कोई सहायता दी गई है, उक्त खण्ड (ब) (ङ) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की मंजूरी के लिए पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए किसी ऋण के प्रतिसंदाय के अभिव्यक्त प्रयोजन के सिवाय, पात्र नहीं होगा ;

(iv) किन्तु समिति इसमें के खण्ड (i) (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक, निधि में उसके नाम जमा प्रतिलेख के तीन चौथाई तक रकम का प्रत्याहरण (i) उस उद्देश्य का, जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है, (ii) अभिदाता की प्राप्ति का, और (iii) उस रकम का, जो निधि में उसके नाम जमा है, सम्यक् ध्यान रखते हुए मंजूर कर सकेगी ;

(v) अभिदाता की सेवा की अवधि के अन्तर्गत सेवा की भग्न अवधियों यदि कोई हो, आंग्रेजी जो निगम की सेवा में उसके स्थायी आमेसन के पहले, सरकारी सेवा में रहते हुए, की गई हो ।

(3) वह अभिदाता, जिसे उपविनियम (1) के अधीन निधि में से धन का प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी गई है, मंजूर करने वाले प्राधिकारी का, उस युक्तियुक्त अवधि के भीतर जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समाधान करेगा कि धन का उस प्रयोजन के लिए उपयोग कर लिया गया है जिसके लिए उसका प्रत्याहरण किया गया था, तथा यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत की गई सम्पूर्ण धनराशि या उसका उतना भाग जो उस प्रयोजन के लिए उपयोगित नहीं किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत किया गया था उस पर व्याज सहित, तत्क्षण एक-मुहूर्त राशि में अभिदाता द्वारा निधि को प्रतिसंदाय किया जाएगा, तथा ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह आवेदन दिया जाएगा कि उसे उसकी उपस्थितियों में से या तो एकमुहूर्त राशि रूप में या उतनी मासिक किश्तों में, जो मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए बसूल कर लिए जाएं” ।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 15 के उपविनियम (2) के खण्ड (ख) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसे भर्ती कर्मकार की बाबत, जो निगम की सहमति से, निगम में अपनी सेवा के पांच वर्ष के भीतर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस

उपनिमित्त के कार्य में, अपरिहार्य कारणों से अपने नियोजन को छोड़ दिया है।”।

[फा० सं० 6-38/73-एस० जी०]

ए० के० गढ़, अवर सचिव

(Department of Food)

New Delhi, the 6th February, 1976

S.O. 787.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, (hereinafter referred to as the said regulations), in clause (iii) of regulation 4, after the words “The Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882),” the words “or the State Bank of India” shall be inserted.

3. In the said regulations, in sub-regulation (1) of regulation 12,—

(a) after proviso to clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(aa) the Committee may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of any advance if it is specified that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in clause (a).”;

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) When an advance is sanctioned under clause (a) before repayment of last instalment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.”.

4. In the said regulations, for regulation 12A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“12A. WITHDRAWAL FROM THE FUND.—(1) Subject to the Conditions specified herein, withdrawals may be sanctioned by the Committee for special reasons from the amount standing to the credit of a subscriber to the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of any child of the subscriber in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years.

(b) Meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters and if he has no daughter, of any other female relation dependent on him.

(c) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling ex-

penses, of the subscriber or any person actually dependent on him.

(d) Building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site or repaying outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date, or reconstructing, or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber.

(e) Purchasing a house-site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date.

(f) For constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (e).

(2) (i) The withdrawal under clauses (a) and (c) of sub-regulation (1) shall be sanctioned at any time after the completion of 20 years' service of a subscriber or within 10 years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, and the amount withdrawn at one time shall not exceed two thirds of the amount standing to his credit in the Fund.

(ii) The withdrawal under clause (b) of sub-regulation (1) shall be sanctioned after the completion of 10 years of service of a subscriber or within 10 years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, and the amount withdrawn shall not exceed one-half of the amount standing to his credit.

(iii) The withdrawal under clauses (d), (e) and (f) shall be sanctioned at any time after the completion of 10 years of service of a subscriber or within 10 years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, and the amount withdrawn shall not exceed two thirds of the amount standing to his credit in the Fund.

Provided that a subscriber, who has availed himself of an advance under the scheme of the Department of Works & Housing, for the grant of advances for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall not be eligible for the grant of final withdrawal under the said clauses (d), (e) and (f) except for the express purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid Scheme.

(iv) The Committee may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of the limits specified in clauses (i), (ii) and (iii) herein, to three-fourths of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount standing to his credit in the Fund.

(v) The period of service of a subscriber shall include broken periods of service, if any, and the service, if any, rendered, while in the Government service, before his permanent absorption in the service of the Corporation.

(3) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under sub-regulation (1), shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn, shall forthwith be repaid in one lump sum together with interest thereon by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority.”

5. In the said regulations, in clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 15 the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that an enlisted worker voluntarily retiring with the concurrence of the Corporation within five years of his service in the Corporation, shall be deemed to have left his employment for unavoidable causes within the meaning of this sub-regulation."

[F. No. 6-38/73-SG.]

A. K. GARDE, Under Secy.

नौवहन और परिवहन में तलव

(परिवहन पत्र)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1976

का० घा० 788.—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है।

2. काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खण्ड 14 के उपखण्ड (2) में, 'नामनिर्देशित चिकित्सक अधिकारी' शब्दों के स्थान पर, 'स्थापित चिकित्सा बोर्ड' शब्द रखे जाएंगे।

[सं० एल डी के/7/75-I]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 4th January, 1976

S.O. 788.—The following draft of a Scheme further to amend the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1976.

2. In sub-clause (2) of clause 14 of the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 for the words "Medical Officer nominated", the words "Medical Board set up" shall be substituted.

[No. LDK/7/75-II]

का० घा० 789.—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1968 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है।

2. विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खण्ड 21 में, "नियुक्त चिकित्सक अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, 'स्थापित चिकित्सा बोर्ड' रखे जाएंगे।

[सं० एल डी के/7/75-II]

S.O. 789.—The following draft of a Scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1976.

2. In clause 21 of the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, for the words "Medical Officer appointed", the words "Medical Board set up" shall be substituted.

[No. LDK/7/75-II]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1976

का० प्रा० 799.—श्री एच० ओ० पेरेरा ने, जिसे डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशाखापत्तनम डॉक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अपना पद त्याग दिया है ;

और उक्त सदस्य के त्यागपत्र से उक्त डॉक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[सं० बी०-15021/1/74-एल जी० I]

New Delhi, the 6th February, 1976

S.O. 790.—Whereas Shri H. O. Pereira who was appointed as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board established under sub-section (1) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), has resigned his office under sub-rule (3) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board by the resignation of the said member ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies said vacancy.

[No. V-15021/1/74-LDI]

का० प्रा० 791.—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आई० एस० राजू को श्री एच० पी० पेरेरा के स्थान पर विशाखापत्तनम डॉक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और यह निवेश करती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3582, तारीख 28 सितम्बर, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, “डॉक कर्मकारों के नियोजकों और पोत परिवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य” शीर्षक के अधीन, सब (4) के सामने,

“श्री एच० पी० पेरेरा” प्रविष्टि के स्थान पर “श्री आई० एस० राजू” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० बी०-15021/1/74-एल जी० II]

बी० संक्रालिंगम, प्रवर सचिव

S.O. 791.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5A of the Dock Workers' (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri I. S. Raju as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board, vice Shri H. O. Pereira and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3582, dated the 28th September, 1968, namely :—

In the said notification, under heading, “Members representing the Employers of Dock Workers and Shipping Companies”, against item (4) for the entry “Shri H. O. Pereira”, the entry “Shri I. S. Raju” shall be substituted.

[No. V-15021/1/74-LD. II]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

भार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 फरवरी 1976

का० प्रा० 792.—अमरावती टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(III) (बी-बी) में प्रपेक्षित है अमरावती में जासू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 18 मार्च, 1975 को “नागपुर टाइम्स” तदनभारत” नागपुर, “हिन्दुस्तान” अमरावती तथा ‘अमरावती समाचार’ अमरावती समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी-बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-3-1976 से अमरावती का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

“अमरावती टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था”

अमरावती का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि अमरावती नगरपालिका के अन्तर्गत पड़ता है :

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि अमरावती नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें अमरावती टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से भुगतानी करेंगे।

[सं० 3-8/74-पी० एच० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P & T Board)

New Delhi, the 5th February, 1976

S.O. 792.—Whereas a public notice for revising the local area of Amraoti Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Amraoti, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 18th March, 1975 in ‘Nagpur Times’ Nagpur ‘Tarun Bharat’ Nagpur, ‘Hindustan’ Amraoti and ‘Amraoti Samachar’ Amraoti Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-3-1976 the revised local area of Amraoti shall be as under;

Amraoti Telephone Exchange System

The local area of Amraoti shall cover an area falling under the jurisdiction of Amraoti Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Amraoti Municipal limit but who are served from Amraoti Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-8/74-PHB]

का० प्रा० 793.—बदनरा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(III) (बी-बी) में अपेक्षित है बदनरा में खालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 18 मार्च, 1975 को 'नागपुर टाइम्स' नागपुर, 'तरुनभारत' नागपुर, 'हिन्दुस्तान' अमरावती तथा 'अमरावती समाचार' अमरावती समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी-बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-3-1976 से अमरावती का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा:—

बदनरा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

बदनरा का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि बदनरा नगर-पालिका के अन्तर्गत पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि बदनरा नगर-पालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें बदनरा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अवायगी करेंगे।

[सं० 3-8/74-पी० एच० बी०]

S.O. 793.—Whereas a public notice for revising the local area of Badnera Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Badnera, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 18th March 1975 in 'Nagpur Times', Nagpur, 'Tarun Bharat' Nagpur, 'Hindustan' Amraoti and 'Amraoti Samachar' Amraoti Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-3-1976 the revised local area of Badnera shall be as under :

Badnera Telephone Exchange System

The local area of Badnera shall cover an area falling under the jurisdiction of Badnera Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Badnera Municipal limit but who are served from Badnera

Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-8/74-PHB]

का० प्रा० 794.—वर्धा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(III) (बी-बी) में अपेक्षित है वर्धा में खालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 18 मार्च, 1975 को 'नागपुर टाइम्स' नागपुर, 'तरुनभारत' नागपुर, 'हिन्दुस्तान' अमरावती तथा 'अमरावती समाचार' अमरावती समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी-बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-3-1976 से वर्धा का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा:—

वर्धा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

वर्धा का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि वर्धा नगरपालिका के अन्तर्गत पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि वर्धा नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें वर्धा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अवायगी करेंगे।

[सं० 3-8/74-पी० एच० बी०]

S.O. 794.—Whereas a public notice for revising the local area of Wardha Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Wardha inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 18th March 1975 in 'Nagpur Times' Nagpur, 'Tarun Bharat' Nagpur, 'Hindustan' Amraoti, and 'Amraoti Samachar' Amraoti Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-3-1976, the revised local area of Wardha shall be as under :

Wardha Telephone Exchange System

The local area of Wardha shall cover an area falling under the jurisdiction of Wardha Municipality;

Provided that the telephone subscribers located outside Wardha Municipal limit but who are served from Wardha Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-8/74-PHB]

का० अ० 795.—बंगलूर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिये जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बी-बी) में अपेक्षित है बंगलूर में खालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 14 नवम्बर, 1975 को अंग्रेजी दैनिक "डकन हेरल्ड" और कन्नड़ दैनिक "कन्नड प्रभा" व "संयुक्त कर्नाटक" समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III)(बी-बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-3-1976 से बंगलूर का स्थानीय संगोष्ठित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

बंगलूर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

बंगलूर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि बंगलूर नगर निगम के अन्तर्गत पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जोकि बंगलूर नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें बंगलूर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे।

[सं० 3-22/74-पी० एच० बी०]

S.O. 795.—Whereas a public notice for revising the local area of Bangalore Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Bangalore, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers.

And whereas the said notice was made available to the public on 14th November, 1975 in English daily 'Deccan Herald' and Kannada Dailies 'Kannada Prabha' and 'Samyukta Karnataka' Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-3-1976 the revised local area of Bangalore shall be as under;

Bangalore Telephone Exchange System

The local area of Bangalore shall cover an area falling under the jurisdiction of Bangalore Municipal Corporation;

Provided that the telephone subscribers located outside Bangalore Municipal Corporation limit but who are served from Bangalore Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-22/74-PHB]

का० अ० 796.— बंगलूर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बी-बी) में अपेक्षित है, बंगलूर में खालू समाचारपत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 14 नवम्बर, 1975 को अंग्रेजी दैनिक "डकन हेरल्ड" और कन्नड़ दैनिक "कन्नड प्रभा" "संयुक्त कर्नाटक" समाचारपत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III)(बी-बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-3-1976 से बंगलूर का स्थानीय संगोष्ठित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

बंगलूर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

बंगलूर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि बंगलूर नगर निगम के अन्तर्गत पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जोकि बंगलूर नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें बंगलूर टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे।

[सं० 3-22/74-पी० एच० बी०]

S.O. 796.—Whereas a public notice for revising the local area of Bangalore Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Bangalore, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers.

And whereas the said notice was made available to the public on 14th November, 1975 in English daily 'Deccan Herald' and Kannada Dailies 'Kannada Prabha' and 'Samyukta Karnataka' Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-3-1976 the revised local area of Bangalore shall be as under;

Bangalore Telephone Exchange System

The local area of Bangalore shall cover an area falling under the jurisdiction of Bangalore Municipal Corporation;

Provided that the telephone subscribers located outside Bangalore Municipal Corporation limit but who are served from Bangalore Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-22/74-PHB]

का० प्रा० 797.—लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बसली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जिसका भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(iii) (बी-बी) में अन्तर्भूत है लखनऊ में पालू समाचारपत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई मुद्दा हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 15 अगस्त, 1975 को 'दैनिक जागरण' (हिन्दी) व 'नेशनल हेराल्ड' (अंग्रेजी), 23 अगस्त, 1975 को 'पायोनीर' (अंग्रेजी) और 13 सितम्बर, 1975 को 'स्वतन्त्र भारत' व 'नव जीवन' (हिन्दी) समाचारपत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियाँ और मुद्दा प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली, के नियम 434(iii)(बी-बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है कि तारीख 1-3-1976 से लखनऊ का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

लखनऊ का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि लखनऊ महापालिका तथा लखनऊ छावनी के अन्तर्गत पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जोकि लखनऊ महापालिका तथा लखनऊ छावनी सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु लखनऊ टेलीफोन व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से आवागमि करेंगे।

[सं० 3-30/74-पी० एच० बी०]

एस० एम० प्रसाद, निदेशक फोन (टी)

S.O. 797.—Whereas a public notice for revising the local area of Lucknow Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Lucknow, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 15th August, 1975 in 'Dainik Jagran' (Hindi) and 'National Herald' (English), on 23rd August 1975 in 'Pioneer' (English) and on 13th September, 1975 in 'Swatantra Bharat' and 'Navjivan' (Hindi) Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-3-1976 the revised local area of Lucknow shall be as under;

Lucknow Telephone Exchange System

The local area of Lucknow shall cover an area falling under the jurisdiction of Lucknow Mahapalika and Lucknow Cantonment Board.

Provided that the telephone subscribers located outside Lucknow Mahapalika and Lucknow Cantonment Board limits but who are served from Lucknow Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms. of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-30/75-PHB]

S. M. PRASHAD, Dir. Phones (T)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1976

का. आ. 798.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के प्रैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पुत्तूर टेलीफोन केंद्र में दिनांक 1-3-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-6/76-पी. एच. बी.]

प्रा. ना. कौल, निदेशक फॉन्स (ई)

New Delhi, the 11th February, 1976

S.O. 798.—In pursuance of para (a) of Section III of rule 434 of Indian Telegraph rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-3-76 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Puttur Telephone Exchange, Karnataka Circle.

[No. 5-6/76-PHB.]

P. N. KAUL, Director Phones (E)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1976

का० प्रा० 799.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 56 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि किसी रेलवे स्टेशन तक केवल माल को ले जाने के लिए आशयित रेल गाड़ियों द्वारा बुक किए गए माल का, ऐसे स्टेशन से अविलम्ब हटाया जाना आवश्यक है और उसे उपधारा के परन्तुक में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रेल स्टेशनों को 1 फरवरी, 1976 से 6 महीने की अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित करती है; अर्थात्:—

1. मुम्बई (वाड़ी बन्दर)
2. नागपुर
3. हावड़ा गृहस
4. इलाबाद
5. कानपुर सेन्ट्रल गृहस गौड (ब्रॉड गेज)
6. नई दिल्ली
7. मद्रास साल्ट कोटारस
8. एर्णाकुलम गृहस
9. बंगलौर सिटी जंक्शन
10. शालीमार
11. कांकरिया
12. बड़ीदा जंक्शन
13. असरवा जंक्शन

14. मुम्बई (कार्मिक विज)
15. रांची
16. टाटा नगर
17. न्यू गुहाटी
18. न्यू जलपाईगुड़ी

[संख्या टी०सी० 1/1680/74/1]

ए० एल० गुप्त, सचिव, पवेन संयुक्त, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

New Delhi, the 28th January, 1976

S.O. 799.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 56B of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government, being satisfied that it is necessary that goods booked by trains intended solely for the carriage of goods to any railway station should be removed without delay from such railway station and having regard to the factors specified in the proviso to that sub-section, hereby declares the following railway stations as "notified stations" for a period of six months with effect from the 1st February, 1976, namely :—

1. Bombay (Wadi Bandar).
2. Nagpur.
3. Howrah Goods.
4. Allahabad.
5. Kanpur Central Goods Shed (Broad Gauge).
6. New Delhi.
7. Madras Salt Cotaurs.
8. Ernakulam Goods.
9. Bangalore City Junction.
10. Shalimar.
11. Kankaria.
12. Baroda Junction.
13. Asarva Junction.
14. Bombay (Carnac Bridge).
15. Ranchi.
16. Tatanagar.
17. New Gauhati.
18. New Jalpaiguri.

[No. TCI/1680/74/1]

A. L. GUPTA, Secy. and ex-officio Jt. Secy.

धत्तः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कोयला खान प्राधिकरण लि० की संग्रामगढ़ कोयला खान, डाकखाना समदी, जिला बर्दवान के बिनोदीकाटा यूनिट के श्री दारोगासिंह मजदूरी येतन लिपिक को 22-2-1973 से लिपिकीय ग्रेड-3 में नियुक्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किरा अनुत्तोर का हकदार है ?

[सं० एल०-19012/22/75-डी-3 बी]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

MINISTRY OF LABOUR ORDER

New Delhi, the 4th November, 1975

S.O. 800.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Salanpur Sub Area of Coal Mines Authority Limited, Bonjemahari Colliery, Post Office Salanpur, District Burdwan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Coal Mines Authority Limited in placing Shri Daroga Singh, Wages/Pay Clerk of Binodikatta Unit of Sangramgarh Colliery, P.O. Samdi, District Burdwan, in clerical Grade III with effect from 22-2-1973 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 19012/22/75/DIIB]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

भम संज्ञासय

प्रादेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1975

का० आ० 800.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण लि०, बोजेमाहारी कोयला खान, डाकखाना सालनपुर, जि० बर्दवान के सालनपुर उपक्षेत्र के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

प्रादेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1975

का० आ० 801.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री कालू खान स्वामी के बलुआ पत्थर खान, (सेण्ड स्टोन माइने), डाकखाना लम्बाजी, जिला बुर्गी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायान्तरण के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री कालू सोना, मुमुक्षु श्री किशन जी, खान-स्वामी डाकघर लम्बाखो जिला बून्दी (राजस्थान) की लम्बाखो बलुआ पत्थर खान (सैंड स्टोन माइन्स) डाकखाना लम्बाखो जिला बून्दी (राजस्थान) में नियोजित श्रमिक किसी सवेतन राष्ट्रीय और त्यौहारी अवकाश दिन की संजूरी के हकदार हैं? यदि हाँ, तो किन अवकाश दिनों के और किस वर्ष से?

[संख्या एल०-29011/120/75-सी-3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1975

S.O. 801.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sand Stone Mines, Lambakho, of Shri Kalu Mina Mine Owner, Post Office Lambakho, District Bundi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Lambakho Sand Stone Mines, Post Office Lambakho in the District of Bundi (Rajasthan) of Shri Kalu Mine, son of Shri Kishanji, Mine Owner, Post Office Lambakho District Bundi (Rajasthan) are entitled for grant of any paid national and festival holidays? If so, on what holidays and from which year?

[No. L-29011/120/75-DIIB]

New Delhi, the 3rd February, 1976

S.O. 802.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs. Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th January, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT :

Shri K. K. SARKAR, Judge, Presiding Officer.

Reference No. 22 of 1975

(In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947)

Order of Reference

(Ministry's Order No. L-29012/18/74-LR-IV-D.O. 3(B) dated the 22nd February, 1975.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited.

AND
Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers.—Shri Santilal Jhobak.

On behalf of the workmen.—Shri Kukund Ram Tanti, Deputy President, Singhbhum Satla Mitti Khan Avang Sambandhit Udyog Mazdoor Sangh, P.O. Jagannathpur, Dist. Singhbhum.

INDUSTRY : China Clay

STATE : Bihar.

Dated, Dhanbad, the 23rd January, 1976

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :—

"(1) Whether the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs Jaipuria China Clay, Mines (Private) Limited, at Raikaman Post Office Andhari, District Singhbhum was justified in retrenching Sarvashri Natho, Sukhlal, Mata, Raghunath, Sambhu, Rupa, Manjit and Shrimati Renso, Sombari, Jambi, Junai, Namsi, Anama, Rukmani, Sura I, Somitra, Dasma, Sumi Miners and Shri Adhuro Nalk, Khalasi employed at their mines with effect from 13th May, 1974?

(2) If not, to what relief these workmen are entitled?"

The case of the workmen briefly stated is that the management refused work to 222 workmen inclusive of 32 retrenched workmen for 3 days i.e. 13th May to 15th May, 1974. Subsequently out of 32 workmen retrenched, 13 workmen were again given employment. The remaining 19 workmen who are named in the order of reference have been illegally retrenched. The retrenchment of the above workmen are alleged to be illegal and unjustified and uncalled for and no notice of retrenchment were served on the workmen nor any retrenchment compensation were given. It is therefore prayed that 19 workmen who were retrenched illegally should be reinstated with full back wages.

2. The case of the employers on the other hand is that the reference is misconceived inasmuch as there had been no retrenchment in the mines either from 13th May to 15th May or at any other time. It is alleged that out of 19 workmen as named in the order of reference S/Shri Sukhlal, Raghunath, Reno and Shrimati Sobari are still working in the mines and the question of their retrenchment does not arise. The remaining persons were not on the rolls from the week starting from 12-5-74 and so the question of their retrenchment from 13-5-74 does not arise. There was a strike on 15th May, 1974 and there was no refusal of employment to any person who turned up for job from 16th May, 1974.

3. In this reference no party has chosen to adduce oral or documentary evidence. The parties submitted their papers and simply advanced their arguments on the papers filed. According to law the papers filed must be legally proved before they can be admitted in evidence or can be taken into consideration. Simply filing of papers without proving them legally does not serve any purpose. In the absence of evidence oral or documentary, I have to see how else the industrial dispute before me can be adjudicated. The issue framed by the Government is whether the management was justified in retrenching the 19 persons as named therein with effect from 13th May, 1974. This Tribunal has to answer the above issue. The contention of the learned representative of the employers in that person alleged to be retrenched were never their employees and they were never retrenched on the relevant date. In the absence of any evidence the employers have failed to controvert the issue as

framed by the Government that these persons were retrenched by the employers with effect from 13th May, 1974. In the context of the issue as framed by the Government of India the employers are required to show that they were not workmen or that they were not retrenched from the relevant date. Employers have failed to controvert the issue framed by the Government. The Tribunal derives its jurisdiction from the order of Reference and must limit its jurisdiction within that. In this circumstances I cannot but hold that the 19 persons were retrenched by the employers with effect from 13th May 1974. The employers have no doubt a right to take a decision to retrench their workmen as he has a right to reorganise his business in any fashion for the purpose of economy or convenience but the justification for retrenchment has to be assessed by the reasonableness of the decision taken by the management in a particular situation. The employers must be acting bona fide. In the absence of any reason as to why the management retrenched the workmen, the bona fides of the action of the management has not been proved. According to Section 25F of the Industrial Disputes Act there are certain conditions to be fulfilled by the employers before taking recourse to retrenchment and payment of retrenchment compensation is a pre-condition for retrenchment of workmen. The non-compliance with the mandatory provision of law makes retrenchment invalid and inoperative. Workmen who have been retrenched in contravention of the provision of the above section must be taken to be still in service so that they continue to earn notwithstanding termination of their employment. Such unlawful retrenchment justifies an order of reinstatement with a right of continuity of service and back wages. The accepted fact as per the issue framed by the Government is that 19 workmen concerned were retrenched. The employers have failed to show justification for their retrenchment and their non-compliance with the requirement of law before the retrenchment. Accordingly I cannot but hold that the retrenchment is invalid and illegal and this gives right to the workmen to be put back in service with continuity of service and back wages. It is true that in this case the workmen also did not adduce any evidence but the issue which is before me for adjudication is such that it does not require the workmen so much to prove that it is a case of invalid and improper retrenchment.

4. In the result, I find that the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited, at Raikaman Post Office Andhari, District Singhbhum was not justified in retrenching Sarvashri Natho, Sukhlal, Mata, Raghunath, Sambhu, Rupa Manjit and Shrimati Rensu, Sombari, Jambi, Junai, Namsi, Anama, Rukmani, Sura I. Somitra, Dasma, Sumi Miners and Shri Adhuro Naik, Khalasi with effect from 13th May, 1974. They are therefore entitled to be put back in their jobs with continuity of service and back wages. The issues are so answered.

This is my award.

[No. L-29012/18/74-LR IV/DIIB]

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

New Delhi, the 4th February, 1976

S.O. 803.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Raikaman China Clay Mines of M/s Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited at Raikaman, P.O. Andhari, and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th January, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge, Presiding Officer.

Reference No. 24 of 1974

(In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947).

Order of Reference

(Ministry's Order No. L-29011(44)/74-LR-IV, dated the 21st October, 1974).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Raikaman China Clay Mines of M/s. Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited at Raikaman Post Office Andhari, District Singhbhum.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers.—Shri Santilal Jhabak.

On behalf of the Workmen.—Shri Mukunda Ram Tanti, Deputy President, Singhbhum Sada Mitti Khan Avang Sambandhit Udyog Mazdoor Sangh, P.O. Jagannathpur, District Singhbhum.

STATE : Bihar

INDUSTARY : Cina Clay

Dated, Dhanbad, the 24th January, 1976

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent this reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :

"(1) Whether the action of the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited at Raikaman Post Office Andhari, District Singhbhum in refusing employment to the 222 workers mentioned below at their Raikaman China Clay Mines from the 13th May, 1974 to 15th May, 1974 was justified ?"

(2) If not, to what relief are the workmen concerned.

Locked of Employees

(1) Quarry Section

1. Sri Pitobas
2. Smt. Mukho.
3. Smt. Pusba
4. Sri Darunaik
5. Sri Biranchi
6. Smt. Rupee
7. Smt. Sarwati
8. Sri Kora Koro
9. Smt. Niraso
10. Smt. Sumitra
11. Sri Puradh Dharo
12. Smt. Sabitri
13. Smt. Chandri
14. Sri Jorahar
15. Smt. Sultanti
16. Smt. Jima
17. Sri Gajadhar.
18. Smt. Lorito
19. Smt. Roma
20. Sri Kailash
21. Smt. Bilaso
22. Smt. Gulapo
23. Sri Renudhar
24. Smt. Gomi
25. Smt. Dosma
26. Sri Surjan
27. Smt. Niraso II
28. Smt. Luchona
29. Sri Adhiro.
30. Smt. Namsi

31. Smt. Saro
32. Sri Renso
33. Smt. Sombari
34. Smt. Randhi
35. Smt. Negi
36. Smt. Junia
37. Sri Suklal
38. Smt. Sunai
39. Smt. Randhi
40. Sri Natho
41. Smt. Indair
42. Smt. Pepli
43. Sri Bhagvan
44. Smt. Manjit
45. Smt. Dosu
46. Sri Raghunath
47. Smt. Menjo
48. Smt. Pepli
49. Sri Anand
50. Smt. Rabibari
51. Smt. Panbhati
52. Sri Bhanu
53. Smt. Chama
54. Smt. Ludhri
55. Sri Onumo
56. Smt. Sumi
57. Smt. Suru
58. Sri Boidu
59. Smt. Kairi
60. Smt. Kriri
61. Smt. Jambi
62. Sri Chran
63. Sri Kamala
64. Smt. Sunika
65. Sri Ramtia
66. Smt. Sobari
67. Smt. Menjhari
68. Sri Rupa
69. Smt. Suru
70. Smt. Dosma
71. Uchba
72. Smt. Belo
73. Smt. Lalmoti
74. Sri Lambra
75. Smt. Moti
76. Smt. Podni
77. Smt. Sahbhu
78. Smt. Dangol
79. Smt. Raibari
80. Sri Suklal
81. Smt. Bhajmoti
82. Sri Kirson
83. Smt. Sabni
84. Smt. Manjhi
85. Sri Chono
86. Smt. Sabni
87. Smt. Biranjh

SORTING SECTION

89. Smt. Solto
90. Smt. Osbin
91. Smt. Jaimoni

92. Smt. Kondo
93. Smt. Bimla
94. Smt. Subani
95. Smt. Paro
96. Smt. Raibari
97. Smt. Chamba
98. Smt. Dosmoti
99. Smt. Rukmoni
100. Smt. Monti
101. Smt. Dosu I
102. Smt. Dosu II
103. Smt. Nonita
104. Smt. Konsola
105. Smt. Subani
106. Smt. Gurubari
107. Smt. Horo
108. Smt. Surjo

PLATFORM SECTION

109. Smt. Nra
110. Smt. Jobri
111. Smt. Bhomini
112. Smt. Mukta
113. Smt. Sandu
114. Smt. Sombri
115. Smt. Poti
116. Smt. Fulmoti
117. Smt. Fulmoti II
118. Smt. Dosmoti
119. Smt. Omka
120. Smt. Susila
121. Smt. Kokilo
122. Smt. Hemo
123. Smt. Sarwati
124. Smt. Doyamoti
125. Smt. Sudra
126. Smt. Champa
127. Smt. Gori
128. Smt. Suden I
129. Smt. Suden II
130. Smt. Ludri
131. Smt. Biranj (Saro)
132. Smt. Saro
133. Smt. Moni
134. Smt. Duti
135. Smt. Sabitri
136. Smt. Sita
137. Smt. Podma
138. Smt. Churmba
139. Smt. Daurpati
140. Smt. Bimla
141. Smt. Pani
142. Smt. Nitma
143. Smt. Menjo
144. Smt. Dosma
145. Smt. Nuji
146. Smt. Nanika
147. Smt. Menjo II

WASHING SECTION

148. Sri Dhram
149. Sri Roya
150. Sri Pandu

151. Sri Kailash
152. Sri Jumal
153. Sri Congala
154. Sri Ramo
155. Sri Hori
156. Sri Gurucharan
157. Sri Pomo
158. Sri Soban
159. Sri Suna
160. Sri Suban
161. Sri Goura
162. Sri Sonatan
163. Sri Mutra
164. Sri Sonu
165. Sri Conga
166. Sri Robi
167. Sri Gasiram
168. Sri Sulo

THIRD SHIFT

169. Sri Kushu
170. Sri Roro

WASHING SECTION

171. Sri Divakaro
172. Sri Dundka
173. Ghumbroo
174. Sri Sanatan
175. Sri Totna
176. Sri Rupsing
177. Sri Nando
178. Sri Mankoro
179. Sri Mandai

NET WORK WASHING**1ST SHIFT**

180. Smt. Kuni
181. Smt. Sobari
182. Smt. Radhi
183. Smt. Juidho

PRESS SECTION

184. Sri Pitam
185. Sri Samu
186. Sri Singa
187. Sri Roya
188. Sri Reswa
189. Sri Rasika
190. Sri Krishna
191. Sri Sagro
192. Sri Soban
193. Sri Jabira
194. Sri Daso
195. Sri Raghunath
196. Sri Gonga
197. Sri Joba

PUMP KHALASI

198. Sri Arjun
199. Sri Chinta
200. Sri Karia
201. Sri Ranso
202. Si-bo

GOODS TRANSPORTING

203. Sri Somanath
204. Sri Gopi

205. Sri Podu
206. Sri Ramesh
207. Sri Singa
208. Sri Jumbal
209. Sri Doru
210. Sri Gasi Ram Naik

WAGIN COLLE

211. Sri Naresh
212. Sri Budhu
213. Shri Kesai
214. Shri Gopi
215. Sri Mangal Singh
216. Sri Bondhia
217. Sri Sagar
218. Sri Lahu
219. Sri Jhari

QUARRY CONTINUED

220. Sri Pratap
221. Smt. Kodma
222. Smt. Chami.

2. The case of the workmen in short is that the management whimsically disallowed 222 number of workmen from their respective duties from 13-5-1974 to 15-5-1974 although the workmen daily attended for work. This is due to fact that the union issued a call for token strike of one day on 15-5-1974 to press their demands. The management are reported to the preparing false documents to desist the claim of the workmen in respect of 222 employees. They pray full wages from 13-5-1974 to 15-5-1974 in favour of 222 workmen of Raikaman China Clay Mines. The management in their written statement maintain that the reference is not maintainable. They deny the correctness of the list of 222 workmen as mentioned in the schedule specified in the order of Reference. They also deny that they ever refused employment to 222 workers mentioned in the list and crave leave to produce the particulars as regards persons named in the Order of Reference.

3. The short point of decision in this case is whether the management refused work to 222 persons from 13-5-74 to 15-5-1974 who, it is claimed, reported for duties on all those days. The management deny the correctness of the numbers of workmen as given out by the union and they also deny having been refused employment to them. Before me the workmen examined only one witness who is Renso Hembram as WW 1. The management chose not to adduce any witness in support of their case. It appears that the workmen attached with their written statement a list giving particulars of 222 persons who are alleged to have been refused employment from 13th May to 15th May, 1974. In their written statement the management disputes the correctness of the numbers given out by the workmen and craved leave of this Tribunal to produce particulars as regards persons named in the order of Reference at the time of hearing. It appears that at the time of hearing the management did not supply the particulars as regards the correct position of workmen involved. The workmen called for production of B Register and the attendance Register in respect of the workmen of the mines. It appears that inspite of sufficient time being given to the management for this purpose they failed to produce the Attendance Register. The management, it appears, produced a Form III Register (Ext. W. 1) of weekly paid workers. The learned Representative of the workmen submits that this register does not reflect the correct position and it has been prepared for the purpose of this case. Be that as it may, this register is not sufficient for the purpose of this case. It appears that the management filed some registers i.e. Form E, Form D, Form III. Simply production of the registers does not help. These registers must be legally proved before they can be admitted in evidence and before they can be relied upon. I do not know what prevented the management to prove these registers according to law. The learned Representative of the management submits that the records produced would show that the strength of workmen on 13th, 14th and 15th of May, 1974 was much less than given out by the workmen. I could have appreciated this submission if

the management cared to prove these registers by competent persons. They did not do so and accordingly I cannot look into those registers to see for myself the correct position of staff strength as submitted by the learned Representative of the management. Not only this, as I have already pointed out, the management did not also choose to examine any witness in support of their case. So far as the workmen are concerned I have already pointed out that they have submitted particulars of 222 workmen along with their written statement. Their witness Renso Hembram, WW 1 says in his evidence that on 13th May, 1974, 222 workmen of the mines including himself went to work but they were refused employment. Similarly on 14th and 15th of May, 1974 these persons reported for their duties but they were refused employment. There is nothing to counter evidence adduced, and no witness examined by the management to controvert the same. We may then look into the term of the Reference as referred to by the Govt., Ministry of Labour. The issue framed by the Government is whether the action of the management in refusing employment to the 222 workmen on 13th May to 15th May, 1974 was justified. The management also did not produce satisfactory evidence to counter the issues framed by the Government and sent to me for adjudication. The Tribunal derives its jurisdiction from the order of Reference, and in the order of Reference the specific term is that the management refused employment to 222 workmen and this Tribunal was called upon to adjudicate whether this action of the management was justified. So in the context of the issue framed in the Reference and in the light of evidence adduced from the side of the workmen and failure of the management to give satisfactory evidence in support of their case, I am inclined to hold that the act of the management in refusing employment to 222 workmen is not justified. These workmen are therefore entitled to 3 days wages for 13th, 14th and 15th May, 1974.

4. In the result, I find that the management of Raikaman China Clay Mines of Messrs Jaipuria China Clay Mines (Private) Limited, at Raikaman Post Office Andhari, District Singhbhum was not justified in refusing employment to the 222 workers mentioned below at their Raikaman China Clay Mines from 13th May 1974 to 15th May, 1974.

List of the workmen

(1) QUARRY SECTION

1. Sri Pitobas
2. Smt. Mukho
3. Smt. Pusba
4. Sri Darunaik
5. Sri Branchi
6. Smt. Rupee
7. Smt. Sarwati
8. Sri Kora Koro
9. Smt. Niraso
10. Smt. Sumitra
11. Sri Puradh Dharo
12. Smt. Sabitri
13. Smt. Chandri
14. Sri Jorahar
15. Smt. Sultanti
16. Smt. Jima
17. Sri Gajadhar
18. Smt. Lcrito
19. Smt. Roma
20. Sri Kailash
21. Smt. Bilaso
22. Smt. Gulapo
23. Sri Benudhar
24. Smt. Gomi
25. Smt. Dosma
26. Sri Surjan
27. Smt. Niraso II
28. Smt. Luchona
29. Sri Adhiro
30. Smt. Namsi

31. Smt. Saro
32. Sri Renso
33. Smt. Sombari
34. Smt. Randhi
35. Smt. Negi
36. Smt. Junia
37. Sri Suklal
38. Smt. Sunai
39. Smt. Randhi
40. Sri Natho
41. Smt. Indair
42. Smt. Pepli
43. Sri Bhagvan
44. Smt. Manjit
45. Smt. Dosu
46. Sri Raghunath
47. Smt. Menjo
48. Smt. Pepli
49. Sri Anand
50. Smt. Rabibari
51. Smt. Panbhati
52. Sri Bhanu
53. Smt. Chama
54. Smt. Ludhri
55. Sri Onumo
56. Smt. Sumi
57. Smt. Suru
58. Sri Boldu
59. Smt. Kalri
60. Smt. Kiri
61. Smt. Jambi
62. Sri Chran
63. Smt. Kamala
64. Smt. Sunika
65. Sri Ramtia
66. Smt. Sobari
67. Smt. Menjhari
68. Sri Rupa
69. Smt. Suru
70. Smt. Dosma
71. Uchba
72. Smt. Belo
73. Smt. Lalmoti
74. Sri Lambra
75. Smt. Moti
76. Smt. Podni
77. Smt. Sahbhhu
78. Smt. Dangoi
79. Smt. Raibari
80. Sri Suklal
81. Smt. Bhajmoti
82. Sri Kirson
83. Smt. Sabni
84. Smt. Manjhi
85. Sri Ghono
86. Smt. Sabni
87. Smt. Biranjh
88. Sri Oiban

SHORTING SECTION

89. Smt. Soito
90. Smt. Osbin
91. Smt. Jaimoni
92. Smt. Konko

93. Smt. Bimla
94. Smt. Subani
95. Smt. Paro
96. Smt. Roibari
97. Smt. Chamba
98. Smt. Dosmoti
99. Smt. Rukmoni
100. Smt. Monti
101. Smt. Dosu I
102. Smt. Dosu II
103. Smt. Nonita
104. Smt. Konsola
105. Smt. Subani
106. Smt. Gurubari
107. Smt. Horo
108. Smt. Surjo

PLATFORM SECTION

109. Smt. Nra
110. Smt. Jobri
111. Smt. Bhomini
112. Smt. Mukta
113. Smt. Sandu
114. Smt. Sombri
115. Smt. Poti
116. Smt. Fulmoti
117. Smt. Fulmoti II
118. Smt. Dosmoti
119. Smt. Omka
120. Smt. Susila
121. Smt. Kokilo
122. Smt. Hemo
123. Smt. Sarwati
124. Smt. Doyamoti
125. Smt. Sudra
126. Smt. Champa
127. Smt. Gori
128. Smt. Suden I
129. Smt. Suden II
130. Smt. Ludrik
131. Smt. Biranj (Saro)
132. Smt. Saro
133. Smt. Moni
134. Smt. Duti
135. Smt. Sabitri
136. Smt. Sita
137. Smt. Podna
138. Smt. Churmba
139. Smt. Daurpati
140. Smt. Bimla
141. Smt. Pani
142. Smt. Nitma
143. Smt. Manjo
144. Smt. Dosma
145. Smt. Nuji
146. Smt. Nanika
147. Smt. Menjo II

WASHING SECTION

148. Sri Dhram
149. Sri Roya
150. Sri Pandu
151. Sri Kallash
152. Sri Jumal

153. Sri Congala
154. Sri Ramo
155. Sri Horl
156. Sri Gurucharan
157. Sri Pono
158. Sri Soban

SECOND SHIFT

159. Sri Suna
160. Suban
161. Sri Goura
162. Sri Gonatan
163. Sri Mutra
164. Sri Sonu
165. Sri Conga
166. Sri Robi
167. Sri Gasiram
168. Sri Sulo

THIRD SHIFT

169. Sri Kusnu
170. Sri Roro

WASHING SECTION

171. Sri Dibakaro
172. Sri Dundka
173. Sri Ghumbroo
174. Sri Sanatan
175. Sri Rotna
176. Sri Rupsing
177. Sri Nando
178. Sri Mankoro
179. Sri Mandal

NET WORK WASHING

1st SHIFT

180. Smt. Kuni
181. Smt. Sobari
182. Smt. Radhi
183. Smt. Jidho

PRESS SECTION

184. Sri Pitam
185. Sri Samu
186. Sri Singa
187. Sri Roya
188. Sri Beswa
189. Sri Rasika
190. Sri Krishna
191. Sri Sagro
192. Sri Soban
193. Sri Jabira
194. Sri Daso
195. Sri Raghunath
196. Sri Gongga
197. Sri Joba

PUMP KHALASI

198. Sri Arjun
199. Sri Chinta
200. Sri Karla
201. Sri Ranso
202. Sri Sibbo

GOODS TRANSPORTING

203. Sri Somnath
204. Sri Gopi

205. Sri Podu
206. Sri Ramesh
207. Sri Singa
208. Sri Ratha
209. Sri Jumbal
210. Sri Doru
211. Sri Gasi Ram Naik

WAGIN COLLE

212. Sri Naresh
213. Sri Budhu
214. Sri Kesai
215. Sri Gopi
216. Sri Mangal Singh
217. Sri Bodhla
218. Sri Sagar
219. Sri Lalu
220. Sri Jharl
221. Sri Pratap
222. Smt. Kodma
223. Smt. Chamli

The workmen are, therefore, entitled to full wages for the period from 13th May to 15th May, 1974, subject to adjustment of any payment that might have been made by the management to the workmen.

This is my award.

K. K. SARKAR, Judge, Presiding Officer.

[No. L 29011/44/74-LR IV]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

कां.प्र.० 804.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०, डाकघर-नुधखुर्की, जिला-धनबाद की नुधखुर्की कोयला खान के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 का उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०, डाकघर नुधखुर्की, जिला धनबाद की नुधखुर्की कोयला खान के प्रबन्धतंत्र की श्री मनोखे लाल यादव, सोडियम पर्यवेक्षक को 19-7-1971 से श्रेणो-2 (लिपिकीय) में रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकवार है ?

[संख्या एन-20012(118)75-डी-3 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 804.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nudkharkee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkharkee, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Nudkharkee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkharkee, District Dhanbad, is justified in placing Shri Anokhey Lal Yadav, Loading Supervisor, in Grade II (Clerical), with effect from 19-7-1971? If not to what relief is the said workmen entitled to and from what date?

[No. L-20012(118)/75-D-III(A)].

आदेश

कां.प्र.० 805.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सी०एम०ए० लिमिटेड की खूडिया कोलियरी, डाकघर मुग्मा (जिला-धनबाद) के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स सी एम ए लिमिटेड की खूडिया कोलियरी, डाकघर मुग्मा (जिला धनबाद) के प्रबन्धतंत्र की 3-6-1973 से श्रीमती सुलोचना बोडियाकर, सीडिंग कामिन का काम मस्टर रोल से काटने और उन्हें बहाल करने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष की हकवार है ?

[सं० एन-20012/120/75-डी-3(ए)]

ORDER

S.O. 805.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khoodia Colliery of M/s. CMA Ltd., P. O. Mugma (Distt. Dhanbad), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Khoodia Colliery of M/s. C.M.A. Ltd., P. O. Mugma (Distt. Dhanbad) in striking off name from Mustar Roll of Smt. Sulochana Badyakar, Leading Kamin with effect from 3-6-73 and refusing her to reinstate was justified? If not, to what

[No. L. 20012/120/75/DIIIA]

New Delhi, the 2nd February, 1976

S.O. 806.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal cum Labour Court No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Sinidih Colliery (unit of Jogidih Colliery) of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Tundoo, Distt. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th January, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD

PRESENT: Shri K. K. Sarkar, Judge, Presiding Officer.

Reference No. 42 of 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

ORDER OF REFERENCE

(Ministry's Order No. L-20012/161/74/LRII/D.IIIA dt. 19-4-1975)

PARTIES : Employers in relation to the management of East Sinidih Colliery (Unit of Jogidih Colliery) of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Tundoo, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers : Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri P. K. Bose, Advocate
Industry : Coal. State : Bihar.

Dated, Dhanbad, the 22nd January, 1976.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent this reference to this Tribunal for adjudication of the Industrial dispute involved with the following issues framed :—

- (1) Is the action of the management of East Sinidih Colliery (Unit of Jogidih Colliery) of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Tundoo, Distt. Dhanbad in stopping the work of the following workmen from the respective dates mentioned against them, justified?
- (2) If not, to what relief are the said workmen entitled.

Sl. No.	Name and designation of workman	Date of stoppage
1.	Sri Neman Gope, Miner	19-7-1974
2.	„ Bharan Gope, Miner	12-8-1974
3.	„ Lutan Gope, Miner	13-7-1974
4.	„ Bharat Gope, Miner	19-7-1974
5.	„ Lutan Mondal, Miner	19-7-1974
6.	„ Fuchu Majhi, Miner	12-7-1974
7.	„ Seo Kumar Roy, Cap Lamp Fitter	19-7-1974
8.	„ Jhaman Gope, Miner	5-10-1974

On receipt of the above order of reference notices were duly sent to both sides. Both sides appeared and filed their written statement in due course. Thereafter the reference proceeded along its course. It appears that the parties took a few adjournment of the case on the ground of filing a settlement. Ultimately on the last date fixed for the purpose Shri S. S. Mukherjee, Advocate representing the employers and Shri P. K. Bose, Advocate representing the workmen appeared and filed a memorandum of settlement with a request that the reference may be disposed of in terms of memorandum of settlement. I heard the parties on the settlement. The settlement was signed on behalf of the employers by the General Manager, Area No. III Bharat Coking Coal Ltd. and for the workmen by the Secretary of the Colliery Mazdoor Sangh. Over and above the individual workmen involved in this reference also put their L.T.I. on the memorandum of settlement. So it appears that the memorandum of settlement have been properly signed by the parties and the same is beneficial to both sides. There is, therefore, no reason why the memorandum of settlement should not be accepted.

In the result, I pass an award in terms of memorandum of settlement which do form part of the Award as annexure A.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In Reference No. 42 of 1975

Employers in relation to East Sinidih Colliery

AND

Their Workmen

JOINT PETITION FOR COMPROMISE SETTLEMENT

The humble petitioner, on behalf of the Parties above named, most respectfully begs to state—

1. That the Parties have arrived at an amicable settlement of the dispute, in the above noted case on the terms stated below—

TERMS OF SETTLEMENT

2. (i) That the management agrees to provide employment to

- (1) Neman Gope.
- (2) Barhan Gope.
- (3) Lutan Gope.
- (4) Bharat Gope.
- (5) Lutan Mondal.
- (6) Fuchu Majhi.
- (7) Jhaman Gope-All Miners.
- (8) Shoe Kumar Roy, Cap Lamp Fitter.

in any colliery of B.C.C. Ltd., within fifteen days of their reporting for resumption of duty before the Area General Manager, Area No. III.

(ii) That the parties agree that if any of the above named workers fails to report for duty within 15 days of the date of filing of this settlement he will forfeit his claim for employment.

(iii) That the management agrees to maintain the continuity of service of the concerned workmen and to treat the period of their idleness from their respective dates of stoppage to their duties of resumption of duty as leave without pay—for the purpose of gratuity, retrenchment etc.

(iv) That the Union agrees that the concerned workmen shall have claim against the management for any wages, bonus etc. for the period specified in the proceeding paragraph.

(v) That the parties agree that the above noted terms finally settle this dispute between the parties and the parties shall have no further claim against each other, in this respect.

(vi) That the parties agree that the settlement shall come into effect from the date on which the settlement is filed before the Hon'ble Tribunal.

(vii) That the management agrees to pay Rs. 100 (Rupees one hundred only) as the cost of proceeding to the Union representative on the date of settlement.

3. That the humble petitioners submit that the above terms of Settlement are reasonable and proper, and the Hon'ble Tribunal may be pleased to approve the same and pass Award in terms thereof.

And for this the humble petitioners shall ever pray.

For Workman
Sd/- Illegible
Secretary

For Management.
Sd/- Illegible
General Manager.
Area No. III.

Colliery Mazdoor Sangh.

- (1) L.T.I. Haman Gope.
- (2) L.T.I. Borahor Gope.
- (3) L.T.I. Lotan Gope.
- (4) L.T.I. Bhorot Gope.
- (5) L.T.I. Laton Mendal.
- (6) L.T.I. Fuchu Maghi.
- (7) L.T.I. Jshman Gope.
- (8) Sheokumar Roy.

Sd/-

Presiding Officer,

Central Government Industrial Tribunal (No. 3)
DHANBAD

[F. No. L. 20012/161/74-LR II]

G. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976

का० प्रा 807.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियोजनों को उस अधिनियम की अनुसूची के भाग I में जोड़ती है, ऐसा करने के केन्द्रीय सरकार के आग्रह की सूचना उक्त धारा द्वारा यथाप्रेक्षित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2396, तारीख 11 जुलाई, 1975 में पहले ही दी जा चुकी है, अर्थात् :—

- (क). कार्टोजाइट खानों में नियोजन ;
- (ख). क्वार्ट्ज खानों में नियोजन ; और
- (ग). सिलिका खानों में नियोजन ।

[एस० 32017 (2)/74 डब्ल्यू० सी० (एम-डब्ल्यू)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 4th February, 1976

S.O. 807.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act the following employments, notice of its intention to do so having already been given by the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2396, dated the 11th July, 1975, as required by the said section, namely :—

- (a) employment in quartzite mines;
- (b) employment in quartz mines; and
- (c) employment in silica mines.

[S-32017(2)/74-WC(MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

S.O. 808.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd February, 1976.

In the matter of Arbitration in the Industrial Dispute between the Food Corporation of India, West Zone and their workmen represented by the Transport & Dock Workers' Union, Kandla over the Union's demand for giving retrospective effect to the Incentive Piece Rate Scheme.

PRESENT

Shri S. M. Dikhale, Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi—ARBITRATOR.

Representing Food Corporation of India—(1) Shri M. Pichamuthu, Manager (IR), Hqs. (2) Shri B. K. Sethi, Sr. Dy. Manager (IR), Hqs. (3) Shri M. S. Vaswani, Dy. Manager (Labour), Bombay.

Representing Workmen—(1) Shri M. G. Kotwal, President, Transport & Dock Workers' Union, Kandla. (2) Shri Ramakant Desai, General Secretary, Transport & Dock Workers' Union, Kandla.

State : Gujrat Industry : Food Corporation of India.

AWARD

By an Arbitration Agreement under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947) between the Zonal Manager, Food Corporation of India, West Zone, Bombay and the Transport & Dock Workers' Union, Kandla representing Food Corporation of India Departmental Workers at Kandla Port, which was published by the Government of India, Ministry of Labour *vide* their order dated 21-7-1975 in the official Gazette of India, the parties agreed to refer the following issue to my arbitration :—

"While finalising the Incentive Piece Scheme for Kandla Departmental Workers, the Transport & Dock Workers' Union representing workmen have demanded that the Scheme should have retrospective effect from 1-1-1972. This is not agreed to by the employer represented by the Zonal Manager (West), Food Corporation of India, Bombay. Hence both the parties agree to refer this item to arbitration. The Scheme at present will be effective from 15-11-1973".

As soon as the Arbitration Agreement was published in the Gazette of India S.O. No. 2489 dated 2-8-1975, I sent registered letters to the parties on 4-8-1975 calling for their statements and rejoinders if any. The Union's statement of claim was received by me on 19-8-1975. I had preliminary discussion with the parties at Bombay on 9-9-1975. Subsequently the employer's statement and rejoinder to the union's statement were received by me on 16-9-1975. The hearing was fixed at Delhi on 29-10-1975. However, at the request of both parties it was postponed. The next hearing was held in my office at New Delhi on 20-11-1975. During this meeting after prolonged discussions the need for examining of certain documents was felt and as these documents were available in the office of the Zonal Manager (West), Bombay, the parties requested for the final meeting to be fixed at Bombay on 28th & 29th November, 1975. Accordingly the last joint meeting was held on 28th & 29th November, 1975 at Bombay. The relevant documents were examined and the parties made their concluding arguments. The parties also agreed to extend the period for giving the award by the Arbitrator upto 15-12-1975. However, subsequently at my request the parties agreed to further extend the date for giving my award upto 31-1-1976 as I wanted time to attend to my pressing official work and also to have an opportunity to discuss the matter separately with both the parties which I did.

Union's Case—

The Transport & Dock Workers Union, Kandla *vide* its letter dated 28th November, 1970 submitted a charter of demands regarding introduction of an incentive piece-rate scheme and certain other improvements in the service conditions of the foodgrain handling workers employed by the Food Corporation of India at the Port of Kandla, following the charter of demands submitted by the Transport and Dock Workers' Union, Bombay which had also demanded revision

in the piece-rates of the workers working in docks and evolving a piece-rate scheme for godown workers and other service conditions of foodgrain handling workers employed by the Food Corporation of India, Bombay. In both the cases, Bombay and Kandla, Food Corporation of India made a request to have a settlement in two parts once consisting of service conditions other than revision of piece-rate and the second revision/evolving of piece-rate. Accordingly an agreement was signed by Food Corporation of India, following an agreement in Bombay, for the workers of Kandla, wherein the service conditions, other than the piece-rate scheme, were revised. In the meantime, the negotiations for the revision of piece-rate of the food-grain handling workers at Bombay was in progress and, as the negotiating parties for both the workers i. e. at Bombay and Kandla were the same, a request was made by Food Corporation of India to have a settlement regarding piece-rate for the workers of Bombay first, and subsequently for the workers employed by them at Kandla. As no mutual settlement could be arrived at with regard to the revision of piece-rate in the port of Bombay, the matter was referred to the arbitration of Shri S. K. Gokhale, Dy. Chairman, Bombay Dock Labour Board. After the Award of Shri Gokhale was received which provided the retrospective effect for the revised piece-rate and the new incentive piece-rate scheme evolved for godown workers at Bombay, negotiations for evolving an incentive piece-rate scheme for Kandla workers were held and the settlement was reached in December, 1973, except on the issue of the retrospective effect for the revised piece-rate provided in the scheme. As the Charter of Demands for Kandla workers was submitted to the Food Corporation of India simultaneously with similar demand made on behalf of the Bombay workers and as the Food Corporation of India wanted to settle the Kandla incentive piece-rate scheme only after Shri Gokhale's award in respect of Bombay foodgrain workers, the union demanded that the retrospective effect for the incentive piece-rate scheme at the Port of Kandla should be the same (i.e. 1-1-72) as it was given in the case of Bombay foodgrain handling workers. The Union, therefore, feels that its demand for the retrospective effect from 1-1-72 of the incentive piece-rate scheme, which was made operative from 15-11-73 at the Port of Kandla, is quite justified.

Management's Case—

The representatives of the Management stated that a charter of demand relating to the Kandla workers was received subsequent to the charter of demands relating to the Bombay workers. They denied that the Food Corporation of India made a request to have a settlement in two parts, one consisting of service conditions and the other relating to the introduction of incentive piece-rate scheme. The Food Corporation of India, however, signed a Memorandum of Settlement dated 23-10-71 relating to the workers at Kandla only with regard to their service conditions other than the incentive piece-rate scheme, as the agreement regarding the said scheme differed in view of the union's promise to furnish a comprehensive draft scheme. In the discussions held with the union on 21-5-71 by the Dy. Zonal Manager, the Union had promised to send a comprehensive draft scheme. The union, however, never sent a comprehensive draft scheme of the incentive piece-rate as promised. They also denied that a request was made by the Food Corporation of India to have a settlement regarding piece-rate for the workers at Bombay first and subsequently for the workers at Kandla. Though the union did not furnish the promised draft scheme, it again took up the matter with the management in December, 1972 and after series of discussions a settlement was arrived at on the incentive piece-rate scheme which was made operative w.e.f. 15-11-73. They argued that as the instant one is an incentive piece-rate scheme there should not be any question of giving it retrospective effect, much less from 1-1-72 as claimed by the union. The word 'incentive' itself implies that the scheme was introduced with the definite purpose of stirring up the labour to do more work and to increase their output. The increase in wages under the scheme will be in the nature of a quid pro quo for the increase in the output of the labour. As such the increase in wages has to be necessarily prospective, inasmuch as the labour cannot increase their output retrospectively. In other words, giving retrospective effect to the scheme will amount to compelling the employer more for something which the labour did not do or could not have done. The labour could not be expected to work on incentive in the past by virtue of a scheme, which had not existed at all then. Had there been such a scheme at Kandla the labour

could have optimised their output to the benefit of Food Corporation of India, thereby avoiding wharfage and demurrage. Not having the benefit of saving or despatch money on ships or reducing the demurrage payable, the Food Corporation of India should not be made to pay the labour on incentive piece rate retrospectively. The demand of the union is arbitrary and unprecedented. It is further argued that if the scheme is given retrospective effect from 1-1-72 as claimed by the Union, it is going to involve the Corporation in an additional expenditure to the tune of more than Rs. 34 lakhs.

It will not be fair to compare the case of Bombay workers with that of Kandla workers. At Bombay even before Shri Gokhale's award the incentive piece-rate scheme was in existence, whereas at Kandla there was never an incentive piece-rate scheme. Moreover, even today the rates of the two piece-rate schemes at Bombay and Kandla are not identical. The contention of the union that the Food Corporation of India asked the union to negotiate the incentive piece-rate scheme relating to Kandla workers after the Gokhale award was contested and denied. The settlement relating to the incentive piece-rate scheme for Kandla workers was arrived at on 11-4-74 in view of the fact that the union did not furnish the comprehensive draft scheme as promised.

The representatives of the Management very strongly contended that the Food Corporation of India is not a profit making body but in fact it is a service organisation doing social service for the weaker section of the people. The resources of the Corporation comprise equity capital and loans given by the Government of India, bank overdraft and its internal resources constituted by the Depreciation Reserve and other general reserves. The entire equity capital given by the Government of India has been utilised to meet the cost of Central Storage Depots transferred by the Government, the cost of further construction of godowns, as also, the capital cost on various processing units set up by the Corporation. The loans given by the Government have been primarily used for meeting the requirements of the working capital needed by the Corporation, although a small portion has also been used for the acquisition of fixed assets. The bank overdraft allowed to the Corporation is used entirely as working capital. The Depreciation Reserve or other reserves are utilised to finance not only the minor capital assets for which equity is available but also for supplementing the requirements of liquid cash. The bulk of the operation of the Corporation is on behalf of the Government of India. Nearly all its operations are undertaken on a no-profit no-loss basis, unlike other Public Sector Undertakings. The procurement prices at which the Corporation purchases foodgrains, the issue prices at which it sells this and the procurement incidentals payable to the various procurement agencies are fixed/determined by the Government of India. The issue prices fixed by the Government of India for the foodgrains have fallen short of the full economic cost incurred by the Corporation, and the gap, which represents the losses suffered, is reimbursed to the Corporation in full as consumer subsidy. Difference between the purchase price and issue price is not taken into account and every year the National Budget shows food subsidy to the tune of Rs. 250 crores because of loss in State trading in foodgrains.

In view of the above the representatives of the management felt that it is not possible for the Corporation to agree to the union's unjustified demand which will involve tremendous additional expenditure which will be a drain on the Public Exchequer, ultimately leading to the increase in price of consumer goods and affecting the common man. More so, such an enormous expenditure from the National Coiffers is also not in tune with the present emergency.

AWARD

I have gone through the statements furnished and the documents produced by the parties very carefully. I also heard their arguments patiently. I quite appreciate the arguments advanced by the Food Corporation of India's representatives that the Food Corporation of India is not a profit-making body and in fact it is a service organisation. Even then the Food Corporation is an industry employing a large labour force and as such they will have to observe certain principles in the matter of labour relations. The departmental workers at Bombay and Kandla are under the control of the Zonal Manager (West), Bombay. The leaders of Transport and Dock Workers' Union representing Food

Corporation of India workers at Bombay and Kandla are the same persons. Thus the employer and labour leaders are the same parties as far as Bombay and Kandla are concerned. The Union raised demand on behalf of Bombay workers in September, 1970 (for revision of piece rates in respect of workers working in docks and evolving Incentive Piece Rate Scheme for Godown Workers) and on behalf of Kandla Workers in November, 1970 (for certain service conditions and introduction of Incentive Piece Rate Scheme).

The case of Bombay workers was referred to the arbitration of Shri S. K. Gokhale, Dy. Chairman, Bombay Dock Labour Board. The Arbitrator evolved an Incentive Piece Rate Scheme for Godown workers giving retrospective effect from 1-1-1972. Shri Gokhale's Award given in November, 1972 was implemented by the employer. As far as Kandla workers are concerned, their demand regarding the service conditions was settled on 23-10-1971. But the demand for Incentive Piece Rate Scheme could not be considered then as the union failed to send a comprehensive draft scheme though promised on 21-5-1971 to do so. Though the union did not furnish promised draft Scheme, it again took up the matter in December 1972, and after series of discussions a settlement on the Incentive Piece Rate Scheme was arrived at on 11-4-1974, wherein it was stated that the said Scheme shall become operative w.e.f. 15-11-1973.

It will be seen from the above para that a new Incentive Piece Rate Scheme was evolved in November 1972 for Bombay Godown workers and it was made applicable with retrospective effect from 1-1-1972. Similarly a new Incentive Piece Rate Scheme was evolved for Kandla workers and it became operative w.e.f. 15-11-1973. It will be unfair to deny the benefit of retrospective effect if not from 1-1-1972 atleast from some reasonable back date in respect of Kandla workers.

The union formally raised the demand for Incentive Piece Rate Scheme for Kandla workers in November, 1970. In the discussion with the Dy. Zonal Manager on 25-1-1971 the union promised to furnish the draft scheme. But it did not do so. I feel the union also did not pursue the matter with that seriousness for a long time. It raised the same demand quite seriously in December 1972. After series of discussions it was settled and the Scheme became operative from 15-11-1973. I, therefore, feel it will meet the ends of justice if the scheme is made applicable with retrospective effect from 1-12-1972 and I award accordingly.

S. M. DIKHALE, Chief Labour Commissioner (Central)
& Arbitrator

[No. L. 142012/33/74-LR II/D-II B]

HARBAN BAHADUR, Section Officer (Spl.).

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1976

का० बा० 809.—श्रम-जीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दरें नियत और पुनरीक्षित करने के प्रयोजनार्थ एक मजदूरी बोर्ड गठित करती है जिसमें इससे उपाबद्ध सारणी में वर्णित समाचार-पत्र स्थापनों से संबंधित कर्मचारियों और श्रम-जीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि तथा स्वतंत्र व्यक्ति होंगे और श्री डी० जी० पालेकर, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम सं०	नाम	हितों का प्रतिनिधित्व
1.	डा० राम एस० तरनेजा, सह महाप्रबन्धक, टाइम्स आफ इंडिया, डा० बाबाभाई नोरोजी रोड, बम्बई-1,	नियोजकों के प्रतिनिधि
2.	श्री नरेन्द्र तिवारी, नई दुनिया, नई दुनिया कम्पाउण्ड केशरबाग रोड, पी० ब्रो० बाक्स नं० 45, इन्दौर।	
3.	श्री एस बी कोलपे अध्यक्ष, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद, प्राप्तेकट पैम्बर प्रतेक्सी, डा० बी एन रोड, मुम्बई-1	श्रम-जीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि
4.	श्री टी० आर० रामस्वामी, महा सचिव, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद, द्वारा मद्रास पत्रकार संघ, 15, रियो स्ट्रीट, माडण्ड रोड, मद्रास-2	
5.	श्री डी० जी० पालेकर, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय।	स्वतंत्र व्यक्ति
6.	श्री बी० सी० भगवति, संसद सचिव	
7.	श्री आर० सी० बल, सेवा निवृत्त सचिव, भारत सरकार।	

[का० सं० बी-24011(2)/75 डब्लू बी०

डी० बन्धोपाध्याय, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 6th February, 1976

S.O. 809.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous provisions Act, 1955 (45 of 1955) the Central Government hereby constitutes a Wage Board for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of working journalists in accordance with the provisions of the said Act, consisting of the representatives of employers in relation to newspaper establishments and of working journalists and independent persons mentioned in the Table annexed hereto and appoints Shri D.G. Palekar, Retired Judge of the Supreme Court of India as the Chairman of the said Board.

TABLE

Sl. No.	Name	Interests represented
1.	Dr. Ram S. Tarneja Associate General Manager, Times of India, Dr. Dadabhoj Naroji Road, Bombay	Representatives of employers.
2.	Shri Narendra Tiwari, The Nai Dunia, Nai Dunia Compound, Kesharbagh Road, Post Box No. 45-Indore-452002	

1	2	3
Sl. No.	Name	Interests represented
3.	Shri S.B. Kolpe, President Indian Federation of working Journalists, Prospect Chamber Annexe, Dr. D.N. Road, Bombay-1	Representatives of working journalists.
4.	Shri T.R. Ramaswami, Secretary General, Indian Federation of Working Journalists, C/o Madras union of Journalists, 15, Ritchie Street, Mount Road, Madras-2	
5.	Shri D.G. Palckar, Retired Judge, Supreme Court of India.	Independent persons.
6.	Shri B.C. Bhagawati, M.P.,	
7.	Shri R.C. Dutt, Retired Secretary to the Government of India	

[F.No.V-24011(2)/75-WB
D. Bandyopadhyay, It. Secy

का० प्रा० 810—लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपस्कर नियम, 1963 के नियम 3 के साथ पठित, लोह अयस्क श्रम कल्याण उपस्कर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के श्रम और नियोजन विभाग की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3399, तारीख 26 सितम्बर, 1972 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्रम मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई अध्यक्ष
2. खनन और भूविज्ञान निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, नागपुर उपाध्यक्ष
3. श्री एस० एन० देसाई, सचिव, विधान सभा, महाराष्ट्र बेंगलुरा, जिला रत्नागिरि
4. श्री ए० बी० गोगटे, भागीदार गोगटे मिनरल्स, 146, तिलकवाडी बेलगुम (महाराष्ट्र)
5. श्री एस० श्रीवास्तव, निदेशक, न्यू इण्डिया माइनिंग कारपोरेशन, निर्मल, 17 वीं मंजिल, नारीमन पोयण्ट मुम्बई-20
6. श्री बी० ए० गावंस, महा सचिव आई० एन० टी० यू० सी० कोपेम, गोवा
7. श्री एम० एस० राने, न्यू इण्डिया माइनिंग कारपोरेशन, रेडी लोह अयस्क खान कर्मचारियों के प्रतिनिधि।
8. श्री मती यशोधरा बजाज, सचिव विधान सभा, महारामांगंधी मार्ग, चम्बपुर (महाराष्ट्र) महिला प्रतिनिधि।
9. सहायक कल्याण प्रशासक, लोह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, महाराष्ट्र सचिव

2. लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपस्कर नियम, 1963 के नियम 18 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नागपुर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है।

[का० सं० यू-19012/1/75-एम 4]
पी० के० सेन, अवर सचिव

S.O. 810.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) read with rule 3 of the Iron Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment No. S.O. 3399 dated the 26th Sept. 1972 the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Maharashtra with the following as members namely:—

1. Labour Minister, State of Maharashtra Chairman Bombay.
2. Director of Mining and Geology, Government of Maharashtra, Nagpur. Vice-Chairman
3. Shri S.N. Desai, Vengurla, Dist. Ratnagiri. Member of the Legislative Assembly, Maharashtra.
4. Shri A.B. Gogte, Partner, Gogate Minerals, 146, Tilakwadi, Belgaum (Maharashtra).
5. Shri S. Shrivastava, Director, New India Mining Corporation Nirmal, 16th Floor, Nariman, point, Bombay-20
6. Shri. V.A. Gavas, General Secy., INTUC Quepem, Goa.
7. Shri. M. S. Rane C/o New India Mining Corporation Redi.
8. Smt. Yeshodhra Bajaj, MLA, Mahatma Woman representative Gandhi Marg, Chandrapur (Maharashtra).
9. The Asstt. Welfare Administrator, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund for Maharashtra. Secretary
2. In pursuance of rule 18 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby fixes Nagpur to be the headquarters of the said Advisory Committee.

[F.No.U.19012/1/75-M.IV/W.A(M)]
P. K. Sen, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

का० प्रा० 811—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राधेश्याम तीर्थवासी पाल, डाकधर औरंगाबाद, जिला मुंशिदाबाद, पश्चिमी बंगाल नामक स्थापन से संबंधित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिष्ठा निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अप्रैल के तेरहवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(34)/73-पी० एफ० 2(i)]

New Delhi, the 27th January, 1976

S.O. 811.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Radha-shyam Tirthabashi Paul, Post Office Aurangabad, District Murshidabad (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirteenth day of April, 1972.

[No. S. 35017(34)/73-PF. II]

का० प्रा० 812.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 13, अप्रैल 1972 से मैसेज राधेश्याम तीर्थबाशी पाल, आकबर औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017(34)/73-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 812.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirteenth day of April, 1972, the establishment known as Messrs Radha-shyam Tirthabashi Paul, Post Office Aurangabad, District Murshidabad (West Bengal) for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(34)/73-PF. II(ii)]

का० प्रा० 813.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेज संजीव वीविंग वर्क्स, चोव्वा, कन्नानोर-6, केरल नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(215)/74-पी० एफ० 2]

S.O. 813.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sanjeev Weaving Works, Chovva, Cannanore-6, Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1974.

[No. S. 35019(215)/74-PF. II]

145GI/75—27

का० प्रा० 814.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेज फूड एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, सी-9 एण्ड 10, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, विजयवाड़ा-7 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(190)/75-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 814.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Food and Allied Products, C-9 & 10, Industrial Estate, Vijayawada-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1974.

[No. S. 35019(190)/75-PF. II(i)]

का० प्रा० 815.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् फूड एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, सी-9 एण्ड 10, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, विजयवाड़ा-7 नामक स्थापन को 1 अक्टूबर, 1974 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(190)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 815.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1974, the establishment known as Messrs. Food and Allied Products, C-9 & 10, Industrial Estate, Vijayawada-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(190)/75-PF. II(ii)]

का० प्रा० 816.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेज हर्ष ट्रेडिंग लिमिटेड, 42, जनपथ, नई दिल्ली-1, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस० 35019(202)/75-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 816.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harsha Tractors Limited, 42, Janpath, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1970.

[No. S. 35019(202)/75-PF. II(i)]

का० प्रा० 817.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स हर्ष ट्रैक्टर लिमिटेड, 42, जनपथ नई दिल्ली-1 नामक स्थापन को 1 अक्टूबर 1970 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिश्चित करती है।

[सं० एस० 35019(202)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 817.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1970, the establishment known as Messrs Harsha Tractors Limited, 42, Janpath, New Delhi-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(202)/75-PF. II(ii)]

का० प्रा० 818.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुंजर टीके मोटर सर्विस, इरेट्टुपेट्ट पंचायत, कोण्डूर ग्राम, मीनाचिल तालुक केरल राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (208)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 818.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Poonjar Teakay Motor Service, Erattupetta Panchayat, Kondoor Village, Meenachil Taluk, Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(208)/75-PF. II]

का० प्रा० 819.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केलराम टेक्स्टाइल्स, माम्बा डाकघर, अंजारकण्डी ग्राम, कन्नानोर जिला, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(214)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 819.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kelram Textiles, Mamba, Post Office, Anjarakandy Village, Cannanore District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(214)/75-PF. II]

का० प्रा० 820.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स री रायल वीवरर्स इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सं० 211, चिरककल ग्राम, डाकघर अलाविल, कन्नानोर जिला, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (216)/75 पी० एफ० 2]

S.O. 820.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Royal Weavers' Industrial Co-operative Society Limited, No. 211, Chirakkal Village, Post Office, Alavil, Cannanore District, Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(216)/75-PF. II]

का० प्रा० 821.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वनजा वीवर्स इण्डस्ट्रियल प्रोप्राइटेड सोसाइटी लिमिटेड, संख्या एच० एल० प्राई० एन० डी० सी० 4, चिरक्कल, कन्नानोर-11 (केरल) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के दशतम्वर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(217)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 821.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Vanaja Weavers' Industrial Co-operative Society Limited, No. HLIND.C. 4, Chirakkal, Cannanore-11, (Kerala), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1975.

[No. S. 35019(217)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1976

का० प्रा० 822.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वीर रबड़ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एम० प्राई० डी० सी० इन्डस्ट्रियल एस्टेट, प्लॉट सं० 1 अम्बरनाथ नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के दिसम्बर के दशतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35018 (63)/75-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 29th January, 1976

S.O. 822.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Vir Rubber Products Private Limited, M.I.D.C. Industrial Estate, Plot No. 1, Ambernath, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtyfirst day of December, 1974.

[No. S. 35018(63)/75-PF. II]

का० प्रा० 823.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ल्यूसोब ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बेल बिल्डिंग, सर फीरोज शाह मेहता रोड, मुम्बई, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35018 (127)/73-पी० एफ० II(i)]

S.O. 823.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Lusob Trading and Engineering Company Private Limited, Bell Building, Sir Pherozshah Mehta Road, Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1973.

[No. S. 35018(127)/73-PF. II(i)]

का० प्रा० 824.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स ल्यूसोब ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बेल बिल्डिंग सर फीरोज शाह मेहता रोड, मुम्बई नामक स्थापन को 1 अप्रैल, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35018 (127)/73-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 824.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1973 the establishment known as Messrs Lusob Trading and Engineering Company Private Limited, Bell Building, Sir, Pherozshah Mehta Road, Bombay-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(127)/73-PF. II(ii)]

का० प्रा० 825.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डस्ट्रियल एण्ड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड मेकर भवन सं० 2 छटी मंजिल, न्यू मीरीन लाईंस, मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक, और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35018 (129)/73-पी० एफ० II(i)]

S.O. 825.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Industrial and Structural Private Limited, Maker Bhavan No. 2, 5th Floor, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1973.

[No. S. 35018(129)/73-PF. II(i)]

का० प्रा० 826.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स इण्डस्ट्रियल एण्ड स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड, मेकर भवन सं० 2, छठी मंजिल न्यू मरीन लाइन्स, मुम्बई-20 नामक स्थापन की 1 जून, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018 (129)/73-पी० एफ० II (ii)]

S.O. 826.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of June, 1973, the establishment known as Messrs. Industrial and Structural Private Limited, Maker Bhavan No. 2, 5th Floor, New Marine Lines, Bombay-20, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(129)/73-PF. II(ii)]

का० प्रा० 827.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुन्नर क्लब, क्लब रोड, कुन्नर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019 (6)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 827.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Coonoor Club, Club Road, Coonoor, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019(6)/75-PF. II]

का० प्रा० 828.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओरियेंटल होटल्स लिमिटेड (ताज कोरोमण्डल होटल) 5, नुंगम्बक्कम हाई रोड, मद्रास-34 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019 (33)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 828.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Oriental Hotels Limited, (Taj Coromandel Hotel) 5, Nungambakkam High Road, Madras-34 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35019(33)/75-PF. II]

का० प्रा० 829.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री मंगल टेक्सटाइल्स, ए० पी० औद्योगिक एस्टेट, गुजरात हाउसिंग कालोनी के निकट, अहमदाबाद-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019 (115)/75-पी० एफ० 11]

S.O. 829.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shree Mangal Textiles. A. P. Industrial Estate, Near Gujarat Housing Colony, Ahmedabad-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1974.

[No. S. 35019(115)/75-PF. II]

का० आ० 830.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिक बिल्डर्स लिमिटेड, सी-13, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कटक-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35019 (157)/75-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 830.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Unique Builders Limited, C-13, Industrial Estate, Cuttack-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1973.

[No. S. 35019(157)/75-PF. II(i)]

का० आ० 831.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स यूनिक बिल्डर्स लिमिटेड, सी-13, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कटक-3 नामक स्थापन को 1 अगस्त, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019 (157)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 831.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1973, the establishment known as Messrs. Unique Builders Limited, C-13, Industrial Estate, Cuttack-3 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(157)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 832.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री दुर्गा एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, गान्धी नगर, विजयवाड़ा-3, जिसके अन्तर्गत 132, माउन्ट रोड, मद्रास-6 स्थित उसकी शाखा भी आती है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35019 (193)/75-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 832.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shree Durga Agencies Private Limited, Gandhi Nagar, Vijayawada-3 including its branch at 132, Mount Road, Madras-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March 1975.

[No. S. 35019 (193)/75-PF. II(i)]

का० आ० 833.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स श्री दुर्गा एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, गान्धी नगर, विजयवाड़ा-3 जिसके अन्तर्गत 132, माउन्ट रोड, मद्रास-6 स्थित उसकी शाखा भी आती है, नामक स्थापन को 31 मार्च, 1975 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019 (193)/75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 833.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of March, 1975, the establishment known as Messrs. Shree Durga Agencies Private Limited, Gandhi Nagar, Vijayawada-3 including its branch at 132, Mount Road, Madras-6, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019(193)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 834.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जमनादास माधव जी एण्ड कम्पनी, एनीमल फीड्स डिवीजन, गोपालराव स्ट्रीट, हनुमान पेठ, विजयवाड़ा-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस-35019(194)/75-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 834.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jamnadas Madhavji and Company, Animal Feeds Division Gopalrao Street, Hanumanpet, Vijayawada-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1975.

[No. S. 35019(194)/75-PF.II(i)]

क्रा० प्रा० 835.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक ज्ञान धर लेने के पश्चात् मैसर्स जमनादास माधव जी एण्ड कम्पनी, एनीमल फीड्स विविजन, गोपाल राव स्ट्रीट हनुमान पेठ, विजयवाड़ा-3 नामक स्थापन को 1 अगस्त, 1975 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019 (194) /75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 835.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1975, the establishment known as Messrs Jannadas Madhavji and Company, Animal Feeds Division, Gopalrao Street Hanumanpet, Vijayawada-3, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(194)/75-PF.II(ii)]

क्रा० प्रा० 836.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेन हार्विक, इण्डस्ट्रियल एस्टेट पोस्ट बॉक्स सं० 39, रोड सं० 1, उधना जिला सुरत, जिसके अन्तर्गत (1) 37, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मुम्बई-2 और (2) सं० 9, मिघ कावोली, बोलकपुर, सिकन्दराबाद स्थित उसकी शाखाएं भी आती हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (196)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 836.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sen Harvic, Industrial Estate, Post Box No. 39, Road No. 1, Udhna, District Surat including its branches at (1) 39 Abdul Rehman Street, Bombay-2 and (2) No. 9, Migh Colony Bolakpur, Secunderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1973.

[No. S. 35019(196)/75-PF.II]

क्रा० प्रा० 837.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरियाणा पेपर मिल्स, 50, न्यू इण्डस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (197) /75-पी० एफ० 2]

S.O. 837.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Haryana Paper Mills, 50, New Industrial Town, Faridabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1973.

[No. S. 35019(197)/75-PF.II]

क्रा० प्रा० 838.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पाल ब्रदर्स, ई-66, इण्डस्ट्रियल एरिया, जलन्धर सिटी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (198)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 838.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Paul Brothers, E-66, Industrial Area, Jullundur City, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1975.

[No. S. 35019(198)/75-PF.II]

का० प्रा० 839.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महाराजा सवाई मान सिंह-II म्यूजियम ट्रस्ट, सिटी पैलेस, जयपुर-2 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, धन, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1975 के सितम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(201)/75-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 839.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Maharaja Sawai Man Singh II Museum Trust, City Palace, Jaipur-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1975.

[No. S. 35019(201)/75-PF.II (i)]

का० प्रा० 840.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स महाराजा सवाई मानसिंह II, म्यूजियम ट्रस्ट, सिटी पैलेस, जयपुर-2 नामक स्थापन को 1 सितम्बर, 1975 के उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिश्चित करती है ।

[सं० एस-35019 (201)/75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 840.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1975, the establishment known as Messrs. Maharaja Swai Man Singh II Museum Trust, City Palace, Jaipur-2, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(201)/75-PF.II(ii)]

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० प्रा० 841.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 ब की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1460 तारीख 9 मई, 1973 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी०एस० छोटरेकर के स्थान पर श्री धार० एम० गांधी को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों का निर्वहन

करने में सहायता देने के लिए, समस्त पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अन्धमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए एतद्वारा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करती है ।

[सं० ए-12016 (14) /73-पी० एफ० 1 (i)]

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 841.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 1460, dated the 9th May, 1973, the Central Government hereby appoints Shri R. M. Gandhi as the Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of West Bengal and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties, vice Shri P. S. Dhotrekar.

[No. A. 12016(14)/73-PF-I(i)]

का० प्रा० 842.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1459 तारीख 9 मई, 1973 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री धार० एम० गांधी को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में, जिसकी एक से अधिक राज्य में शाखाएं या विभाग हों। सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अन्धमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए-12016 (14)/73-पी० एफ० 1 (ii)]

S.O. 842.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 1459 dated the 9th May, 1973 the Central Government hereby appoints Shri R. M. Gandhi to be an Inspector for the whole of the State of West Bengal and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(14)/73-PF.I(ii)]

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1976

का० प्रा० 843.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के धन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2853 तारीख 18 अगस्त, 1975 के अनुक्रम में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के अर्थात्तन से, 23 अक्टूबर, 1975 से 22 अक्टूबर, 1976 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उससे शोध्य थीं,

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का कोई पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

- (i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या
- (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन कायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना रहता है जिसको ध्यान में रखते हुए इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या
- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सम्भवतः किया जायगा कि वह—
 - (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करेगा कि वह उसे ऐसी सूचना दे जो वह आवश्यक समझे; या
 - (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिसोपाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे बहियाँ और अन्य वस्तावेजों, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करे या उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
 - (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अधिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करे; या
 - (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य वस्तावेज की प्रतियाँ तैयार करे या उससे उद्धरण ले।

व्याख्यात्मक शायन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि नियोजक से छूट के नवीकरण के लिए आवेदन विनियम से प्राप्त हुआ था। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को मूल रूप से छूट प्रदान की गई थी, वे अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छूट की पूर्वापेक्षी प्रभाव से मंजूरी किसी भी व्यक्ति के हिस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस० 38017/9/74-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रानमन, उप सचिव

New Delhi, 2nd February, 1976

S.O. 843.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2853 dated the 18th August, 1975 the Central Government hereby exempts the National Physical Laboratory, New Delhi from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 23rd October, 1975 upto and inclusive of the 22nd October, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for renewal of exemption was received late from the employer. However, it is certified that the condition under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/9/74-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 7th February, 1976

S.O. 844.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the Industrial dispute between the employers in relation to the South Indian Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th February, 1976.

**BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
MADRAS.**

(Constituted by the Central Government)

Thursday, the 22nd day of January, 1976

Industrial Dispute No. 33 of 1974

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of South India Bank Ltd., Trichur-1.)

BETWEEN

The workmen represented by the General Secretary, All Kerala Bank Employees Federation, Y.M.C.A. Road, Trivandrum.

AND

The Chairman, South Indian Bank Ltd., Head Office, P.B. No. 28, Trichur-1.

REFERENCE :

Order No. L. 12012/26/74/LR. III, dated 16-8-1974 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru M. Venugopalan, advocate, appearing for the management and the workmen and their advocates being absent, this Tribunal made the following.

AWARD

By order No. L. 12012/26/74/LR. III, dated 16th August, 1974, the Government of India, Ministry of Labour have referred the following dispute between the employees and the management of the South Indian Bank Limited for adjudication by this Tribunal.

2. The point for determination is :

"Whether the action of the management of South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur-1, in

transferring Shri Srikumaran, District Secretary of the All Kerala Bank Employees Federation from the branch bank at Manjeri, the district headquarters to branches at other places overlooking the rights and privileges enjoyed under awards and agreements in respect of an office bearer and in violation of the agreement dated the 20th August, 1973 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

3. The General Secretary of the All Kerala Bank Employees' Federation, Trivandrum has filed a claim statement alleging that the workers concerned in this dispute are regarded as a protected workmen; that the respondent management has victimised Sri Kumaran Nair for his legitimate trade union activities in transferring him from the branch at Manjeri.

4. The respondent management has filed a counter statement denying the allegations. The positive case of the management is that the transfer was due to exigencies of service.

5. **POINT :** Unfortunately, the counsel for the union nor anybody on behalf of the Union was present when the case was called though the counsel for the Union was served on 9-1-1976 intimating the fact of the posting of this case. The learned counsel for the management filed Ex. M-1 which is a copy of the agreement between the management and the South Indian Bank Employees' Association. Ex. M-1 does not show that there was violation of any of the terms of the settlement. There are no merits in this claim made in the claim statement. Under those circumstances, I find this issue against the claimant.

6. In the result, an award is passed negating the claims of the Union. There will be no order as to costs.

Dated, this 22nd day of January, 1976.

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED :

For both sides.—None.

DOCUMENTS MARKED :

For workmen.—Nil.

For management :

Ex. M-1 : Memoranda of settlement arrived at between the South Indian Bank Limited, Trichur and the South Indian Bank Employees' Association (copy).

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.

Note : Parties are directed to take return of their documents within six months from the date of the Award.

[No. L-12012/26/74-LR-III]

New Delhi, the 10th February, 1976

S.O. 845.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the South Indian Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th February, 1976.

**BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
MADRAS.**

(Constituted by the Central Government)

Thursday, the 22nd day of January, 1976

Industrial Dispute No. 34 of 1974

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of South Indian Bank Ltd., Trichur-1.)

BETWEEN

The workmen represented by the General Secretary, South Indian Bank Employees Association, P.B. No. 131, Post Office Road, Trichur-1.

AND

The Chairman, South Indian Bank Ltd., Head Office,
P.B. No. 38, Trichur-1.

REFERENCE :

Order No. L-12012/27/74-LR.III, dated 16-8-1974 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for hearing this day, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru M. Venugopalan, Advocate appearing for the management and the workmen and their advocates being absent, this Tribunal made the following.

AWARD

By order No. L-12012/27/74/LR.III, dated 16th August, 1974, the Government of India, Ministry of Labour have referred the following dispute between the employees and the management of the South Indian Bank Limited for adjudication by this Tribunal.

2. The point for determination is :

"Whether the transfer order issued by the management of South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur-1 to Shri Davis, Clerk transferring him from Trichur to Dindigul during the pendency of the conciliation proceedings is legal and justified? If not, to what relief is he entitled?"

3. The General Secretary of the South Indian Bank Employees' Association has filed a claim statement alleging that the claimant Davis raised a dispute and it was amicably settled; that while the conciliation proceedings was pending the management transferred him from Trichur to Dindigul.

4. The respondent management has filed a counter statement contending that the conciliation related only to the promotion and after the matter was settled and promoted he was transferred due to exigencies of service.

5. POINT: Unfortunately, there was no representation on behalf of the Union and their counsel also was absent. The counsel for the management filed Exs. M-1 to M-3. Ex. M-2 is the report of the Assistant Labour Commissioner (Central),

Ernakulam. It is dated 10th January, 1973. It reads that the claimant Sri M. O. Davis has been promoted to the clerical cadre with effect from 18-12-73 and under those circumstances the matter was closed. Ex. M-3 dated 27th February, 1974 is the order transferring Sri M. O. Davis from Trichur to Dindigul. Thus it is seen that after the disposal of the conciliation proceedings he was transferred as per the custom and the practice and also on the ground of the exigencies of service from Trichur to Dindigul. It is clearly seen that the conciliation is related only to his promotion and not his transfer. As per the Sastri and Desai Awards, the Bank is entitled to transfer its employees on administration grounds. There are no merits in this contention raised by the Association. This point is found against the union.

6. In the result, an award is passed negating the claims of the Association. There will be no order as to costs.

Dated, this 22nd day of January, 1976.

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.
WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For workmen : Nil.

For management :

Ex. M-1/4-5-1974.—Letter from Under Secretary with reference No. L-12012/25/74/LR.III, Ministry of Labour, Government of India, addressed to the workmen and the management of South Indian Bank Ltd., Trichur-1 declining reference. (copy).

Ex. M-2/10-1-1973.—Letter from Asst. Labour Commissioner (Central) Ernakulam, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Government of India addressed to South Indian Bank Employees' Association, Trichur-1 stating that Sri M. O. Davis has been promoted to the clerical cadre with effect from 18-12-73 (copy).

Ex. M-3/27-2-1974.—Office order regarding Sri M. C. Davis, Clerk transferred to Br. Dindigul. (copy).

(Sd)/- T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.
Note : Parties are directed to take return of their documents within six months from the date of the award.

[No. L-12012/27/74-LR. III]
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.